



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 849]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2016/अग्रहायण 22, 1938

No. 849]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2016/AGRAHAYANA 22, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशालय)

(सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

विषय: “अनरॉट एल्यूमिनियम” (अलॉय और गैर- अलॉय एल्यूमिनियम) के भारत में आयातों से संबंधित जांच –  
अंतिम निष्कर्ष।

**सा.का.नि. 1131(अ).**—सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) अधिनियम, 1975  
एवं उसके सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के संबंध में।

## I. प्रक्रिया

- सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष (i) मैं वेदांता लिमिटेड – एल्यूमिनियम एवं पावर, भुरकामुंडा, जिला झारसूगुडा-768202, उड़ीसा (ii) मैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को), एल्यूमिनियम सदन, कोर-6, स्कोप ऑफिस कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 एवं (iii) मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचूरी भवन, तीसरी मंज़िल, डॉ. एनी बेसेट रोड, वर्ली, मुंबई-400030 द्वारा अनरॉट एल्यूमिनियम” (अलॉय और गैर- अलॉय एल्यूमिनियम) के वर्धित आयातों से अनरॉट एल्यूमिनियम” (अलॉय और गैर- अलॉय एल्यूमिनियम) के घरेलू उत्पादकों को हुई गंभीर क्षति/ खतरों उनकी रक्षा के लिए

अनरॉट एल्यूमिनियम” (अलॉय और गैर- अलॉय एल्यूमिनियम) के भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए दिनांक 19.04.2016 को एक अद्यतन आवेदन दिया गया है। घरेलू उद्योग ने भी अनरॉट एल्यूमिनियम” (अलॉय और गैर- अलॉय एल्यूमिनियम) के वर्धित आयातों के परिणामस्वरूप अपने निष्पादन में तीखी गिरावट को ध्यान में रखते हुए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

2. उक्त रक्षोपाय नियमों के नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं को जहां तक आवश्यक समझा गया, जांचा गया। जांच रिपोर्ट का अगोपनीय संस्करण सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। यह संतुष्ट होने पर की नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं, अनरॉट एल्यूमिनियम” (अलॉय और गैर- अलॉय एल्यूमिनियम) के भारत में आयातों के विरुद्ध दिनांक 19.04.2016 के जांच की शुरुआत के नोटिस, जो उसी दिन भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, द्वारा जांच शुरू की गई।

3. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) एवं 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति के साथ दिनांक 19.04.2016 के जांच की शुरुआत के नोटिस की प्रति केंद्र सरकार के वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों को, मुख्य निर्यातक देशों की सरकारों को उनके दूतावासों के माध्यम से, घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में वर्णित अन्य इच्छुक पक्षों को अग्रेषित की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात इच्छुक पक्षों को प्रश्नावली इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे जांच की शुरुआत के नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचारों से लिखित में अवगत करा दें।

#### 4.1 घरेलू उत्पादक/आयातक (मै.).:

- क. एलम एक्स्ट्रैजन लिमिटेड.
- ख. एलम एक्स्ट्रैजन लिमिटेड
- ग. एनम इलेक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी
- घ. अनामिका कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
- ड. अनविल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
- च. अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- छ. एपीएस एंटरप्राइज
- ज. असोसिएटेड एल्यूमिनियम
- झ. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
- ञ. भोरुका एल्यूमिनियम लिमिटेड
- ट. सेंचुरी मैटल रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. कोंटीनेंटल इंजन्स लिमिटेड
- ड. दीपल केबल्स
- ढ. डायमंड केबल्स लिमिटेड
- ण. ग्लोस्टर केबल्स
- त. गुसा पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
- थ. हरियाणा कंडक्टर्स
- द. हेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ध. हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- न. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- प. हिंदुस्तान विद्युत प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- फ. हिरेन एल्यूमिनियम

- ब. जे. एम. इंडस्ट्रीज
- भ. जे एंड के एल्यूमिनियम
- म. जिंदल एल्यूमिनियम
- ग. केर्डआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- कक. केजेवी
- खख. लुमिनो इंडस्ट्रीज
- गग. मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
- घघ. मनकसिआ लिमिटेड
- डड. मास्टर इंडिया
- चच. मास्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- छछ. मैटल पॉवर कंपनी लिमिटेड
- जज. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
- झझ. नोएडा एल्यूमिनियम
- जज. नॉर्थ इस्टर्न केबल्स एंड कंडक्टर्स
- टट. पैरामाउंट कोम्पनिकास्हंस लिमिटेड
- ठठ. पोलीकैब वायर प्राइवेट लिमिटेड
- डड. प्रेम केबल्स लिमिटेड
- ढढ. राजस्तान केबल्स एंड कंडक्टर्स
- णण. रवीन केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
- तत. स्मिता इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- थथ. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- दद. द मैटल पाउडर कंपनी लिमिटेड (मेप्को)
- धध. यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड
- नन. वाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- पप. वेंकटेश्वरा वार्यस प्राइवेट लिमिटेड
- फफ. विजय इलेक्ट्रीकल्स

#### 4.2 ज्ञात नियांतक (मै.):

- क. एल्कन प्राइमरी मैटल
- ख. अल्बा
- ग. एएलसीओए
- घ. अलमंडी एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन
- ड. अल्बा एल्यूमिनियम लिमिटेड
- च. एओएसटीएआर
- छ. बहरीन अलॉच्ज मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी

- ज. बीएचपी विलिटॉन/ बीएचपी विलिटॉन लिमिटेड  
 झ. बीएचपी विलिटॉन पीएलसी.  
 अ. चाल्को  
 ट. दुर्वई एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड  
 ठ. यूरेशियन वेंचर्स एफज़ेडए.  
 ड. ग्लैनकोर  
 ढ. इराल्को  
 ण. लकी अलॉय्ज लिमिटेड  
 त. एमआईएनएल लिमिटेड (मनकसिआ)  
 थ. नैनजिंग वैलबो मैटल्स कंपनी लिमिटेड  
 द. ओ एंस एस मैटलिम्पोर्ट जीएमवीएच  
 ध. फिनिक्स स्टील मिल्स लिमिटेड  
 न. रिओ टिंटो इंकलिया  
 प. शंघाई ज़ैंग्यू स्पेशल अलॉय्ज  
 फ. शेंजैन ऐडा एल्यूमिनियम अलॉय्ज  
 ब. ट्रेफिगुरा  
 भ. यूनिजेम्स इम्पैक्स लिमिटेड  
 म. यूनाइटेड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड  
 य. यूनिवर्सल कॉरपोरेशन
- 4.3 निर्यातक देशों की सरकार/ विदेशी प्रतिनिधि मंडल
- क. यूएई का दूतावास  
 ख. मलेशिया का दूतावास  
 ग. रशियन फैडरेशन का दूतावास  
 घ. दक्षिण अफ्रीका का दूतावास  
 ड. ओमान का दूतावास  
 च. क्रतर का दूतावास  
 छ. बहरीन का दूतावास  
 ज. थाइलैंड का दूतावास  
 झ. सऊदी अरेबिया किंगडम का दूतावास  
 अ. ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग  
 ट. नाइजीरिया उच्चायोग  
 ठ. सिंगापुर रिपब्लिकन उच्चायोग  
 ड. भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल
5. निम्नलिखित पक्षों से या तो इच्छुक पक्ष मानने का अनुरोध मिला है अथवा उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं:

- क. ऑल इंडिया एल्यूमिनियम सेकेंडरी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
- ख. ऑल इंडिया नॉन-फेरस मैटल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
- ग. एल्यूमिनियम एक्स्ट्रुडर्स काऊंसिल (एलैक्स)
- घ. एसोसिएटेड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
- ङ. केवल्स एंड कंडक्टर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
- च. सीएमआर निकै इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- छ. सीएमआर तोयोत्सु एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ज. डायनैमिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
- झ. इलैक्ट्रीकल सेंटर
- ञ. ग्लोबल एल्यूमिनियम
- ट. जीटीएल लिमिटेड
- ठ. इंडियन इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए)
- ड. इंडो एलुसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ढ. जेएसके इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- ण. केर्झीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
- त. केजेवी अलॉय कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड
- थ. महाराष्ट्र कंडक्टर एसोसिएशन
- द. मैटल रिसाइकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- ध. ओपल इंडस्ट्रीज
- न. ओसवाल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
- प. पैरागोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- फ. सरगम मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ब. श्री बालाजी एल्यूमिनिकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
- भ. साउथ एशिया फोरम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी
- म. श्री सुमंगला मैटल्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- य. स्टर्डी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 28, अशोका
- कक. सुपर टैक फोर्जिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- खख. ठाकुर इलैक्ट्रीकल्स एंड इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
- गग. वेदांता लिमिटेड, एल्यूमिनियम एंड पॉवर
- घघ. विर्गो एल्यूमिनियम लिमिटेड
- ङङ. वेस्टर्न इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- चच. हीरो मोटरकोर्प लिमिटेड, गुडगांव
- छछ. एंड्योरेंस टैक्लोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद

- जज. रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लुधियाना
- झज्ज. ट्रांस सोल्यूशन, इंदौर
- बज. शिव एंटरप्राइजेज, इंदौर
- टट. कल्पतरू पॉवर ट्रांसमीशन लिमिटेड, गुजरात
- ठठ. एल्को इलेक्ट्रोस्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल
- डड. आदिनाथ इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर
- ढढ. शशि केवल्स लिमिटेड, लखनऊ
- णण. ब्हाइट मैटल लिमिटेड, नोएडा
- तत. इंडियन फाउंडरी ऑर्गनाइजेशन, बैंगलूरु
- थथ. जेएम इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र
- दद. प्रेस मैटल बरहद, मलेशिया
- धध. हाइड्रो एल्यूमिनियम एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- नन. मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ द रशियन फेडरेशन, मॉस्को
- पप. युनाइटेड कंपनी रूसेल, रशिया
- फफ. इकोनोमिक डीविजन, ताइपे इकोनोमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया
- बब. डायरेक्टर ऑफ ट्रेड डिफेंस, डायरेक्टोरेट जनरल ओफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया
- भभ. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट

6. उक्त सभी अनुरोध मान लिए गए थे और वे पक्ष जिन्होंने अपने विचार भेजे थे उन्हें भी इच्छुक पक्ष मान लिया गया। कुछ इच्छुक पक्षों ने जांच की शुरुआत के नोटिस के संबंध में अपने विचार भेजने हेतु समय विस्तार के लिए अनुरोध किया था। उनका अनुरोध मान लिया गया और उनको समय विस्तार दे दिया गया।

7. घरेलू उद्योग ने अपने दायर आवेदन में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के द्वारा तत्काल राहत के लिए अनुरोध किया है। इसके समर्थन में उन्होंने सूचीबद्ध मापादंडों पर आधारित अपनी अनिश्चित स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा झेली जा रही महत्वपूर्ण परिस्थितिओं का विद्यमान होना दर्शाया गया है और यह भी अनुरोध किया है कि यदि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाता है तो उनको अपूरणीय क्षति होगी, जिसको दुरुस्त करना कठिन होगा।

8. घरेलू उद्योग द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के अनुरोध की जांच की गई थी और प्रथम दृष्टया यह पाया गया ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को होने वाली अपूरणीय क्षति, जिसको दुरुस्त करना कठिन होगा, से बचाने के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की आवश्यकता है।

9. तदनुसार, अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के लिए प्रारंभिक निष्कर्ष सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 9(2) के अधीन 21 अप्रैल, 2016 को जारी कर दिया गए थे और उसी दिन अर्थात् 21 अप्रैल, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे।
10. अनंतिम रक्षोपाय शुल्क केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया है।
- II. पश्च शुरुआत निवेदन: उन निवेदनों का जो कि जांच शुरू करने के नोटिस की प्रतिक्रिया स्वरूप परंतु लोक सुनवाई से पूर्व प्राप्त हुए थे, का सारांश इस प्रकार है:
- अ. मै. इंडियन इलेक्ट्रोनिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
- क. मूल सीमा शुल्क ड्यूटी (बीसीडी), एलएमई एवं अन्य कारकों में वृद्धि के साथ आयातित माल के उतारने तक की लागत में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है (>13%).
  - ख. एसईजैड के अतिरिक्त अन्य संयत्रों में क्षमता-उपयोग का बहुत अच्छा उपयोग है (लगभग 80%)। वेदांता का एसईजैड संयत्र सिर्फ निर्यात के लिए बना है और इसे क्षमता-उपयोग आंकड़ों तथा क्षति मार्जिन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
  - ग. हालिया बजट में, एल्यूमिनियम पर बीसीडी 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया था जिसने गिरते एल्यूमिनियम उपभोक्ताओं पर पहले ही भारी दबाव डाल दिया। कंडक्टर निर्माता इस वर्धित लागत को वहन करने में सक्षम नहीं है क्योंकि ट्रांसमीशन लाईन्स के लिए अपनाई जाने वाली टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के कारण उनके अनुबंधोंकी कीमतें कम हो गई हैं।
  - घ. याचिकाकर्ता अमेरिकन डॉलर के सामने भारतीय रूपये के मूल्य ह्रास के भी हिताधिकारी हैं क्योंकि उनकी प्राप्ति भारतीय राष्ट्रीय रूपये में है। विनिमय दर \$ = आईएनआर, जो कि तीन वर्ष पूर्व @ 50 रुपये थी, अब वर्तमान में @ 68 रुपये है।
  - ड. एलएमई मूल्य भी यूएसडी 1500 लेवल से बढ़कर यूएसडी 1500 लेवल हो गया है, जिसके कारण घरेलू उत्पादकों को बहुत अधिक प्राप्ति हो रही है।
  - च. चीन अथवा मध्य पूर्व के एल्यूमिनियम आपूर्तिकर्ता एलएमई मूल्य के आधार पर एल्यूमिनियम धातु के विक्रय मूल्य का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय मूल्य के अनुसार कर रहे हैं। उनके मूल्य सस्ते/कम नहीं हैं जैसा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा अभिकथित है।
  - छ. चीन अथवा मध्य पूर्व के निर्माताओं के पास कोई प्राकृतिक साधन नहीं हैं अतः वे मूल एल्यूमिना आयात करते हैं जब कि भारतीय प्राथमिक उत्पादकों के पास उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय बॉक्साइट एवं कोयले का लाभ है।
  - ज. भारत की तुलना में मध्य पूर्व के निर्माताओं की कर्मचारी वेतन एवं मजदूरी लागत 40 से 45% ज्यादा है। भारतीय आयातक, इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी, समाशोधन खर्च का भुगतान करते हैं एवं माल के पत्तन से अपनी फैक्टरी तक का परिवहन व्यय भी वहन करते हैं।
  - झ. बीसीडी में वृद्धि के कारण वे पहले ही विकट इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना कर रहे हैं। तैयार माल अध्याय 98 के अधीन प्रोजेक्ट आयात के आधार पर आयात के लिए ग्राह्य है, जहां कंडक्टर और केबल्स पर ड्यूटी की मैरिट लिस्ट के बजाए मूल आयात ड्यूटी 5% है।
  - ज. अनुबंध एल-1 आधार पर दिए गए हैं और वर्तमान में भारतीय निर्माता अपने चीनी समकक्षों के पक्ष में अपना बाजार हिस्सा खो रहे हैं। न्यूनतम आयात मूल्य मैकेनिजम में वृद्धि के अतिरिक्त स्टील पर ड्यूटी में 10% की वृद्धि एवं एल्यूमिनियम पर ड्यूटी 7.5% बढ़ गई है, जबकि अध्याय 98 के अधीन कंडक्टर पर

- ज्यूटी 5% की दर पर बनी हुई है। चीनी निर्माताओं ने अध्याय 98 के अधीन भारत में 5% ज्यूटी से कम में कोट करना शुरू कर दिया है।
- ट. यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो भारतीय कंडक्टर एंड केबल निर्माता अपने संयंत्र बंद करने को बाध्य हो जाएंगे क्योंकि चीनी एवं अन्य विदेशी कंडक्टर एवं केबलों की भारतीय बाजार में भरमार हो जाएगी। एल्यूमिनियम निर्माता लाभदायक घरेलू हिस्सा खो देंगे जहां आयातित एल्यूमिनियम पर मूल कस्टम ज्यूटी के कारण 7.5% की सुरक्षा का लाभ उठाते हैं और तदनुसार आयात समता के अनुसार अपनी कीमतों में वृद्धि कर लेते हैं।
- ठ. एल्यूमिनियम पर ज्यूटी की वर्तमान दर के साथ भारतीय कंडक्टर निर्माताओं की लागत चीनी लागत की तुलना में पहले से ही ऊँची है। तथापि, यदि अतिरिक्त 5% रक्षोपाय शुल्क के कारण एल्यूमिनियम पर ज्यूटी बढ़ाई जाती है तो यह भारतीय निर्माताओं को चीनियों की तुलना कहीं अधिक मंहगा बना देगा।
- ड. जबकि स्टील पर वर्धित ज्यूटी के उद्योग को क्षति हुई है, एल्यूमिनियम पर ज्यूटी बढ़ाने से भारत में पॉवर सेक्टर की एल्यूमिनियम की मांग खत्म हो जाएगी क्योंकि तैयार कंडक्टर/केबल का आयात बढ़ जाएगा। यह दृष्टिकोण भारतीय कंडक्टर एवं केबल निर्माताओं को इनवर्टेड ज्यूटी स्ट्रक्चर से आगे भी नुकसान पहुंचाएगा, जो कि भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल के प्रतिकूल है।
- ढ. घरेलू बाजार के लिए अपने उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करते हुए ज्यूटी में वृद्धि पर प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्माता विचार करेंगे और घरेलू निर्माताओं के तैयार एल्यूमिनियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में ऊँची होंगी। इससे तैयार उत्पादों का आयात ज्यादा लाभदायक हो जाएगा और इससे पहले ही नीचे की ओर गिरते उद्योग अलाभकारी बन जाएगे और अंततः बंद हो जाएंगे और रोजगार प्रभावित होंगे।
- ण. सीमा शुल्क ज्यूटी में किसी भी वृद्धि से उपभोक्ता, सामान्यतः, आम आदमी के लिए भी कीमतों में वृद्धि होगी। इसका एक संक्रामक प्रभाव होगा जिससे सरकार के सभी को 24X7 विजली देने और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- त. एल्यूमिनियम उत्पादकों ने अपनी अंतरिक कार्य प्रणाली की सही तथ्यात्मक सूचना नहीं दी है। उनकी अभिकथित क्षति आत्म-प्रवृत्त है न कि जैसा की वे बता रहे हैं आयात के कारण हैं।
- थ. सभी याचिकार्ताओं ने हाल में अतिरिक्त क्षमता अर्जित की है जो कि घरेलू बाजार से बहुत अधिक है। वास्तव में ब्याज की लागत और मुख्यतः निर्यात के लिए विस्तार करने के कारण हुए मूल्य ह्लास के बजह से उनके वित्त पर चोट पड़ी है।
- द. वेदांता का 1.2 मिलियन टन एल्यूमिनियम का विशाल निवेश विशेष रूप से एसईज़ेड के लिए है। यह निवेश बहुत वर्षों पूर्व किया गया था, परंतु इसका प्रचालन नियमगिरि आदि खदानों से बॉक्साइट के चलते उनके समूह की समस्याओं के कारण प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है। तथापि, एसईज़ेड का निवेश और ब्याज एवं मूल्यह्लास की सम्बद्ध लागतें उनके लाभ एवं हानि में दर्शाई गई हैं।
- ध. यह तर्क कि उनकी क्षति आयात की कम कीमतों के कारण हुई है, सही नहीं है क्योंकि एसईज़ेड बहरहाल मात्र निर्यात के लिए प्रयोग करने हेतु बने हैं। यदि क्षमता उपयोग की गणना करते हुए एसईज़ेड की क्षमता को हटाया जाए तो एल्यूमिनियम उत्पादकों का क्षमता उपयोग वर्तमान में प्रस्तुत क्षमता उपयोग का लगभग 80% होगा।
- न. एल्यूमिनियम उत्पादक कंडक्टर एवं केबल निर्माताओं को मानित निर्यात आधार पर बेचने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय एलएमई+ज्यूटी फ्री कीमतों पर प्रीमियम कीमतों की बराबरी करने की इच्छा नहीं रखते हैं। एल्यूमिनियम उत्पादक भौतिक रूप से निर्यात करते हुए लाभ में रहते हैं क्योंकि उन्हें निर्यात लाभ मिलते हैं जबकि मानित निर्यात व्यवसाय में उनको ये प्रोत्साहन नहीं मिलते हैं।

- प. कंडक्टर एवं केवल निर्माता एल्यूमिनियम का आयात ड्यूटी फ्री बेसिस पर करने के लिए बाध्य कर दिए गए हैं। 100000 एमटी से अधिक एल्यूमिनियम कंडक्टर उद्योग जो तैयार उत्पादों के निर्यात के लिए हैं, की खपत के लिए आयात किए जा रहे हैं।
- फ. कंडक्टर के निर्यात में वृद्धि हुई है जो एचएस कोड 76042910, 76041000 एवं 76049000 के अधीन वर्गीकृत की गई है। यदि केवल उद्योग का निर्यात शामिल किया जाए तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में सिल्लियों का पूरा आयात एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम उत्पादों के अंगेस्ट है। अतः प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क में एल्यूमिनियम सिल्लियां कवर नहीं होनी चाहिए।
- आ. मै. ठाकुर इलेक्ट्रीकल्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड; इलेक्ट्रीकल सेंटर; स्टर्डी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड; जीटीएल लिमिटेड; महाराष्ट्र कंडक्टर एसोसिएशन (एसएसआई)
- क. उन्होंने रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का मजबूती से विरोध किया है क्यों कि प्राथमिक निर्माता रक्षोपाय शुल्क के परिमाण में घरेलू बाजार में एल्यूमिनियम सिल्लियों की कीमतों में वृद्धि कर फायदा उठाएंगे।
- ख. पिछले फरवरी, 2016 के बजट में सरकार ने एल्यूमिनियम पर आयात ड्यूटी पहले से ही 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दी है। सीमा शुल्क ड्यूटी में वृद्धि के बाद एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों ने अपने पूरे उत्पादों की मूल कीमत में वृद्धि कर दी है।
- ग. तैयार माल जैसे कंडक्टर केवल पर सीमा शुल्क ड्यूटी अपरिवर्तित रखी गई है। उद्योग पहले से ही कड़ी आयात प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। यदि आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की अनुमति दी गई तो लधु उद्योगों को तैयार माल के आयातों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।
- घ. अग्रिम लाइसेंसों के सामने आयात के अलावा बहुत ही सीमित मात्रा में आयातित एल्यूमिनियम सिल्लियां हैं।
- ड. प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्माता प्रत्येक माह में अपने माल का 25-35% निर्यात कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- च. रक्षोपाय शुल्क की एवं सीमा शुल्क ड्यूटी की प्रचलित दर जो भी हो, प्राथमिक निर्माता तदनुसार आयात समता फॉर्मूला के अनुसार कीमतें बढ़ा देंगे। भार अंततोगत्वा सरकार विशेष रूप से इलेक्ट्रीकल सेक्टर पर आएगा। संरचनात्मक प्रोजेक्ट्स की लागत भी प्रबलता से बढ़ेगी क्यों कि 40% हिस्सा एल्यूमिनियम का है। एसएमई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा और एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों के दोहन से रुग्ण हो सकता है।
- मै. स्टर्डी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिए गए अतिरिक्त बिंदू**
- छ. भारतीय निर्माताओं ने उत्पादक संघ बनाया है और अपने उत्पादन आउट पुट एवं माल के निर्यात में कमी की है। एल्यूमिनियम का कच्चा माल नालको/बाल्को से ही अग्रिम भुगतन कर खरीदना पड़ता है जबकि अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता उधार देते हैं।
- ज. कुछ विशेष श्रेणियां सिर्फ आयातित हैं।
- झ. निर्यात आधारित इकाइयां केवल आयात के आधार पर ही बनी रह सकती हैं अन्यथा वे समाप्त हो जाएंगी। एल्यूमिनियम गौण उत्पादों जैसे केबल्स, कंडक्टर्स एवं रोड्स का निर्यात बेहद तेजी से कम जाएगा।

### **महाराष्ट्र कंडक्टर एसोसिएशन (एसएसआई) द्वारा दिए गए अतिरिक्त बिंदू**

- ज. इन उपायों का मुद्रास्फीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एल्यूमिनियम विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होता है।

**इ. मै. सूपर टेक फॉरजिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**

- क. भारत में एल्यूमिनियम की कीमतें आयात कीमतों के सममूल्य पर हैं। यदि आयात कीमतों में वृद्धि होती है तो घरेलू एल्यूमिनियम उत्पादक भी कीमतें बढ़ा देंगे और इससे अंत उपयोगकर्ता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- ख. सभी स्टेट डिस्कॉम, पॉवर यूटीलीटिज एल्यूमिनियम उत्पादों के मुख्य उपयोगकर्ता हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर एल्यूमिनियम उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ड्यूटी का भार उनके उद्योग पर प्रत्यक्षत और पॉवर सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अप्रत्यक्षतः पड़ेगा।
- ग. उनके, एसएसआई यूनिट्स के पास बहुत सीमित संसाधन हैं और 90% निधियों का प्रयोग एल्यूमिनियम की खरीद पर होता है। कीमतों में वृद्धि के कारण उनकी उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी।
- ई. मै. जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड**
- क. वे भारत में एल्यूमिनियम एक्स्ट्रूजन के मुख्य उत्पादक हैं और एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पादों के भी उत्पादक हैं। उनका मुख्य कच्चा माल एल्यूमिनियम की सिलिंयर्स है जो कि भारत में प्राथमिक उत्पादकों से ली जाती है। वे आयातित मात्रा के अंगेस्ट पात्रता के अनुसार अग्रिम लाइसेंस के अधीन भी आयात करते हैं।
- ख. यह आरोप कि आयातित माल सस्ता है, पूर्णतः गलत है। एल्यूमिनियम की घरेलू कीमतें अनुचित रूप से उंची और अंतरराष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा हैं क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों का कीमत निर्धारण तंत्र पक्षपातपूर्ण है और इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये उद्योग में विद्यमान एकाधिकारी स्थिति का लाभ उठाकर प्रयोगकर्ता उद्योग का शोषण करता है। एल्यूमिनियम पूरी दुनिया में एक समान संदर्भ जो कि लंदन मैटल एक्सचेंज (एलएमई) है, पर व्यापारित किया जाता है। भारत में, प्राथमिक उत्पादक अपनी कीमतों को विद्यमान (एलएमई दर + में जेपनिज पोर्ट (एमजेपी प्रीमियम+ सीमा शुल्क ड्यूटी)  $\times$  विनिमय दर + किलोरिंग एवं फॉरवार्डिंग प्रभार के आधार पर समायोजित कर लेते हैं। इस तरह यूएस डॉलर में व्युतपन्न लागत का मूल्य निर्धारण उच्चतम विनिमय दर पर होता है। हालांकि वे एमजेपी और सीमा शुल्क ड्यूटी दोनों को अपने ऊपर नहीं लेते, ये उनके लिए एक अतिरिक्त लाभ है। यदि किसी स्थिति में इन में किसी घटक में परिवर्तन होता है तो प्रयोगकर्ता उद्योग के लिए एल्यूमिनियम की घरेलू कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भारतीय ग्राहक के लिए आयातित माल के उत्तराने तक की लागत याचिकाकर्ताओं के लिए स्थानीय रूप से विक्रय किए गए माल की लागत के समान होगी।
- ग. हालिया यूनियन बजट में सीमा शुल्क ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गई थी और आयात पहले से ही लगभग 3% महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी ने पहले से ही बहुत दबाव डाल दिया है, क्योंकि इसके तुरंत बाद देश के सभी प्राथमिक उत्पादकों ने कीमतें रुपये 3500/- एमटी तक बढ़ा दी थी। सीमा शुल्क ड्यूटी में वृद्धि के कारण भारत में प्रयोगकर्ता के लिए एल्यूमिनियम की कीमतों में वृद्धि हो गई और आयातित एवं स्थानीय धातु के मध्य समता अपरिवर्तित रही।
- घ. अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से आयात को नियंत्रित करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने पर डीआई घरेलू कीमतें बढ़ा देंगे और स्थानीय कीमतों और आयात कीमतों के मध्य समता पुनः वही रहेगी। रक्षोपाय शुल्क भारतीय प्रयोगकर्ता के लिए एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ा देगी। आयात ज्यों का त्यों रहेगा।
- ङ. यदि याचिकाकर्ता वास्तव में आयात बंद/कम करना चाहते हैं तो उनको अपने उत्पादों की कीमतें आयातित माल की तुलना में कम रखनी पड़ेगी। उनके पास ऐसा करने के और उचित लाभ कमाने के बहुत अवसर हैं।
- च. घरेलू उत्पादक लगभग प्रत्येक दूसरे वर्ष अथवा 2/3 वर्ष में अपनी संस्थापित क्षमता में लगातार विस्तार/वृद्धि कर रहे हैं।
- छ. क्यों कि देश में एल्यूमिनियम का मुख्य कच्चा माल अर्थात बॉक्साइट अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एल्यूमिनियम के उत्पादन की लागत भारत में अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम मानी जाती है।

- ज. घरेलू बाजार में कीमतों की तुलना करने पर, भारत में प्राथमिक धातु/एल्यूमिनियम के उत्पादक अंतरराष्ट्रीय कीमतों (बाजार में विद्यमान एलएमई) पर सीमा शुल्क ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, उपकर, इंश्योरेंस क्लियरिंग चार्जेस आदि के माध्यम से आयातित एल्यूमिनियम की माल उतारने तक की लागत की तुलना में 10% से अधिक के अतिरिक्त विशेषाधिकार का लाभ ले रहे हैं।
- झ. याचिकाकर्ता भारतीय रूपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर से संबंधित मूल्यहास से अपनी प्राप्ति भारतीय रूपये में होने कारण पहले ही लाभांवित हो चुके हैं। तगभग एक वर्ष पूर्व, एक अमेरिकी डॉलर = 62 रूपये था और वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर = 67 रूपये है। 2011 में, एक अमेरिकी डॉलर की दर @44.50 रूपये थी जो अब मूल्यहासित होकर 66.50 रूपये हो गई है। अर्थात् 2011 में एलएमई कीमत 1500 अमेरिकी डॉलर प्रति टन मानी जाए जिसकी प्राप्ति भारतीय रूपये में 66,750/- प्रति टन होती जो की आज भारतीय रूपये में 99,750/- होती – मतलब केवल विनिमय अस्थिरता के कारण रूपये 33,000/- का लाभ।
- ञ. एलएमई कीमतें स्वयं ही अमेरिकी डॉलर 1500 के स्तर से बढ़कर अमेरिकी डॉलर 1670 हो गई है जो घरेलू उत्पादकों को अत्यधिक ऊंची प्राप्ति दे रहा है।
- ट. डीआई ने गलत विवरण देने के लिए वर्ष 2011-12 का चयन किया है। 2011-12 में एल्यूमिनियम की कीमतें अपने चरम पर 2317 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन थी जो की तुलना में 2015-16 में 1562 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन थी। एल्यूमिनियम किसी भी अन्य वस्तु की तरह अस्थिर एवं उतार-चढ़ाव प्रवण है। वर्तमान में एल्यूमिनियम की कीमतें कम हैं परंतु यह एक व्यवसाय-चक्र है एवं घरेलू उद्योग को स्थिति को अपनी कीमतें कर कर एवं अपनी परिचालन दक्षताओं को बढ़ाकर संभालना चाहिए। आधार-वर्ष 2007-08 लिया जाना चाहिए जब स्थिति अब विद्यमान स्थिति के समान थी और उस समय कोई रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया था।
- ठ. डीआई की पिछली याचिका महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा अक्तूबर, 2014 में अस्वीकार कर दी गई थी, आज की स्थिति में तब की तुलना कोई बदलाव नहीं आया है और अस्वीकार किए जाने कारण अब भी प्रयोज्य हैं। जब कभी धातु की कीमतें घटती हैं जैसे 2009 एवं 2014 में हुआ था, वे रक्षोपाय का अनुरोध करते हैं।
- ड. आवेदकों का विशाल क्षति का दावा बिल्कुल गलत है। याचिकाकर्ता अधोमुखी उत्पाद जैसे उत्सारण, रोल्ड उत्पाद, बिलेट्स, वायर रोड्स, अलॉय सिलिंग्स आदि जो की उनकी उत्पादन/गलाने की क्षमता का भी हिस्सा हैं, पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये उत्पाद हॉट एल्यूमिनियम धातु से बने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, वे अपनी क्षमता का 100% प्रयोग कर पा रहे हैं।
- ढ. उनकी बदतर होती वित्तीय स्थिति का वास्तविक कारण मूल्यहास की बढ़ती घटनाएं एवं आरंभ की गई उत्पादन क्षमताओं में बढ़ोत्तरि के लिए किए गए भारी निवेश का ब्याज है।
- ण. याचिकाकर्ता अपनी वर्तमान क्षमताओं में और अधिक विस्तार के लिए या ग्रीनफिल्ड परियाजनाओं को योजना बनाने के लिए विशाल निवेश जारी रखे हुए हैं।
- त. डीआई की निवेश योजनाएं उनके द्वारा प्रक्षेपित स्थिति के पूर्णतः विरोधाभासी हैं। वेदांता उड़ीसा में अपने एल्यूमिनियम स्मेलटरों में उत्पादन 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन करने के लिए तैयारी कर रहा है और कोरबा में दूसरे स्मेलटर में निवेश कर रहा है। क्षमता में वृद्धि का निर्णय और नई क्षमताओं की योजना बनाना भी इसकी पुष्टि करता है कि चालू मंद स्थिति एक अस्थायी घटना है।
- थ. प्राथमिक उत्पादकों को अपने लाभ को बढ़ाने के लिए पहले अपने अधोमुखी उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी।
- द. इस कदम से भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्यों कि तैयार एल्यूमिनियम उत्पादों का आयात बढ़ जाएगा।
- ध. इससे प्राथमिक उत्पादकों को धातु की कीमतों में वृद्धि करने की छूट मिल जाएगी।

- न. वर्ष 2015-16 में डीआई ने विशाल लाभ कमाया है। शायद वेदांता एवं बाल्को को कुछ नुकसान हुआ है, परंतु यह एल्यूमिनियम की कीमतों के कारण नहीं बल्कि उनको सरकार द्वारा बॉक्साइट खानों को आबंटित न किए जाने के कारण है। उन्होंने बिना कच्चे माल अर्थात् बॉक्साइट जिसके बगैर वे अपना संयत्र नहीं चला पाते, की व्यवस्था किए भारी निवेश कर दिया और वे मूल्यहास और ब्याज को वहन करते हुए निष्क्रिय पड़े हुए हैं और यह उनके नुकसान का मुख्य कारण है। ब्याज और मूल्यहास की बढ़ती घटनाओं के कारण हिंडाल्को का लाभ कम हुआ है क्यों कि पिछले दो वर्ष में उनको 10.5 लाख टन एल्यूमिनियम की वर्धित क्षमता प्राप्त हुई है जिसमें विशाल निवेश सम्बद्ध है। यदि उनके तुलन-पत्र से मूल्यहास और ब्याज निकाल दिया जाए तो उनको बड़ा लाभ होगा।
- प. भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के मामले में कोई भी क्षति कारक लागू नहीं होता है। न तो किसी आवेदक की उत्पादन में कमी आई है और न ही उनको नुकसान हुआ है और न ही श्रम-शक्ति में छंटनी हुई है।
- फ. लगभग सभी उत्पादक अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। सभी उत्पादकों का उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। उनका क्षमता उपयोग 90% से अधिक है।
- ब. उनकी क्षमता उपयोग पर विचार करते समय उनके कुल उत्पादन में उनके अधोमुखी उत्पाद जैसे उत्सारण, रोल्ड उत्पाद, बिलेट्स, वायर रोड्स, स्लैब्स, अलॉय सिलिंग्स आदि की उत्पादन मात्रा को भी ध्यान रखना होगा।
- भ. अपने लाभ बढ़ाने के लिए हिंडाल्को ने पिछले 2 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता में लगभग 10.5 लाख टन की वृद्धि कर ली है, वेदांता ने अपनी उत्पादन क्षमता में 5 लाख टन से 7.5 लाख टन की वृद्धि कर ली है, बाल्को ने 2 लाख टन से 3.5 लाख टन की वृद्धि कर ली है।
- म. क्योंकि वर्ष के अंत में डीआई के पास लगभग निल इंवेंटरी है, अतः उनको कोई क्षति नहीं हुई है और वे उसी वर्ष के दौरान अपने पूरे उत्पादन को बाजार भाव पर बेच पाए हैं।
- य. हालांकि आयातों में वृद्धि हुई है परंतु उसी समय के दौरान एल्यूमिनियम धातु के घरेलू विक्रय में वृद्धि हुई है जो कि आयात से कहीं अधिक है। क्योंकि डीआई अपनी वर्धित उत्पादन को भी बेच पाए हैं, अतः उनको क्षति नहीं हो सकती।
- कक. जो भी मात्रा आयात की जा रही है वह मुख्यतः प्रयोगकर्ता उद्योग द्वारा अग्रिम लाइसेंस के अंगेस्ट आयात की जा रही है।
- खख. इस कदम से बहुत से अधोमुखी निर्माताओं जो कि अपने अस्तित्व के लिए एल्यूमिनियम उत्पादकों पर निर्भर हैं, को गंभीर क्षति होगी और इससे मध्यम और छोटी इकाइयां बीमार हो जाएंगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी और अंततः आम जनता के लिए एल्यूमिनियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
- गग. एलएमई कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं। 6 माह पूर्व एलएमई कीमतें प्रति मीट्रिक टन 1450 अमेरिकन डॉलर थी और वर्तमान में पहले ही 1675 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन को छू चुकी है।
- घघ. यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया, अधोमुखी उत्पाद जैसे उत्सारण, रोल्ड उत्पाद, वर्तन, केवल्स, कंडक्टर्स आदि का आयात बढ़ जाएगा चुंकि एल्यूमिनियम सिलिंग्स के आयात की तुलना में इन वस्तुओं का आयात सस्ता हो जाएगा। इससे हजारों उद्योग बंद होने पर बाध्य हो जाएंगे और लाखों कर्मचारियों अपनी नौकरियां खो देंगे।
- डड. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया तो एल्यूमिनियम धातु की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी।
- चच. भारत में एल्यूमिनियम की उत्पादन लागत विश्व में न्यूनतम है; डीआई को वाजिब लाभ हो रहा है और उनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।

- छद्द. पूरे विश्व में प्राथमिक एल्यूमिनियम कंपनियों ने ऐसी ही कठिन स्थितियों का सामना किया है।
- जज. उत्पादन और संस्थापित क्षमता से संबंधित डाटा तथ्यात्मक रूप से गलत/झूठा है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर विचार आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद के हिस्से के लिए गुमराह करने के इरादे से किया गया है। आवेदकों ने पीयूसी के रूप में चयनात्मक रूप से सिर्फ एचएस कोड 7601 पर विचार किया है जबकि वे रोल्ड उत्पाद, फॉयल्स, उत्सारण का भी उत्पादन करते हैं और इन उत्पादों के लिए अपनी स्मेलटिंग क्षमता के अधिकांश का प्रयोग कर रहे हैं।
- झझ. क्षमता उपयोग की गणना हॉट धातु उत्पाद की मात्रा के आधार पर होनी चाहिए और क्षमता उपयोग के सही आंकड़ों पर पहुंचने के लिए सिर्फ सिल्लियों की मात्रा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- जज. प्राथमिक उत्पादकों ने पहले और लाभ कमाने के लिए अपने अधोमुखी उत्पादों जैसे एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पाद, फॉयल्स और उत्सारण आदि के उत्पादन को बढ़ाने प्राथमिकता दी है। अतः वर्धित आयात के कारण उनको कोई “क्षति” नहीं हुई है। क्योंकि आवेदकों द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं को सिल्लियों की बहुत कम मात्रा उपलब्ध कराई गई है, अतः वे आयात ज्यादा करने के लिए बाध्य हो गए हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह के पहले 10-12 दिन धातु की कमी का सामना करना पड़ेगा।
- टत. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन दावे के अनुसार घटा नहीं है बल्कि वास्तव में बढ़ा है, । उनमें से अधिकांश संस्थापित क्षमता के 100% के आस-पास पर परिचालन कर रहे हैं एवं “गंभीर क्षति” का कोई आधार नहीं है।
- ठठ. महानिदेशक, रक्षोपाय को याचिका में दिए गए उत्पादन और क्षमता उपयोग की सटीकता की जांच के लिए याचिकाकर्ताओं के उत्पादन रिकॉर्ड का अन्वेषण करना चाहिए।
- डड. याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई संस्थापित क्षमता पूरी तरह से परिचालित नहीं है। वेदांता का एसईजेड झारसुगुडा का 1.25 मिलियन टन का स्मेलटिंग संयंत्र पॉवर और एल्यूमिना मुद्दों के कारण पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है।
- ढढ. नाल्को जो कि उद्योग में एक अग्रणी उत्पादक है, इस याचिका में शामिल नहीं है।
- णण. उस स्थिति में जहां, किसी वस्तु का मूल्य पूरे विश्व में यूनिफार्म है, वहां क्रेता कहीं से भी अपनी जरूरत आवश्यकतानुसार पूरी करने हेतु स्वतंत्र है।
- तत. जब कभी भी एल एम ई मूल्यों में अथवा विदेशी विनियम दरों में सुधार होता है तो आवेदकों द्वारा भी मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं हालांकि उनकी लागत वही रहती है।
- थथ. एल एम ई मूल्यों में इस वृद्धि ने डी आई को पहले ही पर्याप्त लाभ दिया है।
- दद. आवेदकों ने गिरते प्रीमियम के बारे में शिकायत की है जिसने उनके प्रापण को प्रभावित किया है परंतु सच्चाई यह है कि प्रीमियम, जो कि अपर्याप्त रूप से ऊपर उठा, वह अपने सामान्य स्तर तक धीरे-धीरे आ गया। यद्यपि प्राइमरी धातु भारत में उत्पादित की जाती है परंतु विक्रय दरों तक पहुंचने हेतु एल एम ई मूल्यों में इस प्रीमियम को जोड़ा जाता है हालांकि विनिर्माण लागत से इसका कोई संबंध नहीं है।
- धध. मुख्य उत्पादकों की लाभप्रदता मध्य पूर्व उत्पादकों के साथ तुलनीय है।
- नन. आवेदकों ने कम प्रापण एवं आयात में अचानक वृद्धि के कारण उनकी लाभप्रदता में अचानक कमी की शिकायत की है जिसके कारण कम उपयोग क्षमता में वृद्धि हुई।
- पप. हिंडाल्को ”मूल्यहास, व्याज एवं कर” से पूर्व उचित लाभ कमा रहा है एवं अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। हिंडाल्को के मामले में कम लाभ का वास्तविक कारण कमी में वृद्धि एवं क्षमता में अत्यधिक

- विस्तार के कारण 2011-2012 के पश्चात् 178% तक व्याज में वृद्धि है। कम्पनी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उनके नए शुरू किए गए महन स्मेल्टर एवं आदित्य स्मेल्टर पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहे हैं।
- फफ.** वेदांता के मामले में, केवल अलमूलियम सेगमेंट में लगाए गए केपिटल क्षमता में वृद्धि करते हुए 234% तक बढ़े जिसने स्पष्ट रूप से उनके मूल्यहास एवं व्याज को बढ़ाया।
- बब.** कम एल एम ई मूल्यों के कारण 11 महीने पहले बंद की गई अपनी रोलिंग मशीनों को बाल्को ने पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। जहाँ तक मूल्यों का मामला है इससे स्थिति सुधार दिखाई देता है कि स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जैसी कि दर्शाई जा रही है।
- भभ.** नाल्को, जिसने तरीके से एवं अनुशासित विस्तारण कौशल से तरक्की की है, आयात से प्रभावी नहीं हुआ है एवं उचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- मम.** उत्पादन में कमी के कारण किसी भी उत्पादक ने विगत दो दशकों में अपने किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं है।
- यय.** एल्युमिनियम धातु की मांग में प्रतिवर्ष 8-10% की दर से वृद्धि हो रही है एवं डी आई का उत्पादन भी बढ़ रहा है। उनके रोजगार के स्तर में भी वृद्धि हो रही है जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पुष्ट होता है।
- ककक.** मध्य पूर्व में उत्पादन की लागत एवं उनके मूल्य कम नहीं है, जैसा कि दावा किया गया है। वे बहुत ही उच्च लागत पर अल्मुना का आयात करते हैं एवं मैनपावर लगाते हैं जो कि एल्युमिनियम के विनिर्माण में मुख्य लागत तत्व हैं। भारत में मुख्य उत्पादक के पास बेहतर गुणवत्ता में से एक स्थानीय बाक्साइट का प्राकर्तिक लाभ है। मध्य पूर्व के आपूर्तिकर्ता भी एल एम ई के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर अपने विक्रय मूल्य निर्धारित कर रहे हैं जैसा कि भारतीय उत्पादकों द्वारा किया जाता है।
- खखख.** धीमी एवं कमजोर बाजार स्थिति एल्युमिनियम सेगमेंट में सभी यूनिटों को प्रभावित करती है चाहे यह मुख्य उत्पादक हों अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग हो। इसने चीन को भी प्रभावित किया है।
- गगग.** द्वितीय एल्युमिनियम विनिर्माताओं एवं प्रोसेसर्स द्वारा भारत में एल्युमिनियम का आयात उनकी निर्यात हक्कारी के विपरीत है। उपभोक्ता उद्योग को उनके अग्रिम लाइसेंस पर आयात के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि आवेदक इन लाइसेंसों पर एल्युमिनियम की आपूर्ति नहीं करना चाहते हैं एवं आयात की तुलना में अधिक उच्च मूल्य उद्धृत करते हैं।
- घघघ.** डी आई को क्षति नहीं हो सकती क्योंकि आयात में वृद्धि कम है।
- डडड.** मूल्य में कमी : गैर अलॉय धातु एवं अलॉय धातु समरूप उत्पाद नहीं है। अलॉय धातुओं को उच्च मूल्य पर बेचा जाता है एवं इन्हें तुलना के प्रयोजन हेतु नहीं लिया जाना चाहिए। अलॉय धातुओं का विनिर्माण आवेदकों द्वारा नहीं किया जाता है एवं इन्हें कुल आयात में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- चचच.** पिछले चार वर्षों में आयात में 78% की मार्जिनल वृद्धि है जो ज्यादा नहीं है। आवेदकों का अपना उत्पादन भी 76% तक बढ़ा है उनकी घरेलू विक्री 40% तक बढ़ी है एवं निर्यात 336% तक बढ़ा है।
- छछछ.रक्षोपाय ड्यूटी** के अधिरोपण की मांग स्थानीय मूल्यों को बढ़ाने के जरिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की मंशा से है।
- जजज.** आवेदकों ने चीन से वर्धित आयात का दावा किया है लेकिन चीन से आयात 2015-16 में केवल 2.68% था।
- झझझ.** उत्पादन से संबंधित प्रस्तुत किए गए आंकड़े गलत हैं। हॉट धातु का उत्पादन एवं प्रेषित मात्रा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर अंतिम वस्तुओं का स्टॉक, उत्पादन क्षमता, विनिर्माण की लागत एवं विक्रय

- मूल्य/कुल प्रापण एवं एल एम ई मूल्य – प्रीमियम को सत्यापित किया जा सकता है। डी आई के कुल उत्पादन को कुल आयात से तुलना की जा सकती है।
- बजज. आवेदक विभिन्न कारणों हेतु एक पूर्व नियोजित दूरगामी रणनीति के अधीन निर्यात कर रहे हैं एवं अपनी इंवेटरी को लिक्रिडेट करने हेतु निर्यात के लिए बाध्य नहीं है। आयात में उन्होंने बेहतर प्रगति की है क्योंकि वे निर्यात लाभ, जैसे एम ई आई एस के साथ-2 ई पी सी जी बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं। हिंडाल्को अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग अपने सहयोगी कम्पनी नोवेलिस को ट्रांसफर करता है। भारतीय विर्निमाताओं की विद्यमान क्षमता घरेलू मांग से बहुत अधिक है।
- टटट. आवेदकों ने बहुत से महत्वपूर्ण ऑकडे दिए नहीं हैं अथवा गोपनीयता के नाम पर इंडेक्सड ऑकडे दिए गए हैं। वित्तीय स्थिति का 2011-12 के आंकड़ों के साथ इंडेक्स किया गया है जिसे बेंचमार्क नहीं माना जा सकता।
- ठठठ. आरंभिक एवं अंतिम स्टॉक एवं विक्रय की लागत को प्रभावित पक्षों को भ्रमित करने हेतु इंडेक्स किया गया है।
- डडड. आवेदकों ने 47%-48% की क्षमता उपयोगिता का दावा किया है। कैप्टिव उपभोग की मात्रा को शामिल करना 2014-15 में 64.8% एवं 2015-16 में 63.7% का क्षमता उपयोग है। आवेदकों की वास्तविक क्षमता उपयोगिता का निर्धारण करने हेतु एक सघन जांच की जानी चाहिए।
- ढढढ. आवेदकों ने स्वयं रोजगार एवं उत्पादकता में वृद्धि का दावा किया है।
- णणण. उधोग, जिसने वेतन 150% तक बढ़ाए, अतिरिक्त कर्मचारियों को हायर किया, के पास कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है, को आशंका के अधीन नहीं माना जा सकता है।
- ततत. गुमराह करने हेतु वर्ष 2011-12 को बेंचमार्क बनाने के माध्यम से वित्तीय स्थिति को कमजोर प्रवर्ति के रूप में दर्शाया गया है। डी आई की लाभप्रदता वर्ष 2011-12 के संबंध में वैश्विक मंदी के कारण थोड़ी सी प्रभावित हुई है एवं इसका आयात से कोई संबंध नहीं है।
- थथथ. नीचे के उधोग कम मांग, उभरती ब्याज लागत, रूपए की मांग में कमी एवं वैश्विक मंदी तथा कम होते लाभ के कारण एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं।
- ददद. सभी उत्पादक उनके द्वारा उत्पादित धातु की पूर्ण मात्रा को एक वर्ष तक विक्री करने में सक्षम है।
- धधध. रक्षोपाय शुल्क अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु काउंटर प्राडक्टिव होगी, सभी एल्युमिनियम उत्पादों की लागत बढ़ाएगी, एल्युमिनियम धातु का आयात नहीं रोकेगी, द्वितीय पदार्थ जैसे एक्सट्रॉशन, रोल्ड उत्पाद, फॉइल्स आदि का आयात बढ़ाएगी।
- ननन. नाल्को, जो कि देश में एल्युमिनियम धातु के अग्रणी विर्निमाता है, के वित्तीय परिणामों के बारे में एल्युमिनियम एशोसियन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक खबर के अनुसार नाल्को ने मार्केट गिरावट को सफलतापूर्वक हैंडल करके लाभ प्राप्त किया है, एवं पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में 14% अधिक उत्पादन प्राप्त किया है।
- पपप. हिंडाल्को ने इसके मुख्यतया एल्युमिनियम व्यापार से प्राप्त किए गए स्ट्रांग मार्च तिमाही के परिणाम पोस्ट किए हैं। कम्पनी का क्षमता विस्तार किया गया है एवं कुछ वर्षों के पश्चात फ्री कैश फ्लो-पाजिटिव हो जाएगा। आयकर से पूर्व इसकी आमदनी पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा थी। उन्होंने अपना अब तक का सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त किया है एवं उनके संयंत्र पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। मूल्यहास एवं वित्तीय लागत में 30% तक वृद्धि के कारण लाभ नीचे चला गया है। वित्तीय वर्ष 2016 की चौथी तिमाही की तुलना में 113% अधिक था। वित्तीय वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी

तिमाही में पी वी आई टी ए 49% अधिक था। टैक्स डिपाजिट लो एल एम ई प्राइस के पश्चात मै. हिन्डालको को ₹0 607 करोड़ का कुल लाभ प्राप्त किया है।

**ड. मै. इंडो एलुसिस इंडस्ट्रीज लि0**

- क. वे एल्युमिनियम प्रोफाइल्स के एक्सट्राईवर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं।
- ख. एल्युमिनियम के द्वितीय विनिर्याताओं, जो कि पूर्ण रूप से उन पर निर्भर है, एवं वनरेबल एवं वोलाटाइल मार्केट स्थितियों में अपने सर्वाइल हेतु संघर्ष कर रहे हैं, के सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए सेल्फमोटिव के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- ग. बहुत सी एल्युमिनियम यूनिटों हेतु यह उपाय सिक्नेस का एक कारण बन जाएगा एवं उपभोक्ताओं हेतु एल्युमिनियम उत्पाद मंहगे हो जाएंगे जिसके कारण बेरोजगारी एवं स्क्रिति बढ़ेगी।

**च. मै. पैरागान इंडस्ट्रीज लि0**

- क. वे एल्युमिनियम रोल्ड उत्पादों, जिसमें एल्युमिनियम फॉइल्स शामिल हैं, के विनिर्माता हैं।
- ख. किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ड्यूटी एल्युमिनियम के सभी निचले विनिर्माताओं को गंभीर क्षति पहुंचाएगी एवं जिसके कारण बहुत से छोटे एवं मध्यम एल्युमिनियम यूनिट बंद हो जाएंगे।
- ग. इससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी एवं देश में अधिक से अधिक आयात को आगे बढ़ाएगी।

**छ. मै. ओपल इंडस्ट्रीज**

- क. कृत्रिम कमी पैदा करते हुए आयात मूल्य की तुलना में अनरॉट एल्युमिनियम उत्पादक काफी उच्च मूल्य रख रहे हैं।
- ख. घरेलू मूल्य निर्धारण नियम है एल एम ई मूल्य + आयात ड्यूटी + आयात लागत + उसे 4% /वर्ष 2013, 2014 एवं मध्य 2015 तक प्रीमियम यू एस डी 300 से यू एस डी 450 तक चार्ज किया गया एवं उन्होंने भारी लाभ कमाया।
- ग. अब एल एम ई अधिक हैं एवं आयात ड्यूटी 7.5% है। 2015 की तुलना में अनरॉट एल्युमिनियम के मूल्य 13% तक बढ़ा दिए गए हैं।
- घ. डी आई अनरॉट एल्युमिनियम को उत्पादन लागत से अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं तथा घरेलू मूल्य से 18% सस्ते मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं।

**ज. मै. केबल एंड कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स एशोसियसन ऑफ इंडिया**

- क. मुख्यतः वे भारत में छोटे एवं मध्यम दर्जे के उधोग, जो कि पावर ट्रांसमिशन हेतु केबल एवं कंडक्टरर्स, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु विनिर्माण में लगे हैं, का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ख. प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों द्वारा शुल्क सुरक्षा का आवेदन फाइल किया गया था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने के कारण मै. नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि0 (नाल्को) ने आवेदन को ज्वाइन नहीं किया है।
- ग. आवेदन फरवरी, 2016 में फाइल किया गया था एवं इसे 19 अप्रैल, 2016 को अपडेट एवं फाइल किया गया। बिना उपभोक्ता उधोग को सुने आवेदन में पुनरीक्षण के कुछ दिनों के अंदर 5% रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति दी गई थी हॉलाकि दो अवसरों पर पूर्व में आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।
- घ. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े सत्यता से कहीं दूर हैं एवं संस्तुति हेतु कठोर निर्णय लेने हेतु विश्वसनीय नहीं हैं।

- इ. पिछले यूनियन बजट में 2.5% अधिक की सीमा शुल्क छूटी का उपभोक्ता उधोग ने पहले ही सामना किया है जिसने निचले एल्युमिनियम उपभोक्ताओं, विशेषकर उनके सदस्य जिन्होंने लॉग टर्म फर्म प्राइस आधार पर स्टेट इलेक्ट्रोसिटी एवं पी जी सी आई एल से आर्डर बुक किए हैं, पर दबाव डाला है। टैरिफ आधारित बिडिंग ऐक्टिस, जो ट्रांसमिशन लाइनों हेतु अपनाई जानी है, के कारण वृद्धि को पास नहीं किया जा सकता है।
- च. यू एस डॉलर की तुलना में भारतीय रूपये में गिरावट से भी आवेदकों को लाभ हो रहा है। लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रति यू एस डॉलर की विनिमय दर 50 रूपए थी एवं अब यह विनिमय दर प्रति यू एस डॉलर 67 रु0 है। तीन वर्ष पूर्व 1600 यू एस डी प्रतिटन की एल एम ई मूल्य = 80,000 रु0, 107,200/मी.टन प्राप्त करेगी जो रु0 27,200/मी.टन के एफटर गेन को प्रदर्शित नहीं करती।
- छ. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्युमिनियम एल एम ई के संदर्भानुसार निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। अतः कम कीमतों पर घरेलू उधोग द्वारा किया गया आयात का तर्क आधारहीन है।
- ज. चीन एवं मध्य पूर्व देशों को बैक्साइट ( bauxite ) अथवा एल्युमिनियम एवं कोयला (प्रारंभिक एल्युमिनियम बनाने हेतु मूल कच्चा माल) अपने देश में साधन न होने कारण आयात करना होता है, की तुलना में घरेलू स्मेल्टर्स/आवेदकों के डिस्पोजल पर भारत में काफी साधन उल्ब्ध है।
- झ. भारत की तुलना में चीन एवं मध्य पूर्व देशों में वेतन ढांचा 40% तक अधिक है एवं इसके बावजूद चीन एवं मध्य पूर्व देशों में आपूर्तिकर्ताएल एम ई इंडेक्स के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर एल्युमिनियम धातु के अपने मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। उनके मूल्य कम नहीं हैं जैसा कि आवेदन में आरोप लगाया गया है। भारत में आयातकों को आयात के पत्तन पर सीमा शुल्क छूटी एवं निकासी प्रभार का भुगतान करना होता है।
- ञ. कंडक्टर विनिमाता भी इन्वर्टिड छूटी स्ट्रक्चर मुद्रे का सामना कर रहे हैं। तैयार कंडक्टर चेप्टर 98 के अधीन प्रोजेक्ट आयात के आधार आयात हेतु पात्र हैं जहां मूल सीमा शुल्क छूटी कंडक्टर/केबल पर शुल्क की मेरिट दर के बजाए 5% है। उधोग एल आई आधार पर काट्रेक्ट हेतु पात्र हो रहा है। प्रोजेक्ट आयात के अधीन समद्र पार प्रतिस्पर्धा इन्वर्टिड शुल्क का लाभ प्राप्त करते हैं एवं एल आई स्टेटस क्वालीफाई कर लेते हैं और घरेलू कंडक्टर विनिमाताओं को अनदेखे लेबल प्लेटिंग फील्ड पर वंचित कर देते हैं। 7.5% सीमा शुल्क छूटी की दर प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु स्वयं में एक चैलेंज है जिसका सामना करना है।
- ट. यदि अतिरिक्त 5% रक्षोपाय शुल्क का भार अधिरोपित किया जाता है तो यह घरेलू कंडक्टर उधोग को सामप्त कर देगा एवं चीन एवं अन्य देशों कंडक्टर एवं केबल की बाढ आनी शुरू हो जाएगी।
- ठ. आवेदक सीमा शुल्क छूटी को अपनी जेब में रख रहे हैं एवं यदि कोई अतिरिक्त शुल्क सुरक्षा दी जाती है तो यह भी उनके पास ही जाएगा।
- ड. अंतर्राष्ट्रीय मूल्य एवं घरेलू स्मेल्टर्स के बिक्री मूल्य दर्शाते हैं कि कुल प्राप्त वैल्य, जिसमें सीमा शुल्क छूटी एवं अनकंडीशनल डिस्काउंट शामिल हैं, जो भारत में स्मेल्टर्स द्वारा ऑफर किया जा रहा है वह घरेलू स्मेल्टर्स बिक्री मूल्य से कम है।
- ढ. डी जी रक्षोपाय द्वारा की गई कार्यवाही प्राकर्तिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। डी जी रक्षोपाय ने आवश्यक अवधि के बीत जाने का भी इंतजार नहीं किया एवं जल्दी में अपने प्रारंभिक निष्कर्ष जारी कर दिए। इससे जांच की क्रिटिकल स्टेज पर पार्टीसिपेट करने हेतु इच्छुक पक्षों को अधिकारों से वंचित कर दिया।

- ण. महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पूर्ण एवं वृहत्त सूचना उपलब्ध नहीं थी जब प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किया गया था।
- त. वर्ष 2009 एवं 2014 में घरेलू उधोग ने अनुचित एवं अनापेक्षित सुरक्षा की मांग की थी एवं कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था। रक्षोपाय शुल्क संस्तुत नहीं किया गया था। आवेदकों की सम्पूर्ण आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।
- थ. महानिदेशक (रक्षोपाय) को जांच की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी एवं प्रारंभिक निष्कर्ष नहीं देना था क्योंकि डी आई द्वारा कोई समायोजन योजना फाइल नहीं की गई थी।
- द. प्रारंभिक निष्कर्ष सार्वजनिक हित के मुद्दे पर खामोश है। अर्थव्यवस्था के मुख्य सेक्टर अर्थात् केबल एवं कंकटकर, आटोमोबाइल, उपभोग योग्य, यूटेन्सिल, पैकेजिंग एवं हाउसिंग सेक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला एल्युमिनियम बहुत एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एल्युमिनियम महंगा करने की कोई भी कार्रवाई निचले उधोगों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगी।
- ध. भारत में कुल एल्युमिनियम का 40% पावर सेक्टर उपयोग करता है। केबल एवं कंडक्शन की कुल लागत के 70% से अधिक एल्युमिनियम होता है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के माध्यम से मूल कच्चे माल की लागत में कोई भी वृद्धि अंतिम उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक एवं इस सेक्टर की व्यवहार्यता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगी। पावर में लागत वृद्धि सभी पर प्रभाव डालेगी। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण 300 से अधिक केबल एवं कंकटकर विनिर्माण इकाइयों, जो लगभग दो लाख कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं, को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगी।
- न. क्योंकि बहुत से निचले उत्पाद का वैल्यू एडिशन बहुत कम है, रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से अंतिम निचले उत्पाद के आयातों में वृद्धि होगी जिससे उधोग बंद हो जाएंगे।

**झ. मै. ग्लोबल एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड**

- क. वे मुख्य एल्युमिनियम निर्यातिक हैं जिनके पास वैल्यू एडिट जैसे एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग एवं सेमी फेब्रिकेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- ख. मुख्य उत्पादकों द्वारा यह आवेदन अप्रत्यक्ष उद्देश्य से फाइल किया गया है जिससे कि वे एल्युमिनियम के बहुत से उन निर्माताओं, जिनकी विद्यमानता इन बड़े स्तर के एल्युमिनियम उत्पादकों पर निर्भर है, को गंभीर क्षति पहुंचाकर अनुचित एवं गलत लाभ कमा सके।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का कोई भी अन्य अधिरोपण बहुत से छोटे एवं मध्यम एल्युमिनियम यूनिटों को खराब कर देगा। बेरोजगारी बढ़ेगी एवं जिससे आम जनता हेतु एल्युमिनियम उत्पाद महंगे होंगे।

**ज. मै. वर्गो एल्युमिनियम लिमिटेड**

- क. वे एल्युमिनियम उत्पादों के विनिर्माता हैं।
- ख. यह उपाय एल्युमिनियम रोल्ड उत्पादों के बहुत से निचले/सहायक विनिर्माताओं को गंभीर क्षति पहुंचाएगा।
- ग. गैर अलाय एल्युमिनियम के लिए वे बड़े स्तर के मुख्य एल्युमिनियम उत्पादकों पर निर्भर हैं।
- घ. वर्तमान बजट में, सरकार ने पहले ही गैर अलाय एल्युमिनियम पर सीमा शुल्क 2.5% तक बढ़ा दिया है।
- ङ. अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क ऊटी लगाने से बहुत सी ऊटी एवं मध्यम एल्युमिनियम इकाईयां बहुत नीचे आ जाएंगी बेरोजगारी बढ़ेगी एवं इससे आम जनता हेतु एल्युमिनियम उत्पादन महंगे होंगे।

**ट. मै. मनाकसिया एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड**

- क. वे एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जिससे बैल्यू एडिड उत्पाद जैसे प्रीपेंटिड एल्युमिनियम का इल्सशामिल है, के सहायक विनिर्माता हैं।
- ख. डी आई का यह आवेदन स्पष्ट रूप से यह प्रयास है कि सहयोगी एल्युमिनियम विनिर्माताओं, जो अपना कच्चा माल उनसे प्राप्त करते हैं, को गंभीर क्षति पहुंचाते हुए अनुचित एवं अपर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सके।
- ग. यह उपाय बहुत से सहायक एल्युमिनियम विनिर्माताओं को बिजनेस से बाहर कर देगा, बेरोजगारी बढ़ेगी एवं एल्युमिनियम कीमतों में अनावश्यक वृद्धि के कारण एल्युमिनियम उत्पादों के उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी होगी।
- घ. सहायक एल्युमिनियम विनिर्माताओं का एल्युमिनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जो भारतीय बाजार में चीन जैसे देशों से बेयर एवं प्री-पेंटिड एल्युमिनियम कॉइल्स के सस्ते आयात की अनुमति देता है, के कारण हानि उठा रहे हैं।
- ङ. वर्तमान में, एल्युमिनियम स्क्रेप 2.5% की मूल सीमा शुल्क छूटी के अध्यधीन है जो पहले शून्य प्रतिशत थी। इससे सहायक विनिर्माताओं को पर्याप्त अतिरिक्त इन्पुट लागत को कंटीब्यूट किया है जो वर्तमान में नकद हानि से गुजर रहे हैं।

**ठ. मै. एल्युमिनियम एक्सट्रॉडर्स (एलेक्स)**

- क. इस प्रकार की एवं विस्तृत जांच 2014 में की गई थी एवं दिनांक 7.10.2014 के अंतिम निष्कर्षों ने “गैर अलॉय इंगाट ऑफ अनरॉट एल्युमिनियम के आयात पर रक्षोपाय शुल्क छूटी की संस्तुति नहीं की गई थी। आवेदकों की असली मंशा घरेलू विक्री से लाभ बढ़ाने की है।
- ख. पूरे विश्व में प्रचालित प्रेक्टिस के विपरीत भारतीय उत्पादक एल्युमिनियम हेतु भारतीय मूल्य रखते हैं। एल एम ई आधारित मूल्य, जो मार्केट ड्राईवन है एवं ट्रांसपरेंट है, के विपरीत उत्पादकों द्वारा भारतीय मूल्यों की घोषणा की जाती है।
- ग. आवेदक आयात की उत्तराई की लागत के आधार पर घरेलू मूल्यों की गणना करते हैं। इसलिए रक्षोपाय शुल्क छूटी का वास्तविक अर्थ है भारत में मूल्यों को बढ़ाना जो भारतीय उधोग, जिसमें एक्सटरेशन उधोग एवं अंतिम उपभोक्ता शामिल हैं, को प्रभावित करेगा।
- घ. हालांकि आवेदन में दिया गया है कि आवेदक कम्पनियों के उपभोक्ता एक ऐसे उधोग में हैं जहां वे “Pass Through” के सिद्धांतों पर संचालन करते हैं, वे एल एम ई + प्रीमियम प्राइसिंग, जिसे विश्व में पूरे एल्युमिनियम उधोग द्वारा अपनाया जाता है, का पालन नहीं करते हैं।
- च. भारत में मूल्य, घरेलू रूपए के मूल्य, जिसमें 7.5% आयात शुल्क शामिल होता है, के आधार पर होता है। इसलिए आयात शुल्क में प्रत्येक वृद्धि सीधे आवेदकों की लाभप्रदता में जुड़ती है। आवेदकों को अपनी विक्री हेतु सीमा शुल्क छूटी क्यों प्रभारित करनी चाहिए।
- छ. रक्षोपाय शुल्क छूटी का आवेदन केवल घरेलू विक्री से आवेदकों के लाभ को बढ़ाने के लिए दिया गया है। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि उनकी लाभप्रदता एल एम ई मूल्यों एवं प्रीमियम में गिरावट के कारण घटी है न कि पी यू सी के आयात से प्रतिस्पर्धा के कारण।

- ज. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि एल एम ई एवं प्रीमियम में कभी वैश्विक मांग आपूर्ति स्थिति के कारण है जिसमें उनके मूल्यों को प्रभावित किया है न कि पी यू सी के कारण जिस पर वे रक्षोपाय शुल्क ड्यूटी का दावा करते हैं।
- ट. 1.3 मिलियन का अतिरिक्त वैश्विक उत्पादन विश्व के उत्पादन का लगभग 2% है जो कि बहुत बड़ा नहीं है।
- ठ. 1.25 मिलियन टन की उच्च क्षमता वाला मै. वेदांता का झारसुगुडा प्लांट-2 जो कि एस ई जेड में स्थित है, को भी कुछ भारतीय क्षमता की गणना करते समय शामिल किया है। 1.25 मिलियन टन का यह प्लांट आपरेशनल नहीं है क्योंकि वेदांता के पास इस प्लांट को चालू रखने हेतु बॉक्साइट एवं एल्युमिनियम नहीं है।
- ड. आवेदन में दर्शाए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्यात हेतु, घरेलू विक्री हेतु इंडेक्स की गई लागत 95/- रुपये की तुलना में 131/-रुपये उच्च है। निर्यात हेतु वस्तुओं की लागत पैकेजिंग एवं शिपिंग लागत के कारण अतिरिक्त लागत होनी चाहिए।
- ढ. आवेदकों द्वारा निर्यात की इंडेक्स लागत 95 रुपए दर्शाई गई है जब कि आयात हेतु इंडेक्सकी गई मूल लागत 125/-रु0 (बिना ड्यूटी के) दर्शाई गई है। इसका अर्थ है कि आवेदक भारत के बाहर के उपभोक्ताओं को कहीं कम मूल्यों पर निर्यात कर रहे हैं।
- ण. मूल्य कम होने की गणना वैध गणना नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा के शुल्क मुक्त आयात हेतु कोई अलग गणना नहीं होती है।
- त. सेकेन्डरी एल्युमिनियम के उत्पादन, जो कि स्क्रेप प्रयोग करते हुए किया जाता है, को आवेदकों के मार्केट शेयर की गणना करने हेतु शामिल किया गया है हालांकि स्क्रेप आयात पी यू सी के अधीन नहीं आता है।
- थ. भारत से पी यू सी का निर्यात 2011-12 में 147K से 2015-2016 में 644K तक बढ़ा, आवेदकों का कैप्टिव उपभोग पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में लगभग 70 K मी. टन तक कम हो गया है।
- द. मै. नाल्को इस आवेदन का हिस्सा नहीं है।
- ध. एक्सट्रूशन विनिर्माताओं की स्थिति बहुत खराब है, लगभग 40 एक्सट्रूशन इकाईयां बंद हो चुकी हैं। चीन से भारत एक्सट्रूशन के आयात की आशंका है। पी यू सी पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भारत में उत्पादन की लागत बढ़ाएगा एवं भारत में एक्सट्रूशन की विक्री, शुल्क में अंतर होने के कारण सस्ते आयातित एक्सट्रूशन की तुलना में, उच्च लागत पर होगी।
- न. यह उपाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहां बहुत बड़ी संख्या में एक्सट्रूडर्स को अपने आपरेशन बंद करने होंगे एवं लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
- (ड) **मै. वेस्टर्न मेटल इंडस्ट्रीज प्रादबेट लि0**
- क. सीमा शुल्क टैरिफ की शीर्ष संख्या 76109990 के अधीन आने वाले एल्युमिनियम स्लग्स का वे निर्माण करते हैं जो पैकिंग के लिए अपेक्षित हैं एवं जो कि अनरॉट एल्युमिनियम से निर्मित एक सेकेन्डरी उत्पाद है।
- ख. यदि अनरॉट एल्युमिनियम पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो इससे अनरॉट एल्युमिनियम से बनाए जाने वाले इंटरमीडियटरी उत्पादों के आयात में वृद्धि हो सकती है जिसके कारण घरेलू उधोग को गंभीर क्षति फलित हो सकती है। यदि अनरॉट एल्युमिनियम पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो यह अनरॉट एल्युमिनियम से बने इंटरमीडियटरी उत्पादों के आपात पर भी लागू होना चाहिए जिससे घरेलू उधोग के बने रहने हेतु सहायता मिलेगी।

- ग. वेदांता लिमिटेड, एस ई जेड में स्थित एक यूनिट है एवं इसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में सीमित मात्रा में आपूर्ति की अनुमति है। आवेदकों द्वारा यह साबित करने की आवश्यकता है कि वे सभी इकट्ठे रूप में घरेलू उधोग की व्याख्या को संतुष्ट करते हैं।
- घ. घरेलू आवेदकों की उत्पादन मात्रा कुछ समयावधि के पश्चात बढ़ी है एवं घरेलू बाजार में उनका शेयर 28% से वर्ष 2016 में 31% तक बढ़ा है।
- ड. आवेदक जांच के अधीन कॉमेडिटी के प्रमुख उत्पादक है अतः घरेलू उधोग को आरोपित क्षति रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण को न्यायोचित नहीं ठहराती है।
- च. लाभप्रदता में कमी कई कारकों के कारण है अतः यह अकेला पहलू नहीं हो सकता जिसके आधार पर घरेलू उधोग को क्षति आरोपित की गई है। कई बार, नियांत पर प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहन की अवधि अस्थाई रूप में लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है।
- छ. उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, जाहे टैक्स से पहलेके हो या बाद के, को भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, या दोनों आंकड़े आवेदकों द्वारा दिए जाने चाहिए।
- ज. चीन की अर्थव्यवस्था के कूलिंग डाउन होने के मुद्दे को अथवा मध्यपूर्व विनिर्माताओं के ईंधन लागत में कमी के मुद्दे को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।
- झ. प्रत्येक देश को कुछ फायदे एवं नुकसान होते हैं। बैक्साइट भारत में पर्याप्त मात्रा में हो सकता है परंतु वस्तुओं के विनिर्माण हेतु मध्यपूर्व से इसे आयात किया जाना है।
- ञ. चीन भी एल्युमिनियम का पर्याप्त मात्रा का आयात करता है एवं इसलिए चीन अर्थव्यवस्था का कूलिंग डाउन सीधे तौर पर चीन से नियांत में वृद्धि का कारण नहीं हो सकता जो घरेलू उधोग को गंभीर क्षति पहुंचाए। यदि ऐसे कोई मामले मौजूद भी हो तो इन्हे डम्पिंग एक्टीविटी के रूप में मानना चाहिए।
- ट. विजली के बारे में यदि चीन की विभिन्न प्रादेशिक सरकारों ने प्रोत्साहन दिए गए हैं तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 सी अथवा 9 के अधीन जांच की जानी चाहिए एवं रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण हेतु आवेदन नहीं करना चाहिए।
- ठ. जांच के अधीन वस्तु का मूल्य लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) पर प्रचलित मूल्यों पर आधारित होता है एवं किसी एक विनिर्माता द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता।
- ड. भारत में पूरे घरेलू उधोग द्वारा जांच के अधीन वस्तु के मूल्य, एल एम ई पर प्रचलित मूल्यों, समय – समय पर प्रचलित विनियम दरों, उनके द्वारा दावा किए गए प्रीमियम एवं वस्तु के आयात पर छूटी के स्तर के आधार पर, निर्धारित किए जाते हैं।
- ढ. जब मेटल बाजार अपने पीक पर था या होगा, वेनिफिट या तो ले लिया गया है या लिया जा सकता है एवं लाभ प्रदता में कमी रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का कारण नहीं हो सकता।
- ण. पूरे वैश्विक वस्तु बाजार में मूल्यों ने एक विशेष “साइक्लिकल” व्यवहार देखा है। यदि किसी विशेष अवधि में वस्तु के मूल्य निचले स्तर पर हैं तो इस कारण को क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता।
- त. वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में एल्युमिनियम (गैर अलॉय) क्रमशः 343 टन एवं 432 टन आयात हो चुका है। इसी प्रकार इस वस्तु का नियांत है।
- थ. आवेदकों का यह दावा कि वे घरेलू उत्पादन का 50% नियंत्रण करते हैं, की भी पुष्टि की जानी है।
- द. आरोपित क्षति की वास्तविक प्रकृति, इसकी गंभीरता एवं प्रभाव को आवेदकों द्वारा साबित/दर्शाया नहीं गया है।

- ध. आवेदकों द्वारा नियोजित कदमों एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव, तकनीक का अपग्रेडेशन, विनिर्माता के स्तर का लाभ, आवरहेड में कमी एवं क्रियान्वयन समयवधि को भी सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है।
- न. आंकड़ों अथवा सूचना का दावा की गई गोपनीयता, यदि कोई हो, को भी न्यायोचित दर्शाया है। आवेदक ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ हैं।
- प. यदि रक्षोपाय शुल्क का सहारा लिया जाता है तो अध्याय 76 द्वारा कवर दिए सभी उत्पादों को शामिल करते हुए जांच के दायरे का विस्तार किया जा सकता है।
- फ. रक्षोपाय शुल्क से घरेलू बेची जाने वाली एल्युमिनियम की कीमतों में वृद्धि होगी एवं इस प्रकार एल्युमिनियम से उत्पाद के विनिर्माता आयात में बढ़ोतरी/वृद्धि से बढ़ी एवं अपूर्णीय धनि उठाएंगे।
- ब. द्वितीय स्तर के विनिर्माताओं पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।
- ड. मै. सेंचुरी मेटल रिसाइकिंग प्राइवेट लि. श्री सुमंगला मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज (पी) लि. श्री बाला जी एल्युनिकास्ट लि., सरगम प्राइवेट लि., सी एम आर निस्की इंडिया प्राइवेट लि., सी एम आर टायदसू एल्युमिनियम इंडिया प्राइवेट लि.।
- क. भारत में एल्युमिनियम अलौंय के उत्पादकों में से है।
- ख. लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) मूल्यों में फरवरी 2012 में 2204 डालर/मीटन से फरवरी 2016 में 1535 डालर/मीटन की पर्याप्त गिरावट आई है। वैश्विक मांग में कमी के कारण कीमतों में गिरावट आई है खासकर चीन में सरप्लस ग्लोबल केपेसिटी है।
- ग. प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि करने हेतु क्योंकि मौके उपलब्ध है, एल्युमिनियम अलौंय की आपूर्ति हेतु भारत एक लक्ष्य बन गया है एवं एल्युमिनियम के आयात में नोट करने योग्य वृद्धि हुई है।
- घ. ऑटोमोबाइल पुर्जों के विनिर्माण हेतु विभिन्न कास्टिंग में भारत में 5L एम टी पी ए से अधिक एल्युमिनियम अलौंय का उपयोग होता है।
- ड. एल्यूमियम एलौंय एच एस कोड 7601 के अधीन आयात किए गए जाते हैं तथा देश में डाऊन स्ट्रीम एलौंय निर्माताओं के साथ स्पर्धा करते हैं।
- च. एल्युमिनियम अलौंय का मलेशिया, थाईलैंड एवं मध्यपूर्व से आयात घरेलू उधोग की अक्षुणता को नुकसान पहुंचाता है। यह आवश्यक है कि इन आयातों को बंद करना चाहिए एवं घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- छ. यह उपाय देश में सभी अलौंय विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करेगा एवं घरेलू ग्रोथ में वृद्धि होगी एवं अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्य एवं डाउनस्ट्रीम उधोगों की सहायता हेतु कार्रवाई की जा सकती है।
- (ग) मै. ऑल इंडिया एल्यूमिनियम सेकेन्डरी मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन
- क. एशोसियन, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश ने विभिन्न एल्यूमिनियम उत्पादों, जैसे एल्यूमिनियम युटेसिल, एक्सट्रॉशन, एल्यूमिनियम क्लोज़र स्टॉक, पैकिंग हेतु कन्वर्टर्ड फॉइल्स एवं एल्यूमिनियम हार्डवेयर के सामानों में लगी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (SSI) का प्रतिनिधित्व करती है।
- ख. रक्षोपाय शुल्क/अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सेकेन्डरी एल्यूमिनियम उत्पादों के विनिर्माण में लगी (SSI) यूनिटों के हितों के विरुद्ध होगा।
- ग. यह उनके सदस्य उधोग द्वारा प्रयोग किए जा रहे कञ्चे माल की लागत को काफी बढ़ा देगा।

- घ. यह नोट कर आश्वर्यजनक लग रहा है कि सरकार रक्षोपाय शुल्क केवल मूल एल्यूमिनियम मेटल पर लगा रही है एवं एल्यूमिनियम के सभी उत्पादों पर नहीं।
- इ. भारत में प्राइमरी उत्पादक पहले ही बड़े लाभ कमा रहे हैं। ये अपने उत्पादन की सारी मात्रा उसी वर्ष के दौरान बेचने में सफल हो जाते हैं। उनका एल्यूमिनियम उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।
- च. सरकार ने 2016-17 के बजट में एल्यूमिनियम मेटल पर आयात शुल्क 2.5% यथामूल्य पहले ही बढ़ा दिए हैं।
- छ. पिछले 6 महीनों में रुपया 10% तक मूल्य हासिल होकर ₹ 62.50 से ₹ 66.50 प्रति डॉलर हो गया। इस कारण से भी, प्राइमरी उत्पादकों ने एल्यूमिनियम मेटल के मूल्य बढ़ा दिए।
- ज. एल्यूमिनियम की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित एल एम ई के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। एल्यूमिनियम मेटल का आयात भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित एल एम ई कीमतों के आयात पर किया जाता है। इसलिए देश में एल्यूमिनियम मेटल का सस्ता आयात नहीं हो सकता।
- झ. एल्यूमिनियम मेटल की कीमतें दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के बीच यू एस डी 235 पी एम टी तक बढ़ी हैं एवं इसके कारण मूल उत्पादकों ने एल्यूमिनियम मेटल की कीमतें अप्रैल 2016 में ₹ 7500 पी एम टी तक पहले ही बढ़ा दिए हैं एवं यह और ₹ 5000 पी एम टी तक आगे होने की संभावना है। अतः कुल वृद्धि लगभग 10% होगी।
- ञ. सेकेंडरी एल्यूमिनियम उत्पादों के विनिर्माण में लगी एस एस आई मूल्य वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित होंगी। पूरे देश में विभिन्न एल्यूमिनियम उत्पादों में लगी एस एस आई को, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं, को खत्म कर देगा।
- ट. उनका सुझाव है कि सरकार को देश से एल्यूमिनियम मेटल के निर्यात पर निर्यात शुल्क अधिरोपित करना चाहिए।
- त. मै. मेटल रिसाइकलिंग एसोशियशन ऑफ इंडिया (एम आर ए आई) साउथ एशिया फोरम फॉर एनर्जी एफिसिएन्सी (एस ए एफ ई ई)
- क. एम आर ए आई एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत के फेरियस एवं नान-फेरियस मेटल रिसाइकलिंग उधोग का प्रतिशिनित्व करते हैं जिसके 510 से ऊपर सदस्य हैं जिसमें ज्यादातर क्षेत्रीय मेटल ट्रेड एशोसियशन हैं। उनकी समग्र स्ट्रेंथ 700 छोड़े, मध्यम एवं बड़े इंटरप्राइजेज हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 17.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
- ख. एस ए एफ ई ई को वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्लू ई सी) इंडियन मेंबर कमिटी एवं एनर्जी सेविंग कमीशन ऑफ वर्ल्ड फाउंडरी आर्गेनाइजेशन (डब्लू एफ ओ) यू.के. संयुक्त अभिक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।
- ग. एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग उधोग ऑटोमोबाइल सेक्टर हेतु एल्यूमिनियम अलांय सिलियों के उत्पादन में लगा है।
- घ. वे रक्षोपाय जांच शुरू करने के नोटिस का स्वागत करते हैं।
- इ. एल्यूमिनियम स्क्रेप की रिसाइकलिंग ऊर्जा बचाती है एवं वातावरण को सुरक्षा करती है। रिसाइकलिंग में ऊर्जा उपभोग मूल एल्यूमिनियम के उत्पादन हेतु 14000 यूनिट प्रति टन की तुलना में केवल 500 यूनिट प्रति टन है। व्यावहारिक रूप में रिसाइकलिंग में कार्बन स्लाव नहीं होता है। यू.एन.एफ.सी.सी.प्रोजेक्ट 2016 के मध्य में क्लीन डेवलोपमेंट मैकेनिज्म स्कीम (सी.डी.एम) के अधीन कार्बन क्रेडिट्स हेतु ग्राहय होने के लिए यू.एन.एफ.सी.सी.सी.द्वारा उधोग की स्थापना की गई है।
- च. एल्यूमिनियम अलांय के 150 से ज्यादा घरेलू विनिर्माता हैं जो अधिकतर एम एस एफ सेक्टर में आते हैं। इनकी 20,000 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल इंवेस्टमेंट है एवं लगभग 100,000 कारीगरों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

- छ. यह सेक्टर आटोमोटिव प्रयोग हेतु लगभग 50,000 टन एल्यूमिनियम अलॉय का एवं स्टील मेल्टिंग में डिओक्सिडेशन हेतु स्टील सेक्टर हेतु 180,000 टन डिआक्स का उत्पादन कर रहा है। बहुत से क्रिटिकल आटो अवयव का जिनका पहले आयात किया जा रहा था, भारत के अंदर आटोमोटिव एल्यूमिनियम के विनिर्माण के कारण भारत में भी विनिर्माण किया जा रहा है।
- ज. एच एस 760120 के अधीन आने वाले एल्यूमिनियम स्टील सिलिंयों का आयात थार्डलैंड एवं मलेशिया से इस देशों के साथ एफ टी ए एस के अधीन शुल्क मुक्त किया जाता है। इस तथ्य को संयोजित करते हुए कि एल्यूमिनियम अलॉय सिलिंयों नामतः एच एस 76020010 के अधीन आने वाले एल्यूमिनियम स्क्रैप, के विनिर्माण हेतु मूल कम्ब्रे माल के आयात पर 2.5% का आयात शुल्क है, ने एलुमीनियम अलॉय के विनिर्माताओं के बहुत वित्तीय हानि पहुँचाई है।
- झ. एल्यूमिनियम अलॉय के एक सबसे बड़े विनिर्माता को अपने पी बी टी में कमी को भुगता है। दो प्रमुख जापानी कम्पनियों के साथ संयुक्त वेंचर सहयोग में स्थापित दो अन्य कम्पनियों को भारी हानि उठानी पड़ी है जबकि एक कम्पनी पूर्णतः दिवालिया है। एल्यूमिनियम उधोग की अन्य मुख्य कम्पनियों ने भी उनके लाभ में कमी को भुगता है एवं उधोग की सम्पूर्ण लाभप्रदता नीचे चली गई है।
- ञ. विभिन्न देशों से एल्यूमिनियम अलॉय सिलिंयों का आयात थार्डलैंड एवं मलेशिया से शुल्क मुक्त आयात शामिल है वर्ष दर वर्ष लगभग 55% तक जबरदस्त रूप में बढ़ा है।
- ट. पी.यू.सी पर 5% रक्षोपाय शुल्क लगाने का वे समर्थन करते हैं और वे अस्थायी रक्षोपाय शुल्क लगाने के पक्ष में भी हैं।
- ठ. एल्यूमिनियम अलॉय का प्रयोग ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स के निर्माण हेतु किया जाता है चूंकि यह ईंधन की क्षमता को बढ़ाता है और वेहिक्यूलर इमीशन को कम करता है। आमतौर पर इसका उत्पादन रिसाइकिंग स्क्रैप द्वारा किया जाता है और यह ऊर्जा की बचत और पर्यावरण अनुरूपी दोनों प्रकार का है। उनके अनेक सदस्यों द्वारा द्रव्य रूप में एल्यूमिनियम अलॉय की आपूर्ति की जाती है और यह मेथोडोलौजी क्लीन डिवलपमेंट मेकेनिज्म के अंतर्गत यू.एन.एफ.सी.सी.सी. द्वारा अनुमोदित है और यह कार्बन क्रेडिट्स के लायक है।
- ड. एल्यूमिनियम अलॉय इंडस्ट्री, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से परेशान है क्योंकि बेसिक-रॉ-मटीरियल अर्थात् एल्यूमिनियम स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की दर से आयात कर लगाया जाता है वहीं तैयार माल, थाइलैंड और मलेशिया जैसे एफ.टी.ए. देशों से आयात-कर-मुक्त तरीके से निःशुल्क मंगाया जा सकता है। चीन ने हाल ही में रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम अलॉय पर 30% वैट रिबेट लागू किया है जिससे चीनी कंपनियों के लागत में कम से कम 2 प्रतिशत की लागत आई। इस प्रकार भारतीय मैन्यूफैक्चरर को लागत में तुकसान झेलना पड़ा। एल्यूमिनियम अलॉय इनगेट्स (एच.एस.7601) पर 5 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराया जा सके।
- ढ. यह भी आशंका है की रक्षोपाय शुल्क के लगाने वाद एल्यूमिनियम अलॉय का मूल्य बढ़ जाता है तो इस कारणवश ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का आयात और भी बढ़ जाएगा यह पूरी तरह गलत है। सभी मुख्य ऑटोमोबाइल ओ.ई.एम. आदि एल्यूमिनियम अलॉय हेतु स्वदेशी विनिर्माताओं से सीधे तौर पर मूल्य की चर्चा करते हैं। एल्यूमिनियम अलॉय की घरेलू कीमतों में किसी प्रकार की संभावित बढ़ोतरी, रक्षोपाय ड्यूटी की पोस्ट-लेवी, ऑटो-कम्पोनेंट-विनिर्माताओं के लिए सहायक सावित होगा। इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का स्वदेशीकरण पहले की अपेक्षाकृत अधिक बेहतर और बड़ा होगा।
- ण. ऑटो और अन्य इंजीनियरी अनुप्रयोगों के लिए सभी प्रकार के एल्यूमिनियम अलॉय जैसे-ए डी सी 12, ए सी 4 वी आदि का विनिर्माण भारत में किया जा रहा है। फिर भी एल्यूमिनियम व्हीलस के लिए अपेक्षित एल्यूमिनियम अलॉय (ए। 356.1) का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। एल्यूमिनियम अलॉय पर रक्षोपाय शुल्क की लेवी यह सुनिश्चित करेगा कि स्वदेशी में ही एल्यूमिनियम अलॉय ए 356.1 के विनिर्माण हेतु समुचित प्रोधौगिकी को विकसित किया जा सके।

- त. वर्ष 2012 की 3.36 प्रतिशत पी.बी.टी तथा यहाँ तक कि वर्ष 2015-16 में पहले की अपेक्षा और भी कम/ऋणात्मक, समग्र लाभप्रदता इंडस्ट्री में पाई गई है। यह इस कारण से हुआ है कि मई 2013 से एल्यूमिनियमस्कैप पर 2.5 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगाया गया है और इसके साथ ही एफ.टी.ए.देशों से एल्यूमिनियम अलॉय को डंप किया जा रहा है तथा चीन के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है क्योंकि स्थानीय सरकारों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन को बढ़ाया गया है। एल.एम.ई. पर उतार-चढ़ाव से; एल्यूमिनियम स्कैप मूल्य का कोई संबंध नहीं है चूंकि एल.एम.ई. द्वारा स्कैप के मूल्य नियंत्रित नहीं किए जाते हैं।
- थ. इंडस्ट्री में अत्यंत कम/ऋणात्मक लाभप्रदता के कारण तथा विनिर्माताओं के एक अधिकांश हिस्से का एम.एस.एम.ई. सेक्टर में होने के कारण वैकों द्वारा इंडस्ट्री को दिए गए कर्ज के बड़े हिस्से पर प्रभाव पड़ा है।
- द. 200 दिनों के लिए तत्काल; प्रस्तावित अस्थायी रक्षोपाय शुल्क लगाई जाए ताकि घरेलू उधोगों को बंद होने से बचाया जा सके।

**थ मेसर्स ऑल इंडिया नॉन-फेरस-इंडस्ट्रीज असोसिएशन**

- क. वे विभिन्न मंचों से, नॉन-फेरस-इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ख. रक्षोपाय अन्वेषण में, केवल एवं कंडक्टर शामिल नहीं होंगे; जो देश में एल्यूमिनियम की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे केवल एवं कंडक्टर विनिर्माताओं हेतु कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी जबकि तैयार माल को यह कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाएगा।
- ग. यह डाउनस्ट्रीम मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को भी हतोत्साहित कर रहा है जो एल्यूमिनियम उधोग में सर्वाधिक रोजगार का सृजन करता है।
- घ. यह स्थानीय डाउनस्ट्रीम मैन्यूफैक्चरिंग को पर्याप्त नुकसान में रखते हुए तथा इसे प्रतिस्पर्धा मुक्त बनाते हुए तैयार माल के आयात को प्रोत्साहित करेगा।
- ड. रक्षोपाय अन्वेषण में, इस बात का उल्लेख है कि मिडिल-ईस्ट-स्मेलट्रस; अपेक्षाकृत सस्ते ईंधन स्रोतों के कारण लाभ उठाते हैं। हालांकि वेदांता लिमिटेड के सी.ई.ओ. द्वारा हाल ही में दिए गए साक्षात्कार में; जो कि याचिकाकर्ताओं में से एक हैं तथा उन्होंने यह साफ-साफ बताया है कि भारत के पास एल्यूमिनियम उत्पादन करने हेतु पर्याप्त लाभप्रद अवसर है क्योंकि एक और जहां बॉक्साइट की तत्काल उपलब्धता है वहाँ दूसरी और बिजली तैयार करने के लिए सस्ते कोयले की उपलब्धता भी है। कुछ संयंत्रों के लिए स्थानीय मुद्रों की वजह से यह तात्कालिक रूप में भले ही उपलब्ध नहीं हो परंतु भारत के डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए अधिक भुगतान करने जैसा कोई कारण नहीं है।
- च. रक्षोपाय शुल्क का आरोपण; कंपनियों को दंडित करने के समान होगा जो भारत में एल्यूमिनियम को प्रोसेस करते हैं।
- छ. मेसर्स वेदांता लिमिटेड ने एस.ई.जेड जोन में एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया है जो कि एक याचिकाकर्ता भी है।
- ज. एल्यूमिनियम के आयात की तुलना में; निर्यात अधिक होने के कारण; भारत एल्यूमिनियम का शुद्ध निर्यातिक है। रक्षोपाय शुल्क, निर्यात की तुलना में आयात को नहीं रोकेगा।
- झ. वर्षों के दौरान, वास्तविक आयात के आंकड़ों में खपत के प्रतिशत के रूप में बढ़ोतरी हुई है जिसमें शायद ही कोई बदलाव हुआ है। यह कहना गलत है कि आयात के कारण घरेलू विक्री प्रभावित हुई है।
- ञ. यदि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धा विहीन कर दिया जाता है तो इन बंद होने वाले यूनिटों से बेरोजगारी; डी.आई. से उत्पन्न बेरोजगारी की अपेक्षा अधिक होगी।

- ट. एल्यूमिनियम का मूल्य-निर्धारण, एक खुली एवं पारदर्शी व्यवस्था अर्थात् एल.एम.ई. द्वारा किया जाता है। विगत अवधियों के दौरान ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एल.एम.ई. अत्यंत ऊचा रहा है और याचिककर्ताओं ने बहुत लाभ अर्जित किया है। उत्पाद, सैदैव चक्रों के अधीन होते हैं। सरकार को डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का भी ध्यान रखना चाहिए।
- ठ. बहुत सी द्वितीयक उधोग की शृंखलाएँ, निर्धारित मूल्य पर हैं; जिनमें रक्षोपाय शुल्क का कोई तत्व कारक नहीं है; डाउनस्ट्रीम मैन्यूफैक्चरर पर्याप्त रूप से स्वयं को शक्तिहीन अर्थात् विकलांगता की श्रेणी में पाएंगे।
- द. मेसर्स अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- क. वे 5,000 करोड़<sup>></sup> की कंपनियाँ हैं जो एल्यूमिनियम आधारित कंडक्टरों, केबलों एवं इंडस्ट्री ऑयलों के विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं तथा अपने द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात भी कर रही हैं। वे अपने उत्पादों की आपूर्ति; सेन्ट्रल एण्ड स्टेट ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की तुलना में, उनके डीम्ड-एक्सपोर्ट एवं फर्म-प्राइस-ज्यूटी-पेड प्राइसिंग लिंक से लेकर एल.एम.ई. बेस टेंडरों/अवार्डों तक करती हैं।
- ख. उनकी विक्रियाँ, डीम्ड-एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एवं फिजिकल एक्सपोर्ट की तीन श्रेणियों में उपलब्ध हैं।
- ग. यदि रक्षोपाय शुल्क का आरोपण किया जाता है तो किए गए आयात पर डीम्ड-एक्सपोर्ट की तुलना में रक्षोपाय शुल्क की छूट नहीं दी जा सकती है। इससे भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को व्यापक वित्तीय भार वहन करना होगा जबकि यही एल्यूमिनियम कंडक्टर के; चीन के आपूर्तिकर्ताओं को भारी लाभ दिलाएगा।
- घ. डीम्ड-एक्सपोर्ट की तुलना में एडवांस लाइसेंसों से रक्षोपाय शुल्क में छूट प्रदान की जाए।
- इ. यूटिलिटी कंपनियों को अपनी बोली (बीड) को बूट-बैसिस पर (बिल्ड/ओन/ऑपरेट/ट्रांसफर के आधार पर) प्रस्तुत करना होगा। प्रतिस्पर्धी बोली में जहाँ एक बार मूल्य तय होता है; वहाँ शुल्क अथवा कर में किसी प्रकार के परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। लागू होने की तारीख से, लगभग 6 महीने पूर्व कोटेशनों को भेजा जा रहा है। इस मामले में, यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता हो तो कंडक्टर, के भारतीय विनिर्माताओं को प्राप्त आदेश के अनुसार भारी नुकसान उठाना होगा तथा इस बारे में भी पूर्ण संशय की स्थिति होगी कि भविष्य में इसके लिए किस प्रकार कोटेशन प्रस्तुत किए जाएं।
- च. स्थानीय एल्यूमिनियमउत्पाद डीम्ड-एक्सपोर्ट बेसिस पर आपूर्ति उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
- छ. अपेक्षित अन्वेषण की अवधि में, संशय की स्थिति है क्योंकि फरवरी 2016 में, यूनियन बजट में बेसिक कस्टम्स ज्यूटी को 5 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया गया है और रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव 12.50% (5+7.50) अथवा 10% (5+5) होगा।
- ज. फिजिकल और डीम्ड-एक्सपोर्ट के ऑर्डर को कार्यान्वित करने के लिए इंडस्ट्री द्वारा महत्वपूर्ण आयात किए जाते हैं जिसके लिए शुल्क-मुक्त-आधार पर डी.ई.सी.सी. स्कीम के अंतर्गत कच्चे मालों का आयात किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में से इंडस्ट्री द्वारा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की तुलना में किए गए इम्पोर्ट को घटाए जाने की जरूरत है।
- झ. मेसर्स हिण्डालको, बाल्को स्वयं उक्त मालों के आयातक हैं और इसलिए वे रक्षोपाय बचाव की माँग नहीं कर सकते हैं। कुछ हाई-टेक-प्रोडक्ट-मैन्यूफैक्चरिंग के लिए एल्यूमिनियम अर्थात् ए.एल के अल्ट्रा-हाई-प्यूरिटी की जरूरत है। >99.85 सामग्री जिनका उत्पादन नियमित आधार पर नहीं किया जाता है और कुछ एलेमेण्ट कंट्रोल का रखरखाव किसी भी घरेलू स्मेलटर/याचिककर्ता द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए इसका आयात करना तय है। यदि आयात की मात्रा को घटाया/समायोजित किया जाता है तो अनुपात में परिवर्तन होगा।
- ज. रक्षोपाय शुल्क के इंसीडेंस से कंडक्टर निर्माण की लागत में आनुपातिक बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर विशेषकर चीन से आयातित कंडक्टरों की लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और तदनुसार यह इंडियन कंडक्टर मार्केट

- को स्वैम्प कर देगा जिसके फलस्वरूप भारतीय कंडक्टर इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। भारत में बीमार पड़े एवं दुर्दशा भुगत रहे उधोग-धंधे के अलावा उससे भारी बेरोजगारी एवं सामाजिक अशांति फैलेगी।
- ट. वर्तमान परिदृश्य/तथ्यों को छुपाने हेतु याचिकाकर्ताओं ने जनवरी, 2016 तक की अवधि के आंकड़े हीं दर्शाए हैं। वास्तव में, लागू झूटी की दर 7.50% न कि 5% जैसा कि याचिका में बताया गया है।
- ठ. मेसर्स नाल्को जो एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है वह याचिकाकर्ता के साथ सहयोगी नहीं है।
- ड. याचिकाकर्ताओं ने प्रोडक्शन कम्पोरेटिव डेटा में अपने + नाल्को द्वारा स्कैप के लिए गए आयात को भी जोड़ दिया है। (7602 के अंतर्गत) आयात स्कैप को शामिल करना प्रासंगिक नहीं है क्योंकि याचिका एच.एस.एन.कोड 7601 से संबंधित है। यदि याचिकाकर्ता स्कैप पर रक्षोपाय शुल्क लगवाना चाहते हैं तो उन्हें फिर से नई याचिका दायर करने की जरूरत है। केवल एवं कंडक्टर की डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री स्कैप का आयात बिलकुल नहीं करती है क्योंकि यह कम स्तर/कम शुद्धता वाली सामग्री है जो हाई-ग्रेड कनेक्टिविटी एवं रेसिस्टीविटी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को ही धृति का प्रतिशत कम होगा।
- ढ. खान मंत्रालय के आंकड़ों से तुलना करने पर, यह पता चलता है कि पेटिशनर प्रोडक्शन डेटा प्रामाणिक नहीं है। कम उत्पादन दर्शने एवं क्षमता का कम उपयोग व नुकसान बताने के लिए गलत डेटा प्रस्तुत किया गया है। ऑल इंडिया प्रोडक्शन के लिए याचिकाकर्ताओं ने डेटा के स्रोत का खुलासा नहीं किया है।
- ण. ओपनिंग एवं क्लोजिंग स्टॉक के इंडेक्स किए गए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
- त. याचिकाकर्ताओं का डेटा भरोसे के लायक नहीं है चूंकि संबंधित अवधि में हुए उत्पादन से, बिक्री की मात्रा अधिक है और न्यून-उपयोग अथवा कम-उपयोग का कोई प्रश्न हीं नहीं हैं।
- थ. याचिकाकर्ताओं में से किसी एक ने 1.25 एम.टी.पी.ए. की अनुमोदित क्षमता के लिए; एस.ई.जेड में करीब 13,000 करोड़ का पूँजी-निवेश किया है। यह निवेश भारतीय बाजार/मांग के अनुरूप नहीं है। डी.आई द्वारा भारतीय मांग/बाजार-डेटा का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है।
- द. कुल मांग की गणना करते समय, केवल झूटी-पेड इम्पोर्ट्स पर विचार किया जाना चाहिए।
- ध. यह आंकड़ा याचिकाकर्ताओं को हुए किसी नुकसान को न्यायसंगत नहीं बताता है।
- न. एडवांस लाइसेंस के लिए पूरे तौर पर शुल्क-मुक्त आयात किए गए हैं। शुल्क का भुगतान करने के पश्चात आयात करने का रुझान नकारात्मक है। पिछले दो वर्षों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई खरीद अपने आप में बहुत बड़ी है।
- प. घरेलू बिक्री की लागत में, याचिकाकर्ताओं ने बढ़ोतरी दिखाई है जबकि यही बात निर्यात के मामले में, कम दिखाई गई है, डोमेस्टिक एवं एक्सपोर्ट में लागत-ढांचा भिन्न-भिन्न नहीं हो सकता है।
- फ. याचिकाकर्ताओं का बिक्री-मूल्य झूटी-पेड-इम्पोर्ट्ड प्राइस से परे निरंतर बढ़ते हुए रुझान की ओर है। यह नाल्को के स्थानीय मूल्य से भी अधिक है।
- ब. अन्य बाजारों में, प्रचलित एल.एम.ई.मूल्य निर्धारण के ऊपर, महत्वपूर्ण प्रीमियम पर भारत में मूल्य-निर्धारण किया जाता है। एल.एम.ई.मूल्यों में हुए गिरावट का आयात-प्रतिस्पर्धी से कोई संबंध नहीं है और यह रक्षोपाय संबंधी उपाय करने को किसी प्रकार से न्यायसंगत सिद्ध नहीं करता है।
- भ. याचिकाकर्ताओं का क्षमता दोहन/पूँजी-निवेश बाजार की माँग के अनुरूप नहीं है; याचिकाकर्ताओं की अपनी गैर-दक्षता से लागत-ढांचा उच्चतर होता है जिसके फलस्वरूप घरेलू मूल्य में बढ़ोतरी होती है।

- म. ई.पी.सी. कंपनियों/एस.ई.बी. आदि द्वारा केवल एवं कंडक्टरों के लिए आर्डरिंग पैटर्न में इंटरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग प्रोसीजर का अनुसरण किया जाता है। यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो कोई भी केवल एवं कंडक्टर के लिए अन्तराष्ट्रीय बाजार की लागत को पूरा नहीं कर सकेगा।
- य. वर्ष के पश्चात् अगले वर्ष में, कर्मचारी की लागत निरंतर उच्चतर है जो कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप नहीं है।
- कक. व्याज-लागत में, अप्रत्याशित बढ़ोतरी; वर्किंग कैपिटल (कार्यशील-पूँजी) में अवरोध के कारण नहीं है बल्कि यह केवल इस कारण है कि पूँजी निवेश के लिए ऊँची व्याज दर पर बहुत अधिक ऋण (हायर-बॉरोडिंग) की गई है।
- खग. अप्रैल 2016 में, प्रकाशित समाचार में यह बताया गया है कि एस.ई.जेड. में बेकार पड़े एल्यूमिनियम की क्षमता में वेदांता ने लंबी छलांग लगाई है; वर्ष 2007 से, एस.ई.जेड. के छ: एक्सटेंशन दिए गए हैं तथा यह अनुमोदन का आगे भी विस्तार चाहता है; ऊर्जा की कमी के कारण; एस.ई.जेड. डिप्लीटेड कैपिसिटी से काम कर रहा है।
- गग. वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित हिंडाल्को बिजनेस आउटलुक में भारी मात्रा एवं प्राप्तियों पिछले पांच वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम की माँग में 38% की बढ़ोतरी; कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के तीन मुख्य कारकों के कारण बिक्री की लागत में बढ़ोतरी बॉक्साइट की गुणवता में गिरावट एवं डीजल प्राइस डिरेग्युलेशन के कारण लोजिस्टिक्स में बढ़ोतरी; बढ़ती वैश्विक माँग के कारण निर्यात में बढ़ोतरी के बारे में बताया गया है।
- घघ. डाऊनस्ट्रीम इंडस्ट्री के बारे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने के संबंध में; याचिकाकर्ता ने अनुपयुक्त निर्वचन दर्शाया है।
- झ. जैसे बीडर कॉन्टेक्ट्स एल-1 टेंडर/ई.पी.सी बेस पर आधारित है; इसलिए प्राइवेट पावर इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान होगा और वे सरकारी इंस्टीज के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
- चच. याचिका में; केवल एवं कंडक्टर इंडस्ट्रीज पर दर्शाया गया प्रभाव पूरी तरह गलत है। कंडक्टर इंडस्ट्रीज की बड़ी संविदाएँ “फर्म प्राइस बेस” पर आधारित हैं और इस कारण अंतिम खरीदकर्ता को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लागत का वहन नहीं करना होगा जिससे कंडक्टर इंडस्ट्रीज को अंततः नुकसान उठाना पड़े। वेरिएबल प्राइस बेस में, रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव संबंधी कोई क्लॉज नहीं है और यह केवल कंडक्टर बिजनेस की लागत है।
- छछ. चालू वर्ष में, पहले ही कस्टम्स ड्यूटी को 5 प्रतिशत से 7.50% तक बढ़ा दिया गया है।
- जज. कंडक्टर पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत है इसलिए यह इन्वरटेड ड्यूटी का मामला होगा।
- झझ. केवल इम्पोर्ट स्कैप की मात्रा का ही वर्तन उद्धोग में उपयोग किया जाता है। रक्षोपाय शुल्क केवल स्कैप पर ही लगाया जाता है।
- ञञ. भारत से होने वाले एल्यूमिनियम का निर्यात; भारत को होने वाले एल्यूमिनियम आयात के अनुरूप है इसलिए यह व्यावसायिक हालत ठीक है।
- टट. घरेलू बिक्री एवं निर्यात की बिक्री की लागत में बहुत बड़ा अंतर है। घरेलू मूल्य निर्धारण में, जान बूझकर लागत को शामिल किया गया है और निर्यात मूल्य निर्धारण को नहीं किया गया है। प्रोडक्शन की तुलना में; याचिकाकर्ता की क्षमता का दोहन उपयुक्त नहीं है क्योंकि वर्तमान क्षमता एवं आगे की बढ़ोतरी समग्र बाजार-मांग के अनुरूप नहीं है और इसलिए पूँजी-निवेश/लगाए गए पूँजी से याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं हुआ है। भारी निवेश से याचिकाकर्ता का मूल्य ढांचा उच्च होता है जिससे बिक्री-मूल्य उच्च हो जाता है।

- ऊ. मेसर्स ल्यूमिनों इंडस्ट्रीज लिमिटेड; जे.एस.के इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वेंकटेश्वरा वायर्स प्राइवेट लिमिटेड; के.ई.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड; इंडियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स असोशिएसन; आदिनाथ इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड; कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड
- क. याचिका यद्यपि 3 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना था परंतु वास्तव में केवल 2 कॉर्पोरेट समूहों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। नालकों (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड) एक नवरत्न कंपनी है और यह याचिका में पार्टी के रूप में नहीं है।
- ख. पी.यू.सी में अलॉय इनगोट (76012010) शामिल है जो अधिकतर स्कैप से बनाया जाता है। भारत में इसका आयात ऑटोमोबाइल निर्माताओं अथवा उनकी सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इनका आयात एफ.टी.ए. के अंतर्गत भी किया जाता है। याचिककर्ताओं ने स्कैप-आधारित उत्पादों के इम्पोर्ट बोल्यूम को भी केवल इसलिए जोड़ लिया है कि संख्या में उच्चाल आ सके और इसे इम्पोर्ट-डेटा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- ग. कच्चे माल का आयात करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन के रूप में ड्यूटी-फ्री-लाइसेन्स के तहत हीं करीब 90 प्रतिशत इंगोट्स का आयात किया जाता है और रक्षोपाय शुल्क ऐसे आयात को नहीं रोक सकता है।
- घ. डी.आई द्वारा दी गई याचिका में जो इन्सॉटलड कैपिसिटी दर्शाई गई है उसमें वेदांता की 1.2 मिलियन टन क्षमता भी शामिल है जो उनके एस.ई.जेड. यूनिट में वैश्विक बाजार की माँग को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। न्यामगिरी की पहाड़ियों से संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्यात करने हेतु धातु का उत्पादन करने की सुविधा प्रदान करना था जिस पर आदिवासी समुदाय ने विद्रोह करते हुए आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप बॉक्साइट खनन पर प्रतिबंध लगाया गया। एस.ई.जेड की क्षमता का घरेलू माँग और आयात से कोई संबंध नहीं है। यदि 1.2 मिलियन एस.ई.जेड क्षमता को इसमें से बाहर कर दिया जाए तो डी.आई. द्वारा किए गए 48% के दावे के बजाए इसका उपयोग करीब 80% तक हुआ है।
- ङ. कैपटिव कंजम्पशन को केवल घरेलू विक्री करार देना चाहिए क्योंकि कैपटिव कंजम्पशन के लिए स्थानांतरित धातु का उपयोग मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे-वायर रॉड, रॉल्ड प्रोडक्ट्स आदि के विनिर्माण हेतु किया जाता है।
- च. मूलभूत वर्ष (बेस-ईयर) के लिए 29 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी माँग में हुई है। इसी समान अवधि के दौरान निर्यात में हुई बढ़ोतरी नाम-मात्र की है।
- छ. भारत में अपने विक्री मूल्य को बढ़ाने में ड्यूटी प्रोटेक्शन डी.आई. की मदद उच्चतर आयात समानता मूल्य की प्राप्ति द्वारा तेजी से एवं अनुचित लाभ के लिए करेगा अंततः जो अंतिम ग्राहक है उसे उच्चतर मूल्य अदा करना होगा जिसे किसी और पर पर नहीं टाला जा सकता है।
- ज. एल्यूमिनियम की विक्री मूल्य में, किसी प्रकार की बढ़ोतरी अथवा कमी से विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति धीमी होगी।
- झ. उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले किसी प्रकार के प्रभाव के संबंध में दी गई सूचना पूरी तरह गलत है। शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी करने से उनकी विक्री मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा जो आयात-समानता के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। खपत करने कम्पनियों की बड़ी संख्या को नजरअंदाज करते हुए रक्षोपाय द्वारा ड्यूटी-प्रोटेक्शन-ग्रांट करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है।
- ञ. धातु के व्यवसाय में; मूल्य में उत्तार-चढ़ाव (प्राइस बोलेटिनी) शामिल होता है जिसका लिंकेज एल.एम.ई. के साथ होता है। एल.एम.ई. मार्केट प्राइस डिस्कवरी मेकेनिज्म है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल भारतीय धातु उत्पादकों पर हीं लागू होती है।
- ट. वर्ष 2016-17 के बजट में, एल्यूमिनियमधातु पर सीमा शुल्क को पहले ही 5% से बढ़ाकर 7.50% कर दिया गया है। धातु के मूल्य में की गई कोई बढ़ोतरी से इन्वर्टेड-ड्यूटी स्ट्रक्चर पर असर होगा तथा यह खपत करने वाली कम्पनियों को बजूद कायम रखने हेतु प्रतिस्पर्धा से मुक्त कर देगा। अंततः तैयार माल का आयात ही सीधे तौर पर होने लगेगा। लघु और मध्यम श्रेणी के बहुत उधोग-धंधों को बंद करना होगा।

- ठ. याचिका में, फॉलिंग “प्रीमियम” का उल्लेख किया गया है जबकि इसे कभी भी लाभवर्धक कारक नहीं माना गया है। एल.एम.ई. द्वारा शुरू किए गए रेग्युलेटरी एक्शन के बाद मैन्यूपुलेटेड हायर-लेवल से प्रीमियम लेवल में गिरावट आई।
- ड. चीन और मध्य पूर्व की सरकारें उनकी उद्योग को सब्सिडी के माध्यम से कीमतों को रोकने में समर्थन करेंगे जबकि डीआई ने कीमत में लाभप्रदता वृद्धि को सुधारपूर्वक लागू करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।
- ढ. बॉक्साइट और कोयले के स्थानीय रूप से होने का बहुत बड़ा फायदा भारतीय उत्पादकों को मध्य पूर्व उत्पादकों की तुलना में है जिनको गैस सब्सिडी का फायदा है। मध्य पूर्व उत्पादक आयातित एल्यूमिना पर निर्भर हैं। वे एलएमई कीमत के संदर्भ में अपने उत्पादों को बेचते हैं और न की कम कीमत पर।
- ण. डीआई अनुकूल विनियम दर की गति से लाभान्वित हुआ है, वास्तविक बिक्री मूल्य भारतीय रूपयों में है।
- त. वैश्विक वस्तुओं की कीमत में गिरावट, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए ऐसे अन्य मामलों और अधिक्षमता, संरचनात्मक मामले हैं उनका उद्योग द्वारा समाधान किया जायेगा और लाभप्रदता में सुधार हेतु उच्च संरक्षण की मांग में कटौती पूरी तरह से केवल एल्यूमीनियम आधारित उद्योग को नुकसान पहुँचाने का परिणाम देगा।
- न. मे. एसोशियेटेड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
- क. वे एल्यूमीनियम वॉयर रॉड (अध्याय 7605) के निर्माता हैं। प्राथमिक एल्यूमीनियम के साथ अपने उत्पादों के निर्माण में सिल्ली प्रमुख कद्दा माल अक्सर उत्पादन की लागत (सीओपी) का  $>90\%$  का गठन किया है।
- ख. अध्याय 7601 के तहत उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए उल्टे शुल्क ढांचे का नेतृत्व करेगा जोकि उनकी क्षमता उपयोग और फायदे के लिए खतरा होगा।
- ग. सिल्लियों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल मूल्य वर्धित उत्पादों को छोड़कर इस सिगमेंट में लगे हुए बहुत से निर्माताओं को प्रभावित करेगा। इस डाउनस्ट्रीम इकाइयों को अप्रतिस्पर्धी प्रस्तुत करना होगा; तैयार माल के आयातों को बढ़ावा देना होगा क्योंकि हजारों लोगों की अपनी नौकरी के खोने का खतरा रहता है।
- घ. सिल्लियों से वॉयर रॉड की परिवर्तन लागत, आमतौर पर, सिल्लियों की लागत का कम से कम 5% है। इसलिए, सिल्लियों पर केवल @ 5% (या अधिक) ही रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होगा लेकिन वॉयर रॉड पर नहीं, संभावित, भारत में कारोबार में से सभी वॉयर रॉड निर्माण बाहर हो जायेंगे - यह सीधे वॉयर रॉड (सिल्लियां 5% से भी कम ड्यूटी पर) आयात करने के लिए स्थानीय स्तर पर सिल्लियों को खरीदने और वॉयर रॉड में परिवर्तित करने की तुलना में भारी आर्थिक रूप में संवेद होगा। भारत प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक वॉयर रॉड टन का उत्पादन करता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण सेगमेंट की अर्थक्षमता और हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- ड. यदि सिल्लियों के लिए रक्षोपाय शुल्क माना जाता है, तब रक्षोपाय के अधिरोपण के लिए वॉयर रॉड के बराबर माना जा सकता है।
- प. मे. पोलीकैब वॉयर प्रा0लि0
- क. वे केवल निर्माणकर्ता हैं। केवल उद्योग के विकास के लिए रक्षोपाय शुल्क हानिकारक होगा।
- ख. सभी केवल निर्माताओं के लिए पर्याप्त आदेश में परिणास्वरूप विजली क्षेत्र में सुधार हुआ है और परिणामतः दोनों स्वदेशी और आयातों पर मैटल की मांग में मजबूती आई है।
- ग. पिछले दो वर्षों के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण स्क्रैप आयात की वृद्धि हुई है और स्क्रैप (2.5%) एवं प्राथमिक धातु (7.5%) पर आयात शुल्क के बीच 5% का अंतर शुल्क है।

- घ. गलत मूल्य निर्धारण नीति के कारण, स्थानीय उत्पादकों को भारी अंतरीय शुल्क के कारण पकड़ने में सक्षम नहीं है।
- ड. स्थानीय उत्पादक किसी भी उपभोक्ता को मैटल उपलब्ध नहीं कर रहे हैं जो मैटल निर्यात कर रहे हैं इसके परिणामस्वरूप शुल्क फैक्टर में घाटा हुआ है जोकि प्राथमिक उत्पादक द्वारा आरोप लगाया जा रहा है।
- च. स्थानीय उत्पादक मूल्य निर्धारण तंत्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं हैं जिसका विश्व स्तर पर पालन हो रहा है जबकि सामग्री को बढ़े हुआ मूल्य निर्धारण फार्मूले पर बेचा जा रहा है जिससे उत्पादकों को पूरा लाभ हुआ है। जब कीमत बढ़ती है तब उत्पादक आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कीमतों में गिरावट की स्थिति में उत्पादक उनकी कीमतों को संशोधित नहीं करते हैं।
- छ. यदि उपभोक्ता अग्रिम लाइसेंस के तहत खरीदना चाहते हैं तो वहां घरेलू उद्योग में कोई आपूर्तिकर्ता नहीं है और उपभोक्ता के पास आयात करने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है।
- ज. घरेलू एल्यूमीनियम उद्योग आयात समता मूल्य निर्धारण मॉडल का पालन कर रहे हैं। वे उद्योग और स्थानीय प्रयोगकर्ताओं को 7.5% गुणा शुल्क (हाल के बजट में 5% से वृद्धि की) फैक्टर लगाते हैं।
- झ. रक्षोपाय अन्य उद्यमों के वैध व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल परिमाण जनहित को प्रभावित करेगा और मंहगाई बढ़ने का कारण होगा।
- ञ. उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई विनिमय दर लगाया जा रहा है। ईंधन की कीमते 70% कम हुई हैं जबकि स्थानीय उत्पादकों ने मालभाड़ा कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं।
- ट. मे. नालको, प्रमुख उत्पादकों में से एक को याचिकाकर्ताओं में शामिल नहीं किया है इसलिए डीआई रूपमें उनकी योग्यता का दावा संदिग्ध है।
- ठ. आयातों के कारण डीआई का लाभ और उत्पादन में कमी नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलएमई और एमजेपी की कीमतों में कमी के कारण हुई है। पिछले पांच वर्षों में एमजेपी कीमत बढ़ी हैं परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादकों को भारी मुनाफा एकत्रित हुआ है। हाल ही में एमजेपी में गिरावट आई है लेकिन किसी अन्य देश ने आयात शुल्क न लगाया या न बढ़ाया है।
- ड. लाभप्रदता और हानि में कमी आगे विस्तार को ठहराया है, कंपनियों द्वारा आंतरिक पुनर्गठन और व्याज लागत वृद्धि में विस्तारपूर्वक परिणाम आया है। मुख्यतः डीआई द्वारा कमियों का दावा किया है क्योंकि सरकार से बॉक्साइट खदानों और कोयला आवंटन नहीं मिल रहा है और उनके अनायोजित और विशाल पूंजी खर्च पर भारी व्याज का बोझ बढ़ा है।
- ढ. माध्यमिक एल्यूमीनियम मिश्र धातु और रिमेल्टेड एल्यूमीनियम सिल्लियों पर आयात शुल्क, प्राथमिक एल्यूमीनियम @ 7.5% के ऐवज में एल्यूमीनियम स्क्रैप वर्तमान में 2.5% है जोकि देश में पीयूसी की बिक्री प्रभावित कर रही है। मामले में इन्हें रक्षोपाय से बाहर रखा गया है ताकि आयात आगे बढ़े।
- ण. निर्यात पात्रता के ऐवज में आयात घटाने के बाद शुद्ध आयातों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आयात डॉटा लगता है कि अध्याय 76 के तहत सभी उत्पादों को शामिल किया है। संपूर्ण डॉटा की बजाय क्रमाँक डॉटा उपलब्ध है इस रूपमें तुलना करना असंभव है।
- त. पीयूसी के आयातों का मूल्यांकन करते हुए एडीसी 12 जैसी विशेष ऑटोमोबाइल ग्रेड जोकि डीआई द्वारा उत्पादित नहीं है और भारी मात्रा में भी आयात किया जा रहा है, को अलग से विचार किया जाना चाहिए।
- थ. जिस समय मे. नालको निर्यात एल्यूमिना, वेदांता उसी बंदरगाह से एल्यूमिना आयात कर रहा है, जबकि डीआई की लागत को नीचे लाने के लिए देखा जाना चाहिए।
- द. क्योंकि अपनी लांजीगढ़ परियोजना वेदांता के लिए बॉक्साइट की अनुपलब्धता की लोडिंग हो रही है यह कॉपेक्स अप्रयुक्त लागत खर्च है और जिससे घाटा देखा जा रहा है।

- ध. याचिकाकर्ताओं ने अधिक मुनाफा कमाने हेतु मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए उनको थोक में गलाने की क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और सिल्लियों की मात्रा डीआई द्वारा की कमी के कारण आयात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
- न. उच्च शुद्धता के साथ सिल्लियां आयातित करते समय डीआई से उत्पाद की गुणवत्ता हीन है (कम चालकता और शुद्धता के साथ वाणिज्यिक ग्रेड के बराबर है) और चालकता उपलब्ध है।
- प. आयात के कारण वहां कोई हानि नहीं हुई है लेकिन मोटे तौर पर उत्पादकों के बिक्री मूल्य की गिरावट के उत्प्रेरण के एलएमई और एमजेपी कीमत गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
- फ. डीआई के बाजार शेयर आयत वृद्धि के साथ समानुपाती में बढ़ी है। आयात में मामूली वृद्धि अधिसूचित विजली परियोजनाओं के लिए शून्य शुल्क पर आईसीबी के तहत निर्यात और खरीद से जुड़े होने की संभावना है।
- व. विदेशी उत्पादकों की ऊर्जा की लागत वास्तव में काफी हद तक कम कर दिया गया है और इसे "अनापेक्षित" नहीं माना जा सकता।
- भ. डीआई उच्च माल दुलाई लागत लगाते समय तक आयातित पीयूसी बहुत कम माल दुलाई लागत पर आता है।
- म. रक्षोपाय शुल्क के किसी अधिरोपण उपयोगकर्ता उद्योगों में रोजगार और देश में आर्थिक गतिविधि के नुकसान होने पर अग्रणी को बंद करने का नेतृत्व करेंगे और केवल जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का आयात होता है।
- य. तैयार माल पर बुनियादी सीमा शुल्क छूटी 0% से 7.5% है जबकि एल्युमीनियम भी 7.5% बीसीडी आकर्षित करती है। कंडक्टर, केवल और केपिसिटर निर्माता के लाभ का अंतर अत्यंत कम है। यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तब विशेषतः चीन से कंडक्टर, केवल, और केपिसिटर के आयातों से भारतीय बाजार अभिभूत होगा, अनुप्रवाह निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे विशाल वेरोजगारी और सामाजिक अशांति पैदा हो रही है, परिणामतः उद्योग बिमार हो रहे हैं।
- कक. रक्षोपाय शुल्क का प्राधिभार केवल और कंडक्टर निर्माताओं के लागत में एक आनुपातिक वृद्धि में परिणाम होगा और आयातित केवल और कंडक्टर भारतीय बाजार अभिभूत होगा।
- खख. उपयोगकर्ता उद्योगों के बंद होने के कारण भारतीय एल्युमीनियम उत्पादकों के लिए रक्षोपाय शुल्क काउंटर उत्पादक साबित होगा।
- गग. आर्थिक रक्षोपाय शुल्क अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का काउंटर उत्पादक होगा और यह उत्पादों की लागत में वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं, ऑटोमोबाइल आदि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मांग को प्रभावित करेगा।
- फ. मे. हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
- क. भारत में 400 से अधिक कंडक्टर निर्माण होने से बहुत रोजगार पैदा हो रहे हैं। कंडक्टर उद्योग परिचालन आमतौर पर लॉ सिंगल डिजिट उनके लिए इसे असंभव परिचालन मार्जिन बनाने के साथ अतिरिक्त लागत को आमेलन करने के लिए बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चल रही है।
- ख. भारतीय कंडक्टर निर्माताओं को अंतर्निहित असुविधा बनाम उनकी वैश्विक पिअर्स निर्गत स्केल, परिवर्तनीय कीमत, उच्च ब्याज लागत और सीएसटी @2% की अर्थव्यवस्थाओं से हुई है जोकि आयातों पर लागू नहीं है।
- ग. कच्चे माल पर केवल रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होगा लेकिन 5% द्वारा उत्पादन की लागत में कंडक्टरों पर वृद्धि नहीं होगी जबकि भारत में कंडक्टरों का उत्पादन अलाभकारी होगा। यह चीन और मध्य पूर्व जैसे देशों से आयातों की बाढ़ का नेतृत्व करेंगे।

- घ. यदि प्राथमिक एल्यूमीनियम पर रक्षोपाय शुल्क माना है, तब स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कंडक्टरों पर उच्च शुल्क पर विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा यह लगभग निश्चित है कि यह बंद हो जायेगा।
- ब. मे. ओसवाल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
- क. वे एल्यूमीनियम कंडक्टर, केबल आदि के निर्माता हैं और एल्यूमीनियम सिल्ली / रॉड उनके प्रमुख कच्ची सामग्री हैं।
- ख. घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों की आड में तीन कंपनियों नामतः वेदांता, बालको और हिन्डालको द्वारा याचिका दायर की है जबकि वे निजी क्षेत्र में हैं। देश में मुख्य उत्पादकों में से एक, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मे. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) याचिका में पार्टी नहीं है।
- ग. रक्षोपाय शुल्क के आवरण के तहत अनुचित लाभ हासिल करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए व्यवसायी समूह ने याचिका दायर की गई है।
- घ. हाल के बजट में, बुनियादी सीमा शुल्क 5.0 से 7.5% बढ़ाया गया है और कठिनाई को पहले से ही संकलित किया गया है। आगे रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने से शुल्क संरचना में उल्टा परिणाम होगा।
- ड. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है वे बहुत कठिनाई महसूस करेंगे; भारी नुकसान होगा; कर्मचारियों की छंटनी के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह उद्योग के विकास के लिए अत्यंत निवारक होगा और खपत उद्योग अप्रतिस्पर्धी बन जायेगा परिणामस्वरूप तैयार माल की आयातों में वृद्धि होगी। उनकी जैसी एसएसआई इकाईयों की बड़ी संख्या बुरी तरह से हिट होगी।
- च. देश में एल्यूमीनियम धातु के आयात अधिकांशतः शुल्क मुक्त लाइसेंसों के खिलाफ हैं, निर्यातों के खिलाफ निर्यात प्रोत्साहन (शुल्क मुक्त कच्ची सामग्री आयात करने के लिए) रूप में पेशकश की और ऐसे आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह घरेलू एल्यूमीनियम प्रयोग करने वाले उद्योग को हिट करेगी जो बहुमूल्य कच्ची सामग्री बना रही हैं।
- छ. मिश्रित सिल्लियों के संयुक्त आयात द्वारा याचिकाकर्ताओं ने भ्रामक डॉटा डाल दिया है जोकि स्कैप से बनाया गया है और एएसईएएन से शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।
- ज. घरेलू मांग में वृद्धि अवधि से अधिक सकारात्मक होने की तुलना में एल्यूमीनियम धातु के आयात में नाममात्र की वृद्धि हुई है।
- झ. रक्षोपाय शुल्क के आवरण के तहत, कीमते बढ़ाने से डीआई अनुचित लाभ हासिल करना चाहता है। खपत बंदी उत्पादन भी घरेलू बिक्री के रूप में माना जाना चाहिए।
- ञ. डीआई की उपयोगी क्षमता निष्पक्ष है और एसईजेड (केवल निर्यात के लिए ही बने) में स्थित इकाईयों की क्षमता उपयोग जोड़ करके वे अनावश्यक रूप से कम क्षमता दर्शाया है साथ ही साथ सामाजिक-कानूनी मुद्दों के कारण गैर क्षमता बनाया गया है।
- ट. उद्योग करीब 60% एल्यूमीनियम की खपत करता है, जिनमें से अधिकतर बिजली सैक्टर को चला जाता है - देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। लागत में वृद्धि का बोझ रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के कारण अंततः यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को पारित कर दिया जायेगा। भारत सरकार / राज्य सरकारों के रुरल एलेक्ट्रिफिकेशन, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम उपग्रेडेशन आदि कठोर हिट होगी।
- ठ. उच्च क्षमता उपयोग के साथ याचिकाकर्ताओं का संबंध नहीं है या लागत में कमी की कार्यवाही कर रही है लेकिन रक्षोपाय शुल्क के आवरण के तहत अनावश्यक रूपसे उनका लाभ बढ़ाने के लिए है।

- ड. अपने उद्योग के एक बड़े कार्यबल को रोजगार और 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पर्याप्त वित्तीय पहुंचाया गया है जोकि रक्षोपाय शुल्क के प्राधिभार द्वारा बहुत प्रभावित भी हो जाएगा।
- ढ. एल्यूमीनियम का एलएमई कीमत में उतार-चढ़ाव कोई मुद्दा नहीं है इस रूपमें यह देश विर्द्धनिष्ट नहीं बल्कि एक वैश्विक घटना है। एल्यूमीनियम का एलएमई की कीमतों पर प्रीमियम के बारे में उठाया गया मुद्दा बिल्कुल अस्पष्ट है और रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण का समर्थन करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं मिली है। लाभ के लिए प्रीमियम का मतलब नहीं है लेकिन केवल लोजिस्टिक और मूल्य परिवर्धन लागत आवरण करना होगा।
- ण. भारतीय उत्पादकों का स्थानीय स्तर पर सस्ता कच्चे माल का बहुत लाभ है जबकि विश्व स्तर पर एल्यूमीनियम के उत्पादकों की सबसे ऊँची कीमत आयात पर निर्भर करता है।
- त. लाभ अनुकूल विनिमय दर आईएनआर की तुलना में यूएसडी के कारण डीआई को प्रोद्भूत लाभ हुआ है, घरेलू उत्पादकों द्वारा भारतीय रूपयों में वास्तविक विक्री मूल्य पहुंचा गया है।
- थ. कीमतों में वैश्विक गिरावट, अधिक क्षमता आदि स्थानीय उद्योग को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। इन मुद्दों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा संचालन, आधुनिकीकरण और लागत-कटौती के उपायों में दक्षता हासिल करने के द्वारा हल करना साथ ही साथ खपत वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
- भ. मे. डाइनैमिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड; स्मिता कंडेक्टरस प्राइवेट लिमिटेड; केजेवी एलोए कंडेक्टरस प्राइवेट लिमिटेड; एल्को एल्क्ट्रोस्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड; शिव इंटरप्राइसेस; ट्रंस सोलुशन।
- क. अध्याय शीर्षक सं 7601 के तहत सिल्लियों में आने वाली गिरावट लेकिन / या अध्याय शीर्षक 7605 के तहत आने वाले वॉयर रॉड अपने उत्पादों के निर्माता में कच्ची सामग्रियां मुख्य हैं अर्थात् अध्याय शीर्षक सं. 7604 के तहत कंडक्टरों की गिरावट प्राथमिक एल्यूमीनियम के साथ अक्सर उत्पादन की लागत का >80% गठन होता है।
- ख. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल सिल्लियों पर लगेगा और वॉयर रॉड्स पर नहीं, छोटे कंडक्टर बनाने वालों पसंदीदों को प्रभावित करेगा।
- ग. सिल्लियों से वॉयर रॉड्स की रूपांतरण लागत सामान्यतः सिल्लियों की लाग का कम से से कम 5% है। अतः रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल सिल्लियों पर लगेगा लेकिन वॉयर रॉड्स पर नहीं, भारत में वॉयर रॉड के निर्माताओं को व्यवसाय से बाहर कर देगा। स्थानीय स्तर पर सिल्लियों को खरीदने की तुलना में यह सीधेतौरपर भारी अर्थिक संवेद रूपमें और भारत में वॉयर रॉड में परिवर्तित होगा।
- घ. कीमतों में अस्थिरता के कारण अंतर्निहित जोखिम और कार्यशील पूँजीगत सीमाओं के कारण छोटे कंडक्टर निर्माता को यह असंभव वॉयर रॉड सीधेतौर पर आयात करने के लिए मिल जाएगा। वे सिल्लियों और वॉयर रॉड के बीच में बहुत अधिक अंतर होने से स्थानीय स्तर पर बल्पूर्वक खरीद की जाएगी।
- ङ. कंडक्टर उद्योग में बड़े खिलाड़ी सीधेतौर पर वॉयर रॉड आयात के लिए अनुचित लाभ पाने को सक्षम हो जायेंगे। छोटे खिलाड़ी को बिना आदेश के ही बंद का सामना करना पड़ेगा।
- च. सिल्लियां और वॉयर रॉड्स, कंडक्टर निर्माताओं के लिए दोनों कच्ची सामग्री होने के कारण, युगपत के लिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के बराबर माना जा सकता है। रक्षोपाय शुल्क भी कंडक्टर (सीटीएच 7604) पर लगाया जा सकता है।
- म. मे. कैर्ल्स इंटरनेशनल लिमिटेड
- क. वे 220केवी रेंजिंग पॉवर केबल्स का निर्माण करते हैं। वे पॉवर ट्रॅंजमिशन लाइनों के लिए इंजिनियरिंग, प्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) के ठेके के निष्पादन में लगे हुए हैं।

- ख. भारत में पॉवर ट्रंजमिशन लाइन परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में, वे भारतीय निर्माताओं से एल्यूमिनियम कंडक्टर्स खरीदते हैं।
- ग. कंडक्टर करीब 70% से 80% एल्यूमिनियम निहित है, उसके द्वारा कंडक्टर की लागत मुख्य रूप से एल्यूमिनियम की कीमत पर निर्भर है। एक प्रारूपिक पॉवर ट्रंजमिशन लाइन परियोजना कंडक्टर में कुल परियोजना लागत का लगभग 30% शामिल हैं। एल्यूमिनियम की कीमतों में कोई वृद्धि समग्र परियोजना के लाभप्रदता पर गंभीर असर डालेगा।
- घ. आम तौर पर ईपीसी परियोजनाओं प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सम्मानित किया जाता है और ईपीसी ठेकेदारों के लिए मार्जिन बहुत कम हैं।
- इ. भारत में देरी से पॉवर उपयोगता निर्धारित मूल्य के ठेके और कंडक्टर में मूल्य वृद्धि के लिए जोर दे रहे हैं विजली उपयोगिताओं को पारित नहीं किया जा सकता।
- च. विजली वॉयर एल्यूमिनियम का लगभग 60% का समावेश है। विजली वॉयर उद्योग वेफर पतली लाभप्रदता और पास होने की परिचालित संभावना पर लागत में वृद्धि बहुत दूरवर्ती है।
- छ. अब से चीन एल्यूमिनियम का मूल्य वर्धित उत्पादों पर कर छूट है, वहाँ चीन से निर्यात बढ़ोतरी की उच्च संभावना है। भारत में केबल्स उद्योग का परिचालन ठप्प हो सकता है।
- ज. याचिका वास्तव में दो कॉर्पोरेट समूहों द्वारा दायर की गई हैं और मे. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) याचिका में पार्टी नहीं है।
- झ. छ्यूटी-प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए डी.आई.स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। उनका इरादा ग्राहकों से उच्चतर आयात समानता मूल्य हासिल करना और खपत करने वाली कम्पनियों के बलबूते लाभप्रदता को बढ़ावा देना है। बजट में, पहले हीं अल्यूमिनियम धातु पर सीमा शुल्क 5% से 7.50% कर दिया गया है और सभी घरेलू अल्यूमिनियम उत्पादकों ने उस हद तक अपनी कीमतें बढ़ा दी है।
- ज. ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में गिरावट; अत्यधिक क्षमता आदि जो बातें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई हैं; ये ढाँचागत मुद्दे हैं और जिनका निवारण इंडस्ट्री द्वारा किया जाएगा।
- ट. खपत करने वाली उद्योग धर्थों की बड़ी संख्या के बलबूते; रक्षोपाय द्वारा छ्यूटी प्रोटेक्शन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की मंजूरी देना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है।
- थ. **मेसर्स मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।**
- क. यह अभ्यावेदन केवल मेसर्स हिंडाल्को, बाल्को और बेदांता द्वारा किए गए हैं और मेसर्स नाल्को द्वारा नहीं किए गए हैं।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने अपने ऑपरेशनों में नुकसान की बात बताई है लेकिन नियमित अंतरालों पर वे नई संयंत्रों की स्थापना कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।
- ग. अल्यूमिनियम मूल्य-निर्धारण एल.एम.ई. से जुड़ा हुआ है जो की वैश्विक माँग और आपूर्ति की स्थिति के कारण या तो कम अथवा अधिक होता है और इसलिए इसमें कभी नुकसान अथवा कभी लाभ भी हो सकता है।
- घ. सीमा शुल्क को बढ़ाकर 5 प्रतिशत से 7.5 % करने के कारण; डी आई द्वारा अल्यूमिनियम उत्पादों की कीमत अंततः बढ़ाया गया ताकि इसे आयात-मूल्य के समतुल्य किया जा सके। डी आई द्वारा कीमतें कम रखनी चाहिए ताकि कोई आयात नहीं किया जा सके।
- झ. एम.एस.एम.ई. के लाभ के लिए फ्री-ट्रेड-अग्रीमेंट-देशों से आयात किए गए सभी अल्यूमिनियम उत्पादों पर और अल्यूमिनियम से तैयार किए गए सभी उत्पादों जैसे अल्यूमिनियम एक्सट्रुजन; सर्कल्स; तैयार आकृति में अल्यूमिनियम शीटों एवं सभी गेजों में फॉयलों तथा सभी देशों से मँगाए गए और विशेषकर चीन से मँगाए गए अल्यूमिनियम वायर रॉड पर रक्षोपाय शुल्क लगाना चाहिए।

च. एम.एस.एम.ई. अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएँगे यदि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की गई क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन है।

**कक. रशियन फेडरेशन; आर्थिक विकास मंत्रालय**

- क. 5 प्रतिशत शुल्क लगाने की सिफारिश से संबंधित चिंता उनके द्वारा व्यक्त की गई है।
- ख. जांच की शुरुआत एवं अस्थायी उपाय लागू करने से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में साक्ष्य का अभाव है।
- ग. प्राइमरी इनांट्स कमोडिटी (ए.7.ई.पी 1020, ए.यू. कान्टेंट >99%) एवं सभी अलॉय (ए.एल.यू. कान्टेंट <99%) अन्वेषण के अधीन है। शीर्ष 7601 के अधीन के उत्पाद अन्तर-परिवर्तनीय नहीं हैं क्योंकि बिलेट्स एवं अलॉय की प्रोसेसिंग एवं एन्ड यूज अलग-अलग है।
- घ. विचाराधीन उत्पादन का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है। भारत कमॉडिटी 76011010 का शुद्ध निर्यातक एवं कमॉडिटी 76012010 का शुद्ध आयातक है।
- ड. याचिका में, आयात की मात्रा की गणना गलत रूप में की गई है।
- च. कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में, आयात की मात्रा की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्ष 2011-2016 की अवधि के दौरान माँग में 659,3 एम.टी. की अथवा 29% की बढ़ोतरी हुई है। इसी समान अवधि में, कुल भारतीय उत्पादन 676 एमटी की अथवा 46.25% की वृद्धि हुई और याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में 76.22% की वृद्धि हुई। इसलिए आयात की मात्रा में उत्पादन की तुलना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- छ. डब्लू.टी.ओ विवाद निपटान (अर्जेंटीना में, फुटवियर के आयात पर विशेषकर पैनल रिपोर्ट) में यह स्पष्ट किया गया है कि “इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्रा” का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि पिछले साल की आयात की मात्रा का मैथ्रेमेटिकल इन्ड-ट्रू इन्ड-प्वाइंट अथवा पाँच वर्ष की अवधि के लिए तुलना हो। डब्लू.टी.ओ रक्षोपाय शुल्क संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद XIX:1(क) जी.ए.टी.टी. में यह बताया गया है कि आयात में बढ़ोतरी “अनपेक्षित” होनी चाहिए; अत्यंत पर्याप्त होनी चाहिए और मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तौर पर पूरी तरह से “महत्वपूर्ण भी” होनी चाहिए।
- ज. “अनपेक्षित घटनाओं” जैसे परिभाषित किए गए कारक भी इतने अप्रत्याशित एवं अदृश्य नहीं थे जैसा कि आवेदनकर्ताओं द्वारा बताया गया है।
- झ. वर्ष 2011 में; एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट की शुरुआत दुनिया में हुई और चीन में एल्यूमिनियम खपत में कमी आने की पूरी संभावना थी और यह दीर्घकाल प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है वर्ष 2011 में इसकी झलक दिखी थी।
- ञ. वर्ष 2010 में, मध्य पूर्व में बढ़ती हुई क्षमता का पूर्वानुमान यू.एस. मिनिस्ट्री ऑफ द इन्टेरियर के मिडिल ईस्ट जियोलाजिकल सर्वे द्वारा किया गया था।
- ट. भारत में, हुए व्यापक-खपत-बढ़ोतरी के कारण आयात में वृद्धि निर्धारित की गई है न कि किसी प्रकार की अनपेक्षित घटना के कारण यह हो पाया है।
- ठ. वर्ष 2007 से, हीं एल्यूमिनियम खपत में बढ़ोतरी की दृष्टि से चीन और भारत को अग्रणी माना जा रहा है। भारत एल्यूमिनियम खपत की दौड़ में अग्रणी रहा है क्योंकि इस धातु की माँग इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इंजीनियरी, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एवं पैकेजिंग में है।

- ड. याचिका में डी.आई. के बताए गए कारकों का जो विश्लेषण किया गया है उससे इस सुदृढ़ तर्क की पुष्टि नहीं हो पाती है कि भारतीय उधोग-जगत को भारी नुकसान हुआ है।
- ढ. वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी में हुई गिरावट से यह मात्र 1.53% तक हीं पहुँच पाया है और इसका कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी एवं चीन का सस्ता आयात है।
- ण. प्राइस अंडरकटिंग: भारतीय एल्यूमिनियम के ऊँचे मूल्य का कारण उत्पादन में, ऊँची लागत का होना है। उत्पादक; पर्यावरण शुल्क के साथ ऊँची लागत को जोड़ रहे हैं जिनकी मात्रा 29 फरवरी, 2016 को दोगुनी हो गई।
- त. भारतीय उत्पादकों के लाभ में गिरावट का मुख्य कारण; अल्युमिनियम की कीमत में भारी कमी के साथ-साथ भारत में ऊर्जा लागत का ऊँचा होना है। इन मिले-जुले कारणों से राजस्व की गंभीर क्षति हुई है। जुलाई 2016 में कोरबा में पुनः उत्पादन की शुरुआत होगी।
- थ. अन्य धातुओं के उत्पादन से भी याचिकाकर्ता जुड़े हैं। इन डोमेनों में कार्यकलाप से नकारात्मक वित्तीय परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- द. घरेलू उधोग-लाभ के मुल्यांकन की गिरावट में वर्ष 2014-2015 से वर्ष 2015-2016 की तीसरी तिमाही तक 30% तक की अल्युमिनियम की कीमतों में गिरावट के प्रभाव के विश्लेषण में, ऊँची उत्पादन लागत; क्षमता विस्तार में वित्तीय निवेश और शेर्यर निवेश एवं क्रेडिट कार्डों का उपयोग करते हुए लाभ के अनुसार भुगतान के विश्लेषण को भी शामिल करना चाहिए।
- ध. वर्ष 2011-12 और 2015-2016 की तुलना में, याचिकाकर्ता का आंकड़ा यह दर्शाता है कि इन्वेटरी में 51 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में खपत बढ़ गई है और घरेलू उधोग को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है।
- न. कॉंजल लिंक: अल्युमिनियम एक एक्सचेंज ट्रेड कमोडिटी है और इसका मूल्य मुख्य तौर पर वैश्विक बाजार में आपूर्ति और माँग पर निर्भर करता है। डी.आई. क्लेम के कंपनी प्रतिनिधियों के अनुसार; अल्युमिनियम इंडस्ट्री के वित्तीय परिणामों पर बाह्य कारकों का नकारात्मक असर होता है। वैश्विक बाजार में; वर्तमान अति-आपूर्ति के अंतर्गत अल्युमिनियम की कीमतों में तेजी से गिरावट हुई और जिसके फलस्वरूप अल्युमिनियम की विक्री में कमी; लाभ में कमी एवं नुकसान का यह मुख्य कारण बना। डी.आई. सबमिशन के अनुसार इसमें आगे बताया गया है कि भारतीय कम्पनियों में प्रोसेस यूटिलाइजेशन के सार-तत्व के अनुसार वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक भारतीय कंपनियों में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और समग्र उत्पादन में 48.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा स्टाफ का विकास हुआ एवं इसमें 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। इस अन्वेषण की अवधि की विशेषता इस रूप में महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अरब अमीरात; साउथ अफ्रीकन-रिपब्लिक एवं ओमान के सस्ते आयात में भारी बढ़ोतरी एवं चीन के नकली-सेमियों द्वारा सस्ता आयात भी इस दौरान किया गया।
- प. डी. आई. के लिए गंभीर नुकसान की कमी है और भारतीय कंपनियों के लिए उनके वित्तीय परिणाम पर नकारात्मक असर की शुरुआत अल्युमिनियम वर्ल्ड-प्राइस से होती है।

#### **ख ख रशियन फेडरेशन; उधोग एवं व्यापार मंत्रालय**

- क. पी.यू.सी. के आयात में; समान उत्पाद की घरेलू उत्पादन की तुलना में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की कमी है।

- ख. पिछली अवधियों की तुलना में; कुल खपत में आयात एवं घरेलू पी.यू.सी. का अनुपात कमो-बेश समान स्तर पर रहा है। खपत में भारतीय उत्पाद की हिस्सेदारी में 3 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक की कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादकों पर प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- ग. वर्ष 2011-2016 के दौरान खपत में, आयात की हिस्सेदारी बहुत हद तक स्थिर रही है और घरेलू उधोग एवं अन्य उत्पादकों के बीच एक बाजार पुनर्वितरण था।
- घ. भारत में; पी.यू.सी. के घरेलू उत्पादन की तुलना में; अल्युमिनियम के आयात में विकास का कोई साक्ष्य नहीं है कि वह डी.आई. को गंभीर नुकसान की सीमा तक प्रभावित कर सकता है।
- ड. रक्षोपाय अन्वेषण की शुरुआत को न्यायोचित बताने हेतु पी.यू.सी. के आयात में, अप्रत्याशित एवं नाटकीय बढ़ोतरी होनी चाहिए। डब्ल्यू.टी.ओ. विवाद निपटान निकाय के केस-लॉ के अनुसार आयात में, हाल ही में व्यापक बढ़ोतरी; अचानक बढ़ोतरी, बहुत तेजी से बढ़ोतरी तथा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों स्तर पर पर्याप्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। वर्ष 2015-2016 में, पी.यू.सी. के आयात में हुई बढ़ोतरी को किसी भी प्रकार से तेजी एवं व्यापक से हुई बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता है।
- च. डोमेस्टिक रिस्पोन्स की “असाधारण प्रकृति” इस तथ्य पर निर्भर करती है कि बढ़ी हुई आयात अदृश्य एवं अप्रत्याशित थी। पी.यू.सी. के आयात में हुई बढ़ोतरी को पूरी तरह से अदृश्य एवं अप्रत्याशित नहीं माना जा सकता है क्योंकि उदाहरण के लिए; चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट अप्रत्याशित नहीं थी और इसका पूर्वनुमान विशेषज्ञों द्वारा मौटे तौर पर लगाया गया था।
- छ. गंभीर नुकसान होने के साक्ष्य के बारे में, निदेशालय अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में यह बताने में असफल रहा। पी.यू.सी. के आयात में, पूर्णता अथवा सापेक्षता की दृष्टि से भारत के घरेलू उत्पादन की मात्रा से तुलना करने पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जिससे डी.आई. को कोई गंभीर नुकसान पहुँच सके।
- ज. वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान, भारत के घरेलू बाजार में पी.यू.सी. के आयात की हिस्सेदारी में बहुत थोड़ी बढ़ोतरी; भारतीय बाजार में अल्युमीनियम की माँग को पूरा करने के कारण हुई। वर्ष 2011 से 2016 की अवधि में, घरेलू उधोग की बिक्री के स्तर में 40% तक की बढ़ोतरी हुई जबकि सभी उत्पादकों के समान उत्पाद की बिक्री के स्तर में 23% की बढ़ोतरी हुई।
- झ. वर्ष 2011 से 2016 की अवधि में घरेलू उधोग ने पी.यू.सी. के उत्पादन में महत्वपूर्ण 76% की बढ़ोतरी हासिल की जो यह दर्शाता है कि उधोग के विकास में सकारात्मक गतिशीलता थी। सभी भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमता एवं समग्र खपत की तुलना; सकल तौर पर सभी भारतीय उत्पादकों की पी.यू.सी. के उत्पादन से तुलना करने के बजाय आवेदनकर्ताओं की उत्पादन क्षमता से तुलना करके निदेशालय ने एक तकनीकी गलती किया।
- ञ. वर्ष 2015-16 में, भारतीय उत्पादकों की क्षमता-उपयोगीकरण 87% के उच्च स्तर पर बरकरार रहा।
- ट. भारतीय उत्पादकों के लाभ एवं हानि से संबन्धित डेटा अपारदर्शी है। वर्ष 2012-14 की अवधि में, भारतीय घरेलू उधोगों का मुनाफा पहले से ही नकारात्मक (-4%) रहा था। इसलिए यह माना भी जाए कि घरेलू उधोग को कोई गंभीर नुकसान हुआ है तो यह भी वर्ष 2015-16 में नहीं हो सकता है बल्कि इसे पिछले वर्षों के दौरान होना चाहिए। डी.आई. की लाभप्रदता में कमी का कारण शायद क्षमता-उपयोगीकरण के निरंतर विकास का परिणाम है जो बिना लागत वसूली किए बगैर हुआ है।
- ठ. वर्ष 2011-12 वित्तीय वर्ष की स्थिर स्थिति से; वर्ष 2015-16 वित्तीय वर्ष की पी.यू.सी. के के स्टॉकपाइल्स की स्तर से तुलना करने पर क्षमता उपयोगीकरण में वृद्धि के बाबजूद 51 प्रतिशत की कमी हुई है।

- ड. वर्ष 2011-12 में, प्रति व्यक्ति उत्पादकता 77 टन था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 129 टन प्रति व्यक्ति उत्पादकता तक बढ़कर खास तौर पर पहुँचा और अन्वेषण की अवधि के दौरान; रोजगार दर में 11 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी।
- ढ. पी.यू.सी. की खपत में, डी.आई. की हिस्सेदारी स्थिर रही है जो यह दर्शाता है कि गिरावट का अभाव रहा है तथा डी.आई. को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है।
- ण. घरेलू बाजार की पी.यू.सी. की विक्री-मूल्य की तुलना में, भारतीय उत्पादक, उत्पाद का निर्यात-अपेक्षाकृत कम मूल्य पर कर रहे हैं। घरेलू उधोग को हुए तथाकथित नुकसान का कारण शायद पी.यू.सी. की निर्यात-विक्री का हानि अनुपात हो सकता है चूँकि भारत से हुए निर्यात में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।
- त. आर्थिक आंकड़ा स्पष्ट तौर पर; बढ़ी हुई आयात एवं भारत की घरेलू उधोग-धंधों को हुए तथाकथित नुकसान के बीच अस्थायी संपर्क-सूत्र का अभाव दर्शाता है।
- थ. केवल गंभीर परिस्थितियों में, ही अस्थायी रक्षोपाय कदम उठाए जा सकते हैं जहाँ देर होने से ऐसी क्षति होने की आशंका हो जिसको दूर करना कठिन हो। आयात के अचानक और तीव्र बढ़ोतरी द्वारा घरेलू उधोग की किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था; तदनुसार अस्थायी रक्षोपाय कदम का उठाया जाना; एस.जी. करार के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है।

#### **गग संयुक्त अरब अमीरात**

- क. पी.यू.सी. का स्कोप बनावटी तौर पर आयात के डेटा को बढ़ा देता है जो कि भ्रमित करने वाला है चूँकि इसमें अलॉय इनगोट्स का डेटा शामिल है जिसका उत्पादन आवेदनकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है। गैर अलॉयड इनगोट्स से संबंधित आयात पर, आयात संबंधी डेटा, आधारित होना चाहिए।
- ख. उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों के संबंध में उत्पाद; अंतर परिवर्तनीय उत्पाद नहीं है। टैरिफ वर्गीकरण केवल एक सूचक की तरह है परन्तु यह एकमात्र निर्धारक/निर्णायक कारक नहीं है। पी.यू.सी. का स्कोप सीमित किया जाना चाहिए।
- ग. डी.आई. की परिभाषा उन लोगों का उल्लेख करता है जो “समान” अथवा “सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद” का उत्पादन करते हैं जबकि आवेदनकर्ता “अलॉयड इनगोट्स” का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और “अलॉयड इनगोट्स” उनके साथ कोई “सीधे प्रतिस्पर्धी” नहीं है जो “अलॉयड इनगोट्स” नहीं हैं और वे अंतरपरिवर्तनीय नहीं हैं।
- घ. भारतीय घरेलू उत्पादन के विचारधीन उत्पाद के संबंध में; आयात में कोई सापेक्ष बढ़ोतरी नहीं है चूँकि भारतीय उत्पादन के संबंध में; आयात का प्रतिशत प्रायः समान अथवा कुछ कम रहा है। इससे आयात में; ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जो कोई गंभीर नुकसान उत्पन्न कर सके।
- ड. “अनपेक्षित घटना” की बाध्यकारी अपेक्षाओं का समुचित निवारण करने में महानिदेशक, रक्षोपाय महानिदेशालय असफल रहा है और जी.ए.टी.टी.1994 के अनुच्छेद XIX के अभिप्राय के अंतर्गत रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे “अदृश्य विकास” के रूप में साबित कर सके।
- च. इस बात का कोई भी सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि तथाकथित बढ़े हुए आयात से आवेदनकर्ताओं को कोई भारी नुकसान हो सकता है अथवा उन्हे किसी भी प्रकार की भारी नुकसान की आशंका है। आवेदनकर्ता के डेटा से यह खुलासा साफ तौर पर हुआ है कि आवेदनकर्ताओं की स्थिति में कोई समग्र नुकसान नहीं हुआ है।
- छ. डी.आई. की संस्थापित क्षमता में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

- ज. आवेदनकर्ताओं के उत्पादन एवं विक्रय, में क्रमशः 76% एवं 70% की भारी बढ़ोतरी हुई है। क्षमता-उपयोगीकरण में बेहतरी आई है और हाल ही के छान-बीन की अवधि में, माल-सूची के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- झ. भारतीय उत्पादकों सहित घरेलू उधोग बाजार की हिस्सेदारी; भारतीय बाजार के केवल 2/3 से भी अधिक हिस्से पर हीं प्रभावी नहीं है बल्कि वे बाजार में अपनी हिस्सेदारी को भी अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। भारतीय घरेलू बाजार में आयात बाजार हिस्सेदारी 15% से भी कम है।
- ञ. आर्थिक सूचकों की बढ़ोतरी के बारे में, अन्वेषण की अवधि के पिछले वर्ष के दौरान विशेषकर रिपोर्ट किए गए तथ्य से स्पष्ट तौर पर गंभीर नुकसान की किसी आशंका का आकलन कम किया गया है।
- ट. प्रस्तुत किए गए इन तथ्यों एवं विधिक कारणों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आवेदनकर्ताओं को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है और न किसी गंभीर नुकसान का खतरा है।
- ठ. बढ़ी हुई आयात और तथाकथित गंभीर नुकसान के बीच कोई कैज़्युअल लिंक नहीं है। डी.जी. रक्षोपाय नाँू-एट्रिब्यूशन-अनालिसिस करने में असफल रहा है और पी.यू.सी. के डी.आई. में किसी प्रकार कि हानि के नहीं होने का कारण आयात में बढ़ोतरी है। बढ़े हुए आयात से हुए नुकसान के अलावा अन्य कारणों से हुए नुकसान के लिए बढ़े हुए आयात को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है इस बारे में डी.आई. रक्षोपाय “तर्कपूर्ण एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण” देने में विफल रहा है।
- ड. बढ़े हुए आयात के अलावा अन्य कारक; आवेदनकर्ता को हुए किसी प्रकार के तथाकथित नुकसान का कारण है।
- ढ. प्राथमिक तत्व की मूल्य-निर्धारण-पद्धति एक निर्णायक कारक है चूंकि यह मुख्यतः लंदन धातु विनियम (एल.एम.ई.) मूल्य पर आधारित है जो एक ग्लोबल रेफरेंस प्राइस है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक की वित्तीय स्थिति पर एल.एम.ई. मूल्य का व्यापक प्रभाव होता है। पी.यू.सी. के बिक्री मूल्य के एक अत्यंत छोटे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व प्रीमियम करता है। एल.एम.ई. मूल्य में उतार-चढ़ाव; माँग का वैश्विक रूख एवं समूची दुनिया की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।
- ण. अन्वेषण की अवधि के दौरान, एल.एम.ई. मूल्यों में उतार-चढ़ाव का रुख बना रहा। वर्ष 2013 में, बढ़ी हुई लागत सहित, कम एल.एम.ई. अल्युमिनियम मूल्य ने पूरी दुनिया में फैले सभी अल्युमिनियम कंपनियों पर दबाव बनाया जो अन्ततः वित्तीय मुद्दों से पीड़ित रहे।
- त. आवेदनकर्ता स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि कम एल.एम.ई. प्राइसिंग ने उनके वित्तीय निष्पादन पर प्रबलतापूर्वक प्रभाव डाला। इसलिए आयात की बढ़ोतरी और तथाकथित गंभीर नुकसान के बीच अन्वेषण की अवधि के दौरान कोई ऐसा संबंध नहीं हो सकता है जो एल.एम.ई. प्राइसिंग उतार-चढ़ाव से संबंधित हो। डी.जी.रक्षोपाय ने “सकारात्मक साक्ष्य” पर आधारित किसी प्रकार की “निष्पक्ष जाँच” नहीं की है।
- थ. डी.आई. की हानि संबंधी सूचना का सख्ती से गोपनीय आधार पर किए गए अत्यधिक निदान ने इच्छुक पार्टियों के बचाव के हक को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया है।
- द. डी.आई. की हानि संबंधी सूचना से गंभीर नुकसान अथवा किसी भी प्रकार के नुकसान के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हो सकती है क्योंकि डी.आई. की स्थिति में समग्र तौर पर किसी प्रकार के महत्वपूर्ण नुकसान की कोई बात नहीं है।
- ध. ऐसी कोई भी गंभीर स्थिति नहीं है जो अस्थायी रक्षोपाय झूटी लगाने को न्याय संगत साबित कर सके।

## घघ. यूरोपियन यूनियन

- क. डी.आई. का निर्धारण ऐसे उत्पादों से करना होगा जो कि समान अथवा सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी हों। इंगोट्स, बिलेट्स, वायर बार एवं वायर रॉड; किसी भी उत्पाद के मात्र विभिन्न रूपों से कहीं अधिक है। प्रोडक्ट स्कोप में ऐसे उत्पाद हैं जिनके अलग-अलग अनुप्रयोग हैं और वे अन्तर-परिवर्तनीय नहीं हैं; इसलिए इनको सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी नहीं माना जा सकता है। इनगोट्स सीधे तौर पर वायर रॉड के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं है क्योंकि पहली सामग्री को दूसरी सामग्री के तौर पर परिवर्तित होने में कई चरणों से होकर गुजरना होता है।
- ख. घरेलू उद्योग की स्थिति पर, आयात और उनके प्रभाव का तीन विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता है अन्वेषण में शामिल विभिन्न उत्पादों के लिए एक अलग से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- ग. 2011/12 से आयात में सतत बढ़ोतरी हुई। यद्यपि, बाजार में हिस्सेदारी के अनुसार इस पूरी अवधि में आयात में केवल 4% की ही बढ़ोतरी हुई तथा यह भारत की कुल मांग के मुकाबले केवल 15% के बराबर हिस्से तक ही पहुँच पाया।
- घ. समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा तुलनात्मक रूप से लगभग 50% पर स्थिर रहा।
- इ. मुख्य जोखिम सूचकांक बढ़त का रूझान दिखाते हैं। उत्पादन की मात्रा 76%, बिक्री 32% तथा क्षमता 40% तक बढ़ गयी है। क्षमता उपयोग दर में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है परंतु यह 48% के निम्न स्तर पर बना हुआ है। इसी अवधि में बाजार का हिस्सा मांग में 29% वृद्धि के मुकाबले ज्यादातर 48% के आस पास स्थिर रहा।
- च. केवल लाभ में गिरावट के संकेत हैं, जो 2015/16 में हानि में परिवर्तित हो गया। चूंकि, प्रदान किया गया डाटा सूची के रूप में है, इसलिए यह पता कर पाना कठिन था कि हानि किस स्तर पर हुई।
- छ. 2015/16 में ब्याज तथा कर से पहले के परिणाम सकारात्मक हैं। अन्य सभी जोखिम सूचक के अनुकूल होने के मद्देनजर गिरते हुये लाभ का स्पष्टीकरण दे पाना कठिन प्रतीत होता है तथा यह दिखाता है कि आयतों के अतिरिक्त भी अन्य कारक हैं जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है।
- ज. शिकायत में अन्य कारकों के बारे में सूचना प्रदान नहीं की गई है।
- झ. 2011/12 की आरंभिक अवधि में क्षमता उपयोग 38% के निम्न स्तर का था। बाद में, आयात में वृद्धि के बाद भी क्षमता उपयोग दर 2015/16 में वृद्धि के बाद 48% पर पहुँच गई।
- ञ. यह स्पष्ट करना कठिन है कि विश्लेषित अवधि में उद्योग ने विद्यमान क्षमता का पूरी तरह प्रयोग किए जाने के स्थान पर अपनी क्षमता को लगभग 30% तक बढ़ाए जाने का निर्णय क्यों लिया। और, क्षमता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों तथा घरेलू उद्योग की स्थिति में इसके प्रभाव के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई।
- ट. शिकायत में प्रदान की गई सूचना के अनुसार आयात मूल्यों को घरेलू मूल्यों से कम किया गया प्रतीत होता है। यद्यपि, आयात मूल्य केवल एल एम ई के रूब का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरी ओर, विश्लेषित पूरी अवधि में घरेलू उद्योग के मूल्य एल एम ई स्तर से बहुत ऊपर रहे। इसी समय बिक्री की लागत 30% बढ़ गई। बिक्री की लागत में हुई वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। यह घरेलू उद्योग की अक्षमता का परिणाम हो सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपने बिक्री मूल्यों में कच्चे माल के घटते मूल्यों को दिखा नहीं पाए।
- ठ. वेतन में 150% की वृद्धि हुई जबकि कर्मचारियों की संख्या में केवल 5% की ही वृद्धि हुई, परंतु वेतन में इस असाधारण वृद्धि का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

- ड. तथ्यात्मक विश्लेषण सुनिश्चित किए जाने के लिए जांच अधिकारी को उन सभी कारकों का जिनका आवेदकों की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है ध्यानपूर्वक विश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए।
- ढ. 20% रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुरोध के साथ याचिककर्ताओं ने इसकी गणना के तरीके के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चूंकि, मूल्य कम किए जाने पर सूचना केवल सूची के रूप में दी गई है, अतः यह पता लगाया जाना संभव नहीं कि क्या प्रस्तावित उपाय कथित रूप से मूल्य कम किए जाने से संबंधित हैं।
- ण. ऐसा प्रतीत होता है रक्षोपाय उपाय अधिरोपित किए जाने के मापदण्ड पूरे नहीं किए गए हैं। लाभ के संबंध में डी आई को जो कठिनाईयां पेश आईं साफ तौर पर उसका कारण आयात में वृद्धि नहीं था, बल्कि उत्पादन क्षमता में विकास; जैसा उपयोग क्षमता कि कमी में दर्शाया गया है साफ तौर पर आवेदकों कि अक्षमता; उत्पादन कि लागत में वृद्धि तथा वेतन में असाधारण वृद्धि जैसे कारण हैं।

#### **उज. भारत में ताइपे आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र**

- क. 2013-2015 के दौरान ताइवान ने भारत को सालाना केवल 1,000 टन से कम अनरॉट एल्यूमीनियम का निर्यात किया, जो भारत में संबंधित उत्पाद की कुल आयात मात्रा का 0.14% - 0.17% है।
- ख. ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ताइवान का भारत में अनरॉट एल्यूमीनियम का निर्यात भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाता है या पहुंचा सकता है। अतः, रक्षोपाय पर डब्ल्यू टी ओ के करार की धारा 9(1) ताइवान पर लागू नहीं होती। भारत सरकार ने दिनांक 5 फरवरी 2016 को अधिसूचना संख्या 19/201 ए – सीमा शुल्क (एन टी) जारी की तथा ताइवान को रक्षोपाय उपायों में छूट से बाहर कर दिया गया। भारत सरकार, भारत के घरेलू रक्षोपाय क्लानूनों में ताइवान को विकासशील देश का दर्जा दे सकती है।

#### **ऊज. मेसर्स राविन केबल लिमिटेड**

- क. उत्पाद का वर्णन “अनरॉट एल्यूमीनियम (एलॉयड रहित एल्यूमीनियम तथा एलॉयड एल्यूमीनियम) के रूप में करते हुए दोनों उत्पादों का एच एस कोड नहीं दिया गया है।

#### **ऋक्त. मेसर्स पैरागान इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

- क. ऐसी ही जांच 2014 में की गई थी तथा जांच रोक दी गई।
- ख. सीमा शुल्क शीर्ष 7601 के अधीन अधिकतर स्क्रैप से बनाई गयीं एलॉयड सिलियाँ (76012010) सम्मिलित हैं। यह डी आई का लक्षित बाजार नहीं है तथा आयात के डाटा से इसे निकाल दिया जाना चाहिए।
- ग. ड्यूटी फ्री लाइसेन्स के द्वारा बढ़ी मात्रा में आयात किया गया है तथा इसे अन्य अतिरिक्त ड्यूटी इन आयातों पर प्रभाव नहीं ढालेगी।
- घ. याचिककर्ता द्वारा यह तथ्य छुपाया गया है कि वेदांता का झारसागुडा प्लांट जिसकी 1.25 मिलियन की क्षमता है एस ई जेड में स्थित है और जिसका उद्देश्य वैश्विक बाजार की जरूरतें पूरी करना है। उपयोग का निर्धारण करने के लिए क्षमता को घरेलू क्षमता के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि एस ई जेड की 1.2 मिलियन क्षमता को क्षमता उपयोग से निकाल दिया जाए तो क्षमता उपयोग 80% के आस पास रहेगा। वेदांता के पास प्लांट चलाने के लिए बॉक्साइट तथा एल्यूमिना नहीं हैं तथा यह चल नहीं रहा है।
- इ. हिंडाल्को ने अपने माहान तथा आदित्य प्लांटों को शुरू कर दिया है तथा दावा किया है कि यह प्लांट पूरी क्षमता से चल रहे हैं।
- च. दुनिया भर में प्रचलित एल एम ई आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति जो बाजार द्वारा चालित तथा पारदर्शी है के आधार पर घरेलू मूल्य कि गणना न करते हुए याचिकार्ता द्वारा घरेलू मूल्य की आयात की लेंडेड लागत पर गणना की गई है। आयात ड्यूटी में होने वाली हर वृद्धि याचिककर्ताओं के लाभ में जुड़ जाती है।
- छ. याचिकार्ता ने स्वीकार किया है कि उनकी लाभप्रदता में कमी एल एम ई मूल्य में गिरावट तथा प्रीमियम के कारण आई है न कि आयात से स्पर्धा के कारण।

ज. सेकण्डरी उत्पादक कि स्थितियाँ बड़ी अनिश्चित हैं क्योंकि बहुत सी एक्स्ट्रॉश तथा रोलिंग यूनिट पहले ही बंद हो चुकी हैं। छूटी में अंतर के कारण आ रहे सस्ते आयातित वस्तु की तुलना में बेस मेटल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से लागत में वृद्धि हो जाएगी।

झ. पूरे विश्व में वस्तुओं के मूल्य में गिरावट से कमता उपयोग में कमी तथा अन्य मुद्रे ढांचागत मुद्रे हैं।

#### एए. मेसर्स इंडियन फाउंडरी ओर्गेनाइजेशन (आई एफ ओ)

क. फाउंडरी उद्योग का उत्पादन 10 मिलियन टन के आस पास है।

ख. एल्यूमीनियम एलॉय के 150 से अधिक घरेलू निर्माता हैं जो अधिकतर एम एस एम ई सेक्टर में आते हैं जिनका पूंजी निवेश रूपए 20,000/- करोड़ से अधिक का है तथा लगभग 100,000 कर्मियों को सीधा रोजगार प्रदान करते हैं।

ग. एल्यूमीनियम स्क्रैप की रिसाइकिंग से ऊर्जा की बचत होती है तथा पर्यावरण की रक्षा होती है। प्राइमरी एल्यूमीनियम उत्पादन की तुलना में रिसाइकिंग में ऊर्जा खपत कहीं कम होती है। रिसाइकिंग में वस्तुतः कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता।

घ. आई एफ ओ को बड़ी संख्या में मेटल रिसाइकलरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्होने एच एस 7601 के शीर्षक के अंतर्गत आने वाले एल्यूमीनियम पर रक्षोपाय छूटी लगाए जाने का समर्थन किया है।

इ. एफ टी ए के अंतर्गत एच एस 760120 के अधीन आने वाली एल्यूमीनियम एलॉय सिल्लियों का थार्डेलैंड तथा मलेशिया से आयात छूटी फ्री कर किया गया है। एल्यूमीनियम एलॉय सिल्लियों के निर्माण के लिए प्राथमिक कद्दा माल जो एच एस 76020010 के अंतर्गत एल्यूमीनियम स्क्रैप के रूप में जाना जाता है के आयात पर 2.5% की आयात छूटी है। इसके परिणामस्वरूप मेटल रिसाइकलरों तथा एल्यूमीनियम एलॉय के निर्माताओं को बड़े वित्तीय घाटे उठाने पड़े हैं।

च. आई एफ ओ अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सहित पी यू सी पर 50% रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना संस्तुत करता है।

#### ऐए. मेसर्स हाइड्रोएल्यूमीनियम एशिया पीटीई लिमिटेड

क. कोई भी रक्षोपाय शुल्क इनके विधिक व्यापार हितों पर गंभीर तथा प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तथा भारतीय बाज़ार में उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उनकी सप्लाई को गैर प्रतिस्पर्धात्मक बना देगा।

ख. महानिदेशक रक्षोपाय अपने अनंतिम रक्षोपाय उपायों अथवा कोई भी अंतिम उपायों की पुष्टि नहीं करते तथा भारत में इनके सहित कथित वस्तुओं के बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं पर एसे रक्षोपाय शुल्कों के प्रतिकूल व गंभीर प्रभावों के मद्देनजर वर्तमान रक्षोपाय जांच को समाप्त कर सकते हैं।

#### ओओ. मेसर्स हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड

यह भारत में कथित वस्तुओं के अंतिम उपयोगकर्ताओं में से एक है।

#### औओ. मेसर्स शशि केबल्स लिमिटेड

क. प्रस्तावित रक्षोपाय उपाय का कोई उपाय नहीं है।

ख. एल्यूमीनियम सिल्लियों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपन से भारतीय प्राथमिक उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ा सकते हैं।

ग. वायर रॉड के रक्षोपाय शुल्क से बच जाने के कारण इन्हें भारतीय समेल्टरों अथवा सेकण्डरी उत्पादकों से प्राप्त होने वाली रॉड के मुकाबले 5% कम दरों पर आयात किया जाएगा। लगभग 300 छोटी यूनिट इस भार से टूट जाएंगी।

घ. या तो कोई रक्षोपाय शुल्क न लगाया जाए अथवा साथ ही साथ इसे एल्यूमीनियम रॉड पर भी लगाया जाए।

इ. हॉट मेटल का उत्पादन 2014-15 की तुलना में 2015-16 में बढ़ा है और 2015-16 की तुलना में हॉट मेटल का उत्पादन 2016-2017 में बढ़ा है। इन बढ़ोतरीयों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई लगातार मंदी के प्रकाश में तथा कंडक्टर की मांग में आई बहुत अधिक कमी के रूप में देखा जाएगा।

- च. एल्यूमीनियम के प्रसंस्करण में बहुत समय लगता है व बहुत पूँजी की आवश्यकता होती है तथा इन प्रोजेक्ट के डेवेलपर्स में वित्तीय दबावों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए।
- छ. एल्यूमीनियम वह वस्तु है जिसका एल एम ई तथा अन्य एक्सचेंजों में वैश्विक व्यापार होता है। अच्छे समय में भारतीय उत्पादक एल एम ई सूचकांकों के अनुसार अपने मूल्य निर्धारित करते हुए पूरा लाभ प्राप्त करते हैं परंतु जब प्रतिस्पर्धा कड़ी होती है तब वे चाहते हैं कि डाउन स्ट्रीट उपभोक्ता रक्षोपाय शुल्क के तरीके से बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक भुगतान करें।
- ज. भारतीय उत्पादकों कि तरह अन्य देशों के निर्माताओंकी अयस्कों, खनिजों तथा कोयला आदि पर पहुँच तक भी नहीं है।
- झ. रक्षोपाय शुल्क का तदर्थ तरीका बाजार को जटिल बना देगा व बिगाड़ देगा इसके स्थान पर टैरिफ़ को 7.5% से 10% तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।
- ञ. एल्यूमीनियम मेटल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का कोई मामला नहीं है।
- ट. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया भी जाता है तो यह वायर रॉड पर भी लागू होना चाहिए जिसे अधिकतर एल्यूमीनियम उत्पादक प्राथमिक मानते हैं, अन्यथा घरेलू कंडक्टर उद्योग में छोटे निर्माताओं का हित जोखिम में पड़ जायगा।

#### अंग. मेसर्स ब्लाइट मेटल

- क. दो देशों में 300 से अधिक मध्यमिक एल्यूमीनियम एक्सट्रॉडरों में से एक है।
- ख. उद्योग आपस में इस तरह बुना है कि प्राथमिक उद्योगों के हितों में अलग से लिया गया कोई भी निर्णय न केवल उनके अस्तित्व पर प्रभाव डालेगा अपितु देश में वर्तमान आयात ड्यूटीढांचे तथा चीन तथा अन्य एफ़टीए देशों से आक्रामक रूप से आ रहे सामान के कारण देश की बहुत सी यूनिट बर्बाद हो जाएंगी।
- ग. वर्तमान में भारत में उत्पादन लगभग 1.5 मिलियन टन है, चीन में उत्पादन तथा खपत 7 मिलियन टन पार कर गयी है। इस असमानता का मुख्य कारण औद्योगिक विकास तथा पर्याप्त मात्रा में एल्यूमीनियम की अनुपलब्धता थी। ड्यूटीकी ऊंची दर ने आयतों पर प्रभाव डाला तथा देश में डाउनस्ट्रीम गतिविधि को पनपने नहीं दिया।
- घ. औद्योगिकीकरण के कारण तथा विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार आरंभ किए जाने के पश्चात निर्माताओं को गुणवत्ता पूर्ण एल्यूमीनियम कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य हो गया।
- ङ. कच्चे माल पर रक्षोपाय शुल्क बहुत नुकसानदायक होगा, इसके बजाए तो छोटे तथा मझोले उद्योग को बचाने के लिए सरकार को डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसकी अवश्यकता भी है, क्योंकि चीन जैसे कुछ देश निर्यात पर बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर दबाव बढ़ा रहा है।
- च. सामान्यतया प्राथमिक कच्चे माल का व्यापार लंदन मेटल एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, अतः उद्योग के किसी भी हिस्से के लिए यह चिंता का विषय नहीं है।
- छ. घरेलू उत्पादकों कि गुणवत्ता संबंदीमुद्दों के चलते ये एक्सट्रॉडर के रूप में कुछ श्रेणी के विलेट्स का आयात करते हैं।
- ज. देश में एल्यूमीनियम एक्सट्रॉशन की स्थापित क्षमता के मुकाबले कुल विलेट्स का कुल उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, अतः उत्पादकों को यूनिट में ही उत्पादन (जो कि ज्यादातर घटिया स्तर के होते हैं) करने पर अथवा गुणवत्ता पूर्ण विलेट्स की कमी पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहने पर विवश होना पड़ता है।
- झ. निर्यात कि बाध्यताओं को पूरा किए जाने के लिए देश में प्राथमिक मेटल आयात अग्रिम लाइसेंस के द्वारा होता है जहां मूल्य के बेंचमार्क का निर्धारण एल एम ई के विद्यमान मूल्य के आधार पर होता है।

- ज. चूंकि भारत में वर्तमान में एल एम ई मूल्य पर बिना कर के मेटल प्राप्त किए जाने की प्रणाली उपलब्ध नहीं है वास्तव में, माल को आयात किए जाने की अवश्यकता है।
- ट. आगे, दर्शाया गया डाटा प्राइमरी मेटल को सेकण्डरी मेटल से अलग नहीं करता अतः सही आकलन किया जाना कठिन है।
- ठ. 78% अनुमानित वृद्धि का कारण अधिकतर कास्टिंग उद्योग में सेकण्डरी मेटल की खपत किया जाना हो सकता है, जहां देश में मोटर वाहन उद्योग में विकास के कारण खपत में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
- ड. 5 इंच से लेकर 14 इंच के व्यास के साथ 1 इंच के अंतर वाले बिलेट्स की उद्योग को आवश्यकता रहती है। मशीन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता की अवश्यकता भी अलग ही आकार की होती है। प्रत्येक आकार को बनाने के लिए विभिन्न साँचों की अवश्यकता पड़ती है, इसके लिए प्राथमिक उत्पादक सभी आकार में विशेष के लिए तैयार नहीं होते, विशेषकर 5 इंच के आकार के उत्पादन में कठिनाईयां हैं।
- ढ. भारत में प्रति वर्ष 3.5 लाख टन से अधिक के बिलेट की अवश्यकता है। बिलेट्स की अनुपलब्धता के कारण मजबूरन लोगों को जैसी उनकी अवश्यकता है, बिलेट्स अथवा स्क्रैप को आयात करना पड़ता है।
- ण. एक्सट्रॉडर के लिए जिनका देश में निर्माण नहीं किया जाता कुछ प्रकार के उच्च गुणवता बिलेट्स को आयात किया जाना अवश्यक है।
- त. यह निश्चित हो गया है कि घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि 78% तक बढ़े हुये आयात के विश्लेषण से गम्भीर क्षति के अनुमान का दावा धराशायी हो गया है।
- थ. इसके विपरीत, कच्चे माल पर रक्षोपाए शुल्क लगाये जाने से सेकण्डरी एक्सट्रॉशन निर्माता जो छोटे तथा मध्यम सैक्टर में हैं को उनकी इनपुट लागत बढ़ने के कारण गंभीर क्षति पहुँच सकती है।
- द. घरेलू उत्पादन में 76% की बढ़ोतरी डी आई के लिए अच्छा संकेत है। वैश्विक वित्तीय मंदी ने उद्योग के सभी हिस्सों पर प्रभाव डाला है।
- ध. डी आई की वस्तु सूची बहुत ही संतोषजनक स्तर की है। घटती हुई वस्तु सूची उत्पादकों के लिए अच्छा संकेत है।
- न. यूएई, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ओमान तथा थाईलैण्ड जैसे देश प्राइमरी मेटल का उत्पादन नहीं करते हैं। कतर तथा बहरीन बिलेट्स के उत्पादक हैं तथा आयात नगण्य है इन सभी देशों का उल्लेख किया जाना इस तथ्य का संकेत है कि अनुमानित डाटा गलत है।
- प. कास्टिंग तथा स्क्रैप के लिए सेकण्डरी मेटल का आयात बढ़ गया है तथा मोटर वाहन व अन्य उद्योगों के विकास के साथ यह बढ़ता ही रहेगा तथा इसे डी आई के साथ जोड़ा नहीं जा सकता।
- फ. और अन्य भारतीय निर्माता जिसने भाग नहीं लिया वह मेसर्स नाल्को है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि अन्य भारतीय उत्पादकों के आकड़ों की शुद्धता को जांचा जाए।
- ब. जिस गति से प्राइमरी मेटल की क्षमता का विस्तार हुआ, उसी गति से डाऊनस्ट्रीम सैक्टर का विकास नहीं हुआ क्योंकि उद्योग को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
- भ. उपयोग का वर्तमान अनुमान भ्रामक है क्योंकि प्रत्येक क्षमता विस्तार की, प्रत्येक कंपनी की नीति पर आधारित क्षमता उपयोग को वर्णित करते हुए एक कार्य योजना होती है। डी आई से यह डाटा लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- म. एल एम ई में मूल्य कम हुए हैं, परंतु वर्तमान हानि का यह कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय उत्पादकों की लागत विश्व बैंच मार्क से बहुत कम है। यह विभिन्न शीर्षों जैसे की मूल्यहास के लिए बैलेन्स शीट का विश्लेषण किए जाने का मामला है ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके।

- य. सभी उत्पादक अपने मूल्य को आयातित मेटल कीलेंडे लागत जो ए एम ई पर आधारित है के साथ जोड़ रहे हैं, अतः लाभप्रदता अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का एक कारक है तथा कोई भी देश अथवा उत्पादक इससे बचा नहीं रह सकता।
- कक. एक्सट्रूशनउद्योग में रिटर्न संभवत सबसे कम हैं तथा उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है।
- खख. अनरॉट - अल्युमिनियम के आयात पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह सेकेंडरी अल्युमिनियम उद्योग के कार्यों को विशेषकर देश में बड़ी संख्या में एक्स्ट्रूडर्स को गंभीर रूप से जोखिम में डालेगा।
- गग. ऐसे देशों द्वारा निर्यात पर, विशेष रूप से चीन से निर्यात पर ऑफर दिए जा रहे प्रोत्साहनों के आलोक में एवं अल्युमिनियम एक्स्ट्रूसन्स के आयात पर, रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु यह एक उपयुक्त मामला है।
- घघ. अन्य देशों के विपरीत भारत से मूल एवं डाउनस्ट्रीम उत्पादों के बीच कोई शुल्क अंतरता नहीं है।

#### अ:अ: मै.जे.एम. इंडस्ट्री

- क. यदि अल्युमिनियम पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो अल्युमिनियम की स्थानीय लागत में वृद्धि की संभावना है जिससे लकड़ी, प्लास्टिक जैसे वैकल्पिक उत्पादों की माँग में वृद्धि हो सकती है।
- (ख) वर्तमान में तैयार अल्युमिनियम उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य है जो उनके निर्यात को प्रभावित करेगा जो प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। ऐसे सभी संभावित समस्याओं के कारण सभी अल्युमिनियम उद्योग पर उनके विधमानता हेतु प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

#### अ.अ. किंगडम ऑफ सऊदी अरब

- क. रक्षोपाय पर डब्लू टी ओ समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अधीन एक विकासशील सदस्य देश से होने वाले उत्पाद के आयात पर रक्षोपाय उपाय अधिरोपित नहीं किया जा सकता यदि इसके आयात का शेयर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होता है एवं बशर्ते तीन प्रतिशत से कम आयात शेयर वाले विकासशील सदस्य देशों का आयात शेयर कुल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक समग्र रूप में न होता हो।
- ख. सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद पर्याप्त रूप से वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान कुल आयात के तीन-प्रतिशत से कम बैठता है क्योंकि सऊदी अरब एक विकासशील देश डब्लू टी ओ सदस्य है, इसके निर्यात को भारत में किसी रक्षोपाय उपाय के विषय से बाहर कर देना चाहिए।
- ग. दी किंगडम ऑफ सऊदी अरब को विकासशील सदस्य देशों शामिल नहीं किया गया है जिन पर अनुच्छेद के अधीन उपाय लागू नहीं किया गया है। रक्षोपाय पर समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अधीन भारत की बाध्यताओं के अनुसार सऊदी अरब से आयात को भारत में लगाए जाने वाले किसी रक्षोपाय उपाय से छूट दी जा सकती है।

#### आआ. इंडोनेशिया सरकार

- क. रक्षोपाय पर समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अनुसरण में प्राधिकारी रक्षोपाय शुल्क से विकासशील देशों को तब तक अलग रखेंगे जब तक संबंधित उत्पाद का आयात आयातक देश में 3% से अधिक न होता हो बशर्ते कि तीन प्रतिशत से कम आयात वाले विकासशील देश का आयात शेयर कुल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक समग्र रूप में न होता हो।
- ख. आयात का इंडोनेशिया का शेयर नगण्य (भारत के कुल आयात के 3% से कम) है एवं अन्य देशों के कुल योग 9% से कम है। महानिदेशक रक्षोपाय अपने अंतिम निष्कर्ष में प्रारम्भिक निष्कर्षों के भाग X में निष्कर्ष को बनाए रख सकते हैं।
- इइ. ई ई पी सी इंडिया (फार्मली इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल)
- क. अल्युमिनियम आधारित उत्पादों के विनिर्माण में लगे बड़ी संख्या में विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- ख. यह दावा कि 2011-12 से 2015-16 तक पी यू सी का आयात काफी बढ़ा है, भ्रामक है। कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में यह बढ़ा नहीं है। 2011-12 में यह 13% था जो 2013-14 में 17% तक बढ़ा एवं 2015-16 में फिर से 15% तक नीचे आ गया।
- ग. यह दावा कि वर्धित निर्यात से घरेलू उधोग को क्षति हो रही है, गलत है।
- घ. निर्यात संवर्धन शुल्क मुक्त योजना के अधीन आयात को अलग नहीं किया गया है। शुल्क प्रदत्त माध्यम के अधीन बहुत कम एवं अपर्याप्त मात्रा का आयात किया जा रहा है।
- ड. अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यातकों को पी यू सी की आपूर्ति करने की डी आई की मंशा नहीं है।
- च. चीन से सस्ता आयात डी आई को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है क्योंकि शुल्क प्रदत्त योजना के अधीन पर्याप्त मात्रा में चीन से पी यू सी का आयात नहीं हो रहा है।
- छ. सभी घरेलू अल्युमिनियम उत्पादक कंपनियाँ, जिसमें सरकारी क्षेत्र की नाल्को शामिल हैं, आकर्षक लाभ कमा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की कम्पनी नाल्को ने रक्षोपाय शुल्क सुरक्षा हेतु मांग को ज्वाइन नहीं किया है। प्राइवेट सेक्टर उत्पादकों का दावा अनुचित लाभ प्राप्त करने से प्रेरित है।
- ज. घरेलू उधोगों के मार्केट शेयर को आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। बल्कि यदि वे शुल्क मुक्त योजना के अधीन अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ाते हैं तो तैयार उत्पादों के निर्यातक, जो अपनी मांग हेतु आयात करने हेतु बाध्य हैं, घरेलू निर्यातकों से माल प्राप्त करने हेतु इच्छुक से ज्यादा हो जाएंगे।
- झ. यह भी नोट किया जा सकता है कि घरेलू उधोग अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जमा प्रीमियम जमा आयात शुल्क यू एस सी को पुन विनियम दर को मल्टीप्लाई कर प्रयोग कर रही है एवं घटते रूपए के कारण बढ़ा लाभ कर रहे हैं।
- अ. यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो घरेलू उत्पादक आयातित मेटल की उत्तराई की लागत के आधार पर अपने उत्पाद के मूल्य बढ़ा देंगे।
- ट. कई बहुत से छोटे विनिर्माता एवं निर्यातक हैं जो पी यू सी का कम मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। वे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास शुल्क मुक्त योजना के अधीन पी यू सी का आयात करने हेतु पर्याप्त वाल्यूम नहीं है अथवा वित्तीय क्षमता नहीं है।
- ठ. तैयार/अर्ध तैयार वस्तुओं के आयात शुल्क में बिना अनुपातिक वृद्धि के बिना पी यू सी (कच्चा माल) के शुल्क में वृद्धि से एक इन्वर्टिड ड्यूटी ढाँचा फलित होगा जो कि बढ़ी संख्या में घरेलू अल्युमिनियम का उपभोग करने वाले उधोग को नुकसान पहुँचाएगा।
- ड. शुल्क में कोई भी वृद्धि छोटे विनिर्माता की प्रतिस्पर्धात्मकता को अलग-अलग प्रभावित करेगी जो कि भारत सरकार की नीति के विपरीत है।
- ई. मै. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया अल्युमिनियम यूटेसील मैन्युफैक्चरर्स**
- क. पी यू सी के भारत में वास्तविक आयात एवं भारत से निर्यात को ध्यान में रखते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक आँकड़ों, स्थापित क्षमता एवं उत्पादन का भी विश्लेषण किया जा सकता है।
- ख. जाँच के अधीन अवधि के दौरान डी आई का उत्पादन एवं क्षमता उपभोग बढ़ा है अतः उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है।
- ग. जाँच की अवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में आयात का प्रतिशत वर्ष 2011-2012 में 27.33% था, वर्ष 2013-14 में 33.19 तक बढ़ा एवं 2015-16 में 26.99 तक गिर गया जिससे साक्ष्य मिलता है कि कोई क्षति कारित नहीं हुई है।
- घ. जाँच की अवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में आयात का प्रतिशत बढ़ा है।

- इ. आवेदकों ने अत्यधिक निर्यात के जरिए एक सीमित आपूर्ति की है। जिससे एकाधिकारी निर्धारित घरेलू विक्रिय मूल्यों ने डाउनस्ट्रीम सेकेन्डरी विनिर्माताओं का क्षति पहुंचा रहे हैं।
- च. देश से बाहर पी यू सी के निर्यात का आयात के इन्टेंडम विश्लेषण किया जा सकता है। आयात की तुलना में निर्यात में ज्यादा वृद्धि हुई है बल्कि डाउनस्ट्रीम सेकेन्डरी विनिर्माताओं को क्षति हुई है क्योंकि डी आई ने सीमित आपूर्ति की है जिससे उन्होंने एकाधिकारिक रूप में घरेलू विक्री मूल्य का निर्धारण किया है इस कारण से अल्युमिनियम के डाउनस्ट्रीम सेकेन्डरी विनिर्माताओं को आयात के बाध्य किया गया है।
- (छ) निर्यात की तुलना में भारत में आयात अधिक मूल्यों पर थे।
- (ज) जी ए टी टी 1994 के अनुच्छेद XIX मे यह जांच जरूरी है कि क्या रक्षोपाय उपाय को लागू करना सार्वजनिक हित में होगा।
- (झ) किसी भी प्रकार का रक्षोपाय उपाय आवेदकों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाएगा क्योंकि वे घरेलू कीमतों में वृद्धि कर देंगे।

### **III. सार्वजनिक सुनवाई**

1. सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को आयोजित की गई थी। इच्छुक पक्षों के साथ-साथ घरेलू उधोगों ने सार्वजनिक सुनवाई के समय मौखिक निवेदन किया था। कस्टम्स टैरिफ़ (ट्रांजिसनल प्राडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी) रूल्स 1997 के नियम 6 के उपनियम 6 के अनुसार सभी इच्छुक पक्षों, जिन्होंने सार्वजनिक सुनवाई के भाग लिया था, से उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक निवेदन को लिखित रूप में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था।
2. एक इच्छुक पक्ष द्वारा फाइल की गई लिखित निवेदनों की प्रति सभी अन्य इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराई गई थी अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई लिखित निवेदनों पर रिजाइन्डर, यदि कोई हो, को फाइल करने का मौका भी अन्य पक्षों को दिया गया था।
3. 29 सितम्बर 2016 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में इच्छुक पक्षों द्वारा अपने लिखित निवेदन मे व्यक्त किए गए सभी दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया एवं उचित निर्धारण करने हेतु इनका ध्यान रखा गया है।
4. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात इच्छुक पक्षों द्वारा फाइल किए गए लिखित निवेदनों का सार-संक्षेप निम्नानुसार है:-

#### **अ. मै. रविन केबल्स लि.**

- क. अध्याय 98 के अधीन प्रोजेक्ट आयात पर लागू शुल्क की दर 5% है जबकि इलेक्ट्रिकल उधोग के ज्यादातर अवयवों पर आयात शुल्क 7.5% है।
- ख. सरकार को इन्वर्टिंड ड्यूटी ढांचों के अवसरों को भावहीन करने हेतु ट्रांसफॉर्मरस अथवा किसी अन्य उत्पाद समूह, जो अल्युमिनियम को मूल कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- ग. सरकार को ट्रांसफॉर्मरस, केबल्स एवं कंडक्टरस एवं अध्याय 98 के अधीन अन्य कोई उत्पाद (वर्तमान में भारत में निर्मित) के आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- घ. अल्युमिनियम के निर्यात पर निर्यात कर लगाना चाहिए जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ सके।
- ड. अल्युमिनियम उधोग को अल्युमिनियम की आपूर्ति निर्धारित दरों पर एवं एल एम ई कांट्रोकट ऑफर के अनुसार करनी चाहिए जिससे डाउनस्ट्रीम उधोगों के हितों की सुरक्षा की जा सके उन मामलों में जहाँ वे या तो निर्धारित मूल्य कांट्रोकट में प्रविष्ट हुए हो या उन्होंने निर्धारित मूल्य बोली के विपरीत उधर्दत किया हो।
- च. अल्युमिनियम उधोग को निर्यात/सम निर्यात आदेशों हेतु अनुचित प्रीमियम की मांग किए बिना, शुल्क मुक्त माल की आपूर्ति करनी चाहिए।

- छ. अल्युमनियम हजारों डाउनस्ट्रीम उधोगों हेतु कच्चा माल है एवं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता नकारात्मक रूप में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- ज. शुल्क सुरक्षा दिए जाने से पूर्व रक्षोपाय शुल्क के प्रस्तावित अधिरोपण के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
- झ. वर्ष 2009 में वर्तमान पी यू सी एवं अन्य उत्पादों से संबंधित आवेदन फाइल किया गया था लेकिन बाद में वापिस ले लिया गया था। वर्ष 2014 में अनरॉड अल्युमनियम की गैर अलॉय सिल्लियों के मामले में आवेदन महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- ज. क्योंकि मै. नाल्को अल्युमनियम का मुख्य उत्पादक होते हुए भी वर्तमान आवेदन का हिस्सा नहीं है, यह आवेदन सम्पूर्ण घरेलू उधोग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- ट. आवेदन में कई विसंगतियाँ हैं। अग्रिम प्राधिकरण के अधीन शुल्क मुक्त आयात हेतु कोई पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- ठ. कुछ मामलों में इंडेक्स किए गए आँकड़े गोपनीयता के आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए कोई तुलना संभव नहीं है।
- ड. आवेदन पब्लिक की लागत पर बड़े स्तर पर लाभ कमाने की दुर्भावनापूर्ण नीयत से फाइल किया गया है।
- ढ. पी यू सी बहुत से डाउनस्ट्रीम उधोग के लिए मूल कच्चा माल है एवं पूरे विश्व में एल एम ई आधारित मूल्यों पर बेचा जाता है। इसलिए डाउनस्ट्रीम उधोग को पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु पी यू सी की स्थानीय कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ लिंक किया जाना है।
- ण. प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पी यू सी का आयात सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल नहीं है।
- त. पी यू सी के मूल कच्चे माल होने के कारण, उसके आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उधोग पर प्रीतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पूरी अर्थव्यवस्था पर इफ्लेमेटरी ट्रेंड सेट करेगा।
- थ. रुपए में कमी का अनुचित लाभ लेते हुए पी यू सी के प्रीमियम में कमी एवं एल एम ई कीमतों में कमी के बावजूद अपने मूल्य कम नहीं किए हैं।
- द. मांग के बावजूद व्यवसायी समूहन के जरिए आवेदक अपनी स्थापित क्षमता के बहुत नीचे उत्पादन को नियंत्रित कर रहे हैं जिससे वे पब्लिक को हानि पहुंचाकर अपने लाभ को बढ़ा सके।
- ध. पी यू सी की बिक्री के संबंध में आवेदक बेहतर वाणिज्यिक टर्मस उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जो उनके समुन्द्री पार सहयोगी उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके बचे रहने हेतु पी यू सी के उपभोक्ताओं को समुन्द्री पार बाजार से पी यू सी के आयात हेतु बाध्य कर दिया गया है।
- न. आवेदकों द्वारा पी यू सी का उत्पादन, अखिल भारतीय उत्पादन की वास्तविक मदों में एवं संबंधित मदों में बढ़ रहा है।
- प. जांच की अवधि के पहले पी यू सी का अखिल भारतीय उत्पादन के सामने 13% से 15% के बीच रहा है। इसलिए पी यू सी के आयात में अचानक, तेज एवं काफी वृद्धि नहीं हुई है।
- फ. आयात में वृद्धि के बावजूद आवेदकों का उत्पादन बढ़ रहा है।
- ब. वास्तविक मदों में उत्पादन (अखिल भारतीय स्तर पर) में वृद्धि की तुलना में आयात में कोई बड़ी वृद्धि नहीं है।
- भ. आवेदकों का निर्यात वास्तविक मदों में एवं उनके उत्पादन की प्रतिशतता की मदों में काफी बढ़ा है। आवेदकों का घरेलू आपरेशन आयात में वृद्धि से प्रभावित नहीं हुआ है।
- म. आवेदकों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में अखिल भारतीय आयात से ज्यादा है।

- य. पी यू सी का अखिल भारतीय नियंत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 मे अखिल भारतीय आयात से काफी ज्यादा है। इसलिए आवेदकों पर आयात मे इस तथाकथित वृद्धि का कोई असर नहीं होगा।
- कक. आयात मे तथाकथित वृद्धि के बावजूद आवेदक कम्पनियों की बिक्री (वास्तविक मदों मे) एवं मार्केट शेयर बढ़ रहा है।
- खख. आवेदकों ने जांच की अवधि के पश्चात अपनी स्थापित क्षमता मे काफी वृद्धि की है।
- गग. आवेदकों की स्थापित क्षमता अखिल भारतीय मांग से अधिक है।
- घघ. आवेदकों ने अपनी क्षमता उपयोगिता मे 14% से 48% तक की वृद्धि की है एवं वह भी स्थापित क्षमता के विस्तारित आधार पर।
- ङङ. दोनों, इंडेक्स किए गए बिक्री एवं इंडेक्स किए गए उत्पादन आँकड़े, लगातार बढ़ रहे हैं।
- चच. इंडेक्स किया गया टर्नओवर अनुपात मे 01 से 3.45 तक की वृद्धि हुई है। इन्वेंटरी होल्डिंग मे गिरावट आयात मे वृद्धि के कारण नहीं है बल्कि बिक्री से उत्पादन कम रहने के कारण है।
- छछ. वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक रोजगार का स्तर घट रहा है। उसी अवधि के दौरान, प्रति व्यक्ति उत्पादकता मे काफी सुधार हुआ है। दोनों ये तथ्य एक साथ आवेदकों के लिए शुभ हैं।
- जज. आवेदकों की घरेलू बिक्री, नियंत, उत्पादन, स्थापित क्षमता एवं इसके उपभोग एवं मार्केट शेयर मे ग्लोबल बैंचमार्क से अधिक उनके बिक्री मूल्य होने के बावजूद सम्पूर्ण उधोग निष्पादन के विपरीत वास्तविक एवं संबंधी मदों मे स्पष्ट एवं कायम रखने योग्य सुधार है।
- झझ. आवेदकों की लाभप्रदता मे कभी स्थापित क्षमता के काफी विस्तारण के कारण अधिक व्याज दरों आपरेशनल सेट बैंक, प्राकृतिक आपदाओं, विजली एवं कोयले की कमी एवं वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था मे मंदी के कारण है न कि आयात मे तथाकथित बढ़ोत्तरी के कारण।
- जज. आयात मे तथाकथित वृद्धि एवं आवेदकों के परिचालन निष्पादन मे गिरावट, यदि कोई हो, के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- टट. आवेदकों ने यह आवेदन पब्लिक के नुकसान पर घरेलू बाजार मे अपने मूल्य बढ़ाकर लाभ कमाने की नीयत से किया है।
- ठठ. मई 2016 मे हिंडाल्को के एम डी के प्रेस इंटरव्यू के अनुसार भारत की अल्युमिनियम मांग दो अंकों मे पहुँच गई है, उनके राजस्व वर्तमान स्तर से कम नहीं होंगे, हिंडाल्को का लाभ बढ़ रहा होगा, एल एम ई पर अल्युमिनियम मूल्य को रेंज बाउंड देखा है, अल्युमिनियम के प्रीमियम उच्च वाल्यूम की सहायता से जहाँ है वहीं पर रहें की आशा है, हिंडाल्को को कमजोर प्रापण के प्रभाव को दूर करेगा, अल्युमिनियम की मांग मे वृद्धि है एवं अल्युमिनियम मुल्यो एवं एल एम ई पर प्रीमियम स्थायी रहेगा अतः आवेदक कम्पनियों को गंभीर क्षति की कोई आशंका नहीं है।
- डड. चीन एवं मध्यपूर्व देशों मे स्वभावत: विनिर्माण क्षमता मे विस्तारण को अनापेक्षित घटना नहीं माना जा सकता क्योंकि विनिर्माण क्षमता रातों-रात तैयार नहीं होती है।
- दद. चीन अर्थव्यवस्था मे वृद्धि दर मे कमी के कारण चीन से पी यू सी के वार्धित आयात को अनापेक्षित घटना नहीं माना जा सकता क्योंकि यह पुरे विश्व मे आर्थिक प्रव्रति के अनुसार है। चीन से पी यू सी के आयात से संबंधित आँकड़े आवेदन मे दर्शाए नहीं गए हैं।
- णण. मध्यपूर्व देश तेल एवं गैस रिजर्व्स एवं फ्राइट कास्ट एडवांटेज के कारण, भात से निकटता मे कारण एनर्जी उत्पादन की कम लागत रखते हैं। इसलिए मध्यपूर्व देशों से पी यू सी का नियंत किसी अनापेक्षित घटना के

कारण नहीं है। पी यू सी के आयात पर अपनी पहली जांच में महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा यही दृष्टिकोण लिया जा चुका है।

- तत. निकट भविष्य हेतु मध्यपूर्व देश के इन निहित एडवांटेज से पर पाने हेतु आवेदक कोई एडजस्टमेंट प्लान नहीं दे सकते। इसलिए यह आवेदन किसी एडजस्टमेंट प्लान विहीन है।
- थथ. जब याचिका फाइल की गई थी, तब मूल सीमा शुल्क झूटी की दर 5% थी, और जो यूनियन बजट, 2016 में बढ़ाकर 7.5% कर दी गई थी। अतः वर्धित सीमा शुल्क झूटी के अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- दद. याचिकाकर्ताओं ने याचिका दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की है ताकि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से उनकी स्वयं की विक्रय कीमतें बढ़ जाएं और इस प्रकार आम जनता की कीमत पर मुनाफाखोर बन जाएं।
- धध. पीयूसी के एक आधारभूत कझा माल होने के कारण उस पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से उनकी कझे माल की लागत में वृद्धि के संबंध में अधोमुखी उद्योगों पर प्रपातन प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में स्फीती की प्रवृत्ति स्थापित होगी।
- नन. पीयूसी पर रक्षोपाय शुल्क का परिणाम इनवर्टेड झूटी स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कझे माल पर आयात झूटी की दर तैयार माल पर झूटी की दर से कहीं अधिक होगी और अधोमुखी उद्योगों की जीवन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
- पप. क्योंकि अधोमुखी उद्योग खंडित है, उनके उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना संभव नहीं है, जिसके कारण उनका पतन हो जाएगा व उनकी जीवन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- फफ. याचिकाकर्ताओं की अपेक्षा अधोमुखी उद्योग ज्यादा श्रम प्रधान हैं और इसके कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी।
- बब. घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री, उत्पादन, इंवेंट्री, क्षमता उपयोग, सभी में काफी वृद्धि हुई है और डीआई की आर्थिक जीवन क्षमता और स्थिरता खतरे में नहीं है। ऐसी कोई अनेपक्षित घटनाएं नहीं हैं जिसके कारण आयातों में उछाल आया हो। अतः आयातों में इतनी मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को महत्वपूर्ण व्यापक हानि हुई हो।
- भभ. जब याचिकाकर्ताओं को महत्वपूर्ण व्यापक हानि नहीं हुई है तो पीयूसी पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।
- मम. यदि स्वतंत्र रूप से रक्षोपाय शुल्क सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है तो, यदि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण व्यापक हानि हुई हो फिर भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

#### आ. इंडोनेशिया

रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसरण में, प्राधिकारी विकासशील देशों को रक्षोपाय कार्यवाहियों से बाहर रख सकता है जब तक कि उनका इम्पोर्टिंग सदस्य के रूप में संबंधित उत्पाद के आयात का हिस्सा 3% से अधिक न हो वशर्ते 3% से कम आयात शेयर वाले विकासशील सदस्यों का सामुहिक हिस्सा कुल आयात के 9% से अधिक न हो। इंडोनेशिया का आयात का हिस्सा नगण्य है (भारत के कुल आयात के 3% से कम) और अन्य विकासशील देशों का संचयन 9% से कम है। महानिदेशक, रक्षोपाय अंतिम निष्कर्षों में प्राथमिक निष्कर्षों के भाग X में निर्णय रख सकते हैं।

#### इ. ताइवान

- क. जैसा कि पिछली जांच में किया गया था विचाराधीन अवधि के दौरान देशानुसार आयात का व्यौरा प्रकट किया जाना चाहिए।

- ख. प्राथमिक निष्कर्षों में उल्लेखित अनपेक्षित गतिविधियां जीएटीटी के अनुच्छेद XIX: (1) (ए) की कानूनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं। गतिविधियां देश द्वारा तब अनपेक्षित मानी जानी चाहिए जब इसे किसी एक खास घरेलू उद्योग ने नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन ने स्वीकार किया हो।
- ग. ताइवान एक विकासशील देश है और इसे रक्षोपाय करार के अध्याय 9.1 के अनुसार अपवाद का लाभ मिलना चाहिए।
- घ. केस के तथ्य दर्शते हैं कि रक्षोपाय करार के अध्याय 4 एवं अध्याय 2.1 के अनुसार घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। विल्कुल हाल की अवधि में घरेलू उद्योग के बहुत से आर्थिक पैमानों यथा उत्पादन, विक्री, इवेंट्री, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, रोजगार आदि में सुधार हुआ है। जिस समय 2014-15 की तुलना में 2015-16 (वार्षिक) में विषायाधीन वस्तुओं के आयात में 26% की वृद्धि हुई, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री में 32% की विक्री हुई। वास्तव में 2015-16 (वार्षिक) में जब आयात सर्वाधिक था, तब घरेलू उद्योग की विक्री उच्चतम थी। इससे कॉजल लिंक का खंडन होता है।
- ङ. घरेलू उद्योग की समायोजन योजना का खुलासा इच्छुक पक्षों को अगोपनीय प्रारूप में किया जाना चाहिए क्योंकि याचिका में इसएक गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- इ. रशियन फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेंट  
रशियन फेडरेशन ने अपने पश्च शुरूआत राय को दोहराया है।
- उ. मै. नोएडा एल्यूमिनियम कंपनी प्रा. लिमिटेड; इनलैंड इम्पोर्टर्स एंड कन्जयूमर एसोसिएशन
- क. चुंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरे देश में फैले हुए हैं इसलिए उनके हितों को पहले देखा जाना चाहिए क्योंकि ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और इन मुख्य उत्पादकों के तुलना में गई गुना अधिक निवेश उपलब्ध कराते हैं।
- ख. डीआई को याचिका केवल एचएस कोड 7601.10 के अधीन एल्यूमिनियम नॉट अलॉयड तक सीमित रखनी चाहिए।
- ग. डीआई को 7601.10 के आयात आंकड़े ही प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए जो कि नगण्यप्राय है। उनके द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों में अलॉय सिल्लियां भी शामिल हैं जो कि कच्चा माल नहीं है बल्कि रॉट एल्यूमिनियम से बना एक उत्पाद है।
- घ. एचएस कोड 7601.10 के अधीन एल्यूमिनियम के उत्पादन में लगी डाउनस्ट्रीम उद्योग को आयात से बड़ा आधार पहुंचा है विशेष रूप से एफटीए के अधीन एएसईएन देश।
- ङ. उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए एक अवाधित, मुक्त एवं समान अवसर क्षेत्र की आवश्यकता है।
- च. आयात में वृद्धि हुई है और डीआई की घरेलू विक्री में भी वृद्धि हुई है।
- छ. गैर अलॉय सिल्लियों का निर्यात 2011-12 में 234% से बढ़कर 2015-16 में 372% हो गया है। आवेदक पीयूसीके निर्यात के लिए फ्री हैंड चाहते हैं, इससे भारत में एल्यूमिनियम के द्वितीयक उत्पादकों को क्षति पहुंचेगी।
- ज. विश्व के अन्य भागों जहां उद्योग को एल्यूमिनियम सिल्लियां एलएमई+प्रीमियम कीमत पर मिलती है, से तुलना करने आवेदकों ने माल की कीमत इस तरह निर्धारित की है कि इसमें एलएमई+प्रीमियम+सीमा शुल्क ड्यूटी+ लॉजिस्टिक लागत ( आयात के मामलों की तरह)  $X \$ X$  रुपये कीमत के घटक शामिल हैं।
- झ. डीआई का कम प्राप्ति का तर्क भ्रामक है। वास्तव में वे सीमा शुल्क ड्यूटी में वृद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं।
- ञ. पिछले बजट में जब आयात ड्यूटी 5% से बढ़कर 7.5% कर दी गई थी, उन्होंने तुरंत घरेलू कीमतें 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दी थी।

- ट. डीआई ने आधार संदर्भ वर्ष के रूप में वर्ष 2011-12 ध्यान भटकाने के लिए लिया है क्योंकि उस समय एलएमई अपने उच्चतम स्तर पर थी। उन्हें रुपये के मूल्यहास से लाभ हुआ है। उन्हें ईंधन की लागत, जो कि उत्पादन लागत का 45% होता है, के नीचे गिरने की प्रवृत्ति के कारण लाभ हो रहा है।
- ठ. हिंडालकों की समापन वर्ष 2016 की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार समापन वर्ष 2015 के तुलना में बिक्री में रुपये 3000 करोड़ की वृद्धि हुई है। शुद्ध लाभ में गिरावट वर्ष के दौरान पूंजीकरण के कारण आई है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यहास में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वे संस्थापित क्षमता के बेहतर उपयोग के कारण उच्च बिक्री कर पाए हैं।
- ड. आवेदक एक व्यवसायी समूह में है जिससे कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग मरणासन्धि हैं और बहुत उत्सारण, अलौय एवं उत्पादन संबंधी निर्माता अपना काम बंद कर रहे हैं।
- ढ. आवेदकों की घरेलू कीमतें उनकी निर्यात कीमतों से कम हैं जो दर्शाता है कि वे आयात पर सीमा शुल्क छूटी के अधिरोपण का पूरा लाभ उठा रहा है। यदि घरेलू उद्योग को निर्यात की जा रही कीमत पर माल ऑफर किया जाए तो माल का आयात बहुत कम हो जाएगा।
- ण. डीआई का क्षमता उपयोग 2012 से 2016 तक बढ़ा है और वे बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहे हैं। उनकी क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग हो रहा है क्योंकि वे अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए पीयूसी का प्रयोग कर रहे हैं।
- त. एल्यूमिनियम से संबंधित एमएसएमई सेक्टर बहुत बुरी हालत में है और उनको सहायता की आवश्यकता है।

#### ऊ. मलेशिया

- क. डीआई को गंभीर क्षति आयात के अतिरिक्त अन्य कारकों से हो सकती है।
- ख. डीआई की संस्थापित क्षमता पूरे पीओआई के दौरान लगातार बढ़ी रही है जिसके कारण उनकी परिचालन लागत और वित्तीय निष्पादन प्रभाव पड़ा हो सकता है।
- ग. आयात का बाजार हिस्सा लगातार 11 से 15 प्रतिशत के मध्य था जबकि घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा 85 से 90 प्रतिशत के मध्य था जो कि दर्शाता है कि आयात ने डीआई के बाजार हिस्से को प्रतिस्थापित नहीं किया है।
- घ. इसका निर्धारण कि क्या रक्षोपाय कदमों की वास्तव में आवश्यकता है, उद्देश्यपरक रूप से किया जाना चाहिए।
- ঙ. रक्षोपाय जांच विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के संगत तरीके से की जानी चाहिए।

#### ऋ. यूरोपियन कमीशन

- ক. उत्पाद के दायरे में एल्यूमिनियम सिलियां, एल्यूमिनियम वायर रॉड्स और एल्युबिलेट्स आते हैं। तथापि, ये उत्पाद परस्पर विनिमेय नहीं हैं, इनकी उत्पादन प्रक्रिया में अंतर है और इसलिए उनको सीधे प्रतिस्पर्धी नहीं माना जा सकता।
- খ. भले ही इन उत्पादों की जांच समान प्रक्रिया के तहत की भी जा सके तो भी तीन विभिन्न उत्पादों के आयात और घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का विशेषण अलग से करना पड़ेगा।
- গ. हालांकि 2014/15 और 2015/16 के मध्य कुल आयात में वृद्धि हुई है, तथापि यह वृद्धि एकाएक और तेज नहीं हुई है बल्कि यह 2011/12 से धीरे-धीरे हुई है।
- ঘ. जिस समय आयात के बाजार हिस्से में लगभग 5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि हुई है, उसी समय याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा भी लगभग 3 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ा है। अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा काफी कम हुआ है जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं पर आयात का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

- ड. विश्लेषण की पिछली कुछ अवधियों के दौरान आयात की मात्रा और कुल घरेलू उत्पादन का अनुपात स्थिर रहा है और यहां तक कि हाल के वर्षों में कम हुआ है। आयात में वृद्धि की तुलना में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन मात्रा में वृद्धि ज्यादा थी। अतः इसको न्यायोचित ठहराना कि वर्धित आयात के कारण गंभीर क्षति हो रही है अथवा होने की संभावना है, कठिन है।
- च. एंटी डंपिंग और एंटी सबसिडी जांच में मैटेरियल क्षति की अपेक्षा रक्षोपाय जांच में गंभीर क्षति एक उच्च क्षति मानक है। तथापि, वर्तमान जांच में, क्षति के मुख्य संकेतक जैसे उत्पादन की मात्रा, घरेलू बिक्री और रोजगार, वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शते हैं। क्षमता में 40% की वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग दर में 10% प्वाइंट्स की वृद्धि हुई।
- छ. अधोमुखी प्रवृत्ति दर्शने वाला एक मात्र संकेतक लाभ है, जो प्रतीत होता है कि अंतिम वर्धित क्षमता के उपरांत 2015/16 में हानि में परिवर्तित हो गया। स्पष्ट आंकड़ों के अभाव में वे लाभ अथवा हानि के स्तर पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। क्षति के अन्य सभी संकेतकों में अनुकूल गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, घटता लाभ सुझाता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति पर आयात नहीं बल्कि अन्य कारकों ने प्रभाव डाला था।
- ज. कॉजेलिटी: क्षमता और क्षमता उपयोग, भारतीय कीमतें एवं लागत स्तर, मजदूरी, सीमित उपभोग और घरेलू प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया जाए। क्षमता में 40% की वृद्धि हुई है जिससे उद्योग प्रभावित हुए हैं क्योंकि चुकाए गए व्याज में वृद्धि हुई है। आयात तो एलएमई के ट्रेंड का अनुसरण मात्र था जबकि घरेलू उद्योग की कीमतें एलएमई से बहुत अधिक रही। कच्चे माल की कीमतों में कुल कमी के अगेस्ट बिक्री की लागत में 30% की वृद्धि से घरेलू उद्योग की संभावित अक्षमताओं का संकेत मिलता प्रतीत होता है।
- झ. मजदूरी में 150% की वृद्धि है, जबकि कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 5% बढ़ी है।
- ञ. विश्लेषण की अवधि में सीमित उपभोग में 70% तक की कमी आई है। इस कमी के कारण और घरेलू उद्योग की हालत पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।
- ट. प्राथिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं की हालत पर घरेलू प्रतिस्पर्धा के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- ठ. रक्षोपाय उपायों के अधिरोपण के मानदंडों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई।
- ए. मेटल रिसाइकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई)**
- क. अनरॉट एल्यूमिनियम पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से द्वितीयक उत्पादकों के वित्तों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- ख. प्राथमिक उत्पादकों की चाल बाजार पर एकाधिकार और द्वितीयक उत्पादकों को समाप्त करने की है।
- ग. पूर्व में आवेदकों ने रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग की थी जो कि अस्वीकार कर दी गई थी। वर्तमान मांग के विश्लेषण से भी यही निष्कर्ष निकलेगा।
- घ. रक्षोपाय करार के अनुसार, रक्षोपाय आपात आपात स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ड. प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत क्षमता उपभोग एवं उत्पादन के आंकड़े दर्शते हैं कि उत्पादन के साथ-साथ क्षमता उपभोग में वृद्धि हुई है।
- च. 2011-12 एवं 2013-14 में आयात में नियमित वृद्धि हुई है। 2015-16 में आयात में गिरावट आई है।
- छ. यदि निर्यात और उत्पादन के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो वे भी यही दर्शते हैं कि आवेदकों को शायद ही कोई क्षति हुई हो। इससे द्वितीयक उत्पादकों को नुकसान हुआ है और प्राथमिक उत्पादकों ने इसकी वजह से एक व्यवसायी समूह का सुजन कर लिया और इस तरह घरेलू बिक्री कीमत का एकाधिकारी निर्धारण करने लगे।

- ज. निर्यात/आयात के उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि गैर अलाँय सिल्लियों के निर्यात/आयात का प्रतिशत 2011-12 में 234% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही में 403% हो गया है। अतः जबकि मुक्त निर्यात की अनुमति हो रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग तर्कहीन है।
- झ. घरेलू उद्योग को शायद ही कोई क्षति हुई है।
- ऐ. **यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (मिनिस्ट्री ऑफ इकोनोमी)**
- क. प्रवृत्तियों के वस्तुपरक निर्धारण से पता चलता है कि भारत में अनरॉट एल्यूमिनियम के आयात में कोई औचक, तेज और बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। जांच के लिए सिर्फ यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि उत्पाद का आयात पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा था – अथवा पांच वर्ष पूर्व.....मात्र आयात की कोई वर्धित मात्रा पर्याप्त नहीं होगी। रक्षोपाय उपायों को लागू करने की इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी “वर्धित मात्रा” होनी चाहिए कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो सके अथवा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो सके।
- ख. महानिदेशक, रक्षोपाय के प्राथमिक निष्कर्षों की रिपोर्ट में बताई गई गतिविधियों का ध्यान से किया गया परीक्षण दर्शाता है कि वे भारत की विश्व व्यापर संगठन की बाध्यताओं के अंतर्गत ‘अनपेक्षित घटनाओं’ की परिभाषा के अंतर्गत आने की पात्रता नहीं रखते हैं। महानिदेशक, रक्षोपाय ने दृढ़ता से कहा था कि बहुत ही कम ऊर्जा लागत की मदद से मध्य-पूर्व में एल्यूमिनियम की उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि अनपेक्षित थी। उन्होंने कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं पाया कि घरेलू उद्योग के लिए ये अनपेक्षित क्यों होगा कि ‘बहुत कम ऊर्जा लागत’ वाले एक स्थान के पास उत्पादन की नई क्षमता थी। यह निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है कि अनपेक्षित घटनाओं के अस्तित्व के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई थी और इसलिए रक्षोपाय उपायों के अधिरोपण की पूर्वअपेक्षाएं पूरी नहीं होती है।
- ग. इसका कोई प्रमाण नहीं है कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1.(ए) जो कि क्षति के निर्धारण के उच्च मानदंड स्थापित करता है, के अनुसार तथाकथित वर्धित आयात के कारण आवेदकों को गंभीर क्षति हुई है अथवा होने का खतरे है। उत्पादन क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री, निर्यात, कर्मचारियों की संख्या एवं मजदूरी से संबंधित आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग किसी गंभीर क्षति से पीड़ित नहीं है।
- घ. पिछली रक्षोपाय शिकायत 2014 में दायर की गई थी जहां महानिदेशक, रक्षोपाय ने निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई थी, के बाद से डीआई के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- ड. आयात में किसी वृद्धि एवं तथाकथित क्षति के मध्य कोई कॉजल लिंक नहीं है। न तो रक्षोपाय जांच की शुरुआत के आवेदन और न ही महानिदेशक, रक्षोपाय के प्राथमिक निष्कर्ष कोई उत्साहपूर्ण साक्ष्य अथवा वर्धित आयात एवं तथाकथित क्षति के मध्य कोई कॉजल लिंक विद्यमान होने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। 2015-16 में जब आयात के स्तर में वृद्धि हुई तब घरेलू बिक्री, उत्पादन की क्षमता, बाजार हिस्सा, उत्पादन, संस्थापित क्षमता और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई।
- च. घरेलू उद्योग के लाभ में औचक कमी सीधे एलएमई कीमतों में उतार-चढ़ाव का परिणाम है।
- छ. नियमों के अधीन रक्षोपाय जांच जारी रखने की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।
- ज. जांच कोई उपचार अधिरोपित किए बिना समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- ओ. **मै. हीरो मोटर्स कोर्प लिमिटेड**
- क. वे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनरॉट एल्यूमिनियम के उपयोगकर्ता हैं। अनरॉट एल्यूमिनियम की खपत मुख्यतः ऑटोमोबाइल सेक्टर, बरतनों सहित उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग एवं पैकेजिंग सेक्टर में होती है।

- ख. महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंधन है। महानिदेशक (रक्षोपाय) ने अनिवार्य अवधि की समाप्ति तक की प्रतीक्षा नहीं की और जल्दबाजी में प्रारंभिक निष्कर्ष जारी कर दिए। इससे जांच की महत्वपूर्ण अवधि में इच्छुक पक्ष इसमें सम्मिलित होने के अपने अधिकार से बंचित रह गए।
- ग. जब महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए गए तो उनके पास संपूर्ण एवं व्यापक सूचना नहीं थी।
- घ. 2009 एवं 2014 में घरेलू उद्योग ने अनुचित व अकारण सुरक्षा मांगी थी और तब कार्यवाही बंद कर दी थी/रक्षोपाय शुल्क की अनुशंसा नहीं की गई थी। आवेदकों की समग्र आर्थिक व वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ड. डी ई द्वारा कोई समायोजन योजना दायर नहीं की गई, इसलिए महानिदेशालय (रक्षोपाय) जांच शुरू नहीं कर सकता था और प्रारम्भिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था।
- च. महानिदेशक (रक्षोपाय) को एकदम हाल की अवधि के लिए डी आई के निष्पादन को देखना चाहिए। लेखा वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही के लिए हिन्डाल्को के वित्तीय परिणाम स्पष्टतया स्थापित करते हैं कि इसको बम्पर लाभ हुआ है तथा घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं है।
- छ. जनहित के मुद्दे पर प्रारम्भिक निष्कर्ष चुप है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् ऑटोमोबाइल, पावर उपभोग्य वस्तुएं, बर्तन, पैकेजिंग एवं आवास क्षेत्र द्वारा उपयोग में लायी जा रही कच्ची सामग्री में एल्युमिनियम सबसे महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम को महंगा बनाने वाली सरकार की किसी भी कार्रवाई से डाउन स्ट्रीम उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं को अस्थिर करने के किसी प्रयास से रोजगार की गंभीर स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी।

**औ. मैसर्स इण्डियन इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई ई ई एम ए)**

- क. एल्युमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों को, किसी रक्षोपाय शुल्क के किसी काल्पनिक आरोपण को ध्यान में रखे बिना, पूरी प्रोजेक्ट आपूर्ति अवधि के लिए, केबल्स, कन्डकर्ट्स, ट्रान्सफार्मर्स और/ अथवा कोई और अन्य इलैक्ट्रीकल उत्पाद के निर्धारित कीमत के विरुद्ध, सभी आई ई ई एम ए सदस्यों को आपूर्ति उपलब्ध कराने पर सहमत होना चाहिए।
- ख. हमेशा ही यह मूल सिद्धांत रहा है कि तैयार वस्तुओं की अपेक्षा कच्चे माल पर कम ड्यूटी हो, परंतु पूर्व बजट में, एल्युमिनियम पर आयात शुल्क की दर को 5% से 7.5% तक बढ़ाया गया इस प्रकार केवल, कन्डकर्टर्स इत्यादि के लिए कच्चे माल एवं तैयार माल पर आयात शुल्क की दर तैयार माल के बराबर है।
- ग. प्राईमरी एल्युमिनियम पर कोई रक्षोपाय शुल्क लगाने से पहले, उलटे ड्यूटी ढाँचे की घटना को प्रभावहीन करनेके लिए, केबल्स, कन्डकर्ट्स, ट्रान्सफार्मर्स अथवा अन्य कोई उत्पाद समूह, जो एल्युमिनियम को कच्चे माल के हिस्से के रूप में प्रयोग करता है, को मजबूत शुल्क संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, और संरक्षण, रक्षोपाय शुल्क, यदि लगाया जाता है, की मात्रा से अधिक होना चाहिए।
- घ. प्रोजेक्ट आयात के अंतर्गत प्रयोज्य ड्यूटी मात्र 5% है और इलैक्ट्रीकल उद्योग के अधिकांश हिस्सों पर आयात शुल्क पहले ही 10% तक है, इस प्रकार इसका परिणाम नकारात्मक विभेदी है। किसी भी रक्षोपाय ड्यूटी को लगाने से पहले, चैप्टर 98 के अंतर्गत मौजूद, उलटे ड्यूटी ढाँचे के समाधान के लिए इलैक्ट्रीकल उपस्कर उद्योग के लिए प्रोजेक्ट आयात के अंतर्गत दीर्घावधि समाधान प्रदान किया जाए।
- ड. वर्तमान में भारत में निर्माण किए जा रहे केबल्स, ट्रान्सफार्मर्स तथा अन्य उत्पादों चैप्टर 98 के अंतर्गत आयात की अनुमति न दी जाए।

- च. 0% की दर पर एच. एस. कोड 7607 के अंतर्गत आयात की गई 5 माइक्रोन एल्युमिनियम फायल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से गंभीर उल्टा झूटी ढांचा पैदा हो जाएगा क्योंकि तैयार माल अर्थात् कैपीसिटर, पर भी 0% सीमा शुल्क झूटी दर है। एच एस कोड 7607 के अंतर्गत एल्युमिनियम फायल को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाए।
- छ. निर्यात के विरुद्ध आयात को कम करने के लिए, स्थानीय प्राईमरी उत्पादकों से, अनुचित प्रीमियम प्रभारित किये विना, एल एम ई आधार पर शुल्क मुक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिए कहा जाए।
- ज. स्थानीय डाउनस्ट्रीम उद्योग पर निहितार्थ का आकलन किया जाए तथा इसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

**अं मैसर्स एल्युमिनियम सेकेण्डरी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन**

- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन घटा नहीं है बल्कि इसके विपरीत सभी तीनों आवेदकों ने अपना उत्पादन बढ़ाया है, आवेदकों ने उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया है और नियमित निवेश करते हुए इसे और बढ़ाना जारी रखे हुए हैं और समस्त उत्पादन को विक्रय करते हैं, तो वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आयात के कारण कोई धृति पहुंची है।
- ख. डी आई (घरेलू उद्योग) की लाभप्रदता कम हुई है परंतु किसी भी उत्पादक को घाटा नहीं हुआ है। घटी हुई लाभप्रदता का कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त एल्युमिनियम की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा क्षमता बढ़ाने के लिए डी आई द्वारा किए गए निवेश के कारण वहन किया गया भारी ह्रास एवं व्याज लागत है। इसलिए आयात ने उनकी लाभप्रदता को प्रभावित नहीं किया है।
- ग. आवेदकों को पहले ही कम से कम 13% संरक्षण प्राप्त है। पहले ही 7.5% मूल्यवर्धित (प्रभावी रूप से 8.25%) आयात शुल्क है और वे आयातित धातु पर निकासी एवं फारवर्डिंग प्रभार के रूप में 5% और जोड़ रहे हैं। इस प्रकार भारत में एल्युमिनियम धातु की कीमतें विश्व में अन्य जगहों पर प्रचलित एल्युमिनियम धातु की कीमत की तुलना में कम से कम 13% अधिक हैं। आवेदकों को अन्य अगले संरक्षण पर विचार करने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है।
- घ. आवेदकों के सूचीबद्ध आंकड़े 2011-12 में रोजगार के स्तर में 5% की वृद्धि को सिद्ध करते हैं। विगत 5 वर्षों में आवेदकों ने उनकी क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि की है और वे उनकी पूर्ण उत्पादन क्षमता से चल रहे हैं। आवेदकों द्वारा श्रमशक्ति में कोई कटौती अथवा छटनी नहीं की गई है, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता और रक्षोपाय शुल्क की उगाही का कोई औचित्य नहीं है।
- ड. आवेदक एल्युमिनियम धातु की आयात मात्रा में तेज वृद्धि को सिद्ध करने में असफल रहे हैं क्योंकि आयात में 15% की वृद्धि को किसी भी प्रकार से आयात में तेज वृद्धि नहीं कहा जा सकता।
- च. आवेदकों की लाभप्रदता में एल्युमिनियम धातु की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में कमी से गिरावट आई है। वे रक्षोपाय शुल्क के उद्धरण की मांग उनकी कीमतों में वृद्धि करके अनुचित लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं।
- छ. ज्यादातर आयात, लघु सेकेन्डरी विनिर्माताओं द्वारा निर्यात के विरुद्ध एडवांस लाइसेंस के अंतर्गत हो रहे हैं।
- ज. आवेदकों का यह निवेदन कि चीन और मध्यपूर्व से एल्युमिनियम धातु का सस्ता आयात होता है, बिलकुल झूठ एवं भ्रामक है। चीन की सरकार उनके देश से एल्युमिनियम धातु के निर्यात पर 5% निर्यात शुल्क उद्धरण करती है जिसके कारण चीन से भारत में प्राइमरी एल्युमिनियम धातु का कोई आयात नहीं हो रहा है, आयातित एल्युमिनियम धातुकी कीमत निश्चित है जो लंदन मैटल एक्सचेंज (एल एम ई) में विद्यमान कीमत पर आधारित है जो पूरे विश्व में एक समान है। आयात का फार्मूला है एल एम ई + एम जे पी

+आयात शुल्क (8.25%) + 5% निकासी एवं फारवर्डिंग प्रभार आवेदक भी उनकी कीमतें इसी प्रकार निर्धारित कर रहे हैं और यह एल एम ई कीमत में परिवर्तन पर आधारित है।

- झ. उत्पादन घरेलू मांग से अधिक होने के कारण आवेदक उनकी धातु को विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात कर रहे हैं। वे धातु को एल एम ई कीमत + निर्यात के समय विद्यमान प्रीमियम पर निर्यात कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं।
- ज. एल. एम. ई. कीमतों में वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में बढ़ोतरी हुई है, स्वाभाविक रूप में वे चालू वित्त वर्ष में बहुत अधिक लाभ कमाएंगे।
- ट. पहले दो अवसरों पर डी आई के रक्षोपाय शुल्क के अनुरोध को न्यायोचित नहीं पाया गया।
- ठ. गर्म धातु उत्पादन पर आधारित, डी. आई का क्षमता उपयोग लगभग 100% है।
- ड. एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इण्डिया समस्त एल्युमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

**अ: मैसर्स जिन्दल एल्युमिनियम लिमिटेड, सैन्चुरी एक्सट्रूनल लिमिटेड**

- क. चैप्टर 76.01 के अधीन मदों के अतिरिक्त, आवेदक वायर रॉड, स्लेन्स, शीट्स, सर्कल्स, एक्सट्रूजन एवं फायल्स का विनिर्णय भी करते हैं। ये सभी उत्पाद केवल हॉट मेटल से ही बनाये जाते हैं, इसलिए हॉट मेटल के संबंध में परिगणित स्थापित क्षमता से ही वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा। आवेदकों का यह दावा गलत है कि उनका क्षमता उपयोग 48% तक घट गया है, और ये सभी उनकी 100% क्षमता से चल रहे हैं। जब क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, अतः कोई नुकसान नहीं है।
- ख. याचिका में दर्शायी गई 38.58 लाख एम टी की स्थापित क्षमता ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दर्शायी गई है और पूरी तरह क्रियाशील नहीं है। वेदान्ता का एस ई जैड, झारसुगदा में 1.25 मीलियन टन स्मेलिंग प्लाण्ट बिजली एवं एल्युमिना मुद्दों के कारण पूरी तरह स्ट्रीम में नहीं है। कम क्षमता उपयोग को दर्शनी के लिए इरादतन बढ़ा-चढ़ा कर क्षमता को बताया गया है।
- ग. वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में आयात में मामूली वृद्धि देखी गई है, परंतु उत्पादन के मामले में प्रतिशत के रूप में यह लगभग उसी स्तर पर रहा है और थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 2011-12 में उत्पादन 13% था जो 2015-16 में बढ़कर 15% हो गया। अन्यथा भी 4 वर्ष में 78% की वृद्धि विलकुल भी खतरनाक नहीं है बल्कि एमदम सामान्य है और इसे उद्घाल नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क नगाया जाये। याचिकाकर्ताओं का स्वयं का उत्पादन 76% तक बढ़ा है और उनके निर्यात में 336% की वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ताओं की स्थापित क्षमता एवं घरेलू बिक्री में भी 40% की वृद्धि हुई है।
- घ. चूंकि आयात का थोक हिस्सा निर्यात के विरुद्ध एडवांस लाइसेंस पर शुल्क मुक्त आधार पर आयात किया जा रहा है इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है।
- ङ. लाइसेंस के विरुद्ध आयात की गई मात्रा के विवरण से शुल्क प्रदत्त आयात की वास्तविक मात्रा का पता चलेगा।
- च. डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री को उनके एडवांस लाइसेंस के विरुद्ध एल्युमिनियम का आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता इन लाइसेंसों के विरुद्ध एल. एम. ई. दरों पर शुल्क एवं करों को अदा किये विना एल्युमिनियम की आपूर्ति नहीं करना चाहते हैं।
- छ. स्थानीय उत्पादकों से एडवांस लाइसेंस के विरुद्ध निर्यात के लिए प्राइमरी एल्युमिनियम मंगाने के लिए विगत में उनके द्वारा बार – बार किये गये प्रयास कोई सकारात्मक परिणाम देने में असफल रहे हैं।

- ज. आवेदक एल एम ई शर्तों पर निर्यात करते हैं परंतु इसी कीमत पर स्थानीय डाउन स्ट्रीम विनिर्माताओं को मना किया जाता है। डी .आई की निर्यात वसूली कम से कम 13% कम है, फिर भी वे लाभ कमा रहे हैं जबकि घरेलू आपूर्ति के लिए उनकी कीमत पहले ही ऊँची है।
- झ. यह कहना गलत है कि आयातित एल्युमिनियम सस्ता है, क्योंकि आवेदकों की कीमतें आयात समानता से जुड़ी है तथा समय-समय पर विद्यमान आयातित एल्युमिनियम की लागत के समान ही है। यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो आवेदक अपनी कीमतें बढ़ा देंगे और आयात जारी रहेगा और वे सीमा शुल्क ऊँटी, निकासी एवं फारवर्डिंग प्रभार इत्यादि जैसी कुछ लागत को वहन नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी इनको अपनी स्थानीय कीमतों में जोड़ते हैं और उनके विदेशी समकक्षों की तुलना में 13-14% अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं।
- ञ. याचिकाकर्ताओं को यू एस डालर के विरुद्ध भारतीय रूपये में ह्रास से फायदा हुआ है क्योंकि 2011 और 2015 के बीच भारतीय रूपये में लगभग 39% ह्रास हुआ है।
- ट. यथा आरोपित, चीन एवं मध्यपूर्व से एल्युमिनियम धातु का कोई सस्ता आयात नहीं होता है। चीन से एल्युमिनियम धातु के निर्यात पर 5% निर्यात शुल्क है। मध्यपूर्व से आयात एल एम ई कीमत पर आधारित हैं, अतः सस्ते नहीं हैं।
- ठ. याचिकाकर्ताओं का यह दावा आधारहीन है कि बढ़े हुए आयात ने उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है और उनके लगातार घाटे का कारण है।
- ड. हिन्डाल्को नियमित रूप से लाभ कमा रहे हैं और अप्रैल- जून, 2016 को समाप्त पहली तिमाही के लिए उनका लाभ 2014-15 की इसी अवधि में ₹0 61 करोड़ की तुलना में ₹0 294 करोड़ तक उछला है।
- ढ. नाल्को को भी अप्रैल – जून, 2016 में निवल लाभ हुआ है।
- ण. वर्तमान में ह्रासके बढ़े हुए बोझ, अतिरिक्त क्षमता के सृजन में भारी पूँजी व्यय पर वित्तीय खर्चों के कारण याचिकाकर्ताओं की लाभ प्रदत्त थोड़ा सा प्रभावित हुई है।
- त. वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा करते समय हिन्डाल्को द्वारा जारी विवरणी के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान उनका लाभ ₹0 607 करोड़ है, ह्रास एवं क्षमता विस्तार पर बढ़े हुए पूँजी खर्च पर उच्च वित्तीय लागत के कारण लाभ कम है, जब से उन्होंने अपने सभी विस्तार पूरे किये हैं वे पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं; अब से वित्त लागत कम होगी और लाभ बढ़ेगा; ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि आयात में उद्घाल के कारण उनका लाभ कम है।
- थ. डी आई ने कहा है कि घरेलू कीमतों में उनकी घटी कीमतों का कारण गिरता हुआ प्रीमियम है। प्रीमियम को कभी भी लाभ बढ़ाने वाला कारक नहीं माना अथवा समझा गया है और कम प्रीमियम पर भी याचिकाकर्ता भारी लाभ कमा रहे हैं।
- द. किसी भी अन्य वस्तु की तरह ही एल्युमिनियम में भी उतार – चढ़ाव की प्रवृत्ति है और यह अधोमुखी दौर है। याचिकाकर्ता वर्तमान एल्युमिनियम की कम कीमतों को रक्षोपाय शुल्क हेतु अनुरोध का आधार नहीं बना सकते।
- ध. किसी उद्योग को होने वाली क्षति को प्रमाणित करने वाले महत्वपूर्ण चिन्ह अनुपस्थित हैं। इस अवधि के दौरान पर्याप्त बढ़े हुए उत्पादन एवं विक्री के बावजूद वर्ष 2011-12 की तुलना में 2015-16 में इन्वेन्टरी घटी है। श्रमशक्ति भी 5% बढ़ी है।
- न. जो उद्योग छटनी हुए कर्मचारी, कोई अनप्रयुक्त क्षमता, लाभ में कोई असामान्य गिरावट के किसी लक्षण को नहीं दर्शाता है, उसे खतरे में पड़ा नहीं माना जा सकता।

- प. मध्यपूर्व के उत्पादक एल्युमिनियम का बहुत ऊंची लागत पर आयात करते हैं, जबकि भारत में प्राइमरी उत्पादकों के पास सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले स्थानीय बोक्साइड तथा कोयला होने का प्राकृतिक लाभ है।
- फ. भारत की तुलना में मध्यपूर्व के विनिर्माताओं के लिए कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी लागत न्यूनतम 40 से 45% अधिक है। मध्यपूर्व के आपूर्तिकर्ता भी ऐसे इन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर एल्युमिनियम धातु की उनकी विक्री कीमत निर्धारित कर रहे हैं, जैसा कि भारतीय उत्पादकों द्वारा किया जाता है। अतः मध्यपूर्व से एल्युमिनियम का कोई सस्ता आयात नहीं होता।
- ब. एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इण्डिया मूलतः प्राइमरी उत्पादकों द्वारा शासित है और सैकेन्डरी विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जैसा कि दावा किया जा रहा है।
- भ. रक्षोपाय शुल्क लगाने से सैकेन्डरी विनिर्माताओं को बड़ी चोट पहुंचेगी वह भी तब जब वे पहले से रुकी मांग, निर्यात में गिरावट और बढ़ते हुए घाटे से जूझ रहे हैं। चीन से बड़े स्तर पर एल्युमिनियम सैकेन्डरी गुड्स जिसे उनकी सरकार द्वारा 13% निर्यात सहायता के कारण सहायता प्राप्त है, के आयात के कारण बहुत सी लघु एवं मझौली कम्पनियां बंद होने के कगार पर हैं। चीन से आयातित सैकेन्डरी उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।

**(अ) मैसर्स एल्युमिनियम बहरान बी एस सी**

- क. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन:- निर्यातक का निवेदन है कि प्राकृतिक न्याय के मान्य एवं स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए जांच की गई है एवं किया जाना जारी है। यह एक मान्य सिद्धांत है कि उन सभी साक्ष्यों को, जिसे प्राधिकारी द्वारा पार्टी के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाना है, पार्टी के सामने उनकी टिप्पणी एवं प्रतिवाद के लिए रखा जाना चाहिए अन्यथा यह न्याय संगत सुनवाई के विरुद्ध होगा।
- ख. रक्षोपाय नियमावली के नियम 6 द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसके द्वारा महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा की जाने वाली किसी रक्षोपाय जांच को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। ऐसी जांच जो पर्याप्त रूप से उच्च चरण में हो, में निर्यातक के पास स्पष्टता नहीं है कि आंकड़ा प्रस्तुत करते समय घरेलू उधोग से संबंधित किस आंकड़े पर भरोसा किया जाए।
- ग. रिकार्ड में कोई अंतिम सूचना नहीं है। जांच शुरू होने के बाद से भिन्न सूचनओं के साथ पांच भिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं और महानिदेशक रक्षोपाय की ओर से कोई निदेश नहीं है कि इच्छुक पार्टीयों द्वारा विचार एवं टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए किस दस्तावेज पर भरोसा किया जाए जिस अवधि के लिए आंकड़े प्रदान किये गए हैं उसके संबंध में कोई संगतता नहीं है।
- घ. याचिका में वित्त वर्ष 2015-16 के उन सटीक महीनों जिनको ध्यान में रखा गया है, के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। याचिका में दी गई आयात विवरणी में अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक के आंकड़ों पर विचार किया गया। याचिकाकर्ता के वॉल्यूम आंकड़े के लिए, मार्च, 2016 तक की अवधि पर विचार किया गया। कीमत मापदंड, जैसे लाभ के लिए किसी भी अवधि की पहचान नहीं की गई है। वास्तव में उन्हें पता नहीं है कि वित्त वर्ष 2015-16 के किस महीने को ध्यान में रखा गया है।
- इ. दिनांक 23 एवं 24 मई, 2016 के पत्रों में संशोधित आंकड़े – (i) उनके पत्र द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा जो आंकड़े प्रदान किये गए हैं, अप्रैल से , 2015 (वार्षिकीकृत) की अवधि पर आधारित थे। याचिका में मार्च, 2016 तक के आंकड़े दिये गए हैं (कम से कम वॉल्यूम मापदण्ड के संबंध में), 24 मई, 2016 को दायर अद्यतन आंकड़े, संक्षिप्त अविधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराते हैं और फिर इनको वार्षिकीकृत करते हैं। आंकड़ों का नवीनीकरण प्रदान किये गए सभी आंकड़ों के लिए नहीं किया गया है।

- च. प्रथम सत्यापन रिपोर्ट में कुछ मापदण्डों के संबंध में आंकड़े हैं और यह बहुत से अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड जैसे लाभ/हानि, नियोजित पूंजी पर रिटर्न, कीमतों में कटौती, कम दाम पर बिक्री, मजदूरी, ब्याज इत्यादि पर चुप हैं।
- छ. द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट में जून, 2016 तक आंकड़े दिये गये। परन्तु यह बहुत से अन्य मापदण्ड जैसे लाभ/हानि नियोजित पूंजी पर रिटर्न, कीमतों में कटौती, कम दाम पर बिक्री, मजदूरी, ब्याज आदि पर चुप हैं।
- ज. जन सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं ने आंकड़ों का दूसरा सैट प्रस्तुत किया है। इस आंकड़े में अचानक याचिकाकर्ताओं की एस ई जैड यूनिटों के संबंध में सूचना है जिसका जन सुनवाई तक कोई उल्लेख नहीं किया गया। वे जांच के इस चरण में आंकड़े प्रस्तुत करने पर घोर आपत्ति करते हैं और इसे रिकार्ड में नहीं लिया जाना चाहिए। यह नवीनीकृत आंकड़े भी असंगतताओं से भरे हुए हैं।
- झ. संशोधित आंकड़े यह स्पष्ट नहीं करते कि वित्त वर्ष 2015-16 के किन महीनों को ध्यान में रखा गया है और कि क्या आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है।
- ञ. आंकड़े दूसरी सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं।
- ट. जबकि संशोधित आंकड़े घरेलू उद्योग के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं के संबंध में आंकड़ों को नवीनीकृत नहीं किया गया है। डी आई ने 23 मई, 2016 के पत्र के माध्यम से कम्पनीवार आंकड़े प्रस्तुत किए थे, पर इन्हें अद्यतन नहीं किया गया है। जन सुनवाई के बाद के संशोधित आंकड़ों ने यूनिट के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जैड) के अंतर्गत आने के आधार पर डी आई की नुकसान की सूचना को अलग – थलग किया है, परन्तु जिन महीनों को ध्यान में रखा गया है, उनका उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता लगातार अस्पष्ट रहे हैं और आंकड़ों तथा उस अवधि जिसके लिए आंकड़े प्रदान किये गये हैं के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार प्रदान किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करते हैं।
- ठ. निर्यातक की वास्तव में उस सूचना तक पहुंच नहीं है, जिसके लिए वह अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। यह न केवल रक्षोपाय नियमावली के नियम 6 का उल्लंघन है, बल्कि यह निर्यातक के न्यायपूर्ण सुनवाई के अधिकार को भी अस्वीकार करता है।
- ड. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में असंगताएं:- पांच दस्तावेजों में आंकड़े परस्पर महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं। जन सुनवाई के बाद संशोधित आंकड़े में प्रदान किये गए क्षति आंकड़े, दूसरी सत्यापन रिपोर्ट, प्रथम सत्यापन रिपोर्ट, याचिकाकर्ता द्वारा उनके 24 मई, 2016 के पत्र द्वारा प्रदान किये गए नवीनीकृत आंकड़े तथा याचिका, न केवल जांच अवधि में प्रदान किये गए आंकड़ों के लिए बल्कि पिछले वर्षों के लिए भी असंगत हैं।
- ढ. एक बार जब दूसरी सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई, सत्यापन रिपोर्ट में शामिल मापदण्डों पर सूचना को रोक दिया गया तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा जन सुनवाई के बाद प्रस्तुत किये गए संशोधित आंकड़े द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट के विरोधी हैं।
- ण. घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री, कैप्टिव खपत, घरेलू बिक्री मूल्य, निर्यात बिक्री मूल्य तथा स्टॉक और द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट तथा जन सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गए निवेदन के बीच अंतर है।
- त. द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट को आधार रखते हुए पांच दस्तावेजों, अर्थात् याचिका, 24 मई, 2016 का पत्र, प्रथम सत्यापन रिपोर्ट, द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट तथा जन सुनवाई के बाद प्रस्तुत किये गये संशोधित आंकड़े में दर्शाएं गए आंकड़ों की तुलना करने से भिन्नता प्रदर्शित होती है।

- थ. जन सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े, महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा उनकी सत्यापन रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों से भिन्न है। महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा जारी सत्यापन रिपोर्ट बहुत से जरूरी आर्थिक मापदण्डों पर स्पष्ट रूप से चुप है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों में असंगतता को देखते हुए आंकड़े पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- द. वे, घरेलू उद्योग के सभी सार्थक आर्थिक मापदण्डों के लिए डाटा/सूचना पर इच्छुक पार्टियों को पहले अधिसूचित करने का महानिदेशक रक्षोपाय से अनुरोध करते हैं, जैसा कि महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा सत्यापित किया गया हो सकता है। फिर महानिदेशक रक्षोपाय इच्छुक पार्टियों को उनकी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए समुचित समय प्रदान करें तथा एक और जन सुनवाई तय करें ताकि इच्छुक पार्टियों के पास टिप्पणी करने के लिए सभी सार्थक एवं सत्यापित सूचना हो। यदि सत्यापित आंकड़ों तक पहुंच प्रदान किये बिना परिभाषित जांच अवधि तक जांच जारी रहती है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का खुला उल्लंघन होगा।
- ध. याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा दिनांक 24 मई, 2016 को प्रस्तुत शक्ति सूचना के संबंध में बहुत अधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा जारी ट्रेड नोटिस की अपेक्षाओं का पूर्ण उल्लंघन करते हुए सभी सूचनाओं को सूचीबद्ध किया है, जो याचिका में सूचीबद्ध नहीं थी।
- न. याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका के गैर गोपनीय पाठ में कोई समायोजन योजना नहीं दी गई है जो ट्रेड नोटिस का स्पष्ट उल्लंघन है। इच्छुक पार्टियां बिना किसी सूचना के समायोजन योजना पर कोई अर्थपूर्ण प्रस्तुति नहीं कर सकते।
- प. जन सुनवाई के दौरान महानिदेशक रक्षोपाय ने निदेश दिया कि समायोजन योजना के गैर गोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध कराया जायेगा। इसे 06 अक्टूबर, 2016 अर्थात् इन लिखित प्रस्तुतियों के देय होने से केवल एक दिन पहले उपलब्ध कराया गया।
- फ. याचिकाकर्ताओं द्वारा जांच में बाद के चरण में प्रदान किया गया गैर गोपनीय पाठ कोई अर्थपूर्ण सार संक्षेप प्रदान नहीं करता, इसमें गंभीर कमियां हैं और याचिकाकर्ताओं ने बहुत अधिक गोपनीयता का दावा किया है। इससे निर्यातिक के अर्थपूर्ण निवेदन करने के अधिकार को बुरी तरह से कमजोर किया है।
- ब. याचिकाकर्ताओं ने अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किये बिना केवल कहा है कि वे बिजली खपत, विभिन्न कच्चे माल की खपत, प्रशासनिक एवं बिक्री लागत को घटायेंगे और क्षमता उपयोग को बढ़ायेंगे। यह आंकना असंभव है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित योजना व्यवहारिक है।
- भ. महानिदेशक रक्षोपाय याचिकाकर्ताओं से समायोजन योजना के संशोधित गैर गोपनीय पाठ की मांग कर सकते हैं जिसमें प्रदान किए गए आंकड़ों के लिए सूचीबद्ध संख्या तथा उपायों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण शामिल होगा।
- म. याचिकाकर्ताओं ने आयात आंकड़े के संबंध में अद्यतन सूचना दायर नहीं की है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2015-16 (421,963.70 एम टी) के लिए आंकड़ा डी जी सी आई एंड एस के डाटा बेस में उपलब्ध है। इस माह की अवधि के लिए ( 432,925 एम टी) आंकड़े का वार्षिकीकरण डी आई के पक्ष में टेंडर परिणाम प्रस्तुत करता है।
- य. याचिकाकर्ताओं ने आयात में वृद्धि दिखाने के लिए 2007 से 2016 तक आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जबकि क्षति मापदण्डों का विश्लेषण वर्ष 2011 से 2016 तक किया गया है।

- कक. “ऐसी बढ़ी हुई मात्रा” वाक्यांश का मतलब है कि आयात में वृद्धि पर्याप्त रूप से तीव्र, अचानक महत्वपूर्ण एवं हाल की होनी चाहिए।
- खख. आयात का बड़ा हुआ परिमाण “अभूतपूर्व” अथवा “अप्रत्याशित” होना चाहिए था। आयात की केवल कुछ बढ़ी मात्रा पर्याप्त नहीं होगी। “ऐसी बढ़ी हुई मात्रा” द्वारा डी आई को अवश्य ही गम्भीर क्षति पहुंचाने का खतरा या कारण होना चाहिए।
- गग. हाल ही की वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए, निर्यातकों का निवेदन है कि महानिदेशक रक्षोपाय को 2007 से आंकड़ों पर बिलकुल विचार नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सर्वाधिक हाल के आंकड़े पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। महानिदेशक रक्षोपाय को याचिकाकर्ताओं को सर्वाधिक हाल के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए।
- घघ. आयात में कथित वृद्धि अचानक एवं हाल की नहीं है। 2007-2008 से 2011-12 तक आयात में वृद्धि 143% थी और 2011-12 से जांच की अवधि तक 178 थी जो यह प्रमाणित करता है कि आयात में वृद्धि की घटना अचानक एवं हाल की नहीं थी।
- डड. “अप्रत्याशित घटना” को स्थापित करने के लिए उन घटनाओं को दर्शाना आवश्यक है, जो ‘अदृष्ट’ अथवा “अप्रत्याशित” थी, ऐसी घटनाएं जी ए टी टी (गैट) के अंतर्गत सदस्य द्वारा वहन किए गए दायित्व के प्रभाव स्वरूप थी। ऐसी घटनाओं से आयात में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता याचिका में यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि कौन सी घटनाएं अप्रत्याशित थी और ऐसी घटनाओं एवं आयात में वृद्धि के बीच संबंध था। महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा प्राथमिक निष्कर्षों में निर्धारित घटनाओं को अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं माना जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ताओं अथवा महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा अपेक्षित तीन शर्तों की पुष्टि अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है। “नोट अलॉयड इनगॉट ऑफ अनरॉट एल्युमिनियम की अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 2014के अंतिम निष्कर्ष में, महानिदेशक रक्षोपाय ने पूर्व में स्वयं ही निर्णय दिया कि घटनाओं को “अप्रत्याशित घटना” नहीं माना जा सकता है।
- चच. यदि चीन में सचमुच पी यू सी अधिशेष है तो चीन से महत्वपूर्ण रूप में आयात होना चाहिए था। जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए आंकड़े दर्शते हैं कि चीन से आयात भारत में किए गये कुल पी यू सी आयात का लगभग 2.6% है।
- छछ. किसी “अप्रत्याशित घटना” की अनुपस्थिति में वर्तमान जांच में कोई दम नहीं है। अतः इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- जज. डी आई को कोई क्षति नहीं हुई है, गम्भीर क्षति को तो छोड़ ही दें। निवेदन के उद्देश्य से, उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा जन सुनवाई के बाद प्रस्तुत किए गए संशोधित आंकड़े पर यथासंभव सीमा तक विचार किया है।
- झझ. जन सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंकड़े में, क्षति सूचना के दो पाठ उपलब्ध कराए गये हैं : (i) एस ई जैड यूनिटों को छोड़ना तथा : (ii) एस ई जैड यूनिटों को शामिल करना। निर्यातकों ने निवेदन किया है कि एस ई जैड यूनिटों प्राथमिक रूप से निर्यातोन्मुख यूनिट है। किसी एस ई जैड यूनिट द्वारा की गई लगभग सम्पूर्ण विक्री को निर्यात बाजार में विक्री किया जाता है और वे घरेलू व्यापारी बाजार में प्रवेश नहीं करते। अतः एस ई जैड यूनिटों के उत्पादन एवं विक्री पर घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा की दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए एस ई जैड यूनिटों को “घरेलू उद्योग” में शामिल करने का कोई कारण नहीं है। विगत में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना से भारत में आयात किए गए इलैक्ट्रीकल इनसुलेटर्स के संबंध

में रक्षोपाय जांच के अंतिम निष्कर्ष दिनांक 27 सितम्बर, 2012 में महानिदेशक रक्षोपाय ने यह सिद्धांत अपनाया है।

- ब्रज. निवेदन के उद्देश्य से उन्होंने क्षति आंकड़े (एस ई जैड यूनिट को छोड़कर) पर विचार किया है।
- टट. रक्षोपाय समझौते के अनुसार “गंभीर क्षति” का मतलब घरेलू उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण समग्र क्षति समझा गया, जो बहुत ऊंची एवं क्षति के सख्त मानकों के अनुसार है। “गंभीर” शब्द एण्टी डम्पिंग समझौते के अंतर्गत विचारित “महत्वपूर्ण” शब्द की तुलना में क्षति के बहुत ऊच्च मानक की ओर संकेत करता है। किसी भी रक्षोपाय कार्रवाई को अवश्यक ही अवसाधारण के रूप में देखा जाना चाहिए।
- ठठ. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा दर्शाता है कि गंभीर क्षति को तो छोड़ दें, कोई क्षति ही नहीं हुई है।
- डड. पी ओ आई एवं वे घरेलू विक्री के ऊपर घरेलू उद्योग का उत्पादन 52% बढ़ा है तथा पी ओ आई के ऊपर घरेलू विक्री मूल्य 32% बढ़ा है।
- ढढ. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई कम्पनीवार लाभप्रदता सूचना प्रमाणित करती है कि दो याचिकाकर्ता अर्थात् वेदान्ता एवं बाल्को भारी लाभ कमा रहे हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें क्षति हुई है। याचिकाकर्ताओं में से दो याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से जांच की अवधि के दौरान लाभ कमाया इसलिए हिन्डाल्को को हुई क्षति का कारण आयात नहीं माना जा सकता। हिन्डालकों ने उनकी वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 के द्वारा कहा है कि वे उन्हें लाभ प्रदता में आरोही प्रवृत्ति का अनुभव हुआ है।
- णण. जन सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जांच की पूरी अवधि में कीमत में कटौती नकारात्मक है। इस प्रकार कीमत मापदण्ड के संबंध में कोई क्षति नहीं है।
- तत. रक्षोपाय समझौते के अनुसार आवश्यक है कि कोई भी कथित क्षति आयात के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।
- थथ. आकस्मिक कड़ी जांच में यह जांचना आवश्यक है कि क्या आयात में आरोही प्रवृत्ति का क्षति कारक में अवरोही के साथ होना संयोग मात्र है और यदि नहीं, तो क्या पर्याप्त, तर्कसंगत एवं उचित स्पष्टीकरण दिया गया है कि फिर भी क्यों आंकड़े के करणीय संबंध दर्शाते हैं; क्या यथा विश्लेषित आयातित एवं घरेलू उत्पाद के मध्य प्रतिस्पर्धा की दशाएँ आयात एवं किसी क्षति के बीच आकस्मिक लिंक को प्रदर्शित करती है; और क्या अन्य सार्थक कारकों का विश्लेषण किया गया है और क्या यह स्थापित हुआ है कि आयात को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई क्षति का जिम्मेदार आयात को तो नहीं ठहराया गया है।
- दद. यदि याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक की लाभ प्रदता का विश्लेषण किया जाता है तो आयात एवं याचिकाकर्ताओं की लाभ प्रदत्ता के बीच कोई सह संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है। आयात परिणाम में वृद्धि ने याचिकाकर्ताओं की लाभ प्रदता को प्रभावित नहीं किया है। उदाहरणार्थ वर्ष 2014-15 में आधार वर्ष से आयात 42 सूचकांक बढ़ा है और इसी समयावधि में, हिन्डाल्कों का लाभ 14 सूचकांक तक गिरा है। वर्ष 2014-15 में वेदान्ता का लाभ सूचकांक 509 था जबकि इसी अवधि के दौरान बाल्को का लाभ 832 सूचकांक तक बढ़ा। पी ओ आई के ऊपर बाल्को की लाभ प्रदता बढ़ते हुए आयात के साथ 2487 सूचकांक तक बढ़ी। भारत में आयात में निरंतर वृद्धि हो रही है जबकि याचिकाकर्ताओं के मुनाफे में उन कारणों से उतार-चढ़ाव हुआ है जिन्हें आयात से नहीं जोड़ा जा सकता। इस प्रकार एक भी याचिकाकर्ता की लाभ प्रदता का सह संबंध आयात से नहीं हो सकता है।
- धध. घरेलू उद्योग की विक्री का आयात से कोई सह संबंध नहीं है। आयात एवं विक्री परिमाण की पी ओ आई के ऊपर लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में 36 सूचकांक की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का विक्री परिमाण भी 38 सूचकांक बढ़ा है।

- नन. वर्ष 2013-14 के दौरान आयात कीमतों में 5 सूचकांक तक वृद्धि हुई है और यह वही अवधि थी जिसमें याचिकाकर्ताओं की लाभ प्रदत्ता में 15 सूचकांक की गिरावट हुई है। स्पष्ट रूप से विषयाधीन आयात कीमतों और याचिकाकर्ताओं की लाभ प्रदत्ता के बीच कोई आकस्मिक लिंक नहीं है।
- पप. वर्तमान मामले में, आर्थिक मानकों में भुवनेश्वर का आयात मात्रा से कोई सह संबंध नहीं है जिसका मतलब है कि या तो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है अथवा आयात के अलावा अन्य कोई कारक हैं जिन्होंने याचिकाकर्ताओं को कथित क्षति, यदि कोई हो, पहुंचाई।
- फफ. स्पष्ट रूप से यह स्थापित है कि आयात मात्रा एवं याचिकाकर्ताओं के निष्पादन के बीच कोई आकस्मिक लिंक नहीं है।
- बब. याचिकाकर्ताओं को हुई कथित क्षति आयात में कथित बढ़ोतरी को छोड़ कर अन्य कारणों से हुई है।
- भभ. याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके दिनांक 24 मई, 2016 के पत्र द्वारा व्याज के संबंध में सूचना प्रदान की गई है और जन सुनवाई के बाद प्रदान किया गया संशोधित आंकड़ा असंगत है और क्षति अवधि के दौरान चुकाये गये व्याज के लिए इसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित भी नहीं करता।
- मम. जब आधार वर्ष से तुलना करें तो वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान व्याज में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। अतः याचिकाकर्ताओं को कथित क्षति उच्च व्याज लागत से ज्यादा हुई है, न कि आयात में कथित वृद्धि से।
- यय. एल्युमिनियम के अतिरिक्त एल्युमिनियम के विनिर्माण में सबसे बड़ी लागत विद्युत् शक्ति की लागत है। भारतीय घरेलू उद्योग ने विद्युत् शक्ति एवं ऊर्जा लागत के संबंध में बहुत अधिक बाधाओं का सामना किया है। हिन्डाल्कों की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि “यू एस डी के विरुद्ध विभिन्न स्थानीय मुद्राओं में ह्लास के साथ लागत अपस्कीति, विशेषकर ऊर्जा लागत के परिणाम स्वरूप एल्युमिनियम लागत कर्व में नीचे की ओर झुकाव हुआ है। इस प्रकार एल एम ई कीमतों पर दबाव पड़ा है। तथापि, अब प्रतीत होता है कि कीमतें नीचे से बाहर हो गई हैं।”
- ककक. एल्युमिनियम की वैश्विक कीमतों का निर्धारण ज्यादातर लन्दन मैटल एक्सचेंज (एल एम ई) द्वारा प्रभावित होता है। एल एम ई के अनुसार गंभीर रूप से ऊपर नीचे होती कीमतों के कारण, घरेलू उद्योग सहित पूरे विश्व में कीमतें विपरीत रूप से प्रभावित हुई हैं। हिन्डाल्कों की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि “औसत एल्युमिनियम एल एम ई पूर्व वर्ष की तुलना में 16% नीचे था जबकि वित्त वर्ष 15 की तुलना में प्रीमियम 68% तक बहुत अधिक नीचे थे।”
- खखख. घरेलू उत्पादकों द्वारा स्वयं ही प्रचुर मात्रा में विशेष रूप से दर्शये गये गैर आरोपणीय कारकों तथा याचिकाकर्ताओं की अपनी संख्या में बताये गये आकस्मिक लिंक में विभाजन से यह प्रमाणित होता है कि आयात में उच्चाल को घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के परस्पर संबंध को दर्शने वाली वर्तमान जांच में कोई आकस्मिक लिंक नहीं है।
- गगग. रक्षोपाय समझौता इच्छुक पार्टियों को यह टिप्पणी करने की अनुमति प्रदान करता है कि रक्षोपाय लगाया जाना जन हित में है अथवा नहीं। रक्षोपाय समझौते का आरोपण जनहित के विपरीत होगा क्योंकि इससे यूजर उद्योग विपरीत रूप से प्रभावित होगा और यही यूजर उद्योग द्वारा किए गए निवेदन से प्रमाणित होता है।
- घघघ. लघु कन्डक्टर विनिर्माताओं के लिए इनगाँट्स से वायर रॉड्स की परिवर्तन लागत 5% से कम है। अतः 5% से अधिक रक्षोपाय शुल्क लगाने से अभी वायर रॉड्स विनिर्माताओं को गंभीर हानि होगी।

- डंड़न. पावर केबल व्यापार में, पावर केबल में 60% एल्युमिनियम होता है जो वर्तमान जांच के प्रोडॉक्ट स्कोप के अंतर्गत आता है और यह बहुत ही कम लाभ प्रदत्ता पर कार्य करता है जिसके कारण निर्माण की लागत में किसी भी वृद्धि से उल्लिखित क्षेत्र विपरीत रूप से प्रभावित होगा।
- चचच. इन कारणों की वजह से, महानिदेशक रक्षोपाय जांच समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि रक्षोपाय शुल्क का लगाया जाना यूजर उद्योग तथा पी यू सी के उपभोक्ताओं के जनहित में नहीं होगा।
- छछछ. विचाराधीन उत्पाद पर मूल सीमा शुल्क छ्यूटी 29 फरवरी, 2016 को 5% से बढ़कर 7.5% हो गई है। अतः घरेलू उद्योग को पहले ही लाभ मिल चुका है, यद्यपि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची है। मूल सीमा शुल्क छ्यूटी में वृद्धि को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (अ) मैसर्स हाइड्रो एल्युमिनियम एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर, रॉकमेन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, एण्ड्यूरेंस टेक्नोलोजीज लिमिटेड
- क. प्रैस में अक्टूबर, 2016 में वेदान्ता बयान दर्शाता है कि एल्युमिनियम क्षेत्र उर्ध्वमुखी है और कम्पनी के लिए सुखद है कि कीमते उचित स्तर पर बढ़ रही है। अतः रक्षोपाय शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मामला समाप्त किया जा सकता है।
- ख. रक्षोपाय उपाय असाधारण उपचार हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है। जब गुणवत्ता के आधार पर बहुत मजबूत मामला हो और एक मरते हुए घरेलू उद्योग को बचाने के लिए छ्यूटी लगाने के अलावा कोई विकल्प न हो। तभी रक्षोपाय उपायों का सहारा लेना चाहिए।
- ग. डब्ल्यू टी ओर द्वारा निर्धारित इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रखे बिना वर्तमान रक्षोपाय जांच शुरू की गई तथा प्रारम्भिक रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई। यह जांच को अरक्षणीय बनाता है क्योंकि विषयाधीन वस्तुओं के घरेलू उद्योग के संबंध में किसी आपातकालीन परिस्थितियों को याचिका कर्त्ता भी सिद्ध नहीं करती जिसके कारण, जिस तेजी एवं तरीके से असाधारण उपाय जिसमें जांच प्रक्रिया एवं रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई, उसे न्याय संगत ठहराया जाए।
- घ. चयनित पी यू सी बहुत बड़ा है और एक पी यू सी के अंतर्गत विजातीय उत्पादों को साथ रखा गया है। “सीमा शुल्क शीर्ष 7601 के अंतर्गत आने वाले अनरॉट एल्युमिनियम” की परिभाषा न केवल अस्पष्ट है बल्कि जो उत्पाद आयात किया गया है जिसके विरुद्ध आवेदकों द्वारा रक्षोपाय शुल्क की मांग की गई है उसकी स्पष्ट पहचान भी नहीं करती। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पी यू सी केस की परिभाषा के संदर्भ में स्पष्टता एवं शुद्धता की कमी है।
- इ. नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 बी (i) महानिदेशक रक्षोपाय की छ्यूटी निश्चित करती है कि वह रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तु की पहचान करें। अधिनियम एवं नियमों की योजना से यह स्पष्ट है कि पी यू सी (आयातित वस्तु) की विशिष्ट रूप से पहचान किये जाने की जरूरत है। वस्तुओं की बहुलता हो सकती है जिन्हें विनिर्मित वस्तुओं की तरह कहा जा सकता है।
- च. वर्तमान जांच में पी यू सी में वास्तव में दो मोटी – मोटी श्रेणियां हैं, यह है एल्युमिनियम अलॉयड एवं नॉट अलॉयड तथा कच्चे माल में महत्वपूर्ण भिन्नता, मूल प्राकृतिक गुण एवं भिन्न उपयोग में महत्वपूर्ण अंतर वाली विभिन्न उप श्रेणियां एवं प्रकार।
- छ. याचिकाकर्ता केवल एल्युमिनियम का उत्पादन कर रहे हैं न कि अलॉय श्रेणी का और वे एल्युमिनियम अलॉय के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माता नहीं हैं। उपशीर्ष 760120 के अंतर्गत आने वाले एल्युमिनियम अलॉय को पी यू सी के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- ज. सीमा शुल्क के अनुसार एल्युमिनियम अलॉय को वर्जिन मैटल से बने प्राइमरी अलॉय और स्क्रेप अथवा स्क्रेप और वर्जिन मैटल के मिश्रण से बने सैकेन्डरी अलॉय की उप श्रेणियों में रखा गया है। 7601 स्तर पर पी यू सी पर विचार करने से अलग – अलग उत्पादों की विस्तृत श्रेणी को इनकी विशेषता, गुण एवं अंतिम उपयोग के साथ ही एक छाते के अंतर्गत शामिल करना होगा जो बहुत ही अनुचित त्रुटिपूर्ण होगा।
- झ. एल्युमिनियम नॉट अलॉयड एवं एल्युमिनियम अलॉय के उत्पादन में काम आने वाली कच्ची सामग्री एवं इसके अंतिम उपयोग में महत्वपूर्ण अंतर है। मूल उत्पाद गुण भिन्न है।
- ञ. याचिका में स्वीकार किया गया है कि अलॉय एवं नान अलॉय की कीमत के बीच महत्वपूर्ण अंतर है और आयात की महत्वपूर्ण मात्रा अलॉय ग्रेड की है और घरेलू उद्योग की अधिकांश विक्री नॉन अलॉय ग्रेड की है।
- ट. नॉन अलॉयड उत्पादों, जिनकी याचिकाकर्ताओं द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती, को आयात संख्या को बढ़ाने के लिए जानबूझ कर पी यू सी में शामिल किया गया है।
- ठ. एल्युमिनियम नॉट अलॉयड एवं एल्युमिनियम अलॉय परस्पर न तो अंतर परिवर्तनीय हैं और न प्रतिस्थापनीय हैं।
- ड. याचिकाकर्ता एल्युमिनियम अलॉय का भी निर्माण नहीं कर रहे हैं। एल्युमिनियम उत्पादों के अंतर्गत ए 356 सिरीज जैसे बहुत ही विशिष्ट उत्पादों को तो छोड़ ही दें। याचिकाकर्ता एल्युमिनियम अलॉय पर झूटी की मांग करके भारत में एल्युमिनियम अलॉय के कुछ अन्य उत्पाद के कन्धे पर बन्दूक रख कर नहीं चला सकते।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एल्युमिनियम नॉट अलॉयड विभिन्न देशों से आयातित एल्युमिनियम अलॉय की वस्तुओं के समान नहीं है।
- ण. आवेदकों द्वारा दिये गये आयात आंकड़े के अनुसार उत्पाद की कीमत ₹0 99 प्रति कि0ग्रा0 से लेकर ₹0 2447 कि0ग्रा0 है। ऐसी विकृत कीमत याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गये दोष पूर्ण पी यू सी निर्धारण तथा त्रुटिपूर्ण उत्पाद बकेटिंग का परिणाम है।
- त. डी आई द्वारा दायर आवेदन पत्र में पूरे उपशीर्ष में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं। महानिदेशक, डी आई को निदेश दे सकते हैं कि वे उनके द्वारा उत्पादित पी यू सी केटेगरी के भीतर आने वाले उत्पादों की सूची को उनके साथ साझा करें।
- थ. ऑटोमेटिक उद्योग को अनुचित परेशानी से बचाने के लिए वे ए 356 सिरीज के एल्युमिनियम अलॉय इनगाँट्स जिसका डी आई द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता, को पी यू सी के दायरे से बाहर करने का अनुरोध करते हैं।
- द. वर्तमान जांच में रक्षोपाय मामलों की मूल विधिक पूर्व अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है।
- ध. सूचना अद्यतन वास्तविक सूचना नहीं है। 2015-16 की अवधि के लिए आयात उपलब्ध करया गया जो जनवरी, 2016 तक की वास्तविक सूचना के साथ वार्षिकीकृत आंकड़े पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं को बहुत ही हाल की अवधि के लिए अद्यतन सूचना उपलब्ध करानी चाहिए और यह भी तिमाही के आधार पर आयात की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए महानिदेशक रक्षोपाय डी जी सी आई एण्ड एस के अनुसार आयात के सौदावार आंकड़े प्रदान कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा प्रयोग में लाये गये समरी आंकड़े में गंभीर कमियां हैं।
- न. जैसा कि याचिकाकर्ताओं का आरोप है पी यू सी के भारत में आयात में कोई अचानक एवं तेज वृद्धि नहीं हुई है।

- प. आयात में वृद्धि धीरे – धीरे वर्षों की वृद्धि है और अचानक एवं तीव्र वृद्धि नहीं हुई है। केवल 2011-12 के आयात एवं 2015-16 के आयात को ध्यान में रखकर शुरू से अंत तक विश्लेषण करना बहुत ही अनुचित है। 2015-16 के दौरान वास्तविक आयात को पहले तिमाही विभाजन के साथ वास्तविक आधार पर देखे जाने की आवश्यकता है। मार्च, 2016 से 6 माह से अधिक भी बीत गये हैं। वर्तमान मामले में, वित्त वर्ष 2015-16 और अंतिम तिमाही अर्थात् जुलाई से सितम्बर, 2016 तक आयात की तिमाही जांच की अत्यंत आवश्यकता है।
- फ. 2015-16 के दौरान कुल मांग में आयात का हिस्सा बहुत ही कम 15% रहा और बाजार का 85% हिस्सा बहुत आराम से घरेलू उद्योग के पास रहा है।
- ब. आयात आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हाल ही के समय में आयात में कोई अचानक एवं तेज वृद्धि नहीं हुई है।
- भ. कोई अनपेक्षित घटना नहीं है जिससे क्षति की स्थिति बनी हो सकती है। "अनपेक्षित घटना" व उत्पाद के वर्धित आयात के मध्य कोई तार्किक संबंध होना आवश्यक है जिसके कारण गंभीर क्षति हुई हो अथवा होने की संभावना हो। एवं अनपेक्षित घटना के दावे का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता के कुछ कमज़ोर और निराधार दावों पर भरोसा किया गया है इस तरह मध्य पूर्व के देशों की क्षमता में वृद्धि हुई है; उत्पादकों ने भी निर्यात शुरू कर दिया है; मध्य पूर्वी क्षेत्र में सस्ती लागत ऊर्जा है; मध्य पूर्व से समुद्र माल में गिरावट आई है; चीन पीआर और चीन बिल्डिंग शेररों से प्राथमिक एल्युमीनियम निर्यात कर और मूल्य वर्धित उत्पादों पर कर छूट है।
- म. याचिकाकर्ताओं ने आयातों की योग्यता के रूप में चीन के विशेष कारण की पहचान की है लेकिन नवीनतम अवधि के दौरान चीन पीआर से पूरा आयात भारत में कुल आयात का कम से कम 3% था। ऐसे इत्यादि देशों में सस्ती लागत या मध्य पूर्व के देशों के बारे में संभावना से अधिक सब्सिडी देने के लिए उनपर आरोप लग रहे हैं। डॉटा स्वयं ही याचिकाकर्ताओं के दावों का खंडन करते हैं। 2016 के दौरान भी उसी नंबरों पर 2015 में पूर्व के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा खपत और उत्पादन में अंतर की स्थिरता की पहचान की गई थी। इस कारण वहाँ 2015-16 के दौरान के आयातों में वृद्धि के बढ़ने का कोई सबाल ही नहीं है।
- य. भारत को पीयूसी के आयात में अचानक और तेजी से वृद्धि करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचान के किसी कारण को योगदान नहीं माना जा सकता है।
- कक. पीयूसी जोकि एलएमई दरों के अनुसार एक प्लस प्रीमियम और विनिमय दर समायोजन उपायोगी वस्तु व्यापार है, एलएमई दरों में उतार-चढ़ाव और एलएम कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है जो रक्षोपाय उपायों के प्राधिभार के लिए नहीं माना जाता है जिससे भारत में उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या पर गंभीर असर पड़ता है।
- खख. घरेलू उद्योग के प्रयास केवल अपने लाभ को रक्षोपाय शुल्कों द्वारा ही बढ़ाने के लिए लगाया गया है।
- गग. कथित अनपेक्षित घटना, आयातों में कथित अनपेक्षित घटना और याचिका में कथित क्षति का कोई तार्किक संबंध नहीं है और जांच को समाप्त किया जा सकता है।
- घघ. अनुबंध के अनुसार रक्षोपायों पर "गंभीर क्षति" घरेलू उद्योग की स्थिति में एक महत्वपूर्ण समग्र हानि का मतलब समझ में आता है और "गंभीर क्षति की संभावना" का मतलब समझ में आता है कि स्पष्ट रूप से आसन्न है। महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले एक उद्देश्य और मात्रात्मक प्रकृति के सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
- डड. पीएफ और याचिका में क्षति के आंकड़ों की अपने ही प्रारंभिक आपत्ति है कि हाल की अवधि के लिए वास्तविक डॉटा भरोसे लायक नहीं है और उक्त एक बहुत बड़ी निर्वलताओं से ग्रसित है क्योंकि पीयूसी की

- गलत अवधारणा है। पीयूसी में आवश्यक परिवर्तन पूरा करने के बाद आयात डेटा को ठीक करके आयातों में कोई तेजी से वृद्धि नहीं देखी जा सकती है।
- चच. ऐसी क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के रूप में मुख्य मापदंडोंनुसार बहुतायत वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और हाल की अवधि के माध्यम से जब घरेलू उद्योग पर गंभीर ध्वनि का आरोप लगाया है। एक मजबूत वॉल्यूम स्थिति सरलता से संभव नहीं है यदि अदृष्ट विकास के कारण आयात में अचानक और तेजी से वृद्धि पर घरेलू उद्योग को प्रतिकूल प्रभावित कर रहा था।
- छछ. यह सिर्फ क्षमता, उत्पादन ही नहीं है बल्कि बिक्री भी बढ़ गई हैं, यहां तक कि क्षमता उपयोग भी बढ़ गया है और पिछले वर्षों की तुलना में उच्चतम स्तरों पर था। वहाँ कोई संभावना नहीं है कि डीआई को गंभीर ध्वनि का सामना करना पड़ा सकता है जबकि वॉल्यूम मानकों की मजबूत स्थिति देखी गई है। ऐसी स्थिति में ध्वनि का कोई भी दावा अत्यधिक विवादित है और डीजी रक्षोपाय द्वारा महत्वपूर्ण जांचों की आवश्यकता है।
- जज. वर्षों में केवल घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में ही वृद्धि नहीं हुई, घरेलू उद्योग भारतीय मांग की विषमता से अधिक उच्च क्षमता है। घरेलू उपयोगकर्ताओं के निर्यात बाजार को लक्षित कर इस तरह के अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना के किसी भी आधात को सहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जब यह स्वीकृत तथ्य है कि एसईजेड और ईओयू क्षेत्र पर अपने घरेलू उद्योगों के संयंत्र हैं जोकि निर्यात लक्ष्यों को स्थापित कर रहे हैं।
- झझ. इस तरह तय की लागत का भार, व्याज का भार आदि रूपमें इस तरह की अधिक क्षमताओं के भार डीआई की ध्वनि होने से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच की जानी चाहिए। डीआई और उनके उचित मूल्य की लागत कम से कम डि और उनकी निष्पक्ष लागत मूल्य की लागत की गणना प्रमाणिक क्षमता उपयोगों का कम से कम 80% पर विचार किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं।
- जज. वित्त / व्याज, मूल्यहास आदि की तरह निर्धारित लागत के कारण उत्पादन की लागत पर इस तरह की अधिक क्षमताओं का कोई भी दबाव लाभप्रदता में किसी भी गिरावट का कारण हो सकता है और इस तरह की गिरावट विशेषतः आयातों को आरोपित नहीं किया जा सकता है जब उत्पादकों के पास एसईजेड/ईओयू इकाइयां हैं।
- टट. इनवेंटरी स्तर में सुधार हुआ है जोकि गंभीर ध्वनि के दावों के बीच का एक सकारात्मक संकेत है। डीआई के साथ समापन शेयरों में काफी गिरावट आई है और एक नगण्य बिंदु पर टिके हुए हैं। इस प्रकार, ध्वनि के पूरे दावे झौठे हैं।
- ठठ. आयातों को लाभप्रदता की स्थिति के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता और कोई गंभीर ध्वनि स्पष्ट नहीं है। डीआई की व्याज लागत में तेजी से वृद्धि हुई है और उक्त एक ही वर्ष 2015-16 में 390 अंकों के आधार वर्ष में 100 अंक से वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान कीमतों में अंडरकटिंग की स्थिति को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह कारणों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है जोकि 2011-12 से 2013-14 के दौरान में डीआई की लाभप्रदता को प्रभावित कर दिया है इस रूपमें पीबीटी के आंकड़ों से देखा जा सकता है और अवधि 2015-16 में इस तरह के अन्य कारकों की स्थिति क्या थी।
- डड. इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पीबीटी के बाद माल उतारने तक की कीमत को 2015-16 में गिरते हुए घाटे को आरोपित नहीं किया जा सकता था जब शुरुआती 2011-12 के पिछले 3 वर्षों में नकारात्मक अंडरकटिंग थी जोकि वहाँ अन्य महत्वपूर्ण कारण दर्शाता हैं जो डीआई के निष्पादन को प्रभावित करता है।
- ढढ. रिकॉर्ड पर कुछ नहीं दिखाई देता है, 2015-16 के दौरान इस तरह के अन्य फैक्टर्स प्रचलित नहीं थे। इस प्रकार, 2015-16 में घाटा सकारात्मक कीमत अंडरकटिंग को ओरोपित नहीं किया जा सकता है।
- णण. पीबीटी की स्थिति को एक विकृत चित्र रूपमें दिखाया है क्योंकि व्याज लागत में तेजी से वृद्धि की और किसी भी अन्य कारणों से नहीं। 2015-16 में 2014-15 से 31 अंक में से 132 अंक से पीबीआईटी में

- गिरावट नहीं कहा जा सकता इस रूपमें तेज गिरावट वस्तु की प्रकृति पर विचार किया जा रहा है और इस तरह के उत्तर-चढ़ाव पिछले वर्ष में भी प्रतीत हुए थे। उदाहरण के लिए, पीबीआईटी 2012-13 में 91 अंक पर गिर गया और उसके बाद 2013-14 में 44 अंक पर गिर गया और 2014-15 में 132 अंक की वृद्धि हुई। तो, क्या 2015-16 में वहाँ केवल अस्थिरता की पुनरावृत्ति है जो इस उत्पाद के वाणिज्य के लिए निहित है जोकि प्राथमिक तौर पर एलएमई कीमतों द्वारा चालित है।
- तत. घरेलू उद्योग के साथ रोजगार के स्तर के आधार वर्ष में वृद्धि हुई है और वहाँ वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हुई है। इस प्रकार, वहाँ रोजगार पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा है या मजदूरी भुगान करने की क्षमता है और इस गंभीर क्षति का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है।
- थथ. उत्पाद की कीमत में विश्व स्तर पर एलएमई प्लस एम जे पी / प्रीमियम के आधार पर निर्धारित होता है और आदान-प्रदान दर का भी प्रभाव है जोकि एक पारदर्शी तंत्र है। इस प्रकार, कीमत आयात का कोई दावा प्रमाणरहित है और इस उत्पाद में अस्वीकार्य है।
- दद. घरेलू मांग का 85% भारतीय उत्पादक धारण किया है और आयात मुश्किल से 15% है जोकि गंभीर क्षति पहुंचाने के काविल नहीं है।
- धध. भारतीय उत्पादों की ऊंची व्याज लागत आदि द्वारा तथाकथित क्षति बढ़ायी जा रही होगी और आयातों को उक्त के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।
- नन. वेदांता के मुद्दे उनकी वार्षिक रिपोर्ट से उनकी बॉक्साइट और कोयला खरीद स्पष्ट रूपमें असत्य है और उक्त पर आयातों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- पप. वेदांता की अक्षमता के लिए ग्राहकों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए, इस तरह अन्य निर्माता ऊपरी तौर-से लाभ में परिचालन कर रहे हैं।
- फफ. डीआई द्वारा स्थापित अतिरिक्त क्षमता की क्षति सहन करने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।
- बब. जबकि उत्पादन की उनकी लागत का निर्धारण केआई के मध्यस्थ के स्थानान्तरण के हस्तांतरण लागत सख्त जांच के अधीन किया जाना चाहिए।
- भभ. भारत के आयात में अचानक और तेजी से वृद्धि के कारण गंभीर क्षति का कोई मजबूत मामला घरेलू उद्योग को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता है।
- मम. घरेलू उद्योग के लिए बढ़े आयात और क्षति के मध्य अनौपचारिक लिंक रक्षोपाय शुल्क लगाने के आदेश में जरूरत स्थापित किया जाना चाहिए। डीआई ने कोई सामग्री का अधिकार नहीं दिया है जिसपर यह प्रदर्शन किया जा सकता है कि उनके द्वारा क्षति का दावा आयात वृद्धि के कारण आरोपित किया है। याचिका में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वहाँ आयातों और क्षति दावों के मध्य लिंक नहीं है। घरेलू उद्योग को क्षति के कारण लागत व्याज का भार है और वहाँ आयात कीमतों का कोई प्रभाव नहीं है। लाभ घट रहा है जबकि प्रारंभिक तीन वर्षों में नकारात्मक अंडरकटिंग थी जोकि लाभ में दिखाई गई कोई गिरावट कुछ अन्य कारणों से किया गया है। इस तरह के कञ्च माल की खरीद के मामलों के कारण और क्षति का दावा आयात से नहीं जुड़ा है, उच्च व्याज लागत आदि दृश्यमान हैं। किसी भी तथाकथित क्षति के कारण पूरी तरह अन्य कारणों से है और आयातों में किसी भी अचानक वृद्धि से प्रेरित नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आयातों में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं दिखाई जा सकती है। वेदांता महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है और पर्यावरण मामलों के रूपमें मुकदमें उनकी खानों से संबंधित हैं और उक्त का कोई प्रभाव आयातों को आरोपित नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- यय. उद्योग एक अस्थिर अवधि के माध्यम से किया गया है और उक्त खत्म हो गया है और उद्योग को उदार कीमतों से फायदा हो रहा है। रक्षोपाय योजना के तहत उपचारी दावा को एक परिवर्तनशील आधार नहीं बनाया जा सकता है।
- ककक. पीयूसी पर आयात शुल्क पहले से ही 2.5% द्वारा वृद्धि हुई है और एक अतिरिक्त संरक्षण के रूप में अब 7.5% है और इस तथ्य को डीजी द्वारा विचार के लिए लाया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी भी

रक्षोपाय शुल्क पारदर्शक कमजोरियों में अंतिम उपयोगकर्ता को छोड़ना होगा और अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उल्टे शुल्क की स्थिति का संचालन करेंगे।

- खखख. समायोजन की योजना का एनसीवी संस्करण में कम से कम प्रतिशत के संदर्भ में कोई सार्थक टिप्पणी / समझने की अनुमति नहीं देते तो क्या योजना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित योजना का प्रभाव होगा। उक्त मात्रा पर किसी सारांश के अभाव में, वे कोई भी सार्थक टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हैं।
- गगग. सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का मूल्यांकन और पहचान) नियमावली, 1997 के नियम 7 के साथ पठित रक्षोपाय पर समझौते के अनुच्छेद 3.2 की मानक आवश्यकता की गैर गोपनीय संस्करण में कम गिरावट आई है। आवेदन में सूचना अस्पष्ट प्रस्तुत है और डीआई के मामले की उचित और सार्थक समझ की अनुमति नहीं है। बिना कोई कारण बताए डेटा की एक संख्या के संबंध में गोपनीय दावा किया गया है। इसलिए, अवहेलना की पूरी गोपनीय सूचना महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा देने की जरूरत है।
- घघघ. जबकि किसी भी उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के मामले में निर्णय लेते समय, डॉउन लाईन उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव सहित जनहित विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए। संबंधित वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित के खिलाफ है, विशेषतः पीयूसी को देखने के रूप में परिभाषित किया गया है।
- डड़ड. रक्षोपाय शुल्क लगाने से विभिन्न उपयोगकर्ता क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव हो जाएगा। घरेलू उद्योग के रक्षोपाय शुल्कों के माध्यम से केवल उनके लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उत्पादों की विविधता का पूरा लॉट पीयूसी रूपमें परिभाषित को शामिल किया है जोकि डीआई के निष्पादन के साथ नहीं किया गया है। यह व्यापक जनहित में पीयूसी पर शुल्क नहीं लगाया जायेगा। मे. वेदांता ने स्वीकार किया है कि एल्यूमीनियम की स्थिति प्रबलतापूर्वक अंतिम वर्ष के दौरान परिवर्तनशीलता के बाद सुधार आया है। इस मौके पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- चचच. संपूर्ण रूप से, यह प्रतीत होता है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु कोई मामला न होने के बावजूद एक मामला शुरू किया गया है।
- छछछ. उनके द्वारा प्रस्तुत निवेदन को देखते हुए, वे निवेदन करते हैं कि वर्तमान जांच को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
- जजज. भारत के बाहर कम कीमतों पर आयात या सामग्री की उपलब्धता में प्रत्येक वृद्धि बुरी नहीं है और हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। माल की उपलब्धता भारत से बाहर कम कीमत पर है उनकी तुलना में जोकि स्वदेशी उत्पादित हैं जो भारतीय उद्योग के बीच प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करेगा और प्रतिद्रिंद्री को हटाने में स्वयं परिणाम नहीं आयेगा।
- झझझ. डीआई निवेदन है कि एसईजेड/ईओयू इकाईयां विभिन्न एंटी-डंपिंग में घरेलू उद्योग के भाग के रूप में व्यवहार किया गया है और भारत में रक्षोपाय की जांच वास्तव में सही है। हाल के एंटी डंपिंग "गैर बुने हुए कपड़े" फा.स.14/23/2015-डीजीएडी, दिनांक 15 जून, 2016 के संबंध में, याचिकाकर्ता स्थायी के निर्धारण के लिए एसईजेड क्षेत्र में उत्पादक के लिए विचार नहीं किया और एसईजेड में निर्माता कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए बाहर रखा गया था।
- जजज. रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवेदन और वर्तमान कार्यवाही उक्त आधार पर शुरू किया गया है जोकि अनुरक्षणीय नहीं है और उसे समाप्त किया जायेगा।

### इ. मे. विरगो एल्यूमिनियम लिमिटेड

- क. वहाँ पिछले पांच साल में घरेलू बाजार में मांग के मुकाबले आयात में केवल 4.07% वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू बाजार में अनरॉट एल्यूमीनियम की कुल मांग 2011-12 की मांग के आधार से अधिक पिछले पांच वर्षों में 29% की वृद्धि हुई जबकि प्राथमिक उत्पाद की उत्पादन क्षमता में 40% की वृद्धि हुई है।
- ग. याचिकाकर्ता की विक्री पिछले पांच वर्षों में 40% की वृद्धि हुई है।
- घ. माध्यमिक उत्पादकों की विक्री पिछले पांच साल में 2.65% की वृद्धि हुई है।

- ड. सभी घरेलू उद्योग कुल मांग का लगभग 85% शेयर बाजार का लाभ उठा रहे हैं।
- च. मे. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), एक नवरक्त पीएसयू है जिसने ऐसी याचिका की कभी सिफारिश नहीं की है।
- छ. पिछले बजट में सीमा की शुल्क 2.5% से अधिक वृद्धि हुई थी इससे पहले 5% सीमा शुल्क था, सभी घरेलू प्राथमिक उत्पादकों की रूपये 3500/- द्वारा प्रति मीट्रिक टन कीमतों में वृद्धि हुई।
- ज. घरेलू प्राथमिक उत्पादक बाजार में एकाधिकार के साथ अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं।
- झ. वहाँ याचिकाकर्ताओं के लिए कोई क्षति नहीं हुई है।
- ई. **मे. ईईपीसी इंडिया**
- क. वे निर्माणकर्ताओं की एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जोकि एल्यूमीनियम के उत्पादन में लगे हुए हैं।
- ख. यह तर्क की पीयूसी का 2011-12 से 2015-16 तक काफी बढ़ाया है एवं वर्धित निर्यात से घरेलू उद्योग को हानी पहुंच रही है, भ्रामक / गलत है। कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात अधिक नहीं बढ़ा है। यह 2011-12 में 13% था जोकि 2013-14 में 17% तक बढ़ा और 2015-16 में 15% तक कम हुआ है।
- ग. निर्यात प्रोत्साहन के तहत किए गए आयात "शुल्क मुक्त" योजना को अलग-अलग नहीं किया गया है। बहुत छोटे और नगण्य मात्रा के शुल्क का भुगतान रूट के तहत आयात किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यातकों को उनकी आवश्यकतानुसार आयात करना पड़ता है, घरेलू उद्योग के रूप में अंतरराष्ट्रीय कीमत पर निर्यातकों को पीयूसी आपूर्ति करने को तैयार नहीं है।
- घ. महत्वपूर्ण मात्रा में चीन से शुल्क भुगतान पर पीयूसी आयात नहीं किया जा रहा है और यह सच नहीं है कि सस्ते चीनी आयात से घरेलू बाजार में बढ़ोतरी हो गई है और वे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाने रहे हैं।
- ड. यह सत्य नहीं है कि डीआई को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सभी घरेलू एल्यूमीनियम उत्पादन नालको सहित कंपनियों को ज्यादा लाभ हो रहा है। रक्षोपाय शुल्क संरक्षण के लिए नालको मांग में शामिल नहीं हुई है।
- च. निजी क्षेत्र के उत्पादकों के दावे को अनुचित लाभ पाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- छ. घरेलू उद्योग ने आयातों के लिए किसी भी बाजार में हिस्सेदारी को नहीं खोया है।
- ज. यदि डीआई शुल्क मुक्त योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ाते हैं, तैयार उत्पादों के निर्यातक घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से उक्त खरीद करने के लिए तैयार हो जाएगा।
- झ. डीआई अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्लस प्रीमियम प्लस गुणित शुल्क आयात यूएसडी द्वारा रूपया विनिमय दर उनके उत्पादों के मूल्य आधार रूपमें प्रयोग कर रहे हैं। उनको रूपये में गिरावट के कारण बहुत लाभ मिल रहा है जोकि कृत्रिम रूप से उनके उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है।
- ड. याचिका के प्रयोजन के लिए अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाना है अब से वे आयातित धातु के उच्च लेडे लागत के आधार पर उनकी कीमत तुरंत जैकअप होगी।
- च. कई छोटे विनिर्माण और निर्यातकों को जो कम मात्रा में पीयूसी उपयोग कर रहे हैं, अधिकांशतः कठोरता से प्रभावित होंगे क्योंकि वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं या "ज्यूटी मुक्त" योजना के तहत पीयूसी आयात करने की वित्तीय क्षमता नहीं है।
- छ. तैयार / अर्द्ध तैयार माल के आयात शुल्क में विना वृद्धि के अनुरूप पीयूसी (कच्ची सामग्री) के शुल्क में कोई वृद्धि का परिणाम उल्टे शुल्क की संरचना होगी जोकि घरेलू एल्यूमीनियम खपत करने वाले उद्योगों को बड़ी संख्या में बहुत नुकसान होगा।
- ज. भारत में पीयूसी के आयात पर रक्षोपाय की उगाही का कोई मामला नहीं है।
- उ. मे. सेंचुरी मेटल रिसाइकिंग प्राइवेट लिमिटेड; (सीएमआर), सीएमआर निक्स इंडिया लिमिटेड (सीएमआरएन); सीएमआर-टोयोट्सु एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआरटी)।

- क. एलॉय और जिंक एलॉय - अनरॉट एल्यूमीनियम की बिक्री और उत्पादन में सीएमआर शामिल हैं। केवल एलॉय - अनरॉट एल्यूमीनियम के उत्पादन में सीएमआरएन एवं सीएमआरटी शामिल हैं।
- ख. एल्यूमीनियम एलॉय सिल्लियां प्रमुखतः एल्यूमीनियम डॉई कॉस्ट कंपोनेंट्स के लिए कच्ची सामग्री के रूपमें करते हैं और आँटो पार्ट्स की कॉस्टिंग में एल्यूमीनियम मॉल्डिंगस की आवश्यकता होती है और सफेद माल और टिकाऊ उपभोक्ता की कास्टिंग में एक छोटी बढ़ोतरी हुई है। अनरॉट एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए, स्क्रैप खरीद करके आवश्यकतानुसार वर्गीकृत करते हैं।
- ग. पीयूसी के आयातों पर कुछ एशिया के देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, जापान आदि से वहां एफटीए के तहत कोई शुल्क नहीं है। एफटीए देशों से आयात में वृद्धि की वजह एफटीए को रियायत देने से है और मूल्य संवर्धन शर्तों के पालन के बिना आयात किया जा रहा है।
- घ. ऐसी मात्रा में आयात की बहुत वृद्धि हुई है और कुछ ऐसी स्थिति में उक्त घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है।
- ङ. इसके बावजूद आयातों में वृद्धि महत्वपूर्ण है कि वे बराबर या कीमत पर भी गैर लाभकारी कीमतें दे रहे हैं जोकि लागत वसूली की भी अनुमति नहीं है।
- च. चूंकि चीन सीधेतौर पर भारत को पीयूसी निर्या नहीं कर सकता, इस रूपमें @ 7.5% सीमाशुल्क आकर्षित करती है, इसलिए चीन मूल के उद्यमियों ने पीयूसी के निर्यात के लिए मलेशिया और वियतनाम में संयंत्र लगाए हैं इस तरह के आयात भारत में शुल्क मुक्त होते हैं। मलेशिया और वियतनाम से पीयूसी के आयात में काफी वृद्धि हुई है।
- छ. आयातों में वृद्धि के परिणाम आने से वे भी बहुत पीड़ित हैं।
- ज. हालांकि क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, क्षमता की उपयोगति में कमी आई है। एकाकीपन में मात्रा के मापदंडों पर देखे जा रहे उद्योग के प्रदर्शन के मामलों की सही स्थिति नहीं देनी होगी। अपने मुनाफे में वृद्धि हुई और शेयर बाजार में ऐसा नहीं हुआ और भारतीय बाजार में आयातित सामग्री की आसान उपलब्धता के कारण हुआ है, कंपनी को आयातित कीमतों के स्तर पर कीमतों को बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया था जबकि पूरी लागत की वसूली की भी अनुमति नहीं दी है, विशाल निवेश पर मार्जिन को छोड़ दें।
- झ. उनकी लाभप्रदता प्रचंडतौर पर घटती जाती है। आधार वर्ष में प्रति मीट्रिक टन 100 (अनुक्रमित) के लाभ से, वे अब घरेलू परिचालनों के लिए वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष में 23 की हानि बना दी गई है। लाभ में गिरावट के कारण, मूल नियोजित पर उनकी नगदी प्रवाह और रिटर्न भी बहुत खराब हो जाता है।
- ञ. वहाँ आयातों में और लाभ में गिरावट का वृद्धि में सीधा संबंध है।
- ट. रोजगार उत्पादन के रूप में (हालांकि पूर्ववर्ती वर्ष 2015-16 में इस तरह गिरावट आई है) इसी तरह का रुक्षान दर्शाता है। 2015-16 में प्रति किलो मजदूरी की गिरावट आई है और उक्त हानि के बावजूद वृद्धि हुई है। कंपनी द्वारा उत्पादन क्षमता की उपलब्धि के साथ लाइन में उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी में गिरावट आई है।
- ठ. प्रति दिन की उत्पादन क्षमता और प्रति कर्मचारी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी हुई दिखाई गई है, इस प्रकार, उत्पादन क्षमता में भी संभावित गिरावट की क्षति का कोई कारण नहीं है। उत्पादन क्षमता में सुधार के बावजूद, लाभप्रदता में कमी हुई है।
- ड. आयात ने मूलभूत संचालन मापदण्डों को बुरी तरह से प्रभावित किया जैसे लाभ जिसका इलाज कथित आयातों के बीच समुचित रक्षोपाय शुल्क लगा कर ही किया जा सकता है।
- ढ. कथित देशों से बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप लगाई गई पूंजी पर आने वाले रिटर्न पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

- ण. माल सूचियों में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।
- त. भारत में अनरॉट एल्यूमीनियम (7601) के बड़े हुए आयातों से उन्हें गंभीर क्षति उठानी पड़ी है।
- थ. समुचित रक्षोपाय शुल्क संस्तुत किया जाए तथा तत्काल लगाया भी जाए।
- ऊ. **मेसर्स मास्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
- क. नोटिस में दी गई उत्पादकता (एम टी) प्रति कर्मचारी के आधार पर मापी गई। परंतु श्रमिक, लागत ढांचों का मुख्य हिस्सा नहीं होते। वैश्विक स्तर पर मापे जाने का स्टेंडर्ड तरीका एक टन एल्यूमीनियम के उत्पादन में खपत हुई विजली को मापा जाना है (एम डब्ल्यू एच प्रति टन), क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि विजली उत्पाद लागत का लगभग 40% होती है। उत्पादकता का पुनः निर्धारण किए जाने की पुनः आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप आयातों तथा प्राइमरी उत्पादकों को हानियों के मध्य पारस्परिक संबंध पुनः स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
- ख. आर्थिक पैरामीटर का प्रयोग न केवल सीमित है, परंतु इनका आवेदन भी अकेले में तैयार किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि बड़े हुए आयातों तथा हानियों के मध्य किस प्रकार यूं ही एक लिंक स्थापित कर दिया गया। उन्होंने महानिदेशक, रक्षोपाय से आवेदकों को हानि तथा आयातों के मध्य लिंक स्थापित करने वाले आर्थिक पैरामीटर्स के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध किया है।
- ग. हिंडाल्को के बयान के अनुसार 2015-16 में प्राप्त किया गया ईबीआईडीटीए अभी तक का सबसे अधिक था; लाभ-कम थे क्योंकि “नई सुविधाएं शुरू किए जाने के कारण व्याज तथा मूल्यह्रास प्रभार बहुत अधिक बढ़ गए।”
- घ. हाल ही के वर्षों में लाभप्रदता में कमी बिना गणना किए कर्ज के बोझ तथा परिचालन अक्षमताओं के कारण हुई है।
- इ. अब जबकि एलएमई मूल्य स्थिर हो गए हैं, प्राइमरी उत्पादकों के व्यापार हालात अच्छे होते जा रहे हैं।
- च. नालको भी आवेदकों में से एक नहीं है।
- छ. रक्षोपाय शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर गंभीर प्रभाव होगा। जैसे ही रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, शुल्क प्रतिशत वृद्धि डीआई के मूल्यों में दिखाई पड़ने लगेगी।
- ज. एफ टी ए देश जो भारत में पी यू सी के मुख्य आयातक हैं अभी भी शुल्क से मुक्त रहेंगे।
- झ. छोटी अवधि में छूटी के कारण आपूर्ति में कमी आएगी।
- ञ. छूटी में बढ़ोतरी से देश की निर्यात वृद्धि में बाधा आएगी क्योंकि, प्राइमरी मेटल की लागत में बढ़ोतरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घरेलू उत्पादकों के मूल्य स्पर्धात्मक नहीं रह पाएंगे।
- ट. डी आई निर्यातकों को शुल्क मुक्त माल उपलब्ध नहीं कर रही है तथा उन्हें अग्रिम लाइसेंस द्वारा माल को आयात करना पड़ रहा है।
- ठ. रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की अवस्था में आवेदकों को मूल्य बनाए रखने का वचन देना चाहिए।

**ऋ मेसर्स वेदांता लिमिटेड –एल्यूमीनियम एवं पावर; भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड; हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (घरेलू उद्योग)**

- क. इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ताओं का संयंत्र एस ई ज़ेड में है याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता पर प्रश्न सामने आया। विधि के अधीन घरेलू उद्योग की परिभाषा में एस ई ज़ेड यूनिट एक घरेलू उद्योग होता है। रक्षोपाय विधि में “भारत में \_\_\_\_\_ उत्पादक” पदबंध का प्रयोग किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग माने जाने के लिए तथा इसकी परिधि में उत्पादक उचित मापदंड हैं न की इस उत्पादन का उपयोग किया जाना। ऐसी स्थिति में जहाँ एक डी टी ए घरेलू उत्पादक अपने उत्पादन का 90% निर्यात कर देता है, निदेशालय घरेलू उद्योग मानने के उद्देश्य से इसके सारे उत्पादन पर अब भी विचार कर सकता है।
- ग. एस ई ज़ेड अधिनियम के अधीन आयात तथा निर्यात शब्द की परिभाषाओं के अनुसार आयात का अर्थ है किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में किसी यूनिट अथवा डेवेलपर द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भूमि, समुद्र या वायु अथवा किसी अन्य तरीके से वस्तुएँ मंगवाना अथवा सेवाएँ प्राप्त करना तथा निर्यात का अर्थ है किसी विशेष आर्थिक ज़ोन से भारत के बाहर भूमि, समुद्र या वायु अथवा किसी अन्य तरीके से वस्तुएँ ले जाना अथवा सेवाएँ प्रदान किया जाना। अतः, एस ई ज़ेड की किसी यूनिट द्वारा डी टी ए में विक्री किया जाना निर्यात नहीं है, वस्तुतः यह घरेलू विक्री है।
- घ. खातों की बही में तथा सभी उद्देश्यों के लिए जैसे राजस्व मान्यता, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य आदि के लिए एस ई ज़ेड में किसी यूनिट द्वारा की गई विक्री को घरेलू विक्री माना जाता है। किसी एस ई ज़ेड यूनिट द्वारा किसी भारतीय इकाई को की गई विक्री को निर्यात के एफ ओ बी मूल्य (चाहे यह किसी एस ई ज़ेड यूनिट को की गई हो) निर्धारण में शामिल नहीं किया जा सकता है। केवल बाह्य निर्यात की ही इस उद्देश्य से निर्यात माना जा सकता है। डी टी ए, ई ओ यू, एस ई ज़ेड की विक्री को घरेलू विक्री माना जाएगा तथा कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में “निर्यात के एफ ओ बी मूल्य” को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से भारत में बाह्य निर्यात को ही निर्यात विक्री माना जाएगा।
- इ. देश के विभिन्न विनियमों के लिए एस ई ज़ेड में केवल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधानों को छोड़कर किसी यूनिट को भारतीय निर्माता माना जाएगा। यद्यपि, वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधान कानून समग्र रूप से असंगत हैं। केवल इस लिए कि सरकार ने सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना इनपुट्स के आयात की अनुमति दे दी है इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्पादन को घरेलू उत्पादन नहीं माना जाएगा।
- ज्ञ. भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर लाभ वर्तमान उद्देश्यों के लिए पूरी तरह असंगत हैं। यद्यपि आय कर में केवल छूट होने के कारण से नामित प्राधिकारी किसी कंपनी की घरेलू उद्योग की स्थिति को नहीं नकारेंगे।
- छ. एस ई ज़ेड की यूनिट पर सभी दिवानी, फौजदारी अथवा व्यापार कानून लागू होंगे।
- ज. एस ई ज़ेड की किसी यूनिट द्वारा किसी भारतीय कंपनी को की गई विक्री को सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा घरेलू विक्री माना जाता है तथा इसे आयात अथवा निर्यात के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एस ई ज़ेड यूनिट द्वारा किए गए केवल बाह्य निर्यातों को निर्यात के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। किसी एस ई ज़ेड यूनिट द्वारा किए गए आयात, आयात के रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- झ. पॉलीप्रोपाईलिन, सोलर सेल, इलैक्ट्रिक इनसूलेटर, एलॉय व्हील, डी वी डी आर व डी वी डी आर डब्ल्यू, सी डी आर तथा विटामिन-ए पालमिटेट के मामलों में नामित प्राधिकारी द्वारा पहले एंटी डोपिंग को ई ओ यू अथवा एस ई ज़ेड में यूनिट को घरेलू उद्योग माना जाता था।

- ब. रक्षोपाय महानिदेशालय में सैचुरेटेड कैटी एल्कोहल के मामले में घरेलू उद्योग 100% ई ओ यू है।
- ट. नामित प्राधिकारी के सामने सोलर सेल के मामले में इनकी पात्रता को लेकर बहुत सी बहस तथा चर्चाओं के बाद एस ई ज़ेड में किसी यूनिट को घरेलू उद्योग माना गया।
- ठ. उन स्थितियों में जहां कोई घरेलू उत्पादक डाऊनस्ट्रीम उत्पाद का सीमित उपभोग करता है। नामित प्राधिकारी तथा महानिदेशक रक्षोपाय सीमित उपभोग को शामिल करते हुये तथा शामिल न करते हुए दोनों तरीकों से यह घरेलू उद्योग है या नहीं का निर्धारण करते हैं।
- ड. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन अध्याय 98 के अधीन प्रोजेक्ट श्रेणी के अधीन किए गए आयात सामान्यतया शून्य सीमा शुल्क पर तथा ज्यादातर रियायती सीमा शुल्क दरों पर किए जाते हैं। यद्यपि, केवल इसलिए कि अध्याय 98 के अधीन विना अथवा रियायती सीमा शुल्क के साथ आयातों की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिणामी उत्पाद को घरेलू उत्पादन न माना जाए।
- ढ. अन्य देशों द्वारा भारतीय एस ई ज़ेड की किसी यूनिट के साथ व्यवहार: एस ई ज़ेड से उत्पादन तथा निर्यात पर व्यापार रक्षा उपाय लागू होते हैं। ऐसी यूनिट को लाभ दिए गए होते हैं इसलिए सब्सिडी झूटी लगाई जाती है। अतः इन आयातों को “भारत में उत्पादित” वस्तुएँ माना जाता है।
- ण. एस ई ज़ेड यूनिट को दिए गए विभिन्न लाभ का ऐसी यूनिट को घरेलू उद्योग माने जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी स्थिति में तथा वस्तुत तैयार उत्पाद पर लगाया गया सीमा शुल्क एस ई ज़ेड यूनिट द्वारा प्राप्त कर्त्त्व माल तथा इनपुट्स पर सीमा शुल्क तथा अन्य लाभों से कुछ ही ज्यादा होता है। अतः यह वह मामला नहीं है कि एस ई ज़ेड यूनिट को दोहरा लाभ हो रहा है।
- त. पहले भी कई बार याचिकाएँ दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में विचाराधीन उत्पाद का दायरा लगातार बदलता रहता है। जहां पहली याचिका 7601 व 7602 के अधीन आने वाले उत्पादों पर थी; इसके पश्चात याचिककर्ताओं ने 7601 से 7608 तक 7603 के अलावा, आने वाले सभी उत्पाद तक इसके दायरे का विस्तार कर दिया। यद्यपि, अंततः याचिककर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद का दायरा केवल 7601 तक सीमित कर दिया, क्योंकि महानिदेशक का विचार था कि 7601 से 7608 तक के सभी उत्पादों के लिए एक आवेदन दायर किए जाने कि अनुमति नहीं दी जा सकती।
- थ. न तो रक्षोपाय तरीकों पर घरेलू कानून न ही रक्षोपाय पर करार जांच की अवधि के बारे में कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान करते हैं। यद्यपि, कोरिया के विरुद्ध यू एस - लाइन पाइप मामले में पेनल के निष्कर्षों में जांच की अवधि के मामले को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया, जहां यह फैसला दिया गया कि यह आयात सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेक पर है कि वह “जांच की अवधि की सीमा” तथा इसके “ब्रेक डाउन” पर फैसला ले। संगत जांच अवधि समुचित रूप से लंबी होनी चाहिए ताकि बढ़े हुए आयात तथा गंभीर क्षति पर निष्कर्ष निकाला जा सके तथा यह एकदम हाल के दिनों में समाप्त नहीं होनी चाहिए अपितु जांच अवधि हाल ही की होनी चाहिए। वर्तमान निवेदन भी 2011-12 से आगे 2015-16 तक की सूचना के ऊपर आधारित है।
- द. याचिका अप्रैल-दिसम्बर 2015 की अवधि पर आधारित है। प्रारम्भिक याचिका दायर करने के बाद, महानिदेशक रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग की सूचना का टेबल पर सत्यापन किया। तदनुसार, याचिका में कुछ छोटे सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा उन्हें किया गया। इसके पश्चात तथा प्रारम्भ के उपरांत महानिदेशक ने सभी कंपनियों के परिसरों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया तथा एक सत्यापन रिपोर्ट जारी की। अतः अब जबकि महानिदेशक रक्षोपाय ने प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया है तथा सत्यापन रिपोर्ट जारी कर दी है, याचिककर्ताओं ने वर्तमान निवेदन महानिदेशक रक्षोपाय की सत्यापित सूचना के आधार पर प्रस्तुत किया

है। तदनुसार, क्षति विवरण में सूचना की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान निवेदन निदेशालय द्वारा किए गए सत्यापन के साथ तर्कयुक्त बन सके।

- ध. याचिककर्ताओं द्वारा दायर डाटा/सूचना तथा निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट में एक प्रमुख अंतर क्षमता उपयोग के विषय में है। महानिदेशक रक्षोपाय याचिककर्ताओं की हॉट मेटल क्षमता के साथ आगे बढ़े हैं। आगे, क्योंकि यह हॉट मेटल क्षमता याचिककर्ताओं द्वारा विचारधीन उत्पाद तथा अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की गई है इसलिए, महानिदेशक रक्षोपाय ने अन्य उत्पादों के डाटा/सूचना को भी ध्यान में लेते हुए क्षमता उपयोग कर विचार किया है। अन्य शब्दों में विचारधीन उत्पाद में क्षमता उपयोग की वजाय महानिदेशक ने कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों को ध्यान में रखते हुए इसकी क्षमता उपयोग पर विचार किया है। तदनुसार, याचिककर्ताओं ने पूरी क्षति सूचना को संशोधित कर दिया।
- न. याचिककर्ताओं को 2015-2016 का अध्यतन डाटा फाइल करने का निदेश देते हुए महानिदेशक ने याचिकाकर्ताओं को एस ई जेड संयंत्र से संबंधित डाटा निकाल दिए जाने का निदेश दिया। चूंकि यह एक निदेश था, याचिककर्ताओं ने एस ई जेड संयंत्र का डाटा हटाने का यह निदेश ठीक है अथवा कुछ और है पर ध्यान दिए बिना इसका पूरी तरह अनुपालन किया। यद्यपि, याचिककर्ताओं ने - एक बार एस ई जेड प्लांट के डाटा के बिना तथा एक बार एस ई जेड के प्लांट का डाटा शामिल करने के बाद दो बार सूचना प्रदान की। तदनुसार, याचिकाकर्ता एस ई जेड संयंत्र डाटा शामिल करते हुये व शामिल न करते हुये दोनों तरीकों से इन निवेदनों के साथ क्षति का विवरण संलग्न कर रहे हैं। एस ई जेड संयंत्र का डाटा हटाए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- प. पी यू सी के आयात केवल पी यू सी के लिए समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण के अधीन सूचित किए गए हैं तथा डी जी सी आई व एस द्वारा आयात की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रकाशित की गई संक्षिप्त सूचना को माना गया। विभिन्न आर्थिक पैरामीटर्स पर डाटा कंपनी द्वारा मेटेन किए गए रिकॉर्ड पर आधारित है। उत्पादन, बिक्री तथा माल सूचियों से संबंधित डाटा कंपनी द्वारा मेटेन किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेकॉर्ड पर आधारित है। बिक्री मूल्य, उत्पादन लागत तथा लाभ/हानि संबंधी डाटा कंपनी द्वारा मेटेन किए गए रिकॉर्ड पर आधारित है।
- फ. कुछ सूचना/डाटा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया तथा उस पर गोपनीयता बरतने का अनुरोध किया गया।
- ब. रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए विचारधीन उत्पाद “अनरॉट एल्यूमीनियम” है जिसमें सीमा शुल्क शीर्षक 7601 बिना एलॉय एल्यूमीनियम तथा एल्यूमीनियम एलॉय शामिल हैं। विचारधीन उत्पाद में एल्यूमीनियम की सिल्लियाँ, एल्यूमीनियम वायर रॉड तथा एल्यूमीनियम बिलेट्स हैं। एल्यूमीनियम सिल्लियाँ कास्ट एल्यूमीनियम (अनरॉट) का मूल रूप है तथा इसे तरल हॉट मेटल को साँचों में डालकर तरल को ठोस करने की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। सिल्लियाँ, तरल एल्यूमीनियम मेटल को एलॉय तत्वों को मिलकर अथवा बिना मिलाए कास्ट की जाती हैं। एल्यूमीनियम वायर रॉड्स पिघले हुए एल्यूमीनियम में से कास्टिंग तथा रोलिंग मिल में बनाई जाती हैं जिसका कॉमन व्यास 9.5 mm होता है (अन्य व्यास 7.6mm तथा 12.5mm है)। एल्यूमीनियम बिलेट मेटल का टुकड़ा है जिसका गोल अथवा चौकोर तिरछे रूप में कटा आकार होता है जिसका व्यास 4” से लेकर 20” तक होता है। बिलेट्स निरंतर कास्टिंग द्वारा सीधे ही बनाए जाते हैं। एक्स्ट्रशन के लिए बिलेट्स का आगे प्रोसेस किया जाता है। तैयार उत्पादों में प्रोफाइल, ट्यूब तथा रॉड्स आते हैं।

- भ. वर्तमान मामले में पी यू सी के दायरे में सभी आकार, प्रकार व रूपों के अनरॉट एल्यूमीनियम शामिल हैं। वर्तमान लिखित निवेदन में जहाँ तक 7601 के अधीन वर्गीकरणीय है वहाँ तक सभी आयामों, आकारों, प्रकारों, विशिष्टताओं, रूपों के पी यू सी कवर होते हैं तथा चाहे ये 7601 के वर्गीकरण के अलावा भी वर्गीकृत किए गए हों।
- म. नॉन एलॉय सिल्लियाँ किसी भी प्रकार के एल्यूमीनियम उत्पादों जैसे एक्ट्रशंस, केबलस, कंडक्टरस, सेकण्डरी वायर रॉड, मेटल पाउडर, रसायनो, मोटर वाहन उद्योग के लिए एलॉय सिल्लियाँ तथा विभिन्न कास्टिंग, वर्तनों, फ़ाउण्डरी, कास्टिंग तथा अन्य औद्योगिक व अभियांत्रिक यंत्रों, स्टील डी आँक्सीडाइजिंग, बिल्डिंग तथा निर्माण तथा इसी प्रकार के लिए बेस मेटल की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। एलॉय सिल्लियाँ, एल्यूमीनियम डाइ कास्टिंग उद्योग में ऑटो कॉम्पोनेंट, विभिन्न कास्टिंगों में प्रयोग की जाती हैं। एलॉय कंडक्टर्स के लिए एलॉय वायर रॉड्स से वायर बनाए जाते हैं। नॉन एलॉय बिलेट्स तथा एलॉय विलेट्स एक्ट्रशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नॉन एलॉय एल्यूमीनियम वायर बार तथा एलॉय वायर बार सजावट, निर्माण, रिवेट्स आदि में प्रयोग किए जाते हैं।
- य. एल्यूमीनियम आमतौर पर सबसे अधिक प्रचलित खनिज अयस्क बाक्साइट से प्राप्त किया जाता है। पिसे हुए अयस्क को कास्टिक सोडे में घोलकर तथा घोल को सेटिंग टैंक में पम्प कर एल्यूमिना (एल्यूमीनियम हाइड्रेट) को अयस्क से अलग किया जाता है। इसे वायर प्रक्रिया कहते हैं। जिस घोल में एल्यूमिना है उसमें उच्च विद्युत प्रवाह गुजार कर इलेक्ट्रोलेसिस की प्रक्रिया से शुद्ध मेटल प्राप्त की जाती है। लगभग एक टन के प्राइमरी एल्यूमीनियम के लिए 6 टन से कम बाक्साइट की आवश्यकता होती है।
- कक. सीमा शुल्क का वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान लिखित निवेदन तथा प्रस्तावित तरीकों के दायरे में यह बाध्यकारी नहीं है तथा वर्गीकरण की परवाह करे बगैर इन्होंने उत्पाद के वितरण पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।
- खख. नार्वे से (a) ईसी – बेड लिनेन तथा (b) फार्म्ड सालमन के मामलों में डब्ल्यू टी ओ के निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि विचाराधीन उत्पाद की व्याख्या के संबंध में कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है। जांच प्राधिकारी जिस तरीके को भी उचित मानते हैं उससे विचाराधीन उत्पाद की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। विचाराधीन उत्पाद की प्रत्येक प्रकार के लिए अलग से जोखिम विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत अलग से जोखिम विश्लेषण गैर कानूनी है।
- गग. सिल्लियाँ, बिलेट्स, बार, वायर, रॉड उत्पाद के केवल विभिन्न प्रकार हैं। इसी प्रकार, एलॉय तथा नॉन-एलॉय के मध्य एल्यूमीनियम संयोजन ही एकमात्र अंतर दर्शाता है, जो उत्पाद के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होता है। वैश्विक रूप से अधिकतर उत्पादक विभिन्न प्रकार के अनरॉट एल्यूमीनियम का उत्पादन करते हैं।
- घघ. पी यू सी कई रूपों में हो सकता है, जिसमें सिल्लियाँ, बिलेट्स, वायर बार, वायर रॉड आदि शामिल हैं। केवल आकार, प्रकार के रूप में अंतर होने मात्र से अलग अलग प्रकार को अलग उत्पाद नहीं माना जा सकता। महानिदेशक रक्षोपाय ने बहुत से निष्कर्ष जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न आकारों, रूपों तथा प्रकारों को एक वस्तु माना गया है। एक्रेलिक फाइबर से संबंधित जाँचों में, टो, टॉप तथा स्टेपल को एक वस्तु माना गया है; एल्यूमीनियम एफ आर पी तथा फॉयल के मामले में विभिन्न प्रकार के एफ आर पी तथा फॉयल को एक वस्तु माना गया है; स्टेनलेस स्टील के मामले में, विभिन्न आवेदनों को विभिन्न आकार, चौड़ाई व मोटाई को एक उत्पाद माना गया; विद्युत इंसुलेटर मामले में, ग्लास व पोरसलीन इंसुलेटर तथा विभिन्न आवेदनों

- के इंसुलेटरों को एक उत्पाद माना गया है। आगे, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन इंसुलेटर, यंत्र इंसुलेटरों को एक उत्पाद माना गया है। इसी प्रकार, विभिन्न आकार, प्रकार, उत्पाद की चौड़ाई को एक उत्पाद माना गया है। आँकसी एल्कोहल में एनबीए, आईबीए तथा ईएचए को एक उत्पाद माना गया है; सीमलेस पाइप व ट्यूब के मामले में विभिन्न प्रोसेस के द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं तथा लाइन, बोयलर, कास्टिंग तथा ट्यूबिंग को एक उत्पाद माना गया है। इसी प्रकार, वैश्विक रूप से अन्य प्राधिकारियों द्वारा रक्षोपाय तथा एंटी डंपिंग पर नामित प्राधिकारी द्वारा की गई की जांच के बहुत से उदाहरण हैं।
- उड़. याचिककर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तुएँ सीधे तौर पर अथवा उस जैसे स्पर्धात्मक उत्पाद हैं। भौतिक व रसायनिक विशेषता निर्माण प्रक्रिया व तकनीक, कार्यप्रणाली व प्रयोग, उत्पाद विशिष्टता, मूल्य, वितरण व मार्केटिंग तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मापदण्डों के संबंध में दोनों उत्पादों की विशेषताएँ तुलनीय हैं। घरेलू उत्पाद एवं आयातित उत्पाद के संबंध में आवश्यक उत्पाद विशेषताओं में तुलना किया जाना दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ आयातित वस्तुओं के साथ तुलना की जा सकती है। जबकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 7601 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद ही आते हैं व इन जैसे व सीधे तौर पर जिन से प्रतिस्पर्धा है भारत में वे स्कैप (सेकेण्डरी उत्पादक) तथा एल्यूमिना (प्राइमरी उत्पादक) के प्रयोग से उत्पादित हो रहे हैं।
- चच. जहां तक “मुख्य हिस्सा” की आवश्यकता से संबंध है, याचिकाकर्ताओं मेसर्स वेदांता लिमिटेड, बाल्को इंडस्ट्रीज तथा हिंडाल्को लिमिटेड के पास विषयक वस्तुओं के विरुद्ध याचिका दायर करने तथा उसे बनाए रखने का कारण है। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक के हिस्से के बराबर बनता है।
- छछ. नियमों के अर्थ के अंतर्गत अनरॉट एल्यूमीनियम का आयात “बढ़ा हुआ आयात” बनता है। रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए घरेलू उत्पादन से संबन्धित व घरेलू खपत से संबन्धित तथा बढ़े हुए आयात के कारण क्षति की समग्र शर्तों के साथ बढ़ा हुआ आयात है। नियमों में अपेक्षित है कि बढ़े हुए आयात की दर तथा मात्रा का घरेलू उत्पादन तथा खपत के संबंध में समग्र शर्तों के साथ विश्लेषण किया जाए। उत्पाद का आयात एकाएक; महत्वपूर्ण, हालिया तथा स्पष्ट होना चाहिए परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी वृद्धि आवश्यक रूप से जांच की अवधि के अंत में अथवा निर्धारण के समय हुई हो। आयात में वृद्धि को निर्धारित किए जाने के उद्देश्य से दोनों सिरों की तुलना की जानी चाहिए व बीच के रुझानों को भी देखा जाना चाहिए।
- ii. यूएस लाइन पाइप में, प्राधिकारी ने वक्तव्य दिया कि “आयात के रूख में अस्थायी बदलाव बढ़े हुए आयात के अस्तित्व को दर्शनी वाले समग्र रूप को पलट दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता”。 यू एस लाइन पाइप में, पेनल ने पाया कि “हालिया” शब्द का अर्थ है “पूर्व प्रभावी विश्लेषण”; परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी के निर्णय से ठीक पहले की स्थितियों का विश्लेषण न ही इसका अर्थ है कि विश्लेषण आवश्यक रूप से जांच की एकदम अंतिम अवधि की स्थितियों पर केन्द्रित हो।
- बज. आवेदकों ने निर्धारण किया है। कि क्या भारत में पी यू सी का आयात उत्पादन की तुलना में बढ़ा है एवं पी यू सी के आयात के साथ भारत में पी यू सी के उत्पादन एवं उपभोग की तुलना की है। विचाराधीन उत्पाद के आयात में समय रहते अचानक तेज एवं काफी वृद्धि दर्शाई है। आगे, आयात एंड टू एंड प्वाइंट नहीं बढ़ा है लेकिन पूरी अवधि में बढ़ा है। आयात दोनों, वास्तविक मदों के संबंध में एवं भारत में उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में बढ़ा है।

- टट. घरेलू उधोग का मार्केट शेयर 2014-15 में गिर गया परन्तु उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा। तथापि मांग में वृद्धि के बावजूद मूल वर्ष से घरेलू उत्पादक अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में असफल रहे। आयात का मार्केट समय के बाद बढ़ा। घरेलू उधोग का मार्केट शेयर, सम्पूर्ण रूप में, कम हुआ है।
- ठठ. रक्षोपाय उपाय लागू करने के लिए आयात में वृद्धि एक मूल पूर्व अपेक्षा के रूप में नियमों में अपेक्षित है। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद का आयात रक्षोपाय उपाय लागू करने के प्रयोजन हेतु “इतनी मात्रा में बढ़ा”, आयात में वृद्धि, वास्तविक मदों में एवं घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में के विश्लेषण की नियमों में अपेक्षा है। आयात में वृद्धि गंभीर क्षति पहुँचाने या गंभीर क्षति की आशंका हेतु वर्तमान, अचानक, तेज एवं पर्याप्त रूप में काफी होनी चाहिए। शब्द “वर्तमान” “पूर्वव्यापी विश्लेषण” का संकेतक है परन्तु यह प्राधिकारियों के निर्णय के तत्काल पूर्व शर्तों के विश्लेषण का संकेत नहीं है न ही यह संकेत है कि जांच की अवधि के तुरंत बाद की स्थितियों पर विशेष रूप से विश्लेषण केंद्रित होना चाहिए। अनरॉड अल्युमिनियम के वर्धित आयात का विश्लेषण इन मूल्यांकनों की रोशनी में किया जा चुका है।
- डड. आयात में वृद्धि के कारण हैं कि पुरे विश्व में उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से अधिक क्षमता है जो उन्हें उत्पाद को अन्य बाजारों में बेचने हेतु बाध्य करती है। भारतीय बाजार उच्च वृद्धि संभावनाओं वाला एक काफी बढ़ा बाजार है एवं इसका प्रयोग सस्ती वस्तुओं की विक्री हेतु किया जा चुका है। आयात किए जा रहे धातु की बहुलता मध्य पूर्व क्षेत्र की है।
- ढढ. मध्य पूर्व में उत्पादकों ने विश्व में एलुमीनियम की मांग का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमताओं का विस्तार किया जिससे मध्य पूर्व की कंपनियों के पास अधिक अप्रयुक्त क्षमता हो गई जो भारतीय बाजार में निर्यात हेतु प्रयुक्त की जा रही है।
- णण. मध्य पूर्व देशों ने मूल एलुमीनियम उत्पाद हेतु उनकी अपनी क्षमता में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि की है। चीन एलुमीनियम उत्पाद में कमी का कोई संकेत नहीं है, मध्य पूर्व उत्पादकों की वर्धित क्षमता का उपयोग भारत में हो रहा है। इन देशों में एलुमीनियम के उत्पाद एवं उपभोग में बढ़ा अंतर है इसलिए भारत जैसे फ्राइट फ्रेंडली बाजार वस्तुओं के निर्यात हेतु बड़े बाजार है।
- तत. चीन ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर बाजार में भी एक मजबूत खिलाड़ी की तरह प्रवेश किया है। इससे मध्य पूर्व देशों को भारतीय बाजार में आक्रामक रूप से निर्यात हेतु बड़ावा दिया है।
- थथ. इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पी यू सी का भारत में आयात इतना असार्थक है कि इसे अनापेक्षित घटना नहीं माना जा सकता। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि कारक/कारण, जिनके कारण आयात में वृद्धि हुई है, विधि के अधीन अपेक्षित है। यह अपेक्षा यह संकेत नहीं है कि संबंधित देश से उस हिसाब से आयात बढ़ना चाहिए। यदि चीन में बाजार अवस्था में परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण तीसरे देशों से आयात बढ़ा है तो वर्तमान मामले में आयात में वृद्धि हेतु कारण निर्धारित करने हेतु चीन में प्रचलित ऐसे कारक/कारण न ही संगत हैं न ही आवश्यक हैं। इस संदर्भ में चीन में प्रचलित मार्केट स्थिति एल एम ई की फ्री गिरावट एवं फलस्वरूप आयात में वृद्धि हेतु तथ्यों में से एक है।
- दद. एलुमीनियम विनिर्माण में मुख्य लागत एनर्जी है। मध्य पूर्व देशों की विजली लागत अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है इसलिए इस क्षेत्र में स्मेलर्ट्स लाभप्रदता एडवांटेज के साथ व्यापार शुरू करते हैं। भारतीय स्मेलर्ट्स की एनर्जी लागत लगभग 38% बैठती है जो कि लगभग 700 डालर प्रति मी. टन है। यू ए ई स्मेलर्ट्स की एनर्जी लागत लगभग 360 डालर प्रति मी. टन है। इसके विपरीत भारतीय स्मेलर्ट्स कोयले से चलाए जा रहे पावर प्लांट्स द्वारा उत्पन्न विजली पर चलते हैं। कोयला विजली संयंत्र से चलाए जाने की लागत महंगी है।
- धध. भारत की भोगौलिक स्थिति के कारण मध्य पूर्व देशों के लिए भारत फ्राइट फ्रेंडली है इसलिए उनके लिए भारत को एलुमीनियम का निर्यात सुविधाजनक एवं आर्थिक रूप में अधिक व्यवहार्य है। विचाराधीन उत्पाद

की यूरोप में स्थिर वृद्धि के कारण मध्य पूर्व के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए लक्ष्य बाजार बन गया है जिसके कारण इन देशों से आयात में वृद्धि हुई है आगे मध्य पूर्व से भारत तक का समुद्री भाड़ा वर्तमान अवधि में कम हुआ है जिसके कारण भी आयात में वृद्धि हुई है।

- नन. प्राइमरी एलुमीनियम के निर्यात पर चीन 15% निर्यात कर लगाता है। दूसरी ओर, यह वैल्यू एडिड एलुमीनियम उत्पादों के निर्यात पर 13% कर रिबेट का ऑफर देता है। जिससे चीन उत्पादों को एक एडवाटेज मिलता है जिसने विश्व में एलुमीनियम व्यापार को स्किवड कर दिया है एवं जिससे पूरे विश्व में विभिन्न स्मेलटर्स को बंद करने के लिए बाध्य कर दिया है।
- पप. चीन अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण चीन ने जरूरत से अधिक क्षमता का सामना किया। इसमें बावजूद, स्थानीय सरकारों के समर्थन के कारण चीन के एलुमीनियम उत्पादक अपने स्मेलटर्स बंद नहीं कर रहे हैं। चीन में लगभग सभी एलुमीनियम उत्पादक वर्तमान एलुमीनियम कीमतों पर वित्तीय हानि उठा रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट बताती हैं कि चीन का एलुमीनियम उत्पाद 11% से 2015 में 30 मी.टन तक बढ़ेगा एवं आगामी वर्ष में और 1.8 मी. टन की क्षमता होने की संभावना है। चीन ने अपने सरप्लस को शेष विश्व को भेजना जारी रखा है, मूल्य कम किए हैं एवं स्मेलटर्स को, जहाँ कहीं भी हों, को बंद होने के किनारे पर ला दिया है।
- फफ. एजेड चीन के अनुसार गनसु प्रदेश कि स्थानीय सरकार ने बिजली की लागत को इस प्वाइंट तक कम किया है कि लियाचेंग वर्तमान कीमतों पर भी कम से कम ब्रेक हो सकता है।
- बब. चीन से बाहर एलुमीनियम मार्केट में किसी प्रकार की आपूर्ति-मांग के अंतर के समय इसे अर्धनिर्मित उत्पादों के चीन निर्यात द्वारा पूरा किया जाता है जिससे निर्यातकों को मेटल के निर्यात पर निपेधात्मक 15% कर बचाने में सहायक होती है और वे वैल्यू एडिड उत्पादों के निर्यात पर कर छूट प्राप्त कर लेते हैं।
- भभ. “गंभीर क्षति” के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कुछ सूचीबद्ध तथ्यों के साथ-साथ अन्य संगत तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रत्येक सूचीबद्ध तथ्य के मूल्यांकन में यह दर्शाना आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा प्रत्येक तथ्य “डिक्लाइनिंग” है। यह आवश्यक है कि उधयोग की अवस्था पर प्रभाव रखने वाले सभी संगत तथ्यों की रोशनी में घरेलू उधयोग की सम्पूर्ण अवस्था का मूल्यांकन किया जाता है।
- मम. वर्धित आयात एवं क्षति विश्लेषण हेतु डी आई ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि पर विचार किया है। आयात में ऐसी वृद्धि के कारण घरेलू उधयोग को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
- यय. आवेदकों ने वेदांत एवं बाल्को हेतु समर्पित क्षमता पर विचार किया है। हालांकि हिन्डाल्को के मामले में क्योंकि क्षमता को समर्पित नहीं किया गया है, आवेदकों ने (हाटमेटल उत्पादन एवं क्षमता पर रेशियों प्रोपोरशन मेथड लागू करते हुए गणना की गई) वर्किंग क्षमता पर विचार किया गया है।
- ककक. घरेलू उधयोग का उत्पादन एवं घरेलू बिक्री समय के बाद बढ़ी है। ऐसे उत्पादों के संयंत्र को उच्च परिचालन दरों पर चलाना अपेक्षित होता है। यदि इन संयंत्रों को कम उपभोग दरों पर चलाया जाता है तो औवर हेड/फिक्सड लागत प्राप्त नहीं होती है। मांग में वृद्धि के साथ घरेलू उधयोग ने अपनी क्षमता बढ़ाई। संक्षिप्त तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क्षमता	मी. टन	12,51,400	12,53,700	13,54,480	21,88,728	31,39,569
उत्पादन	मी. टन	9,97,282	10,63,882	11,53,951	15,01,542	15,99,740

आयात	मी. टन	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964
घरेलू बिक्री	मी. टन	5,18,295	5,91,784	5,04,675	5,01,513	7,00,486
निर्यात	मी. टन	1,48,485	1,34,555	2,96,301	5,95,931	6,64,197
मांग	मी. टन	20,36,574	22,34,732	21,46,481	23,63,727	24,39,251

मूल वर्ष के बाद वृद्धि

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उत्पादन	मी. टन		66,600	1,56,669	5,04,260	6,02,458
घरेलू बिक्री	मी. टन		73,489	-13,620	-16,782	1,82,192
निर्यात	मी. टन		-13,930	1,47,816	4,47,445	5,15,712
आयात	मी. टन		65,746	1,06,352	1,00,895	17,94,31
मांग	मी. टन		1,98,157	1,09,907	3,27,153	4,02,676

**खण्डख.** उत्पादन में वृद्धि अधिकांशतः मांग में वृद्धि के साथ अनुक्रम में है। इस प्रकार डी आई अपना वर्धित उत्पादन घरेलू बाजार में आसानी से बेच सकते थे। तथापि डी आई वर्धित उत्पादन घरेलू बाजार में बिक्री करने में सक्षम नहीं रहे हैं एवं बढ़ते आयात की दृष्टि से इन्वेंटरी के जमा होने से बचने के लिए पी.यू.सी. को निर्यात करने हेतु बाध्य हो गए हैं।

**गगग.** क्योंकि वर्तमान वर्ष (2015-16) में डी आई को निर्यात में वित्तीय हानि उठानी पड़ रही थी, तो डी आई ने अपनी बिक्री बढ़ाने हेतु घरेलू बाजार में आयातित उत्पाद के मूल्यों एवं अपने मूल्यों के बीच के अंतर को धीरे-धीरे कम किया।

**घघघ.** डी आई भारत में वर्धित आयात के कारण पी.यू.सी. को निर्यात करने को बाध्य हुए हैं। निर्यात एवं निर्यात में हुई वित्तीय हानियों को डी आई को क्षति के मानदंडों में से एक के रूप में विचार करना चाहिए।

**ड-ड-ड-** क्योंकि आयात के काफी वाल्यूम अलॉय ग्रेड के हैं, डी आई की बिक्री का काफी हिस्सा गैर अलॉय ग्रेड का है। सारणी दर्शाती है कि अलॉय एवं गैर अलॉय उत्पाद के बीच काफी मूल्य अंतर है:-

एच एस कोड	वाल्यूम	शेयर	औसत मूल्य
760110	1,43,023	45.86	119.24
760120	1,68,820	54.14	132.91
कुल	3,11,843	100	126.64

- चचच. डी आई ने उस अवधि के दौरान घरेलू उधोग के बिक्री मूल्यों, एवं आयात की उत्तराई की मासिक आधार पर लागत, आयात की उत्तराई की लागत यदि आयात औसतन प्रचलित एल एम ई मूल्यों पर किया गया होता, का निर्धारण किया है।
- छछछ. जुलाई 2015 से टाइम टैग के कारण एल एम ई मूल्य आयात मूल्यों से काफी कम है आयात एवं एल एम ई मूल्य डी आई के बिक्री मूल्यों से काफी कम है। अतः आयात की उत्तराई की लागत डी आई के बिक्री मूल्य से काफी कम है। मूल्यहास निश्चय ही ज्यादा है। यह विश्लेषण आवेदक कंपनियों के बिक्री मूल्यों पर आधारित है।
- जजज. क्योंकि 2015-16 के अवधि में आयात मूल्य धीरे-धीरे कम हुए, आयात का वाल्यूम काफी बढ़ गया।
- झझझ. पी यू सी का आयात बहुत प्रतिकूल रूप में उत्पादन क्षमता के उपयोग को देश में प्रभावित कर रहा है जो कि निश्चय ही कम है। एलमुना रिफाइनिंग एवं एलमीनियम स्मेलटिंग, दोनों प्रोसेस आपरेशन हैं एवं इसलिए दोनों में क्लालिटी पावर की लगातार आपूर्ति की आवश्यकता है। आवेदकों को उपयोगिता लागत को कम करने के उद्देश्य से अधिकतम संभावित उत्पादन को सुनिश्चित करना है। कोई उत्पादक इनवेंटरी को कायम रखने का समर्थन नहीं कर सकता। उसी समय, कोई उत्पादक उत्पादन को विनियमित या निलंबित करने का समर्थन नहीं कर सकता। वर्तमान उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक जैसे उधोग से पूर्णतया भिन्न है जहाँ उत्पादान का स्विच ऑफ एवं स्विच आन काफी मायने नहीं रखता।
- जजज. इनवेंटरी के इकट्ठा होने का सामना कर चुके आवेदक पहले भी उत्पाद के पर्यास निर्यात का सहारा ले चुके थे। जब कभी भी आवेदक घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उन्होंने भारत के बाहर के बाजार से आर्डर लिए एवं उत्पाद का निर्यात किया। ज्यादा हानि के बावजूद डी आई ने निर्यात का सहारा लिया है। यदि डी आई निर्यात में वृद्धि करते हैं, जहाँ वे बहुत हानि उठा रहे हैं, तो उसके लिए घरेलू बाजार में अपना उत्पाद बेचने में अक्षमता सत्यभासी कारण होना चाहिए।
- टटट. वर्धित आयात के कारण घरेलू उधोग अपनी इनवेंटरी का निपटान करने में अक्षम है। आवेदक अपनी इनवेंटरी के निपटान हेतु निर्यात का सहारा ले रहे हैं।
- ठठठ. इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क किया गया है कि आवेदक निर्यात मूल्यों के तुलनीय मूल्यों पर घरेलू बाजार में अपना माल अच्छी तरह से बेच सकते हैं। यदि डी आई ने उत्पाद का निर्यात न किया होता एवं इसे घरेलू बाजार में बेचा होता तो उन्हें वित्तीय हानि न उठानी पड़ती।
- डडड. डी आई ने क्षमताओं में वृद्धि के साथ मैनपावर भी बढ़ाया। तथापि डी आई को अपनी मैनपावर घटाने को बाध्य होना पड़ा। आवेदक कंपनियों में से एक ने व्यक्तियों को हटा दिया एवं और रोजगार को कम करने को बाध्य होंगे। क्या वर्तमान स्थिति जारी रहनी चाहिए रोजगार स्तरों में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उधोग को भुगतान किए गए वेतन में वृद्धि हुई है।
- ढढढ. वर्तमान अवधि के पश्चात घरेलू उधोग की लाभप्रदता अलग-अलग बहुत ही कम हो गई है।
- णणण. घरेलू उधोग का नकद लाभ काफी नीचे आ गया है एवं वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उधोग को नकद हानि का सामना करना पड़ा।
- ततत. काम में नियोजित केपिटल पर रिटर्न पूरी क्षति अवधि के दौरान कम रहा एवं वर्तमान अंकड़ों में निम्नतम स्तर तक गिर गया। घरेलू उधोग को हो रही क्षति पी ओ आई में घरेलू उधोग द्वारा अर्जित इनवेस्टमेंट पर रिटर्न से प्रमाणित होती है। घरेलू उधोग द्वारा अर्जित इनवेस्टमेंट पर रिटर्न इतना कम है कि यह व्याज लागत पर भी रिकवरिंग की अनुमति भी नहीं दे रहा है घरेलू उधोग को पर्यास लाभ की बात तो छोड़ दीजिए। जारी वर्धित आयात घरेलू उधोग को लाभप्रदता के संबंध में गंभीर क्षति के रूप में फलित होगा।
- थथथ. रक्षोपाय विधि के अधीन गंभीर क्षति की आशंका के निर्धारण के संबंध कोई विहित तरीका नहीं है। नियमों के अधीन विशिष्ट तरीकों के अभाव में, गंभीर क्षति की आशंका का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है,

के लिए आवेदकों ने डम्पिंग विधि एवं डब्ल्यू टी ओ निर्णयों को संदर्भित किया है। किसी मामले की विशेष परस्थितियों में, पूर्व के वर्तमान में ही वर्धित स्तर पर आयात का जारी रहना, ऐसी आशंका का कारण काफी होता है।

**ददद.** घरेलू उद्धोग को पहले ही पहुंची गंभीर क्षति के अलावा विचारधीन उत्पादन के वर्धित आयात से घरेलू उधयोग को ऐसी गंभीर क्षति की आशंका हो रही है। गंभीर क्षति की आशंका को निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित किया जा सकता है:-

- i. घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच मूल्य अंतर निश्चय ही काफी है।
- ii. एल एम ई लगातार गिर रहा है। आयात में वृद्धि की दृष्टि में एल एम ई में धीरे-धीरे गिरावट है एवं घरेलू उत्पादकों के मूल्यों के बीच कमी हो रही है।
- iii. विदेशी उत्पादकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमता इकट्ठा है। परिणामतः विदेशी उत्पादक संभावित एक्सटेंट तक अतिरिक्त मार्केट की तलाश कर रहे हैं।
- iv. आयात का वाल्यूम प्रासंगिक कम अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है।
- v. घरेलू उद्धोग को जमा हुई इनवेटरी का सामना करना पड़ा है।
- vi. न केवल विश्व स्तर पर विचारधीन उत्पाद की मांग में कमी ही बल्कि जारी कम मांग की संभावना है। वास्तव में मांग लगातार गिर रही है।

**धधध.** मांग में विश्व स्तरीय कमी ने उत्पाद की कीमतों में अत्यधिक कमी को प्रेरित कर दिया है। एल एम ई में अस्थायी वृद्धि से घरेलू उधयोग को कोई राहत नहीं है। अब उपलब्ध कराई गई क्षति सूचना मार्च 2016 तक की अवधि हेतु है। घरेलू उधयोग को महत्वपूर्ण वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा है जब औसत एल एम ई 1742 यू एस डालर प्रति मी. टन था। कम से कम एल एम ई में और कमी है। यदि घरेलू उधयोग को 2015-16 में महत्वपूर्ण हानि उठानी पड़ी है इसका अर्थ है कि घरेलू उधयोग वर्तमान एल एम ई पर भी वित्तीय हानि से गुजर रहे हैं।

**ननन.** चीन अर्थवयवस्था में मंदी के कारण चीन को अधिक क्षमता का सामना करना पड़ा है। चीन ने अपने सरप्लस को शेष विश्व को भेजना जारी रखा है, कीमतें कम की है एवं स्मेलर्ट्स कों, कहीं भी हों, को बंद होने के कगार पर ला दिया है।

**पपप.** इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चीन से भारत में पी यू सी का आयात इतना अपर्याप्त है कि इसे अनपेक्षित घटना के रूप में नहीं माना जा सकता। विधि के अधीन अपेक्षित है, कारक/कारण, जिनकी वजह से आयात में वृद्धि हुई। अपेक्षा इसका संकेत नहीं है कि आयात स्वभावतः संबंधित देश से होना चाहिए। यदि चीन में बाजार स्थिति में बदलाव हुए हैं जिनके कारण आयात तीसरे देश से बढ़ा है तो चीन में प्रचलित ऐसे कारक/कारण संगत हैं। चीन में प्रचलित बाजार स्थिति एल एम ई में फ्री गिरावट एवं परिणामी आयात में वृद्धि हेतु तथ्यों में से एक है।

**फफफ.** पी यू सी का आयात पहले ही गंभीर क्षति पहुंचा रहा है, भविष्य में भी इसके बढ़ने की संभावना है तो क्या रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

**बबब.** कोई अन्य कारक नहीं हैं जो वर्धित आयात के अलावा घरेलू उधयोग को गंभीर क्षति के उत्तरदायी हो सकते हों। भारत में पी यू सी की मांग में कोई संकुचन नहीं है इसलिए मांग में संभावित कमी ने घरेलू उधयोग को क्षति नहीं पहुंचाई है। पी यू सी के संबंध में उपभोग के पेटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रेक्टिसनहीं हैं जो घरेलू उधयोग को क्षति के सहायक हो सकते हो। उत्पाद के उत्पादन हेतु तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, घरेलू उधयोग को दावा की गई क्षति घरेलू संचलनों के कारण है, एवं निर्यात के बजह से नहीं।

**भभभ.** घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति पी यू सी के कारण है। आवेदकों ने पी यू सी से संबंधित वित्तीय सूचना को अलग किया है एवं आवेदन में दिया है।

**ममम.** अपेक्षा “एक” कारणात्मक संबंध है न कि “वही” कारणात्मक संबंध है। “एक कारणात्मक संबंध” एवं “वही कारणात्मक संबंध” में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बाद वाला संकेतक है कि वर्धित आयात क्षति का वही कारण होना चाहिए, पहले वाला संकेतक है कि वर्धित आयात क्षति के कारणों में से एक है।

**ययय.** अकेला तथ्य, कि साथ ही साथ क्षति के कुछ अन्य कारण भी है, का अर्थ यह नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात क्षति का एक कारण नहीं है।

**कककक.** वर्तमान मामले के तथ्यों में, निर्यात में वृद्धि एवं डी आई द्वारा उठाई गई हानियाँ कारकों में से एक है जो कारणात्मक संबंध दर्शाता है। घरेलू उद्योग केवल भारत में आयात के कारण निर्यात करने हेतु बाध्य हुए हैं। इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि घरेलू उद्योग को निर्यात क्यों करना चाहिए जबकि भारत में उत्पाद की मांग है।

**खखखख.** इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में वर्धित आयात और घरेलू उद्योग के मध्य कॉजल लिंक दर्शाया गया है;

- i. उत्पाद काफी हद तक आयात की तुलना/प्रतिस्पर्धा में बेचा जाता है।
- ii. बिल्कुल हाल की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- iii. वर्धित आयात के कारण इंवेंट्रिज का ढेर हो गया है।
- iv. घरेलू उद्योग निर्यात का सहारा लेने के लिए विवश हैं, जिसमें वैश्विक बाजार में उत्पाद की कम कीमतों के कारण घरेलू उद्योगों को बहुत क्षति हो रही है।
- v. उत्पाद के आयात में 2014-15 गिरावट आई है। परिणामतः घरेलू उद्योग का लाभ बढ़ा है। तथापि 2015-16 में आयात पुनः बढ़ा और घरेलू उद्योगों को वित्तीय हानि उठानी पड़ी। यह भारतीय बाजार में कम कीमत वाले आयातों के प्रवेश के कारण हुआ।
- vi. परिणास्वरूप घरेलू उद्योगों की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है और उनका नुकसा उठाना पड़ रहा है।

**गगगग.** याचिकाकर्ताओं ने दो वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु अनुरोध किया है।

**घघघघ.** लोक हित: वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण तीन विभिन्न पक्षों – उत्पादक, उपभोक्ता और आम जनता के नजरिए से लोक हित में इस प्रकार होगा:

- i. यह उपाय भारत में वर्धित आयात के कारण घरेलू उद्योग को आगे होने वाली क्षति से बचाएगा। घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण क्षति के पीड़ित हैं और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से घरेलू उद्योग इस क्षति से बच जाएंगे। जिस उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण महत्वपूर्ण है उसका उत्पादन किए जाते रहने कि अनुमति याचिकाकर्ताओं को दी जानी महत्वपूर्ण है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण ज्वेली गई क्षति से उबारेगा, निष्पादन में गिरावट को रोकेगा, डीआई को जीवनक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
- ii. ऐसा घरेलू उद्योग उपभोक्ता के हित में है जो कि उपभोक्ताओं को पीयूसी की आपूर्ति करने में सक्षम हो एवं विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर सके। यदि वर्तमान स्थिति को ऐसे ही चलने दिया गया तो भारतीय घरेलू उद्योग को और हानि होगी और उनका बिल्कुल ही सफाया हो सकता है और इससे विदेशी उत्पादकों को वर्धित प्रभावन क्षमता मिलेगी।

- iii. ऐसे बहुत ही कम उपभोक्ता हैं जो पीयूसी की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी के कारण बढ़ने वाली लागत को वास्तव में बहन कर सकें और गिरती कीमतों को लाभ उठा सकें। उद्योग के बहुत से प्लेयर्स पास थ्रू बेसिस पर कार्य करते हैं अर्थात् वे वृद्धि एवं कमी को कब्जे माल की लागतों पर हस्तांतरित कर देते हैं। उपभोक्ता पर 10% रक्षोपाय शुल्क का संभावित प्रभाव 0.053% होगा। अतः इसका कोई आधार नहीं है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को भुगतना पड़ेगा।
- iv. एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग का होना व्यापक रूप से जनता के हित में है। बढ़ते व्यापार-घाटे एवं क्षीण होते विदेशी मुद्रा रिजर्व के कारण यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर भरोसा किया जाए। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सबजेक्ट गुड्स का प्रयोग आवश्यक है। अतः आयात पर निर्भरता को कम करना रणनीतिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है।
- v. यदि घरेलू उद्योग को इस गिरती स्थिति में जाने दिया गया जहां वे प्रचालन न कर सकें तो भारतीय उपभोक्ता पूरी तरह से विदेशी उत्पादकों पर निर्भर हो जाएंगे।
- डडडड. भारतीय घरेलू उत्पादकों के पास देश की वर्तमान एवं संभावित/आगामी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता एवं सामर्थ्य है।
- चचचच. अंतिम उत्पाद की लागत पर संभावित प्रभाव नगण्य है।
- छछछछ. भारतीय उत्पादकों ने एक व्यवहार्य समायोजन प्लान निर्धारित किया है जिसमें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लागत में कमी, विद्यमान उत्पादन क्षमता का आगे उपयोग एवं क्षमता विस्तार पर ध्यान केंद्रीय किया गया है।
- जजजज. याचिकार्ताओं ने पीयूसी के उत्पादन के लिए एक दूसरा संयत्र स्थापित किया है। संयत्र ने परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है लेकिन वर्धित आयात के कारण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर पाया था जिससे महत्वपूर्ण क्षति हुई है। एक बार रक्षोपाय शुल्क मंजूर किए जाने के बाद संयत्र अपने इष्टतम स्तर पर पूर्णतः प्रचालित हो जाएगा।
5. दूसरे इच्छुक पक्षों के लिखित निवेदन का अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा दायर प्रत्युत्तर का सारांश इस प्रकार है:-
- अ. मै. सेंचुरी मैटल रिसाइकिंग प्राइवेट लिमिटेड

- क. विभिन्न मुक्त व्यापार करारों के अधीन दी गई रियायतें, एलएमई कीमतों में गिरावट, मुख्य निर्यातिक देशों में पश्च एफटीए छूटी रियायत क्षमताओं का स्थापित किया जाना अथवा उनको बढ़ाना जैसे कारक आयातों में वृद्धि का युक्तियुक्त कारण बनते हैं और इसी कारण से अनपेक्षित गतिविधियां/परिस्थितियां बनती हैं।
- ख. अनरॉट एल्यूमिनियम- अलाँय और गैर अलाँय दोनों- के आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है। फोकस अलाँय एल्यूमिनियम उत्पाद के वर्धित आयात पर है जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है। हालिया अवधि में आयातों में यह वृद्धि रक्षोपाय नियमों की भावना के अंतर्गत अभूतपूर्व, औचक, महत्वपूर्ण एवं तेज है।

अलाँय एल्यूमिनियम सिल्लियों के आयात का विवरण (एचएस760120)

वर्ष	मलेशिया	वियतनाम
2013-14	32329.35	51.00
2014-15	53821.71	1260.33
2015-16	53898.41	2401.92
2016-17 (वार्षिक)	83316.60	7561.42
2013-14 की तुलना में 2016-17 में आयातों में वृद्धि	162.5%	14723%

(स्रोत:- वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट)

- ग. एल्यूमिनियम अलॉय सिल्लियों (एचएस760120) का कुल घरेलू उत्पादन लगभग 500,000 मीट्रिक टन के बराबर है जब कि उक्त वस्तु का 2015-16 के दौरान आयात 224,570 मीट्रिक टन था जो कि कुल घरेलू उत्पादन का 45% होता है।
- घ. ऐसे आयात बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे आयातों के हिस्से को नगण्य नहीं माना सकता खास तौर पर ऐसी स्थिति में जहां देश में पहले से ही महत्वपूर्ण सरप्लस क्षमता हो। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कम कीमत जिस पर आयात किया जा रहा है, के कारण भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है और इस पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण द्वारा रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।
- ड. यह सत्य नहीं है कि संपूर्ण आयात अग्रिम लाइसेंस के अधीन है। बहरहाल, केवल यह तथ्य कि कुछ आयात अग्रिम लाइसेंस के अधीन है पूर्णतः अनावश्यक है। महानिदेशक वर्धित आयात के निर्धारण के लिए, आयातों की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना, और इस तथ्य के निर्धारण के लिए कि ये आयात बिना सीमा शुल्क ड्यूटी चुकाए किए गए थे और वे पूर्व में प्रासंगिक नहीं माने गए थे, सभी आयातों पर विचार करते हैं।
- च. कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अस्पष्ट एवं वाइड है। यह निवेदन किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों में भिन्नता सिर्फ संबंधित आकार, परिमाण और कंपोजिशन के संदर्भ में है। जबकि प्राथमिक उत्पादकों का फोकस विचाराधीन उत्पाद के गैर-अलॉय रूप के उत्पादन पर है, द्वितीयक उत्पादकों का प्राथमिक फोकस विचाराधीन उत्पाद के अलॉय रूप पर है। तथापि, दोनों में अंतर मात्र रासायनिक संरचना का है। अन्यथा विचाराधीन उत्पाद के सभी प्रकार तुलनीय हैं।
- छ. यह सत्य है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप मै. सेंचुरी मैटल रिसाइकिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी बहुत क्षति हुई है।
- ज. विचाराधीन उत्पाद के अलॉय रूप की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- झ. जनता के हितों की चिंता करते विरोधी पक्षों के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि जनता का हित घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने में है। शायद छोटी अवधि में सस्ते उत्पादों से अंतिम उपयोग उपभोक्ता को लाभ हो सकता है परंतु घरेलू उद्योग का दीर्घकालीन लाभ रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण में निहित है। रक्षोपाय शुल्क का विरोध करने वाले पक्ष यह स्थापित करने कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से अंतिम उपयोग उपभोक्ता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव होगा, के संबंध में कोई सत्यसाधनीय सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हुए हैं।
- ञ. अनरॉट एल्यूमिनियम (एचएस7601) (एचएस7601) जिसमें गैर अलॉय एल्यूमिनियम (एचएस760110) एवं एल्यूमिनियम अलॉय (एचएस760120) पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे आयात, जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है, में औचक एवं महत्वपूर्ण वृद्धि पर रोक लगेगा।
- ट. आयात, विशेषतः एफटीए देशों से, पर प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का अंतिम प्रयोग उपभोक्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ठ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण 760110 के अंतर्गत आने वाले गैर अलॉय एल्यूमिनियम और 760120 के अंतर्गत आने वाले अलॉय एल्यूमिनियम दोनों प्रकार का अनरॉट एल्यूमिनियम निर्मित करने वाले घरेलू उद्योग को समान अवसर क्षेत्र प्रदान करेगा। यह न सिर्फ घरेलू उद्योग बल्कि अंतिम प्रयोग उपभोक्ता के बहुत हितों की रक्षा भी करेगा।

### आ. डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्रीऑफ कॉमर्स, थाइलैंड

- क. आयात की मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, सकारात्मक ढंग से घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो रही है एवं घरेलू इवेंट्री घट रही है।
- ख. पीयूसी में उत्पादों की एक रेंज शामिल है जो रक्षोपाय उपायों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- ग. वस्तुपरक साक्ष्य का आधार, संबंधित उत्पाद के वर्धित आयात और गंभीर क्षति अथवा उसके होने की संभावना के मध्य कॉजल लिंक का अस्तित्व संदिग्ध है।
- घ. हालांकि घरेलू उद्योग घरेलू हानि का सामना कर रहे हैं फिर भी वे अपनी क्षमता, रोजगार स्तर में वृद्धि कर पाए हैं और अपने वेतनों में भारी वृद्धि कर पाए हैं। यह विवादास्पद है कि घरेलू उद्योग को हुई ऐसी हानि वर्धित आयात अथवा घरेलू उद्योग की अक्षमताओं अथवा अन्य कारकों के कारण हुई है।

### इ. मै. जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड

- क. याचिकाकर्ताओं के एसईजेड यूनिट को एक घरेलू उद्योग ठहराने के स्पष्टीकरण के बावजूद, वास्तव में एसईजेड प्रमुखतः निर्यात के लिए घरेलू क्षेत्र में स्थित एक यूनिट है। लगभग सभी विक्री निर्यात बाजार के लिए है और माल घरेलू बाजार के लिए नहीं बना है। तथापि, यदि माल घरेलू एरिया में बेचा जाता है तो लागू कर एवं ड्यूटियां चुकानी पड़ेंगी। नीति में यह प्रावधान एसईजेड को कुछ मात्रा, जो कि निर्यात नहीं की जा सकती, घरेलू एरिया में बेचने की अनुमति देने के लिए शामिल किया गया है।
- ख. क्योंकि एसईजेड घरेलू एरिया में विद्यमान प्रतिस्पर्धा से प्रभावित नहीं है, क्षमता उपयोग का परिकलन करते समय एसईजेड की संस्थापित क्षमता, उत्पादन एवं विक्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ग. वेदांता का एसईजेड संयंत्र पावर एवं एल्यूमिना मुद्दों के कारण पूर्णतः परिचालित नहीं है। क्षमता उपयोग कम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से कुल संस्थापित क्षमता में इस संयंत्र की 1.25 मीलियन टन की क्षमता को लिया जा रहा है।
- घ. मै. वेदांता ने लाभ, छूटों और उनको यूनिट की स्थापना के लिए प्रदान प्रोत्साहनों के बल पर एसईजेड यूनिट स्थापित की है। यदि एसईजेड को घरेलू यूनिट माना जाता है तो प्रदान किए गए लाभों का उनके द्वारा अभ्यर्पण किया जाना चाहिए।
- ड. पीयूसी की परिभाषा काफी बड़ी है और कुछ उत्पाद तो महत्वपूर्ण मात्रा में आयात भी नहीं किए जाते हैं। पीयूसी की परिभाषा में सिलियों, विलेट्स, वायर रॉड्स, वायर वार्स आदि के रूप में गैर अलॉय एल्यूमिनियम और अलॉय एल्यूमिनियम दोनों आते हैं। ये सभी उत्पाद परस्पर विनिमेय नहीं हैं और अलग हैं। इनमें से कुछ जैसे वायर रॉड्स तो आयात भी नहीं किए जाते हैं।
- च. याचिकाकर्ताओं ने पहले 'अध्याय 7601 के अधीन अनरॉट एल्यूमिनियम' को कवर करते हुए आवेदन दिया था, परंतु अधिसूचित करते समय महानिदेशक ने यह उचित पाया कि इसके साथ गैर अलॉय एल्यूमिनियम और अलॉय एल्यूमिनियम को भी जोड़ दिया जाए। यह साफ नहीं है कि महानिदेशक ने अपने आप पीयूसी के स्कोप को क्यों बढ़ा दिया।
- छ. गैर अलॉय एल्यूमिनियम और अलॉय एल्यूमिनियम विभिन्न तकनीकी गुणों वाली दो विभिन्न व्यापक श्रेणी को कवर करते हैं और समरूप नहीं माने जा सकते हैं।

- ज. सिर्फ दो आइटमें हैं जो कि आयात की जाती हैं; अनरॉट एल्यूमिनियम (76011010) और बिलेट्स (76012020)। शीर्ष 7601 के अधीन अन्य सभी उत्पाद या तो आयात नहीं किए जाते या याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते।
- झ. अलॉय सिल्लियों का निर्माण याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता बल्कि छोटे द्वितीय उत्पादकों द्वारा स्क्रेप के प्रयोग द्वारा किया जाता है एवं रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न्यायोचित नहीं है।
- ञ. गुणवत्ता एवं ऊंची घरेलू कीमतों के कारण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अलॉय सिल्लियों का आयात किया जाता है।
- ट. जबसे जांच शुरू हुई है, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत आंकड़ों में 4-5 बार व इस हद तक परिवर्तन कर दिया है कि प्रभावित पक्ष भ्रमित हो गए हैं और यह समझने की स्थिति में नहीं है कि आंकड़ों का कौन सा समूह अंतिम है जिसके अनुसार उन्हें अपना प्रत्युत्तर दायर करना है।
- ठ. याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक सुनवाई के बाद आंकड़ों का दूसरा सैट प्रस्तुत किया है जो कि ऑन साइट सत्यापन के बाद महानिदेशक द्वारा दिए गए आंकड़ों से भी असंगत है।
- ड. न तो याचिका और न ही संशोधित डाटा और महानिदेशक की प्रारंभिक जांच वर्धित आयात और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर इसके सीधे प्रभाव के मध्य किसी लिंक को निर्णायिक रूप से स्थापित करती है।
- ढ. 2011-12 से 2015-16 से चार वर्ष की अवधि के दौरान आयात में केवल एबसोल्यूट टर्म्स में 1,89,837 एमटी की मार्जिनल वृद्धि हुई है परंतु उत्पादन के अनुसार प्रतिशत के रूप में, यह लगभग उसी स्तर पर स्थिर रही है और थोड़ी सी वृद्धि हुई है।
- ण. रक्षोपाय जांच की शुरुआत के नोटिस के अनुसार 2011-12 में आयात उत्पादन का 13% था और 2015-16 में 15% की वृद्धि हुई थी। अन्यथा भी, 4 वर्षों में 78% की वृद्धि भी भारत में समग्र बढ़ोतरी को देखते हुए बिल्कुल भयप्रद नहीं है। यह वृद्धि जो कि बिल्कुल सामान्य है और 'उछाल' अथवा 'औचक' नहीं मानी जा सकती और जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का आवश्यकता पड़े।
- त. आयात में वृद्धि क्रमिक व सुसंगत रही है जिससे आवेदकों को, यदि आवश्यकता हो तो, अपने व्यवसाय प्लान को ट्रिवक करने का पर्याप्त समय मिल गया। इस अवधि में आवेदकों का उत्पादन 76% बढ़ा और उनका निर्यात 336% बढ़ा है। आवेदकों की संस्थापित क्षमता और घरेलू बिक्री में भी 40% की बिक्री हुई है।
- थ. याचिकाकर्ताओं द्वारा 7 अक्टूबर, 16 को दिए अपने लिखित सबमिशंस के डाटा के अनुसार, आवेदकों की लाभप्रदता और आयात की मात्रा में कोई लिंक अथवा संबंध, चाहे जो भी हो, बिल्कुल नहीं है। 2013-14 में उनके लाभ में गिरावट आई जबकि 2014-15 में आयात की उसी मात्रा के साथ लाभ में 2011-12 का 10 गुना वृद्धि हुई।
- द. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्धित आयात की मात्रा का आवेदकों के लाभ पर कोई कोई प्रभाव नहीं है। अर्थिक विकास के साथ आयात में क्रमिक वृद्धि होती रही है जबकि कई कारणों जिनका आरोप आयातों पर नहीं लगाया जा सकता, से आवेदकों का लाभ घटता-बढ़ता रहा है।
- ध. वर्ष 2015-16 प्राथमिक धातु अर्थात सिल्लियों (गैर अलॉय) का आयात मात्र 1,97,394 एमटी था जिसमें से अधिकांश मात्रा उनकी निर्यात पात्रता के लिए, निर्यातक के अग्रिम लाइसेंस के अंगेस्ट आयात की गई थी। चुंकि यह निर्यातकों को भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा विशेष प्रोत्साहन है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, देश में 2,24,570 एमटी की सीमा तक अलॉय एल्यूमिनियम सिल्लियों का आयात हुआ है जिसकी आपूर्ति एफटीए देशों अर्थात् वे देश जिनका भारत सरकार के साथ मुक्त व्यापार करार है, ने की थी। अतः, देश में ओजीएल के अंगेस्ट अनरॉट एल्यूमिनियम का नगण्य प्राय आयात है और देश में धातु का कोई आयात नहीं है जिसके कारण घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े।

- प. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि वर्धित आयात के कारण गंभीर क्षति हुई है, उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है और उनको लगातार नुकसान हुआ है, आधारहीन है। इसका वास्तविक कारण सभी आवेदक कंपनियों; हिंडाल्को, वेदांता और बाल्को द्वारा किए गए भारी पूंजीगत खर्चों पर मूल्यह्रास और बढ़ा हुआ ब्याज है।
- फ. वर्ष 2015-16 के अपने वार्षिक लेखा में हिंडाल्को ने माना है कि उन्होंने अपना विस्तार प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और कोई पूंजीगत खर्च नहीं होगा। अतः, वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक लाभ कमाएंगे। इसलिए उनके रक्षोपाय शुल्क के किसी अनुरोध को मानने का कोई औचित्य नहीं है।
- ब. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित करते हुए हिंडाल्को के प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार,
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान उनका लाभ 607 करोड़ रुपये है।
  - उनके लाभ के कम होने का कारण मूल्यह्रास और क्षमता विस्तार पर किए गए वर्धित पूंजीगत खर्चों की उच्च वित्तीय लागत है।
  - वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं।
  - चूंकि वे अपने सभी विस्तार पूरे कर चुके हैं, भविष्य में उनकी वित्तीय लागत कम होगी और लाभ बढ़ेगा।
- भ. हिंडाल्को के नए मुख्य कार्यकारी ने विस्तृत प्रेस साक्षात्कार में लाभ में और वृद्धि के उद्देश्य से ऋण के भार को कम करने की हिंडाल्को की रणनीति स्पष्ट की है।
- म. हिंडाल्को ने 2014-15 की अप्रैल-जून की प्रथम तिमाही में 61 करोड़ के लाभ की तुलना में 2016 की तदनुरूपी तिमाही में 294 करोड़ का लाभ कमाकर- 382% की वृद्धि- चमकदार निष्पादन दर्शाया है। योजनानुसार उनके ऋणों में कमी के साथ आगामी तिमाही में और सुधार होगा।
- य. मै. नाल्को (जो कि याचिकाकर्ता नहीं है) ने भी अप्रैल-जून, 16 में 139.12 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है।
- कक. मूल्यह्रास के बढ़ते बोझ से, अतिरिक्त क्षमता निर्माण में बड़े पूंजीगत व्यय पर हुए वित्तीय खर्चों के कारण वर्तमान में याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता पर कुछ प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कहीं भी यह साबित नहीं किया जा सका कि बढ़ते आयात से उद्योग खतरे में हैं।
- खख. आवेदकों का 48% तक कम क्षमता उपयोग का दावा गलत है। क्योंकि, केवल अनरॉट एल्यूमीनियम का उत्पादन ही लिया गया है।
- गग. रक्षोपाय निदेशालय द्वारा ऑनसाइट दौरा किए जाने के बाद आवेदकों ने 97% क्षमता उपयोग दर्शाते हुए संशोधित डाटा प्रस्तुत किया। इस कारण, पहले प्रस्तुत डाटा की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है, इस आधार पर जाँच आरंभ की गई है।
- घघ. हिंडाल्को के एम डी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय परिणामों की घोषणा करते समय यह पुष्टि की कि हिंडाल्को अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है।
- डड. एल्यूमीनियम एक वस्तु है, इसलिए इसके मूल्य में भी किसी भी अन्य मेटल की तरह उतार चढ़ाव हो सकता है। क्योंकि, याचिकाकर्ताओं के मूल्य एल एम ई से जुड़े हुए हैं इन उतार चढ़ावों के चलते उनकी संपत्तियों में भी लगातार बदलाव होता रहता है। जब भी एल एम ई मूल्यों में मंदी आती है याचिकाकर्ता बढ़ते आयात, सामग्री डंप किए जाने आदि जैसे कमज़ोर तर्कों के आधार पर ऐसे आवेदन दायर कर देते हैं।

- चच. वर्तमान वर्ष में जनवरी से एल्यूमीनियम के मूल्य लगभग 12% तक बढ़ गए एवं याचिकाकर्ताओं के लाभ में रु. 14,500/- एम टी तक बढ़ोतरी हो गई, यद्यपि आयात जारी रहे।
- छछ. चूंकि एल एम ई मूल्यों में सुधार आया है, डी जी एस जी को इस डाउनवर्ड रुख के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए।
- जज. मांग में मंदी तथा डाऊन ट्रेंड से सेकण्डरी निर्माता भी एक समान रूप से प्रभावित हुए हैं।
- झझ. किसी भी उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित सिद्ध करना होगा:
- i) आयतों के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हो गया है।
  - ii) सस्ते आयतों के कारण घरेलू उद्योग को घाटा उठाना पड़ रहा है।
  - iii) घरेलू उद्योग को कर्मियों की संख्या घटाने पर मजबूर होना पड़ा है।
  - iv) आयात में भरी बढ़ोतरी हुई, घरेलू उद्योग को इसके कारण क्षति पहुँची है।
  - (v) माल सूची बढ़ गई है क्योंकि घरेलू उद्योग बेचने में असफल हो रहे हैं।
- जज. निम्न महत्वपूर्ण संकेतों में से कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सका कि इस मामले में किसी उद्योग को क्षति पहुँची है और
- i) घरेलू उद्योग अपनी लगभग 100% क्षमता से चल रहे हैं।
  - ii) घरेलू उद्योग लाभ कमा रहे हैं परंतु लाभ में कमी आई है। उनके लाभ ऊँचे ब्याज तथा उनके बड़े पूंजीगत व्ययों में आए मूल्यहास के कारण कम हुए हैं न कि आयतों के कारण।
  - iii) 2011-12 व 2015-16 में घरेलू उद्योग के कार्मिकों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा वेतन में 100% की वृद्धि हो गई।
  - iv) आयतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। आयतों में काफी कुछ निरंतरता बनी रही तथा इस अवधि के दौरान जो कुछ भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई वह सामान्य तथा आर्थिक बढ़ोतरी के अनुरूप ही थी।
  - V) डी जी एस जी के दिनांक 19/04/2014 के नोटिस के अनुसार, 2015-2016 में 2011-12 की तुलना में इन अवधियों में उत्पादन तथा विक्री में सराहनीय वृद्धि होने पर भी माल सूची में कमी आई। इससे यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता अपनी पूरी मात्रा की विक्री करने में सक्षम रहे तथा कोई क्षति नहीं हुई।
- टट. ऐसे उद्योग जो कर्मियों की छटनी, अनुप्रयोगी क्षमताओं, लाभों में असमान्य गिरावट का कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं को आशंका के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है और आम जनता की कीमत पर अतिरिक्त लाभ जमा करने के लिए रक्षोपाय शुल्क या कोई अन्य शुल्क का अतिरिक्त संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
- ठठ. निर्यात पात्रता के लिए अधिकतर आयात अग्रिम लाइसेन्स के आधार पर आयात किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा अधिकतर एफ टी ए देशों से आयात की गई है। डी जी एस जी डाटा का सत्यापन कर सकता है तथा यदि उसे आवश्यक प्रतीत होता है तो एफ टी ए देशों से आयात को रोका जा सकता है।
- डड. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह पूरे सेकण्डरी निर्माण उद्योग जो डाउनस्ट्रीम एल्यूमीनियम उत्पादों को बनाने में लगा है को गंभीर क्षति पहुँचाएगा तथा इसके कारण वे बद भी हो जाएंगे।

ठ. विभिन्न एल्यूमीनियम उत्पादों के सेकेण्डरी निर्माता एम प्राईमरी उत्पादकों से ऊचे मूल्यों पर कञ्चा माल खरीदे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए उन्हें प्राईमरी उत्पादकों से स्पर्धा करनी होगी क्योंकि ये भी बड़े पैमाने पर इन्हीं उत्पादों के निर्माण में लगे हैं।

ण. अतः प्राईमरी उत्पादकों के हाथ में यह दुधारी तलवार के समान होगा, एक ओर तो कञ्चे माल की विक्री से लाभ कमाना तथा दूसरी ओर डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर एकाधिकार जमाने के लिए छोटे तथा मध्यम उद्योगों पर अपनी यूनिटें बंद किए जाने का दबाव बनाना।

### ई. एल्यूमीनियम सेकेण्डरी निर्माता एसोसिएशन

क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका पूरी तरह आधारहीन तथा तथ्यों से परे है।

ख. जहां तक क्षति का संबंध है, निम्नलिखित स्थितियों में यह हो सकती है:

- i) यदि आयतों के कारण उद्योग हानि में चल रहे हों।
- ii) यदि जहां स्थापित क्षमता का कम उपयोग हो रहा हो।
- iii) यदि जहां कर्मियों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों को नौकरी से हटाया गया हो।
- iv) यदि जहां बड़े पैमाने पर आयात हुए हों।

ग. बिना किसी संदेह के यह मिठ्ठ हो गया है कि उपर्युक्त वर्णित कोई भी स्थिति आवेदकों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वे बहुत अच्छे लाभ कमा रहे हैं। वे हिंडाल्को के 2016-17 कि पहली तिमाही के अन अंकेक्षित परिणाम, 2015-2016 के लिए वेदांता (बाल्को सहित) के अंकेक्षित परिणामों की प्रतियाँ संलग्न कर रहे हैं।

घ. यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-2016 में उनके लाभ प्रतिशत पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। परंतु पूर्णतया यह व्याज में वृद्धि, अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु प्राप्त बड़े पूंजीगत व्यय पर मूल्यहास अथवा और कुछ विशेष खर्चों के समायोजन के कारण है।

ङ. आवेदकों द्वारा 48% क्षमता उपयोग का दावा पूरी तरह गलत है, क्योंकि सभी आवेदक अपने संयंत्र पूरी क्षमता से चला रहे हैं।

च. चैप्टर 7601 में सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त आवेदक कई अन्य उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रूशन, रोल्ड उत्पाद, फोइल आदि। इस कारण से स्थापित क्षमता को स्मेलटेड हॉट एल्यूमीनियम जिसे आवेदकों के निर्णय पर किसी भी अन्य उत्पाद में बदला जा सकता है के संदर्भ में गिना जाना चाहिए।

छ. जैसा कि रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा सत्यापित किया है इन कंपनियों की हॉट मेटल की संयुक्त स्थापित क्षमता 20,39,569 एम टी प्रति वर्ष है; जबकि, उपर्युक्त स्थापित क्षमता के मुकाबले वर्ष 2015-2016 में उत्पादन 19,84,765 एम टी था अर्थात् स्थापित क्षमता से 97% अधिक।

ज. 2011-12 तथा 2015-16 के मध्य घरेलू उद्योग के कार्मिकों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई तथा वेतन 100% से अधिक बढ़ा।

झ. घरेलू उद्योगों की मानवशक्ति की लागत 100% तक बढ़ गई है। यह अपने आप में शीर्ष लाभप्रद उद्योग होने का पर्याप्त प्रमाण है।

ज. वर्ष 2011-12 से तुलना करने पर वर्ष 2015-16 में उत्पादन एवं विक्री में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी सहित इन्वेंटरी में भी इन अवधियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इससे यह साबित होता है कि याचिककर्ताओं ने अपनी पूरी मात्रा की विक्री की है तथा इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है।

- ट. इसलिए, ऐसा उद्योग जो पर्याप्त मुनाफे की कमाई कर रहा हो जिसकी संस्थापित क्षमता 97% तक हो, जो अपनी मानवशक्ति को बढ़ाता है और अपनी इन्वेंटरी को कम करता है उसे अनुचित संरक्षण पाने का कोई हक नहीं है और उनके रक्षोपाय शुल्क संबंधी आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।
- ठ. अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर अर्थात्- एल.एम.ई + प्रीमियम पर आवेदनकर्ता पहले हीं लगभग 8.2 लाख एम.टी प्राइमरी अल्युमिनियम का निर्यात कर रहे हैं जबकि घरेलू बाज़ार में पूरी आपूर्ति लगभग 12 लाख एम.टी की सीमा तक वे 13% देय प्रीमियम ; 8.25% सीमा शुल्क एवं आयात के लिए लागू निकासी एवं अग्रेषण शुल्क का लाभ उठा रहे हैं।
- ड. देश में धातु का उत्तराई-लागत ; - एल.एम.ई प्राइम+ प्रीमियम सीमा शुल्क+ उपकर+ निकासी एवं अग्रेषण शुल्क, इनलैंड हौलेज शुल्क आदि पर आधारित हैं। घरेलू उद्योग सदैव अपना मूल्य; घरेलू बाज़ार में आयातित धातु के अवतरण मूल्य के समतुल्य रखते हैं और 13% की अतिरिक्त कमाई वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ऊपर की करते हैं।
- ढ. घरेलू उद्योग में संरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश में प्राइमरी धातु के आयात में कोई उछाल नहीं हैं। पिछले छह वर्षों के दौरान प्राइमरी धातु का आयात कुल उत्पादन की 13% से लेकर 15% तक की सीमा के अंतर्गत हैं।
- ण. आयात में वृद्धि मार्जिनल और समग्र आर्थिक विकास के अनुरूप थी। अधिकतर आयात जो होते हैं वो एडवांस अथोराईजेशन स्कीम की तुलना में निर्यात की हकदारी के रूप में निरंतर होते हैं और घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, एलॉय इनगौट्स की कुछ मात्रा का आयात निकटस्थ एफ.टी.ए. देशों से किया जाता है।
- त. अलॉय इनगौट्स का आयात से घरेलू देशों को कोई नुकसान नहीं होता है चूँकि घरेलू उद्योग इसका विनिर्माण नहीं करता है क्योंकि इसके लिए कद्दा माल स्कैप है। आयात की इन दोनों श्रेणियों में रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं है और घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं करते हैं।
- थ. घरेलू उद्योग बढ़ते आयात और उनके लाभ के साथ कोई लिंक कायम नहीं कर सका है। आयात में यद्यपि नाममात्र की वृद्धि हुई है परन्तु इनके उत्पादन का प्रतिशत समान रहा है जबकि घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 के दौरान उत्तार-चंदाव हुआ है।
- द. आवेदन भरने का प्रयोजन, बेचे गए अल्युमिनियम का घरेलू बाज़ार में मूल्य बढ़ाकर अपेक्षाकृत और अधिक लाभ कमाना है।
- ध. घरेलू कीमतों को बढ़ाने से आयात नहीं रुकेगा क्योंकि घरेलू कीमतें, आयातित अल्युमिनियम की लागत से जुड़ीं हैं। रक्षोपाय शुल्क आयातित अल्युमिनियम की लागत को बढ़ाएगा।
- न. वे रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाने के लिए अनुरोध करते हैं क्योंकि ऐसा करना द्वितीय विनिर्माणकर्ताओं को भागी नुकसान देगा और यह ड्यूटी इन्वर्टेड-स्ट्रक्चर को उत्पन्न करेगा। रक्षोपाय शुल्क के कारण कद्दा माल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और द्वितीय उत्पाद अपेक्षाकृत और सस्ते होंगे।
- प. विभिन्न प्रकार के अल्युमिनियम उत्पाद के सभी द्वितीय विनिर्माणकर्ताओं को जहां एक ओर, इन प्राथमिक उत्पादकों से अपने कद्दा माल की खरीदारी उच्चतर मूल्य पर करने को बाध्य होना होगा और वहीं दूसरी ओर, उन्हें उनके साथ (प्राथमिक उत्पादकों) के साथ डाउनस्ट्रीम अल्युमिनियम उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा करना होगा क्योंकि वे डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विनिर्माण से भी जुड़े हुए हैं।
- फ. यह उस समय होगा जब छोटे डाउनस्ट्रीम निर्माता पहले ही स्थिर मांग, निर्यात में गिरावट एवं वर्धित हानियों की चपेट में हैं।

ब. चीन की सरकार द्वारा 13% नियंत्रित सब्सिडी के कारण चीन से एल्यूमिनियम द्वितीयक वस्तुओं के बड़े स्तर पर आयात के कारण बहुत ही छोटी एवं मध्यम कम्पनियां बंद होने के कगार पर हैं एवं रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उनकी स्थिति को और अधिक खराब कर देगा।

#### ड. मै. एल्यूमिनियम बहरीन बी.एस.सी

क. पीआईजी आयरन मैन्युफैक्चरर्स बनाम नामित प्राधिकारी 2000(116) ई.एल.टी.67 (ट्रिब्यूनल) के मामले में सेस्टेट के निर्णय के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि कथित उत्पाद के संबंध में उत्पाद के कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि वे घरेलू मर्चेंट बाजार में ऐसा उत्पाद नहीं बेचते एवं इसलिए कथित उत्पाद के आयात की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। इसी प्रकार एक ईओयू या एसईजेड यूनिट, जो मूल रूप से नियंत्रित बाजार में बेचती है एवं डीटीए में प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।

ख. आवेदकों ने उन विभिन्न परिवर्तनों को सिद्ध करने की कोशिश की है जो घरेलू उद्योग से संबंधित आंकड़ों में किए गए हैं। अपने लिखित निवेदन दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के जरिए इस मुद्दे पर नियंत्रितकों ने विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए हैं। नियंत्रितकों ने आगे प्रस्तुत किया है कि:-

- i. कतिपय पैरामीटर के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में परिवर्तन के लिए क्षमता में परिवर्तन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उत्पाद के उत्पादन, विक्री, लाभ/हानि एवं स्टॉक आंकड़ों जो कि विचाराधीन उत्पाद के पार्ट नहीं हैं, पर विचार नहीं किया जा सकता था।
- ii. आवेदकों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुत किए गए संशोधित आंकड़े द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट के विपरित हैं। द्वितीय सत्यापन रिपोर्ट एवं सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुत संशोधित आंकड़ों में केवल क्षमता उपयोग डाटा समान है और जो कि एकमात्र मापदंड है जिसे आवेदकों द्वारा स्पष्ट किया गया था। अन्य सभी मापदंडों के छोटे परिवर्तन के रूप में होने का दावा किया गया है।

ग. यह स्पष्ट नहीं है कि महानिदेशक रक्षोपाय ने पहले ही कब औंन साइट सत्यापन किया एवं बाद में सत्यापन रिपोर्ट जारी की, जांच की पूरी अवधि के आंकड़े इतने बड़े रूप में कैसे बदल गए।

घ. नियंत्रितकों ने कहा है कि घरेलू उत्पादकों से संबंधित किन आंकड़ों पर अपनी प्रस्तुति देने हेतु विश्वास करना चाहिए जो कि प्राकृतिक न्याय के स्थापित एवं मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।

ड. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में अपेक्षा है कि पक्ष, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, को ऐसे पक्षों के विरुद्ध सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए एवं उसे ऐसे साक्ष्यों की काट करने का मौका दिया जाना चाहिए। विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने की आवेदकों की अक्षमता के कारण नियंत्रितकों को साक्ष्यों की काट करने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

च. अपने लिखित निवेदन के माध्यम से नियंत्रितकों द्वारा प्रस्तुत की गई क्षति सूचना एवं समायोजन योजनापर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।

छ. किसी ईओयू अथवा एसईजेड यूनिट के घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है एवं तदनुसार एसईजेड यूनिट से संबंधित आंकड़ों को महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा स्वीकृत कर देना चाहिए।

ज. यह सिद्ध करने हेतु कि आयात में वृद्धि औचक, हालिया एवं तेज है, आवेदकों ने मूल वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि अर्थात् 2015-15 में हुए आयात की तुलना करते हुए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की शुरु से अंत तक तुलना की है।

- झ. आवेदकों द्वारा किए गए एंड टू एंड विश्लेषण विश्व व्यापार संगठन के असंगत हैं। एंड टू एंड तुलना को मुद्रे पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा अर्जेंटीना-सेफगार्ड मेजर्स ऑन दि इम्पोर्ट ऑफ फुटवेयर (अर्जेंटीना -फुटवेयर) में चर्चा की गई थी एवं अपनी पैनल रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 1999-डब्ल्यूटी/डीएस121/आर के साथ-साथ उनकी अपीलीय बॉडी ने 14 दिसम्बर, 1999 - डब्ल्यूटी/डीएस121/एवी/आर में कहा है कि आयात में वृद्धि से संबंधित विश्लेषण और प्वाइंट, अर्थात् जांच की अवधि एवं मूल वर्ष, की तुलना के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि आवश्यक रूप से चीन की अवधि शामिल होनी चाहिए।
- ज. आवेदकों को अपने दावे को साबित करने के लिए पहले के वर्ष (मी.टन) को मूल वर्ष (मी.टन) के रूप में गलत रिपोर्ट किया गया है।
- ट. 2011-12 से 2012-13 तक आयात में वृद्धि 27% थी एवं 2014-15 से जांच की अवधि तक आयात में वृद्धि 25.8% थी जो साबित करती है कि आयात में वृद्धि अचानक या हालिया घटना नहीं थी। इस प्रकार यदि आवेदकों के आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो भी आयात में वृद्धि के अचानक, हालिया होने के साक्ष्य नहीं है। तदनुसार, जांच को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- ठ. जबकि आवेदकों ने तर्क दिया है कि पूरे विश्व में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है, परंतु आवेदकों ने इसे साबित करने हेतु कोई आंकड़ा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि आवेदकों ने तर्क दिया है कि चीन में अत्यधिक क्षमता है। चीन में आरोपित अत्यधिक क्षमता के संबंध में भारत में अनरॉट एल्यूमिनियम की गैर अलॉय सिलिंयों के आयात से संबंधित पिछली रक्षोपाय जांच में जांच शुरू करने के नोटिस संख्या डी-22011/17/2009 दिनांक 22 मई, 2009 में निम्नानुसार कहा है:-
- “82.3 चीन से आयात में वृद्धि से संबंध में, डीआईने कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं एवं इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं है”
- यह नोत किया जाए कि चीन से संबंधित पिछली जांच में बिल्कुल यही तर्क दिए थे एवं तब महानिदेशक, रक्षोपाय ने कहा था कि “अनपेक्षित घटनाओं” पर कोई मामला आवेदकों द्वारा पूरा नहीं किया गया था।
- ड. मध्य-पूर्व से संबंधित “अनपेक्षित घटना” के दावे के संबंध में 2014 में जांच में महानिदेशक, रक्षोपाय ने निम्नानुसार कहा था:-
- “82.1 मध्य-पूर्व में क्षमता के विस्तार को स्वभावतः अनपेक्षित नहीं माना जा सकता क्योंकि क्षमता में विस्तार कोई रातोंरात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस स्तर तक क्षमता के विस्तारण में काफी समय लगता है। ऐसे विस्तारण जीएटीटी के अधीन भारत की बाध्यताओं से उत्पन्न होने वाले परिणाम के रूप में नहीं है और और इसलिए मध्य-पूर्वमें क्षमता में वृद्धि को अनपेक्षित घटना के रूप में नहीं माना जा सकता।
- 82.2 सस्ती बिजली लागत एवं भारत को निर्याता में कम भाड़ा लागत के दावे के अलावा इसके बारे में कुछ भी अनपेक्षित नहीं है। यह सामान्य ज्ञान है कि उनके ऑयल/गैस भंडारों के कारण मध्य-पूर्व देशों के पास बिजली उत्पादन में लागत लाभ है एवं भारत से अपनी निकटता के कारण उनके पास भाड़ा लागत का लाभ है।“
- ढ. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि क्षमता में थोड़ा सा विस्तारण अथवा सस्ती बिजली को जीएटीटी के अनुच्छेद XIX के अर्थों के अंदर अनपेक्षित घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता।
- ण. स्पष्ट करने के लिए निर्यातकों ने तर्क नहीं दिया है कि एक अनपेक्षित घटना होने हेतु आरोपित अनपेक्षित घटना से संबंधित देश से आयात बढ़ना चाहिए। बल्कि आवेदकों ने यह विचार करते हुए कहा है कि चीन में पीयूसी की अत्यधिक क्षमता है तो कोई कारण नहीं है कि चीन से आयात “डे मिनिमस” से नीचे होगा।

आवेदकों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्यों चीन से आयात “डे मिनिमस” से नीचे है जबकि उन्होंने दावा किया है कि चीन में अत्यधिक क्षमता है। आगे यह अनपेक्षित घटना के संबंध में आवेदकों के दावों के विपरीत है।

- त. निर्यातकों ने कहा है कि आवेदक बिना किसी वैधानिक आधार के अनपेक्षित घटना से संबंधित आधारहीन प्रकथन की कोशिश कर रहे हैं।
- थ. निर्यातक प्रस्तुत करता है कि “गम्भीर क्षति” एक बहुत उच्च सीमा है जिसको पाने की आवश्यकता है और उपरोक्त को यूएस-लेब में अपने अपीलीय निकाय में डब्लू.टी.ओ. द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें “गम्भीर क्षति को क्षति के एक उच्च मानदण्ड के रूप में वर्णित किया गया है। अतः मात्र वितरण संबंधी आंकड़े प्रदर्शित करना किसी भी तरह यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ता” ने सार्थक सम्पूर्ण क्षति सही है। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंकड़े सही हैं तो यह प्रदर्शित करेगा कि कोई क्षति नहीं हुई है, गम्भीर क्षति को छोड़ दिया जाए।
- द. तालिका उत्पादन घरेलू विक्रय और घरेलू विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। घरेलू उद्योग का उत्पादन पी ओ आदि पर 52% तक वृद्धि हुई है, घरेलू विक्रय 32% तक वृद्धि हुई है और इस प्रकार जॉच अवधि पर घरेलू विक्रय की वृद्धि हुई है।

#### याचिकाकर्ता की क्षति का मापदण्ड

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उत्पाद- सूचकांक	100	107	116	150	158
घरेलू विक्रय (एमटी) सूचकांक	100	114	97	97	135
घरेलू विक्रय (मूल्य)	100	118	102	115	132

स्रोत: जन सुनवाई पश्चात संशोधित आंकड़े (एस ई जेड के अलावा )

- ध. अतः निर्यातक प्रस्तुत करता है कि गम्भीर क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रकथन (प्रमाण) को पूरी तरह से उपेक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि ये गलत है और उनके द्वारा प्रयत्न किए गए आंकड़ों से टिकाया नहीं जा सकता है।
- न. याचिकाकर्ताओं ने आयात पर वृद्धि क्षमता को उपयोग करने के लिए अपनी असमर्थता को आरोपित किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि “मांग में वृद्धि” के कारण घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ा ली है। यह कथन गलत हैं क्योंकि क्षमता में वृद्धि, मांग में वृद्धि के आनुपातिक नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2013-14 में 100,780 एम टी तक अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली थी जबकि उसी वर्ष 88,251 एम टी तक मांग घटी थी। इसके अलावा याचिकर्ताओं ने जॉच अवधि के दौरान मांग से कही ज्यादा क्षमता में वृद्धि कर ली है।
- प. याचिकाकर्ताओं ने अपने द्वारा लिए गए गलत व्यवसाय निर्णयों के लिए सुविधाजनक ढंग से आयात पर दोषारोपण लगाया है जिससे अत्यधिक क्षमता में परिणाम आया है।
- फ. आगे याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनके द्वारा किये गए निर्यात एवं निर्यात में उठाई गई वित्तीय हानियों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मापदण्डों में एक के रूप में भी विचार किया जाना चाहिए। यह दावा न केवल विधि द्वारा अमान्य है बल्कि ऐसे किसी तर्क में वंचित है और कहीं ज्यादा अनोखा ( विचित्र ) है। याचिकाकर्ताओं की निर्यात निष्पादन भारत में प्रतिस्पर्धा की शर्तों के साथ जरा भी यह संबंध नहीं रखता है। निर्यातक प्रस्तुत करते हैं कि क्षति का मूल्यांकन ( निर्धारण ) करते समय निर्यात विक्रय में प्रभावित कथित क्षति को विचार नहीं किया जाना चाहिए।

- व. जांच अवधि पर निर्यात विक्रय में अत्यधिक वृद्धि स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं घरेलू बाजार में याचिकाकर्ताओं ने मूल्य कम करने में आँकड़ों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं उपलब्ध कराई है। याचिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़ों पर आधारित किसी भी मामले में यह स्पष्ट है कि आयात मूल्य पूर्णतया एल एम ई मूल्य से ज्यादा होते हैं। आगे इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि मूल्य कम करने आँकड़ों पर पहुँचने के लिए याचिकर्ताओं द्वारा कौन से आँकड़े विचार किए जाने चाहिए अर्थात् कि क्या घरेलू विक्रय मूल्य की एल एम ई मूल्य या आयात मूल्यों के साथ तुलना की गई है।
- म. निर्यातक प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ताओं के आँकड़ों पर निर्भर रहना विश्वास रखना, क्षमता उपयोग के कारण कोई क्षति नहीं है जोकि वास्तव में मूल्यांकन बिन्दु तक की वृद्धि हुई है जब इसे आधार अवधि से तुलना की गई। आगे एल ई जेड के संबंधित आँकड़े को उनके द्वारा वर्णित किए गए कारणों से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
- य. पत्र दिनांक मई 23, 2016 के जरिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त कम्पनी वार लाभप्रदता जानकारी यह साक्ष्य है कि दोनों याचिकाकर्ता जैसे – वेदान्ता और बाल्को अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं और इस प्रकार इन्हें क्षति के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है।
- कक. चूँकि दोनों याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से लाभ उठाया है, हिन्दाल्को द्वारा उठाई गई किसी भी हानि को आयात के लिए ठहराया नहीं जा सकता है। आगे, हिन्दाल्को ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 के जरिए यह वर्णित किया है कि उन्हें लाभप्रदता में उन्नत प्रवृत्ति का अनुभव हुआ।
- खख. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि गम्भीर क्षति की भी आशंका है और एल एम ई कीमत और स्टाक के संबंध में निराधार प्रकथन (प्रमाण) बनाया है जिसे आयात में हुई वृद्धि के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता है।
- (i) एल एम ई में निरंतर गिरावट है – एल एम ई कीमत उतार चढ़ाव एक वैश्विक घटनाक्रम है और एल एम ई कीमतों में कथित गिरावट को आयात की मात्रा से आरोपित नहीं किया जा सकता है जो किसी भी रक्षोपाय मापक हेतु एक पूर्वशर्त है। एल्युमिनियम की वैश्विक कीमत अधिकाशतः धातु विनिमय (एल एम ई) से प्रभावित होती है। एल एम ई के अनुसार, गम्भीर रूप से धरती बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू उद्योग सहित कीमतों ने प्रतिकूल रूप से सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है।
- (ii) संचित सामान सूची : संचित सामान सूची के संबंध में याहि चकाकर्ताओं का अनुरोध पूर्णतया अशुद्ध है क्योंकि अंतिम स्टॉक 5708 एमटी से 891 एमटी तक घटा है जो यह सिद्ध करता है कि याहि चकाकर्ताओं जांच अवधि के दौरान न केवल विक्रय करने में सफलतापूर्वक समर्थ रहे बल्कि वर्ष 2014-15 के दौरान सामान सूची स्टॉक में भी समर्थ रहे।
- गग. दिनांक सितम्बर 7, 2016 के अपने लिखित निवेदन के जरिए निर्यातक ने विभिन्न गैर आरोपणीय कारक प्रस्तुत किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। अतः अन्य गैर आरोपणीय कारकों के अस्तित्व (मौजूदगी) के कारण जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, घरेलू उद्योग द्वारा पीड़ित क्षति हेतु एकमात्र कारण होने पर वृद्धि आयात की आवश्यकता नहीं बन सकती है। डी जी एस जी को अनियमित कड़ी की अस्तिवहीन के कारण जांच को समाप्त कर देना चाहिए।
- घघ. वित्तीय वर्ष 2014-15 आयात आधार वर्ष से पर सूचकाक बिन्दु वृद्धि हुई और उसी समयावधि में, याचिकाकर्ताओं के लाभ में वर्ष से 54 सूचकाक बिन्दु तक वृद्धि हुई। भारत में आयात में सुसंगत रूप से वृद्धि हुई है जबकि याचिकाकर्ताओं के लाभ में उन कारणों में उतार चढ़ाव हुए जिसके लिए आयात को आरोपित नहीं किया जा सकता है।

- डड. वर्ष 2015-16 के अतिरिक्त रूप में आयात पिछले वर्ष से 24 सूचकाक विन्दु तक बढ़े जबकि याचिकाकर्ताओं के लाभ 177 सूचकाक विन्दु तक घटे। याचिकाकर्ताओं के लाभ में ऐसी तीव्र कमी का कारण आयात में थोड़ी सी वृद्धि को नहीं माना जा सकता है।
- चच. याचिकाकर्ताओं ने एक भी मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया है कि कैसे लागत द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा आगे, क्षमताका मात्र विस्तार घरेलू उद्योग की अदक्षता को नहीं कर सकता है।
- छछ. याचिकाकर्ता कुछ सुस्पष्ट एवं तीव्र लालसा के अपेक्षा कोई व्यवहार्य समायोजक योजना प्रस्तुत करने में असफल हुए हैं।
- ऊ. ऐसर्स वेदान्ता लिमिटेड एल्युमिनियम एवं पॉवर; भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग )
- क. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मापदंडों की पहचान अनपेक्षित घटना के रूप में की है और कहा है कि ये रक्षोपाय करार के अर्थों में अनपेक्षित घटना का निर्माण करते हैं:
- (1) मध्य पूर्वी देशों की क्षमता बढ़ना
  - (2) चीनी उत्पाद जो की निर्यात होना प्रारम्भ हो गए हैं
  - (3) सस्ती उर्जा लागत
  - (4) मध्य पूर्व देशों से समुद्री भाड़े में गिरावट
  - (5) प्राथमिक एल्युमिनियम पर निर्यात कर तथा चीन से मूल्यवर्धित उत्पादों पर कर छूट
  - (6) चीन द्वारा भण्डार बढ़ाना
- ख. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि एफ टी ए रियायत पर अप्रत्याशित विकास संस्थापित करता है, जूँकि ऐसी आशा ही किया जा सकता कि एफ टी ए रियायत के परिणामस्वरूप (क ) नवीन उत्पादन विनिर्माण सुविधाएं स्थापित होगी (ख) निर्यातक कम कीमत पर विक्रय प्रारम्भ करेंगे। अन्य सदस्य राष्ट्रों को भारत में उत्पाद को बेचने की अनुमति प्रदान करने के सरकार द्वारा एफ टी ए रियायतें दी गई हैं, तथापि यह अपेक्षा की जाती है कि उसे कम कीमत पर नहीं बेचा जायेगा।
- ग. डब्ल्यू टी ओ को स्वीकारते समय, भारत को यह पूर्वानुमान नहीं था कि यह सदस्य राष्ट्रों को रियायत प्रदान करेगा और एवं उपरोक्त भारत में आयात को कम कीमत की ओर ले जाएगा।
- घ. डब्ल्यू टी ओ को स्वीकारते समय, भारत को यह पूर्वानुमान नहीं था कि एल एम ई जिस मात्रा में गिरा है उतना गिरेगा।
- ङ. महानिदेशक ने जांच प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया है।
- च. इच्छुक पार्टियों वास्तव में जॉच में भाग ले रही है और अपनी इच्छा तक अपने हितों के प्रति रक्षा की है। डी जी ने सुसंगत जानकारी दाखिल करने के लिए इच्छुक पार्टियों को न केवल अवसर प्रदान किए हैं बल्कि डी जी ने अपने रूचियों की प्रतिरक्षा करने के लिए इच्छुक पार्टियों को मौखिक रूप से अवसर प्रदान किए हैं।
- छ. प्रश्नावली उन कम्पनियों के संबंध में है जो कि याचिका का हिस्सा नहीं हैं। बहरहाल याचिका के हिस्से वाली कंपनियों ने समस्त जानकारी महानिदेशक को पहले ही प्रदान कर दी है। यह घरेलू उत्पादकों के लिए प्रोफार्मा ओर आवेदन प्रोफार्मा के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है।
- ज. नामोदिष्ट प्राधिकारी ने समस्त इच्छुक पार्टियों को अवसर प्रदान किए हैं और जॉच न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से ढंग से की गई है। यह कहने का कोई कानूनी और तथ्यपूर्ण ( तथ्यात्मक ) अन्यायपूर्ण और पक्षपाती रहा है।
- झ. डीजी ने स्थल सत्यापन संचालित किया है और उसके बाद सत्यापन रिपोर्ट जारी की यह सत्यापन रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई जानकारी का स्थान लेता है, आगे याचिकाकर्ताओं ने सविस्तार लिखित अनुरोध किया है, जिसकी प्रति अन्य इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध करायी गई है।

- ज. राष्ट्रवार आयात के ब्यौरे याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही उपलब्ध कराया गया है। आगे याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीआई एवं प्रकाशित आंकड़े अंगीकृत किए हैं जो कि पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं और सभी इच्छुक पार्टियों की उन तक पहुँच है।
- ट. घरेलू उद्योग के लिए दावित क्षति अतिरिक्त लागत क्षमताओं में वृद्धि के कारण अथवा क्षमताओं के संभावित वृद्धि के कारण अतिरिक्त लागत में वृद्धि नहीं है।
- ठ. डीजी ने अपने सत्यापन रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा है कि यह आंकड़े 2015-16 तक के हैं।
- ड. यह तथ्य कि नाल्को ने याचिका का समर्थन नहीं किया है पूर्णतः अमूर्त (असार) है जबकि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पाद में मुख्य हिस्सा बनाता है।
- ढ. चूंकि केवल पी यू सी के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न उत्पाद संरचना आकार व बनावट में भिन्न होते हैं, तो उन पर यह समाविष्ट नहीं होता है कि परिणामी उत्पाद भिन्न है।
- ण. मात्र यह तथ्य कि सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अधीन सम्बद्ध उत्पादों की श्रेणियों का उल्लेख भिन्न है, का अर्थ यह नहीं है कि विभिन्न श्रेणियां विभिन्न वस्तुएं हैं। इच्छुक पार्टियों के तर्क तथा उन पर डी आई के प्रत्युत्तर इस प्रकार है:
- त. उपशीर्षक 7601 रु. के अंतर्गत आने वाले अलाँय एल्युमिनियम को पीयूसी के दायरे में सम्मिलित नहीं करना चाहिए और इसे गैर अलाँय एल्युमिनियम से संबंधित जो कि 76011 के उपाशीर्षक में प्रविकसित कर देना चाहिए: याचिकाकर्ता कड़ी आपत्ति करता है। प्रथम याचिकाकर्ता पी यू पी के लिए समान को प्रत्यक्ष तरीके में प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु प्रस्तुत करता है। स्थल सत्यापन के समय उपलब्ध विस्तृत जानकारीका जिक्र है और उस पर निर्भर है आगे, याचिका का समर्थन उन उत्पादों द्वारा किया गया है जो कि उपशीर्षक 760120 के अंतर्गत आने वाली अनन्य रूप में उत्पादों का विक्रय और उत्पादन करे रहे हैं।
- थ. पी टी एच 7601 स्वयं में उत्पादों का विस्तृत क्षेत्र है। उत्पादों को विभिन्न विशेषताएँ हो सकती हैं जैसे विभिन्न कच्चे धातु, मूल उत्पाद गुण, उपभोग एवं मूल्य/उत्पाद न तो विनिमय है और नहीं स्थानापन्न है: याचिकाकर्ता कड़ी आपत्ति दर्ज करता है। 7601 के अंतर्गत आने वाल उत्पाद अनिवार्य रूप से अपनी संरचना आकार व बनावट में भिन्न होते हैं। उत्पाद के भिन्न आकार को ढलावदार गर्म धातु से वांछित आकार में उत्पादित किया जा सकता है। यह तथ्य मात्र कि परिणामी उत्पाद को विभिन्न विनिर्देशन प्रयोग अथवा कीमत होती है, पूर्णतः अमूर्त है। वास्तव में 7601 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त उत्पाद की कीमत आगे पीछे/उसी दिशा में परिवर्तित हुई है। यह आगे करता है कि कीमतों में अंतर केवल उत्पाद की संरचना, आकार और बनावट में भिन्न होते हैं। हालांकि समस्त उत्पाद क्षेत्र एक उत्पाद निर्मित करते हैं।
- द. यह टिप्पणी करने के लिए प्रासंगिक थी कि विनिमय योग विभिन्न उत्पाद प्रकारों को प्रयोग करने के लिए उपभोक्ताओं की असमर्थता को कभी भी पी यू पी के क्षेत्र को परिभाषित करने हेतु कसौटी नहीं समझा जाता है।
- ध. डीआई एल्युमिनियम अलाँय का उत्पादन नहीं करता है कथन तथ्यों के आधार पर गलत है। सत्यापन दस्तावेज याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित अलाँय एल्युमिनियम उत्पाद के उत्पादन और विक्रय पर स्पष्ट रूप में जानकारी प्रदान करता है।
- त. उत्पादन की कीमत रु. 99 प्रति किग्रा. में 2447 प्रति किग्रा. की सीमा में है। विकृत कीमत फैलाव दोषपूर्ण पी यू मी निर्धारण का परिणाम है: याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हो कि पार्टी द्वारा सुविचारित को कीमत फैलाव अत्यधिक है। एक एच एस कोड के लिए भी उत्पाद की कीमत बहुत अर्थपूर्ण रूप से भिन्न होती है। यदि इच्छुक पार्टियों की दलील को स्वीकार कर लिया जाता तो यह समान 8 अंकीय एच एस कोड के भीतर की उपलक्षित होगा स्पष्ट रूप से वह मामला नहीं हो सकता है 1 तथापि याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि पी यू पी के क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु कीमतों में भिन्नता कभी भी कसौटी नहीं हो सकती है। डीजी ने ऐसे उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क की अनुशंसा की है जिसमें विभिन्न उत्पाद प्रकार अर्थपूर्ण रूप में विभिन्न कीमतें वहन करते हैं। तथापि डी जी ने उनके लिए एक उत्पाद का विचार किया और सरकार ने उन उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क लगाया है।

- प. डी आई द्वारा प्रस्तुत पीयूसी की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए: याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की गई उत्पाद प्रकारों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। वास्तव में यह जानकारी उत्पाद वर्गीकरण के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। अतः डी जी के पास विभिन्न वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली विभिन्न उत्पाद प्रकार के उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में सभी संबद्ध जानकारी रिकार्ड पर है।
- फ. विशेष उत्पाद जैसे ए356 के एल्युमिनियम दिल्ली पी यू पी के क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे उत्पाद डी आई द्वारा उत्पादित और आपूर्तित नहीं की जाती है: याचिकाकर्ता दृढ़ता से इसका खंडन करते हैं। उत्पाद प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की जाती है।
- ब. पीयूसी के अंतर्गत एल्युमिनियम सिल्लियां, वायर और बिलेट्स सम्मिलित है। उत्पाद प्रक्रिया में भिन्नता के कारण वे परस्पर विनिमेय नहीं हैं और यह उन्हें एक दूसरे से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देता है: पीयूसी में ऐसे उत्पाद प्रकारों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जो कि उपभोक्ता के लिए शायद परस्पर विनिमेय हो। वास्तव में ऐसी बहुत सी जांचे की गई हैं जिनमें ऐसे विचाराधीन उत्पाद शामिल जिनमें उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त उत्पादों के विभिन्न प्रकार जो कि परस्पर विनिमेय नहीं थे, शामिल थे। वास्तव में, अधिकांश जांचों में विचाराधीन उत्पाद ऐसे रहे जो उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से विनिमेय नहीं हैं।
- भ. तीन विभिन्न उत्पादों हेतु आयातों के प्रभाव का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है: याचिकाकर्ता प्रतिवाद करता है और प्रस्तुत करता है कि बढ़ा हुआ आयात और घरेलू उद्योग को हुई गम्भीर क्षति को विचाराधीन उत्पाद हेतु सामान्यतः निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है न कि प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए अलग अलग।
- म. याचिकाकर्ता अधिक सस्ते आयात दर की मांग करता है और ऐसे मांग एल एम ई कीमत निर्माण और क्रमिक लागत वृद्धि को रोकता है: पूर्व में किए गए अनुरोध स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं कि पी यू पी आयात कीमत और एल एम ई के मध्य भिन्नता वर्षों से कम हो रहे हैं। इस प्रकार जबकि पी यू पी कीमत एल एम ई के आधार पर निर्धारित की जाती है, आयात कीमत उसी के जैसे एल एम ई कीमत का निर्माण का अनुसरण नहीं करती है जैसा कि पी ओ आई के आधार वर्ष में अनुसरण करती थी। आगे यह सिद्ध करना है कि आयात में वृद्धि निर्यातकों द्वारा अनुसरण किए जा रहे एल एम ई एवं कीमत निर्माण में मध्य अर्थपूर्ण रूप में पड़ने वाले भिन्नता के कारण हैं।
- य. विभिन्न शुल्कों प्रभारों के प्रतिरक्षित होने के बावजूद भी आवेदक विक्रय मूल्य आयातित सामानों के साथ समानता में है: यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि घरेलू उद्योग आयात कीमत का अनुसरण करती है। यह इस कारण से है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति दी है। विभिन्न शुल्क प्रभारों के विषय में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि उनकी कीमतें समस्त लागू होनेवाली सभी शुल्क और प्रभारों को दर्शाती हैं।
- कक. डी आई के लाभ को प्रभावित करने वाला हासमान प्रिमियम आधारहीन है: नीचे दर्शायी गई तालिका में एल एम ई पर मूल्य वृद्धि गिरी है। यह गिरावट वर्षों में एल एम ई कीमत में गिरावट के अतिरिक्त हैं।

माह	एलएमई यूएसडी एमटी	स्पॉट प्रीमियम
अप्रैल-14	1810	367
मई-14	1749	367
जून-14	1834	367
जुलाई-14	1945	405
अगस्त-14	2030	404
सितम्बर-14	1992	404
अक्टूबर-14	1938	410
नवम्बर-14	2054	410
दिसम्बर-14	1913	400
जनवरी-15	1808	400

फरवरी-15	1821	395
मार्च-15	1773	370
अप्रैल-15	1817	270
मई-15	1805	194
जून-15	1683	99
जुलाई-15	1638	100
अगस्त-15	1540	95
सितम्बर-15	1589	93
अक्टूबर-15	1524	88
नवम्बर-15	1466	89
दिसम्बर-15	1494	96
जनवरी-16	1479	110
फरवरी-16	1536	107
मार्च-16	1531	110
अप्रैल-16	1564	111
मई-16	1556	95
जून-16	1592	85
जुलाई-16	1630	80
अगस्त-16	1642	75
सितम्बर-16	1558	70

खग. रक्षोपाय शुल्क डाउन स्ट्रीम (केबल कंडक्टर, ट्रान्सफॉर्मर, अन्य उत्पाद समूह जिनमें प्राथमिक स्तर पर एल्यूमिनियम का प्रयोग कच्चे माल के रूप में हुआ है) उद्योग और अन्त उपभोक्ता पर विपरीत प्रभाव डालेगी। याचिकाकर्ता यह पहले ही स्वीकार कर चुका है कि रक्षोपाय शुल्क उपभोक्ताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि यह उत्पादक कारखानों के द्वारा ही होकर गुजरते हैं। चूंकि इन उत्पादकों को कारखानों के द्वारा ही होकर गुजरना पड़ता है तो वे उपभोक्ताओं के किसी भी लागत की बढ़ातरी और घटोत्तरी से गुजरेंगे अतएव प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क उन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

गग. एल्यूमिनियम के निर्यात कर में वृद्धि एवं बिना प्रीमियम के एलएमई दर पर इसकी शुल्क मुक्त आपूर्ति: विचाराधीन उत्पादन पर निर्यात कर का अधिग्रोपण इस उद्योग को खत्म कर देगा। घरेलू उद्योग अपना माल सार्वजनिक बाजारों में आयात को बढ़ाने की बजह से बेचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। निर्यात कर के लगने से घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को घरेलू बाजार या निर्यात बाजार में बेचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन बंद कर देना पड़ेगा।

घघ. एल्यूमिनियम उद्योग को एल्यूमिनियम एक नियत दर पर प्रदान करने के एल.एम.ई. के साथ करार को जो कि नीचे के स्तर के उद्योग के बेचने के नियत दर और नियत मूल्य के विपरीत अभी भी प्रदान नहीं किए गए हैं: किसी भी मामले में याचिकाकर्ता उन उपभोक्ताओं पर रक्षा शुल्क नहीं लागाने का वचन देते हैं जिनके पास नियत मूल्य का उपभोक्ताओं के साथ करारा रक्षा शुल्क की सिफारिशों के लागू होने के तिथि को लें।

- डड. रक्षा शुल्क को एच. एस. कोड 7601.20 के लिए पारित किया जाना चाहिए जैसे कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु का निचले स्तर के उत्पादन के आयातों में विशेषतः एशियन देश जो कि एफ.टी.ए. के अधीन हैं में लिप्त है: प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क उन सभी उत्पादों पर जो कि 7601 के अन्तर्गत आते हैं और यह सी.एन.आर. द्वारा दायर की गई लिखित प्रस्तुति से एकदम साफ है कि सी.एम.आर. को भी आयात के बढ़ने से काफी माल हानि का सामना करना पड़ता है।
- चच. 7601 के अन्तर्गत आने वाले अविनियम उत्पाद जैसेकि विलिट एवं एलॉय के प्रयोग एवं प्रक्रियाएं अलग होती हैं: विभिन्न उत्पादजो 7601 के अन्तर्गत आते हैं वे उत्पादकों द्वारा समकक्ष स्तर पर उत्पादन सुविधा एवं विनियम योग्य होने चाहिए।
- छछ. माल हानि की जानकारी के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने अतिशय गोपनीयता की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने केवल ऐसी जानकारी जो कि गोपनीय जानकारी की मांग की है: गोपनीयता जो कि नियमों के तहत सुरक्षित हो, कोई भी जानकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा गोपनीय रूप से नहीं मांगी जा सकती जो कि जनता के अधिकार क्षेत्र के लिए हो। जानकारी जो कि जनता के अधिकार क्षेत्र में न हो उसे उजागर नहीं किया जा सकता।
- जज. आयात में अचानक और तेज वृद्धि नहीं हुई है: डाटा में आयातों की बढ़ोतरी का स्पष्ट अंकन होता है। इसके अनुसार वर्तमान मामले में आयात में बढ़त हुई है पहले के मामलों में जहाँ सरकार द्वारा शुल्क लगाए गए हैं।
- झझ. भारत जैसे देश के लिए चार वर्ष के अंतराल में 78% आयात में बढ़त एक आम बात है। डी.आई. इस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। आयात में 15% की समांत बढ़ोतरी: इस अवधि में 74% की बढ़ोतरी आयात में हुई है, बाद में मांग 20% की दर से बढ़ी आयात 74% बढ़ा, अत एव आयात में बढ़ोतरी मांग की बढ़ोतरी से अधिक है। ऐसा देखा गया है कि घरेलू उद्योगों द्वारा निर्यात भारत में आयात के मुकाबले अधिक है, जिससे कि साफ पता चलता है कि घरेलू उद्योग देश में उत्पादन की मांग को पूरा करने में सक्षम है और देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता नहीं है।
- जज. इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों घरेलू उद्योग निर्यात को प्राथमिकता देते हैं और बढ़े घाटे उठाते हैं, घरेलू बाजार में नहीं बेचते। देश में बढ़े हुए आयातित उत्पादों को देखते हुए इन निर्यातों का एक आवश्यक कारण घरेलू उद्योगों का अपने उत्पाद को घरेलू बाजार में बेचने की अक्षमता है।
- टट. आयात को पूर्ण/असीमित शर्तों पर नहीं रोका जा सकता है क्योंकि इनमें से जयादातर अग्रिम लाइसेंस द्वारा आयातित किए जाते हैं। वास्तविक आयात की गणना तभी की जा सकती है जब कुल आयात में से अग्रिम लाइसेंस को निकाल दिया जाए: पिछले मामलों में इस मुद्दे को रक्षा प्राधिकारी द्वारा पहले ही सुलझाया जा चुका है। प्राधिकारी अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत आयात को जुदा नहीं कर सकती। नियम में यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी बढ़े हुए आयात का आंकलन छूट योजना के अन्तर्गत आए आयात को जुदा और पृथक करने के बाद किया जाएगा। आगे, महज आयात जो कि अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत आते हैं, वे रक्षा मापन के अंदर नहीं आते और वही बढ़े हुए आयातों का आंकलन करने एवं विचार करने पर भी बात लागू नहीं होती है।
- ठठ. चीन पी.आर. और मध्य पूर्व से आयातों के संबंध में प्रार्थी द्वारा दी गई गलत और भ्रामक जानकारी। उसका विवरण माँगा गया है: विभिन्न देशों से किए गए आयातों के उत्पाद का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, आगे यांचिकाकर्ताओं का दावा डी.ज.जी.आई. और एस. में मुद्रित आंकड़ों पर आधारित हैं और अत एवं घरेलू उद्योग द्वारा गलत और भ्रामक जानकारी जानकारी प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यांचिकाकर्ताओं ने यह बताया कि चीन बाजारों की स्थिति में आए बदलाव की वजह से भारत में आयात बढ़ा है। जबकि चीन पी.यू.सी. का एक बड़ा आयातक था महत्वपूर्ण और अन्य वैश्विक उत्पादों के परिणामस्परूप चीन पी.यू.सी. का निर्यातक बन गया। अतः यह वैश्विक बाजार में एवं लाभ ही है जो अन्य देशों के उत्पादकों को भारतीय बाजारों में उत्पाद की और रुख करवा रा है।

- डॉ. निचले स्तर के कारखानों को आयात करने का दबाव बनाया जाता है क्योंकि डी.आई. अग्रिम लाइसेंस के बदले में सामान/माल मुहैया कराने के अनिच्छुक होते हैं : अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत किया गया आयात किसी भी तरीके से सुरक्षा शुल्क के दायरे में नहीं आता है और इसीलिए इच्छुक दल का इससे कोई वास्ता नहीं है और उस पर सुरक्षा शुल्क को इस खाते में अदा करने के लिए मना नहीं करना चाहिए । उपभोक्ता अपनी जरूरतों के द्विसाब से अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत बिना किसी सुरक्षा शुल्क को दिए प्रयोग करना जारी रख सकता है ।
- ठृ. एल.एम.ई. पर शुल्क और कर की अदेयता आयातों को कम कर सकती है : जबकि एल.एम.ई. मूल्य पर शुल्क और करों की अदेयता आयातों को कम करने में मदद कर सकती है जो कि घरेलू उद्योगों को तेज चोट पहुंचा सकती है । घरेलू उद्योग को 2015-16 में 170 करोड़ की मिली-जुली हानि हुई थी । यदि करों और शुल्क में से बिक्री मूल्य को घटा दिया जाए तो घरेलू उद्योगों को हुई हानि बढ़कर 432 करोड़ रुपये हो जाएगी ।
- ण. याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर आयात में बढ़ोतर के दावे उसके लाभ वृद्धि और कर्मचारियों की गैर छंटनी : को समर्थित नहीं करते और पी.ओ.आई. में घरेलू उद्योगों के मुनाफे में तेजी से गिरावट आई है । अतएव इच्छुक दलों द्वारा दी गई दलीलें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में याचिकाकर्ताओं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता है अतः कर्मचारियों की छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता है ।
- तत. 'शुल्क फ्री' योजनाओं के साथ ओ.जी.एल. शुल्क फ्री योजना आयातों में गैर अलगाव निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयातों को भटकाती है जो कि शुल्क फ्री देय रास्ते में आते हैं : महानिदेशक ने पहले ही बहुत छानबीन कर ली है और शुल्क माफी और शुल्क देय से आयातों को अलग नहीं किया है । अतएव प्रस्तुत मामले में ऐसा करने का भी प्रश्न नहीं उठता है ।
- थथ. आयात की वजह से किसी भी बाजार की हानि नहीं होती है : डी.आई. को अच्छे उत्पाद निर्यातकों को आकर्षित करने के लिए शुल्क माफी योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ाने चाहिए : दी गई सारणी घरेलू उद्योग और आयातों के बाजार शेयर को दर्शाती है । यह साक्ष्य है कि घरेलू उत्पादक संपूर्ण रूप में बाजार शेयर को खोकर जो आयात से लाभ प्राप्त करते हैं वह बराबर है:

व्यौरे	यू ओ एम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
मांग में बाजार शेयर						
आयात	%	12	14	16	15	17
घरेलू उद्योग	%	42	42	40	37	39
अन्य(नाल्को)	%	16	12	10	11	7
द्वितीय उत्पादक	%	31	33	34	37	36
कुल प्राथमिक उत्पादक	%	57	53	50	49	46
कुल भारतीय उत्पादकों का	%	88	86	84	85	83

- दद. आयात के आंकड़े भ्रामक हैं, जो पहले प्रस्तुत किए गए वे कुल 7601 से संबंधित हैं । 7601.10 का आयात डाटा को जमा करने के लिए आवश्यक है, जो कि नजरअंदाज किया जा सके । नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि 760110 और 760120 आयात जुदा है । यह पाया गया है कि दोनों वर्गीकरणों में आयात महत्वपूर्ण है ।

व्यौरे	यू ओ एम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
760110 मे आयात	एम.टी.	97,596	1,60,496	1,94,104	1,56,326	1,97,394
760120 मे आयात	एम.टी.	1,44,937	1,47,783	1,54,782	1,87,101	2,24,570
कुल	एम.टी.	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964

- धध. प्रस्तुत संदर्भ में बढ़े हुए आयात के महेनजर बढ़ा हुआ निर्यात यह दर्शाता है कि प्राथमिक पी.यू.सी. का निर्यात भारतीय बाजारों में अभाव उत्पन्न करके करना चाहता है जिसके चलते द्वितीय स्तर के बाजार आहत होते हैं : प्रस्तुतियाँ पहले भी बार-बार दोहराई जा चुकी हैं। यांचिकाकर्ताओं द्वारा बढ़ाए गए निर्यात का है। यह घेरेलू उद्योगों के घेरेलू और निर्यात बाजार के लाभ की तुलना करके साफ पता लगाया जा सकता है। यांचिकाकर्ताओं उत्पाद का निर्यात नहीं करना चाहते हैं। यांचिकाकर्ताओं पर दबाव है उत्पाद को निर्यात करने का उसकी वजह है देश में उत्पादों की आयात में बढ़ोतरी।
- नन. मालहानि की छानबीन अवधि दो एफ.टी.ए. मलेशिया- भारत एफ.टी.ए. (जुलाई 2011) और एशियन-भारत एफ.टी.ए. (जनवरी 2016) से मेल खाती है : यह यांचिकाकर्ताओं का सही तर्क है। आयात में बढ़ोतरी भारत द्वारा कुछ देशों के साथ एफ.टी.ए. हस्ताक्षर करने की वजह से है। ये एफ.टी.ए. साफ तौर पर कुछ अनदेखा विकसित करते हैं जो कि तार्किक रूप से आशा नहीं क जा सकती कि एफ.टी.ए. का परिणाम कम मूल्य का आयात हो सकता है और इन एफ.टी.ए. के परिगामस्वरूप यांचिका में दिए गए व्यौरे के अनुसार मध्य पूर्व और चीप पी.आर में नई क्षमताओं की व्यवस्था की गई है। अतएव जब ये एफ.टी.ए. पर हस्ताक्षर किए गए थे यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि ये इन देशों में नई क्षमताओं की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पप. अचानक और तीव्र वृद्धि पहीं हुई है अर्जेन्टीना-फुटवियर डब्ल्यू.टी.ओ. अपीलीय निकाय रिपोर्ट (फुटवियर मामला) अचानक, तेजी से और महत्वपूर्ण आयात की विशेषताएं एवं प्रमुखताएं : भारतीय नियम और विश्व व्यापार संगठन के करार के तहत तात्कालिक अवधि में आयात की बढ़ोतरी में अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि साफ है।
- फफ. ए.ओ.एस. गैट के अनुसार, वर्तमान यांचिका आधारहीन है। यांचिका में अप्रत्यक्ष विकास और आयात के बढ़ने में तार्किक सम्बन्ध का अभाव है : संस्था की यू एस स्टील सुरक्षा और यू.एस. परिभाषित तरीकों पर रिपोर्ट के अनुसार : ए.ओ.एस. और गैट की जरूरतें पूरी तरह से वर्तमान माले से मिलती हैं। वास्तव में रूचिकर पक्षों ने स्वीकार किया है कि बढ़ा आयात एफ.टी.ए. के हस्ताक्षर के होने का प्रभाव है। अतः यह उनका अपना मामला आयात का बढ़ने का प्रभाव से अप्रत्यक्ष कारण विकसित हो रहे हैं। अब तक समझौते में सुरक्षा और अप्रत्यक्ष कारणों के विकास के प्रति प्रश्न कहे गए हैं। यांचिकाकर्ताओं ने समझौते के सम्बन्धित भाग को उपलब्धकराया है। ये देखा गया है कि समझौते के अनुसार आयात का बढ़ना आयातदरों में छूट और भारत द्वारा दी गई सहूलियतों के कारण है।

#### छूट और अन्य बाध्यताएं

सुरक्षित तरीकों को प्रभावी करने के लिए सदस्यों को पर्याप्त सतर पर प्रभावित निर्यातक सदस्यों को छूट और सहूलियतें देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, पर्याप्त तरीके का व्यापारिक मुआवजा प्रभावित निर्यात सदस्य स्वयं के सतर पर पर्याप्त बराबर छूट और अन्य सहूलियतों को निलंबित कर सकते हैं। यह बाद में सुरक्षित तरीकों को प्रभवित करने के प्रथम तीन वर्ष तक उपयोग में नहीं लाए जा सकते अगर यह तरीका पूरी तरह से

आयात के बढ़ने के कारण है अन्यथा समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है। असल में भारत ने ट्रैरिफ रियायतों का दाचित्व लिया हुआ है और इससे सीमा शुल्क कर में कमी आई है।

- बब. आयातों के खाते में डी.आई. को उत्पादन की हानि नहीं होती है, जबकि डी.आई. उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में घन का संचार करता है और उत्पाद को बेचने में भी सक्षम होता है : डी.आई. को स्पष्ट तौर पर उत्पादन की हानि का सामना करना पड़ा है आयातों में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से कम है।
- भभ. पिछले पांच वर्षों में याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी हानि दर्ज नहीं की गई है। केवल लाभ में कमी हुई है वह भी आयात की वजह से नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ए. 1 के मूल्यों में गिरने के कारण हुई है। व्यान पूर्ण रूप से गलत है। नीचे दी गई सरणी डी.आई. में हुए लाभ में दर्शाती है। यह देखा जा सकता है कि डी.आई. को निवेश के बदले में वित्तीय हानिमुद्रा हानि, और विपरित बदले का सामना करना पड़ा है: यह पी.यू.सी. में अंकित मुद्रा अवस्थीति के कारण है।

व्यौरे	शू ओ एम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लाभ/हानि	रु. लाख	100	13	-4	149	-50
नकद लाभ	रु. लाख	100	23	10	152	-31
निवेश पर लाभ	प्रतिशत	100	60	20	100	0

- मम. डी.आई. को अपने विस्तार योजना, भारी मात्रा में मूल्यमुद्रा और व्याज की दरों में कमी की वजह से काफी क्षति उठानी पड़ी है : लाभ में कमी मांग में गिरावट और व्याज की दरों में वृद्धि की वजह से नहीं है। बल्कि यदि यह स्वीकार कर लिया गया कि लाभ में कमी मांग में गिरावट और व्याज दर की वजह से है तो यह नहीं कहा जा सकता कि डी.आई. नियमों के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकारी नहीं हो सकता है। परिशिष्ट-॥ में प्रेरणार्थक सम्बन्ध की अवश्यकताओं का आशय यह नहीं निकाला जा सकता है कि प्रेरणार्थक संबंध की अनुपस्थिति गिरावट में बढ़ोतरी और व्याज की लागत के कारण है। मौजूदा याचिका सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण के लिए और पाटन-निरोधी डियूटी के लिए नहीं है।
- यय. संयुक्तराष्ट्र संघ—डेफिनिटिव सेफगार्ड मापन सर्कुलर वेल्डेड आयात पर कार्बन क्वालिटी लाइन पाइप जो कि कोरिया से, डब्ल्यू टी/डी.एस.202/ए.बी./आर, 8 मार्च, 2002 में स्वीकार किया गया डी.एस.आर.2002: IV, 1403, सुरक्षा उपाय एक असाधारण उपचार है, जिसको आपातकालीन स्थितियोंमें अपनाया जाना चाहिए: मौजूदा मामले में तथ्य, वर्तमान उद्योग में एक असाधारण स्थिति को स्थापित करते हैं। उद्योग द्वारा अपने घरेलू और निर्यात संचालन, दोनों में सही गई संयुक्त हानि लगभग 463 करोड़ रुपए से ऊपर परिवर्तित हो गई। इसको, कल्पना के किसी भी विस्तार से, असाधारण व्यापार की स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ककक. डी.आई., सुरक्षा ड्यूटी प्राप्त करने के लिए कोई विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) प्रावधान प्रस्तुत करने में असफल रहा है: मौजूदा याचिका भरतीय नियमों के तहत दी गई है, और यह याचिका विश्व व्यापार संगठनअनुबंध के अन्तर्गत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने व्यापार नोटिस को ध्यान में रखते हुए याचिका पुस्तुत की है और उन्होंने वह सभी सूचना प्रदार कर दी है, जो अपन महानिदेशक ने निर्धारित की है। किसी भी

हितधारक पक्ष की यह दलील कोई मायने नहीं रखती है कि विश्वव्यापार संगठन अनुबंध, भारतीय नियमों से भिन्न है। इस प्रकार, मौजूदा याचिका डब्ल्यू.टी.ओ. के सुरक्षा अनुबंधके अनुरूप है।

- खखख** डी.आई. द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के अनुसार, कामगारों छंटनी/ काम से हटाना संभव नहीं है। रोजगार चोट का कोई चिन्ह नहीं प्रदर्शित होता है : यह आवश्यक नहीं है कि हानिसे संबंधित सभी पैरामीटर आवश्यक रूप से हानि को प्रदर्शित करें। वास्तव में, इस विषय पर न्यायशास्त्र पूर्णतः स्पष्ट है – जब, विधि के अन्तर्गत पैरामीटर अधिक संख्या में निर्धारित किए गए हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी पैरामीटर विकृति को प्रदर्शित करें और किसी एक पैरामीटर के आधार पर हानि को स्थापित किया जाए। बल्कि इसके विपरित यह भलि, भंति ज्ञात है, कि चोट को विश्लेषण का आयोजन करना उद्योग से संबंधित सभी पैरामीटरों पर विचार करने के पश्चात आवश्यक होता है। इसके अलावा, ऐसी स्थितिमें जहां पर कुछ हानि पैरामीटरों ने कुछ सुधर प्रदर्शित किया है और कुछ पैरामीटरों की विकृति प्रदर्शित हुई है, अपर महानिदेशक द्वारा यह जांच की जानी अनिवार्य है कि कहाँ पर कुछ पैरामीटरों की विकृति, कुछ अन्य चोट पैरामीटरों के सुधार से बहुत अधिक है।
- गगग.** डी.आई.निर्यात द्वारा लाभ कमा रहा है और घरेलू उपभोक्ताओं का अपना उत्पाद नहीं बेचता है : याचिकाकर्ताओं न तथ्यप्रक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इससे स्पष्ट रूप में यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ताओंने धरेलू संचालनां की तुलना में, निर्यात में महत्वपूर्ण रूप से अधिकतर हानियां सहन की है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निर्यात, बढ़े हुए निर्यात के परिणामस्वरूप ऐ प्रकार की बाध्यता थी और वास्तवमें याचिकाकर्ताओं का कोई चयन नहीं था।
- घघघ.** प्रति कर्मचारी, उत्पादन से उत्पादकता तक प्रसारित डी.आई; के आर्थिक पैरामीटरों में सुधार हुआ था। : सन्दर्भित और भरोसेमंद लिखित प्रस्तुतियां, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप डी.आई. को गंभीरचोट पहंची है। लाभ में कमी, आर.ओ.आई., मार्केट शेयर,निर्यात में हानियों की वृद्धि,आयात में वृद्धि के कारण निर्यात में वृद्धि जैसेपैरामीटरों पर विचार करनेपर गंभीर चोट का दावा पूर्णतः स्थापित होता है। ये सभी पैरामीटर, सामूहिक और संचयी रूप से स्थापित करते हैं कि डी.आई. को गंभीररूप से चोट पहंची है।
- इइइ.** मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) की उत्पादन क्षमता की लगातार वृद्धि के पूर्वानुमान सहित 2011 में चीन की उपभेद पद्धति में कमी आने के कारण एल्यूमिनियम के संबंध में बाजार का व्यवहार भविष्य सूचक था : चीन में उपभोग की कमी और मध्यपूर्व में उत्पादन की बढ़ती हुई क्षमता, दोनों मिलकर अप्रत्यापित घटनाक्रमों का निर्माण करते हैं।
- चचच.** डी.आई. के एक भाग के रूप में विशेष आर्थिक जोन को शामिल किए जाने को चाइना पी.आर. से इलेक्ट्रिकल इंसूलेटर्स का उदाहरण देकर याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनोती प्रदान की गई : विस्तृत लिखित प्रस्तुतियां संदर्भित की गई है और उन पर भरोसा किया गया है। इंसूलेटर्स के मामले में, जहाँ तक प्राधिकर संस्था के निर्णय का संबंध है, याचिकाकर्ताओंने पहले ही अपने विस्तृत निवेदनों में यह बताया है कि किस प्रकार यह निर्णय मौजूदा मामले में, कानूनी रूप से बाध्यकारी उदाहरण नहीं बन सकता है।
- छछछ.** यू.एस. लैम्ब मामले में अपीलीय निकाय गंभीर चोट को परिभाषित करता है और गंभीर एवं आर्थिक क्षति की भिन्न-भिन्न प्रकृतियाँ स्थापित करता है : यू. एस. लैम्ब मामले में अपीलीय निकाय का निर्णय जब मौजूदा मामले में लागू किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि डी.आई को गंभीर चोट सहन करनी पड़ती है।

- जजज.** क्षति दावों को निष्प्रभावी करने के निमित डी.आई के लिए आर्थिक पैरामीटरों में वृद्धि प्रदर्शित करता है : जब कुछ अन्य पैरामीटरों में कार्य-निष्पादन गंभीर रूप से विकृत हुआ है, तो कुछ आर्थिक पैरामीटरों में वृद्धि होने का आशय यह नहीं निकाला जा सकता कि चोट नहीं है । वास्तव में घरेलू उद्योग के लिए, इन पैरामीटरों में वृद्धि होने की लाभ कुछ भी नहीं है। अन्य पैरामीटरों में डी आई का कार्य-निष्पादन आर्थिक रूप में इस प्रकार से विकृत हुआ है ।
- झझझ.** सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात प्राप्त डाटा नकारात्मकमूल्य में कमी करना प्रदर्शित करता है : मौजूदा मामले में, मूल्य में कमी करना स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। चूंकि मिश्र धातु और गैर मिश्र धातु के उत्पादों में महत्वपूर्ण अंतर है, इसलिए महानिदेशक दोनों की तुलना अलग से कर सकता है ।
- जजज.** अन्वेषण से चाइनीज अपवर्जन के कारण डी.जी.एस.जी. द्वारा घटनाक्रमों को “अप्रत्याशित नहीं” और “व्यर्थकि रूप में उल्लिखित किए जाने को चुनौती दी जाती है : चीन से कम परिणाम में आयात होने का आशय यह नहीं है कि चीन में आर्थिक स्थिति का अर्थ अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं है।
- टटट.** 2014 में, पूर्व के मामले में महानिदेशक सुरक्षा के अंतिम निष्कर्ष में, जिसके द्वारा डी.आई.को, हानि के अन्तर्गत नहीं के रूप में न्यायनिर्णित किया गया था: पहले के मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, मौजूदा मामले के तथ्य गंभीर चोट स्थापित करते हैं। वास्तव में, याचिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि 2014-15 में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वृद्धि हुई थी। महानिदेशक की टिप्पणियां 2014-15 की Q I में कार्य निष्पादनपर आधारित थी और इसलिए पूर्व मामले में, डी.पी.एस.जी. के अंतिम निष्कर्ष की टिप्पणियां और मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं के दावे पूर्णतः तर्कसंगत हैं। हालांकि 2014-15 में कार्य-निष्पादन में सुधार के पश्चात, एल.एम.ई. मूल्यों में कमी आने कारण, 2015-16 में कार्य निष्पादन में आकस्मिक कमी हुई थी।
- ठठठ.** कोई प्रेरणार्थक सम्बन्ध नहीं। डी.आई. ने मौजूदा क्षमता का इष्टतम उपयोग किए बिना ही अपनी क्षमता को बढ़ाया। इससे बढ़े हुए ब्याज भुगतान करने पड़े : प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर भरोसा किया गया है। महानिदेशक ब्याज और हास के पूर्व लाभ पर विचार कर सकता है, जिससे घरेलू उद्योग की लाभन्विता में महत्वपूर्ण विकृति प्रदर्शित होगी। इस प्रकार, तर्क निराधार है। उस स्थिति में भी जहाँ पर, डी.आई. उन क्षमताओं का विस्तार करता है, जो पूर्ण रूप में स्थापित नहीं हो पा रही है, वहाँ पर भी, डी.आई., सुरक्षा ड्यूटी संरक्षण का हकदार है। डी.आई. स्पष्ट रूप में संरक्षण का हकदार है, भले ही वह क्षमताओं की वृद्धि के लिए स्थिरीकरण की अवस्था में हैं। मामले के तथ्य यह नहीं प्रदर्शित करते हैं कि डी.आई. मौजूदा क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किए बिना ही अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा था। यह दृष्टव्य होगा कि चोट की अवधि के दौरान, ब्याज में कमी आने के पहले लाभ में महत्वपूर्ण कमी हुई है। इस प्रकार से, यह स्पष्ट है कि डी.आई लाभों में विकृति, ब्याज की लागत में वृद्धि कि कारण नहीं हुई थी। यह विकृति, एल.एम.ई. मूल्यों में महत्वपूर्ण कमी के परिणामस्वरूप, विक्रय मूल्यों में कमी आने के कारण हुई थी।
- डडड.** डी. आई. कि पास अतिरिक्त क्षमता के लिए घरेलू उपभोक्ता, संवर्ग सहन नहीं कर सकते हैं : घरेलू उद्योग के पास अतिरिक्त क्षमता हाने की स्थिति में उपभोक्ताओं द्वारा आयात करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यदि उस स्थिति में, जहाँ पर उद्योग पहलेसे ही अतिरिक्त क्षमता के कारण हानि उठा रहा है, इस स्थिति से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में वृद्धि की ओर अग्रसर होने की संभावना है और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को उच्चतर मूल्य चुकाने होंगे।
- ढढढ.** ब्याज की लागत में तीव्र वृद्धि : प्राधिकरण संस्था, घरेलू उद्योग की लाभन्वित पर, ब्याज व्ययों के पूर्व और पश्चात विचार कर सकती है। यह दृष्टव्य होगा कि लाभ में ब्याज में कमी आने के पहले ही गंभीर रूप से

कमी आई है। यह पुनः स्थापित करता है कि घरेलू उद्योग की लाभन्विता में कमी, ब्याज की लागत में वृद्धि के कारण नहीं हुई है।

णणण. डी.आई.एल.एम.ई. मूल्य का अनुसरण नहीं करती है असल में, डी आई का मूल्य एलएम ई के मूल्य से ज्यादा है। तथ्य तो यह है कि घरेलू उद्योग के विक्री मूल्य में भी इस अविधि में तेजी से गिरावट आई है। अतः घरेलू उद्योग के लाभ में भी अर्थपूर्ण रूप से गिरावट आई है।

ततत. कच्चे माल के मूल्य में कमी आने पर भी डी आई के मूल्य में कमी नहीं आई। विक्री मूल्य एवं कच्चे माल के खर्च में आए परिवर्तन का लिखित प्रमाण भी है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने अर्थपूर्ण रूप से मूल्य कम किए हैं, जो कि कच्चे माल के मूल्य की कमी से भी कम तक आ गई है।

थथथ. वेतन को 150 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया जबकि रोजगार सिर्फ 5 प्रतिशत तक ही बढ़ा। निम्नलिखित टेबल में प्रति किलो वेतन खर्च एवं घरेलू उद्योग का लाभ का आधटन दिखाता है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट को बढ़े हुए वेतन के खर्च की दर से नहीं जोड़ा जा सकता है।

विवरण	यू.ओ.एम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उत्पादन के प्रति एमटी हेतु वेतन खर्च	रु./एम टी	100	101	122	139	127
लाभ/(हानि) घरेलू	रु./एम टी	100	11	-4	154	-37
प्रतिवर्ष परिवर्तन						
उत्पादन के प्रति एमटी हेतु वेतन खर्च	रु./एम टी	100	1631	1325	-944	100
लाभ/(हानि) घरेलू	रु./एम टी	100	17	-178	215	100

ददद. बंधक उपभोग आंकड़ा जो 70% दिख रहा है उसके अन्वेषण की आवश्यकता है। सभी तथ्यपरक सूचनाओं का लिखित प्रमाण उपलब्ध है। घरेलू उद्योग को आगे की सारी सूचना उपलब्ध करानी होगी, जो भी इस मामले में प्राधिकारी को प्रासंगत या यथोचित लगे।

धधध. पूर्ण/ अर्ध-पूर्ण उत्पाद को बनाए बिन पी यू सी के आयात शुल्क को बढ़ा देने से पूरा ढाचा ही उलट हो जाएगा। लिखित प्रस्तुतीकरणों का ही सहारा लिया गया है। जैसाकि पहले भी बताया गया है कि, उपभेदका ज्यादातार प्रभाव अंतरित उद्योगों में शामिल हैं, और यह अंतरण निवेश खर्च में बन जाता है।

ननन. घरेलू प्रतिस्पर्धा- घरेलू उद्योग कुल उत्पादन के 30% से ज्यादा भाग का प्रतिनिधित्व करता है अतः याचिकाकर्ता पर घरेलू प्रतिस्पर्धा का अन्वेषण करना आवश्यक है। घरेलू उद्योग की दावा की गई हानि आयात प्रतिस्पर्धा एवं एल एम ई मूल्य में गिरावट की वजह से आयात मूल्य में गिरावट के कारण है। असल में, घरेलू उत्पादकों में प्रासंगिक अविधि के दौरान लगातार प्रतिस्पर्धा चलती ही रही है। फिर भी घरेलू उत्पादकों के बीच आपस की प्रतिस्पर्धा के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ की दर में अर्थ पूर्ण गिरावट आई है।

पपप. वर्ष 2015-16 में आयात 26% बढ़ने से उच्चतम विक्री आंकड़ों के साथ-साथ घरेलू उद्योग का उत्पादन 32% तक बढ़ गया। अतः अनियत कड़ी को तोड़ते हुए : निम्नलिखित सूची में पी यू सी का आयात, उत्पादन एवं घरेलू उद्योग का नियर्त एवं विक्री दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू बाजार में विक्री की बढ़त, उत्पाद के उत्पादन एवं मांग से कहीं कम है।

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयात एमटी	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964
उत्पादन- पीयूसी एम टी	9,97,282	10,63,882	11,53,951	15,01,542	15,99,740
घरेलू बिक्री एमटी	5,18,295	5,91,784	5,04,675	5,01,513	7,00,486
निर्यात एमटी	1,48,485	1,34,555	2,96,301	5,95,931	6,64,197

फफक. दुग्ध उत्पाद सहित फुटवियर केस एवं अमरीकीवीट ग्लूटेन- आदर्श कारण कार्य संबंधः उक्त मामले वर्तमान मामले में निकाले गए निष्कर्षों को नष्ट नहीं करता है। यह बढ़े हुए आयात ही है, जिनहोंने घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है।

बबब. बढ़े हुए आयातों के कारण कम हुए लाभ कोई संयोग नहीं है। बढ़े हुए आयात के कारण बिक्री में कमी का कोई प्रमाण नहीं है। निम्नलिखित टेबल पी यू सी का आयात एवं घरेलू उद्योग की लाभ दर दिखाता है। यह तो जाहिर ही है कि घरेलू उद्योग की लाभ दर वर्तमान अवधि में आयात के बढ़ाने के कारण अर्थपूर्ण रूप से नीचे आ गई है। आगे, याचिकाकर्ता ने भी प्रस्तुत किया है कि (a) आयात की मात्रा की तुलना घरेलू उद्योग की मात्रा एवं बाजार शेयर से की जानी चाहिए। (b) आयात का मूल्य की तुलना उद्योग के लाभ से की जानी चाहिए। निम्नलिखित टेबल पी यू सी का आयात मूल्य एवं घरेलू उद्योग की लाभ दर को दिखाता है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की लाभ दर आयात मूल्य के पीछे-पीछे ही बन गई है। अतः घरेलू उद्योग की लाभ दर में कमी का कारण आयात मूल्य ही है।

विवरण	यूओएम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयात मात्रा	एमटी	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964
लाभ/(हानि) - घरेलू	रु. एमटी	100	11	-4	154	-37
आयात मूल्य सीआईएफ	रु. एमटी	120490	123000	128420	138640	123930

भभभ. लाभ में कमी किसी समन्वय का चिह्न नहीं है बल्कि इसका कारण एल.एम.ई. मूल्य में गिरावट आई थी, अनियत कड़ी को स्थापित करता है। यदि भारतीय आयातक एल एम ई से संबंधित मूल्यों पर आयात न कर रहे होते तो घरेलू उद्योग अपने मूल्यों को एल एम ई से मिलाने के लिए बाध्य न होते। अतः यदि कोई आत मूल्य, एल एम ई के कारण गिरा है तो, वही इस अनियत कड़ी को जोड़ता है। आयात मूल्य में कमी का कारण इस अनियत कड़ी के लिए प्रासंगिक नहीं है। आयात मूल्य में कमी का कारण अप्रत्यक्षित विकास के निर्णय के लिए प्रासंगिक है। यह एल एम ई की ही गिरावट है, जो बढ़े हुए आयात के लिए जिम्मेदार है। आगे, जहाँ तक घरेलू उद्योग का सवाल है, तो एल एम ई में गिरावट बिलकुल ही अप्रत्याशित था।

ममम. घरेलू उत्पादक के बाजार शेयर में कमी के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क को उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी एवं चीन पी आर से सस्ते आयात द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है: इस विवाद में कोई तर्कसंगतता नहीं है। सबसे पहले, उत्पादन खर्च में कमी/बढ़ोतरी का बाजार शेयर से कोई मेल नहीं है। घरेलू उत्पादकों का बाजार

शेरय उत्पादन खर्च में परिवर्तन के साथ बदलता नहीं है। आगे, यह वर्तमान मामला एक संरक्षण मामला है एवं इसलिए चीन से सस्ते आयातों की उपलब्धता अपने-आप में अनियत कड़ी को तोड़ने के लिए प्रासंगिक एवं पर्याप्त मापदंड नहीं है। असल में, रुचि रखने वाले पार्टियों ने दावे के साथ कहा है कि चीन से किए गए आयात नगण्य हैं। इसी के साथ, कुछ पार्टियों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सस्ते आयातों के कारण भारी गिरावट आई है। जाहिर है कि पार्टियाँ एक दूसरे के पक्ष के खंडन कर रही हैं।

यथय. अल्मूनियम बाजार मूल्य गिरावट एवं भारत के उच्च उर्जा खर्च के सम्मिलित परिणाम राजस्व की हानि कर रहे हैं : यह स्पष्टरूप से अनियत कड़ी को जोड़ता है। यह वही मूल्यों की गिरावट है जो घरेलू उद्योग की हुई हानि के लिए जिम्मेदार है। यह तथ्य की भारत में उर्जा खर्च बहुत ज्यादा है, बिलकुल ही निराधर है। इस हानि अवधि के पहले, इसी के जैसे उच्च श्रेणी के उर्जा खर्च के साथ भी, पहले यही घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा था, और अब हानि उठा रहा है। निम्नलिखित टेबल में घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई उर्जा खर्च एवं उसकी लाभ दर को दिखाया गया है।

विवरण	यूआरएम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उर्जा खर्च	रु./एमटी	100	123	131	169	143
लाभ/(हानि)- घरेलू	रु./एमटी	100	11	-4	154	-37

कक्कक. स्टॉक में कमी घरेलू खपत में बड़ोत्तरी की ओर इशारा करती है। स्टॉक में सुधार जैसा कि पहले बताया गया है कि पी यू सी के उच्च मूल्य के कारण एवं याचिकाकर्ताओं के प्रतिदिन उत्पादन को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योगों के लिए स्टॉक को रोके रहना संभव नहीं है। असल में विभिन्न पौकों पर, स्टॉक को खत्म करने के लिए घरेलू उद्योग निर्यात करने के लिए बाध्य हैं।

**खखखख.** अल्मूनियम के वैश्विक मूल्यों के कारण भारतीय उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव, डाउन स्ट्रीम उद्योग द्वारा ए आई खपत में विकास आयात में बढ़ोत्तरी को प्रतिबद्ध कर देता है : यह याचिकाकर्ताओं का एकदम सही वर्क है । विश्व स्तर पर अल्मूनियम मूल्यों में गिरावट ने भारत में आयात को बढ़ाया है । इसकी वजह से, घरेलू उद्योग को काफी कम मूल्यों पर महत्वपूर्ण निर्यात करने पड़े । घरेलू उद्योग उदेश में बढ़ते हुए आयातों के कारण निर्यात करने के लिए बाध्य था ।

गगगग. घरेलू उद्योग का घरेलू माँग के 85% हिस्से पर अधिकार है। सिर्फ 15% से कोई विशेष हानि नहीं हो सकती : 15% बाजार शेयरको ऐसी स्थिति में मामूली नहीं कहा जा सकता जहाँ घरेलू उद्योग ने खुद अपरिमित मात्राओं पर अधिकार की बात मानी है।

घघघघ. वेदांता के साथ, बाक्साइट एवं कोयले के प्रबन्ध का मामला है, जो उनके वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित है : आरोपित मामलों ने संभवतः उत्पादन पर प्रभाव डाला होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा माना गया है कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई भी, जिससे यह स्थिति होता है कि आरोपित कारणों से घरेलू उद्योग पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि याचिकाकर्ता शेष मात्रा की बिक्री घरेलू बाजार में नहीं कर पा रहे थे, तो इसका कारण देश में आयातों की बढ़ोत्तरी ही था।

डंडडंड़. जब शुरूआत 3 वर्षों तक जब मूल्य को, कम करके ऋण की स्थिति तक ले जाया गया था, तब घरेलू उद्योग भारी हानि उठा रहा था : मूल्य को कम करके ऋण की स्थिति तक कभी नहीं ले जाया गया था । प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे तुलनात्मक आधार पर आयतित उत्पाद एवं घरेलू उद्योग के उत्पाद मूल्यों की तुलना करते हुए ध्यान दें ।

चचचच. क्षति बढ़ी हुई पूंजी विस्तार पर विमूल्यन खर्च एवं उच्च वित्तीय खर्च के कारण हुई है: यह निम्नलिखित टेबल में देखा जा सकता है कि सभी मापदंड गिरावट दिखा रहे हैं। स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के लाभ दर में गिरावट आरोपित विमूल्यन एवं ब्याज दर के कारण नहीं है। यह एल एम ई में अर्थपूर्ण गिरावट एवं इसके कारण हुई आयात मूल्य में गिरावट जिससे मूल्यों में भारी गिरावट हुई के कारण हुई है।

विवरण	यूओएम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लाभ/(हानि) घरेलू	रु.लाख में	100	13	-4	149	-50
लाभ/(हानि) ब्याज के पूर्व	रु.लाख में	100	73	35	162	23
लाभ/(हानि) ब्याज एवं मूल्यहास से पूर्व	रु. लाख में	100	75	40	163	29

छछछछ. पीयूसी विस्तार एवं सभी के लिए प्रयोग हूँडता है अतः शुल्क का आरोपण निम्नगामी उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। याचिका एवं लिखित प्रमाणों पर ध्यान दिया गया एवं विश्वास किया गया है कि संरक्षण शुल्क का 10% का सामान्य प्रभाव का प्रभाव उपभोक्ता पर सिर्फ 0.53% ही पड़ेगा, जो बेहद ही मामूली है। आगे, लोकहित को सिर्फ उपभोक्ता के तत्काल हित के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

जजजज. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण विभिन्न प्रयोक्ता क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव डालेगा एवं घरेलू उद्योग के लिए बड़ा लाभ होगा। यह लोक हित के प्रतिकूल है। यूनाइटेड फॉस्फोरस बनाम महानिदेशक (सेफगार्ड), 2000 (118) ई.एल.टी.326(दिल्ली) : इस तक में कोई आधार नहीं है। जहाँ तक घरेलू उद्योग का सवाल है, घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण वित्तीय हानियां उठा रहा है, एवं बड़े लाभ उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। महानिदेशक ने पहले 10% रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी। जहाँ तक प्रयोक्ताओं पर रक्षोपाय शुल्क के नकारात्मक प्रभाव की बात है, याचिकाकर्ता बार-बार कह रहे हैं, कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है। 10% रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव उपभोक्ताओं पर सिर्फ 0.053% होगा। पहले ही दायर की गई विस्तृत सूचना को ध्यान में रखा गया है, एवं विश्वास योग्य समझा गया है।

झझझझ. इस शुल्क से बाजार पूर्ण उत्पादों से भर जाएगा, जिससे निम्नगामी उद्योग बर्बाद होंगे, एवं कार्मिक के रोजगार समाप्त हो जाएंगे : यह तर्क सिर्फ एक कल्पना है। सीमा-शुल्क में बढ़ोत्तरी के बावजूद पूर्ण निम्नगामी उत्पाद में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। रुचि रखने वाली पार्टियों ने भी इस अनुमान को स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

जजजज. कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद के एस.एस. के 400 सीरीज के अंतिम निर्णय, जिससे यह संभावित होता है कि घरेलू उद्योग के हित को जनहित से नहीं जोड़ा जा सकता: इस मामले के तथ्य बिलकुल ही अलग हैं, अतः वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

टटटट. छूटी का अधिरोपण जनहित के खिलाफ होगा, तथा छोटे कंडक्टर निर्माता तथा पावर केवल विजनेस को हानी उठानी पड़ेगी :इस तर्क में कोई दम नहीं है कंडक्टर उद्योग पास यू उद्योग है। पावर केवल के मामले में भी उपभोगता डाऊनस्ट्रीम उद्योग की एल्यूमिनियम लागत में आए परिवर्तनों को पास आँन कर देते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के, यदि डाऊनस्ट्रीम उत्पादों के आयात में बढ़ोत्तरी होती है तब घरेलू उद्योग निश्चित ही दी याचिका दायर कर सकते हैं तथा निवारण प्राप्त कर सकते हैं केवल इसलिए कि डाऊनस्ट्रीम उत्पादों के आयात बढ़ सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वर्तमान घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति सहने दी जाएगी।

ठठठठ. “हरिदास एक्सपोर्ट बनाम आल इंडिया फ्लोट ग्लास विनिर्माता संगठन (2002 (145) ई एल टी 241 (एस.सी)“ यह स्थापित करता है कि प्रतिस्पर्धी मूल्यपर पीयूसी का आयात जन हित में लिए पूर्वाग्रह से युक्त हो, तो भी घरेलू उद्योग को क्षति होने के बाद भी शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। 2000(118) ई.एल.टी. 310 (एस.सी): उपर्युक्त निर्णय को बिलकुल प्रसंग से विपरित उद्धरित किया गया है। यदि यह

स्थापित कर दिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में एवं ऐसी शर्तों पर आयातित किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग जिससे घरेलू उद्योग को भारी हानि उठानी पड़ सकती है, तो सरकार को आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाना चाहिए।

- डडडड. एनसीवी प्रारूप में, रूचि रखने वाले पक्षों को निपटारे हेतु प्लॉन बताया जाए, जैसा कि दावा गोपनीय प्रारूप में किया गया था: याचिकाकर्ताओं ने महानिदेशक (रक्षोपाय) के निदेशानुसार संशोधित एनसीवी उपलब्ध कराई है। आगे, महानिदेशक (रक्षोपाय) ने इच्छुक पक्षों को संशोधित एनसीवी भी परिचालित भी किया है।
- ढढढढ. निपटारे हेतु प्लॉन के एनसीवी प्रारूप में यह स्पष्ट नहीं होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित प्लॉन का क्या असर होगा: महानिदेशक को दी गई जानकारी यह स्पष्ट करती है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित निपटारे के प्लॉन से उत्पादन के खर्च में कमी आएगी।
- णणणण. वेदांता के चेयरमैन ने प्रेस में सार्वजनिक बयान दिया है कि उनके मूल्य सही दिशा में जा रहे हैं, एवं बुरा वक्त निकल चुका है: एलएमई तो वास्तवमें 2015-16 के औसत से भी कम पर आ गई है। वेदांता के चेयरमैन के बयान के विषय में कहा है कि ये सकारात्मक बयान हैं एवं संभावित बाजार स्थिति पर किसी भी मामले में, यदि बाजार स्थिति भविष्य में अचानक प्रभावशाली तरीके से बदल जाती है, तो रक्षोपाय शुल्क को वापस लेने के लिए पुनर्विचार करने की शक्तियां महानिदेशक के पास होती हैं।
- तततत. यह प्रस्तुतिकरण कि एसईजेड को घरेलू उद्योग की तरह माना जाना चाहिए, एक तथ्यपरक सही प्रस्तुति है। पर हाल ही में नॉन-वुवेन फैब्रिक की एक एंटी-डिपिंग शुरूआत जिसका प्रवर्तन या निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, सऊदी अरब या चीन पी.आर से हुआ हो, फा. सं 14/23/2015-डीजीएडी, दिनांक 15 जून, 2016, याचिकाकर्ता ने एसईजेड को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना एवं महानिदेशक को घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन की प्रति मंगानी चाहिए, विशेष रूप से उस मामले का भाग-॥। यह देखा जा सकेगा कि डीए ने घरेलू बिक्री के स्तर तक ही एसईजेड को घरेलू उद्योग के रूप में माना है।
- थथथथ. घरेलू उद्योग एलएमई शर्तों पर उत्पादों का निर्यात करता है, पर इसके घरेलू प्रयोक्ता को मनाही है। घरेलू उद्योग घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों में ही एलएमई से जुड़े मूल्यों पर ही उत्पाद बेचता है।
- दददद. आयातित एल्यूमिनियम सस्ता आयात नहीं है। घरेलू उद्योग के मूल्य आयातित उत्पादों के अनुरूप हैं: यह तर्क दूसरे पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के विरुद्ध है। एक तरफ तो कई पक्षों ने बार-बार यह कहा है कि घरेलू उद्योग एलएमई मूल्यों पर उत्पाद नहीं बेच रहा है एवं अन्य पक्षों ने बार-बार कहा है कि घरेलू उद्योग का मूल्य आयातित उत्पाद के अनुरूप है। तथ्य यह है कि पीयूसिके मूल्य में जबरदस्त गिरावट आई, जिसके कारण आयातित उत्पाद के मूल्य में भी बड़ी गिरावट आई।
- धधधध. घरेलू उद्योग पहले ही यथामूल्य आयात शुल्क के साथ-साथ निकासी एवं अग्रेषण प्रभार के नाम पर अतिरिक्त प्रतिशत प्वाइंट का प्रभार उठाकर पर्याप्त सुरक्षा (13%) का लाभ उठा रहे हैं: याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई क्षति वर्तमान शुल्कों को ध्यान में रखकर ही दिखाई गै है।
- नननन. क्षमता उपयोग के बारे में आवेदकों द्वारा सरकार को गलत सूचना दी गई है। क्षमता को तय करने के लिए चयनात्मक उत्पाद शीर्षों को चुना गया एवं संस्थापित क्षमता को बढ़ा कर दिखाया गया जिसके द्वारा आंकड़ों में कमी प्राप्त की गई: याचिकाकर्ताओं ने महानिदेशक द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक सूचना उपलब्ध करा दी है। किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। पूरी सूचना का प्रमाप उपलब्ध है।

- पपपप. रुपए के विमूल्यन से घरेलू उद्योग को लाभ हो रहा है: दावा की गई क्षतिको लाभ/हानि के आधार पर जोड़ा गया हो जिसमें रुपए के विमूल्यन का ध्यान पहले ही रखा गया था।
- फफफफ. आवेदकों ने एल्यूमिनियम सिलियों के मूल्य (एल एम ई + प्रीमियम आदर्श परिपाटी की तुलना में) ऐसे रखे हैं जिसमें एल एम ई + प्रीमियम + सीमाशुल्क + लॉजिस्टिक खर्च शामिल हैं: कोई भी उद्योग जारी सीमा शुल्क एवं लॉजिस्टिक खर्च को ध्यान में रखे बिना अपने उत्पाद का मूल्य नियत नहीं करता है। वास्तव में, उपभोक्ता उद्योग में भी सीमा-शुल्क एवं लॉजिस्टिक खर्च को ध्यान में रखकर ही मूल्य-निर्धारण किया जाता है।
- बबबब. आयात शुल्क की 5% से 7.5% की वृद्धि के रूप में बजटीय परिवर्तन के परिणामस्वरूप घरेलू मूल्यों में रु. 3500 प्रति एमटी की बढ़ोतरी: जब सीमा-शुल्क छूटी को 5% से 7.5% तक बढ़ाया गया था तो उसका प्रभाव रु. 000 प्रति एमटी था। जबकि, इसी प्रकार जब सरकार ने कोयले पर उपकर बढ़ाया, तो इसका प्रभाव उद्योग के उत्पादन खर्च पर पड़ा। अतः घरेलू उद्योग को सीमा-शुल्क 5% से 7.5% तक बढ़ा दिए जाने से कोई अर्थपूर्ण सुरक्षा नहीं मिली थी।
- भभभभ. 2011-12 को मूल संदर्भित वर्ष के रूप में प्रयोग करना डाइवर्जन है क्योंकि एक समय एल एम ई अपनी ऊंचाइयों पर था : यदि किसी और अवधि को भी मूल अवधि मान लिया जाए, तो भी यही परिणाम प्राप्त होगा।
- मममम. यूएस डॉलर बनाम भारतीय रुपये के मूल्य ह्रास का फायदा उठाया। इसके साथ ही ईंधन खर्च (जो उत्पादन खर्च का 45% होता है) के निम्नगामी गति से भी फायदा उठाया: याचिकाकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन उनके द्वारा रखे अभिलेखों के आधार पर पर प्रस्तुत किया है।
- यययय. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता का तर्क का कोई आधार नहीं है। 2012-16 के दौरान न सिर्फ उनकी उत्पादन क्षमता 10% बढ़ गई, बल्कि वे विशालकाय विस्तार भी कर रहे हैं: उत्पादन 60% तक बढ़ गया पर विक्री सिर्फ 35% तक बढ़ी एवं नियर्ति 345% तक बढ़ गया। याचिकाकर्ता घरेलू की तुलना में नियर्ति में कहीं अधिक हानि उठा रहे हैं, जो यस स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता बढ़े हुए आयात के कारण हानि उठा रहे हैं।
- रररर. नियर्ति मूल्य घरेलू उद्योग को बेचे गए उत्पाद के मूल्य से 6-9% तक कम हैं। अतः सीमा शुल्क छूटी का फयदा उठा रहे हैं: याचिकाकर्ता सीमा-शुल्क छूटी का फयदा लेने के लिए कानूनी तौर पर हकदार हैं, पीयूसी के उपभोक्ता भी ऐसा ही कर रहे हैं। जहां तक याचिकाकर्ताओं के नियर्ति मूल्य का प्रश्न है, याचिकाकर्ता भारत में हुए आयात के कारण कम मूल्य पर नियर्ति करने के लिए बाध्य है।
- ऋ. हाइड्रो एल्यूमिनियम एशिया लिमिटेड; रॉकमैन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड; एंड्योरेंस टेक्नोलोजिस लिमिटेड
- क. घरेलू उत्पादकों के तर्क सामान्यतया नकार दिए गए।
- ख. चुंकि सूचना में बहुत परिवर्तन हुआ है, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया क्षति का डाटा गंभीर जांच के अधीन होना चाहिए।
- ग. एक एसईजेड यूनिट को घरेलू उद्योग की परिधि में रखे जाने अथवा न रखे जाने का प्रश्न विधि का एक अनिश्चित प्रश्न है। महानिदेशक, रक्षोपाय को इसके निष्कर्ष पर रक्षोपाय नियमों के अनुसार पहुंचना चाहिए। तथापि आवेदकों द्वारा नियर्ति बाजार को लक्ष्य कर स्थापित की गई विशाल नियर्ति क्षमताओं के

भार के कारण घरेलू उद्योग के लिए उचित भाव बहुत अधिक नहीं बढ़ने चाहिए और उनके द्वारा स्थापित ऐसी निर्यात क्षमताओं का आधार भारतीय प्रयोक्ता को बहन नहीं करना चाहिए।

- घ. क्षति विश्लेषण के लिए 2015-16 के पूरे वर्ष की क्षति सूचना लेना परंतु उसको तिमाही विश्लेषण के अधीन न लेना बहुत ही अपर्याप्त होगा। जैसा कि स्वयं मैं वेदांता के चेयरमैन ने स्वीकार किया है कि 2016 के प्रारंभ में एल्यूमिनियम सेक्टर के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अतः 2011-12 का आधार वर्ष और 2015-16 के बिल्कुल हालिया अवधि के डाटा की तुलना करने से घरेलू उद्योग की सही व सटीक तस्वीर नहीं दिखेगी।
- इ. 2015-16 की सूचनाओं का आगे तिमाहियों में विश्लेषण किया जाना और 30 सितम्बर, 2016 तक की सूचना पर विचार किया जाना घरेलू उद्योग की बेनेवोलेंट स्थिति की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर प्रस्तुत करेगा।
- ज्ञ. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित डाटा पर भरोसा नहीं किया जाए। डीजीसीआई एंड एस के अनुसार लेन-देनानुसार आयात का डाटा इन शीर्षों के अधीन काफी विभिन्न कीमतों पर आयात किए जा रहे उत्पाद की कई किस्मों की वास्तविक विविध प्रकृति दर्शाएगा।
- छ. ऐसी सभी गोपनीय सूचना जो कि अनुचित व अगोपनीय रूप में फाइल की गई हैं या गोपनीयता के दावे के समुचित औचित्य के बिना दायर की गई हैं, की अवहेलना कर दी जाए।
- ज. डीआई का निवेदन स्पष्ट रूप से बताता है कि पीयूसी विविध उत्पादों की एक विशाल टोकरी है और पीयूसी की परिभाषा को वास्तविकता और नियमों के अनुरूप करने के लिए बहुत से बहिष्करण आवश्यक हैं।
- झ. गैर अलौंय का भिन्न आवेदन है और अलौंय का भिन्न आवेदन है। वायर रोड्स एंवं सिल्लियां सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी आइटम्स नहीं हैं। यह बिल्कुल अनुचित है कि अलौंय और गैर अलौंय उत्पाद एक टोकरी में रखे गए हैं जबकि अलौंय और गैर अलौंय में अतिरिक्त विभिन्न परस्पर श्रेणियां हैं जो कि तकनीकी गुणों और कीमतों के अनुसार भी भिन्न-भिन्न हैं। उन आइटमों जो कि डीआई द्वारा कभी निर्मित नहीं की गई हैं, को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
- ञ. सीएमआर सेंचुरी मेटल रिसाइकिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआर), सीएमआर निकै इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआरएन) और सीएमआर-तोयोत्सु एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआरटी) द्वारा दायर सबमिशंस में यह दावा किया गया है कि उन्होंने सिर्फ अलौंय एल्यूमिनियम का उत्पादन किया है। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 'समान वस्तु' का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और याचिकाकर्ता अलौंय एल्यूमिनियम के उत्पादन जो कि प्रत्यक्षतः अलग श्रेणी है, में संलग्न उद्योगों के विभिन्न समूहों के अस्तित्व को रिकॉर्ड पर नहीं लाए थे। अतः, याचिकाकर्ताओं का कथन कि वे घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता रखते हैं, ठीक नहीं है और तथ्यों की और अधिक विस्तृत रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- ठ. आयात में वृद्धि के साथ यह तथ्य कि इस कथित वृद्धि के बाद भी, आयात की मांग का समग्र हिस्सा 15% से कम है जो यह दर्शाता है कि बाजार हिस्से के 85% पर आराम से घरेलू उत्पादकों का कब्जा है। अतः, आयात में वृद्धि का आरोप सत्य नहीं है और रक्षोपाय योजना के अधीन अनुचित सुरक्षा लेने के लिए उठाया गया है।
- ठ. याचिकाकर्ताओं के इन दावों में कोई सार नहीं है और वे परस्पर विरोधाभासी हैं। याचिकाकर्ताओं ने आयात में औचिक उद्धाल के कुछ संभावित कारण बताए हैं लेकिन ऐसे कारण प्रथम दृष्टया दर्शते हैं कि बहुत छोटी समय अवधि में उनके कारण आयात में कोई उद्धाल नहीं आया है। यहां तक कि बताए गए कुछ कारणों में कथित सब्सिडी है। कमोडिटी बाजार में छोटी समय अवधि के लिए मात्र चक्रीय परिवर्तन, विशेषतः जब

- कीमतें एलएमई द्वारा गवर्न की जाती है, मात्रा में उछाल के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्कों के अधीन नहीं होने चाहिए क्योंकि प्रयोक्ता उद्योग पर इसका प्रभाव अपूरणीय होगा।
- ड. जैसा कि मै. वेदांता ने स्वयं स्वीकार किया है याचिकाकर्ताओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और वे संदर्भित वस्तुओं की उचित कीमतें पा रहे हैं। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण याचिकाकर्ताओं को अनुचित लाभ प्राप्त करने में सहारा देने में मदद करेगा और प्रयोक्ता उद्योग जो कि पहले ही ऊँची कीमत चुका रहा है किसी भी रक्षोपाय शुल्क के परिणामस्वरूप और अधिक कीमत चुकाने पर बाध्य हो जाएंगे।
- ढ. उनके लिखित समझिंशंस में स्थापित वर्तमान मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता गंभीर क्षति दर्शाते में असफल रहे हैं और दावे मात्र हैं। क्षति के आरोप की सब्जत जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उत्पादकों के पास एसईजेड/ईओयू यूनिट्स और विशाल अतिरिक्त क्षमता है। घरेलू उद्योग ने महानिदेशक के समक्ष सटीकता से प्रतिनिधित्व नहीं किया है क्योंकि वे उत्पादकों के नए समूह हैं और दावा कर रहे हैं कि वे सबजेक्ट गुड्स जैसे सीएमआर का भी निर्माण कर रहे हैं।
- ण. आयातों की स्थिति और घरेलू उत्पादकों के निष्पादन की जांच त्रैमासिक रूप से 2015-16 के दौरान एवं सितम्बर, 2016 की तिमाही तक की जाए क्योंकि 2011-12 एवं 2015-16 के मध्य तुलना अनुचित है।
- त. रक्षोपाय नियमों के अधीन व्यापक क्षति का दावा तर्कसंगत नहीं है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग का लगभग 85% का बड़ा हिस्सा है। 15% का आयात एक पीयूसी टोकरी में रखा गया है जिसमें उत्पादों का पूरा गुच्छा तकनीकी फीचर और मूल्य के भी संबंध में अलग है। बहुत से वस्तुएं तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित भी नहीं की जाती या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के जैसी ही वस्तु नहीं है।
- थ. याचिकाकर्ता मात्रा में कथित वृद्धि, गंभीर क्षति एवं क्षति की संभावना के समान मापदंडों पर आश्रित हैं। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित कारण ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी बाजार में अंतर्निहित चक्रीय मुद्दे हैं और ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं है जिसके कारण आयात में अचानक उछाल आया हो जैसा कि याचिकाकर्ता दावा कर रहे कि इनके कारण उनको किसी प्रकार क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने क्षति की संभावना का दावा करते समय ऐसे कोई कारक नहीं दिखाए हैं जिनसे उनको क्षति की संभावना हो जाए। क्योंकि निसंदेह घरेलू उद्योग की स्थिति पहले से ही भारी सुधार के पथ पर है। अतः न गंभीर क्षति है एवं न ही क्षति की संभावना है।
- द. वैश्विक चक्रीय प्रभावों ने शायद भारतीय उद्योग पर प्रभाव डाला हो परंतु अब स्थिति बदल गई है और पीयूसी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ध. आयात एवं कथित क्षति के मध्य कोई कॉजल लिंक नहीं है क्योंकि
- जब शुरुआती तीन वर्षों में अंडरकटिंग नकारात्मक थी तब लाभ घट रहा था जो दर्शाता है कि लाभ में कमी किन्हीं दूसरे कारणों से होनी चाहिए।
  - क्षति का दावा आयात से सम्बद्ध नहीं है और कारण जैसे कच्चे माल की अधिप्राप्ति के मुद्दे, उच्च व्याज दर आदि अपारेंट हैं।
  - किसी भी कथित क्षति का कारण केवल अन्य कारण हैं और यह आयात में किसी औचक उछाल के नहीं है क्योंकि 01 आयात में ऐसी कोई वृद्धि नहीं दिखा सका है।
  - डीआई के पास 85% से अधिक का बाजार हिस्सा है और मात्रा कीमत मापदंडों के अनुसार कोई क्षति दृष्टिगोचर नहीं है।
  - अतः आयात में कथित उछाल और डीआई को हुई कथित गंभीर क्षति के मध्य कोई कॉजल लिंक नहीं है।
  - वेदांता उनकी खानों के कारण महत्वपूर्ण विधिक मुद्दे एवं लिटिगेशंस का सामना कर रहे हैं इसके किसी प्रभाव को आयात पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

- vii. जैसा कि ऊपर दिया गया है यह स्वीकृत तथ्य है कि उद्योग अस्थिरता वाली अवधि से निकल चुका है और यह अब उससे गुजर चुका है और उद्योग बेनेवोलेंट कीमतें प्राप्त कर रहा है।
- न. याचिकाकर्ताओं ने रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए कोई केस स्थापित नहीं किया है अतः दो वर्ष के लिए शुल्क अधिरोपित करने के अनुरोध को भी नकार दिए जाने की जरूरत है।
- प. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का प्रयोक्ता उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा वो भी तब जबकि सबजेक्ट गुड्स की कीमतें महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई हैं और बीसीडी पहले ही 2.5% तक बढ़ चुका है। याचिकाकर्ताओं का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है।
- फ. समायोजन प्लान का एनसीवी संस्करण प्लान के किसी अर्थपूर्ण अध्ययन की अनुमति नहीं देता। टिप्पणियां देने के लिए डीआई को अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध करानी चाहिए।
- ब. आवेदन मेटेनेबल नहीं है और चालू कार्यवाहियां समाप्त कर दी जाएं।
- भ. पीयूसी जिसमें उत्पादों की व्यापक रेंज शामिल है और जो कि एक जांच के स्कोप में साथ-साथ नहीं रखे जा सकते, के वर्तमान स्कोप के साथ वर्तमान जांच नहीं की सकती और ऐसी बेकेटिंग विकृत परिणाम प्रस्तुत करेगी जो कि भारत में प्रयोक्ताओं के विधि सम्मत अधिकारों के विरुद्ध है।

#### **IV. महानिदेशक (रक्षोपाय) की जांच एवं निष्कर्ष**

- मैंने मामले के अभिलेखों का एवं घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ता/आयातकों, निर्यातकों तथा निर्यातक देशों द्वारा फाइल किए गए उत्तरों का, ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उनके द्वारा दिए गए लिखित निवेदनों और प्रत्युत्तरों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए निवेदनों और इनसे उठे मुद्दों से उपयुक्त स्थानों पर निम्न निष्कर्षों में निपटा गया है:
- सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से संबंधित है। इसकी उपधारा (1) केंद्र सरकार द्वारा किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के बारे में है यदि वह वस्तु भारत में ऐसी वर्धित मात्रा में और ऐसी स्थिति के अंतर्गत आयात की जा रही हो कि उसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर झंति हो अथवा गंभीर झंति की संभावना हो।
- सीमा-शुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 जांच को संचालित करने के तरीकों एवं सिद्धांतों के बारे में है।
- जांच उक्त नियमों के अनुसरण में की गई है और अंतिम निष्कर्ष इस अधिसूचना के माध्यम से अभिलेखित किए गए हैं।
- अ. घरेलू उद्योग (डीआई)**
- सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

  - “(ख) “घरेलू उद्योग” अर्थात् उत्पादक-

  - भारत में समान वस्तुओं का अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का समग्र उत्पादक; अथवा
  - जिसका भारत में समान वस्तुओं का अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हो;”

- कुछ इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि मै. वेदांता का एसईजे ड संयंत्र सिर्फ निर्यात के लिए है अतः उसे घरेलू की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। तथापि, डीआई कहते हैं कि मै. वेदांता के एसईजे ड संयंत्र को निम्नलिखित कारणों से घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए:

- क. रक्षोपाय कानून में प्रयोग किया गया शब्द “उत्पादक – भारत में” है और एसईजेड्स में स्थापित एसईजेड यूनिटें विल्कुल भारत में उत्पादक हैं।
- ख. ‘घरेलू उद्योग’ की पदवी और स्कोप के लिए प्रासंगिक मानदंड उत्पादन है, न कि ऐसे उत्पादन का उपयोग है।
- ग. एसईजेड अधिनियम के अधीन, आयात से तात्पर्य एक विशेष आर्थिक ज़ोन में, भारत के बाहर के एक स्थान से एक यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा भूमि, समुद्र अथवा वायु अथवा किसी अन्य माध्यम से वस्तुओं का लाना अथवा सेवाओं का प्राप्त करना है और निर्यात से तात्पर्य एक विशेष आर्थिक ज़ोन से भूमि, समुद्र अथवा वायु अथवा किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर वस्तुओं को ले जाना अथवा सेवाएं प्रदान करना है। इसलिए, एक एसईजेड यूनिट द्वारा डीटीए में विक्री निर्यात नहीं है बल्कि वास्तव में एक घरेलू विक्री है।
- घ. एसईजेड में किसी यूनिट द्वारा की गई विक्री खाता-बहियों में घरेलू विक्री मानी जाती है; सीमा-शुल्क प्राधिकारी भी एसईजेड यूनिट द्वारा भारतीय खरीदारों को की गई विक्री को घरेलू विक्री मानता है; एसईजेड्स पर दिवानी, फौजदारी अथवा व्यापारिक कानून लागू होते हैं। विभिन्न विनियमों के लिए एसईजेड को भारतीय निर्माता माना जाता है।
- ड. एंटी डंपिंग प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार, ईओयू अथवा एसईजेड में स्थापित यूनिट को घरेलू उद्योग माना जाता है।
- च. सैचुरेटेड फैटी एल्कोहल के डीजी सेफगाइर्स के मामले, 100% ईओयू यूनिट को घरेलू उद्योग माना गया है।
- छ. भारतीय एसईजेड्स द्वारा किए गए निर्यात को अन्य देशों द्वारा ‘भारत में उत्पन्न’ माना जाता है।
- ज. एसईजेड यूनिटों को घरेलू उद्योग मानने पर उनको दिए गए विभिन्न लाभों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

7. इस संबंध में, मैंने पाया है कि :

- (i) 23 जून, 2005 को अधिनियमित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 कहता है कि यह:-  
 “निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, विकास एवं प्रबंधन तथा इससे संबंधित मामलों अथवा उनके तत्संबंधी प्रसंगों के लिए बना एक अधिनियम है”।
- (ii) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(i) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को निम्नानुसार परिभाषित करती है:-  
 “घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से अभिप्राय पूरे भारत (टैरिटोरियल वार्ट्स एवं कॉन्टीनेंटल शेल्फ सहित) से है परंतु जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र के एरियाज शामिल नहीं होते हैं;”।
- (iii) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एम) (ii) के अनुसार निर्यात से अभिप्राय, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एक यूनिट अथवा डेवलपर को अन्य बातों के साथ-साथ “वस्तुओं की आपूर्ति करना अथवा सेवाएं प्रदान करना है,”।
- (iv) एसईजेड अधिनियम की धारा 30 के अनुसार:  
 “इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट स्थितियों के अधीन:-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र से हटाकर घरेलू टैरिफ एरिया में भेजी गई किसी भी वस्तु पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रतिकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क सहित सीमा-शुल्क ड्यूटी, जहां भी लागू हो, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन प्रभार्य है, जैसा कि ऐसे वस्तुओं पर उद्ग्राहय होती है जब वे आयात की जाती हैं; एवं

(v) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अनुसार आगे:-

प्राधिकृत ऑपरेशंस के संचालन के उद्देश्य से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को उसके स्थापना के दिन से व उस दिन के बाद से भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र माना जाएगा।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अधीन एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को उस तारीख से जब केंद्र सरकार उसे अधिसूचित करे, पोर्ट, इन्लेंड कंटेनर डिपो, लैंड स्टेशन और लैंड कस्टम स्टेशन, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा:

बशर्ते इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार भिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भिन्न तारिखें अधिसूचित करे।

(vi) विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 बताती है कि:

“ घरेलू टैरिफ क्षेत्र – (1) एक यूनिट अस्वीकार की गई या अपशिष्ट या स्कैप या अवशेष या टूटे हुए हीरे या निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गौण उत्पाद या इनसे संबंधित उत्पादों सहित वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय घरेलू टैरिफ एरिया में धारा 30 के अधीन सीमा-शुल्क ड्यूटियाँ चुका कर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, कर सकती हैं:

(क) उप-नियम (1) के अंतर्गत घरेलू टैरिफ एरिया में, एक यूनिट द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय आयात लाइसेंस के सबमिशन पर होगा, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन भारत में समान वस्तुओं के आयात पर लागू होता है।

8. एसईजेड अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों एवं इनके अधीन बनाए गए नियमों से यह पाया गया है कि:

- (i) आयातों को बढ़ावा दिया जाना एस ई जेड यूनिटों को स्थापित किए जाने का मूल उद्देश्य है।
- (ii) एस ई जेडों का क्षेत्र घरेलू टैरिफ क्षेत्र ( डी टी ए) की परिभाषा से हटा दिया गया है तथा यहाँ से हटाये जाने पर भी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन एंटीडंपिंग, प्रतिकारी तथा रक्षोपाय ड्यूटीयों सहित सीमा शुल्क ड्यूटियाँ भी लागू होंगी।
- (iii) डी टी ए से एस ई जेड को वस्तुओं की आपूर्ति किया जाना आयात माना जाता है।
- (iv) एस ई जेड की धारा 53 के अधीन एस ई जेड को भारत में सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर कारक क्षेत्र माना जाता है तथा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 7 के अधीन इसे जैसा भी मामला हो एक पोर्ट, इनलेण्ड कंटेनर डिपो, लैंड स्टेशन तथा लैंड कस्टम स्टेशन भी माना जाता है।
- (v) किसी एस ई जेड यूनिट द्वारा निर्मित वस्तुओं की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्री केवल आयात लाइसेंस जैसा कि भारत में समान वस्तुएँ आयात किए जाने पर लागू हैं, को प्रस्तुत किए जाने पर ही की जा सकती है।

9. जैसे की नीचे चर्चा की गई है, डी आई का एस ई जेड यूनिट को घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

- क. डी आई का यह तर्क की रक्षोपाय विधि में “भारत में उत्पादक” शब्द का प्रयोग किया गया है तथा एस ई जेडों में स्थापित एस ई जेड यूनिटें भारत के ही उत्पादक हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एस ई जेड अधिनियम, 2005 की धारा 53 के अधीन एक एस ई जेड यूनिट को भारत में सीमा-शुल्क क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र माना जाता है तथा इसमें उत्पादित सभी उत्पादों को ऐसा माना जाता है जैसे की भारत के क्षेत्र से बाहर उत्पादित हुए हों।
- ख. डी आई ने तर्क दिया है कि ‘घरेलू उद्योग’ की पात्रता तथा दायरे का संगत मापदंड उत्पादन है न की ऐसे उत्पादन का उपयोग। मेरे विचार से, क्योंकि एस ई जेड भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर एक क्षेत्र माना जाता है इसे घरेलू उत्पादक अथवा घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है। सर्वप्रथम, किसी भी यूनिट की घरेलू उत्पादन / उद्योग के रूप में पात्रता को सिद्ध किए जाए उसके बाद ही उसे घरेलू उद्योग माने जाने के उद्देश्य से उसके उत्पादन पर विचार किया जा सकता है।
- ग. यह तर्क दिया गया है कि एस ई जेड अधिनियम के अधीन, आयात का अर्थ किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भूमि, समुद्र अथवा वायु अथवा किसी अन्य माध्यम से वस्तुएँ मंगवाना अथवा सेवाएँ प्राप्त करना है तथा निर्यात का अर्थ किसी विशेष आर्थिक जोन से भूमि, समुद्र अथवा वायु अथवा किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर वस्तुएँ ले जाना अथवा सेवाएँ प्रदान किया जाना है। अतः किसी एस ई जेड यूनिट द्वारा डी टी ए में वस्तुएँ भेजा जाना निर्यात नहीं है अपितु, वास्तव में यह घरेलू विक्री है। मैंने यह पाया कि एस ई जेड अधिनियम की धारा 2(ड) के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र से किसी यूनिट अथवा डेवलपर को वस्तुओं की आपूर्ति किया जाना अथवा सेवाएँ प्रदान किया जाना निर्यात की परिभाषा में आता है। साथ ही, विशेष आर्थिक जोन से किसी भी वस्तु को हटा कर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ले जाए जाने पर रक्षोपाय शुल्क सहित सीमा-शुल्क छूटी लागू होगी।
- घ. एस ई जेड में किसी यूनिट द्वारा की गई बिक्री को खाता बहियों में अथवा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा घरेलू बिक्री माने जाने से संबंधित डी आई का तर्क; एस ई जेडों पर दीवानी, फौजदारी अथवा व्यापारिक कानूनों को लागू किए जाने अथवा विभिन्न विनियमों के लिए एस ई जेड को भारतीय निर्माता माने जाने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तर्क संगत नहीं हैं। एस ई जेड में किसी यूनिट को घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता के विषय में एस ई जेड अधिनियम तथा नियमों के साथ पठित रक्षोपाय कानून के विद्यमान विधिक प्रावधानों के दायरे में ही निर्णय लिया जाएगा।
- ड. ई ओ यू अथवा एस ई जेड में किसी यूनिट को घरेलू उद्योग माने जाने के विषय में एंटी डम्पिंग प्राधिकारियों के निर्णय एंटी डम्पिंग कानूनों के दायरे में लिए गए हैं तथा यह रक्षोपाय जँचों पर लागू नहीं होते हैं।
- च. आवेदकों ने ध्यान दिलाया की सैचुरेटिड फैटी अलकोहोल्स के डी जी सेफगाइर्स मामले में घरेलू उद्योग 100% ई ओ यू माने गए हैं। क्योंकि एस ई जेड तथा ई ओ यू अलग अलग विधिक प्रावधानों से शासित होते हैं, इसलिए, वर्तमान जँचों में यह लागू नहीं होता।
- छ. यह तर्क दिया गया कि भारतीय एस ई जेड से निर्यात को अन्य देशों द्वारा “भारत में उत्पन्न” वस्तुएँ माना जाता है। मेरे विचार से अन्य देशों द्वारा अपने घरेलू कानूनों के अनुसार एस ई जेड के निर्यातकों के साथ किया जा रहा व्यवहार यहाँ प्रासांगिक नहीं है।
- ज. डी आई ने तर्क दिया कि एस ई जेड यूनिट को दिये गये विभिन्न लाभ ऐसी यूनिट को घरेलू उद्योग माने जाने पर कहीं प्रभाव न डालें। इस संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में एस ई जेड कि पात्रता का निर्धारण रक्षोपाय नियमों के प्रसांगिक प्रावधानों तथा एस ई जेड अधिनियम के अधीन बने नियमों के आधार पर किया जाएगा न कि उन्हें प्रदान किए गए किसी लाभ के आधार पर।

10. मैंने यह भी पाया है कि दिनांक 27.9.2012 फा.सं. डी- 22011/14/2011 के तहत जारी पुरानी रक्षोपाय जाँच जो भारत में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के आयातों के संबंध में थी में, इस विषय पर कि क्या कोई एस ई जेड यूनिट एस ई जेड के दायरे में शामिल हो सकती है। महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया :
- “एस ई जेड में चल रही कोई यूनिट आयातों के कारण बाज़ार में व्यवधान का दावा नहीं कर सकती। इन एस ई जेड यूनिटों को भारतीय सीमा-शुल्क क्षेत्रों से बाहर माना जाता है तथा अन्य घरेलू यूनिटों से इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तदनुसार, यह निर्णय लिया जाता है कि विशाखापट्टनम में स्थित डब्ल्यू एस आई कि एस ई जेड यूनिट के संबंध में डाटा पर वर्तमान जाँच के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।”
11. पूर्व में कि गई चर्चा के दृष्टि कोण से मेरा मानना है कि मेसर्स वेदांता की एस ई जेड यूनिट को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर किया जाता है। तदनुसार, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से मेसर्स वेदांता को एस ई जेड यूनिट के संबंध में स्थापित क्षमता तथा अन्य डाटा पर विचार नहीं किया गया।
- मेसर्स वेदांता लिमिटेड - एल्यूमीनियम व पावर ,
  - मेसर्स भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा,
  - मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आवेदन दायर किया गया है तथा ये तीनों मिलकर भारतीय उत्पादन का 50% से अधिक उत्पादित करते हैं तथा इस प्रकार ये मुख्य उत्पादक हैं। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट भी है:

तालिका-1

वर्ष	डी आई का उत्पादन (एम टी)	समग्र भारतीय उत्पादन (एम टी)	डी आई का हिस्सा (%)
2011-12	8, 77, 948	19, 18, 126	46
2012-13	9, 31, 324	20, 72, 915	45
2013-14	10, 52, 132	20, 89, 929	50
2014-15	13, 61, 447	25, 57, 548	53
2015-16	15, 60, 141	28, 15, 481	55

13. तदनुसार, यह माना जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 कि धारा 8 ख (6)(ब) के अधीन डी आई की परिभाषा के अंदर आवेदक घरेलू उत्पादक, घरेलू उद्योग हैं तथा घरेलू उद्योग(डी आई) (मेसर्स वेदांता की एस ई जेड यूनिट के अलावा )का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आ. विचारधीन उत्पाद (पी यू सी )

14. विचारधीन उत्पाद पर बहुत सी इच्छुक पार्टियों ने मुद्दे उठाए हैं। इस मुद्दों का समाधान इस प्रकार है:-

- कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया कि पी यू सी का दायरा बहुत व्यापक है तथा एक पी यू सी के तले विभिन्न प्रकार के उत्पादों कि बकेट है। : इस संबंध में मेरा यह दृष्टिकोण है कि क्योंकि पी यू सी के दायरे में शामिल विभिन्न उत्पाद आकृति, आकार अथवा संयोजन के आधार पर अलग हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि उनसे बने उत्पाद भी पूरी तरह अलग होंगे और उन्हें अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
- कुछ इच्छुक पार्टियों का तर्क था कि प्रारम्भिक निष्कर्ष में पी यू सी को जैसा परिभाषित किया गया था वह न केवल अस्पष्ट है परंतु आयात किए जा रहे उत्पाद तथा जिसके विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाना है को

परिभाषित भी नहीं करता है: इस तर्क का कोई आधार नहीं है प्रारम्भिक निष्कर्षों में पी यू सी का दायर बिलकुल स्पष्ट है तथा इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

“सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं.7601 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद अनरॉट एल्यूमीनियम (एल्यूमीनियम गैर अलॉय और एल्यूमीनियम अलॉय) (जिसे इसके बाद पीयूसी कहा गया है) के अधीन उत्पाद को वर्गीकृत किया गया है।”

iii. यह तर्क दिया गया है कि टैरिफ वर्गीकरण एल्यूमीनियम अलॉय और एल्यूमीनियम गैर अलॉय की पहचान अलग अलग करता है और वर्तमान जांच के लिए इसको एक उत्पाद की तरह नहीं माना जा सकता: इस तर्क को सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें विभिन्न सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत से उत्पादों को पीयूसी के रूप में साथ-साथ लिये जा रहे हैं।

iv. कुछ इच्छुक पार्टियों का तर्क है कि घरेलू उद्योग एल्यूमीनियम अलॉय का उत्पादन नहीं करता और उप शीर्ष 760120 के अंतर्गत आने वाला एल्यूमीनियम अलॉय को पीयूसी के स्कोप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसको एल्यूमीनियम गैर अलॉय से संबंधित उप शीर्ष 760110 तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। आवेदकों ने निवेदन किया है कि वे पीयूसी के समान या इसके सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस संबंध में मैंने घरेलू डेटा के पाके पर सत्यापन के समय उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की है और पाया है कि आवेदक उप शीर्ष 760120 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का उत्पादन एवं विक्री भी कर रहे हैं।

15. उपर्युक्त को देखते हुए, जांच के लिए लिया गया विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं.7601 के अधीन वर्गीकृत "अनरॉट एल्यूमीनियम (एल्यूमीनियम गैर अलॉय और एल्यूमीनियम अलॉय)" (जिसे इसके बाद पीयूसी कहा गया है) है। यह सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं.7601 के तहत उत्पादों की पूरी रेंज कवर करता है।
16. यह भी माना गया है कि घरेलू रूप से उत्पादित "पीयूसी" जांच के अधीन आयातित उत्पाद के संबंध में उसके समान अथवा उसके सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं की परिधि में आता है और यह कि घरेलू स्तर पर उत्पादित "पीयूसी" सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 2(ङ) के अर्थों में सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 7601 के अंतर्गत आने वाले आयातित "अनरॉट एल्यूमीनियम (एल्यूमीनियम गैर अलॉय और एल्यूमीनियम अलॉय)" के समान वस्तु है।

#### इ. सूचना के स्रोत:

17. विचाराधीन उत्पाद भारत में सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के 76 अध्याय के सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष 7601 के अधीन आयात किया गया है। रक्षोपाय जांच वाणिज्य मंत्रालय (<http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp>), निर्यात आयात डेटा बैंक से लिए गए 2011-12 से 2015-16 (जनवरी, 2016 तक) आयात डेटा और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गए 2011-12 से 2015-16 के घरेलू डेटा के आधार पर शुरू की गई थी। उक्त घरेलू डेटा एक्साईट रिटर्न और डीआई द्वारा महानिदेशक (रक्षोपाय) के कार्यालय में उपलब्ध कराए अन्य दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया गया था।
18. कुछ इच्छुक पार्टियों ने इस ओर संकेत किया गया है कि घरेलू डेटा बेमेल है और यह कि डीआई द्वारा दायर निवेदन में दर्शायी गई कुल संस्थापित क्षमता में मे. वेदांता की एसईजे१ इकाई की संस्थापित क्षमता को शामिल किया गया है। मैंने पाया कि डीआई ने अपने आवेदन में यह नहीं बताया है कि उनकी एक यूनिट एक एसईजे१ यूनिट है। तदनुसार, महानिदेशक, रक्षोपाय द्वारा डीआई की एक निर्माता यूनिट पर ऑन साईट सत्यापन किया गया था।
19. घरेलू डेटा 2011-12 से 2016-17 (जून, 2016 तक) की जांच पर, यह पाया गया था कि विनिर्माण की कुछ इकाइयों की हॉट मेटल के उत्पादन एवं सीमित उपभोग / विक्रियों की प्रविष्टियां सीटीएच 7601 के तहत सिल्लियों के उत्पादों, बिलेट्सों, वॉयर रॉडों इत्यादि की प्रविष्टियों के साथ एक्साईट रिटर्न (ईआर-1) में दर्शाई गई हैं। यद्यपि, यह उत्पाद अर्थात् सिल्लियां, बिलेट्स, वॉयर रॉड्स आदि एक्साईट रिटर्न में पहले से ही प्रविष्ट हॉट मेटल से

उत्पादित किये गए हैं। क्योंकि दोनों हॉट मेटल और पीयूसी (हॉट मेटल से उत्पादित) उसी सीटीएच 7601 के तहत आते हैं, निकासियों/इनवेंटरी से संबंधित पहले से सत्यापित डेटा में ओवरलैपिंग हो गई जिसके कारण पहली सत्यापित रिपोर्ट में दर्शित घरेलू डेटा कुछ बेमेल हो गया।

20. दूसरी जांच रिपोर्ट में मे. वेदांता लिमिटेड की एसईजेड यूनिट का सत्यापित डेटा नहीं है। इसके अलावा उपर्युक्त ओवरलैप्पड डेटा से संबंधित मामला भी हल किया गया गया है और ये अंतिम निष्कर्ष दूसरी सत्यापन रिपोर्ट पर आधारित हैं। अँन साईट सत्यापन रिपोर्ट भी (अगोपनीय संस्करण) सार्वजनिक फाइल में रख दी गई है।
21. आगे, वाणिज्य मंत्रालय (<http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp>), निर्यात आयात डेटा बैंक से लिए गए 2011-12 से 2015-16 के आयात डाटा का प्रयोग जांच की अवधि के विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। 2016-17 की अवधि (अप्रैल से जून, 16) के लिए वाणिज्य मंत्रालय की वैबसाईट से लिया गया और इस अवधि का सत्यापित डाटा पश्च जांच अवधि विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा कंपनियों के लागत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लागत डाटा उपलब्ध कराया गया है और इसकी जांच महानिदेशक (रक्षोपाय) के सलाहकार (लागत) द्वारा की गई है।

#### **ई. जांच की अवधि (पीओआई):**

22. यह देखा गया है कि न तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और न ही सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 विशिष्ट रूप से परिभाषित 'जांच की अवधि' या रक्षोपाय जांच के लिए विचार किये जाने वाली न्यूनतम अवधि को परिभाषित करता है। जांच की अवधि चुनने के लिए रक्षोपाय पर डब्लूटीओ करार में कोई सामान्य या निर्दिष्ट प्रावधान या दिशा निर्देश नहीं है। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे पर यूएस-लाईन पाईप विरुद्ध कोरिया (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201) के केस में पैनल निष्कर्षों में विस्तार से विचार किया गया है। पैनल ने इस केस में निर्णय दिया था कि "जांच की अवधि की लंबाई" और इसके "ब्रेकडाउन" को तय करना आयातक देश के जांच प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर है।

"हमने नोट किया है कि करार में ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह कि विश्लेषण के उद्देश्य से अवधि को ब्रेकडाउन कैसे किया जाना चाहिए। अतः जांच की अवधि और इसका ब्रेकडाउन जांच प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ा जाता है। हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में आईटीसी द्वारा चुनी गई अवधि पांच साल और छह माह थी, जोकि अर्जटीना में अर्जटीनी जांच एजेंसी – फुटवेयर सेवगार्ड द्वारा प्रयुक्त जांच अवधि के समान है। तथापि, हमने नोट किया है कि जांच अवधि की लंबाई पर विचार करने के लिए कोरिया द्वारा भरोसा किये गए निष्कर्षों में अपीलीय निकाय ने वास्तव में अवधि की लंबाई पर जोर नहीं दिया है बल्कि फोकस हालिया आयातों पर होना चाहिए और मात्र जांची गई अवधि के दौरान प्रवृत्तियों पर नहीं होना चाहिए। लाईन पाईप जांच के मामले में आईटीसी ने सिर्फ अंतिम बिन्दुओं पर विचार नहीं किया है या जांच अवधि (जैसाकि अर्जटीना ने अर्जटीना – फुटवेयर सेफगार्ड के मुद्दे की जांच में किया था) के दौरान प्रवृत्ति को देखा था। इसने आयातों से संबंधित डाटा का साल दर साल आधार पर पांच पूरे वर्षों के लिए विश्लेषण किया था और इस पर भी विचार किया था कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा मानना है कि पांच साल और छह महीने से अधिक जांच की अवधि चुनने से आईटीसी ने अनुच्छेद 2.1 और XIX से असंगत कार्य नहीं किया है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है; प्रथम, जांच की अवधि की लंबाई के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं; दूसरा, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि इसको हालिया आयातों पर ध्यान केंद्रित करने देता है; और तीसरा, बढ़े हुए आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए आईटीसी द्वारा चयनित अवधि पर्याप्त लंबी है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7201)

23. उपर्युक्त को देखते हुए, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए इन तथ्यों और उक्त दर्शायी गई सूचनाओं के स्रोत को ध्यान में रखते हुए 2011-12 से 2015-16 अवधि के डाटा को लिया जाना उचित माना गया है।

### उ. प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता:

24. सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण), नियमावली 1997 का नियम 7 और रक्षोपाय पर डब्लूटीओ करार का अनुच्छेद 3.2 कतिपय सूचना को गोपनीय रखने के संबंध में है। नियम के अनुसार एक इच्छुक पार्टी से यह अपेक्षा नहीं है कि वह ऐसी सूचना का खुलासा करे जोकि वास्तव में कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसके कारण ऐसी पार्टी के व्यवसाय हितों के संबंध में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता हो, जोकि पिल्लक डोमेन में नहीं हो और जिसका खुलासा विस्तारपूर्वक पूर्व में याचिकाकर्त्ता ने न किया हो।
25. मैंने पाया है कि घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना उपलब्ध करवाई है और प्रस्तुत सूचना / डाटा की गोपनीयता की मांग की है। रक्षोपाय नियमावली, 1997 के साथ पठित व्यापार नोटिस सं.एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 06.09.1997 और सं. डी22011/75/2009 दिनांक 21.12.2009 के प्रावधानों के अनुसार रक्षोपाय उपाय के लिए घरेलू उद्योग ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण उपलब्ध करवाये हैं। आगे, घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय गोपनीयता रखे जाने की मांग के कारण प्रस्तुत करें जो उचित प्रतीत होते हैं तथा जब भी दावा प्रस्तुत किया गया इन्हें स्वीकार किया गया।

### ऊ. वर्धित आयात:

26. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 कि धारा 8 ख केंद्र सरकार को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए जाने कि शक्ति के बारे में है तथा यह निम्नलिखित प्रकार से है :
- “ (1) यदि केंद्र सरकार, ऐसी जांच जैसा वह सही मानती है करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि भारत में कोई वस्तु ऐसी वर्धित मात्राओं में तथा ऐसी स्थितियों में आयात हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाए अथवा पहुँचने का खतरा हो, तब, वह, शासकीय गज़ट में अधिसूचना के द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है। ”
27. रक्षोपाय नियमावली का अधिदेश है कि रक्षोपाय उपाय लगे जाने के लिए आयात में बढ़ोतरी पहली आवश्यकता है। अतः रक्षोपाय उपाय लागू किये जाने के उद्देश्यों से यह निर्धारित किए जाने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पादन का आयात “ इस मात्रा में बढ़ गया है, बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण समग्र रूप में अथवा घरेलू उत्पादन के संबंध में किया जाना नियमों में अपेक्षित है।
28. सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क कि पहचान एवं निर्धारण ) नियमावली, 1997 का नियम 2 “ वर्धित मात्रा ” को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है :
- “ (ग ) आयतों में वृद्धि चाहे निरपेक्ष रूप में हो अथवा घरेलू उत्पादन के संबंध में यह “ वर्धित मात्रा ” में सम्मिलित है।
29. आयतों में वृद्धि कि प्रकृति के संबंध में, अर्जेन्टीना – फुटवियर (ई सी ) के मामले में अपीलीय निकाय ने पैनल से अलग यह माना कि आयतों में वृद्धि हालिया, एकाएक , तेज तथा इतनी होनी चाहिए कि गंभीर क्षति पहुँचाए अथवा पहुँचाने की संभावना पैदा करे। प्रासंगिक सार इस प्रकार है :
- “ 131. “ ऐसी वर्धित मात्राओं ” से आयतों की आवश्यकता पूरी किए जाने का निर्धारण केवल गणितीय अथवा तकनीकी निर्धारण नहीं है। अन्य शब्दों में, किसी भी जांच के लिए इस वर्ष उत्पाद का आयात पिछले वर्ष या पाँच वर्ष पहले से अधिक था केवल यह दर्शाया जाना पर्याप्त नहीं है। पुनः, फिर से दोहराया जाता है कि केवल किसी भी वर्धित मात्राओं में आयतों से बात नहीं बनेगी। रक्षोपाय तरीकों को लागू किए जाने के लिए यह अपेक्षित है कि “ ऐसी वर्धित मात्राएँ “ होनी चाहियें जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचे अथवा पहुँचने की संभावना हो तथा रक्षोपाय पर करार के अनुच्छेद 2.1 तथा जी ए टी टी 1944 के अनुच्छेद XIX : 1 (ए ) हमारा मानना है कि दोनों के कथ्य में अपेक्षित है कि आयतों में वृद्धि मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से पर्याप्त रूप में हालिया, एकाएक, तेज तथा इतनी हो जो “ गंभीर क्षति “ पहुँचाए अथवा पहुँचाने की संभावना पैदा करे।

30. यू एस – व्हीट ग्लूटेन – पर पैनल ने “ ऐसी वृद्धित मात्राओं “ वाक्यांश को इस प्रकार व्याख्यित किया है।

“8.31 [जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद XIX : 1 (ए) तथा रक्षोपाय पर करार (“ एस ए ”) का अनुच्छेद 2.1] केवल आयतों में “ वृद्धि ” पर ही बात नहीं करता। अपितु, इनमें संबंधित उत्पाद के आयतों में “ वृद्धि ” की मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रकृति के संबंध में विशिष्ट अपेक्षाएं दी गई हैं। जी ए टी टी 1944 के अनुच्छेद XIX: 1 (ए) तथा एस ए के अनुच्छेद 2.1 दोनों में यह अपेक्षा है कि संबंधित सदस्य के क्षेत्र में कोई उत्पाद का आयत ऐसी वर्धित मात्राओं [ निरपेक्ष रूप से अथवा घरेलू उत्पाद के संबंध में ] में होना चाहिए जिससे गंभीर असुरक्षित पहुँचे अथवा पहुँचने की संभावना हो। अतः, आयत में केवल कुछ भी वृद्धि होना पर्याप्त नहीं है। बल्कि, हम अर्जेन्टीना – फुटवेयर सेफगार्ड में अपीलीय निकाय के निष्कर्ष से सहमत हैं कि वृद्धि मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से हालिया, एकाएक, तेज तथा इतनी होनी चाहिए कि गंभीर पहुँचाए अथवा असुरक्षित पहुँचाने की संभावना हो। ”

31. विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयतों का विश्लेषण उपयुक्त वर्णित क्रान्तिकारी तथा डबल्यू टी ओ न्याय शास्त्र के प्रकार में किया गया है।

#### निरपेक्ष रूप से वर्धित आयत :

32. उपर्युक्त प्रावधानों के प्रकाश में पी यू सी के आयतों के रूख का विश्लेषण किया जा चुका है। भारत में पी यू सी का आयत यू ए ई , मलेशिया, रूस, साउथ अफ्रीका, ओमान, कतर, बहरीन तथा थाइलैण्ड सहित कई देशों से हुआ है। कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया कि जैसा डबल्यू टी ओ के करार में अपेक्षित है आयतों में एकाएक तथा तेज वृद्धि नहीं हुई।
33. इस संबंध में, 2011-12 से 2015-16 की जांच अवधि के आयत डाटा का विश्लेषण निम्न रूप से दर्शाया गया है :

**तालिका – 2**

वित्तीय वर्ष	कुल आयत (एमटी)	प्रवृत्ति
2011-12	2,42,533	100
2012-13	3,08,279	127
2013-14	3,48,889	144
2014-15	3,43,428	142
2015-16	4,21,964	174

34. उपर्युक्त तालिका के डाटा से यह स्पष्ट है कि आयत में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई यथा आयत 2011-12 कि अवधि के दौरान 2,42,533 एम टी से बढ़ कर 2015-16 के दौरान 4,21,964 एम टी हो गया। आगे, मैंने यह देखा कि 2014-15 से 2015-16 की विलकुल हालिया अवधि में आयतों में एकाएक 23% की वृद्धि हुई, जोकि पर्याप्त रूप से बहुत, तेज तथा हालिया थी।

#### उत्पादन के संबंध में आयत :

35. पिछले कुछ वर्षों में भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयत इस प्रकार है:

**तालिका- 3**

वित्तीय वर्ष	कुल आयत (एम टी)	सम्पूर्ण भारत का उत्पादन	कुल उत्पादन के संबंध में आयत (%)
2011-12	2,42,533	19,18,126	13
2012-13	3,08,279	20,72,915	15

2013-14	3,48,889	20,89,929	17
2014-15	3,43,428	25,57,548	13
2015-16	4,21,964	28,15,481	15

36. यह देखा गया कि जांच कि अवधि के दौरान पी यू सी का आयात सारे भारत के उत्पादन के संबंध में बढ़ गया। कुल उत्पादन के संबंध में आयात 2011-12 में 13% से बढ़ कर 2015-16 में 15% हो गया।

क्र. गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति की संभावना का निर्धारण :

37. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 कि धारा 8 ख की उप- धारा 6 (सी) के अनुसार :

“गंभीर क्षति” का अर्थ वह क्षति है जो घरेलू उद्योग की स्थिति को समग्र रूप से काफी नुकसान पहुँचाए ;

38. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख की उप- धारा 6 (डी) के अनुसार :

“गंभीर क्षति की संभावना ” का अर्थ है गंभीर क्षति का स्पष्ट तथा आसन्न खतरा।

39. सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क कि पहचान तथा निर्धारण ) नियमावली, 1997 के नियम 8 के उपबंध के पैराग्राफ 1 के अनुसार :

“ यह निर्धारित किए जाने के लिए कि क्या आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचने कि संभावना है के लिए की जाने वाली जांच में महानिदेशक उद्देश्यात्मक तथा मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है का मूल्यांकन करेंगे। विशेष रूप से, संबंधित वस्तु के आयातों में वृद्धि कि दर तथा राशि एक्सोल्यूट तथा रिलेटिव टर्म्स में बढ़े हुए आयातों द्वारा घरेलू बाज़ार का लिया गया हिस्सा, बिक्री के स्तर में बदलाव, उत्पादन, उत्पादकता क्षमता उपयोग, लाभ तथा हानियाँ तथा रोज़गार। ”

40. उद्योग की स्थिति में समग्र नुकसान के संबंध में, अर्जेंटीना के अपीलीय निकाय- फुटवियर (ईसी) ने, पैनल के उलट यह माना है कि गंभीर क्षति के निष्कर्ष के औचित्य को सिद्ध करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कारक को यह दर्शाना पड़ेगा कि ऐसा प्रत्येक कारक “गिर” रहा है। प्रासंगिक सार इस प्रकर है:

“139. हमारी दृष्टि में यह सिर्फ तब है जब उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए, केवल तब ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को “महत्वपूर्ण समग्र हानि” हुई है। तकनीकी रूप से अनुच्छेद 4.2 (क) की अपेक्षा है कि कतिपय सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन किया जाए और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन किया जाएजाए, तथापि इसके प्रावधान यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि ऐसे मूल्यांकन में क्या दर्शाया जाना चाहिए। स्पष्टतः मामले विशेष के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति पर निर्भर करते हुए ऐसा कोई मूल्यांकन भिन्न मामलों में भिन्न उद्योगों के लिए, भिन्न ही होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारकों के मूल्यांकन के लिए यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्रत्येक कारक में “गिरावट” है। उदाहरणार्थ, एक मामले में बिक्री में, रोज़गार में और उत्पादकता में महत्वपूर्ण गिरावट हो सकती है, जो उद्योग की स्थिति में “महत्वपूर्ण समग्र हानि” दर्शाएगा, और इसलिए गंभीर क्षति के निष्कर्ष को उचित सिद्ध करेगा। एक दूसरे मामले में, हो सकता है कि किसी कतिपय कारक में गिरावट न हो रही हो, परंतु फिर भी समग्र तस्वीर उद्योग को हुई “महत्वपूर्ण समग्र हानि” प्रदर्शित कर रही हो। अतः तकनीकी जांच कि क्या एक मामले विशेष

में सक्षम प्राधिकारी ने सभी सूचीबद्ध कारकों एवं अन्य दूसरे प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन कर लिया है, के अतिरिक्त, हमारा मानना है कि पैनल के लिए आवश्यक है कि वह “गंभीर क्षति” के किसी निर्धारण की अपनी समीक्षा में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1 (क) में दी गई “गंभीर क्षति” की परिभाषा को ध्यान में रखें।

41. तदनुसार, गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की संभावना का विश्लेषण करते समय, नियमों में वर्णित सभी कारकों के साथ-साथ अन्य कारकों जो कि गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए उपयुक्त हैं, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की संभावना का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है, और जो कि उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक कारकों जो कि निम्नानुसार हैं, के प्रकाश में हैं:

क. **उत्पादन:** डीआई का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार है:

तालिका-4

वित्तीय वर्ष	डीआई का उत्पादन (एमटी)	प्रवृत्ति
2011-12	8,77,948	100
2012-13	9,31,324	106
2013-14	10,52,132	120
2014-15	13,61,447	155
2015-16	15,60,141	178

यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन 2011-12 में 8,77,948 एमटी से बढ़कर 2015-16 में 15,60,141 एमटी हो गया।

ख. **बिक्री के स्तरों में परिवर्तन:** निम्न तालिका जांच की अवधि के दौरान बिक्री के स्तरों में परिवर्तन को दर्शाती है।

तालिका-5

वित्तीय वर्ष	आयात (एमटी)	डीआई की बिक्री (एमटी)	सीमित उपभोग (डीआई)(एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्सा (%)			
						आयात लाई	डीआई (सीमित उपभोग को छोड़कर)	डीआई (सीमित उपभोग सहित)	हिस्सा
2011-12	2,42,533	6,27,554	1,02,981	9,45,192	19,18,260	13	33	38	49
2012-13	3,08,279	7,10,800	88,898	9,97,410	21,05,387	15	34	38	47
2013-14	3,48,889	6,71,101	76,202	9,40,006	20,36,198	17	33	37	46
2014-15	3,43,428	6,75,798	69,964	11,34,836	22,24,026	15	30	34	51
2015-16	4,21,964	8,90,587	30,472	10,63,907	24,06,930	18	37	38	44

यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की विक्री 2011-12 में 6,27,554 एमटी से बढ़कर 2015-16 में 8,90,587 एमटी हो गई।

- ग. **बाजार हिस्सा:** उक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि 2015-16 में आयातों का बाजार हिस्सा 15% था जो कि 2015-16 के दौरान बढ़कर 18% हो गया और उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी 30% से बढ़कर 37% हो गया (सीमित उपभोग को छोड़कर) और 34% से बढ़कर 38% (सीमित उपभोग सहित) हो गया। तथापि उसी अवधि के दौरान अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा 51% से घटकर 44% हो गया।
- घ. **क्षमता उपयोग:** डीआई पीयूसी के अलावा विभिन्न एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। डीआई द्वारा निर्मित सभी एल्यूमिनियम उत्पादों की सामान्य सामग्री एल्यूमिनियम हॉट मेटल है। जैसा कि महानिदेशक ने निर्णय लिया है, एल्यूमिनियम हॉट मेटल का प्रयोग एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्माण में चाहे वे पीयूसी हों अथवा गैर पीयूसी हों, किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में पीयूसी के उत्पादन के लिए कोई समर्पित हॉट मेटल क्षमता नहीं है। यदि समस्त हॉट मेटल उत्पादन गैर-पीयूसी वस्तुओं के निर्माण प्रयुक्त किया जाए, तो डीआई के पास पीयूसी के निर्माण के लिए कोई मात्रा नहीं बचेगी। इन परिस्थितियों में, पीयूसी की समर्पित क्षमता (यदि कोई हो) अप्रासंगिक होगी। इसलिए, केवल हॉट मेटल उत्पादन की क्षमता ही प्रासंगिक है और इसे ही क्षमता उपयोग की गणना के उद्देश्य से लिया गया है। निम्न तालिका डीआई द्वारा संस्थापित क्षमता की क्षमता उपयोग को दर्शाती है।

#### तालिका -6

वित्तीय वर्ष	हॉट मेटल की संस्थापित क्षमता	हॉट मेटल का उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2011-12	12,51,400	12,55,713	100
2012-13	12,53,700	13,17,023	105
2013-14	13,54,480	14,10,367	104
2014-15	16,38,728	16,86,726	103
2015-16	20,39,569	19,84,765	97

यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग जांच की पूरी अवधि के दौरान 100% के आस-पास रही है।

- इ. **रोजगार एवं उत्पादकता:** निम्न तालिका पिछले कुछ वर्षों के दौरान रोजगार एवं उत्पादकता दर्शाती है।

#### तालिका-7

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (एमटी)	रोजगार (संख्या) (अनुक्रमित)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (एमटी) (अनुक्रमित)
2011-12	8,77,948	100	100

2012-13	9,31,325	95	112
2013-14	10,52,132	112	107
2014-15	13,61,447	112	139
2015-16	15,60,141	106	168

आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में 2015-16 में रोजगार के साथ-साथ प्रति कर्मचारी उत्पादकता ऊंची है। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में रोजगार में 5% की मामूली कमी है। तथापि, उसी अवधि दौरान उत्पादकता में 21% की वृद्धि हुई है।

च. **लाभ एवं हानि (अनुक्रमित):** 2015-16 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने हानि दर्ज की है। इसको निम्न तालिका में देखा गया है:-

**तालिका-8**

वित्तीय वर्ष	घरेलू लाभ/हानि (रु./कि.ग्रा.) (अनुक्रमित)
2011-12	100
2012-13	11
2013-14	-4
2014-15	154
2015-16	-23

छ. **अन्य महत्वपूर्ण कारक:-**

(i) **इंवेंट्रीज़:** इंवेंट्रीज़ की स्थिति इस प्रकार है:

**तालिका-9**

वित्तीय वर्ष	इंवेंट्री (एमटी) (अनुक्रमित)
2011-12	100
2012-13	91
2013-14	149
2014-15	635

2015-16	197
---------	-----

इंवेंट्रीज आधार वर्ष 2011-12 में 100 प्वाइंट्स से बढ़कर 2015-16 के दौरान 197 गई है। हालिया अवधि के दौरान इंवेंट्रीज 2014-15 में 635 प्वाइंट्स से घटकर 2015-16 के दौरान 197 प्वाइंट्स रह गई। वास्तविक अंकड़ों से मैंने भी यह पाया कि इंवेंट्रीज कुल वार्षिक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बहुत महत्वहीन है। अतः, वर्तमान मामले में क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से इंवेंट्रीज के स्तरों में परिवर्तन अप्रासंगिक है।

**(ii) मूल्य में गिरावट, दमन/मंदी:**

क. मूल्य में गिरावट की गणना 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान हुए आयात की लेंडेड वैल्यू के औसत को ध्यान में रखते हुए की गई है। आयातों की औसत लेंडेड वैल्यू की गणना करते समय भारत एवं अन्य देशों के मध्य हुए विभिन्न व्यापार करारों पर आधारित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन प्रयोज्य सीमा शुल्क छूटी पर भी विचार किया गया है। 2011-12 की विक्री की लागत के संबंध में आयातों के माल उतारने तक के मूल्य, विक्री की प्राप्ति, लाभ/हानि और मूल्यों में कमी में विविधता इस प्रकार है:-

**तालिका-10**

(2011-12 की विक्री की लागत के संबंध में अनुक्रमित)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
विक्री की लागत (अनुक्रमित)	100.0	108.8	110.4	116.8	104.5
शुद्ध विक्री प्राप्ति	105.6	109.4	110.2	125.5	103.2
लेंडेड वैल्यू (अनुक्रमित)	109.2	111.9	116.3	125.4	112.4
लाभ/(हानि) (अनुक्रमित)	5.6	0.6	-0.2	8.6	-1.3
मूल्यों में कमी (अनुक्रमित)	-3.6	-2.5	-6.2	0.1	-9.2

ख. यह पाया गया कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री की लागत और विक्री प्राप्ति की तुलना में पीयूसी आयातों की लेंडेड वैल्यू उच्च है। अतः आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन करते नहीं दिख रहे हैं और मूल्यों में कमी नकारात्मक हैं।

ग. डीआई ने अपने सबमिट प्रत्युत्तर में तर्क दिया है कि मूल्यों में गिरावट वर्तमान मामले में स्पष्टतः धनात्मक है और क्योंकि अलॉय और गैर-अलॉय उत्पादों में महत्वपूर्ण अंतर है, महानिदेशक को इन दोनों की तुलना अलग-अलग करनी चाहिए। तथापि, मैं पाता हूँ कि इसके उलट, डीआई ने अपने पहले के सबमिशंस में दलील दी है कि विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक प्रकार के लिए क्षति का विश्लेषण अलग-अलग करने की आवश्यकता नहीं है और यह कि इसके उलट क्षति का अलग-अलग विश्लेषण गैर कानूनी है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में केस लॉ का हवाला दिया है। मैंने उनकी दलीलों की जांच की है और मेरा मानना है कि जब एक बार अलॉय और गैर-अलॉय कवर करते हुए एकल पीयूसी को परिभाषित कर दी गई है तो क्षति का अलग-अलग विश्लेषण करने का कोई स्कोप नहीं है।

42. हालांकि निरपेक्ष चरों के साथ-साथ कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात में उछाल आया है, जांच की पूरी अवधि के दौरान कारकों जैसे उत्पादन, घरेलू विक्री, डीआई की उत्पादकता में सुधार हुआ है और क्षमता उपयोग 100% के आस-पास रही है। इसके अतिरिक्त, पाया गया है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों का लेंडेड प्राइस घरेलू उद्योग के विक्री मूल्य से अधिक है। इसलिए, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन हो रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है मूल्यों में गिरावट नकारात्मक है। इसलिए,

यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि घरेलू उद्योग को आयात कीमतों के कारण हानि पहुंची है। आयात का बाजार हिस्सा 2014-15 में 15% से बढ़कर 2015-16 के दौरान 18% हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (सीमित उपभोग को छोड़कर) 30% से बढ़कर 37% हो गया और (सीमित उपभोग सहित) 34% से बढ़कर 38% हो गया। इसके अतिरिक्त, मैंने पाया कि आयातों के बाजार हिस्से की वृद्धि दर घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की वृद्धि दर से कम है। दूसरी ओर, बिल्कुल हाल की अवधि के दौरान उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक हो गई जिसके कारण डीआई को क्षति पहुंची।

43. अतः, उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन डीआई की लाभप्रदता में कमी आने के बावजूद उनकी स्थिति में कंतिपय क्षेत्रों में सुधार दर्शाता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच की अवधि के दौरान डीआई को क्षति हुई है पर इसे डीआई को हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की संभावना नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए अन्य मापदंडों जैसे कॉजल लिंक, अनपेक्षित घटनाएं, समायोजन प्लान और जन हित के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
44. जांच की अवधि अर्थात् 2016-17 की प्रथम तिमाही तक, के बाद की अवधि में व्यास प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया था। पश्च जांच अवधि विश्लेषण के लिए 2016-17 (अप्रैल से जून, 16) की अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिए गए आयात डाटा और सत्यापित घरेलू डाटा पर विचार किया गया है। डाटा विश्लेषण इस प्रकार है:

**तालिका-11**

	2015-16	2016-17 ( जून, 16 तक)	2016-17 (वार्षिक)	2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि/कमी (%)
कुल आयात (एमटी)	4,21,964	98,209	3,92,836	-6.9
उत्पादन (एमटी)	15,60,141	4,04,910	16,19,640	3.8
घरेलू विक्री (एमटी)	8,90,587	2,39,624	9,58,496	7.6

45. उपर्युक्त डाटा की जाँच करने पर यह पाया गया कि पोस्ट पी ओ आई अवधि के दौरान यथा 2016-17 (जून, 16 तक ) ( वार्षिक) में 2015-16 कि अवधि के मध्य तथा जून, 16 कि अवधि तक ( वार्षिक ) आयातों में लगभग 6.9% की गिरावट हुई। आगे, इसी अवधि के दौरान उत्पादन में लगभग 3.8% की वृद्धि तथा डी आई की घरेलू विक्री में लगभग 7.6% की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि पोस्ट पी ओ आई अवधि के दौरान डी आई की स्थिति में सुधार हुआ।
46. आगे, पोस्ट पी ओ आई अवधि के लिए एल्यूमीनियम के औसत मासिक एल एम ई मूल्यों की वेबसाइट <http://www.lme.com/metals/non-ferrous/aluminium/> से जाँच की गई तथा यह पाया गया कि जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जनवरी, 2016 से एल एम ई मूल्यों में वृद्धि का रुख था :

**तालिका – 12**

माह	यू एस डी / टन	प्रवृत्ति
जनवरी-16	1479.09	100
फरवरी-16	1535.23	104
मार्च-16	1530.22	103

अप्रैल-16	1563.96	106
मई-16	1,555.96	105
जून-16	1591.83	108
जुलाई-16	1629.47	110
अगस्त-16	1,641.13	111
सितम्बर-16	1589.68	107
अक्टूबर-16	1663.57	112
नवम्बर-16	1735	117

47. उपर्युक्त से पता चलता है कि एल्यूमीनियम के औसत मासिक एल एम ई मूल्य अप्रैल, 2016 के दौरान 1564 यू एस डी के स्तर से नवम्बर, 2016 में 1735 यू एस डी तक ऊपर चढ़ गए, इससे घरेलू उत्पादकों को बेहतर प्राप्तियों का स्कोप बना। आगे, विल्कुल हालिया अवधि के दौरान रूपये के अवमूल्यन ने डी आई की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की।

**ए. निष्कर्ष:**

48. जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई।
49. जांच की अवधि के दौरान डी आई के मार्केट शेयर, उत्पादन, घरेलू विक्री तथा उत्पादकता में सुधार हुआ तथा क्षमता उपयोग लगभग 100% तक रहा।
50. पी ओ आई के दौरान आयातों के लेंडेड मूल्य, घरेलू उद्योग के विक्री मूल्यों तथा विक्री की लागत से अधिक थे तथा प्राईस अंडरकटिंग नेगेटिव थी। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू विक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता में सुधार हुआ। अतः उपर्युक्त डाटा के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के लिए आयात उत्तरदायी हैं।
51. पोस्ट पी ओ आई डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि आयात घट रहा है जबकि डी आई के उत्पादन तथा विक्री में वृद्धि हुई। जबकि अप्रैल, 2016 के दौरान एल एम आई मूल्य 1563 यू एस डी से बढ़कर नवम्बर, 2016 में 1735 यू एस डी तक हो गए, घरेलू उत्पादकों को ऊंची प्राप्तियाँ होंगी। रूपये का अवमूल्यन भी उनके पक्ष में काम कर रहा है।
52. डी आई को क्षति हो रही है परंतु, पी ओ आई में घरेलू उद्योग को न तो कोई भी गंभीर क्षति पहुँची है अथवा गंभीर क्षति पहुँचने कि संभावना दिखाई पड़ती है तथा इस प्रकार रक्षोपाय कानून के अधीन किसी भी सुरक्षा कि अवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्त विधेयक, 2016 के द्वारा 1 मार्च से पी यू सी पर सीमा शुल्क छूटी 5% से 7% बढ़ा कर डी आई को पहले ही राहत प्रदान कर दी है, इससे इनकी स्थिति में और सुधार होगा।

**ऐ. संस्तुतियां:**

53. उपर्युक्त विस्तृत चर्चाओं तथा निकाले गए निष्कर्षों की वृष्टि से, पीयूसी पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाए जाने की संस्तुति की जाती है।

[फा. स. 22011/10/2016/पार्ट-VIII/1684]

विनय छाबड़ा, महानिदेशक

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****[DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS]****(Customs and Central Excise)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2016

**Subject: Safeguard Investigation concerning Imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India- Final Findings-Reg.****G.S.R. 1131(E).**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.**I. PROCEDURE**

1. An updated application has been filed before me on 19/04/2016 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, by (i) M/s. Vedanta Limited –Aluminium & Power, Bhurkamunda, Distt. Jharsuguda-738202, Odisha (ii) M/s Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO), Aluminium Sadan, Core -6, Scope Office Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 and (iii) M/s Hindalco Industries Limited, Century Bhavan, 3rd Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030 for imposition of safeguard duty on imports of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India to protect the domestic producers of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” against serious injury /threat of serious injury caused by the increased imports of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)”. They have also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)”.
2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was verified to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. Having been satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India was initiated vide Notice of Initiation dated 19th April, 2016 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.
3. A copy of the Notice of Initiation dated 19th April, 2016 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and other interested parties as mentioned in the application filed by domestic industry, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Questionnaires were sent to the known interested parties as per the information available with a request to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.

**4.1 Domestic Producers/Importers (M/s):**

- a. Alom Extrusions Ltd.
- b. Alom Extrusions Ltd.
- c. Anam Electrical Manufacturing Company
- d. Anamica Conductors Pvt Ltd.
- e. Anvil Cables Pvt Ltd.
- f. Apar Industries Ltd.
- g. APS enterprises
- h. Associated Aluminium
- i. Bharat Aluminium Company Ltd.
- j. Bhoruka Aluminium Ltd.
- k. Century Metal Recycling Pvt Ltd.
- l. Continental Engines Ltd.
- m. Deepak Cables

- n. Diamond Cables Ltd.
- o. Gloster Cables
- p. Gupta Power Infrastructure Ltd.
- q. Haryana Conductors
- r. Havells India Pvt Ltd.
- s. Hind Aluminium Industries Ltd.
- t. Hindalco Industries Limited
- u. Hindusthan Vidyut Products Ltd.
- v. Hiren Aluminium
- w. J M Industries
- x. J&K Aluminium
- y. Jindal Aluminium
- z. KEI industries Limited
- aa. KJV
- bb. Lumino Industries
- cc. Madras Aluminium Company Ltd.
- dd. Manaksia Ltd.
- ee. Master India
- ff. Masters India Pvt Ltd.
- gg. Metal Powder Co Ltd.
- hh. National Aluminium Company Ltd.
- ii. Noida Aluminium
- jj. North Eastern Cables & Conductors
- kk. Paramount Communications Ltd.
- ll. Polycab Wire Pvt. Ltd.
- mm. Prem Cables Limited
- nn. Rajasthan Cables & Conductors
- oo. Ravin Cables Pvt. Ltd.
- pp. Smita Conductors
- qq. Sterlite Industries Limited
- rr. The Metal Powder Company Limited (Mepco)
- ss. Universal Cables Ltd.
- tt. Valco Industries Ltd.
- uu. Venkateshwara Wires Pvt Ltd.
- vv. Vijay Electricals

#### **4.2 Known Exporters (M/s):**

- a. Alcan Primary Metal
- b. ALBA
- c. ALCOA
- d. Almandi Aluminium Corporation
- e. Alva Aluminium Ltd.

- f. AOSTAR
- g. Bahrain Alloys Manufacturing Co.
- h. BHP BILLITON/ BHP Billiton Limited
- i. BHP Billiton Plc.
- j. CHALCO
- k. Dubai Aluminium Co Ltd.
- l. Euroasian Ventures Fze.
- m. Glencore
- n. IRALCO
- o. Lucky Alloys Limited
- p. MINL Limited (Manaksia)
- q. Nanjing Welbow Metals Co. Ltd.
- r. O&S Metallimport GMBH
- s. Phoenix Steel Mills Ltd
- t. Rio Tinto Inclia
- u. Shanghai Zhengyu Special Alloys
- v. Shenzhen Aida Aluminium Alloys
- w. Trafigura
- x. Unigems Impex Ltd.
- y. United Aluminium Industry Co. Ltd
- z. Universal Corporation

#### **4.3 Government of Exporting Countries/ Foreign Delegation**

- a. Embassy of UAE
- b. Embassy of Malaysia
- c. Embassy of Russian Federation
- d. Embassy of South Africa
- e. Embassy of Oman
- f. Embassy of Qatar
- g. Embassy of Bahrain
- h. Embassy of Thailand
- i. Embassy of Kingdom of Saudi Arabia
- j. High Commission of Australian
- k. High Commission of Nigeria
- l. High Commission of the Republic of Singapore
- m. European Union Delegation to India.

5. Either request to consider as an interested parties or submissions were received from the following parties:

- a. All India Aluminium Secondary Manufacturers Association
- b. All India Non-Ferrous Metal Industries Association
- c. Aluminium Extruders' Council(ALEX)
- d. Associated Aluminium Industries Pvt. Ltd., Mumbai.
- e. Cable & Conductor Manufacturers Association
- f. CMR Nikkei India Pvt. Ltd.
- g. CMR Toyotsu Aluminium India Pvt Ltd.
- h. Dynamic Cables Pvt. Ltd.,

- i. Electrical Centre,
- j. Global Aluminium
- k. GTL Limited
- l. Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association (Ieema)
- m. Indo Alusys Industries Ltd.
- n. JSK Industries Pvt. Ltd.
- o. KEC International Ltd.,
- p. KJV Alloy Conductors Pvt. Ltd.,
- q. Maharashtra Conductor Association
- r. Metal Recycling Association Of India
- s. Opal Industries
- t. Oswal Cables Pvt. Ltd.
- u. Paragon Industries Ltd.
- v. Sargam Metals Pvt Ltd.
- w. Shree Balaji Alumnicast Pvt. Ltd.
- x. South Asia Forum for Energy Efficiency
- y. Sree Sumangala Metals & Industries (P) Ltd.
- z. Sturdy Industries Limited, 28, Ashoka
- aa. Supertech Forgings (India) Pvt. Ltd.
- bb. Thakur Electricals and Engineers Pvt. Ltd.
- cc. Vedanta Limited, Aluminium & Power
- dd. Virgo Aluminium Ltd.
- ee. Western Metal Industries Pvt. Ltd.
- ff. Hero Motorcorp Ltd. Gurgaon
- gg. Endurance Technologies Pvt. Ltd., Aurangabad.
- hh. Rockman Industries Ltd. Ludhiana.
- ii. Trans Solution, Indore.
- jj. Shiv Enterprises, Indore.
- kk. Kalpataru Power Transmission Limited, Gujarat.
- ll. Alco Electrostrips Pvt. Ltd., Bhopal.
- mm. Adinath Electricals Pvt. Ltd., Jaipur.
- nn. Shashi Cables Ltd., Lucknow.
- oo. White Metal Limited, Noida.
- pp. Indian Foundry Organization, Bengaluru.
- qq. JM Industriess, Maharashtra.
- rr. Press Metal Berhad, Malaysia.
- ss. Hydro Aluminium Asia Pte. Ltd. Singapore.
- tt. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Moscow.
- uu. United Company RUSAL, Russia
- vv. Economic Division, Taipei Economic & Culture Centre in India.

ww. Director of Trade Defence, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade, Republic of Indonesia

xx. Ministry of Trade & Industry, Arab Republic of Egypt

6. All the above requests were accepted and the parties who forwarded their submissions were also accepted as interested parties. Some of the interested parties requested for grant of extension for filing their reply to the notice of initiation. Their requests were accepted and they were granted extension.
7. The Domestic Industry has made a request for immediate interim relief by way of provisional safeguard duty in their application filed. In support of the same they have submitted details of their precarious condition based on listed economic parameters showing existence of critical circumstances being faced by them and prayed that in case provisional safeguard duty is not levied they would face irreparable damage, difficult to repair.
8. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was *prima facie* found that there exist critical circumstances which warranted imposition of provisional safeguard duty in order to provide interim relief to the domestic industry from suffering irreparable damage, which could have been difficult to repair.
9. Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 21st April, 2016 and was published in the Gazette of India on the same day i.e. 21st April, 2016.
10. Provisional safeguard duty has not been imposed by the Central Government.

**II. POST INITIATION SUBMISSIONS:** The submissions received in response to the initiation notice but prior to the Public Hearing are summarized as under:

**A. M/s. Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association**

- a. With increase in basic customs duty (BCD), LME and other factors, the landed cost of imports has significantly increased (>13%).
- b. The capacity utilization for the plants other than SEZ have a very good utilisation (approx. 80%). The SEZ plant of Vedanta is meant for exports only and should be excluded from the capacity utilisation figures & injury margin.
- c. In the recent Budget, the BCD on aluminium was increased from 5% to 7.5% which has already put enormous pressure on the downstream aluminium users. The conductor manufacturers are not able to pass on this increased cost because the prices of most of their contracts are firmed up due to tariff based competitive bidding practice being followed for transmission lines.
- d. Petitioners are also beneficiary of depreciation of US dollar vis-a-vis Indian Rupees because their realization is in INR. Exchange rate \$ = INR, which was @ Rs 50 about three years ago, is presently @ Rs 68.
- e. The LME price itself has moved upwards from USD 1500 level to USD 1650, giving much higher realization to the domestic producers.
- f. Aluminium suppliers from China or Middle East are fixing their selling price of Aluminium metal at international price on the basis of LME price. Their prices are not cheaper/ lower as alleged by the domestic producers.
- g. Chinese or Middle East manufacturers have no natural source at their disposal and hence, they import basic alumina whereas the primary producers in India have the natural advantage of local bauxite of one of the best quality and coal.
- h. The salary and wages costs of employees are 40 to 45% higher for Middle East manufacturers compared to India. The importer in India, apart from this, pays customs duty, clearing charges and also bears transportation charges from the port till their factory.
- i. Due to increase in BCD, they are already facing an acute inverted duty structure problem. The finished products are eligible for import on the basis of Project Import under Chapter 98, where the basic import duty is 5% instead of the merit rates of duties on conductors and cables.
- j. The contracts are awarded on L-1 basis and presently Indian manufacturers have started losing their market share to their Chinese counterparts. The duty on aluminium has been increased to 7.5% in addition to duty on steel increased to 10% plus Minimum Import Price mechanism, while the duty on conductor remains at 5% under Chapter 98. Chinese manufacturers have started quoting in India with duty of 5% under Chapter 98.
- k. If safeguard duty is imposed, the Indian conductor & cable manufacturers will be forced to close down as the Chinese & other foreign conductors and cables will flood the Indian market. The

aluminium producers will stand to lose the lucrative domestic market where they enjoy 7.5% protection due to the basic customs duty on imported aluminium and accordingly hike their prices to match import parity.

- l. The costing of Indian conductor manufacturers with present rate of duty on aluminium is already higher than Chinese costing. However, if the duty were to be increased on aluminium due to additional 5% safeguard duty it will make the Indian manufacturers far costlier than Chinese.
  - m. While increased duty on steel has injured the industry, duty increase on aluminium will kill the aluminium demand for power sector in India as imports of finished conductor/cable will increase. This approach will further harm the Indian conductor & cable manufacturers through inverted duty structure, which is contrary to the "Make in India" initiative of the Government of India.
  - n. The duty increase will be considered by the primary aluminium producers while pricing their products for domestic market and the price of finished aluminium products of the domestic manufacturers will be higher than the international market price. This will make the import of finished products more lucrative thereby making the downstream industry unviable and eventually close down affecting employment.
  - o. Any increase in customs duty will also result in higher cost for consumers, mostly, common man. It will have a contagion effect adversely impacting the government agenda of 24X7 power to all and rural electrification program.
  - p. The aluminium producers have not given the correct factual information of their internal working. Their so-called injury is self-inflicted, and not caused due to the imports as alleged by them.
  - q. All the petitioners have recently put up additional capacities much greater than the domestic market. The cost of the interest & depreciation on account of the expansions undertaken primarily for exports is what is actually hitting their financials.
  - r. A huge investment of 1.2 million tonnes of aluminium by Vedanta is specifically for a SEZ. This investment was made quite a few years ago, but has not been effectively operational due to their group's problems on account of bauxite from Niyamgiri mines etc. However, the SEZ's investment and associated costs of interest & depreciation has been considered in their profit and loss.
  - s. The contention that their injury is on account of low prices of imports is not correct because the SEZ was any way meant to be used only for exports. If the capacity of the SEZ was to be removed in the calculation of capacity utilization, then the aluminium producers' capacity utilization would be almost 80% of what has been presented.
  - t. The aluminium producers are not willing to sell on deemed export basis to the conductor & cable manufacturers because they do not wish to match the international LME + Premium prices on duty free prices. Aluminium producers are better off physically exporting, because they get export benefits, while in the deemed export business, they do not get these incentives.
  - u. The conductor & cable manufacturers are forced to import Aluminium on duty free basis. Over 100000 mts. of Aluminium are being imported for consumption of conductors industries meant for exporting the finished products.
  - v. There is an increase in export of conductors, which are classified under HS Code 7604 2910, 7604 1000 & 7604 9000. If the cable industries' exports are included, it can be concluded that the entire import of ingots into India is against exports of aluminium downstream products. Hence, the proposed Safeguard duty should not cover aluminium ingots.
- B. **M/s. Thakur Electricals & Engineers Pvt. Ltd.; Electrical Centre; Sturdy Industries Ltd.; GTL Limited; Maharashtra Conductor Association (SSI)**
- a. They strongly oppose imposition of safeguard duty as the primary producers will be taking the advantage by increasing the price of aluminium ingots in domestic market to the quantum of safeguard duty.
  - b. In last February 2016 budget, government has already increased custom duty on imports of aluminium from 5 to 7.5%. Aluminium primary producers have increased the basic prices of their entire product after the increase in custom duty.
  - c. The custom duty on the finished goods like conductor cable have been kept same. Industry is already facing the heat of import competition. If safeguard duty is allowed on imports then small scale industries will face huge competition from imports of finished goods
  - d. There is very limited quantity of imported aluminium ingots, apart from imports against advance licenses.

- e. Aluminium Primary producers are exporting roughly 25-35% of their material every month and they do not need protection.
- f. Whatever customs duty rate or safeguard duty rate prevailing, primary producers will increase the prices accordingly as per import parity formula. The burden will ultimately come on government especially for electrical sector. The cost of infrastructural projects will also increase drastically as 40% of the share is of aluminium. The SME sector will be badly affected and may fall sick due to exploitation of primary producers of aluminium.

**Additional points made by M/s Sturdy Industries Ltd.**

- g. Indian producers form a cartel & cut their production output & export the material. Aluminium raw material has to be purchased only on advance payment from NALCO/BALCO whereas international suppliers extend credit.
- h. Some special grades are imported only.
- i. Export based units can survive on basis of imports only otherwise they will die. Exports of aluminium secondary products like cables, conductors and rods will reduce drastically.

**Additional point made by Maharashtra Conductor Association (SSI)**

- j. The measure will have negative impact on inflation as aluminium is used in various industries.

**C. M/s Super Tech Forgings (India) Pvt. Ltd**

- a. Aluminium prices in India are at par with the import prices. If import prices increase domestic aluminium producers will also increase the prices creating extra burden on the end users.
- b. All the State Discoms, Power Utilities are the main users of Aluminium products. Automobile sector is one of the largest consumers of Aluminium products. Burden of the duty will directly fall on their industry and indirectly to power sector and automobile manufacturers.
- c. They, the SSI units have very limited resources and 90% funds are used in the procurement of aluminium. Their cost of production will rise due to the increase in prices.

**D. M/s. Jindal Aluminium Ltd.**

- a. They are leading manufacturers of aluminium extrusions in the country and also manufacture aluminium flat rolled products. Their main raw material is aluminium ingots which are sourced from primary producers in India. They also import under the advance licence as per entitlement against the quantity exported.
- b. The allegation that imported material is cheaper is totally incorrect. The domestic prices of aluminium are unreasonably high and more than international prices as the pricing mechanism of primary producers is unfair and is designed in such a way that it exploits the user industry by taking advantage of the monopolistic situation prevailing in the industry. Aluminium is traded all over the world on a common reference which is London Metal Exchange (LME). In India, primary producers adjust their prices based on prevailing (LME rate + Main Japanese Port (MJP) Premium + Customs duty) x exchange rate + clearing and forwarding charges. The cost so derived in US Dollar is valued at highest exchange rate. Although they don't incur both MJP and customs duty, it is an added margin to them. In case, if any of these component changes, the domestic prices of aluminium are increased for the user industry. For an Indian consumer the landed cost of imported material will be same as locally sold material of the petitioners.
- c. In the recent Union Budget the customs duty was increased from 5% to 7.5% and imports have already become costlier by about 3%. The increase has already put enormous pressure, since immediately after this, the aluminium prices were increased by Rs 3500/- MT by all the primary producers of the country. The hike in customs duty increased the cost of aluminium for the users in India and parity between imported and local metal remained the same.
- d. Imposing additional safeguard duty will not help curb imports. The domestic prices will be increased by DI when the safeguard is imposed and the parity between local prices and import prices will again be the same. The safeguard duty will increase the cost of aluminium for Indian users. Imports will continue unabated.
- e. If the petitioners really want to stop/ reduce imports, they've to price their products cheaper to that of the imported material. They've ample scope to do that and earn reasonable profits.
- f. The primary producers are continuously expanding / enhancing their installed capacity almost every alternate or 2/3 years.
- g. Cost of aluminium manufacturing is considered to be the lowest in India as compared with any other country as the main raw material i.e. bauxite ore is abundantly available in the country.

- h. Comparing the prices in the domestic market, producers of primary metal/ aluminium in India are additionally enjoying a privilege of more than 10% in comparison to the landed cost of imported aluminium by way of custom/ import duty, special duty, cess, insurance clearing charges etc. on the international price (LME prevailing in the market).
- i. Petitioners have already benefited due to depreciation of US dollar vis-a-vis Indian Rupees because their realization is in INR. About one year back, one US\$ was = Rs.62 and presently one US\$ is = Rs.67. USD was @ Rs.44.50 in 2011 which has depreciated to Rs 66.50, now. This means at a LME price of say 1500 USD per ton in 2011 giving INR 66,750 per ton realization in 2011 is today giving INR 99750 per ton — a benefit of Rs 33,000 per ton due to exchange fluctuation alone.
- j. LME price itself has moved upwards from USD 1500 level to USD 1670 giving much higher realization to the domestic producers.
- k. The DI has selected the year 2011-12 to misrepresent the current situation. The prices of aluminium in 2011-12 were at its peak at USD 2317 PMT which in comparison was USD 1592 PMT in 2015-16. Aluminium is prone to volatility and fluctuation like any other commodity. The aluminium prices are lower currently but, it's a business cycle and the Domestic Industry should tackle the situation by reducing their cost and increasing operational efficiencies. The base year should be taken as 2007-08 when situation was also similar to prevailing now and no safeguard duty was imposed at that time.
- l. DI's last petition for safe guard duty was rejected by DG, Safeguard in October, 2014, there is no change in situation and the reasons for rejection are applicable even now. They seek safeguards whenever metal prices soften as happened in 2009 & 2014.
- m. The applicants' claim of incurring huge losses is totally incorrect. The petitioners are not considering production of downstream products like extrusions, rolled products, billets, wire rods, alloy ingots etc. which is also part of their production/ smelting capacity. These products are made out of the hot aluminium metal. Considering this, they are achieving 100% of their capacity.
- n. The actual reason for worsening of their financial situation is due to increased incidence of depreciation and interest caused by the mind boggling investment for enhancement of production capacities undertaken.
- o. Petitioners are continuing huge investments in expanding their present capacities further or planning Greenfield projects.
- p. The DI's investment plans are in complete contradiction of the situation projected by them. Vedanta is ramping up the production of their aluminium smelter in Orissa from 5 lacs MT to 8 lacs MT and investing in second smelter in Korba. The decision to ramp up the capacity and planning new capacities also confirms that the current sluggish situation is a temporary phenomenon.
- q. Primary producers first give preference to maximise the production of their downstream products to maximise profits.
- r. The measure will adversely affect the interests of Indian industry as the import of finished aluminium products will increase.
- s. It will give free hand to primary producers to increase the prices of the metal.
- t. In the year 2015-16 the DI has earned huge profits. Perhaps Vedanta and Balco are having some loss but it is not because of aluminium prices but more because of not allotting them bauxite mines by Govt. They have made excessive investment without arranging raw material i.e. bauxite without which they are not able to run their plant and it is lying idle incurring depreciation and interest which is a major reason for their loss. Profits of Hindalco have come down due to high incidence of interest and depreciation since they have added capacity of 10.5 lakh tones of aluminium in last 2 years involving huge investment. If depreciation and interest are taken out of their balance sheet, they will be having large profit.
- u. None of injury factors are applicable in case of aluminium industry in India. Neither production of any applicant has come down nor they are suffering loss nor there is any retrenchment of manpower.
- v. All the producers are working almost to their full capacities. Production of all the producers is increasing every year. Their capacity utilization is more than 90%.
- w. Production quantity of their downstream products like extrusions, billets, rolled products, wire rods, slabs, alloy ingots etc. has to be considered in their total production while considering

- capacity utilization
- x. Hindalco has increased their production capacity by almost 10.5 lakh tonnes in last 2 years, Vedanta has increased their production capacity from 5 Iakh tonnes to 7.5 Iakh tonnes, Balco from 2 lakh tonnes to 3.5 lakh tones to maximize their profits.
  - y. There is no injury to the DI as they are having almost nil inventory at the end of the year and they are able to sell their entire production at market price during the same year.
  - z. Though there is increase in imports but at the same time there is increase in domestic sale of aluminium metal which is much more than the imports. As the DI is able to sell even their increased production, there cannot be any injury to them.
  - aa. Whatever quantity is being imported is mainly against advance licence by the user industry.
  - bb. The measure will cause serious injury to many downstream manufacturers who are dependent for their existence on the aluminium producers and will also render many small and medium aluminium units, sick, increase unemployment and ultimately make aluminium products expensive for general public.
  - cc. LME prices are increasing day by day. LME price was USD 1450 PMT before 6 months and has already touched USD 1675 PMT at present.
  - dd. If safeguard duty is imposed, imports of downstream products such as extrusions, rolled products, utensils, cables, conductors etc. will increase since import of these items will be cheaper than import of aluminium ingots. This will force thousands of industries to close down their shutters and lakhs of employees will be thrown out of the job.
  - ee. Aluminium utensils are used in large quantities by middle class, lower middle class and poor people in the villages and rural areas. If safeguard duty is imposed, the price of aluminium metal will go up considerably.
  - ff. Manufacturing cost of aluminium in India is the lowest in the world; DI is having reasonably good profit and they do not require any protection.
  - gg. Primary aluminium companies, all over the world are also faced with the same difficult situation.
  - hh. The data relating to production and also installed capacities are factually incorrect/false and seem to have been considered for part of the products manufactured by the applicants with an intention to mislead. The applicants have selectively considered HS code 7601 only as PUC whereas they also produce rolled products, foils, extrusions also using bulk of their smelting capacity for these products.
  - ii. The capacity utilization should be calculated by taking the quantity of hot metal produced and quantity of only ingots should not be considered to arrive at correct figures of capacity utilization.
  - jj. Primary producers first give preference to maximise the production of their downstream products such as aluminium rolled products, foils and extrusions etc. to earn more profits. Thus, no "injury" is caused to them by increased imports. The Indian consumers are compelled to import more, as very less quantity of ingots is made available to them by the applicants. Consumers in India have to face shortage of metal for first 10-12 days of every month.
  - kk. The production of the petitioners has actually increased and not decreased, as claimed. Most of them are operating at close to 100% of the installed capacity & there are no grounds for "serious injury".
  - ll. DG, Safeguard should investigate the production records of the petitioners to verify the accuracy of production and utilization of capacity given in the petition.
  - mm. The installed capacity shown by the petitioners is not fully in operation. Vedanta's 1.25 million tonne smelting plant in SEZ Jharsuguda is not fully on stream due to power and alumina issues.
  - nn. Nalco, one of the leading players in the industry has not joined them in the petition.
  - oo. In a situation where the price of a commodity is uniform, all over the world, the buyer is free to source his requirements from anywhere.
  - pp. Whenever, there is improvement in LME prices or foreign exchange rates, the prices by the applicants are also raised although their cost remains the same.
  - qq. This increase in LME prices has already given the DI considerable benefit.
  - rr. The petitioners have complained of the declining Premium which affected their realisations but the reality is that premium which shot up unreasonably has gradually settled to its normal level. Even though primary metal is produced in India itself, still this premium is added to LME prices to arrive at selling price though it has no relevance to manufacturing cost.
  - ss. The profitability of primary producers is comparable with Middle East producers.

- tt. The petitioners have complained of sharp erosion in profitability due to lower realisations and sudden increase in imports leading to underutilized capacities.
- uu. Hindalco is making reasonable "Profits before depreciation, interest and tax" and is increasing their capacities regularly. The actual reason for depressed profits in case of Hindalco is increase in depreciation and interest by 178% since 2011-12 due to massive expansion of capacities. It's also admitted by the company that their newly commissioned Mahan smelter and Aditya smelter are running at full capacity.
- vv. In case of Vedanta their capital employed in the aluminium segment alone increased by huge 234% in increasing the capacities which has significantly increased their depreciation and interest.
- ww. Balco has decided to restart the rolling mill which was shut down 11 months back only due to low LME prices. This indicates to improving situation so far as prices are concerned that present condition is not as gloomy as being projected.
- xx. Nalco which has progressed well with a systematic and disciplined expansion strategy is not affected by imports and is making reasonable profits.
- yy. None of the producers have retrenched any employee in last 2 decades due to reduction in production.
- zz. Demand of aluminium metal is growing at the rate of 8-10% per annum and DI's production is also growing. Their level of employment has also kept on increasing which is confirmed by data furnished by them.
- aaa. The cost of production in Middle East & their prices are not low as claimed. They import alumina and hire manpower at a very high cost which are major cost elements in manufacturing aluminium. The primary producers in India have the natural advantage of local bauxite of one of the best quality. The suppliers from Middle East are also fixing their selling price at international price on the basis of LME as is done by Indian producers.
- bbb. The slowdown and sluggish market situation affects all the units in aluminium segment, be it primary producers or downstream industry. It has affected China too.
- ccc. The import of aluminium into the country by the secondary aluminium manufacturers and processors is mainly against their export entitlements. User industry is forced to import aluminium against their Advance License, since the petitioners don't want to supply aluminium against these licenses and quote much higher prices compared to imports.
- ddd. There cannot be an injury to DI as there is small increase in imports.
- eee. Price undercutting: Unalloyed ingots & alloyed ingots are not identical products. Alloyed ingots are sold at higher price and should not be taken for comparison purpose. Alloy ingots are not manufactured by the applicants and should not be included in the total imports.
- fff. There is a marginal increase of 78% in last 4 years in imports which is not excessive. The petitioners' own production has also increased by 76%, their domestic sales have increased by 40% and exports increased by 336%.
- ggg. The request for imposition of safeguard duty is with intention of making extra profits by increasing the local prices.
- hhh. Petitioners have claimed of rising imports from China but the import from China in 2015-16 was a mere 2.68%.
- iii. The submitted data relating to production is false. The production of hot metal & quantity despatched, stock of the finished goods at the end of each financial year, production capacity, cost of manufacturing and selling prices/net realisation and LME Price+ premium may be verified. Total production of DI may be compared with the total import.
- jjj. The applicants are exporting under a pre-planned long term strategy for various reasons and are not forced to exports to liquidate their inventories as claimed. In exports they have better realization since they are getting export benefits like MEIS as well as EPCG benefits. Hindalco transfers a major portion to its associate company Novelis. The existing capacities of Indian manufacturers are much more than the domestic demand.
- kkk. The applicants have not given many important data or given indexed data in the name of confidentiality. The financial position has been indexed to the figures of the year 2011-12 which cannot be treated as bench mark.
- lll. Figures of opening and closing stocks, cost of sale has all been indexed to confuse the affected parties.
- mmm. The applicants have claimed a capacity utilization of 47% -48%. Including the quantities of

- captive consumption gives a capacity utilization of 64.8 % in 2014-15 and 63.7% in 2015-16. A thorough enquiry should be conducted to ascertain the actual capacity utilization of the applicants.
- nnn. The applicants have themselves claimed increases in employment and productivity.
- ooo. The industry which increase the wages by 150%, keep hiring additional employees, has no unutilized capacities, can't be treated as under threat.
- ppp. The financial situation has been shown on a declining trend at many places by bench marking it to year 2011-12 to mislead. The profitability of DI has slightly been affected with relation to year 2011-12 due to global recession and has nothing to do with imports.
- qqq. The downstream industry is passing through one of the worst phase due to low demand, rising interest cost, depreciation of rupee and global recession and squeezing margins.
- rrr. All the producers are able to sell entire quantity of metal produced by them in a year.
- sss. Safeguard duty will be counterproductive for revival of economy; will increase costs of all aluminium products; will not stop import of aluminium ingots; will increase import of secondary products like extrusions, rolled products, foils etc.
- ttt. As per a news item released by Aluminium Association of India about financial results of NALCO, a leading manufacturers of aluminium metal in the country, Nalco has remained profitable by successfully handling the market downturn; have achieved 14% higher production compared to the previous year 2014-15.
- uuu. Hindalco has posted strong March quarter results driven primarily by its aluminium business. Company's capacity expansion is done and it will become free cash flow positive after several years. Its Earning Before Income Tax was higher compared to preceding quarters. They have achieved highest ever production and plants are running at full capacity. Profit has gone down due to increase in depreciation and finance cost by 30%. Net Profit for quarter IV of FY 2016 was 113% higher vis-a-vis quarter IV of FY 2015. PBITDA was higher by 49% in Quarter IV as compared to quarter III of FY 2016. M/s Hindalco has achieved Rs.607 crores Net profit after Tax despite low LME price.

**E. M/s. Indo Alusys Industries Ltd.**

- They are extruders & manufacturers of aluminium profiles.
- The petition has been filed with self motive to reap all profits of secondary manufacturers of aluminium, who are completely dependent on them and are struggling for their survival in vulnerable and volatile market conditions.
- The measure will become a cause of sickness for many aluminium units and making aluminium products expensive for consumers, resulting unemployment and inflation.

**F. M/s Paragon Industries Ltd.**

- They are manufacturer of aluminium rolled products including aluminium foils
- Any additional duty will cause serious injury to all downstream manufacturers of aluminium and will result in closure of many small & medium aluminium units.
- This will increase in unemployment and will expedite more and more imports in the country.

**G. M/s. Opal Industries**

- Unwrought aluminium producers are keeping substantially high price than import price by creating artificial shortage.
- The domestic pricing formula is LME price + Premium + import Duty + import cost + 3 to 4 %. In 2013, 2014 upto mid 2015 premium was charged at USD 300 to USD 450 and they earned hefty margin. If they sell at parity or 2% less than formula, there is no scope of unwrought aluminium import.
- Now LME is high and import duty is at 7.5 %. Prices have been increased of unwrought aluminium by 13% compared to December, 2015.
- The DI is selling unwrought aluminium above production cost and is exporting cheaper by 18 % than domestic price.

**H. M/s. Cable and Conductor Manufacturers Association of India**

- They represent mainly small & medium sized industries in the country engaged in manufacture of cables and conductors for power transmission, distribution lines and projects under constructions.
- The petition for duty protection was filed by the private sector companies. M/s National Aluminium

- Company Ltd., (NALCO), being Public Sector undertaking has not joined to the petition.
- c. The petition was filed in February, 2016 and was updated and filed on 19th April, 2016. The recommendation was given for 5% Safeguard duty within few days of revision in application without hearing the user industry although petitions were rejected in the past in two instances.
  - d. The data submitted by the petitioners are far away from the truth and not reliable to take hasty decision for recommendation.
  - e. The user industry have already faced increase of 2.5% customs duty in the last Union Budget which has already put enormous pressure on the downstream aluminium users, particularly their members who have booked orders from State Electricity Boards and PGCIL on long term firm price basis. The increase cannot be passed on due to tariff based competitive bidding practice being followed for transmission lines.
  - f. The petitioners are also benefiting from the depreciation of Indian rupee against US Dollar. Exchange rate per one USD was Rs. 50 about 3 years ago, and now it has risen to Rs.67 per 1 US dollar. The LME price of USD 1600 per ton 3 years ago = Rs. 80,000/ Mt., will realize Rs.107, 200/Mt. which shows no effort gain of Rs. 27,200/Mt.
  - g. The aluminium is sold in international market at price fixed with reference to LME, hence the argument of import made by domestic users at cheaper price is baseless.
  - h. Chinese and Middle Eastern countries have to import bauxite or alumina and coal (basic raw materials for making primary aluminium) due to not having resources in their countries, as opposed to huge resources available in India at disposal of the domestic smelters/petitioners.
  - i. The wage structure in China and Middle Eastern countries is also much higher than India by 40% and in spite of this the suppliers in China and Middle Eastern countries are fixing their price of aluminium metal at international price on basis of LME index. Their price is not lower as alleged by the Petitioners. The importers in India have to pay customs duty and clearing charges at the port of import
  - j. The conductor manufacturers are also facing inverted duty structure issue. The finished conductor is eligible for import on the basis of Project Import under Chapter 98, where the basic import duty is 5% instead of merit rate of duty on conductor/cable. This industry is qualifying for contracts on L1 basis. Under Project Imports, the overseas competitors get advantage of inverted duty and qualify L1 status depriving domestic conductor manufacturers on uneven level playing field. Rate of 7.5% customs duty itself is a big challenge to be met to face competition.
  - k. The additional 5% safeguard duty burden, if imposed, will kill the domestic conductor industry and flood of conductors and cable will start coming in from China and other countries.
  - l. The petitioners are pocketing the customs duty and addition duty protection whatsoever given will also go in to their pockets.
  - m. Comparing international price and domestic smelters selling prices show that the net realization value including Customs duty and un-conditional discounts being offered by smelters in India is lower than domestic smelters selling prices.
  - n. Proceeding carried out by DG Safeguards is in violation of principle of Natural justice. DG Safeguards has not even waited for the mandatory period to lapse and issued its preliminary Findings in haste. This deprived the interested parties of their right to participate at the critical stages of the investigation.
  - o. Directorate General (Safeguards) did not have complete and comprehensive information when the Preliminary Findings was issued.
  - p. Domestic Industry had sought undue and unwarranted protection in years 2009 & 2014 and the proceedings were terminated/ safeguard duty was not recommended. There is no change in the overall economic and financial condition of the Applicants.
  - q. The Directorate General (Safeguards) could not have proceeded with the investigation and come out with Preliminary Finding as no adjustment plan was filed by DI.
  - r. The Preliminary Finding is silent on the issue of public interest. Aluminium is one of the most important raw materials used by the core sectors of the economy i.e., cable & conductor, automobile, consumable, utensils, packaging, & housing sectors. Any action of the Government to make aluminium expensive will adversely affect the downstream industries.
  - s. Power sector consumes 40% of the total consumption in India. Aluminium constitutes more than 70% of the total cost of cable & conductors. Any increase in cost of basic raw material by way of imposition of safeguard duty will adversely affect the viability of this sector & competitiveness of Indian manufacturers of end products. Cost increase in power would impact all. Imposition of

safeguard duty will adversely affect more than 3000 cable & conductor manufacturing units who are employing about two million employees.

- t. As value addition of most of the downstream products is quite low, imposition of safeguard duty would result in increase in imports of the finished downstream products thereby closing down the downstream industries.

**I. M/s. Global Aluminium Pvt. Ltd.**

- a. They are leading aluminium extruders having value added facilities like anodizing, powder coating and semi fabrication.
- b. The application by the primary produces has been filed with an ulterior motive to earn unreasonable and undue profits by causing serious injury to many downstream manufacturers of aluminium that are dependent for their existence on these large scale aluminium producers.
- c. Any extra imposition of safeguard duty will render many small and medium aluminium units sick, increase unemployment and ultimately make aluminium products expensive for general public.

**J. M/s. Virgo Aluminium Ltd.**

- a. They are manufacturers of aluminium rolled products.
- b. The measure will result in serious injury to many downstream/ secondary manufacturers of aluminium rolled products.
- c. They are having dependence on non alloyed aluminium and large scale primary aluminium producers.
- d. In the current Budget, the Government has already increased customs duty by 2.5% on non alloyed aluminium.
- e. By introducing extra safeguard duty, it will make many small and medium aluminium units below par, increase unemployment and ultimately make aluminium products expensive for general public.

**K. M/s. Manaksia Aluminium Company Limited**

- a. They are secondary manufacturers of aluminium flat rolled products including value added products like pre painted aluminium coils.
- b. The petition is a blatant attempt by DI to reap undue and unreasonable financial benefits by causing serious injury to the operations of secondary aluminium manufacturers who source their basic raw material from them.
- c. The measure will drive numerous secondary aluminium manufacturers out of business, increase unemployment causing undue hardship to consumers of aluminium products due to unnecessary hike in aluminium prices.
- d. The secondary aluminium manufacturers are suffering due to the low rate of import duty on aluminium flat rolled products which allow cheap imports of bare and pre-painted aluminium coils, from countries like China to flood the Indian market.
- e. Presently, aluminium scrap is subject to a basic custom duty of 2.5% which was 0% earlier. This has contributed to substantial additional input costs for secondary manufacturers, who are presently suffering cash losses.

**L. M/s. Aluminium Extruders' Council (ALEX)**

- a. A similar and detailed investigation was done in 2014 and in the final finding dated 7.10.2014 wherein safeguard duty on the imports of "Not alloyed Ingots of Unwrought Aluminium" was not recommended.
- b. The real intension of the petitioners is to increase profit from domestic sales.
- c. The Indian producers unlike the practice worldwide have an Indian price for aluminium. Also, unlike the LME based pricing which is market driven and transparent, the Indian prices are declared by the producers.
- d. Petitioners calculate the domestic price based on the landed cost of imports. Therefore, the safeguard duty is really meant to increase the prices in India and will impact the Indian industry including the extrusion industry and the end consumers.
- e. Though petition states that the consumers of the petitioner companies are in an industry where they operate on the principles of "pass through", they do not follow the LME + premium pricing followed by the entire Aluminium industry worldwide.
- f. In India the pricing is based on the domestic rupee price including import duty of 7.5%. Thus, every

- increase in import duty directly adds to the profitability of the petitioners. Why should the petitioners charge custom duty for their domestic sales.
- g. The safeguard duty petition is only made for increasing the petitioners' profit from domestic sales.
  - h. Petitioners have admitted that their profitability has been reduced due to the fall in the LME price and the premiums, and not because of competition from the import of PUC.
  - i. The petitioners have specified that the reduction in the LME and the premiums are on account of the global demand supply situation which impacted their pricing and not due to the PUC on which they claim a safeguard duty.
  - j. Excess production globally at 1.3 million is about 2% of the world production which is not a very big number.
  - k. M/s Vedanta's Jharsuguda Plant- 2 with 1.25 million ton capacity is located in a SEZ has also been included while calculating the total India capacity. This 1.25 million ton plant is not operational because Vedanta has no bauxite and alumina to run this plant.
  - l. The data furnished in the petition shows that the indexed cost for domestic sales is higher at Rs.131 compared to Rs.95 for exports. The cost of goods for exports should have additional cost on account of the packaging and shipping cost.
  - m. The index cost of exports by the petitioners is shown as Rs. 95 whereas the indexed basic cost for imports is shown as Rs. 125 (without duty). This means that the petitioners are exporting at much lower prices to the customer out of India.
  - n. Calculation of price undercutting is not a valid calculation as there is no separate calculation for large volume of duty free imports.
  - o. Production of secondary aluminium which is done by using scrap has been included to calculate the market share of the petitioners though scarp imports do not fall under the PUC.
  - p. Exports from India for the PUC increased from 147K in 2011-12 to 644K in 2015-16, the captive consumption of the petitioners has reduced by almost 70K MT in 2015-16 compared to last year.
  - q. M/s Nalco are not a part of this petition.
  - r. The condition of the extrusion manufacturers is very precarious; as many as 40 extrusion units have already closed down. There is a threat of imports of extrusions from China into India. The safeguard duty on PUC will increase the cost of production in India and sales of extrusion in India will be at higher cost compared to cheaper imported extrusions due to the duty difference.
  - s. The measure will lead to a situation where large number of extruders will have to close operation and lakhs of people will become jobless.

#### M. M/s. Western Metal Industries Pvt. Ltd.

- a. They manufacture aluminium slugs falling under 76169990 of Customs Tariff required for packing which is a secondary product made from unwrought aluminium.
- b. Safeguard duty, if imposed on unwrought aluminium, may lead to increase in imports of intermediary products, made from unwrought aluminium, resulting in serious injury to the domestic industry. Safeguard duty, if imposed on unwrought aluminium, should also be applicable on imports of intermediary products made from unwrought aluminium, helping the domestic industry to survive.
- c. Vedanta Limited is a unit situated in SEZ and is permitted to supply limited quantity in the Domestic Tariff Area (DTA). It needs to be proved by the Applicant that all of them together satisfy the definition of Domestic Industry.
- d. The production quantity of the applicants has increased over a period of time and their share in the domestic market has also went up from 28% to 31% in the year 2016.
- e. The Applicants are the dominant producers of the commodity under investigation, thus, alleged injury to domestic industry does not justify imposition of safeguard duty.
- f. Reduction in profitability is a function of several factors and thus cannot be the only aspect on the basis of which injury to the domestic industry is ascertained. Several times, availability of incentives on export and period of incentives could temporarily affect the profitability.
- g. The figures provided, whether before or after tax, also need to be clarified, rather both figures should be provided by the Applicants.
- h. The issue of cooling down of Chinese economy or reduction in fuel cost of Middle East manufacturers cannot be considered as a cause of injury.
- i. Each country has certain advantages and disadvantages. Bauxite may be available in ample quantities in India, but is to be imported by the Middle East for manufacture of the commodity.

- j. China also imports substantial quantities of aluminium and thus the cooling down of the Chinese economy straightaway cannot result in increase in exports from China so as to cause an injury to domestic industry. In case any such instances are there, it should be treated as a dumping activity.
  - k. If the incentives are given by the various Provincial Governments of China regarding electricity the enquiry should be under Section 8C or Section 9 of the Customs Tariff Act and not for imposing safeguard duty.
  - l. The price of the commodity under investigation is based on prices prevalent on the London Metal Exchange (LME), and cannot be influenced by a manufacturer.
  - m. In India the price of the commodity under investigation are decided by the entire domestic industry, based on the prices prevalent on LME, exchange rates prevalent from time to time, premium claimed by them and level of duties, on import of the commodity.
  - n. When the metal market was and would be at the peak, the benefit is already received or can be received and the reduction in profitability cannot be a cause for levy of safeguards duty.
  - o. Prices show a certain "cyclical" behaviour throughout the world commodity markets. If, for a particular period, the commodity prices are at a lower level, such cause cannot be treated as an injury.
  - p. In the FY 2014-15 and 2015-16, aluminium (not alloyed) has been imported up to 343 tons and 432 tons respectively. Similarly, there is export of this commodity.
  - q. The claim of the Applicants that they control 50% of the domestic production needs to be confirmed.
  - r. The exact nature of alleged injury, its seriousness and its effect have not been demonstrated/ proved by the Applicants.
  - s. The steps planned by DI and effects thereof on their profitability, upgradation of technology, benefit of scale of manufacture, reduction in overheads and implementation timelines need to be made public.
  - t. The confidentiality claim, if any, of the data or information is not justified, the Applicants being "Public Limited Companies".
  - u. In case the safeguard measure is taken, the scope of the enquiry may be expanded by including all products which are covered by Chapter 76.
  - v. The safeguard duty will result in increase in prices of the domestically sold Aluminium and thus manufacturers of products from aluminium would suffer substantial and irreparable injury by surge/increase in the import.
  - w. The effect of imposition of Safeguards Duty for the second stage purchasers/manufacturers should also be considered.
- N. **M/s. Century Metal Recycling Private Limited; Sree Sumangala Metals and Industries (P) Ltd.; Shree Balaji Alumnicast Pvt. Ltd.; Sargam Metals Private Ltd.; CMR Nikkei India Private Limited; CMR Toyotsu Aluminium India Pvt. Ltd.**
- a. They are one of the producers of aluminium alloys in India.
  - b. There is significant fall in London Metal Exchange (LME) price from \$2204/MT in Feb'12 to \$1535/MT in Feb'16. The fall in prices has been exacerbated by global demand slowdown, notably China, with surplus global capacities.
  - c. As there are opportunities available for increasing the per capita consumption, India has become the target for supply of aluminium alloys and there is a notable surge in imports of aluminium.
  - d. More than 5L MTPA of aluminium alloys is consumed in India in various castings for automobile component manufacturing.
  - e. Aluminium alloys are imported under HS code 7601 and compete with the downstream alloy manufacturers in the country.
  - f. Aluminium alloy imports from Malaysia, Thailand and Middle Eastern countries hurt the viability of domestic alloy manufacturers. It is essential that these imports should be stopped and domestic manufacturing should be encouraged.
  - g. The measure will support all the alloy manufacturers in the country and will result in domestic growth & generate more employment opportunities. Action for the support of both primary and downstream industry may be taken.
- O. **M/s. All India Aluminium Secondary Manufacturers Association**
- a. The Association represents Small Scale Industries (SSI) involved in manufacturing various aluminium products such as aluminium utensils, extrusions, aluminium closure stock, converted foils for packaging and aluminium hardware items from Telangana and Andhra Pradesh states.
  - b. The imposition of safeguard duty/ provisional safeguard duty will be against the interest SSI units

- involved in manufacturing secondary aluminium products.
- c. This will increase the cost of raw material being consumed by their member industries considerably.
  - d. It is surprising to note the Government is imposing safeguard duty only on primary aluminium metal and not on all products of aluminium.
  - e. Primary producers of aluminium in India are already having large profit. They are able to sell the entire quantity produced by them during the same year. Their production of aluminium is increasing every year.
  - f. Government has already increased import duty on aluminium metal by 2.5% ad valorem in the budget for 2016-17.
  - g. The Rupee has depreciated by nearly 10% in last 6 months from Rs.62.50 to Rs.66.50 per dollar. Due to this reason also, primary producers have increased price of aluminium metal.
  - h. Price of aluminium is being fixed based on the LME prevailing in the international market. Import of aluminium metal also takes place based on the LME price prevailing in the international market. Thus, there cannot be cheap imports of aluminium metal in the country.
  - i. Price of aluminium metal has gone up by USD 235 PMT between December, 2015 and April, 2016 and due to this primary producers have already increased price of aluminium metal by Rs.7,500 PMT in April, 2016 and is likely to go up further by Rs.5000 PMT. Hence, the total increase will be about 10%.
  - j. SSIs involved in manufacturing secondary aluminium products will be hit very hard due to the price increase. If Govt. levies safeguard duty, it will kill the SSIs involved in manufacturing various aluminium products in the entire country who are giving employment to lakhs of people.
  - k. They suggest that Govt. should levy export duty on export of aluminium metal from the country.
- P. **M/s. Metal Recycling Association of India (MRAI); South Asia Forum for Energy Efficiency (SAFEE)**
- a. MRAI is a national association, representing the interest of India's ferrous and non-ferrous metals recycling industry with over 510 members, including most regional metals trade associations. Their collective strength comprises of over 7000 small, medium and large enterprises, directly & indirectly employing 17.5 lakh people.
  - b. SAFEE was established as a joint initiative of World Energy Council (WEC) — Indian Member Committee and the Energy Saving Commission of World Foundry Organization (WFO), UK.
  - c. The aluminium recycling industry is engaged in the production of aluminium alloy ingots for the automobile sector.
  - d. They welcome the notice of initiation of safeguard investigation.
  - e. Recycling of aluminium scrap saves energy and protects environment. The energy consumption in recycling is only 500 units per ton compared to 14000 units per ton for production of primary aluminium. There are practically no carbon emission in recycling. The industry has been found by UNFCCC to be eligible for carbon credits under Clean Development Mechanism Scheme (CDM) vide UNFCCC Project 10166.
  - f. There are more than 150 domestic manufacturers of aluminium alloy falling mostly in MSME sector with a capital investment of more than Rs.20,000 crores and providing direct employment to approx. 100,000 workmen.
  - g. The sector is producing nearly 500,000 tons of aluminium alloy for automotive use and 180,000 tons of deox for the steel sector for deoxidation in steel melting. Most of the critical auto components, which were being imported earlier, are now being manufactured in India due to the manufacture of automotive aluminium alloy within the country.
  - h. The import of aluminium alloy ingot falling under HS 760120 is allowed duty free from Thailand and Malaysia under FTAs with these countries. Coupled with the fact that there is an import duty of 2.5% on import of the primary raw material for manufacture of aluminium alloy ingots, namely aluminium scrap falling under HS 76020010 has resulted in huge financial losses to the manufacturers of aluminium alloys.
  - i. A largest manufacturer of aluminium alloy, has suffered a decline in its PBT. Two other companies established in joint venture collaboration with two leading Japanese companies, have suffered huge losses, while one company is completely bankrupt. Other major players in the aluminium alloy industry are also suffering a decline in their profits and the overall profitability of the industry has gone down.
  - j. The huge surge in imports of aluminium alloy ingots from various countries including duty free

imports from Thailand and Malaysia have increased tremendously on year-on-year basis by almost 55%.

- k. They support the levy of safeguard duty of 5% on PUC and they are also in favour of imposition of provisional safeguard duty.
- l. Aluminium alloy (HS760120) is used for manufacture of automobile components as it increases fuel efficiency and reduces vehicular emissions. It is generally produced by recycling scrap and is both energy saving and environment friendly. Many of their members deliver aluminium alloys in liquid form which methodology has been approved by UNFCCC under Clean Development Mechanism and is eligible to Carbon Credits.
- m. The aluminium alloy industry suffers from inverted duty structure since the basic raw material namely, aluminium scrap attracts import duty of 2.5% while the finished goods can be imported duty free from FTA countries like Thailand and Malaysia. Also, China recently introduced 30% VAT rebate on recycled aluminium alloy which effectively gave a cost reduction of at least 2% to the Chinese companies. Thus, the Indian manufacturer suffers a cost disadvantage. The imposition of 5% safeguard duty on aluminium alloy ingots (HS 7601) is essential to provide a level playing field.
- n. Fear that if the price of aluminium alloy is increased due to levy of safeguard duty, it might lead to greater import of automobile components is wholly misplaced. All major automobile OEMs negotiate prices directly with indigenous manufacturer for aluminium alloy. Any possible increase in domestic prices of aluminium alloys post levy of safeguard duty, would be a pass through for the auto component manufacturers. Rather, it will lead to much better and bigger indigenisation of automobile components.
- o. While all types of aluminium alloy for auto and other engineering applications are being manufactured in India, such as ADC12, AC4B, etc. yet aluminium alloy (A356.1) required for production of aluminium wheels is not produced in India. The levy of safeguard duty on aluminium alloy will ensure that adequate technology for manufacture of aluminium alloy A356.1 is developed indigenously.
- p. The overall profitability of the industry has gone down from 3.36% PBT in 2012-13 to less than 0.5% PBT in 2014-15 to even lower/ negative PBT in 2015-16 due to the fact that 2.5% import duty on aluminium scrap was introduced from May 2013 coupled with the fact that aluminium alloy is being dumped from FTA countries and also from China due to increased fiscal incentives by local governments. Aluminium scrap prices are not related to fluctuation on LME as scrap prices are not controlled by LME.
- q. The extremely low / negative profitability in the industry and the fact that most of the manufacturers are in MSME Sector, is creating stress on the large bank loans advanced to the industry.
- r. The proposed provisional safeguard duty be levied for 200 days immediately to save the domestic industry from closure.

**Q. M/s. All India Non-Ferrous Metal Industries Association**

- a. They represent the non-ferrous industries in various forums.
- b. The safeguard investigation does not include cables and conductors which consumes the largest quantity of aluminium in the country. This will increase the raw-material cost for cable and conductor manufacturers while offering no protection on finished goods.
- c. This discourages the downstream manufacturing sector which generates the most employment in the aluminium industry.
- d. It will encourage import of finished goods by putting the local downstream manufacturer at a significant disadvantage and making it uncompetitive.
- e. It is mentioned in the safeguard investigations that Middle East smelters get advantage on account of cheaper energy sources. However, in a recent interview given by the CEO of Vedanta Ltd., one of the petitioners, he has clearly mentioned that India enjoys tremendous advantage of producing aluminium due to ready availability of bauxite as well as access of cheap coal to generate power. Maybe due to local issues these may not be readily available as on date to some plants, this however should not be the reason for which the downstream industry in India has to pay more.
- f. Imposition of safeguard duty will amount to penalizing the companies who process aluminium in India.
- g. One of the petitioners, M/s. Vedanta Ltd. has put up an aluminium plant in a SEZ zone. This capacity has to be removed from the calculation of domestic installed capacity. The SEZ plant is only for

- export and hence cannot be included in the domestic capacity.
- h. The export of aluminium being more than the import of aluminium, India is a net exporter of aluminium. Safeguard duty will not stop import against exports.
  - i. While the actual import figures have shown a jump over the years, as a percentage of consumption, it has hardly changed. It is incorrect to say that imports are eating into domestic sales in a big way.
  - j. If downstream industries are rendered uncompetitive, then the unemployment in these units shutting down would be more than the unemployment in DI.
  - k. The aluminium pricing is determined by an open and transparent mechanism namely the LME. There have been instances in the past when the LME has been very high and the petitioners have made very good profits. Commodities are always subject to cycles. The government should take care of the downstream industry as well.
  - l. As a lot of orders of secondary industry are at a fixed price in which no safeguard duty element is factored in, downstream manufacturer would be severely handicapped.

**R. M/s. Apar Industries Ltd.**

- a. They are > Rs. 5000 crores company engaged in the manufacture of aluminium based conductors, cables & industrial oils in India and are exporting their manufactured products. They are also supplying products to Central & State Transmission & Distribution Utilities against their deemed export & firm price duty paid pricing link to LME base tenders/awards.
- b. Their sales are in the three categories of deemed exports, domestic and physical exports.
- c. If a safeguard duty is imposed, then the imports made against deemed exports are not exempt from safeguard duty. This would put tremendous financial burden on the Indian suppliers, and also give a huge advantage to Chinese suppliers of aluminium conductors.
- d. Safeguard duty be exempted from Advance Licenses against deemed exports.
- e. The Utility companies have to submit their bid as BOOT (Build/Own/Operate/Transfer) basis. In competitive bidding once price is firmed up, no variation in duties or taxes can be claimed. The quotations are being sent approximately 6 months in advance to the execution starting dates. In this case if safeguard duty is levied, the Indian conductor manufacturers will stand to lose heavily for the orders on hand and there will be complete confusion on how to quote for future.
- f. The local aluminium producers are not offering supplies on deemed export basis.
- g. The period of investigation in question is confusing as in February, 2016 the basic customs duty was enhanced from 5% to 7.50% in Union Budget and the impact of safeguard duty would be 12.50% (5+7.50) or 10% (5+5).
- h. Major imports are made by industry for execution of physical and deemed export orders for which raw materials are importable under DEEC scheme on duty free basis. The import made against export orders by the industry needs to be subtracted from the data provided by the petitioners.
- i. M/s Hindalco, Balco are themselves importers of the subject goods and hence cannot seek safeguard protection. Some high tech products manufacturing is having requirement of Ultra High Purity of Aluminium, i.e. Al. contents >99.85%, which is not produced on regular basis and some of the elements control is not maintained by any of the domestic smelters/petitioners and therefore is bound to be imported. If the quantity of imports made are deducted/adjusted, the ratio will change.
- j. The incidence of safeguard duty would result in a proportional increase in the cost to the conductor manufacturer. On the other hand, the imported conductors, particularly from China, would not have any increase in costs & accordingly would swamp the Indian conductor market resulting in massive losses to the conductor industry in India. This will create huge unemployment & social unrest besides resulting in sick industries in India.
- k. Petitioners have restricted the data up to period January, 2016 to suppress current scenario/facts. The factually applicable duty is 7.5% and not 5% mentioned in petition.
- l. M/s NALCO, a Public Sector Undertaking, is not a participant with the petitioner.
- m. Petitioner have added import of scrap in production comparative data with own + NALCO. Inclusion of import scrap (under 7602) is not relevant as petition pertains to HSN Code 7601. If Petitioners want imposition of safeguard duty on scrap, they need to submit fresh petition. Downstream industries of cable & conductor are not importing scrap at all because it's low grade/ low purity material not suitable in high grade conductivity and resistivity. Hence, the percentage of injury to Petitioner will be less.
- n. The petitioners production data is not authentic as compared with data from Ministry of Mines. Wrong data has been given to show lower production & underutilization of capacity and to establish injury.

- Petitioners have not revealed the data sources for all India production.
- o. Indexed data of opening and closing stock is presented erroneously.
  - p. Petitioner's data are not reliable as sales volume mentioned by Petitioners are higher than the production of respective period, and there is no question of underutilization.
  - q. One of the petitioners have done capital investment in SEZ about Rs. 13000 Crores for approved capacity of 1.25 MTPA. The investment is not in line with Indian market/demand. The Indian demand/market data is not appropriately represented by DI.
  - r. While calculating total demand, only duty paid imports should be considered.
  - s. The data do not justify any injury to the petitioner.
  - t. The duty free imports are purely against Advance License. Duty paid imports trend is negative. Purchase from petitioner itself is huge in last two years.
  - u. Petitioner has shown increase in cost of domestic sales whereas same has been down in export, cost structure won't be different for domestic & export.
  - v. Petitioners' sales price, is in continually increasing trend over & above duty paid imported price. It is also higher than NALCO local prices.
  - w. Pricing in India is at a substantial premium over the LME pricing prevailing in other markets. Drops in LME prices are unrelated to import competition and do not justify the imposition of safeguard measures.
  - x. The Petitioners' capacity utilization/ capital investment is not in line with market demand; Petitioners' own inefficiency lead to higher cost structure resulting in higher domestic prices.
  - y. Ordering pattern for cables & conductors by the EPC companies/ SEBs etc. follow an international competitive bidding procedure. If safeguard duty is imposed one will not be able to meet the costing of international market of cable and conductors.
  - z. Cost of employee is consistently higher year after year which is not in line with no. of employee.
  - aa. Abnormal increase in interest cost is not because of blockage in working capital but it's merely due to higher borrowing at high rate of interest for capital investment.
  - bb. A news published in April, 2016 mentions Vedanta's kicking up of the idle aluminium capacity in SEZ, six extensions given to SEZ since 2007 and its seeking further extension of the approval, SEZ's running at depleted capacity for want of power.
  - cc. Hindalco Business Outlook based on annual report of FY 2014-15 refers to strong volumes and realizations, increase in aluminium demand by 38 % in last five years; increase in cost of sales out of three major factors of rising coal prices, declining bauxite quality & rising logistics on account of diesel price deregulation; rise in export due to rising global demand. Hence, unutilized capacity is not the reason for rising cost of sales & increase in exports is not due to reduction in local demand.
  - dd. Petitioner has shown inappropriate interpretation related to downstream industries having no injury.
  - ee. As bidder contracts are based on L-1 Tender/EPC base; therefore, private power industries will suffer heavy injury & will not be able to compete with other government entities.
  - ff. Impact on cable & conductor industries shown in petition is absolutely wrong. Major contracts of conductor industries are on firm price base and any additional cost won't be absorbed by ultimate buyer leading to injury to conductor industries. In variable price base, there is no clause of safeguard duty effect and this is cost to conductor business only.
  - gg. Custom duty has already been increased from 5% to 7.5% in current year
  - hh. Import duty on conductor is 10% therefore, it would be a case of inverted duty.
  - ii. Volume of import scrap is merely used in utensil industries, safeguard duty should be only on scrap.
  - jj. Exports of aluminium from India are in line with import of aluminium in India and therefore, business cycle is healthy.
  - kk. There is considerable difference in cost of domestic sales & cost of sales of export. Costs have been intentionally loaded to domestic pricing & not to export pricing. Capacity utilization of petitioner against production is not appropriate because existing capacity & further enhancement is not in conjunction with overall market demand therefore, capital investment/capital employed haven't benefited the petitioner. The huge investment leads to high cost structure of petitioner resulting in high selling price.
- S. **M/s. Lumino Industries Ltd.; JSK Industries Pvt. Ltd. ; Venkateswara Wires Pvt. Ltd.; KEI Industries Limited; Indian Electrical & Electronics Manufacturers Association; Adinath Electricals Pvt. Ltd.; Kalpataru Power Transmission Ltd.**
- a. Petition though made out to be submitted by 3 companies, is actually submitted by two corporate

- groups; National Aluminium Company Limited (NALCO), a Navratna Company, is not a party to the petition.
- b. PUC include alloy ingot (76012010) which is mostly made from scrap. These are imported into India by automobile manufacturers or their ancillary units. These are also imported under FTA. Petitioners have added import volume of scrap based products just to inflate the numbers and should be excluded from the import data.
  - c. About 90 % of Ingots imported are against Duty Free License as export incentive to import raw material and safeguard duty will not stop such imports.
  - d. The installed capacity as given by DI in their petition includes Vedanta's 1.2 million tons capacity created in their SEZ unit to cater to global market. The facility was to produce metal for export using resources from Nyamagiri hills which got embroiled in agitation by tribal community leading to ban on bauxite mining. The capacity in SEZ should not be clubbed with domestic capacity. Reason for its idling has nothing to do with domestic demand or import. If the 1.2 million SEZ capacity is excluded, utilization is around 80% as against 48 % claimed by the DI.
  - e. The captive consumption should be treated as domestic sale only because metal transferred for captive consumption is used to manufacture value added products like wire rod, rolled products etc.
  - f. The demand has grown 29% over the base year. During the same period growth in import is nominal.
  - g. Duty protection will help DI raise their selling price in India by getting higher import parity price for quick and undue profit. Ultimately the end customer will pay higher price which cannot be passed on to anyone.
  - h. An increase or decrease in selling prices of aluminium could lead to slowing down of Electrification Programme.
  - i. Information given on impact on consumers is totally untrue. Any increase in duty, will only result in their selling price being increased on the basis of import parity. Granting duty protection by safeguard at the expense of large number of consuming industries is against public interest.
  - j. Price volatility is inherent in the metal business which has linkage with LME. LME is market price discovery mechanism. It is not something which applies to Indian metal producers only.
  - k. Customs duty on aluminium metal has already been increased from 5 % to 7.50 % in 2016-17 budget. Any further increase in metal price will result in inverted duty structure and make the consuming industries uncompetitive for survival. Eventually, finished products will get imported directly. Large number of small and medium scale industries will have to close down.
  - l. The petition refers to falling "Premium" but it is never considered to be a profit increasing factor. Premium levels fell from the manipulated higher levels after LME initiated regulatory action. This is applicable to all producers across the globe and is not specific to Indian producers/ market.
  - m. China's & Middle East Governments' support to their industry by way of subsidy holds the prices whereas the DI is requesting government to facilitate implementing an increase in price to improve profitability.
  - n. Indian producers have much bigger advantage of having bauxite and coal locally compared to Middle East producers having advantage of subsidized gas. Middle East producers are dependent on imported alumina. They sell their products with price reference to LME and not at lower prices.
  - o. The DI has benefitted from favourable exchange rate movements as the actual selling price is in Indian rupees.
  - p. Fall in global commodity price, excess capacity and such other issues raised by the petitioners, are structural issues to be addressed by the industry and seeking higher protection as short cut to improve profitability will only result in harming the aluminium based industry as a whole.

#### T. M/s. Associated Aluminium Industries Pvt. Ltd.

- a. They are manufacturers of aluminium wire rods (Ch. 7605). Ingot is the key raw material in manufacturer of their products with primary aluminium often constituting >90% of cost of production (COP).
- b. Imposition of safeguard duty on products under Chapter 7601 alone shall lead to inverted duty structure for value added products which shall threaten their capacity utilization and profitability.
- c. The imposition of safeguard duty on ingots only excluding value added products shall severely impact manufacturers engaged in this segment. This will render downstream units uncompetitive; will encourage imports of finished goods and thousands of people run risk of losing their jobs.
- d. Conversion cost of wire rods from ingots, usually, is less than 5% of the cost of ingots. Hence,

imposition of Safeguard duty @5% (or higher) only on ingots but not on wire rods shall, potentially, throw all wire rod manufactures in India out of business - as it would make enormous economic sense to directly import wire rods (at 5% less duty than Ingots) than buying ingots locally (at 5% higher duty) and converting into wire rod. India produces more than one million tons per annum wire rod, hence viability and interests of this crucial segment must be protected.

- e. If safeguard duty is considered for ingots, then wire rods be treated at par for imposition of safeguards.

**U. M/s. Polycab Wires Pvt. Ltd.**

- a. They are cable manufacturer. Safeguard duty will be detrimental to the growth of the cable industry.
- b. The reforms in the Power Sector have resulted in adequate order for all the cable manufacturers and have resulted in strong demand of metal, both indigenous and on imports.
- c. During the last two years the scrap import has increased due to the increase in automobile sector and duty differential of 5% between import duty on scrap (2.5%) and primary metal (7.5%).
- d. Due to the wrong pricing policy, the local producers are not able to capture the scrap consumers due to huge duty differential.
- e. Local producers are not providing metal to any of the consumer who is exporting the metal as this results in loss of duty factor which is being charged by primary producer.
- f. Local producers are not willing to provide the pricing mechanism which is being followed globally as the material is being sold on average pricing formula which totally benefits the producers. When the price is on rise the producers are not willing to supply and in event of fall in prices the producers do not revise their prices.
- g. In case a consumer want to buy under the Advance License there is no supplier in the domestic industry and consumer has no choice but to import.
- h. The domestic aluminium industry follows an import parity pricing model. They charge the industry and local users multiplying factor of 7.5% duty (increased in the recent budget from 5%).
- i. The safeguard measure would prejudice the legitimate commercial interests of other enterprises contrary to the public interest and will cause inflation.
- j. The consumers are being charged the increased exchange rate. The fuel price has reduced by 70% whereas the local producers are not reducing the freight prices.
- k. M/s Nalco, one of the leading producers has not joined the petitioners hence their claim of qualifying as DI is questionable.
- l. The reduction in production and profits of DI is not due to imports but due to reduction of LME and MJP prices in international market. In the last five years the MJP price has risen resulting in amassing huge profits to local producers. MJP has recently dropped but no other country has imposed or increased the import duty.
- m. Reduction in profitability and loss is further attributed to expansion, over expansion resulting in increased interest cost and internal restructuring by the companies. The losses claimed by the DI are mainly because of not getting bauxite mines and coal allocation from the Government and heavy interest burden on their unplanned and huge capital expenditures.
- n. Import duty on secondary aluminium alloys and re-melted aluminium ingots, aluminium scrap is presently @ 2.5% as against primary aluminium @ 7.5% which is impacting the sales of PUC in the country. In case these are excluded from safeguards than the imports will further increase.
- o. Net imports after deducting the import against export entitlement should be evaluated. Import data seems to include all the products covered under Chapter 76. Indexed data is provided instead of absolute data so as to make comparison impossible.
- p. The special automobile grades like ADC 12 which are not produced by DI and are also being imported in huge quantities should be considered separately while evaluating imports of PUC.
- q. While M/s Nalco exports alumina, Vedanta is importing alumina from the same port, which should be looked into to bring down the cost of DI.
- r. Because of unavailability of bauxite for its Lanjigarh project Vedanta is also loading its cost of unutilized Capex and thereby showing losses.
- s. Petitioners are using bulk of their smelting capacity for value added products to earn higher profits. The Indian consumers are compelled to import due to shortage of good quality and quantity of ingots by DI.
- t. Product quality from DI is inferior (equivalent to commercial grade with low conductivity and purity)

- while imported ingots with high purity and conductivity are available.
- u. There is no injury due to imports but is largely attributed to falling of the LME and MJP price inducing a fall of the selling price of the producers.
  - v. Market share of DI has increased proportionately with increased imports. Marginal increase in imports is likely to be linked to exports and purchases under ICB at zero duty for notified power projects.
  - w. The energy costs of foreign producers have always been substantially lower and this cannot be considered "unforeseen".
  - x. Imported PUC comes at very low freight costs while DI charges high freight cost.
  - y. Any imposition of safeguard duty will lead to closure of user industries leading to loss of employment & economic activity in the country and import of value added products like cable.
  - z. The basic custom duty on finished goods is from 0% to 7.5% whereas aluminium also attracts 7.5% BCD. Profit margin of conductor, cable and capacitor manufacturer are extremely slim. If safeguard duty is imposed then imports of conductor, cable and capacitor, particularly from China would swamp the Indian market, having adverse effect on the downstream manufacturers, creating huge unemployment and social unrest, resulting in sick industries.
  - aa. Imposition of Safeguard duty would result in a proportional increase in the cost to the cable & conductor manufacturers and the imported cables & conductors would swamp the Indian market.
  - bb. Safeguard duty will prove counter productive for the Indian aluminium producers due to closure of user industries.
  - cc. Safeguard duty will be counterproductive of revival of the economy as it will increase cost of products and affect the demand across all sectors of the economy including infrastructure, automobiles etc.

**V. M/s. Hind Aluminium Industries Limited**

- a. There are more than 400 conductor manufactures in India generating a lot of employment. Conductor industry operates in a highly competitive market with usually low single digit operating margins making it impossible for them to absorb the additional cost.
- b. Indian conductor manufacturers have inherent disadvantages v/s their global peers emanating from economies of scale, price volatility, higher interest costs and CST @2% which is not applicable on imports.
- c. Imposition of safeguard duty only on raw materials but not on conductors shall increase cost of production by 5% which shall make it unviable to produce conductors in India. This will lead to a flood of imports from countries like China and the Middle East.
- d. If safeguard duty is considered on primary aluminium, then an even higher duty should be considered on conductors to encourage the local industry. Otherwise it is almost certain that it will shut down.

**W. M/s. Oswal Cables Pvt. Ltd.**

- a. They are manufacturers of aluminium conductors, cable etc. and aluminium ingot / rods are their principal raw material.
- b. The petition is filed by the three companies namely Vedanta, Balco and Hindalco in the guise of the representatives of the domestic industry whereas they are in private sector. One of the main producers in the country, the public sector undertaking M/s National Aluminium Company Ltd. (NALCO) is not party to petition.
- c. The petition is a cartel made to gain undue advantage under the cover of safeguard duty and avoid fair competition.
- d. In the recent Budget, basic customs duty has been increased from 5.0 to 7.5 % and it has already added hardship. Any further increase by safeguard duty will result in inverted duty structure.
- e. If the safeguard duty is imposed they will suffer great hardship; huge losses; would be forced for retrenchment of the workforce. It would be grossly deterrent to the growth of the industry and will make the consuming industry uncompetitive resulting in increased imports of finished goods. Large number of SSI units like them would be badly hit.
- f. Most of the import of aluminium metal in the country is against duty free licenses offered as export incentive (to import duty free raw material) against exports and safeguard duty will have no impact on such imports. It will hit the domestic aluminium using industry making raw material dearer.

- g. The petitioners have put misleading data by clubbing the import of alloy ingots which is made from scrap and can be imported duty free from ASEAN.
- h. Growth in domestic demand has been highly positive over the period vis-à-vis nominal growth in imports of aluminium metal.
- i. Under the cover of the safeguard duty, DI intend to gain undue profit by raising the prices. The captively consumed production should also be considered as domestic sales.
- j. The capacity utilization of the DI is fairly good and they have unduly shown less capacity utilization by adding capacity utilization of units located in SEZ (meant for export only) as well as non-created capacity due to socio-legal issues.
- k. Industry consumes about 60% aluminium, most of which goes in the power sector - the core infrastructure sector for the growth of the economy of the country. The burden of increase in costs due to imposition of safeguard duty will ultimately be passed on to this most crucial sector. The Rural Electrification, Power Transmission System up-gradation etc. of Govt. of India / State Govts. would be hit hard.
- l. The petitioners are not concerned with higher capacity utilization or taking cost reduction measures but to unduly increase their profits under the cover of safeguard duty.
- m. Their industry employs a large workforce and substantial financial exposure of more than 1.5 lakh crore rupees which would also be severely affected by imposition of safeguard duty.
- n. The volatility in LME price of aluminium is no issue as it is not country specific but a global phenomenon. The issue raised about premium on LME prices of aluminium is absolutely vague and has got no relevance to support the cause of imposing safeguard duty. Premium is not meant for the profit but just to cover the logistics and value addition costs.
- o. The Indian producers have big advantage of cheaper raw material locally whereas globally most of the producers of aluminium depend on imports at higher prices.
- p. Benefits have accrued to DI due to favourable exchange rate INR vis-à-vis USD as the actual selling price is arrived in Indian rupees by the domestic producers.
- q. Falling global prices, excess capacity etc. are no solid grounds to substantiate injury to the local industry. These issues require to be solved by the petitioners by achieving efficiency in operations, modernization and cost-cutting measures as well as to focus on consumption growth.

**X. M/s. Dynamic Cables Pvt. Ltd.; Smita conductors Pvt. Ltd.; KJV Alloy Conductors Pvt. Ltd.; Alco Electrostrips Pvt. Ltd.; Shiv Enterprises; Trans Solution.**

- a. Ingots falling under chapter heading No. 7601 and/or wire rods under chapter heading 7605 are the key raw materials in manufacturer of their products i.e. conductors falling under chapter heading No. 7604 with primary aluminium often constituting >80% of cost of production.
- b. Imposition of safeguard duty only on ingots and not on wire rods shall severely affect smaller conductor manufacturers like them.
- c. Conversion cost of wire rods from ingots is usually less than 5% of the cost of ingots. Hence, imposition of safeguard duty only on ingots but not on wire rods shall throw all wire rod manufacturers in India out of business - as it would make enormous economic sense to directly import wire rods than buying ingots locally and converting into wire rod in India.
- d. Smaller conductor manufacturer would find it impossible to import wire rods directly due to working capital limitations and underlying risk on account of price volatility. They shall be forced to buy locally at much higher differential between ingots and wire rods.
- e. Larger players in conductor industry shall be able to import wire rods directly gaining undue advantage. Smaller players without any orders will face closure.
- f. Ingots and wire rods, both being raw material to conductor manufacturers, may be treated at par for simultaneous imposition of safeguard duty. Safeguard duty may also be imposed on conductors (CTH 7604).

**Y. M/s. KEC International Limited**

- a. They manufacture power cables ranging up to 220kv. They are also engaged, in execution of engineering, procurement and construction (EPC) contracts for power transmission lines.
- b. As a part of power transmission line projects in India, they procure aluminium conductors from Indian manufacturers.
- c. The conductors contain about 70% to 80% aluminium, thereby the cost of the conductors is predominantly dependent upon the aluminium price. In a typical power transmission line project

conductor comprises of about 30% of total project cost. Any increase in aluminium prices will have serious impact on profitability of overall project.

- d. Generally EPC projects are awarded on competitive bidding basis and the margins for EPC contractors are very low.
- e. Of late, power utilities in India are insisting for fixed price contracts and price increase in the conductors cannot be passed on to the power utilities.
- f. Power cables comprise of around 60% of aluminium. Power cables industry operates on wafer thin profitability and possibility of passing on the increase in cost is highly remote.
- g. Since China has tax rebate on value added products of aluminium, there is a high possibility of increased exports from China. Cables industry in India may have to wind up their operations.
- h. Petition is actually submitted by two corporate groups and M/s National Aluminium Company Limited (NALCO) is not a party to the petition.
- i. The DI is exaggerating the situation to get increased duty protection. Their intention is to get higher import parity price from customers and increase profitability at the expense of consuming industry. Customs duty on aluminium metal is already increased from 5% to 7.50 % in budget and all the domestic aluminium producers have increased their prices to that extent.
- j. Fall in global commodity price, excess capacity etc. raised by the petitioners are structural issues to be addressed by the industry.
- k. Granting any increase in duty protection by safeguard at the expense of large number of consuming industries is against public interest.

#### Z. M/s. Masters India Pvt. Ltd.

- a. The representation is only by M/s Hindalco, Balco and Vedanta and not by M/s Nalco.
- b. The petitioners claims their operation in loss, but on regular intervals they are commissioning new plants and expanding capacities.
- c. Aluminium pricing is linked to LME, which is either low or high on account of global demand and supply situation, so there could be loss or even profit.
- d. With the increase in custom duty to 7.5% from 5% the price of aluminium products was also eventually increased by DI taking it at par with import pricing. DI should keep lower prices so that no import can be done.
- e. For the benefit of MSME safeguard duty should be imposed on import of all aluminium products from Free Trade Agreement countries and only on import of all aluminium finished products like aluminium extrusion, circles, aluminium sheets in finished shape and foils in all gauges, and aluminium wire rod from all countries specially from China.
- f. MSMEs will not be able to survive if their rights are not protected as they have limited resources.

#### AA. Russian Federation, Ministry of Economic Development

- a. They express concern regarding the recommendation of imposition of 5 % duty.
- b. There is lack of evidence for satisfaction of the requirements by the petitioners concerning the initiation of the investigation and the imposition of a provisional measure.
- c. The primary ingots commodity (A7E, P1020, Au content > 99%) and all alloys (Alu content < 99%) are both falling within the scope of investigation. The products within the heading 7601 are not interchangeable because billets and alloys have different processing and end use.
- d. The product under consideration is wrongly determined. India is a net exporter of commodity 76011010 and net importer of commodity 76012010.
- e. The volume of import has been miscalculated in the petition.
- f. The volume of import has not increased in relation to the total Indian production. During the period 2011-2016 demand increased by 659, 3 MT or by 29 %. In the same time total Indian production increased by 676 MT or by 46.25 % and production of the petitioners increased by 76.22 %. Therefore, the volume of import in relation to the production has not increased.
- g. The WTO dispute settlement (particularly the Panel Report on imports of footwear in Argentina) makes it clear that the notion "such increased quantities" means not only mathematical end-to-end point comparison of the volume of import with the previous year or for the five year period. The Article 2.1 WTO Agreement on Safeguards and the Article XIX:1(a) GATT imply that increase in imports "must have been unexpected, sharp enough and significant enough both quantitatively and qualitatively".

- h. The factors defined as "unforeseen development" were not so unexpected and unforeseen as it is stated by the applicants.
- i. Reduction of world prices of aluminium began in 2011 and the drop of aluminium consumption in China was quite predictable and represents a long term tendency, outlined in 2011.
- j. Forecast of increasing capacities in the Middle East was undertaken in 2010 by the US Ministry of the Interior in its Middle East geological Survey.
- k. The increase in imports has been stipulated by a significant consumption growth in India rather than any unforeseen developments.
- l. Since 2007, China and India are considered the leaders in terms of growth of aluminium consumption. India is leading in the pace of growth of aluminium consumption due to the demand on this metal in electric industry, engineering, transport, automotive industry and packaging.
- m. DI's stated factors' analysis in Petition does not allow to give well-reasoned arguments that the Indian industry has been seriously injured.
- n. From 2011 till 2016 the reduction in domestic producers' share made up 1.53 % and could be explained by the increase in production costs and by the cheap imports from China.
- o. Price undercutting: High Indian aluminium prices result from the high costs of production. Producers are associating high costs with environmental charges, whose volume doubled on the 29 of February, 2016.
- p. The main reason of Indian producers' decrease in profit is due to the market aluminium prices crash and the simultaneous high energy costs in India. These reasons combined are leading to the loss of revenue. The production at Korba will be re-started in July, 2016
- q. The petitioners are carrying their business related to the production of other metals. The activity in these domains could cause negative financial results.
- r. The valuation of domestic industry profits decrease must cover the analysis of the influence of decline in aluminium prices by 30% from the second quarter 2014-2015 till the third quarter 2015-2016 alongwith the analysis of the high production costs, financial investments in capacity expansion and in share investments and payments per interests for using credits.
- s. The petitioner's data shows that the inventory decreased by 51%, if compare 2011-12 and 2015-16. It means that the consumption has increased in India and that the domestic industry has not suffered serious injury.
- t. Causal link: Aluminium is an exchange trade commodity and the price depends significantly on the supply and demand in global market. As company representatives of DI claim, external factors had a negative impact on the aluminium industry financial results. Under the present oversupply in the global market, aluminium price sharply declined and led to reduction of aluminium selling, profits reduction and became a major factor of damages. As per DI submissions, it follows that the summary of process utilizations in Indian companies increased to 40% from 2011 till 2016 and the overall production grew by 48.5%, the number of staff tends to growth and increased by 5%. The period of investigation is characterized by significant increase of cheap imports from United Arab Emirates, South African Republic and Oman and also by cheap import of fake-semis from China.
- u. There is an absence of serious injury for the DI and the negative impact on financial results of Indian companies stems from the aluminium world prices. The increase in imports is stipulated by the aluminium consumption growth in Indian downstream industry and have no unexpected developments preconditions.

#### **BB. Russian Federation, Ministry of Industry and Trade**

- a. There is a lack of significant increase in imports of the PUC in comparison with domestic production of the like product.
- b. The proportions of imported and domestic PUC in total consumption was more or less on the same level in comparison with previous periods. Share of Indian product in consumption decreased by no more than 3% up to 85%, resulting obvious negative impact on Indian producers.
- c. The share of import in consumption during years 2011 - 2016 was pretty much stable, and there was a market redistribution between the domestic industry and other producers.
- d. There is no evidence of growth of imports of aluminium in comparison with the domestic production of the PUC in India to the extent it may cause serious injury to the DI.
- e. There should be an unexpected and dramatic increase in imports of the PUC in order to justify the initiation of the safeguard investigation. In accordance with case law of the WTO Dispute Settlement

Body, the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively. The growth of imports of the PUC in years 2015-16 cannot be regarded as sharp and significant.

- f. The 'extraordinary nature' of the domestic response depends on the fact that the increased imports were unforeseen or unexpected. The DI failed to submit any facts that may be regarded as unforeseen developments. The increase in imports of PUC absolutely cannot be regarded as unforeseen and unexpected because, for instance, a drop in the growth rate of the economy of China was not unexpected and it was largely forecasted by experts.
- g. The Directorate failed to indicate in the preliminary findings evidences of the existence of a serious injury. There is no increase in imports of the PUC in absolute or relative terms in comparison with volumes of the domestic production of India on the level which may cause a serious injury to DI.
- h. With regard to the share of imports of the PUC in the domestic market of India, from 2011-12 to 2015-16, it slightly increased to meet the demand for aluminium on the Indian market. In period from 2011 to 2016, the level of sales of the domestic industry increased by 40%, while the level of sales of all producers of the like product in India increased by 23%.
- i. In period from 2011 to 2016 there was a significant 76% increase in production of the PUC by the domestic industry, which indicates a positive dynamic of development of the industry. The Directorate made a technical mistake by comparing the production capacity of all Indian producers and an overall consumption were compared with the production capacity of the applicants and not with production of the PUC of all Indian producers in total.
- j. The capacity utilization of the Indian producers remained as high as 87% in year 2015-16.
- k. The data concerning profit and loss of Indian producers are non-transparent. Profit of the domestic Indian industry was already negative (-4%) in years 2012-14. Thus, the presumable serious injury to the domestic industry may occur not in 2015-16, but earlier. Decrease in profitability of the DI may be the result of continuous growth of capacity utilization without yet reaching a cost recovery.
- l. Despite increase in capacity utilization there is a 51% decrease of the level of stockpiles of PUC in 2015-16 fiscal year in comparison with 2011-12 fiscal year indicating a stable position.
- m. There is significant increase in productivity from 77 tons per person in 2011-12 up to 129 tones per person per year in 2015-16 and there was an increase in the employment rate of 11% during the period under investigation.
- n. The DI has stable share in the consumption of PUC which demonstrate the absence of significant deterioration and no serious injury has been caused to the DI.
- o. Indian producers are exporting the product at lower prices than the sales price for the PUC on the domestic market. The alleged injury to the domestic industry could be caused by a loss ratio of export sales of the PUC as there is an unprecedented increase in exports from India.
- p. Economic data clearly indicate the absence of a causal link between increased imports and the alleged damage to the domestic industry of India.
- q. A provisional safeguard measure may be taken only in critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair. Given that no evidence regarding the critical state of the domestic industry caused by sudden and sharp increase of import was submitted, imposition of a provisional safeguard measure violates Article 6 of the SG Agreement.

#### **CC. United Arab Emirates**

- a. The scope of PUC artificially inflates the import data which is misleading, since it includes the data of alloyed ingots not produced by the applicants. The import data should be based only on imports pertaining to the not alloyed ingots.
- b. The products are not interchangeable products with respect to consumers or producers. The tariff classification is only indicative but not alone a determinative/ decisive factor. Scope of the PUC should be narrowed.
- c. The definition of the DI refers to those producing "like" or "directly competitive product", while the applicants are not producing "alloyed ingots" and the "alloyed ingot" is not "directly competitive" to "not alloyed ingots" that are not interchangeable.
- d. There is no relative increase of imports in relation to the Indian domestic production of the product under consideration, as the percentage of import with respect to India production remained almost the same or decreased. There is no such increase of imports that might cause or threaten to cause serious

injury.

- e. The DG, Safeguards failed to adequately address the binding requirement of '*unforeseen developments*' and nothing in the report can qualify as unforeseen developments within the meaning of Article XIX of the GATT 1994.
- f. There is no positive evidence that the alleged increased imports are causing or threatening to cause serious injury to the applicants. The applicant's data clearly reveals that there is no overall impairment in the position of the applicants.
- g. There is an increase of more than 40% in the installed capacity of DI.
- h. There is a significant increase in the production and sales of the applicants by more than 76% & 70% respectively. There is better capacity utilization and a noticeable decrease of the level of inventories for the recent period of investigation. There is also a noticeable amelioration of the level of employment for the period of investigation.
- i. The domestic industry market share including other Indian producers is not only dominating more than 2/3 of the Indian market but they are keeping their market share intact. The imports market share in the Indian domestic market is less than 15%.
- j. The facts reported, in particular the improvement of various economic indicators during the last year of the period of investigation evidently undermines any claim of threat of serious injury.
- k. Given these facts and legal grounds, it is very obvious the applicants are not suffering from serious injury or threat of serious injury.
- l. There is no causal link between increased imports and the alleged serious injury. The DG Safeguards failed to conduct the non attribution analysis and no impairment in the DI of the PUC has been caused by an increase of imports. The DG Safeguards failed to provide " a reasoned and adequate explanation, that injury caused by factors other than increased imports is not attributed to increased imports".
- m. Factors other than increased imports are the cause of any alleged injury to the applicants.
- n. The pricing methodology of a primary metal is a decisive factor as it is vitally based on the London Metal Exchange (LME) price which is a global reference price. LME price is a major influence on the financial situation of any producer of the product under consideration all over the world and not only India. The premium represents a very small percentage of the selling price of the PUC. The LME price fluctuates depending on the global trends in demand and worldwide economic conditions.
- o. The London Metal Exchange aluminium prices registered upward and downward movements during the period of investigation. The low LME aluminium price in 2013 together with increasing costs has put pressure on all aluminium companies around the globe who ultimately suffered financial issues.
- p. The applicants clearly recognize that the low LME pricing drastically impact their financial performance. Therefore, there could be no connection between the increase of imports and the alleged serious injury is related to LME pricing fluctuations during the period of investigation. The DG Safeguards did not conduct an "objective examination" based on "positive evidence".
- q. The excessive treatment of the injury information of DI on strictly confidential basis significantly affects the rights of defence of interested parties.
- r. The injury information of DI does not support a finding of serious injury or threat of serious injury as there is no significant overall impairment in the position of the DI.
- s. No critical circumstances exist that justify imposition of provisional safeguard duties.

#### DD. European Union

- a. The DI has to be defined by reference to products that are like or directly competitive. Ingots, billets, wire bars and wire rods are much more than merely different forms of the product. The product scope contains products that have different applications and are not interchangeable, thus cannot be considered as directly competitive. Ingots are not directly competitive with wire rods, as the former need to undergo several steps of transformation to become the latter.
- b. The imports and their impact on the situation of the domestic industry need to be analysed separately for the three different products. A separate analysis should be carried out for the different products covered by investigation.
- c. The imports have been increasing gradually all along since 2011/12. However, in terms of market share, imports increased by 4% only, over the period and reached a still rather modest share of 15% of total Indian demand.

- d. The market share of the DI remained relatively stable at around 50% during the overall period.
- e. The main injury indicators show an increasing trend. The production volume increased by 76%, sales by 32% and capacity by 40%. The capacity utilisation rate increased by 10 percentage points but remains at a low 48%. Market share remained largely stable at around 48% against an increase in demand of 29%, over the same period.
- f. The only decreasing indicator is profits, which seem to turn into losses in 2015/16. However, since the data provided is in indexes, it is difficult to know at which level the losses are.
- g. The results before interest and taxes in 2015/16 are positive. In view of the rather favourable development of all the other injury indicators, the decreasing profits seem difficult to explain and suggest that other factors than imports have had an impact on the situation of the domestic industry.
- h. No information concerning other factors has been provided in the complaint.
- i. The capacity utilisation was at a very low 38% at the beginning of the period in 2011/12. Subsequently, despite the increase of imports, the capacity utilisation rate increased to reach 48% in 2015/16.
- j. It is difficult to explain why the industry decided to increase its capacity by nearly 30% over the period analysed instead of optimising the use of the existing capacity. Furthermore, no information was provided regarding the investments made in order to increase capacity and their impact on the situation of the domestic industry.
- k. According to the information provided in the complaint, import prices appear to undercut domestic prices. However, import prices merely follow the trend of the LME. Prices of the domestic industry, on the other hand, remained far above the LME level throughout the period analysed. At the same time cost of sales increased by 30%. No explanation for this increase in cost of sales has been provided. This may be the result of inefficiencies of the domestic industry as it was not able to reflect decreasing raw material prices in its sales prices.
  - l. There is increase in wages by 150%, while the number of employees increased by only 5% but no explanation for this rather remarkable increase in wages has been provided.
  - m. The investigating authority may analyse carefully all other factors having a bearing on the situation of the applicants, in order to ensure an objective analysis.
  - n. The petitioners have given no explanation on the calculation methodology for the request of imposition of safeguard duty of 20%. Since the information on undercutting is provided in indexes only, it is not possible to see, if the proposed measure is related to the alleged undercutting.
  - o. The criteria for imposition of safeguard measures do not seem to be met. The DI's difficulties in terms of profit are clearly not caused by the increased imports, but due to the development of the production capacity; the apparent inefficiency of the applicants as shown in the low capacity utilisation rate; the increase of cost of production and the enormous increase in wages.

#### **EE. Taipei Economic and Cultural Center in India**

- a. Taiwan merely exported less than 1,000 tonnes unwrought aluminium to India annually during 2013-2015, which accounts for 0.14%-0.17% of India's total import volume on the concerned products.
- b. Taiwan's export of unwrought aluminium to India do not cause or threaten to cause serious injury to India's domestic industry. Therefore, Article 9(1) of the WTO Agreement on Safeguards shall be applicable to Taiwan. Government of India released Notification No 19/201A-Customs (NT) dated 5 February 2016 and Taiwan was excluded for the exemption of safeguard measures. Government of India may grant Taiwan developing country status in India's domestic safeguard laws.

#### **FF. M/s. Ravin Cables Ltd.**

- a. In the description of product as "Unwrought Aluminium (Aluminium not Alloyed and Aluminium Alloyed) the HS Code for both products has not been mentioned.

#### **GG. M/s. Paragon Industries Limited**

- a. A similar investigation was done in 2014 and investigation was terminated.
- b. Products under Customs Heading 7601 include alloy ingot (76012010) mostly made from scrap. The same is not DI's target market and should be excluded from import data.
- c. A very significant quantity is imported against duty free licence and any additional duty will not impact these imports.
- d. The fact has been suppressed by petitioner that Vedanta's Jharsuguda Plant with 1.25 million ton capacity is located in a SEZ meant to cater global market. The capacity should not be clubbed with

domestic capacity to determine utilization. If the 1.2 million SEZ capacity is excluded from the capacity utilization, the capacity utilization is around 80%. Vedanta has no bauxite and alumina to run the plant and the same is not operational.

- e. Hindalco commissioned their Mahan and Aditya plants and claim that plants are running at capacity.
- f. Petitioners calculate the domestic price based on the landed cost of imports unlike the LME based pricing practice worldwide which is market driven and transparent. Every increase in import duty would add profitability of the petitioners.
- g. Petitioners admit that their profitability has been reduced due to the fall in the LME price and the premium and not because of competition from the imports.
- h. The conditions of secondary producer is very precarious as many of extrusions and rolling unit have already closed down. The safeguard duty on base metal will increase the cost compared to cheaper imported downstream product due to the duty difference.
- i. The fall in global commodity price, low capacity utilization and other issued are structural issues.

#### **HH. M/s. Indian Foundry Organization (IFO)**

- a. The production of the foundry industry is around 10 million tons.
- b. There are more than 150 domestic manufacturers of aluminium alloy falling mostly in MSME sector with a capital investment of more than Rs.20,000 crores and providing direct employment to approx. 100,000 workmen.
- c. Recycling of aluminium scrap saves energy and protects environment. The energy consumption in recycling is much less compared to production of primary aluminium. There are practically no carbon emissions in recycling.
- d. IFO has received representations from a large number of metal recyclers supporting the levy of safeguard duty on aluminium falling under HS 7601.
- e. The import of aluminium alloy ingot falling under HS 760120 is allowed duty free from Thailand and Malaysia under FTAs. There is an import duty of 2.5% on import of the primary raw material for manufacture of aluminium alloy ingots, namely aluminium scrap falling under HS 76020010. It has resulted in huge financial losses to metal recyclers and manufacturers of aluminium alloys.
- f. IFO recommends the levy of safeguard duty of 5% on PUC including imposition of provisional safeguard duty.

#### **II. M/s. Hydro Aluminium Asia Pvt. Ltd.**

- a. Any safeguard duty would seriously and adversely affect their legitimate business interests and would render their supply uncompetitive vis-a-vis their competitors in Indian market.
- b. DG Safeguards may not confirm its provisional safeguard measures or any final measures and may terminate the present safeguard investigation in view of the serious adverse impacts of such safeguard duties on the large number of users of the subject goods in India including them.

#### **JJ. M/s. Hero Moto Corp Limited**

They are one of the end users of the subject goods in India.

#### **KK. M/s Shashi Cables Ltd.**

- a. There is no justification for proposed safeguard measure.
- b. With imposition of safeguard duty on aluminium ingots, Indian primary producers will be able to increase prices of their product.
- c. With wire rod escaping the safeguard duty, these will be imported at 5% lower rates than the rod from Indian smelters or secondary producers. Approximately, 300 small units will collapse under the weight.
- d. Either no safeguard duty be imposed or it should be levied simultaneously on aluminium rods.
- e. Hot metals production in 2015-16 has increased over 2014-15 and in 2016-17 over production in 2015-16. These increases have to be seen in the light of continuing slowdown in the global economy and in the backdrop of much reduced conductor demand.
- f. Processing aluminium is a highly capital intensive activity requiring long gestations and developers of these projects should have the capacity to bear the financial stresses.

- g. Aluminium metal is a commodity, traded globally at LME and other exchanges. In good times the Indian producers work out their prices as per LME indices taking full advantage but when the competition is fierce they want downstream users to pay higher than the market determined prices by way of safeguard duties.
- h. Manufacturers elsewhere unlike Indian producers may not even have access to ores, minerals and coal etc.
- i. The ad-hoc measure of safe guard duties will complicate and distort the market place, instead the tariff be increased from a high of 7.5% to 10%.
- j. There is no case for levy of Safeguard duty on import of aluminium metal.
- k. If safeguard duty is to be levied, it should apply to wire rods as well which most aluminium producers treat as primary, otherwise interest of smaller manufacturers in domestic conductor industry will be jeopardised.

#### **LL. M/s. White Metal**

- a. They are one of over 300 secondary aluminium extruders in the country.
- b. The industry is intertwined in a manner that any decision in isolation taken in favour of primaries will immediately impact not only the viability but may result into collapse of many units in the country due to current import duty structure and onslaught of material entering country from China and other FTA countries.
- c. The production in India is approx. 1.5 million tonnes presently, whereas the production and consumption in China has crossed 7 million tonnes. The main factors that contributed to this disparity were industrial growth and non-availability of adequate quantity of aluminium. Higher rate of duty impacted imports and did not allow the downstream activity to flourish in the country.
- d. With advent of industrialization and setting up of shops by various multinationals, it has become imperative to make available quality aluminium raw material to the manufacturers.
- e. Safeguard duties on raw material will be highly damaging, rather the Government should bring safeguard duties on downstream products to save the small and medium industry. This is needed as some of the countries like China, are extending high export incentives, which in turn are creating pressure on downstream industry in the country.
- f. Primary raw material is generally traded with a link to London Metal Exchange and therefore, it should not be a matter of concern to any segment of the industry.
- g. As an Extruder, they do import certain grades of billets due to quality constraints from the domestic producers.
- h. The total production of billets in the country is far below the installed capacity of aluminium extrusion, thus, forcing producers to opt for production (which is largely substandard) within the unit or rely on imports to fill the gap for quality billets.
- i. Import of primary metal in the country takes place against advance licenses to fulfil the obligation of exports, where benchmarking of pricing is done based on the prices prevailing at LME.
- j. Since, there is no mechanism currently available in India to source metal without taxes at LME price, de facto there is a necessity to import the material.
- k. Further, the data indicated does not bifurcate primary metal with secondary metal, therefore, the true assessment is difficult to arrive.
- l. The 78% increase projected could be on account of secondary metal largely being consumed by casting industry where the growth is phenomenal due to growth of automotive industry in the country.
- m. Billets are required by the industry starting with diameter of 5 inch up to 14 inch with a gap of 1 inch. Each consumer's requirement is unique in size depending on equipment. To manufacture each size, different moulds are required for which the primary producers are reluctant to invest in all the sizes, particularly 5" citing productivity constraints.
- n. Billet requirement in the country is over 3.5 lacs tonnes per annum. Due to non-availability of billets, per force, people resort to imports of either billets or scrap as the need may be.
- o. It is a necessity for an extruder to import certain types of billets having high quality needs and not manufactured in the country.

- p. It is established that no serious injury will be caused to the domestic industry as the detailed analysis of 78% increased import demolishes the claim of serious injury as projected.
- q. On the contrary, imposition of safeguard duty on raw material will cause serious injury to the secondary extrusion manufacturers who are in small and medium sector due to increase in their input cost.
- r. The increase of 76% of domestic production shows a healthy sign for the DI. Global financial meltdown had impacted all segments of industry.
- s. The DI's inventory is at a highly satisfactory level. Declining inventory is a healthy sign for the producers.
- t. Countries such as UAE, Malaysia, South Africa, Oman and Thailand do not produce primary metal. Qatar and Bahrain are producers of billets and imports are minuscule. Mentioning of all these countries is an indicator of the fact that data projected is incorrect.
- u. The import of secondary metal for casting and scrap has increased and it will continue to increase with the growth of automotive and other industries and this cannot be linked to the DI.
- v. The only other Indian manufacturer, who has not participated is M/s NALCO, therefore, it is very important to ascertain the correctness of figures of sales of other Indian producers.
- w. The pace with which the capacity expansion of primary metal has taken place, the downstream sector has not grown with same speed because of the various constraints being faced by the industry.
- x. The current projection of utilisation is misleading as for every capacity expansion there is a road map which defines the capacity utilisation based on individual company's strategy. It is very important to have that data from the DI.
- y. The prices at LME have come down, but it cannot be the reason for current losses as the cost of Indian producers is much below the world bench mark. It is a matter of analysing the balance sheets for various heads such as depreciation to ascertain the real causes.
- z. All producers are linking their price to landed cost of imported metal based on LME, therefore, profitability is a factor of international pricing and no country or producer can remain immune to that.
  - aa. Return on investment in extrusion industry is perhaps the lowest and the industry is fighting for survival.
  - bb. No fresh duty on import of unwrought aluminium be imposed as it will seriously jeopardize the operation of the secondary aluminium industry, especially the large number of extruders in the country.
  - cc. There is a fit case of imposition of safeguard duty on import of aluminium extrusions, particularly from China, in light of the incentives on exports being offered from such countries.
  - dd. Unlike other countries, there is no duty difference between primary and downstream products in India.

**MM. M/s. J M Industries**

- a. If safeguard duty is increased for aluminium, local cost of aluminium is likely to increase which may increase demand for substitute product like wood, plastic etc.
- b. At present, import duty on finish aluminium products is nil which will affect their export which will not be competitive. Due to all such expected problems there will be adverse effect on all aluminium industries for their survival.

**NN. Kingdom of Saudi Arabia**

- a. Under article 9.1 of the WTO Agreement on Safeguards, a safeguard measure cannot be imposed on imports of a product originating in a developing country member if its share of imports does not exceed three per cent and provided that developing country members with less than a three per cent import share collectively account for not more than nine per cent of total imports.
- b. The imports of the product under consideration from the Kingdom of Saudi Arabia account for significantly less than 3 percent of total imports into India during the period from 2011-12 onwards till 2015-2016. As the Kingdom of Saudi Arabia is a developing country WTO Member, its exports should be excluded from the scope of any safeguard measure in India.
- c. The Kingdom of Saudi Arabia is not included in the developing country Members to which the measure is not applied under article. In line with the obligations of India under Article 9.1 of the Agreement on Safeguards, imports from Saudi Arabia may be exempted from any safeguard measure

India may impose.

**OO. Govt. of Indonesia**

- a. In accordance with Article 9.1 Agreement on Safeguard, the authority shall exclude developing countries from safeguard measures as long as its share of import of the product concerned in the importing member does not exceed 3 % provided that developing members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 % of total imports.
- b. Indonesia's share of imports is negligible (less than 3% of India total imports) and the accumulation of other developing countries is less than 9%. DG Safeguards may maintain the conclusion in part X of the Preliminary Findings in its Final Findings.

**PP. M/s. EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council)**

- a. The EEPC represents a large number of manufacturers who are engaged in production of aluminium based products.
- b. Contention that import of PUC has significantly gone up from 2011- 12 till 2015-16 is misleading. The import as percentage of total production has not gone up. It was 13% in 2011-12 which went up to 17 % in 2013-14 and again came down to 15% in 2015-16.
- c. The contention that domestic industry is getting harmed by increasing export is false.
- d. Import made under export promotion duty free scheme has not been segregated. A very small and insignificant quantity is being imported under duty paid route.
- e. The DI is unwilling to supply the PUC to the exporters at international price.
- f. Cheap Chinese import are not harming the DI as PUC is not being imported from China in significant quantity under duty paid scheme.
- g. All domestic aluminium producing companies including the govt. sector, M/s NALCO are posting handsome profits. The Government Sector Company NALCO has not joined the demand for safeguard duty protection. The claim of private sector producers is motivated to make undue profits.
- h. The domestic industry has not lost any market share to imports. Rather if they extend the international price under duty free scheme, the exporters of finished products who are forced to import their requirement will be more than willing to procure the same from domestic suppliers.
- i. It may also be noted that the domestic industry is using the international price plus premium plus import duty multiplied by the USD to Re exchange rate as the basis of pricing their products and getting huge benefit on account of depreciating rupee.
- j. If safeguard duty is imposed, DI will increase their product price on the basis of higher landed cost of imported metal.
- k. There are many small manufacturers & exporters who are using the PUC in small quantities. They will be most severely hit since they do not have sufficient volume or financial ability to import the PUC under duty free scheme.
- l. Any increase in duty of PUC (raw-material) without commensurate increase in import duty of finished /semi finished goods will result in an inverted duty structure which will severely harm the large number of domestic aluminium consuming industries.
- m. Any increase in duty will severely affect the competitiveness of the small manufacturers which is against the GOI policy.

**QQ. M/s. Federation of All India Aluminium Utensils Manufacturers**

- a. The absolute figures, installed capacity and production submitted by the applicants may be analyzed taking into consideration the actual of imports into India and also the exports out of India of the PUC.
- b. DI's production & capacity utilization have increased during the period under investigation and hence no injury has been caused to them.
- c. The percentage of imports to production during the period under investigation was 27.33% in the year 2011-12, peaked to 33.19% in the year 2013-14 and has fallen to 26.99% in 2015-16 evidencing that no injury has been caused.
- d. The percentage of exports to production has increased in the period under investigation.
- e. Applicants by way of excessive exports have maintained a restrictive supply and thereby monopolistically determined domestic selling prices causing injury to downstream secondary manufacturers.

- f. The exports of the PUC out of the country may be analysed in tandem with the imports. There is higher increase in exports compared to imports. Rather, injury has been caused to the downstream secondary manufacturers as DI has maintained a restrictive supply and thereby monopolistically determined domestic selling price. Due to this reason downstream secondary manufacturers of aluminium products are forced to import.
- g. The imports into India were at a higher price compared to exports.
- h. Article XIX of GATT 1994 mandates investigation as to whether the application of safeguard measure would be in public interest.
- i. Any safeguard measure would unjustly enrich the applicants as they would increase the domestic selling prices.

### **III. PUBLIC HEARING**

1. A public hearing was held on 29th September, 2016. The interested parties, along with the Domestic Industry made oral submissions at the time of public hearing. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.
2. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.
3. All the views expressed by the interested parties in their written submissions in pursuant to the public hearing held on 29th September, 2016 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file.
4. A brief summary of the written submissions filed by the interested parties after public hearing are as under:

#### **A. M/s. Ravin Cables Limited**

- a. The applicable rate of duty on project imports under chapter 98 is 5% whereas the rate of import duty on most of the components of the electrical industry is 7.5 %.
- b. The government should provide duty protection to finished goods such as cables, conductors, transformers or any other product group which uses aluminium as a primary raw material to nullify the incidents of inverted duty structure.
- c. The government should not allow import of transformers, cables and conductors and any other products (currently manufactured in India) under chapter 98.
- d. Export tax be levied on export of aluminium so as to increase supplies into the local market.
- e. The aluminium industry should supply aluminium at fixed prices and in line with LME contract offering so as to protect the interest of the downstream industries in the cases where they either entered into fixed price contracts or quoted against fixed price bids.
- f. The aluminium industry should supply duty free materials on LME rates, without seeking undue premiums against export/deemed export orders.
- g. The aluminium is raw material for thousands of downstream industries and their competitiveness should not be affected negatively.
- h. The implications of proposed imposition of safeguard duty may be evaluated before duty protection is given.
- i. In the year 2009 petition concerning the present PUC & other products was filed but withdrawn later. In the year 2014, petition in the case of not alloyed ingots of unwrought aluminium was rejected by DG Safeguards.
- j. As M/s Nalco, despite being major aluminium producer, is not party to the present petition this petition doesn't represent the entire Domestic Industry.
- k. There are a number of anomalies in the petition. No separate data for duty free imports under advance authorization has been provided.
- l. In some cases, indexed figures are provided on the ground of confidentiality. Hence, no comparison is possible.
- m. The petition has been filed with a mala fide intention of profiteering, at the cost of public at large.

- n. PUC is a basic raw material to many downstream industries and is sold at LME based prices across the globe. Hence, the local prices of PUC have necessarily to be linked to the international prices to make the downstream industries globally competitive.
- o. Import of PUC at a competitive price is not prejudicial to the public interest.
- p. PUC being a basic raw material, levy of safeguard duty on imports thereof will have a cascading effect on downstream industries, which will set inflationary trend across the economy.
- q. Petitioners have not reduced their prices, in spite of fall in LME prices and premium of PUC, by taking undue advantage of Rupee depreciation.
- r. Petitioners are controlling production much below their installed capacities through cartelization despite demand, so as to maximize their own profits to the detriment of public at large.
- s. Petitioners are not providing better commercial terms in respect of sale of PUC, which their overseas counterparts are providing. Consequently, users of PUC are forced to import PUC from overseas market for their own survival in the domestic and international market.
- t. Production of PUC by petitioners is increasing, both in absolute terms and in relative terms to all India production.
- u. Percentile of all India imports of PUC to all India production is ranging from 13% to 15% over the period of investigation. Hence, there is no sudden, sharp and significant surge in imports of PUC.
- v. Petitioners production is increasing, despite increase in imports.
- w. There is no substantial increase in imports vis-a-vis increase in production (on all India basis) in absolute terms.
- x. Exports of petitioners have substantially increased, both, in absolute terms and in terms of percentile to their production. Domestic operations of Petitioners are not affected by increase in imports.
- y. Export of Petitioners is higher than all India imports, both in FY 2014-15 and FY 2015-16.
- z. All India exports of PUC are substantially more than all India imports of PUC in FY2014-15 and FY 2015-16. Hence, there will be no impact of so called surge in imports over the Petitioners.
- aa. Both, sales (in absolute terms) and the market share of the petitioner companies have been increasing in spite of so called surge in increase in imports.
- bb. Petitioners have substantially increased their installed capacities over the period of investigation.
- cc. Installed capacity of the Petitioner is higher than all India demand.
- dd. Petitioners have improved their capacity utilization from 41% to 48%, that too, on the expanded base of installed capacity.
- ee. Both indexed sales and indexed production figures are consistently increasing.
- ff. Indexed inventory turnover ratio has improved from 1 to 3.45. Fall in the inventory holding is not due to surge in imports, but, due to production being lower than sales.
- gg. Level of employment is reducing from FY 2013-14 to FY 2015-16. During the same period, productivity per employee has improved considerably. Both these factors, taken together, augur well for the petitioners.
- hh. There is marked and sustainable improvement in the domestic sales, exports, production, installed capacity & its utilization and market share of the petitioners, both, in absolute and relative terms, as against the overall industry performance, despite their selling prices being higher than the global benchmark.
- ii. Profitability of the petitioners is lower due to heavy interest cost on account of substantial expansion of the installed capacity, operational set-backs, natural calamities, power and coal shortages, recession in both global and Indian economies and not attributable to the so called surge in imports.
- jj. There is no causal relationship between the so called surge in imports and the deterioration, if any, in the operating performance of the Petitioners.
- kk. Petitioners have filed application with the intention to profiteer by raising their prices of PUC in domestic market to the detriment of the public at large.
- ll. As per the press interview of MD, Hindalco in May, 2016 India's aluminium demand has moved into double digits; their revenues will not be lower than the current levels; margins of Hindalco will be improving; Aluminium price on LME are seen range bound. Premia of aluminium are expected to stay where they are; with the help of higher volumes, Hindalco will offset the impact of weak realization; there is increase in demand for aluminium and stabilization of aluminium prices and premium on LME. Hence, there is no threat of serious injury to the petitioner companies.
- mm. Expansion in manufacturing capacities, per se, in China and Middle East countries cannot be termed as unforeseen development, since manufacturing capacities are not built up overnight.

- nn. Drop in growth rate of Chinese economy leading to increased imports of PUC from China cannot be treated as unforeseen development, since it is in line with economic trends across the globe. No data is provided in the Petition, regarding import of PUC from China.
- oo. Middle East countries have lower cost of energy production, due to oil and gas reserves and freight cost advantage, due to their proximity to India. Hence, surge in exports of PUC from Middle East countries is not due to any unforeseen development. The same view has been taken by the Director General Safeguards in his earlier investigation on the import of PUC.
- pp. Petitioners cannot present adjustment plans to overcome these inherent advantages of Middle East countries over the foreseeable future. Hence, this Petition is devoid of any adjustment plan.
- qq. When the petition was filed, rate of basic customs duty was 5%, which was increased to 7.5% in the union budget, 2016. Hence, levy of safeguard duty over and above the increased basic customs duty is not warranted.
- rr. Petitioners have filed this Petition with a mala fide intention to enhance their own domestic selling price after the introduction of safeguard duty and thereby profiteer at the cost of general public.
- ss. PUC, being a basic raw material, levy of safeguard duty thereon will have a cascading effect on the downstream industries in terms of increase in their raw material cost and set inflationary trend in the economy.
- tt. Safeguard duty on PUC will result into inverted duty structure, wherein the rate of import duty on raw material will far exceed the rate of duty on the finished products and will have adverse impact on the viability of the downstream industries.
- uu. Since the downstream industry is fragmented, it is not possible to levy safeguard duty on their products, which will result into their collapse adversely affecting their viability.
- vv. Downstream industries are more labour intensive than petitioner companies and it will lead to mass scale unemployment.
- ww. Domestic sales, export sales, production, inventory, capacity utilization, all have improved considerably and the economic viability and sustainability of the DI is not at stake. There are no unforeseen events, causing surge in imports. Thus, there is no increase in imports in such quantities, so as to cause significant overall impairment to the Petitioners.
- xx. When there is no significant overall impairment to the Petitioners, levy of safeguard duty on PUC is not in public interest.
- yy. If levy of safeguard duty is prejudicial to public interest at large, safeguard duty is not leviable, even if significant overall impairment has been caused to domestic industry.

## B. Indonesia

In accordance with Article 9.1 Agreement on Safeguard, the authority shall exclude developing countries from safeguard measures as long as its share of import of the product concerned in the importing member does not exceed 3 % provided that developing members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 % of total imports. Indonesia's share of imports is negligible (less than 3% of India total imports) and the accumulation of other developing countries is less than 9%. DG Safeguards may maintain the conclusion in part X of the Preliminary Findings in its Final Findings.

## C. Taiwan

- a. A break-up of imports country-wise during the period under consideration should be disclosed as has been done in the past investigations.
- b. The unforeseen developments cited in the preliminary findings do not meet the legal threshold of Article XIX: (1) (a) of GATT. Developments should be unforeseen by the country when it acceded to the WTO and not by a particular domestic industry.
- c. Taiwan is a developing country and it should be granted the benefit of exception in terms of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards.
- d. The facts of case demonstrate that there is no serious injury to the domestic industry in terms of Article 2.1 and Article 4 of the Agreement on Safeguards. Several economic parameters of the domestic industry, namely, production, sales, inventory, productivity per employee, employment had improved in the most recent period. While imports of the subject goods increased by 26% in 2015-16 (Annualised) in comparison to 2014-15, sales of the domestic industry increased by 32% in the same period. In fact, sales of the domestic industry were highest in 2015-16 (Annualised) when imports were highest. This breaks the causal link.

- e. The adjustment plan of the domestic industry should be disclosed to interested parties in non-confidential format as the same has been claimed confidential in the petition.

**D. Russian Federation, Ministry of Economic Development**

The Russian Federation reiterated the post initiation comments made by it.

**E. M/s. Noida Aluminium Company Pvt. Ltd.; Inland Importers & Consumers Association**

- a. The interest of downstream industry has to be watched primarily since it is spread across the length and breadth of the country because it provides employment to millions of people and investment multiple times higher than these major producers.
- b. The DI should limit the petition to aluminium not alloyed under HS code 7601.10 only.
- c. The DI should be asked to submit import data of 7601.10 only which is just negligible. The figures of imports represented by them are inclusive of alloy ingots which is not a raw material but a product made out of unwrought aluminium.
- d. The downstream industry engaged in manufacturing of aluminium under HS Code 7601.20 is badly hit by imports specially from ASEAN countries under FTA.
- e. The industry needs to have an unrestricted, free and level field to compete in the international markets.
- f. The imports have increased and DI's domestic sales have also increased.
- g. The exports of not alloyed ingots have increased from 234% in 2011-12 to 372% in 2015-16. The applicants want to have a free hand to export the PUC inflicting injury to secondary aluminium manufacturers in India.
- h. As compared to other parts of the world where the industry gets aluminium ingots at a price of LME+ Premium, the applicants have priced the material in such a way that it includes components of LME+Premium + Custom Duty+ Logistic Cost (as in case of import) X \$ X Rs. Price.
- i. DI's plea of low realization is misleading. In fact they want to take advantage of increase in custom duty.
- j. In last budget when the import duty was raised to 7.5% from 5%, they immediately increased the domestic price by Rs. 3500 per MT.
- k. DI's taking 2011-12 as base reference year is to divert the attention since at that time LME was at its peak. They are benefiting due to Rupee depreciation. They are enjoying the downward trend of fuel cost which accounts to 45% of the production cost.
- l. Hindalco as per their audited financial report year ending 2016 is showing a sale increase by Rs. 3000 crores against year ending 2015. The decline in net profit is on account of increase in capitalization during the year resulting in increased depreciation. Report mentions that they have managed higher sales due to better utilization of the installed capacity.
- m. Applicants are into a cartel due to which the downstream industry is into a dying position with lots of extrusion, alloy and other related manufacturers pulling down the shutters.
- n. Applicant's export price is lower than their domestic sales price which shows that they are taking full advantage of the custom duty levied on the imports. If the material is offered to the domestic industry at the price being exported, the import of the material will drastically fall.
- o. DI's capacity utilisation has increased from 2012 to 2016 and they are going for massive expansions. Their capacity is well utilised since they are using the PUC for manufacture of other value added products.
- p. The MSME sector related to aluminium is in a very bad shape and needs to be supported.

**F. Malaysia**

- a. Serious injury to DI could have been contributed by factors other than imports.

- b. The DI's installed capacity has been constantly increasing throughout the POI which could have impacted their operational cost and financial performance.
- c. The market share of imports was consistently between 11 to 15 per cent while the market of domestic producers was between 85 to 90 per cent which shows that imports have not replaced the market share of the DI.
- d. Whether there is a real need to impose safeguards measure may be assessed objectively.
- e. The safeguards investigation may be conducted in a manner consistent with the WTO Agreement on Safeguards.

#### G. European Commission

- a. The product scope covers aluminium ingots, aluminium wire rods and aluminium billets. However, these products are not interchangeable, their production processes differ and therefore they cannot be considered as directly competitive.
- b. Even if these products can be investigated within the same proceeding, the imports and their impact on the situation of the domestic industry need to be analysed separately for the three different products.
- c. Though overall imports have increased between 2014/15 and 2015/16, the increase was not sudden and sharp but rather gradual all along since 2011/12.
- d. While the market share of imports increased by around 5 percentage points, the petitioner's market share also increased by around 3 percentage points. The market share of other producers decreased significantly, which shows that imports have not affected the petitioners negatively.
- e. The ratio between import volumes and total domestic production has remained stable over the period of analysis and even decreased in recent years. The increase in production volume of the petitioners was higher compared to increase in imports. Thus, it is difficult to justify that the increased imports are causing or threatening to cause serious injury.
- f. The serious injury in safeguard investigations is a higher injury standard than material injury in anti-dumping and anti subsidy investigations. However, in the current investigation, the main injury indicators such as production volume, domestic sales and employment show an increasing trend. Despite an increase of capacity of 40%, the capacity utilisation rate also increased by 10 percentage points.
- g. The only indicator showing a downward trend is profits, which seem to turn into losses in 2015/16 after the last capacity increase. In the absence of consolidated absolute figures, they are not in a position to comment on the level of the profit or loss. In view of the favourable development of all other injury indicators, the decreasing profits suggest that other factors than imports have had an impact on the situation of the domestic industry.
- h. Causality: Capacity and capacity utilization, Indian price & cost levels, wages, captive consumption and domestic competition may be analysed. Capacity has been increased by 40% which has affected the industry as there is increase in interest paid. Import prices merely followed the trend of the LME while domestic industry prices remained far above the LME. The increase of cost of sales by 30% against an overall decrease in raw material prices seems to point to potential inefficiencies of the domestic industry.
  - i. There is 150% increase in wages, while the number of employees increased by only 5%.
  - j. The captive consumption has decreased by over 70% over the period of analysis. The reasons for this decrease and its effect on the situation of the domestic industry need to be analysed.
  - k. The effects of domestic competition on the situation of the petitioners may be analysed by the authority.
    - l. The criteria for the imposition of safeguard measures are not met.

#### H. M/s. Metal Recycling Association of India (MRAI)

- a. The levy of safeguard duty on unwrought aluminium would be a premium on purse of the secondary producers.
- b. The move of primary producers is to monopolize the market and get rid of the secondary producers.
- c. Previously, the applicant had demanded implementation of safeguards which was rejected. Analysis of the present demand would fetch the same conclusion.
- d. As per the Safeguard Agreement, safeguard is defined as emergency.
- e. The capacity utilization and production figures submitted by the primary producers state that there is an increase in production and capacity utilization as well.
- f. There is a steady increase in imports between 2011-12 and 2013-14. In 2015-16 there is a fall in imports.
- g. If export to production figures are taken into account, they too show that there is hardly any injury to the applicant. This has harmed the secondary producer & primary producers through this move created a cartel and thereby monopolistically determined domestic selling prices.
- h. Available export/import figures indicate the percentage of export/ import of not alloyed ingots have increased from 234% in 2011-12 to 403% in the first quarter of FY 2016-17. Thus the demand to impose safeguards on imports while allowing free exports is irrational.
- i. There was hardly any injury to the domestic industry.

#### I. United Arab Emirates (Ministry of Economy)

- a. An objective assessment of the trends evidences that there has been no sudden, sharp and significant increase in imports of unwrought aluminium into India. It is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year - or five years ago...not just any increased quantities of imports will suffice. There must be such 'increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfill this requirement for applying a safeguard measure.
- b. A close examination of the developments reported in the DG Safeguards preliminary findings demonstrates that they do not qualify as 'unforeseen developments' within the meaning of India's WTO obligations. DG Safeguards asserted that the very significant increase in production capacity of aluminium in the Middle East backed with very low energy cost was unforeseen. They see no reasonable explanation why it would be unforeseen to the domestic industry that a place with 'very low energy cost' had new capacities of production. A finding that existence of unforeseen developments resulted in the increase in imports cannot be justified and therefore the first prerequisite for the imposition of a safeguard measure is not satisfied.
- c. There is no positive evidence that the alleged increased imports are causing or threatening to cause serious injury to the applicants, in line with Article 4.1. (a) of the SG Agreement which establishes a very high standard to determine injury. The data concerning capacity of production, capacity utilization, production, domestic sales, exports, number of employees and wages significantly increased during the period of investigation. The market share of domestic industry increased. The domestic industry is not suffering from any serious injury.
- d. DI's performance further improved since the previous safeguard complaint was filed in 2014, where the DG Safeguards properly concluded that the domestic industry did not suffer from a serious injury.
- e. There is no causal link between the alleged injury and any increase in imports. Neither the application for the initiation of safeguard investigation nor the DG Safeguards preliminary findings provide compelling explanation or sufficient evidence about the existence of a causal link between increased imports and the alleged serious injury. When the level of imports increased in 2015-2016, the domestic sales, capacity of production, market share, production, installed capacity and productivity also increased.
- f. The sudden decrease of the domestic industry profits is direct consequence of the LME pricing fluctuations.

- g. The conditions for the continuation of the safeguard investigation are not met under the Rules.
- h. The investigation should be terminated without the imposition of a remedy.

**J. M/s. Hero Motors Corp. Ltd.**

- a. They are a user of unwrought aluminium in automobile sector. Unwrought aluminium is mainly consumed by auto mobile sector, consumable durables including utensils, automobile, housing and packaging sectors.
- b. Proceeding carried out by DG (Safeguards) is in violation of principle of Natural justice. DG (Safeguards) has not even waited for the mandatory period to lapse and issued its preliminary findings in haste. This deprived the interested parties of their right to participate at the critical stages of the investigation.
- c. Directorate General (Safeguards) did not have complete and comprehensive information when the Preliminary Findings was issued.
- d. Domestic Industry had sought undue and unwarranted protection in years 2009 & 2014 and the proceedings were terminated/ safeguard duty was not recommended. There is no change in the overall economic and financial condition of the Applicants.
- e. The Directorate General (Safeguards) could not have proceeded with the investigation and come out with Preliminary Finding as no adjustment plan was filed by DI.
- f. DG (Safeguards) must look at the performance of DI for the most recent period. Hindalco's financial results for first quarter of accounting year 2016-17 clearly establish that it has made bumper profit and there is no serious injury to the Domestic Industry.
- g. The Preliminary Finding is silent on the issue of public interest. Aluminium is one of the most important raw materials used by the core sectors of the economy i.e., automobile, power, consumable, utensils, packaging & housing sectors. Any action of the government to make aluminium expensive will adversely affect the downstream industries. Any move to destabilise automobile manufacturers will further aggravate the grim situation of employment.

**K. M/s. Indian Electrical & Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)**

- a. The primary producers of aluminium should agree and undertake to provide supplies to all IEEMA members, against fixed price contracts of cables, conductors, transformers and/or any other electrical products, for the entire project supply period, without taking the impact of any hypothetical imposition of any safeguards duty into consideration.
- b. It is always the basic principle to have a lower duty on raw materials than on finished goods. But in the previous budget, the rate of import duty on aluminium was increased from 5% to 7.5%, and hence the rate of import duty on raw materials and finished goods for cables, conductors etc. is same as that of finished goods.
- c. Before any safeguards duty is imposed on the primary aluminium, substantial duty protection should be given to finished goods such as cables, conductors, transformers or any other product group which uses aluminium as a component of raw material, to nullify the incidents of inverted duty structure, and protection should be greater than the quantum of safeguards duty, if imposed.
- d. The applicable duty under Project Imports is only 5% and already the import duty on most of the components of the electrical industry is up to 10%, thus resulting in a negative differential. Prior to any imposition of safeguards duty, a long term solution to the electrical equipment industry for addressing the inverted duty structure, prevalent under chapter 98, under Project Imports should be provided.
- e. The transformers, cables and conductors and any other products currently manufactured in India should not be allowed to be imported under Chapter 98.
- f. Imposition of safeguards duty on 5 micron aluminium foils, imported under HS code 7607 at 0% will create serious inverted duty structure since the finished goods i.e. capacitors, is also at 0% customs duty. Aluminium foil, under HS code 7607, should be kept out of the purview of safeguards duty.
- g. In order to reduce imports against exports, the local primary producers should be asked to supply duty free material on LME basis, without charging an undue premium.

- h. The implications on the local downstream industry may be evaluated and its protection should be ensured.

#### **L. M/s. Aluminium Secondary Manufacturers Association**

- a. Production of domestic industry has not come down but on the contrary all the 3 applicants have increased their production. The applicants have made huge investments for increasing their production capacities and continue to increase further by making regular investments. When the applicants are able to increase their production and sell the entire production, they cannot claim that they have suffered any injury due to imports.
- b. DI's profitability has come down but none of the producers are suffering loss. The reasons for the reduced profitability are low international price of aluminium metal prevailing in the global economy and huge depreciation and interest cost incurred due to investment made by DI for increasing capacity. Hence, imports have not affected their profitability.
- c. The applicants are already enjoying at least 13% protection. There is already import duty of 7.5% ad valorem (effectively 8.25%) and they are adding another 5% towards clearing and forwarding charges on the imported metal. Hence, price of aluminium metal in India is at least 13% higher than the price of aluminium metal prevailing elsewhere in the world. There is absolutely no need to consider any further protection to the applicants.
- d. The petitioners' indexed data prove 5% increase in level of employment over 2011-12. The applicants have increased their capacity in last 5 years considerably and they are running to their full production capacity. As there is no reduction or retrenchment in the manpower by the applicants there cannot be any injury to them and levy of safeguard duty is not justified.
- e. The applicants have failed to prove any surge in import quantity of aluminium metal as 15% increase in imports by no means can be considered as surge in imports.
- f. Profitability of the applicants has come down due to reduction in international price of aluminium metal. They are seeking levy of safeguard duty to increase their price just to gain unjustified profits.
- g. Imports are taking place mostly under advance licence against export made by small secondary manufacturers.
- h. The submissions of applicants that there are cheap imports of aluminium metal from China and Middle East are absolutely false and misleading. Govt. of China levies 5% export duty on export of aluminium metal from their country due to which no import of primary aluminium metal is taking place from China to India. Price of imported aluminium metal is fixed based on the price prevailing in London Metal Exchange (LME) which is uniform world over. The formula for import is LME + MJP + Import duty (8.25%) + 5% clearing and forwarding charges. The applicants are also fixing their price in the same manner and based on the change in LME price.
- i. The applicants are exporting their metal to various parts of the world since production is more than the domestic demand. They are exporting metal at LME Price + Premium as prevailing at the time of export and making profits.
- j. LME price has gone up during 2016-17 compared to 2015-16. The applicants made reasonable profit during 2015-16, naturally they will be making much more profit during current financial year.
- k. On earlier two occasions DI's requests for safeguard duty were not found justified.
- l. Based on hot metal production, capacity utilisation of DI is almost 100%.
- m. Aluminium Association of India does not represent the entire aluminium industry.

#### **M. M/s. Jindal Aluminium Ltd.; Century Extrusions Limited**

- a. Apart from items under Chapter 76.01, petitioners manufacture wire rods, slabs, sheets, circles, extrusions and foils also. Since all these products are made out of hot metal only, the installed capacity calculated with respect to hot metal only will give the real situation. The Petitioners' claim that their capacity utilization has come down to 48% is incorrect and all of them are running at 100 % of their capacity. When capacity utilization has improved there is no injury.

- b. The installed capacity of 32.58 lacs MT shown in the petition is over inflated and not fully in operation. Vedanta's 1.25 million tonne smelting plant in SEZ, Jharsuguda is not fully on stream due to power and alumina issues. The over inflated capacity is taken to intentionally show low capacity utilization.
- c. Imports have shown a marginal increase only in absolute terms from 2011- 12 to 2015-16 but as a percentage in terms of production, it has remained at almost at the same level and increased slightly. It was 13% of production in 2011-12 which increased to 15% in 2015- 16. Even otherwise, the increase of 78% in 4 years is not at all alarming but is quite normal and cannot be treated as 'spurt' calling for imposition of safeguard duty. The petitioners own production has also increased by 76% and their exports increased by 336%. Petitioners installed capacity and domestic sales also increased by 40%.
- d. As bulk of import is being done on duty free basis on advance license against exports it can't be stopped totally.
- e. Details of quantity imported against advance licence will reveal actual quantity of duty paid imports.
- f. Downstream industry is forced to import aluminium against their Advance License, since petitioners do not want to supply aluminium against these licenses at LME rates without payment of duty and taxes.
- g. Frequent attempts made by them in the past to source primary aluminium for exports against advance license from the local producers failed to yield any positive result.
- h. The applicants export aluminium on LME terms but it is denied to local downstream manufacturers at the same price. DI's exports realization is at least 13% less still they are earning profit whereas for domestic supplies their price is already higher.
- i. It is wrong to say that cost of imported aluminium is cheaper, since the prices of applicants are linked to import parity and is same that of cost of imported aluminium, prevailing time to time. If safeguard duty is imposed the applicants will increase their prices and imports will continue. They don't incur some of the costs like customs duty, clearing and forwarding charges etc. but still add these in their local prices and make additional gain of 13-14% compared to their counterparts abroad.
- j. Petitioners have been benefitted by depreciation of Indian Rupee against the US Dollar as Indian Rupee has depreciated nearly 39% between 2011 and 2015.
- k. There are no cheap imports of aluminium metal from China and Middle East as alleged. There is export duty of 5% on export of aluminium metal from China. The imports from Middle East are based on LME price, hence not cheaper.
- l. Claim of petitioners that increased imports have affected their financial situation and reason for their continuous losses, is baseless.
- m. Hindalco has been earning profits regularly and their profit for the first quarter ended April-June'16 jumped to Rs 294 Crores compared to Rs 61 Crores in the corresponding quarter of 2014-15.
- n. Nalco has also earned net profit in April –June 2016.
- o. The profitability of petitioners is slightly affected presently due to increased burden of depreciation, finance expenses on huge capital expenditure in creating additional capacities.
- p. As per statement issued by Hindalco while announcing their financial result for the FY 2015-16, their profit during FY 2015-16 is Rs. 607 crores; profit is less due to depreciation and high finance cost on increased capital expenditure on capacity expansion; they are working at full capacity since they have completed all their expansions; finance cost will be less henceforth and profit will increase; nowhere it is stated that their profit is less due to surge in imports.

- q. The DI has said that the falling premium is the reason of their reduced prices in the domestic prices. Premium has never been considered or meant to be a profit increasing factor and at even at low premium, the Petitioners are earning huge profits.
- r. Just like any other commodity, aluminium is also prone to fluctuations and is on downward trend. The petitioners can't make the prevailing low prices of aluminium as the basis of requesting for safeguard duty.
- s. These vital signs which prove injury to an industry are totally absent. Inventory has rather reduced in 2015-16 compared to 2011-12 even with appreciable increased production and sales between these periods. The manpower has also increased by 5%.
- t. The industry which doesn't show any signs of retrenched employees, no unutilized capacities, no abnormal decline in profits, can't be treated as under threat.
- u. The Middle East producers import alumina at very high cost whereas the primary producers in India have the natural advantage of local bauxite of one of the best quality and coal.
- v. The salary and wages cost of employees are minimum 40 to 45% higher for Middle East manufacturers compared to India. The suppliers from Middle East are also fixing their selling price of aluminium metal at international price on the basis of LME as is done by Indian producers. Thus, there is no cheap import of aluminium from Middle East.
- w. Aluminium Association of India is basically governed by primary producers and is not the representative of secondary manufacturers as being claimed.
- x. Imposition of safeguard duty will hit the secondary manufacturers very hard when they are already reeling under stagnant demand, fall in exports and increasing losses. Many small and medium companies are on the verge of closure due to large scale import of aluminium secondary goods from China, subsidized by their Government due to 13% export subsidy. Imported secondary products from China will also become cheaper.

#### N. M/s. Aluminium Bahrain B.S.C

- a. Violation of Principles of Natural Justice: The Exporter submits that the investigation has been and continues to be conducted in violation of recognised and established principles of natural justice. It is a recognised principle that all the evidence which the authority wishes to use against a party should be placed before the party for his comment and rebuttal, otherwise it will be against the rule of fair hearing.
- b. Rule 6 of the Safeguard Rules lays out the principles which should govern any safeguard investigation by the DG Safeguards. In the investigation which is at a sufficiently advanced stage, the Exporter has no clarity as to which data pertaining to the domestic industry should be relied upon in order to make its submissions.
- c. No definitive information is on record: Since initiation of investigation five different documents with different information have been made available and there is no directive from the DG Safeguards as to which document should be relied upon by the interested parties to submit their views and comments. There is no consistency with respect to the period for which the data has been provided.
- d. In the petition, there is no clarity with respect to the exact months of the 2015-16 financial year that was taken into account. The import statement provided in the Petition considered data from April 2015 to January 2016. For volume data of the Petitioners, the period till March 2016 was considered. For price parameters e.g. profits no period has been identified at all. In fact they don't know which months of the FY 2015-16 were taken into account.
- e. Revised data in the letters dated May 23 and 24, 2016: The data which was provided by the Petitioner vide their letters was based on the period from April to December 2015 (Annualized). The Petition covers data upto March 2016 (at least with respect to volume parameters), the updated data filed on May 24, 2016 provides data for a reduced period and then annualizes it. The updation of data is not carried out for all the data which has been provided.

- f. First Verification Report contains data with respect to few parameters and it is completely silent with respect many other crucial parameters like profits/losses, return on capital employed, price undercutting and price underselling, wages, interest and so on.
- g. Second Verification Report provided data up to June, 2016. However, it is completely silent with respect many other crucial parameters like profits/losses, return on capital employed, price undercutting and price underselling, wages, interest and so on.
- h. The Petitioners, after the Public Hearing, have submitted another set of data. This data suddenly contains information with respect to SEZ units of the Petitioners about which there was no mention until the Public Hearing. They strongly object to furnishing of new data at this stage of the investigation and the same should not be taken on record. Even this updated data is fraught with inconsistencies.
- i. The revised data does not clarify which months of FY 2015-16 have been taken into account and whether the data has been annualized.
- j. The data is materially inconsistent with the second Verification Report.
- k. While the revised data provides information of all domestic industry, the data with respect to individual Petitioners have not been updated. The DI had submitted company-wise data through May 23, 2016 letter but the same has not been updated. The Revised data post public hearing has segregated the Injury Information of the DI on the basis of the unit falling under a Special Economic Zone ("SEZ"), but the months which have been taken into consideration have not been mentioned. The Petitioners have consistently been ambiguous and failed to provide clarity with respect to the data and the period for which the data is being provided and thus raising questions on the reliability of the data provided.
- l. The Exporter has in effect no access to information to which it may offer its views. This is not only in violation of Rule 6 of the Safeguard Rules, but also negates the Exporter's right to fair hearing.
- m. Inconsistencies in the data submitted by the Petitioners: The data in the five documents are materially inconsistent to each other. The injury data provided in the revised data post public hearing, the second Verification report, the first Verification Report, the updated data provided by the Petitioners vide their letter dated May 24, 2016, and the Petition are inconsistent not only for the data provided in the Period of Investigation but even for the preceding years.
- n. Once the second Verification Report was issued, the information on the parameters included in the verification report was frozen. However, the revised data submitted by the Petitioners post-public hearing contradicts the second Verification Report.
- o. The data for domestic sales, export sales, captive consumption, domestic sales value, export sales value, and stock differ between second Verification Report and the revised submissions made by the Petitioners post-public hearing
- p. Keeping the second Verification Report as base, a comparison of the data reported in five documents i.e. the Petition, letter dated 24 May, 2016, first Verification Report, second Verification Report and the revised data submitted post-public hearing shows variances.
- q. The data provided by the Petitioners post-public hearing differs significantly from the data recorded by the DG Safeguards in its verification report. The verification report issued by the DG Safeguards is conspicuously silent on several crucial economic parameters. Given the inconsistencies in the data provided by the Petitioners, the data cannot be relied upon.
- r. They request DG Safeguards to first notify the interested parties on data/information for all the relevant economic parameters of the domestic industry, as may have been verified by the DG Safeguards. The DG Safeguards may then provide reasonable time to the interested parties to offer their comments and schedule another public hearing so that interested parties may have all relevant and verified information to comment upon. If investigation continues without giving access to verified data for a defined period of investigation, this would be in blatant violation of the principles of natural justice.

- s. The Petitioners have claimed excessive confidentiality with respect to the injury information submitted by them on 24th May 2016. The Petitioners have indexed all the information which was not indexed in the Petition in complete violation of the requirements of Trade Notice issued by DG Safeguards.
- t. No adjustment plan was provided by the Petitioners in the non-confidential version of the Petition which is an outright violation of Trade Notice. The interested parties cannot make any meaningful submissions on the adjustment plan without any information.
- u. The DG Safeguards, during the public hearing, directed that the non-confidential version of the adjustment plan would be made available in public file. The same was made available on October 6, 2016 i.e. just a day before these written submissions were due.
- v. The non- confidential version of the adjustment plan provided by the Petitioners at late stage of the investigation does not provide a meaningful summarisation, contains serious deficiencies and the Petitioners have claimed excessive confidentiality. This severely impaired the Exporter's right to make any meaningful submissions.
- w. The Petitioners have merely stated that they will reduce power consumption, various raw material consumption, administration and selling cost, and increase capacity utilisation without providing any explanation on the process that will be adopted. It is impossible to gauge whether the plan laid out by the Petitioner is feasible.
- x. DG Safeguards may make call for a revised non confidential version of the adjustment plan from the Petitioners which would include indexed figures for the data provided and a detailed explanation for the measures.
- y. The Petitioners have not filed updated information with respect to the import data even when the data for full FY 2015-16 (421,963.70 MT) is available on DGCI&S database. Annualization of data for a ten-month period (432,925 MT) offers skewed results favouring DI.
- z. The Petitioners in order to simulate an increase in imports have analysed data from 2007 to 2016 while the injury parameters have been analysed from the year 2011 to 2016.
- aa. The phrase "such increased quantities" imply that the increase in imports must be sharp enough, sudden enough, significant enough and recent enough.
- bb. The increased quantities of imports should have been "unforeseen" or "unexpected". Just any increased quantities of imports will not suffice. There must be "such increased quantities" as to cause or threaten to cause serious injury to the DI.
- cc. Given the requirement of recent enough increase, the Exporter submits that the DGSG must not consider import data from 2007 and rather it must focus on most recent data. The DGSG must call upon the Petitioners to submit most recent data.
- dd. The alleged increase in imports is not sudden or recent. The increase in the imports from 2007-08 to 2011-12 was 143% and from 2011-12 to Period of Investigation was 178% which proves that the increase in imports is not a recent or a sudden occurrence.
- ee. The establishment of "unforeseen developments" requires the demonstration of developments which were "unforeseen" or "unexpected"; such developments were of the effect of the obligations incurred by a Member under the GATT; these developments led to the increase in imports. The Petitioners have failed to elucidate in the Petition as to what developments were unforeseen and any linkages between such developments and increase in imports. The events laid by the DG Safeguards in preliminary findings cannot be considered to be unforeseen circumstances as the required three conditions have not been successfully substantiated and evidenced by the Petitioner or the DG Safeguards. The DG Safeguards has itself previously in the Final Finding of the Safeguard investigation concerning imports of 'Not Alloyed Ingot of Unwrought Aluminium' into India Notification dated October 7, 2014 ruled that the events cannot be considered as 'unforeseen developments'.

- ff. If there is indeed a surplus of the PUC in China, there should have been significant imports from China. Whereas the data submitted by the Petitioners themselves show that imports from China are approximately 2.6% of total imports of the PUC in India.
- gg. In absence of any 'unforeseen developments', there is no merit in the present investigations and hence, it must be terminated forthwith.
- hh. The DI is not suffering from any injury, let alone serious injury. For purposes of submission, they have to the extent possible, considered revised data submitted by the Petitioners post-public hearing.
- ii. In the revised data submitted by the Petitioners post-public hearing, two versions of injury information have been provided: (i) excluding SEZ units; and (ii) including SEZ units. The exporter submits that a SEZ unit is primarily an export oriented unit. Almost all sales made by an SEZ unit are sold in export market and they do not enter the domestic merchant market. Therefore, the production and sales of a SEZ unit is not impacted by the conditions of competition in the domestic market and accordingly there is no reason for including SEZ unit into the 'domestic industry'. This principle has been adopted by the DG Safeguards in the past in the Final Finding of the Safeguard investigation concerning imports of electrical insulators into India from Peoples Republic of China dated September 27, 2012.
- jj. They have considered the injury data (excluding SEZ unit) for the purposes of the submissions.
- kk. As per Safeguard Agreement 'serious injury' is understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry which is very high & exacting standard of injury. The word 'serious' connotes a much higher standard of injury than the word 'material' envisaged under the Anti-Dumping Agreement. A safeguard action must be seen as extraordinary.
- ll. The data submitted by the Petitioners shows that there is no injury, let alone serious injury.
- mm. The production of the domestic industry has increased by 52% over the POI, domestic sales & domestic sales value have increased by 32% over the POI.
- nn. The company wise profitability information provided by the Petitioners evidences that the two of the Petitioners i.e., Vedanta and Balco are making huge profits and hence cannot be considered as injured. Since two of the Petitioners have clearly made profits during the Period of Investigation, any losses suffered by Hindalco cannot be attributed to imports. However, Hindalco vide their Annual Report 2015-16 have stated that they are experienced an upward trend in the profitability.
- oo. The revised data submitted by the Petitioners post-public hearing shows that the price undercutting is negative throughout the period of investigation. Thus there is no injury with respect to price parameters.
- pp. Safeguards Agreement requires that any injury alleged must be a consequence of the surge in imports. In the present case there is no causal link between alleged injury and increase in imports.
- qq. A causal link examination requires the examination whether an upward trend in imports coincides with downward trends in the injury factors, and if not, whether an adequate, reasoned and reasonable explanation is provided as to why nevertheless the data show causation; Whether the conditions of competition between the imported and domestic product as analysed demonstrate the existence of the causal link between the imports and any injury; and whether other relevant factors have been analysed and whether it is established that injury caused by factors other than imports has not been attributed to imports.
- rr. If the profitability of each of the Petitioners is analysed, no correlation can be drawn between the imports and the Petitioners' profitability. Increase in the import volume has not affected the profitability of the Petitioners. For example in 2014-15, the imports rose 42 index points from the base year and in the same time period, the Petitioners' profits increased by 54 index points from the base year. In 2014-15, the imports reduced by two index points and in the same period, the profits of Hindalco dropped to 14 index points. Vendata's profit in 2014-15 was indexed at -509 while during the same year Balco's profits rose to as high as 832 index points. Balco's profitability increased over the POI to 2487 index points with increasing imports. The imports into India have been consistently increasing while the profits of the Petitioners have been fluctuating due to reasons which cannot be

- attributed to the imports. Thus, the profitability of even one of the Petitioners cannot be correlated to the imports.
- ss. There is no correlation with the sales of the domestic industry and the imports. The imports and the sales volume have been consistently increasing over the POI. The import volume during the FY2015-16 has increased by 36 index points from the previous year while the sales volume of the domestic industry also increased by 38 index points during the same period.
  - tt. During the year 2013-14, the import prices increased by 5 index points and that was the same period when the Petitioners' profitability declined by 15 index points. Clearly, there is no causal link between subject import prices and the profitability of the Petitioners.
  - uu. In the present case, movement in the economic parameters do not bear any correlation with import volume which implies that either the data submitted by the Petitioners is erroneous or there are factors other than imports which have caused alleged injury, if any, to the Petitioners.
  - vv. It is clearly established that there is no causal link between the import volumes and economic performance of the Petitioners.
  - ww. The alleged injury suffered by the Petitioners has been caused due to various factors other than the alleged increased imports.
  - xx. The information with respect to the interest has been provided by the Petitioners vide their letter dated May 24, 2016 and the revised data provided post the public hearing is inconsistent and not even showing the same trend for the interest paid during the injury period.
  - yy. There is an increase in the interest by almost 500% during FY 2015-16 when compared to the base year. Therefore, the alleged injury to the Petitioners are more on account of the high interests cost and not due to alleged increase in imports.
  - zz. The largest cost in manufacturing aluminium apart from alumina is the cost of power. The Indian domestic industry has faced substantial obstacles with regard to power and energy costs. Hindalco's Annual Report 2015-16 states that 'The cost deflation, especially energy costs coupled with depreciation of several local currencies vis-a-vis USD resulted in a downward shift in the aluminium cost curve thus putting pressure on the LME prices. However, now the prices appear to have bottomed out.'
  - aaa. The global pricing of aluminium is largely influenced by the London Metal Exchange (LME). Due to severely fluctuating prices as per the LME, prices across the world have been affected adversely, including the domestic industry. Hindalco's Annual Report 2015-16 states that 'Average aluminium LME was 16% lower than the previous year while the premiums were sharply lower by 68% as compared with FY 15.'
  - bbb. From the substantial non-attributive factors highlighted by the domestic producers themselves, as well as the break in causal link indicated by the Petitioners' own figures, it is evident that there is no causal link in the present investigation correlating the surge in imports to the injury suffered by the domestic industry.
  - ccc. The Safeguard Agreement allows for interested parties to comment on whether or not the safeguard application is in public interest. A levy of the safeguard agreement would be contrary to the public interest as it would adversely affect the user industry and the same can be evidenced from the submissions made by the user industry.
  - ddd. For smaller conductor manufacturers, the conversion cost of wire rods from ingots is less than 5%. Therefore, imposition of safeguard duty above 5% would result in serious losses to all wire rod manufacturers.
  - eee. In power cable business, power cables comprise of around 60% of aluminium which is covered under the product scope of the present investigation and it operates on wafer thin profitability due to which any increase in the cost of manufacture would adversely affect the mentioned sector.

fff. Due to these reasons, the DG Safeguards may terminate the investigation as the imposition of the safeguard duty would not be in the public interest of the user industry and the consumers of the PUC.

ggg. The basic customs duty on the product under consideration has increased from 5% to 7.5% on February 29, 2016. Therefore, the domestic industry has already received a benefit even when they have suffered no injury. The increase in basic customs duty must be taken into account.

**O. M/s. Hydro Aluminium Asia Pte Ltd, Singapore; Rockman Industries Ltd.; Endurance Technologies Ltd.**

- a. M/s. Vedanta's statement in press in October, 2016 shows that the aluminium sector is going upward and the company is very comfortable that the prices are moving at the right level. Therefore, there is no need for imposing safeguard duties and the case qualifies termination.
- b. Safeguard measures are extraordinary remedies to be taken only in emergency situations. Recourse to safeguard measure should be taken only when there is a very strong case on merit and there is no alternative other than imposition of duty to save a dying domestic industry.
- c. Present safeguard investigation was initiated and preliminary safeguard duties were recommended by not bearing in mind this fundamental principle set out by the WTO. This renders the investigation untenable as the petition nowhere proves any emergency situation concerning domestic industry of subject goods which warranted extra ordinary measures in the speed and manner in which the process of investigation and recommendation of Safeguard duties have been carried out.
- d. PUC selected is too wide and have been placed together heterogeneous products under one PUC. A definition "Unwrought Aluminium falling under customs heading 7601" is not only vague but it does not clearly identify the 'product' which is imported against which safeguard duty is sought by the applicants. There is lack of clarity and preciseness vis-a-vis the definition of PUC put forth by the domestic industry.
- e. Section 8B (1) of the Act read with Rule 4 enjoins a duty on DG Safeguards to specifically identify the article liable for Safeguard duty. From the scheme of the Act and the rules it is clear that PUC (imported article) needs to be identified in singularity. There may be plurality of articles which can be called like articles manufactured.
- f. The PUC in the present investigation in effect covers two broad categories, that is aluminium alloyed and not alloyed and various subcategories and types having significant differences in raw materials, basic physical properties and different end uses etc.
- g. The petitioners are producing only aluminium not alloyed category and they are not the manufacturers of goods falling under aluminium alloys. Aluminium alloys falling under subheading 760120 should not be included in the scope of PUC.
- h. As per Customs, aluminium alloys are subcategorized into primary alloys made from virgin metal & secondary alloys made from scrap or a mix of scrap and virgin metal. Consideration of PUC at 7601 level itself would lead to inclusion of a wide range of distinct product with its features, properties and end uses under one umbrella which is highly unfair and flawed.
- i. There is significant difference in the raw materials to produce aluminium not alloyed and aluminium alloys and in their end uses. Basic product properties are different.
- j. Petition admits significant price difference between alloy and non-alloy products and that significant volume of imports are of alloy grades and majority of sales of domestic industry is non-alloy grades.
- k. The non-alloyed products which are not supplied by the petitioners are apparently included in the PUC to inflate the import figures.
- l. Aluminium not alloyed and aluminium alloys are neither interchangeable nor substitutable inter se.
- m. The petitioners are not manufacturing aluminium alloys, leave aside the very specific products like A356 series within aluminium products. The petitioner cannot shoot over the shoulders of certain other producers of aluminium alloys in India by demanding duties on aluminium alloys.

- n. Aluminium not alloyed manufactured by the domestic industry is not like article to the aluminium alloys imported from various countries.
- o. Price of the product ranges from Rs.99 per Kg. to Rs 2447 per Kg. as per the import data given by applicants. Such distorted price is the result of a faulty PUC determination and erroneous product bucketing done by the petitioner.
- p. The application filed by the DI does not stipulate the types of goods produced by them across the subheadings. The DG may direct the DI to share with them the list of products claimed to be within the PUC category produced by them.
- q. They request exclusion of aluminium alloy ingots of A356 series which is not produced by DI from the scope of PUC to avoid unjust hardships to the automotive industry.
- r. The fundamental legal prerequisites of a safeguards case are not met in the present investigation.
- s. The information is not up to date actual information. The import for the period 2015-16 is provided based on annualised data with actual information up till January 2016. The petitioner should provide updated information for the most recent period and that also on quarter to quarter basis. DG Safeguards may provide transaction wise data of imports as per DGCI&S to see the factual position of imports. There are serious infirmities in the summary data being used by the applicants.
- t. There is no sudden and sharp increase in imports of PUC into India as alleged by the petitioners.
- u. The increase in import is a gradual and over the years growth and not a sudden and sharp increase. It is highly unfair to conduct an end to end analysis by taking only 2011-12 imports and 2015-16 imports into consideration. Actual imports during 2015-16 need to be seen on actual basis first with a quarterly breakup. Also more than 6 months have lapsed since March 2016. A quarterly examination of imports during FY2015-16 and till the last quarter i.e., July to Sep 16 is highly essential in the present case.
- v. The share of the imports in total demand remained at a meagre 15% during 2015-16 and 85% of the market share is very comfortably held by the domestic industry.
- w. The import data clearly shows that there is no sudden and sharp increase in imports in recent times.
- x. There are no unforeseen developments which may have triggered the alleged situation of injury. There must be a "logical connection" linking the "unforeseen developments" and an increase in imports of the product that is causing or threatening to cause serious injury. To support the claim of unforeseen developments the petitioner has relied upon certain feeble and unsubstantiated claims such as increasing capacity in Middle East countries; Chinese producers also started exporting; Cheap energy cost in middle eastern region; Decline in sea freight from Middle east; Export tax on primary aluminium and tax rebate on value added products from China PR and China building stocks.
- y. The petitioners have identified most of the factors as attributing to increased imports qua China but entire imports from China PR during the latest period was less than 3% of the total imports into India. The allegations about Middle East countries are more of possible subsidies given to them or the cheap cost in such countries etc. The data itself refutes the claim of the petitioners. The gap in consumption and production identified by the petitioner for Middle East in 2015 stood at same numbers during 2016 also. So there is no question of this factor triggering increase in imports during 2015-16.
- z. None of the factors identified by the petitioners can be considered to have contributed to a sudden and sharp increase in imports of PUC into India.
- aa. The PUC which is a commodity traded as per LME rates plus premium and exchange rate adjustments, have been facing LME price fluctuations and fluctuation in LME rates does not call for imposition of safeguard measures which has serious ramifications on the large number of users in India.
- bb. The attempt of the domestic industry is only to enhance their profit by getting safeguard duties imposed.
- cc. The alleged unforeseen developments, alleged increase in imports and alleged injury in the petition has no logical connection and investigation is liable to be terminated.

- dd. As per the Agreement on Safeguards "serious injury" shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry and "threat of serious injury" shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent. Director General (S) is required to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of industry.
- ee. Their preliminary objection to the injury data in the PF and also in the petition is that the relied upon data is not the actual data for the recent period and the same suffers huge infirmities because of the wrong PUC determination. Correcting the import data after carrying out essential changes in the PUC would show no sharp increase in imports.
- ff. The key parameters such as capacity, production, sales and capacity utilization have tremendously increased over the years and through the recent period when the domestic industry is alleging serious injury. A robust volume situation is simply not possible if sudden and sharp increase in imports on account of unforeseen developments was adversely affecting the domestic industry.
- gg. It is not just capacity, production and sales have also increased, even capacity utilization has increased and was at the highest levels vis-a-vis previous years. There is no possibility that DI may have faced serious injury when the volume parameters showed such robust situation. Any claim of injury in such a situation is highly disputed and requires crucial examinations by the DG Safeguards.
- hh. Not only capacity utilization and production of the domestic industry increased over the years, the domestic industry has disproportionately high capacity qua the Indian demand. The domestic users cannot be asked to bear any brunt of such excess capacities set up targeting the export markets when it is an admitted fact that domestic industries have their plants on SEZ and EOU area which are set up targeting exports.
- ii. The burden of such excess capacities such as fixed cost burden, interest burden etc. must be investigated before reaching to any conclusion on injury to the DI. The cost of the DI and their fair price should be worked out considering normated capacity utilization at least at 80% and not otherwise.
- jj. Any pressure of such excess capacities on cost of production due to fixed costs like finance/interest, depreciation etc. could be the reason of any decline in profitability and such declines cannot be attributed to imports especially when the producers have SEZ/EOU units.
- kk. Inventory level improved which is a positive sign amidst claims of serious injury. The closing stocks with the DI declined significantly and remained at a negligible point. Thus, the entire claims of injury are false.
- ll. Situation of profitability cannot be attributed to imports and no serious injury is apparent. There has been a sharp increase in the interest cost of the DI and the same has increased from 100 points in the base year to 390 points in 2015-16. The price undercutting situation during 2015-16 cannot be seen in isolation. It is important to identify the causes which have been impacting the profitability of DI in the period 2011-12 to 2013-14 as can be seen from figures of PBT and what was the position of such other factors in the period 2015-16.
- mm. Thus, the losses in 2015-16 cannot be attributed to landed price since the PBT of the domestic industry was declining when the undercutting was negative in previous 3 years beginning 2011-12 which shows there are other significant reasons which have been impacting the performance of the DI.
- nn. Nothing on record shows such other factors were not prevalent during 2015-16. Thus, losses in 2015-16 cannot be attributed to positive price undercutting.
- oo. The PBT situation is showing a distorted picture because of the sharp increase in interest cost and not because of any other reasons. The decline in PBIT from 132 points in 2014-15 to 31 points in 2015-16 cannot be termed as a sharp fall considering the nature of the commodity and such fluctuations were apparent in the previous years also. For example, PBIT fell to 91 points in 2012-13 and then to 44 points in 2013-14 and the same increased to 132 points in 2014-15. So, what is there in 2015-16 is only a repetition of the fluctuation which is inherent to the commerce of this product which is primarily driven by LME prices.

- pp. The level of employment with the domestic industry has increased over the base year and there is significant increase in the wages as well. Thus, there is no negative impact on the employability or the ability to pay wages and this do not show any signs of serious injury.
- qq. The price of the product globally is determined based on LME plus MJP/Premium and also exchange rate impacts which is a transparent mechanism. Thus, any claim of low price import per se is unsubstantiated and deniable in this product.
- rr. The Indian producers are holding 85% of the domestic demand and import is barely 15% which is a share incapable of inflicting serious injury.
- ss. The alleged injury appears to be triggered by high interest cost etc. of the Indian producers and imports are not to be blamed for the same.
- tt. The issues of Vedanta lies in their bauxite and coal procurement as evident from their annual reports and any adverse effects on the same should not be attributed to imports.
- uu. Customers should not be made liable to pay for the inefficiency of Vedanta as the other producers are apparently operating in profit.
- vv. The users should not be put to bear the brunt of excess capacity set up by the DI.
- ww. Transfer cost of intermediary transfers of the DI should be subjected to strict scrutiny while determining their cost of production.
- xx. The domestic industry could not bring on record any strong case of serious injury on account of sudden and sharp increases in import into India.
- yy. Causal link between the increased imports and the injury to Domestic Industry must be established in order to impose the Safeguard duty. The DI has not given any material basis on which it can be demonstrated that the injury claimed by them is due to the alleged increased imports. The analysis of data given in petition shows that there is no linkage between imports and claimed injury. The cause of injury to the domestic industry is burden of interest cost and there is no influence of import prices. Profit was declining when the undercutting was negative in the initial three years which shows any decline in profit ought to have been due to some other reasons. Injury claimed is not connected to imports and reasons such as raw material procurement issues, high interest cost etc. are apparent. The reasons of any alleged injury is solely other reasons and are not driven by any sudden surge in imports as the DI could not show any such increase in imports. Vedanta has significant legal issue and litigations concerning environmental issues qua their mines and any impact of the same should not be attributed to imports.
- zz. The industry has been through a volatile period and the same is over and the industry is gaining benevolent prices. Volatility in the segment cannot be made a base to claim remedy under safeguard scheme.
- aaa. The import duty on PUC is already increased by 2.5% and is at 7.5% now as an additional protection and this fact should be taken into consideration by the DG. Any safeguard duty in such circumstance would leave the end user in sheer vulnerabilities and would lead to inverted duty situation for the end users.
- bbb. The NCV version of the adjustment plan do not permit any meaningful comment/understanding at least in percentage terms as to what would be the effect of the plan proposed by the domestic industry. In the absence of any summary on quantification of the same, they are not in any position to comment meaningfully.
- ccc. The non confidential version falls short of the standard requirement of Article 3.2 of Agreement on Safeguards read with Rule 7 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. The information submitted in application is vague and does not allow reasonable and meaningful understanding of the DI's case. Confidentiality has been claimed in respect of a number of data without assigning any reason. Therefore, the entire confidential information needs to be disregarded by DG Safeguards.

- ddd. While deciding the case of imposition of safeguard duty on any product, public interest analysis including the impact of safeguard duty on products down the line must be done. Imposing safeguard duty on subject goods is against public interest, especially looking at the PUC as defined.
- eee. Imposition of safeguard duty would have serious impacts on various user sectors. The attempts of the domestic industry are only to enhance their profits by way of safeguard duties. The PUC as defined includes a whole lot of variety of products which has nothing to do with the performance of the DI. It would be at larger public interest not to impose duty on the PUC. M/s Vedanta have admitted that the situation of aluminium have drastically improved after volatility during the last year. No safeguard duty should be imposed at this juncture.
- fff. In totality, it appears that in spite of being no case for imposition of safeguard duty a case has been initiated.
- ggg. In view of submissions made, they request that a recommendation be made for termination of the present investigation.
- hhh. Every increase in import or availability of material at lower prices outside India is not bad and should not be discouraged. The availability of goods outside India at prices lower than those which are indigenously produced would encourage competition amongst the Indian industry and would not per se result in eliminating the competitor.
- iii. The submission of DI that SEZ/EOU units have been treated as part of domestic industry in various anti-dumping and safeguard investigation in India is factually correct. In a recent anti-dumping initiation concerning "Non Woven Fabric" F.No.14/23/2015-DGAD, dated 15th June, 2016, the petitioner did not consider producer in the SEZ area for the determination of standing and the producer in SEZ was kept out for determination of total Indian production.
- jjj. The application for imposition of safeguard duty and the current proceedings started based on the same is not maintainable and be terminated.

**P. M/s. Virgo Aluminium Ltd.**

- a. There is only 4.07% increase in import against the demand in domestic market in last five years.
- b. Total demand of unwrought aluminium in domestic market increased by 29% in last five years above the base demand of 2011-12 whereas the production capacity of primary product has increased by 40%.
- c. Sale of petitioner has increased by 40% in last five years.
- d. Sale of secondary producers has increased by 2.65% in last five years.
- e. The overall domestic industries are enjoying approx. 85% market share of the total demand.
- f. M/s National Aluminium Company Limited (NALCO), a Navratna PSU never recommended such petition.
- g. In the last budget when the custom duty was increased by 2.5% above the earlier 5% customs duty, all domestic primary producers increased the prices by Rs.3500/- per metric ton.
- h. Domestic primary producers want to earn more and more profit with the monopoly in the market.
- i. There is no injury for the Petitioners.

**Q. M/s. EEPCL India**

- a. They represent a large number of manufacturers who are engaged in production of aluminium.
- b. Contention that import of PUC has significantly gone up from 2011-12 till 2015-16 and domestic industry is getting harmed by increasing export is misleading/ false. The import as percentage of total production has not gone up. It was 13% in 2011-12 which went up to 17 % in 2013-14 and again came down to 15% in 2015-16.
- c. The import made under export promotion "duty free" scheme has not been segregated. Very small and insignificant quantity is being imported under duty paid route. The exporters have to import their

requirement on international competitive prices, as the domestic industry is unwilling to supply the PUC to the exporters at international price.

- d. PUC is not being imported on duty payment from China in significant quantity and it is not true that cheap Chinese imports are flooding the domestic market and harming the domestic industry.
  - e. It is not true that DI is getting harmed as all domestic aluminium producing companies including NALCO are posting handsome profits. NALCO has not joined the demand for safeguard duty protection.
  - f. The claim of private sector producers is motivated to make undue profits.
  - g. The domestic industry has not lost any market share to imports.
  - h. If DI extends the international price under duty free scheme, the exporters of finished products will be willing to procure the same from domestic suppliers.
  - i. The DI is using the international price plus premium plus import duty multiplied by the USD to Rupee exchange rate as the basis of pricing their products. They are getting huge benefit on account of depreciating rupee which artificially increases their product pricing.
  - j. The purpose of petition is to increase their product price since they will immediately jack up their price on the basis of higher landed cost of imported metal.
  - k. Many small manufacturers & exporters who are using the PUC in small quantities will be most severely hit since they do not have sufficient volume or financial ability to import the PUC under "duty free" scheme.
  - l. Any increase in duty of PUC (raw-material) without commensurate increase in import duty of finished/semi finished goods will result in an inverted duty structure which will severely harm the large number of domestic aluminium consuming industries.
  - m. There is no case to levy any safeguard on import of PUC in India.
- R. **M/s. Century Metal Recycling Pvt. Ltd; (CMR), CMR Nikkei India Private Limited (CMRN); CMR-Toyotsu Aluminium India Private Limited (CMRT).**
- a. CMR is involved in production and sales of unwrought aluminium - alloy and zinc alloy. CMRN & CMRT are involved in production of unwrought aluminium - alloy only.
  - b. Aluminium alloy ingots are primarily used as raw material for aluminium die cast components and aluminium mouldings required in casting of auto parts and to a small extent in casting of white goods and consumer durables. For production of unwrought aluminium, scrap is purchased and sorted as per requirements.
  - c. Under FTA, there is no duty on imports of PUC from certain Asian countries like, Thailand, Malaysia, Vietnam, Japan etc.. The increase in imports from the FTA countries is because of FTA concessions and imports being made without adhering to the value addition conditions.
  - d. Imports have increased significantly in such quantity and in such situation that the same have caused severe injury to the domestic industry.
  - e. The increase in imports is significant in spite of the fact that they are offering un-remunerative prices at par or even at a price which does not allow recovery of even cost.
  - f. Since China cannot export PUC directly to India as the same attracts customs duty @7.5%, therefore, entrepreneurs of China origin have set up plants in Malaysia and Vietnam for export of PUC as such imports are duty free in India. Import of PUC from Malaysia and Vietnam have increased substantially.
  - g. They are also suffering injury as a result of increased imports.
  - h. Though capacity, production, and sales increased, the capacity utilization declined. Looking at volume parameters in isolation would not give correct state of affairs of the performance of industry. Increase in its profits and market share did not happen and due to easy availability of the imported

material in the Indian market, company was forced to maintain prices at the level of imported prices, which does not allow recovery of even full cost, leave aside margin over huge investment made.

- i. Their profitability is severely eroded. From a profit of 100 (indexed) per MT in base year, they have now made loss of 23 in the 2015-16 FY for domestic operations. Due to decline in profits, their cash flow and return on capital employed is also severely deteriorated.
- j. There is direct correlation in increase in imports and deterioration in profits.
- k. Employment shows similar trends as that of production (though the same declined in 2015-16 over preceding year). Wages per kg. declined in 2015-16 and despite the same, losses have increased. The wage per unit of production declined in line with the productivity achieved by the company.
- l. Productivity per day and also productivity per employee has shown increases, thus, any possible decline in productivity is not the cause of injury. Despite improvement in productivity, profitability has deteriorated.
- m. Import has severely impacted fundamental operating parameters such as profits which can be cured only through imposition of adequate safeguard duties on subject imports.
- n. Return on capital employed has got significantly impacted as a result of increased imports from subject countries.
- o. There is significant increase in inventories
- p. They have suffered serious injury from the increased imports of unwrought aluminium (7601) in India.
- q. Appropriate safeguard duty may be recommended and got imposed immediately.

#### S. M/s. Masters India Pvt. Ltd.

- a. Productivity in the notice is measured in terms of production (MT) per employee. But labour does not constitute a major part of the cost structure. The standard measure internationally used is electricity consumed to produce a tonne of aluminium (MWH per tonne), primarily, because electricity accounts for about 40% the cost of production. The productivity should be reassessed. Consequently, a correlation between imports and losses to primary producers must be re-established.
- b. The use of economic parameters has not only been limited, but also their application has been made in isolation. It is unclear how a causal link was established between increased imports and losses. They request the DG, Safeguards to reevaluate the economic parameters used to establish the link between the imports and the losses to the applicants
- c. As per Hindalco statement, the EBIDTA attained has been the highest ever in 2015-16; profits were low because "the interest and depreciation charges rose significantly in line with the commissioning of new facilities".
- d. Reduced profitability in recent years has been due to increased uncalculated debt burden and operational inefficiencies.
- e. Since LME prices have now stabilized, there is increasingly healthier business position of the primary producers.
- f. M/s NALCO is also not one of the applicants.
- g. The safeguard duty will have grave effect on the downstream industry. As soon as the safeguard duty is levied, the percentage increase in the duty becomes reflective in the DI's prices.
- h. FTA countries, major exporters of PUC to India, would still be exempt from the duty.
- i. The duty will create a shortfall in supply in short-term.
- j. Increased duty will also deter export growth of the country, since, the prices of domestic producers will likely become uncompetitive in the international market due to increase in primary metal cost.
- k. The DI is not providing duty free material to exporters and they have to import material against advance licence.

- l. Applicants should affirm to maintain the prices in case the safeguard duty is imposed.
- T. M/s. Vedanta Limited- Aluminium & Power; Bharat Aluminium Company Limited; Hindalco Industries Ltd. (Domestic Industry)**
- a. An issue has been raised concerning eligibility of petitioner as a domestic industry in view of the fact that the petitioner's plant is in SEZ. Definition of domestic industry under the law implies SEZ unit is a domestic industry. The term used in the safeguard law is "*producers -in India*". The SEZs Units established in SEZs are very much producers in India.
  - b. The relevant criteria for standing and scope of domestic industry is production and not utilization of such production. In a situation where a DTA domestic producer exports 90% of its production, the Directorate will still consider entirety of its production for the purpose of standing.
  - c. As per the definition of words import and export under the SEZ Act, import implies bringing goods or receiving services, in a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by any other mode and export implies taking goods, or providing services, out of India, from a Special Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode. Therefore, sale by an SEZ unit into DTA is not an export and is in fact a domestic sale
  - d. In the books of accounts and for all the purposes such as revenue recognition, FOB value of exports etc., a sale made by a unit in SEZ is treated as domestic sale. The sale made by an SEZ unit to an Indian entity cannot be included for determining FOB value of exports (even if it is to an SEZ unit). Only physical exports can be considered as exports for the purpose. Sales to DTA, EOU, SEZ are treated as domestic sales and only physical exports are considered as exports sales in India for the purpose of reporting "FOB Value of exports" in the financial records of the company.
  - e. A unit in SEZ is treated as an Indian manufacturer for various regulations in the country, barring with the sole exceptions of direct and indirect taxations. However, direct and indirect taxation laws are grossly irrelevant for the present purposes. It does not mean that production shall not be taken as domestic production merely because the Govt. has allowed import of inputs without payment of customs duty.
  - f. Direct tax benefits given by Govt. of India are entirely irrelevant for the present purposes. The Designated Authority however has not denied the status of domestic industry to such a company only because of income tax exemption.
  - g. All civil, criminal or business laws do apply to a unit in SEZ.
  - h. Customs authorities treat sale made by an SEZ unit to Indian company as a domestic sale and the same is not recorded either as import or as export. Only physical exports made by SEZ unit are reported as exports. Imports made by an SEZ unit are reported as imports.
  - i. The Designated Authority, Anti Dumping in the past considered an EOU or a unit in SEZ as a domestic industry in the cases of polypropylene, solar cell, electric insulator, alloy wheels, DVD-R & DVD-RW, CDR and vitamin-A palmitate.
  - j. In DG Safeguards case of saturated fatty alcohols, the domestic industry is a 100% EOU.
  - k. A unit in SEZ has been held as domestic industry in the matter of solar cells case before the Designated Authority after lot of debate and discussions with regard to their eligibility.
  - l. The Designated Authority and Director General Safeguards have been determining standing of the domestic industry both after including captive consumption and excluding captive consumption in those situations where a domestic producer has captive consumption of the product in the downstream product.
  - m. Imports made under projects category under chapter 98 under Customs Tariff Act are normally at zero customs duty and invariably at concessional customs duty. However, merely because the imports have been allowed under Chapter 98 with no or concessional customs duty does not imply that the resultant production shall not constitute domestic production.
  - n. Treatment of a unit in Indian SEZ by other countries: Production and export from SEZ attracts trade

defence measures. Subsidy duties have been imposed because of the benefits that have been given to such a unit. Thus, these exports have been treated as goods "originating in India".

- o. The various benefits given to SEZ unit should not impact the treatment of such a unit as a domestic industry. In any case and in fact, the incidence of customs duty on the finished product may be marginally higher than the incidence of customs duty and other benefits received by SEZ unit on raw materials and inputs. Thus, it is not a case where SEZ unit is enjoying double benefits.
- p. Petitions were earlier filed a number of times. The scope of product under consideration kept changing in these petitions. While the first petition was only on products falling under 7601 and 7602; the petitioners thereafter enlarged the scope to cover all the product falling under 7601 to 7608, excluding 7603. However, eventually, petitioners restricted the scope of product under consideration to only 7601, as DG considered it impermissible to file one application covering all the products from 7601-7608.
- q. Neither the domestic laws on safeguard measures nor Agreement on Safeguard provide specific guidelines on the period of investigation. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea wherein it was ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown". The relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past but the investigation period should be the recent past. The present submissions are based on information for the period from 2011-12 onwards till 2015-16.
- r. The petition was based on the period Apr-Dec.,'15. After filing initial petition, the DG Safeguards conducted a table verification of domestic industry information. Accordingly, some minor corrections were necessitated in the petition and the same were carried out. Thereafter, and post initiation, DG has conducted physical verification at the premises of all the companies and issued a verification report. Thus, now since DG Safeguards conducted physical verification and has issued a verification report, the petitioners have made present submissions based on this verified information by the DG Safeguards. Accordingly, there is a need for correction in the injury statement, so as to have present submissions consistent with the verification conducted by the Directorate.
- s. One of the major difference in the data/ information filed by the petitioners and verification report issued by the Directorate concerns capacity utilisation. The DG Safeguards have proceeded with the hot metal capacity with the petitioners. Further, since this hot metal capacity has been used by the petitioners for production of product under consideration and other products, the DG Safeguards has considered capacity utilisation by considering data/information of other products as well. In other words, instead of capacity utilisation in product under consideration, the DG has considered capacity utilised by the company for producing various products. Accordingly, petitioners have revised entire injury information.
- t. While directing the petitioners to file updated data for 2015-16, the DG has directed the petitioners to exclude data relating to SEZ plant. Since it was a direction, petitioners complied with the same, regardless of correctness or otherwise of the exclusion of SEZ plant data. However, petitioners provided information twice – once by excluding data of SEZ plant and once by including data of SEZ plant. Accordingly, petitioners are enclosing injury statements with these submissions both after including and excluding SEZ plant data. There is no legal basis for excluding SEZ plant data.
- u. Imports of the PUC are being reported under dedicated customs classifications for the PUC alone and the summary information published by the DGCI&S in determining volume of imports has been adopted. The data on various economic parameters is based on records maintained by the company. Data with regard to production, sales and inventories is based on excise records maintained by the company. Data with regard to selling price, cost of production and profit/loss is based on the financial records maintained by the company.
- v. Some information/ data has been provided on confidential basis and confidentiality has been sought thereon.

- w. The PUC for imposition of safeguard duty is "Unwrought Aluminium" which includes aluminium, not alloyed and aluminium alloys falling under custom heading 7601. The PUC includes aluminium ingots, aluminium wire rods and aluminium billets. Aluminium ingot is basic form of cast aluminium (unwrought) and it is made by the process of solidifying of liquid hot metal by pouring into a mould. Ingots are cast from molten aluminium metal with or without adding alloying elements. Aluminium wire rods are drawn from molten aluminium in a continuous casting and rolling mill with most common diameter of 9.5mm (other diameters are 7.6mm and 12.5mm). Aluminium billet is a length of metal that has a round or square cross-section, typically with a diameter range from 4" to 20". Billets are created directly via continuous casting. Billets are further processed for extrusion. Final products include profile, tubes and rods.
- x. Scope of the PUC in the present case includes all shapes, size, forms of unwrought aluminium. The present written submissions cover PUC of all dimensions, shapes, sizes, specifications, forms so long as these are classifiable under 7601 and even if these can also be classified in a classification other than 7601.
- y. Non alloy ingots are used as base metal for any type of aluminium products like extrusions, cables, conductors, secondary wire rod, metal powder, chemicals, alloy ingots for automobile industries and miscellaneous castings, utensils, foundry, casting and other industrial & engineering equipments, steel de-oxidizing, building and construction and so on. Alloy ingots are used in aluminium die casting industries for autocomponents, miscellaneous castings. Non alloy wire rods are drawn to wire for manufacture of cables and non alloy conductors. Alloy wire rods are drawn to wire for manufacture of alloy conductors. Non alloy billets & alloy billets are used for extrusions. Non alloy wire bars & alloy wire bars are used for decoration, construction, rivets, etc.
- z. Aluminium is most commonly obtained from a mineral ore called bauxite. Alumina (aluminium hydrate) is separated from the ore by dissolving the crushed ore in caustic soda, and pumping the slurry into a setting tank. This is known as the Bayer process. Pure metal is then obtained by the process of electrolysis of alumina by passing huge electric current through a solution containing alumina. About one ton of primary aluminium needs just less than 6 tons of bauxite.
- aa. The customs classifications are indicative only, and the same are not binding on the scope of the present written statement and proposed measures and they request imposition of safeguard duty on the product description regardless of classification.
- bb. WTO decisions in the matters of (a) EC-Bed Linen and (b) Farmed Salmon from Norway make it evident that there is no restriction in the law with regard to definition of product under consideration. The investigating authority is free to define the product under consideration in a manner considered appropriate. The injury analysis is not required to be undertaken separately for each type of the product under consideration. On the contrary, separate injury analysis is illegal.
- cc. Ingots, billets, bars, wire, rods are merely different forms of the product. Similarly, the only difference between alloys and non-alloys is in the composition of aluminium, which is achieved during the product process. Most of the producers globally produce different forms of unwrought aluminium.
- dd. The PUC can be in a number of forms, which includes ingots, billets, wire bars, wire rods, etc.. Mere difference in shape, size, forms do not render different types as different products. The DG Safeguards has issued a number of findings, wherein different shapes, forms and types were treated as one article. In the investigations relating to acrylic fibre, tow, top, and staple were considered as one article; in aluminium FRP & foils case, different kinds of FRP or foils were taken as one article; in stainless steel case, different size, width, thickness for different applications were treated as one product; in electrical Insulators case, glass & porcelain insulators and insulators for different applications were treated as one product. Further, substation, transmission insulators, equipment insulators were treated as one article. Similarly, different size, shape, width of the product were considered as one article. In oxo alcohols NBA, IBA and EHA were treated as one product; In seamless pipes & tubes case, product included several types of the product produced through different processes and line, boiler, casing and tubing were treated as one product. Similarly, there are numerous examples in the safeguard investigations conducted by other authorities globally and Designated Authority on Anti Dumping.

- ee. The goods produced by Petitioners are like or directly competitive product. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods in terms of essential product properties. While the scope of product under consideration is only products falling under 7601, the like and directly competitive article is being produced in India using scrap (secondary producers) and alumina (primary producers).
- ff. The Petitioners M/s Vedanta Ltd, Balco Industries and Hindalco Ltd. have standing to file and maintain petition for the subject goods, as far as "a major share" requirement is concerned. The production of Petitioners constitutes more than 50% of Indian production.
- gg. The scrap generated in India or imported into India can also be used to produce product under consideration. The petitioners have assumed that all the import of 7602 is utilized in producing ingot, billets, bars etc., and determined standing on that basis as well. The production of the petitioner companies still constitutes a major share in the Indian production. In any case, gross consumption of various types of aluminium products in the country is 28 lacs MT, whereas the production of the Petitioner companies is more than 19 lacs MT. The production of the petitioners constitute a major share in the Indian production.
- hh. Imports of unwrought aluminium constitute "increased imports" within the meaning of the Rules. The conditions for imposition of safeguard duty are increased imports- in absolute terms, relative to domestic production & relative to domestic consumption and injury due to increased imports. The rules require an analysis of the rate and amount of the increase in imports, in absolute terms and in relation to domestic production and consumption. The imports of the product should be sudden, significant, most recent and sharp but it does not mean such increase necessarily be at the end of the period of investigation or at the time of determination. Both end to end comparison and intervening trends may be seen in order to determine increase in imports.
- ii. In the US- Line Pipe, the Authority has stated that 'temporary change in the behaviour of the imports may not be sufficient to reverse an overall trend indicating existence of increased imports'. In US-Line Pipe, the Panel found that the word "recent" implies a "retrospective analysis"; but it does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation.
- jj. Petitioners have determined whether imports of PUC have increased in relation to production and consumption in India and compared imports of PUC with production and consumption in India. The imports of the product under consideration have shown a sudden, sharp and significant increase over the period. Further, imports have increased not only from end to end point, but also throughout the period. The imports have increased both in absolute terms as also in relation to production and consumption in India.
- kk. The market share of the domestic industry has declined in 2014-15 but increased marginally thereafter. However the domestic industry is unable to increase its market share since base year despite increase in demand. Market share of the imports have increased over the period. Market share of the Indian industry as a whole has declined.
- ll. The rules require increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms and as a percentage of domestic production. The increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. The word "recent" implies a "retrospective analysis", but it does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation. The analysis of the increased imports of unwrought aluminium has been conducted in the light of these evaluations.

- mm. Reasons for the increase in imports are that the producers across the globe have capacities more than their domestic demand which forces them to sell the products to other markets. Indian market is a sizeable market with a high growth potential and has been used to sell off cheaper goods. The majority of the metal being imported is of Middle Eastern origin.
- nn. The producers in Middle East expanded their capacities considering the global aluminium demand; this has led to excessive unutilized capacities with Middle East companies which are being utilized to export to Indian market.
- oo. Middle Eastern countries have increased their respective capacities for primary aluminium production considerably over the years. With no signs of decline in Chinese aluminium production, the increased capacities of the Middle Eastern producers are being utilized in India. There is a huge gap between the production and consumption of aluminium in these countries; thus, freight friendly markets such as India are a major market for the export of the goods.
- pp. With China expanding its own capacities it has also entered into the market as a strong player. This has led the Middle East countries to aggressively export to Indian market.
- qq. It has been contended by interested parties that imports of PUC from China are so insignificant in India that the same cannot be considered as unforeseen development. Petitioners submit that the requirement under the law is the factors/ reasons that have led to increase in imports. The requirement does not imply that the import per se must increase from the country concerned. If there are changes in market situation in China because of which imports have increased from third countries, such factors/ reasons prevalent in China are nevertheless relevant and important for deciding the reasons for increase in imports in the present case. In this context, market situation prevailing in China is one of the factors for the free fall of LME and resultant increase in imports.
- rr. Major cost in manufacturing aluminium is energy. Middle Eastern countries' electricity costs are significantly lower than other regions, therefore, the smelters in this region begin with a profitability advantage. Energy cost contributes to around 38% to Indian smelter, which is approximately \$700 per MT. The energy cost for UAE smelters stand around \$360 per MT. On the contrary, Indian smelters run on power generated by power plants that run on coal. The cost of running a coal power plant is costlier.
- ss. India is a freight friendly market for Middle East countries due to its geographical location and therefore it is convenient and economically more viable for them to export aluminium to India. Due to stagnant growth of product under consideration in Europe, India has become a target market for exporters/producers of Middle East which has led to increase in imports from these countries. Further the sea freight from Middle East to India has declined in the current period which has further led to increase in imports.
- tt. China imposes a 15% export duty on the export of primary aluminium. On the other hand, it offers a 13% tax rebate on export of value added aluminium products. This serves as an advantage to Chinese producers which have skewed global aluminium trade forcing shutdowns of various smelters across the world. This has also forced producers in other countries to export their products due to inflow of cheap Chinese semis.
- uu. Due to slow down in the Chinese economy, China is faced with excess capacities. Despite this, China's aluminium producers are not shutting down their smelters, because of support of local governments. Almost all aluminium producers in China are making financial losses at current aluminium prices. News reports state that China's aluminium production will rise by 11 per cent to over 30m tonnes in 2015 with a further 1.8m tonnes of capacity likely to come online next year. China continues to pump its surplus out to the rest of the world, depressing prices and pushing more smelters elsewhere to the brink of closure.
- vv. According to AZ China, the local government of Gansu province has lowered the cost of power to the plant to the point that Liancheng can at least break even at current prices.
- ww. At the moment any supply-demand gap in the aluminium market outside of China is being filled by Chinese exports of semi-manufactured products allowing exporters to avoid the prohibitive 15 percent tax on exports of metal and instead earn tax rebates on their exports of value-added products.

- xx. For the purpose of determining the "serious injury" certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". It is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.
- yy. The DI has considered the period from 2011-12 to 2015-16 for increased imports and injury analysis. Due to such increase in imports, the domestic industry is suffering serious injury.
- zz. The petitioners have considered dedicated capacity for Vedanta and Balco. However, in case of Hindalco, since the capacity is not dedicated, the petitioners have considered working capacity (calculated by ratio proportion method applying on hot metal capacity and hot metal production).
- aaa. Production and domestic sales of the domestic industry increased over the period. The plants in this kind of products are required to run at high operating rates. Overheads/ fixed costs are not met, if these plants are run at lower utilization rates. With the increase in demand, the domestic industry increased its capacities. The summarised factual position is as under:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Capacity	MT	12,51,400	12,53,700	13,54,480	21,88,728	31,39,569
Production	MT	9,97,282	10,63,882	11,53,951	15,01,542	15,99,740
Imports	MT	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964
Domestic sales	MT	5,18,295	5,91,784	5,04,675	5,01,513	7,00,486
Exports	MT	1,48,485	1,34,555	2,96,301	5,95,931	6,64,197
Demand	MT	20,36,574	22,34,732	21,46,481	23,63,727	24,39,251
Increase over base year						
Production	MT		66,600	1,56,669	5,04,260	6,02,458
Domestic sales	MT		73,489	-13,620	-16,782	1,82,192
Exports	MT		-13,930	1,47,816	4,47,445	5,15,712
Imports	MT		65,746	1,06,352	1,00,895	179431
Demand	MT		1,98,157	1,09,907	3,27,153	4,02,676

- bbb. The increase in production is largely in line with the increase in demand. Thus, the DI could have easily sold its increased production in the domestic market. However, the DI has not been able to sell the increase in production in the domestic market and has been forced to export the PUC in view of surging imports to prevent piling of inventories.
- ccc. As the DI was suffering losses in exports in the current year (2015-16), the DI gradually reduced the gap between its prices and the imported product prices in the domestic market to increase its sales.
- ddd. The DI is forced to export the PUC due to increased imports into India. The exports and financial losses suffered in exports should also be considered as one of the parameters of injury to the DI.
- eee. Whereas significant volume of imports are of alloy grades, significant portion of sale of DI is of non-alloy grades. Table shows that there is significant price difference between alloy and non-alloy product.

HS code	Volume	Share	Average price
760110	1,43,023	45.86	119.24
760120	1,68,820	54.14	132.91
Total	3,11,843	100	126.64

- fff. The DI has determined month-wise landed price of imports, landed price of imports if imports were made at average prevailing LME price during the period and selling price of domestic industry.
- ggg. From July, 2015, LME prices are significantly lower than the import prices because of the time lag. Imports and LME prices are significantly lower than the selling price of the DI. Thus, the landed price of imports is significantly below the selling price of the DI. The price undercutting is quite significant. The analysis is on the basis of selling price of the petitioner companies.
- hhh. Whereas the import price declined steeply over the period during 2015-16, the volume of import increased significantly.
- iii. Imports of the PUC are very adversely impacting the utilization of production capacities in the country which is quite low. Both alumina refining and aluminium smelting are continuous process operations and, therefore, need a steady supply of quality power. The producers have to ensure maximum possible production in order to reduce the utility costs. No producer can afford to hold inventories. At the same time, no producer can afford to regulate production or suspend production. Production process in the present product is totally different from an industry like electronics where switch off and switch on of production do not have any significant implications.
- jjj. Faced with piling up of inventories, petitioners had earlier resorted to significant export of the product. Whenever petitioners are not able to sell the product in the domestic market, petitioners have taken orders from outside Indian markets and exported the product. The DI has resorted to exports despite higher losses. If DI increases the exports where it is suffering higher losses the only plausible clause for the same must be its inability to sell product in the domestic market.
- kkk. The domestic industry is unable to dispose off its inventories due to increased imports. Petitioners are resorting to exports to dispose off its inventories.
- III. It has been contended by the interested party that the petitioner can very well supply the material in the domestic market at a price comparable to export price. The DI would have in fact suffered higher losses had it not exported the product and sold the same in domestic market.
- mmm. DI added manpower with the enhancement of capacities. The DI was however now forced to retrench manpower. One of the Petitioner companies has retrenched persons and would be forced to reduce more employment, should the present situation continue. Wages paid to the domestic industry have increased with the increase in employment levels.
- nnn. Profitability of the domestic industry has very severely deteriorated over the present period.
- ooo. Cash profits of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry is faced with cash losses during most recent period.
- ppp. The return on capital employed has remained low throughout the injury period and declined to lowest levels in the most recent data. The serious injury being suffered by domestic industry further gets established by the return on investment earned by domestic industry in the POI. Return on Investment earned by domestic industry is so low that the same is not permitting recovering of even interest costs, leave aside reasonable profits to the domestic industry. The continued increased imports would result in injury to the domestic industry in terms of profitability.
- qqq. There is no prescribed methodology with regard to assessment of threat of serious injury under Safeguard laws. In the absence of specific methodology under the Rules, the petitioner has referred to dumping law and WTO decisions to assess how threat of serious injury can be examined. In the particular circumstances of a case, a continuation of imports at an already recently increased level may suffice to cause such threat.
- rrr. In addition to the serious injury already inflicted on the domestic industry, increased imports of product under consideration are threatening serious injury to the domestic industry. The threat of serious injury is established by the following factors:
- The price difference between domestic and imported product is quite significant;
  - LME is constantly falling; the mark up between the domestic producers prices and LME has

- steeply declined in view of surge in imports;
- iii. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible;
  - iv. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period;
  - v. The domestic industry is faced with accumulated inventories;
  - vi. Not only that there is a decline in demand for the product under consideration globally; there is a likelihood of continued low demand. In fact, demand is constantly declining;
- sss. The global decline in demand has triggered steep decline in the product prices. Temporary increases in LME are of no relief to domestic industry. The injury information provided now is for the period upto March, 2016. The domestic industry suffered significant financial loss when the average LME was US\$ 1742 pmt. There is at the least further decline in LME. If the domestic industry suffered significant losses in 2015-16, it follows that the domestic industry is suffering financial losses even on the present LME.
- ttt. Due to slow down in the Chinese economy, China is faced with excess capacities. China continues to pump its surplus out to the rest of the world, depressing prices and pushing more smelters elsewhere to the brink of closure.
- uuu. It has been contended by interested parties that imports of PUC from China are so insignificant in India that the same cannot be considered as unforeseen development. The requirement under the law is the factors/reasons that have led to increase in imports. The requirement does not imply that the import per se must increase from the country concerned. If there are changes in market situation in China because of which imports have increased from third countries, such factors/ reasons prevalent in China are relevant. Market situation prevailing in China is one of the factors for the free fall of LME and resultant increase in imports.
- vvv. The imports of the PUC are already causing serious injury, the same is likely to intensify in due course, should the safeguard duties not be imposed immediately.
- www. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than the increased imports. There is no contraction in demand of PUC in India, thus, possible decline in the demand has not caused injury to the domestic industry. The pattern of consumption with regard to the PUC has not undergone any change. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry. Technology for production of the product has not undergone any change. Though the Petitioner has exported the product under consideration, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations and cannot be attributed to exports.
- xxx. Claimed injury to the DI is on account of PUC. Petitioner has segregated financial information with regard to PUC and provided in the petition.
- yyy. The requirement is "a" causal link and not "the" causal link. There is a very significant difference between "a causal link" and "the causal link". While the later implies that the only cause of injury should be increased imports, the former implies that increased imports should be one of the causes of injury.
- zzz. The mere fact that there is some other cause of injury as well does not mean that increased imports of the product under consideration are not a cause of injury.
- aaaa. In the facts of the present case, the increase in exports and losses being suffered by the DI is one of the factors showing causal link. The domestic industry is forced to export only because of the imports in India. There is otherwise no reason why the domestic industry should export the product when there is a demand in India.
- bbbb. Further, following shows causal link between increase in imports and serious injury to the domestic industry
- i. The product is largely sold in comparison/competition with imports.
  - ii. The imports of the product under consideration have increased significantly during the most recent period.

- iii. Increased imports are leading to significant accumulation of inventories.
  - iv. The domestic industry is constrained to resort to exports, wherein the domestic industry is suffering higher degree of injury due to low price of the product in the global markets.
  - v. The imports of the product declined in 2014-15. Consequently, profits of the domestic industry increased. However, in 2015-16, imports increased again, and the domestic industry suffered financial losses. This is due to the low prices imports entering the Indian market.
  - vi. Resultantly, the profitability of the domestic industry has declined significantly and was suffering losses.
- cccc. Petitioner requests imposition of safeguard duty for a period of two years.
- dddd. Public interest: Imposition of safeguard duty in the present case shall be in public interest, from the perspective of three different parties- the producer, the consumer and the general public as following:
- i. The measure would prevent further injury to the domestic industry from increased imports into India. Domestic industry is suffering significant injury and imposition of safeguard duty would prevent this injury to the domestic industry. It is vital to allow the petitioner to continuously produce the product for which imposition of safeguard duty is vital. Imposition of safeguard duty shall restore the injury suffered, arrest decline in the performance and will make the DI viable and competitive.
  - ii. It is in the consumer's interest to have a competitive Indian domestic industry capable of supplying the PUC to the consumers and compete with foreign producers. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic industry will face further injury and could eventually be wiped out giving foreign producers increased leverage.
  - iii. There are very limited consumers who actually bear the cost increases and benefit from price declines as PUC prices increase or reduce. A number of players in the industry work on pass through basis i.e. they pass on increases and reductions in raw material costs. The eventual impact of 10% safeguard duty on the consumers shall be 0.053%. Thus, it is without any basis that the consumers shall suffer as a result of imposition of safeguard duty.
  - iv. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry. Due to widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on the domestic production capacities. Further, usage of subject goods is must for industrial applications. Therefore it is extremely important from strategic point of view to reduce the import dependence.
  - v. If domestic industry is allowed to deteriorate to a condition in which it can no longer operate, Indian consumers will be almost completely dependent on foreign producers.
- eeee. Indian domestic producers have the capacity and capability required to meet the current and potential/future demand in the country.
- ffff. The eventual impact on the cost of the end products is insignificant.
- gggg. The Indian Producers have laid down a viable adjustment plan which focuses on cost reduction, further utilization of existing production capacity and capacity expansion to cater the growing demand.
- hhhh. The petitioner has set up another manufacturing facility to produce the PUC. The plant has commenced trial production but was unable to commence the commercial production owing to increased imports causing significant injury. The Plant will be fully operational at optimum capacity once the protection is granted under safeguard duty. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of unwrought aluminium in the country and to face fair competition from imports.
5. The brief summary of the rejoinders filed by the interested parties to the written submissions of other interested parties are as under:

**A. M/s Century Metal Recycling Private Limited**

- a. The factors such as concessions given under various Free Trade Agreements, decline in LME prices, setting up or enhancement of capacities in major exporting countries post FTA duty concessions reasonably constitute reasons for increase in imports and the same constitute unforeseen developments/circumstances.
- b. Imports of unwrought aluminium - both non-alloyed and alloyed have shown significant surge. The focus is on alloyed aluminium products where imports have increased as shown in the table below. This increase in imports is unprecedented, sudden, significant, sharp in recent period within the meaning of Safeguard Rules.

Details of Import of Aluminium Alloy Ingots (HS760120)

Year	Malaysia	Vietnam
<b>2013-14</b>	32329.35	51.00
<b>2014-15</b>	53821.71	1260.33
<b>2015-16</b>	53898.41	2401.92
<b>2016-17 (Annualized)</b>	83316.60	7561.42
<b>Increase in imports in 2016-17 over 2013-14</b>	162.5%	14723%

(Source .-Ministry of Commerce Website)

- c. Total domestic production of aluminium alloy ingots (HS760120) are to the tune of less than 500,000 MT whereas the imports of the said goods during 2015-16 was 224,570 MT constituting nearly 45% of the total domestic production.
- d. Such imports are increasing, therefore, the share of such imports cannot be considered insignificant, particularly in a situation where there is already significant surplus capacity in the country. Moreover, the low price at which imports are being made at present is causing severe injury to the Indian industry and the same is required to be checked by imposition of safeguard duty.
- e. It is not true that entirety of imports are under advance license. In any case, the mere fact that some of the imports are under advance license is entirely immaterial. DG considers all the imports, regardless of the nature of imports, for determining increased imports and the fact that these have been made without payment of customs duties has not been considered relevant in the past.
- f. Some parties have contended that the scope of the product under consideration is vague and wide. It is submitted that the different kinds of product under consideration differ only in terms of associated shape, size and composition. While primary producers' focus is production of non-alloyed form of product under consideration, primary focus of secondary producers is alloyed form of product under consideration. However, the only difference between the two is in the chemical composition. Otherwise, all types of product under consideration are comparable.
- g. It is a fact that the imports of the product under consideration are causing serious injury to the Indian industry. In fact, M/s Century Metal Recycling Pvt. Ltd. has also suffered significantly as a result of surge in imports of product under consideration.
- h. There is significant decline in the price of alloyed form of product under consideration.
- i. As regards submissions of opposing parties concerning public interest, it is submitted that public interest lies in protecting the domestic industry. The cheaper imports may benefit the end use consumers in the short run but the long term benefit for the domestic industry lies in the levy of safeguard duty. The parties opposing safeguard duty have failed to provide any verifiable information/documents to establish that imposition of safeguard duty would have any significant adverse impact on the end use consumers.
- j. Imposition of safeguard duty on unwrought aluminium (HS7601) comprising aluminium not alloyed (HS76011 0) and aluminium alloy (HS760120) shall have a significant positive impact on the domestic industry as it will check the sudden and significant surge in imports which is causing serious injury to the domestic industry.
- k. The proposed safeguard duty especially on imports from FTA countries shall not have any adverse impact on the end use consumers.

1. The imposition of safeguard duty shall provide a level playing field to the domestic industry manufacturing unwrought aluminium, both aluminium not alloyed falling under 760110 and aluminium alloy falling under 760120. It will also serve the larger public interest of not only domestic industry but also the end use consumers.

**B. Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand.**

- a. In spite of the increase of import volume, which has been claimed causing serious injury to the domestic industry, the production volume and domestic sales of the domestic industry have been increasing as well as the domestic inventory has been decreasing in the positive manner.
- b. The PUC includes a range of products, which should not be affected by the safeguard measure.
- c. The basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof is dubious.
- d. While the domestic industry is confronting with domestic loss, it is still able to increase its capacity, employment level as well as increase tremendously its wages. It is arguable whether such loss of the domestic industry is caused by increase in import or it is attributable to inefficiencies of the domestic industry or other factors.

**C. M/s. Jindal Aluminium Ltd.**

- a. Notwithstanding the explanation of the petitioners in justifying that a SEZ unit is a domestic industry, in reality SEZ is a unit situated in domestic area primarily for exports. Almost all the sales are for export market and the goods are not meant for domestic market. However, if goods are sold in domestic area the applicable taxes and duties need to be paid. This provision in policy is included to allow SEZ to sell some quantity in domestic area which can't be exported.
- b. Since the SEZs are not affected by the competition prevailing in domestic area, the installed capacity, production and sales of SEZ should not be considered for calculation of capacity utilization.
- c. The capacity of SEZ plant of Vedanta is not fully operational due to power and alumina issues. Taking the capacity of 1.25 million tonne of this plant in total installed capacity is with the malafide intention to lower capacity utilization.
- d. M/s Vedanta has established SEZ unit on the strength of benefits, exemptions and incentives granted to them for setting up the unit. If SEZ is to be treated as a domestic unit, the benefits granted should be surrendered by them.
- e. The definition of PUC is quite large and some of the products are not even imported in significant quantity. The definition of PUC covers both aluminium not alloyed and aluminium alloys in the form of ingots, billets, wire rods, wire bars etc. All these products are not interchangeable and are separate. Some of them, like wire rods are not even imported.
- f. The petitioners earlier submitted the application covering 'unwrought aluminium falling under Chapter 7601', but DG while notifying found it appropriate to add (aluminium non alloyed and aluminium alloyed) with this. It's not understood as to why the DG enlarged the scope of PUC on his own.
- g. Aluminium non alloyed and aluminium alloyed covers two different broad categories with different technical characteristics and cannot be treated as identical.
- h. There are only two items which are imported; unwrought aluminium (76011010) and billets (76012020). All other products under heading 7601 are either not imported or not manufactured by the petitioners.
- i. The alloyed ingots are not manufactured by the petitioners but by small secondary producers using scrap and imposing safeguard duty on this is not justified.
- j. Some quantity of alloy ingots is imported for some specific purposes due to quality and high domestic prices.
- k. Ever since the investigation has started, the data submitted by the petitioners have been changed 4-5 times to such an extent that the affected parties are confused and not in a position to understand as to which set of data is final for filing their response accordingly.
- l. The petitioners have submitted another set of data post public hearing which is even inconsistent with the data furnished by DG after on-site verification.
- m. Neither the petition, nor revised data and DG's preliminary investigation conclusively establish any link between rising imports and its direct impact on the profitability of the domestic industry.

- n. Imports have shown a marginal increase of 1,89,837 MT only in absolute terms in 4 years from 2011-12 to 2015-16 but as a percentage in terms of production, it has remained at almost at the same level and increased slightly.
- o. Import was 13% of production in 2011-12 and increased to 15% in 2015-16 as per Notice of Initiation of safeguard investigation dt 19.04.16. Even otherwise, the increase of 78% in 4 years is not at all alarming considering the overall growth in India. This increase which is quite normal cannot be treated as 'spurt' or 'sudden' calling for imposition of safeguard duty.
- p. The increase in imports has been gradual and consistent giving the applicant sufficient time to tweak their business plan, if required. In this period the petitioners' production increased by 76% and their exports increased by 336%. The petitioners installed capacity and domestic sales also increased by 40%.
- q. As per the data submitted by petitioners in their written submissions given on 7th October '16, there is absolutely no link or relation whatsoever between the profitability of applicants and quantity of imports. In 2013-14, their profits fell down whereas with almost the same quantity of imports in 2014-15, the profits increased to almost 12 times of 2011-12.
- r. It can be concluded that increase in import volumes have no affect on the profits of the applicants. Imports have been rising gradually with increase in economic development while the profits of the applicants have been fluctuating due to reasons which cannot be attributed to imports.
- s. In the year 2015-16, the import of primary metal i.e. ingot (not alloyed) was 1,97,394 MT only out of which most of the quantity was imported against advance license to the exporters, for their export entitlement. The same cannot be stopped as this is the special incentive being given to the exporters by the government of India.
- t. Besides this, there was an import of alloyed aluminium ingot in the country to the extent of 2,24,570 MT that was supplied from the FTA countries i.e. the countries having Free Trade Agreement with the government of India. Hence, there is negligible import in the country of unwrought aluminium ingot against OGL and there is no import of metal in the country to cause any competition to the domestic manufacturers.
- u. Claim of petitioners that increased imports have caused serious injury and have affected their financial situation and are the reason for their continuous losses, is baseless. The actual reason of their losses is increased interest and depreciation on the heavy capital expenditure by all the applicant companies; Hindalco, Vedanta and Balco.
- v. In their annual accounts for the year 2015-16, Hindalco has admitted that they have completed their expansion project and there will be no more capital expenditure during the current financial year. Hence, they will be earning more profits during the current year. Hence, there is no justification in considering their request for any safeguard duty.
- w. According to the statement made by Managing Director of Hindalco while announcing their financial result for the FY 2015-16,
  - i) Their profit during FY 2015-16 is Rs.607 Crores
  - ii) Their profit is less due to depreciation and high finance cost on increased capital expenditure on capacity expansion.
  - iii) They are working at full capacity
  - iv) Since they have completed all their expansions, finance cost will be less henceforth and profit will increase.
- x. Hindalco's new Chief Executive in a detailed press interview has explained Hindalco's strategy to reduce the debt burden in order to improve the profits further.
- y. Hindalco has managed to show a stellar performance in 1st quarter ended April-June '16 by earning profits of Rs 294 Crores as compared to Rs 61 crores in the corresponding quarter of 2014-15 – a growth of 382%. This will improve further in coming quarter with reduction in debt, as planned.
- z. M/s Nalco (not a petitioner) has also earned a net profit of Rs 139.12 Crores in April-June '16.
- aa. The profitability of petitioners is slightly affected presently due to increased burden of depreciation, finance expenses on huge capital expenditure in creating additional capacities. Nowhere is it established by the petitioners that the industry is threatened due to rising imports.
- bb. The applicants' claim of lower capacity utilization of 48% is false as production of only unwrought aluminium has been taken.

- cc. The applicants have submitted the revised set of data showing 97% capacity utilization after onsite visit by Directorate of Safeguards. This raises serious doubt on the authenticity of data submitted earlier, based on which the investigation is initiated.
- dd. The MD of Hindalco while announcing their financial results for FY 2015-16 has confirmed that Hindalco is working at its full capacity.
- ee. Aluminium being a commodity, its prices are prone to fluctuations like any other metal. As the prices of the petitioners are linked with LME, their fortunes also keep on changing with these fluctuations. The petitioners file such applications whenever the LME prices are sluggish, making some flimsy ground like rising imports, dumping of material etc.
- ff. The aluminium prices have increased almost 12% in the current year since January and the profits of the petitioners have increased by Rs 14,500/- MT, though the imports have continued.
- gg. Since the LME prices have improved, the DGSG should wait for this downward trend be over.
- hh. The secondary manufactures are also equally affected by the downtrend and sluggish demand.
- ii. For levy of Safeguard duty on any product, the Applicants must prove the following:
  - i) Production of Domestic Industry has come down due to imports.
  - ii) Domestic industry is suffering loss due to cheap imports.
  - iii) Domestic industry is forced to reduce manpower.
  - iv) There is heavy surge in the import causing injury to the domestic industry.
  - v) Inventory has increased as the domestic industry is not able to sell.
- jj. None of these vital signs which prove injury to an industry are present in this case and
  - i) The domestic industry is operating at almost 100% of its capacity.
  - ii) The domestic industry is making profits but profits have come down. Their profits are lower due to incidence of higher interest and depreciation on their huge capital expenditure, not because of imports.
  - iii) The manpower of domestic industry has rather increased by 5% and wages has increased by 100% between 2011-12 and 2015-16.
  - iv) There is no surge of imports. The imports have been fairly consistent and whatever marginal increase taken place during the period is normal and corresponding with the economic growth.
  - v) As per notice dated 19.04.14 of DGSG, inventory has rather reduced in 2015-16 compared to 2011-12 even with appreciable increased production and sales between these periods. This proves petitioners are able to sell the entire quantity and there is no injury.
- kk. The industry which doesn't show any signs of retrenched employees, no unutilized capacities, no abnormal decline in profits, can't be treated as under threat and be given extra protection of safeguard duty or any other duty just to amass extra profit at the cost of general public.
- ll. Most of the imports are against advance license for entitlement of exports. Apart from that some quantities are imported mostly from FTA countries. DGSG can verify the data and if felt necessary, the import from FTA countries be stopped.
- mm. If safeguard duty is imposed, it will cause serious injury to the entire secondary manufacturing industry engaged in downstream aluminium products and drive them to the closure.
- nn. All the secondary manufacturers of different aluminium products will be forced to buy their raw material from these primary producers on the higher prices. They will have to compete with primary producers for the downstream aluminium products as they are also engaged in the manufacture of the same on large scale.
- oo. Thus, it will be a two edged sword in the hands of the primary producers, on the one hand, to earn profit from sale of raw material and on the other to acquire monopoly on the downstream products by forcing the small and medium industries to close down their units.

#### **D. Aluminium Secondary Manufacturers Association**

- a. The petition submitted by the domestic industry is entirely baseless and far from the facts.
- b. As far as the injury is concerned, the same occurs in the following conditions:
  - i) If the industry is running in losses due to imports.
  - ii) If there is under-utilization of the installed capacity.
  - iii) If there is any retrenchment of the staff, employees and workers.
  - iv) If there are large scale imports.

- c. It has been proved beyond doubt that none of the above mentioned conditions are at all applicable to applicants as they are earning very reasonable profits. They are enclosing the copies of unaudited results of Hindalco for Q1 of 2016-17, audited results of Vedanta (including Balco) for 2015-16.
- d. Though their percentage of profit have slightly been affected for the year 2015-16 in comparison to previous years but that is entirely due to increase in interest and depreciation incurred on huge capital expenditure incurred for increasing their capacities; or /and adjustment of some exceptional expenses.
- e. The capacity utilization of 48% as claimed by the applicants is grossly incorrect since all the applicants are running their plant at full capacity.
- f. The applicants are engaged in many other products apart from those listed under chapter 7601, like extrusions, rolled products, foils etc. The installed capacity for this reason should be calculated with reference to the capacity of smelted hot aluminium which is converted in any products, decided by the petitioners.
- g. As verified by the Directorate General of Safeguard the installed capacity of hot metal combined of these companies is 20,39,569 MT per annum; whereas the production against the above installed capacity during the year 2015-16 was 19,84,765 MT i.e. more than 97% of the installed capacity.
- h. The manpower of the domestic industry has increased 5% between 2011-12 and 2015-16 and wages have increased by more than 100%.
- i. The domestic industry's man power cost has increased by 100%. This is an ample proof of a profitable industry operating at its peak.
- j. The inventory has also reduced in 2015-16 compared to 2011-12 even with significant increase in production and sales between these periods. This proves petitioners are able to sell the entire quantity and there is no injury.
- k. Hence, the industry which is making reasonable profits, running at 97% installed capacity, increases its manpower and reduces its inventory do not deserve any undue protection and their application for the safeguard duty is liable to be rejected.
- l. Applicants are already exporting about 8.2 lakh MT of primary aluminium on the international prices i.e. LME + premium; whereas on the entire supply in the domestic market to the extent of about 12 lakh MT, they are enjoying a premium of about 13% due 8.25% customs duty and clearing/forwarding charges, applicable for imports.
- m. The landed cost of the metal in the country is based on the LME price + premium + customs duty + cess + clearing and forwarding charges, inland haulage charges etc. The domestic industry always keep their prices in the domestic market equivalent to that of the landed price of imported metal and earn extra 13% over and above the international prices.
- n. Protection to domestic industry is not required, since there is no surge in the import of primary metal in the country. During last six years the import of primary metal is ranging between 13 to 15% of the total production.
- o. The growth in imports was marginal and in line with overall economic development. Most of the imports which take place now are against Advance Authorisation Scheme as entitlement of exports which will continue and do not affect the domestic industry. Besides this, some quantity of alloy ingots is imported from nearby FTA countries.
- p. Import of alloy ingots also do not cause any injury to the domestic countries as the same is not manufactured by the domestic industry since raw material for the same is scrap. In both the above category of imports safeguard duty is not applicable and do not affect the domestic industry.
- q. The domestic industry could not establish a link between rising imports and their profits. The imports though increased slightly but are at the same percentage of production whereas the profits of the domestic industry have fluctuated between 2011-12 and 2015-16.
- r. The purpose of filing the application is just to increase the profits by raising the prices of the aluminium sold in the domestic market and earn more profits.
- s. Raising the domestic prices will not stop imports since domestic prices are linked to cost of imported aluminium. Safeguard duty will increase the cost of imported aluminium.
- t. They request not to impose any safeguard duty which will hit the secondary manufacturers very hard and cause inverted duty structure. Prices of raw material will increase due to safeguard duty and secondary products will become cheaper.
- u. All the secondary manufacturers of different aluminium products will be forced to buy their raw material from these primary producers on the higher prices and on the other hand, they will have to

compete with them (primary producers) for the downstream aluminium products as they are also engaged in the manufacture of downstream products.

- v. This will happen at a time when the small downstream manufacturers are already reeling under stagnant demand, fall in exports and increasing losses.
- w. Many small and medium companies are on the verge of closure due to large scale import of aluminium secondary goods from China, subsidized by their Government due to 13% export subsidy and imposition of safeguard duty will worsen the situation further.

#### **E. M/s. Aluminium Bahrain B.S.C**

- a. In light of the decision of the CESTAT in the case of *Pig Iron Mfrs. Assn. V Designated Authority* 2000 (116) E.L.T. 67 (Tribunal), it is clear that captive producers of a product are not considered as domestic industry with respect to the said product as they do not sell such product in the domestic merchant market and thus are not in competition with imports of the said products. Similarly, an EOU or SEZ unit which primarily sells in the export market and does not compete in the DTA cannot be considered as the domestic industry.
- b. The Petitioners have attempted to justify the multiple changes that have been made to the data of the domestic industry. The Exporter had submitted detailed arguments on this issue vide its written submission dated October 7, 2016. The Exporter further submits that:
  - i. The change in the data provided by the Petitioners with respect to the certain parameters cannot be attributed to the change in capacity because the production, sales, profit/loss and stock figures could not have taken into consideration the products which are not a part of the product under consideration.
  - ii. The revised data submitted by the Petitioners post-public hearing contradicts the second Verification Report. The only data that is same in the second Verification Report and the revised data post Public Hearing is capacity utilisation which is the only parameter that was explained by the Petitioners. All the other parameters have been claimed to be minor changes.
  - c. It is not clear when the DGSG has already conducted on-site verification and subsequently issued verification report, how the data for entire period of investigation has changed so substantially.
  - d. The Exporter submits that there is no clarity as to which data pertaining to the domestic industry should be relied upon in order to make its submissions which is a blatant violation of recognised and established principles of natural justice.
  - e. The principles of natural justice require that party who is proceeded against must be made available with all evidence against such party and must be given an opportunity to rebut such evidence. Due to the Petitioners inability to provide reliable data, the Exporter is deprived of its right to rebut evidence.
  - f. The Petitioners have claimed excessive confidentiality on injury information and adjustment plan as submitted by the Exporter vide their written submission.
  - g. An EOU or SEZ unit cannot be considered to be part of the domestic industry and accordingly data pertaining to the SEZ unit must be rejected by the DGSG.
  - h. The Petitioners in order to prove that the increase in imports is sudden, significant, recent and sharp have conducted an end-to-end comparison of the data provided for imports into India by comparing the imports in the base year i.e. 2011 – 12 to the imports in the Period of Investigation i.e. 2015 – 16.
  - i. The end-to-end analysis that was conducted by the Petitioners is inconsistent with the WTO. The issue of end-to-end comparison was discussed by the WTO in the *Argentina - Safeguard Measures on the Import of Footwear (Argentina – Footwear)* and vide their Panel Report dated June 25, 1999 - WT/DS121/R as well as their Appellate Body Report dated December 14, 1999 - WT/DS121/AB/R held that the analysis with regard to the increase in imports must not be based on a comparison of the end points i.e. the Period of Investigation and the base year, but must also necessarily include the intervening periods.
  - j. The Petitioners in order to substantiate their claim have incorrectly reported the increase over preceding year (MT) as the increase over base year (MT).
  - k. The increase in the imports from 2011-12 to 2012-13 was 27.1% and the increase in imports from 2014-15 to the Period of Investigation was 25.8%, which proves that the increase in imports was not

sudden or a recent occurrence. Thus, even if reliance is placed on the Petitioners' data, there is no evidence of the increase in imports being sudden or recent. Accordingly, the investigation should be terminated forthwith.

1. While the Petitioners argue that the producers across the globe have excess capacities, the Petitioners do not provide any data or evidence to substantiate the same. Rather the Petitioners argue that there is excess capacity in China. With respect to the alleged excess capacity in China, the DGSG, in a previous safeguard investigation concerning imports of 'Not Alloyed Ingot of Unwrought Aluminium' into India Initiation Notification F. No. D-22011/17/2009 dated May 22, 2009 has held as follows:

*"82.3 Regarding increase in imports from China, the DI has not submitted any data and therefore, this contention is not acceptable."*

It may be noted that the Petitioners had provided the very same arguments in the previous investigation with respect to China and yet the DGSG had held that no case on 'unforeseen developments' was met by the Petitioners.

1. While the Petitioners argue that the producers across the globe have excess capacities, the Petitioners do not provide any data or evidence to substantiate the same. Rather the Petitioners argue that there is excess capacity in China. With respect to the alleged excess capacity in China, the DGSG, in a previous safeguard investigation concerning imports of 'Not Alloyed Ingot of Unwrought Aluminium' into India Initiation Notification F. No. D-22011/17/2009 dated May 22, 2009 has held as follows:
- m. With respect to claims of unforeseen development regarding Middle East, the DGSG in the 2014 investigation held as follows:

*"82.1 The expansions in capacity in the Middle East per se cannot be considered as unforeseen since expansion in capacity is not an overnight process. It takes considerable time to expand capacities to such levels. Further such expansions are not as a consequence arising out of India's obligations under the GATT and therefore, expansions in capacity in the Middle East, cannot be taken as unforeseen development."*

*"82.2 Regarding other claim of cheap energy cost and freight cost in export to India, there is nothing unforeseen about it. It is common knowledge that due to their oil/gas reserves, Middle East countries have cost advantage in production of energy and due to their proximity to India they have freight cost advantage."*

- n. From the above, it is clear that mere expansion in capacity or cheap energy cannot be seen as unforeseen development within the meaning of Article XIX of GATT.
- o. To clarify, the Exporter does not argue that for an unforeseen development to occur, the imports from the country subject to alleged unforeseen development must increase. Rather, the Exporter submits assuming there is excess capacity of the PUC in China, there is no reason that imports from China would be below *de minimus*. The Petitioners have provided no explanation as to why the imports from China are below *de minimus* even when they claim that there is excess capacity in China. This further contradicts the Petitioners' claim with respect to the unforeseen development.
- p. The Exporter submits that the Petitioners have been attempting to make baseless averments with regard to the unforeseen developments without any legal basis.
- q. The Exporter submits that "serious injury" is a very high threshold that needs to be met and the same has been laid out by the WTO in their Appellate Body in US—Lamb which described "serious injury" as a "very high standard of injury". Therefore, only showing dispositive figures cannot in anyway prove that the Petitioners have suffered "significant overall impairment". Assuming that the revised data submitted by the Petitioners is correct, it would show that there is no injury, let alone serious injury.
- r. The table captures the data on production, domestic sales and domestic sales value. The production of the domestic industry has increased by 52% over the POI, domestic sales have increased by 32% and so has increased the domestic sales value over the Period of Investigation.

#### Petitioners' Injury parameters

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
<b>Production – Index</b>	100	107	116	150	158
<b>Domestic Sales (MT) – Index</b>	100	114	97	97	135
<b>Domestic Sales (Value) – Index</b>	100	118	102	115	132

Source: Revised data post Public Hearing (Without SEZ)

- s. The Exporter therefore submits that the Petitioners' averments with respect to serious injury should be completely disregarded as they are false and cannot be substantiated by the data provided by them.
- t. The Petitioners have attributed their inability to utilize the increased capacity on the imports. The Petitioners have stated that due to the "increase in demand, the domestic industry has increased its capacity". This statement is incorrect because increase in capacity is not proportionate to the increase in demand. The Petitioners had increased their capacity in 2013-14 by 1,00,780 MT while in the same year the demand reduced by 88,251 MT. Moreover, the Petitioners have during the Period of Investigation increased the capacity much more than the demand.
- u. The Petitioners have conveniently blamed the imports for bad business decisions made by them which have resulted in excess capacity.
- v. Further, the Petitioners argue that exports by the Petitioners and financial losses suffered in exports should also be considered as one of the parameters of injury to the domestic industry. This claim is not only unsupported by law but is devoid of any logic and is rather outlandish. The export performance of the Petitioners have no correlation whatsoever with the conditions of competition in India. The Exporter submits that alleged injury suffered in export sales cannot be considered while assessing injury.
- w. The steep increase in export sales over the period of investigation clearly shows that the Petitioners themselves are not supplying in the domestic market.
- x. The Petitioners have not provided any clarity with respect to the data on price undercutting. In any case, based on the data submitted by the Petitioners, it is clear that import prices are above LME prices all throughout. Further, it is not clear as to what figures have been considered by the Petitioners to arrive at price undercutting figures i.e. whether domestic selling prices have been compared with LME price or import prices.
- y. The Exporter submits that relying on the data of the Petitioners, there is no injury on account of capacity utilization which in fact increased by 2 indexed points when compared to base period. Further, the data with respect to SEZ cannot be taken into account for reasons as stated by them.
- z. The company-wise profitability information provided by the Petitioners vide letter dated May 23, 2016, evidences that the two of the Petitioners i.e. Vedanta and Balco are making huge profits and hence cannot be considered as injured.
- aa. Since two of the Petitioners have clearly made profits during the Period of Investigation, any losses suffered by Hindalco cannot be attributed to imports. Further, Hindalco vide their Annual Report 2015-16 have stated that they experienced an upward trend in the profitability.
- bb. The Petitioners claimed that there is also a threat of serious injury and have made baseless averments with respect to LME prices and stock which cannot be attributed to the increase in imports:
  - i) LME is constantly falling: LME price fluctuations are a global phenomenon and the alleged fall in LME prices cannot be attributed to the volume of imports which is a precondition for any safeguard measure. The global pricing of aluminium is largely influenced by the London Metal Exchange (LME). Due to severely fluctuating prices as per the LME, prices across the world have been affected adversely, including the domestic industry.
  - ii) Accumulated inventories: The Petitioners' submission with respect to accumulated inventory is completely inaccurate as the closing stock has reduced from 5,708 MT to 891 MT which proves that the Petitioners have successfully been able to make sales not only of the produced goods during the Period of Investigation but also the inventory stock during 2014-15.
- cc. The Exporter has provided various non-attributable factors which have caused an injury to the domestic industry vide their written submission dated September 7, 2016. Therefore, due to the existence of other non-attributable factors that have caused injury to the domestic industry, the requirement of increased imports being the sole reason for the injury suffered by the domestic industry cannot be met. The DGSG must terminate the investigation due to non-existence of "the causal link".
- dd. In FY 2014-15, the imports rose 42 index points from the base year and in the same time period, the Petitioners' profits increased by 54 index points from the base year. The imports into India have been consistently increasing while the profits of the Petitioners have been fluctuating due to reasons which cannot be attributed to the imports.

- ee. Additionally in 2015-16, the imports increased by 24 index points from the previous year while the Petitioners' profit decreased by 177 index points. Such a sharp decrease in the Petitioners' profits cannot be attributed to the slight increase in the imports.
- ff. The Petitioners have not provided any guidance as to how the cost reduction would be achieved. Further, mere expansion of capacity cannot remove inefficiencies of the domestic industry.
- gg. The Petitioners have failed to submit any viable adjustment plan other than some bald and ambitious statements.

**F. M/s Vedanta Limited- Aluminium & Power; Bharat Aluminium Company Limited; Hindalco Industries Ltd. (Domestic Industry)**

- a. The petitioners have identified following parameters as unforeseen developments and submit that these constitute unforeseen development within the meaning of Safeguard Agreement:
  - i. Increasing capacity with Middle Eastern countries
  - ii. Chinese producers also started exporting
  - iii. Cheap Energy Cost
  - iv. Decline in sea freight from Middle East
  - v. Export tax on primary aluminium and tax rebate on value-added products from China
  - vi. China Building Stock
- b. Petitioners submit that FTA concessions constitute an unforeseen development, as it cannot be expected that as a result of FTA concessions, (a) new manufacturing facilities shall be set up, (b) the exporters will start selling at low price. FTA concessions have been given by Govt. to allow other member country to sell the product in India. However, it is expected that the same shall not be at low price.
- c. While acceding to WTO, India did not foresee that it shall grant FTA concessions to the member countries and the same shall lead to the low price imports in India.
- d. While acceding to WTO, India did not foresee that the LME will fall to the degree it has fallen.
- e. The DG has fully complied with the investigation procedure.
- f. The interested parties are in fact participating in the investigation and have defended their interests to the extent they wished. Not only the DG has allowed opportunity to interested parties to file relevant information, but also, DG has provided opportunity to interested parties to defend their interests orally.
- g. The questionnaire is in respect of companies who are not part of the petition. Those companies who are part of the petition in any case have already provided all these information to the DG. This becomes evident from perusal of the application proforma and performa for domestic producers.
- h. The Designated Authority has provided opportunity to all the interested parties and the investigation has been conducted in fair and impartial manner. There is no legal or factual basis for stating that the DG has been unfair or partial in any manner.
- i. The DG has conducted spot verification and has thereafter issued verification report. This verification report supersedes the information filed by the petitioners. Further, petitioners have made elaborate written submissions, a copy of which has been made available to other interested parties.
- j. Country-wise imports breakup has already been provided by the petitioners. Further, petitioners have adopted published DGCI&S data, which is available in public domain and all interested parties have access to the same.
- k. The claimed injury to the domestic industry is not because of increase in capacities or increase in overhead costs due to possible increase in capacities.
- l. The DG has very clearly written in the verification report that the data is upto 2015-16.
- m. The fact that NALCO has not supported the petition is entirely immaterial when production of the petitioners constitute major share in Indian production.
- n. Merely because different products included in the scope of PUC differs in term of shape, size or composition the same does not imply that the resultant products are different.
- o. The mere fact that the product types involved are bearing different description under the Customs Tariff Act does not imply that the different types are different articles.

The contentions of the interested parties and responses of DI thereon are as under:

- p. Aluminium alloys falling under subheading 760120 should not be included in the scope of PUC and it should be restricted to sub-heading pertaining to aluminium not alloyed which is 760110: The petitioners strongly object. Firstly, petitioners produce the like or directly competitive article to the PUC. Elaborate information provided at the time of spot verification is referred to and relied upon. Further, the petition has been supported by those producers who are exclusively producing and selling products falling under subheading 760120.
- q. CTH 7601 itself includes wide range of products. The products have many different characteristics such as different raw material, basic product properties, end uses and price. The products are neither interchangeable nor substitutable: The petitioners strongly object. Products falling under 7601 essentially differ in terms of their shapes, size and composition. Different shapes of the product can be produced by rolling hot metal into the desired shape. Further, different chemical compositions can be achieved in the product by controlling the raw materials used in making the product. The mere fact that the resultant products have different specification, uses or prices is entirely immaterial. In fact, the price of all the products included under 7601 have moved in tandem/same direction. This further establishes that the difference in price is only because of difference in composition of product or shape or size. However, all product types constitute one product.
- r. It is also relevant to note that the inability of the consumers to use different product types interchangeably is never considered criteria for defining the scope of PUC.
- s. The DI does not produce Aluminium Alloys: The statement is factually incorrect. The verification documents clearly provide information on production and sale of alloyed aluminium products produced by the petitioners.
- t. Price of the product ranges from Rs 99 per KG to 2447 per kg. This distorted price range is result of faulty PUC determination: The petitioners submit that the two price ranges considered by the party are extreme. Even for one HS code, the price of the product varies very significantly. If the argument of interested parties were to be accepted, it shall imply even within the same 8 digit HS code, there are significantly different products. Evidently, that cannot be the case. Notwithstanding, petitioners submit that difference in prices can never be a criteria to determine the scope of PUC. The DG recommended safeguard duties on such products, wherein different product types carry significantly different prices. However, the DG considered them one product and Govt. has imposed safeguard duties on these products.
- u. List of PUC produced by the DI should be provided: The petitioners have provided elaborate information on product types produced and supplied by the domestic industry. In fact, the information has been provided on the basis of excise classifications. The DG therefore has all relevant information on record with regard to the production and sale of different product types falling under different classifications.
- v. Special products like aluminium ingots of A356 series should be excluded from the scope of PUC because the same is not produced and supplied by the DI: Petitioners strongly dispute. The product type is produced and supplied by the domestic industry.
- w. PUC includes aluminium ingots, wire and billets. Non interchangeable due to difference in the production process renders them out of direct competition with each other: The PUC need not include product types which must be interchangeable for the consumers. In fact, there have been large number of investigation conducted wherein product under consideration included such product types which were not interchangeably used by the consumers. In fact, in majority of the investigations, product under consideration is such which are not interchangeable from consumer's point of view.
- x. Impact of the imports needs to be analysed separately for the three different products: Petitioner dispute and submit that increased imports and serious injury to domestic industry is required to be determined for product under consideration as a whole and not separately for each product types.
- y. Petitioners claim cheaper import rates, such claim defeat the LME Pricing structure and successive cost additions: Submissions made before clearly demonstrate that the difference between PUC import price and LME is declining over the years. Thus, while PUC price is decided based on LME, the import price did not follow the same LME pricing structure as was followed in the base year of the POI. This further establishes that increase in import is due to significantly falling difference between LME and pricing structure being followed by the exporters.
- z. Applicants' selling price is in parity with imported goods, in spite of being immune to the various duties and charges: This clearly establishes that the selling price of the domestic industry follows the import price. It is for this reason that the imports have caused injury to the domestic industry. As

regards various duty charges, petitioners submit that their prices reflect all applicable duties and charges.

- aa. Decreasing premium affecting DI's profit is baseless: The mark-up on LME has declined as shown in the table below. This decline is in addition to decline in LME price itself over the period.

Month	LME USD MT	Spot Premium
Apr-14	1810	367
May-14	1749	367
Jun-14	1834	367
Jul-14	1945	405
Aug-14	2030	404
Sep-14	1992	404
Oct-14	1938	410
Nov-14	2054	410
Dec-14	1913	400
Jan-15	1808	400
Feb-15	1821	395
Mar-15	1773	370
Apr-15	1817	270
May-15	1805	194
Jun-15	1683	99
Jul-15	1638	100
Aug-15	1540	95
Sep-15	1589	93
Oct-15	1524	88
Nov-15	1466	89
Dec-15	1494	96
Jan-16	1479	110
Feb-16	1536	107
Mar-16	1531	110
Apr-16	1564	111
May-16	1556	95
Jun-16	1592	85
Jul-16	1630	80
Aug-16	1642	75
Sept -16	1558	70

- bb. The safeguard duty will adversely impact the downstream (cables, conductors, transformers, any product group using aluminium as primary raw material) industry and ultimately the end consumer:

- The petitioners have already established that imposition of safeguard duty will not have adverse effects on the consumers, as these producers are in pass through industry. Since the producers are in pass through industry, they will pass on any cost increase or reduction to the consumers and therefore proposed safeguard duty shall not adversely impact them.
- cc. Increase export tax of aluminium and supply it duty free on LME rates, without premiums: Imposition of export tax on product under consideration will kill this industry. The domestic industry as such is not able to sell in the domestic market due to increased imports. Imposition of export tax shall imply that the domestic industry will not be able to sell the product either in the domestic market or in the export market. Under the circumstances, the domestic industry will have to shut down the production.
  - dd. Aluminium industry to provide aluminium at fixed price in line with LME contract to protect the interest of downstream industries both for fixed price contracts for sale, and against fixed price bids not yet allotted: In any case, petitioners undertake not to charge any safeguard duty to all those consumers who have fixed price contracts with the consumers as of the date of recommendations of safeguard duties.
  - ee. Safeguard duty should be passed for HS Code 7601.20, i.e. Aluminium alloy, as it would aid the downstream industry engaged in manufacturing from the import hit specially from ASEAN Countries under FTA: The proposed safeguard duty is on all products falling under 7601 and it is very clear from the written submissions filed by CMR that CMR also have suffered material injury from the increased imports.
  - ff. Non interchangeable products under 7601 as billets and alloy have different processing and end use: Various products falling under 7601 are produced on the same manufacturing facilities and are interchangeably produced by the producers.
  - gg. Petitioners have claimed excessive confidentiality with respect to Injury Information. : Petitioners have claimed only such information as confidential information, confidentiality of which is protected under the rules. No information has been claimed confidential by petitioners, which is in public domain. Information that is not in public domain cannot be disclosed.
  - hh. There is no sudden and sharp increase of imports: The data clearly establishes increased imports. There is clear increase in imports in present case when compared with other cases where duties have been imposed by Govt.
  - ii. 78% rise in imports over a period of 4 years is natural for a nation like India. DI is not affected negatively. A marginal increase of 15% in imports: The increase in import was 74% over the period. Further, whereas the demand grew by 20%, imports increased by 74%. Thus, increase in imports was far higher than increase in demand. It would be seen that the exports by domestic industry is higher than imports into India, which clearly establishes that the domestic industry could have easily met the demand of the product in the country and imports were not necessary to meet rising demand of the country.
  - jj. There is no reason why domestic industry would prefer to export and incur higher losses rather than selling in the domestic market. The only plausible reason for these exports is inability of domestic industry to sell the product in the domestic market in view of increased imports of the product in the country.
  - kk. Imports cannot be stopped in absolute terms because most of it is imported under advance licensing. Actual imports can be figured out once import against advance licence is excluded out of total import: The issue has already well decided by the Safeguard authority in the past cases. The authority has never segregated imports made under advance license. The rule also does not specify that the authority shall determine increased imports after segregating and eliminating imports made under duty exemption schemes. Further, merely because imports under advance license shall not be subjected to proposed safeguard measures, the same does not imply that the same shall not be considered for determining increased imports.
  - ll. False and misleading information furnished by the applicants regarding imports from China PR and Middle East. Details of the same are sought: Full details of imports of the product from various countries have been provided. Further, the petitioners' claim is based on published DGCI&S data and therefore there can be no question of false and misleading information having been provided by the domestic industry. Petitioners have never alleged that imports have surged from China. Petitioners have contended that in view of changing market situation in China, imports have increased in India. Whereas China was the major importer of PUC, China has become an exporter of

the PUC resulting in significant surpluses with other producers globally. It is thus surplus in the global market which is forcing other countries' producers to divert the product in Indian market.

- mm. Downstream industry forced to import as the DI is reluctant to deliver goods against the Advance License: Import under advance license in any case will not be subject to safeguard duty and therefore the interested parties need not be concerned and should not oppose the proposed safeguard duty on this account. The consumer can continue to source their requirements through imports under advance license and without payment of safeguard duties.
- nn. Non-payment of duties and taxes over LME would aid reducing imports: While non-payment of duties and taxes to the LME price may help in reducing imports, this would lead to intensified injury to the domestic industry. The domestic industry has suffered a combined loss of Rs 170 crores during 2015-16. If the selling price is reduced by an amount of taxes and duties, the losses to the domestic industry shall increase to 432 crores.
- oo. Alleged import influx claims by petitioner are not supported by their ever increasing profits, and non-retrenchment of workforce : Profitability of the domestic industry declined steeply over the POI. Thus, the arguments of interested parties are not based on the facts. As regards retrenchment of workers, petitioners are producing to the extent they can and therefore there is no question of retrenching workers.
- pp. Non segregation of imports made under export promotion "duty free" scheme with "OGL" duty paid scheme, misleads the imports made under duty paid route : The DG had earlier conducted a number of investigations and has not segregated imports into duty free and duty paid. Therefore, question of doing the same in the present case also does not arise.
- qq. No market is lost due to imports. DI should extend their international price under duty free scheme to attract the finished products exporters :The table below shows the market share of domestic industry and imports. It is evident that domestic producers as a whole lost their market share and imports gained the same.

Particulars	UO M	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Market Share in Demand						
Imports	%	12	14	16	15	17
Domestic industry	%	42	42	40	37	39
Others (Nalco)	%	16	12	10	11	7
Secondary producers	%	31	33	34	37	36
Total Primary producers	%	57	53	50	49	46
Total of Indian producers	%	88	86	84	85	83

- rr. Import figures mislead, as the ones presented relates to total ch. 7601. Submission of import data of 7601.10 is required as the same would be negligible: The table below shows the imports segregated into 760110 and 760120. It would be seen that the imports are significant in both the classifications.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Imports in 760110	MT	97,596	1,60,496	1,94,104	1,56,326	1,97,394
Imports in 760120	MT	1,44,937	1,47,783	1,54,782	1,87,101	2,24,570
Total	MT	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964

- ss. Increased exports in wake of increased imports in the present context shows that the applicants want to export PUC, creating scarcity in the Indian markets. Thereby injuring the secondary AI market: Submissions made before are reiterated. Increased exports by petitioners are because of increased imports by consumers. It is not a case of increased imports by consumers because of increased exports by petitioners. This gets clearly established by a comparison of profitability of domestic industry in the domestic and export market. Petitioners do not want to export the product. Petitioners are forced to export the product because of increasing imports of the product in the country.
- tt. The injury investigation period coincides with 2 FTAs namely, Malaysia -India FTA (Jul. 2011) and ASEAN-India FTA (Jan. 2010) : This is the precise argument of the petitioners. Surge in import is due to FTAs signed by India with some of the countries. These FTAs clearly constitute unforeseen developments, as it cannot be reasonably expected that the result of FTA shall be low priced imports. Further, as a result of these FTAs, new capacities have been set up in Midde East and China PR as per details given in the petition. Thus, while these FTAs have been signed, it was totally unforeseen that the same shall lead to setting up of fresh capacities in these countries.
- uu. There is no sudden and sharp increase Argentina- Footwear WTO Appellate Body Report (Footwear case), highlights the characteristics of sudden, sharp and significant imports.: There is clear sudden, sharp, significant increase in imports in recent period within the meaning of increased imports under the WTO Agreement and Indian rules.
- vv. Present petition is baseless as per AoS, GATT. Appellate Body report on US-Steel Safeguards and US-Definitive Measure- logical connection missing in the petition between the unforeseen development and increase in imports. : The requirement of AoS and GATT are fully met in the present case. In fact, interested parties themselves have contended that increased imports coincide with signing of FTAs. Thus, it is their own case that increased imports are coinciding with unforeseen development. In so far as the question of Agreement on Safeguard and the requirement of unforeseen developments stated therein are concerned, petitioners reproduce the relevant part of the Agreement. It would be seen that the Agreement provides that the increased import should be a result of tariff concessions and obligations incurred by India.

#### *Concessions and Other Obligations*

*In applying a safeguard measure, the Member must maintain a substantially equivalent level of concessions and other obligations with respect to affected exporting Members. To do so, any adequate means of trade compensation may be agreed with the affected Members. Absent such agreement, the affected exporting Members individually may suspend substantially equivalent concessions and other obligations. This latter right cannot be exercised during the first three years of application of a safeguard measure if the measure is taken based on an absolute increase in imports, and otherwise conforms to the provisions of the Agreement.*

India has in fact undertaken tariff concessions and the same has led to reduction of customs duty.

- ww. No loss of production to the DI on account of imports, moreover DI infused substantial funds to increase production and are able to sell the produce too. : The DI has clearly faced loss of production due to increased imports. If exports are excluded from production, it would be seen that there is an increase in production significantly lower than increase in demand.
- xx. No loss making recorded for the last 5 years by the petitioners. Only reduction in profitability, that too not because of imports but because of the depressed price of AI in international market. : Statement is factually incorrect. Table below shows profitability of the DI. It would be seen that the DI is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investment. This is because of price depression faced in the PUC.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Profit/(Loss) – Domestic	Rs.Lacs	100	13	-4	149	-50
Cash Profit	Rs.Lacs	100	23	10	152	-31
Return on Investment	%	100	60	20	100	0

- yy. DI injured on account of their own expansion plans, huge depreciation and interest costs being the driving reasons : Decline in profitability is not due to increase in depreciation or interest cost. Even if it is admitted that the decline in profits is due to depreciation and interest cost, it cannot be said that the DI is not entitled to protection under the rules. Under annexure –II, requirements of causal link cannot be read to imply that there is absence of causal link because of increase in depreciation and interest cost. The present petition is a petition for imposition of safeguard duty and not for anti-dumping duties.
- zz. United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea, WT/DS202/AB/R, adopted 8 March 2002, DSR 2002:IV, 1403- safeguard measure is an extra ordinary remedy to be adopted in emergency situation :The facts of present case clearly establish an extraordinary situation in the present industry. The combined loss suffered by the industry in its domestic and export operations was in the region of Rs 463 crore. Further, profitability changed by Rs. over 500 crore over the present injury period. This by no stretch of imagination can be considered as an ordinary business situation.
- aaa. DI failed to produce any WTO provision to seek safeguard duty. : The present petition is under Indian rules and not under WTO Agreement. The petitioners have filed petition considering the trade notice and has provided all such information which the DG has prescribed. It is not an argument of any interested party that the WTO Agreement is different from Indian Rules. Thus, the present petition is fully consistent with the WTO Agreement of Safeguards.
- bbb. Retrenchment/ lay off, of workers not possible as per the facts provided by the DI. Employment doesn't show any sign of injury: It is not necessary that all injury parameters must show injury. In fact, the jurisprudence on the subject is absolutely clear – while there are large number of parameters prescribed under the law, it is not necessary that all these parameters show deterioration and establish injury on individual parameter basis. On the contrary, it is well understood that the injury analysis is required to be conducted after considering all parameters relating to industry. Further, in a situation where some injury parameters have shown improvement and some have shown deterioration, the DG must examine where deterioration in some of the parameters far outweighs improvement in some other injury parameters.
- ccc. The DI is making profits by exporting and does not sell the products to the domestic users : The petitioners have provided factual data. This clearly establishes that the petitioners have suffered significantly higher losses in exports as compared to domestic operations. Thus, exports made by the petitioners were a compulsion as a result of increased imports and was really not a choice of the petitioners.
- ddd. Economic parameters of the DI ranging from production to productivity per employee had improved : The written submission are referred to and relied upon, which clearly establishes that the DI has suffered serious injury as a result of increased imports. The claim of serious injury gets fully established by considering parameters such as significant decline in profits, ROI, market share, increase in losses in exports, increased exports due to increased imports. All these parameters collectively and cumulatively established that the DI has suffered serious injury.
- eee. Market behaviour with regard to aluminium was predictable because of falling Chinese consumption pattern in 2011, along with the forecasts of increasing production capacity of the Middle East : Falling Chinese consumption and increasing production capacity in Middle East both constitutes unforeseen developments.
- fff. Challenges inclusion of SEZ by petitioners as part of DI by citing Final Findings of Electrical Insulators from China PR. : Elaborate written submissions are referred to and relied upon. As far as decision of the authority in the matter of electrical insulators is concerned, petitioners have already made elaborate submissions how this decision cannot become a legally binding precedence in the present case.
- ggg. Appellate Body in US-Lamb defines serious injury and establishes different natures of serious and material injury: The decision of Appellate Body in US lamb case when applied to the present case clearly establishes that the DI has suffered serious injury.
- hhh. Shows increase in economic parameters for the DI, to nullify claims of injury : Increase in some economic parameters, when performance in some other parameters has severely deteriorated, does not imply no injury. In fact, improvement in these parameters is of no relevance/advantage to the domestic industry. Performance of the DI has so materially deteriorated in other parameters.

- iii. Data received post-public hearing shows negative price undercutting :The price undercutting is clearly positive in the present case. Since there is significant difference in alloy and non-alloy products, the DG may compare the two separately.
- jjj. DGSG has laid out events as “not-unforeseen” and futile due to Chinese exclusion from the investigation is challenged: Low volume of imports from China does not mean that economic situation in China cannot mean unforeseen developments.
- kkk. The final findings of DG Safeguards in the previous case in 2014 whereby the DI was adjudicated to be under no harm : Considering the facts of the previous case, facts of the present case establishes serious injury. In fact, petition clearly shows that performance of the domestic industry improved in 2014-15. The observation of the DG was based on performance in Q1 of 2014-15 and therefore the observations of the DGSG in the previous case final findings and claim of the petitioners in the present petition are fully consistent. However, after improvement in performance in 2014-15, there was a dramatic decline in the performance in 2015-16 due to decline in LME prices.
- lll. No causal link. DI increased capacity without optimizing the existing capacity. Thus lead to increased interest payments: Submissions made are relied upon. The DG may consider profit before interest and depreciation which will show a significant deterioration in profitability of domestic industry. Thus, the argument is without any basis. Even in a situation where DI has been expanding its capacity which are not getting fully established, the DI is entitled for safeguard duty protection. The DI is clearly entitled to protection even if it is in stabilization stage for enhancement of capacities. The facts of the case do not show that the DI was increasing capacities without optimizing existing capacities. It would be seen that profit before interest declined significantly over the injury period. It is thus evident that the deterioration in profits of the DI was not due to increase in interest cost. The same was due to decline in selling price as a result of significant decline in LME price.
- mmm. Domestic users cannot bear the brunt for excess capacity with DI: In a situation of excess capacity with the domestic industry, there is no necessity of imports by the consumers. Further, if imports increase in a situation where industry is already suffering from excessive capacity, the situation is likely to lead to increase in cost of production of the domestic industry and resultantly higher prices to the consumers.
- nnn. Sharp increase in interest cost: The authority may consider profitability of domestic industry before and after interests expense. It would be seen that profit before interests declined severely. This further establishes that the decline in profitability of domestic industry was not due to increase in interests cost.
- ooo. The DI does not follow the LME price. In fact the price of DI is higher than LME: The fact is that the selling price of domestic industry declined steeply over the period. Resultantly, the profitability of domestic industry has declined significantly.
- ppp. DI failed to cut down its price despite decrease in raw material prices: The changes in selling prices and raw material costs are on record. It would be seen that the domestic industry has reduced prices significantly and even beyond the decline in raw material prices.
- qqq. Wages increased by 150%, whereas employment only increased 5%: The table below shows the incident of wage cost per kilo and profitability of domestic industry. It would be seen that the deterioration in profitability of domestic industry could not have been due to alleged increased in wage cost.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Wage cost per MT of production	Rs./MT	100	101	122	139	127
Profit/( Loss) - Domestic	Rs. MT	100	11	-4	154	-37
Changes year to year						
Wage cost per MT of production	Rs./MT	100	1,631	1,325	-944	100
Profit/( Loss) - Domestic	Rs./MT	100	17	-178	215	100

- rrr. Captive consumption figure which stood at 70% needs analysis: All factual information is on record. The domestic industry shall provide any further information as is considered relevant and appropriate by authority.
- sss. Only increase in the import duty of PUC without increase in the finished/semi-finished good will result in inverted structure: Written submissions are relied upon. As submitted before, the consumers are largely in pass-through industry and passes on increases in the input cost.
- ttt. Domestic competition- DI amount to be representing more than 50% of the total production thus need to analyze the effects of domestic competition on the petitioner : The claimed injury to the domestic industry is because of import competition and decline in import prices as a result of decline in LME prices. The claimed injury to the domestic industry is not on account of possible inter-se competition amongst the domestic producers. In fact, domestic producers were competing with each other throughout the relevant period. However, profitability of domestic industry has severely declined, despite similar inter-se competition amongst domestic producers.
- uuu. With an increase in imports by 26% in the year 2015-16, the production of the DI increased by 32% along with highest sales figure. Thus breaking the causal link : The table below shows imports of PUC, production, exports and sales of the domestic industry. It would be seen that the increase in sales in the domestic market is far lower than increase in production and demand of the product.

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Imports MT	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964
Production – PUC MT	9,97,282	10,63,882	11,53,951	15,01,542	15,99,740
Sales Domestic MT	5,18,295	5,91,784	5,04,675	5,01,513	7,00,486
Exports MT	1,48,485	1,34,555	2,96,301	5,95,931	6,64,197

- vvv. Footwear Case, along with Korea-Dairy, and US-Wheat Gluten- Causation standard: The stated cases do not vitiate the conclusions drawn in the present case. In the present case, it is increased imports that have caused injury to the domestic industry.
- www. No coincidence of reduced profits due to increasing imports. No proof of fall in sales due to increasing imports: The table below shows the imports of PUC and profitability of domestic industry. It is evident that the profitability of domestic industry has declined steeply in the present period as imports have increased. Further, petitioners submit that (a) the volume of imports are required to be compared with volumes and market share of the domestic industry and (b) price of imports is required to be compared with profits of domestic industry. The table below shows the import price of PUC and profitability of the domestic industry. It would be seen that the profitability of domestic industry has moved in tandem with import price. Thus, deterioration in profitability of domestic industry is due to import price.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Imports Volume	MT	2,42,533	3,08,279	3,48,886	3,43,428	4,21,964
Profit/(Loss) - Domestic	Rs. MT	100	11	-4	154	-37
Import price CIF	Rs. MT	120490	123000	128420	138640	123930

- xxx. Reduction in profits is not a sign of link, but was on account of LME Price Fluctuation: The fact that LME declined for the period also establishes causal link. If Indian importers had not been importing at prices linked to LME, the domestic industry would not have been forced to link its prices to LME. Thus, if import price has declined due to LME, the same nevertheless establishes causal link. The reason for decline in import price is not relevant for causal link. The reason for decline in import price is relevant for decision on unforeseen development. It is the decline in LME which is responsible for

increased imports. Further, this decline in LME was completely unforeseen as far as domestic industry is concerned.

- yyy. The contention of the petitioner regarding reduction in domestic producers' share of market can be explained through increase in production costs and cheap imports from China PR: The argument has no rationality. First of all, increase/decrease in production cost is not linked to market share. The market share of domestic producers does not change with change in production costs. Further, the present case is a safeguard case and therefore availability of cheap imports from China in itself is not relevant and sufficient parameter to break causal link. In fact, interested parties have contended that imports from China are negligible. At the same time, some parties have contended that the performance of domestic industry has deteriorated due to cheap imports. Evidently, the parties are contradicting each other.
- zzz. Combined results from the aluminium market price crash and high energy costs in India are eating up the revenues: This clearly establishes the causal link. It is this price crash which is responsible for injury to domestic industry. The fact that the energy costs in India are high is entirely immaterial. With the similar high level of energy cost over the injury period, the domestic industry was earlier earning profits and is now suffering losses. Table below shows energy cost paid by the domestic industry and its profitability.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Energy Cost	Rs./MT	100	123	131	169	143
Profit/(Loss) - Domestic	Rs. MT	100	11	-4	154	-37

- aaaa. Decrease in inventory pointing towards increasing domestic consumption. Inventory improved : As submitted before, given the high price of PUC and considering per day production by the petitioners, it is not possible for domestic industry to hold inventories. In fact, on several occasions, the domestic industry has been forced to undertake exports in order to liquidate the inventories.
- bbbb. The negative impact on the Indian producers due to aluminium world prices, increase in import stipulated by growth in Al consumption by downstream industry : This is the precise argument of the petitioners. Decline in aluminium prices globally has led to increase in imports in India. Consequently, the domestic industry had to undertake significant exports at much lower prices. The domestic industry was forced to export because of increasing imports in the country.
- cccc. DI holds 85% share of the domestic demand. Mere 15% cannot cause serious injury: 15% market share cannot be called insignificant in a situation where the domestic industry is admittedly holding excessive capacities.
- dddd. Issue with Vedanta is bauxite and coal procurement, as mentioned in their Annual Report: The alleged issues might have impacted production. Production by the petitioners admittedly increased, thus establishing that the alleged factors did not adversely impact the domestic industry. If petitioners were not able to sell remaining volumes in domestic market, it was only because of increased imports in the country.
- eeee. The DI was suffering injury when price undercutting was negative for the initial 3 years : Price undercutting was not negative. The authority is requested to consider and compare the imported product and domestic industry product prices on comparable basis.
- ffff. Injury is due to depreciation cost, high finance cost on increased capital expansion: It would be seen from the table below that all parameters show deterioration. Evidently, decline in profitability of domestic industry is not due to alleged increase in depreciation and interests cost. It is due to steep decline in the prices as a result of steep decline in LME and consequently import prices.

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Profit/(Loss) - Domestic	Rs.Lacs	100	13	-4	149	-50
Profit/ (Loss) – before interest	Rs.Lacs	100	73	35	162	23
Profit/ (Loss) – before interest and depreciation	Rs.Lacs	100	75	40	163	29

- gggg. PUC finds expansive and across-the-board application, thus levy of duty would adversely affect downstream industries: Petition and written submission are referred to and relied upon, which clearly establish that the weighted average impact of 10% of safeguard duties on the consumer shall be 0.053%, which is grossly insignificant. Further, public interest cannot be read merely as immediate consumers interest.
- hhhh. Imposition of safeguard duty would have serious impacts on various user sectors and huge profit for the DI. This is completely against the public interest. United *Phosphorous v. Director General (Safeguards)*, 2000 (118) E.L.T. 326 (Del.): There is no merit in the argument. As far as domestic industry is concerned, the domestic industry is suffering significant financial losses and the question of huge profits is simply ruled out. The DG had earlier recommended 10% safeguard duty. As far as the adverse impact of safeguard duty on the users is concerned, petitioners reiterate that the argument is without any basis. Impact of 10% safeguard duty on the consumers shall be only 0.053%. Detailed information filed before is referred to and relied upon.
- iiii. Duty would flood market with finished products, thus destroying downstream industries and render workers jobless: The argument is a mere conjecture. Despite increase in customs duty, there has not been significant increase in the finished downstream product. The interested parties have provided no evidence to establish their contention.
- jjjj. Final Finding of Cold Rolled Flat Products of SS of 400 Series, to establish that interest of DI cannot be said to be public interest : The facts of that case are entirely different and therefore are not relevant to the present case.
- kkkk. Levy of duty would go contrary to the public interest, and the smaller conductor manufacturer and power cable business would make losses: There is no merit in the argument. Conductor industry is clearly a pass-through industry. In case of power cable also, the consumers pass on the changes in aluminium cost of the downstream industry. Without prejudice, if import of the downstream products surges, that domestic industry can certainly file petition and seek redressal. Merely because downstream products imports may surge does not imply that the present domestic industry is made to suffer serious injury.
- llll. “Haridas Export vs. All India Float Glass Manufacturer’s Association (2002 (145) ELT 241 (S.C.))” establishes that import of PUC at competitive price is not prejudicial to Public Interest. Even if prejudicial in nature duty cannot be levied despite of impairment caused to DI. 2000 (118) E.L.T. 310 (S.C.): The stated decision has been quoted totally out of context. In case it is established that the product under consideration is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, Govt. must impose safeguard duty on imports.
- mmmm. Adjustment plan to be disclosed to the interested parties in NCV Format as claimed in the confidential version: The petitioners have provided revised NCV as per the directions of DGSG. Further, DGSG has circulated revised NCV to the interested parties.
- nnnn. The NCV version of the adjustment plan does not make it clear what will be the effect of the plan proposed by the DI: The information provided to the DG clearly shows the effect of adjustment plan proposed by the domestic industry on reduction on cost of production.
- oooo. Vedanta’s Chairman has made public statement in press that their prices are going in right direction and the worst is over. : LME has in fact declined further beyond the average of 2015-16. As regard Vedanta Chairman’s statement, petitioners submit that these are optimistic statements and in respect of potential market situations. The DG is however required to record findings based on actual information and not considering potential market situation. In any case, if the market situation changes dramatically in future, the DG has powers to undertake a review for withdrawal of safeguard duties.
- pppp. The submission that SEZ should be treated as DI is a factually correct submission. But in a recent anti-dumping initiation concerning-Non Woven Fabric originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR, F.No.14/23/2015-DGAD, dated 15th June, 2016, the petitioner did not consider SEZ as DI and DG should call for copy of the application filed by the DI specially the part II in that case. There should be consistency of approach: A copy of the petition can be provided, if so required by the DG. It would be seen that the DA has considered SEZ as a domestic industry to the extent of domestic sales.
- qqqq. DI exports products on LME terms but the same is denied to the domestic users: The domestic industry sells the products both in domestic and export markets on prices linked to LME.

- rrrr. The imported aluminium is not cheap imports. Price of DI is in parity with the imported products : The arguments contradict argument of other parties. On one hand some parties have contended that domestic industry is not selling at LME and some parties have contended that the price of domestic industry is in parity with the imported product. The fact is that the prices of PUC declined severely; as a result of which, the price of imported product steeply declined.
- ssss. DI already enjoying sufficient protection (13%) owing to ad-valorem import duty in addition to the extra percentage points charged by them in the name of clearing and forwarding charges : The injury to the domestic industry claimed by the petitioners is after taking into account the existing duties.
- ttt. Misleading information provided to the government by the applicants, regarding capacity utilization. Reduced figure achieved by, selective product heads chosen to determine capacity and inflating installed capacity. : Petitioners have provided all relevant information as desired by the DG. There was no suppression of facts. The complete information is on record.
- uuuu. DI being benefitted by the depreciation of rupee: The claimed injury is on the basis of profit/loss which has taken care of depreciation of rupee.
- vvvv. Applicants have priced the Al Ingots in a way to include LME+Premium+Custom Duty+Logistic Cost (as in case of imports), as compared to the standard practice of LME+Premium.: No industry prices its product without having regard to prevailing customs duty and logistic cost. In fact, the consumer industry also prices its product having regard to customs duty and logistic cost.
- wwww. Increase in the domestic price by Rs.3500 per MT in the wake of budgetary changes in form of increase in import duty from 5% to 7.5%. : While customs duty was enhanced from 5% to 7.5%, the impact of the same was about rupee 000 per MT. However, at the same time, the Government enhanced cess on coal, impacting the cost of production of the industry. Thus, the domestic industry has received no material protection from enhancement of customs duty from 5% to 7.5%.
- xxxx. Usage of 2011-12 as the base reference year is a diversion, as during that time LME was at its peak: Even if some other period is considered as a base period, the same will still lead to the same conclusion.
- yyyy. Exploited the depreciation of INR wrt USD along with enjoying downwards tread of fuel cost accounting 45% of the production cost: The petitioners have reported their performance on the basis of records maintained by them.
- zzzz. Installed capacity argument of the DI holds no ground; not only did their production capacity grew by 10% b/w 2012-16 they are also going on for massive expansions: Production increased by 60%, sales increased only by 35% and exports increased by 345%. Petitioners were suffering far higher loss in exports as compared to domestic which establishes that petitioners are suffering injury due to increased imports.
- aaaaa. Export price is 6-9% lower than the price they are selling to the domestic industry. Thus taking advantage of the custom duty: The petitioners are legitimately entitled to take advantages of the customs duty. Even the consumers of the PUC are doing so. As regards export price of petitioners, the petitioners have been forced to export at a lower price because of imports into India.

#### **G. Hydro Aluminium Asia Pte Ltd; Singapore; Rockman Industries Ltd; Endurance Technologies Ltd**

- The contentions of the domestic producers in general stand denied.
- As the information has been changed severally, the injury data submitted by the applicants may be subjected to utmost scrutiny.
- The exclusion or inclusion of an SEZ unit from the ambit of domestic industry is an unsettled question of law. The DG, Safeguards may reach to a finding on the same as per the Safeguard rules. However, the burden of huge export capacities set up by targeting the export markets by the applicants should not lead to very high fair prices for the domestic industry and the Indian users should not be put to bear the brunt of such export capacities set up by them.
- An injury analysis by taking injury information for 2015-16 as a whole and not subjecting the same to quarterly analysis will be highly insufficient. The performance of the aluminium sector recovered significantly during the beginning of 2016 as admitted by the Chairman of M/s Vedanta itself. Thus, conducting a comparison of data with 2011-12 as the base year and 2015-16 as the most recent period would not show the correct and accurate picture of the domestic industry.

- e. Analyzing 2015-16 information further into quarters and considering information till the quarter ending 30th September, 2016 would show a totally different picture of benevolent position of the domestic industry.
- f. The summary data published by DGCI&S as proposed by the petitioners may not be relied upon. The transaction wise import data as per DGCI&S would show the real heterogeneous nature of multiple variety of products getting imported under these headings at significantly different prices.
- g. All such confidential information which has been filed with no appropriate non confidential version or proper justification for claiming confidentiality may be disregarded.
- h. The submission of the DI makes it very clear that PUC is a huge whole basket of heterogeneous products and a lot of exclusions are essential to bring the definition of PUC in sync with the reality and what is fair and just under the rule.
- i. Non alloys have different application and alloys have different application. Wire rods and ingots are not directly competitive items. It is absolutely unjustified that alloyed and non alloyed products are put in one basket whereas non alloy and alloy have further multiple inter se types in it which also vary in terms of technical properties and price. There is no justification for inclusion of those items which have never been manufactured by the DI.
- j. In the submissions filed by CMR Century Metal Recycling Pvt. Ltd (CMR), CMR Nikkei India Private Limited (CMRN) and CMR-Toyotsu Aluminium India Private Limited (CMRT) it is claimed that they have produced only alloy aluminium. This shows the products produced by the petitioners do not represent the 'like article' produced by the domestic industry and the petitioners did not bring on record the existence of different set of industries engaged in alloy aluminium production which is apparently a different category all together. Thus, what the petitioner has shared qua domestic industry and standing is not correct and the facts require much detailed investigation.
- k. The increase in imports along with the fact that even after such alleged increases, overall share of imports in demand has been less than 15% which shows 85% of the market share has been comfortably held by the domestic producers. Thus, the allegations of increase in imports are not real and are hoisted to gain undue protection under the safeguard scheme.
- l. There is no substance in these claims of the petitioners and they are self-contradictory. The petitioner has cited some probable causes of sudden spurt in imports but such causes *prima facie* show that they could not have caused any spurt in imports in a very short period of time. Some of the reasons cited are even alleged subsidy. Mere cyclical changes in the commodity market for a short period of time, especially when the prices are governed by LME should not be subjected to safeguard duties under the garb of spurt in volumes as the effect of the same on the user industry would be irreparable.
- m. The position of the petitioners has tremendously improved and they are realising fair prices for the subject goods as admitted by Chairman of one of the petitioners M/s Vedanta itself. Imposing Safeguard duty would only help the petitioners to resort to gaining unreasonable profits and the user industry which is already paying a higher price would be subjected to pay more as a result of any safeguard duties.
- n. The facts of the present case as established in their written submissions show that the petitioners failed to demonstrate a case of serious injury and the claims are mere. The allegations of injury require strict scrutiny since the producers have SEZ/EOU units and have huge excess capacities. The domestic industry is not represented accurately before the DG since there are new sets of producers claiming they are also manufacturers of subject goods like CMR.
- o. The position of imports and performance of domestic industry may be examined quarterly during 2015-16 and also up to quarter ending September, 2016 as comparison between 2011-12 and 2015-16 is inappropriate.
- p. Blanket claims of injury are not tenable under the safeguard rules. Domestic industry has been holding a substantial position of around 85% of the Indian demand. Import at 15% has been put under one PUC basket with a whole bunch of products varying in terms of technical features and also price. Many of the items are not even produced by the domestic industry or are not like article to the goods produced by the domestic industry.

- q. The petitioners have relied upon same parameters to allege spurt in volume, serious injury and threat of injury. This shows that the reasons pointed out by the petitioners are at the best inherent cyclical issues in the commodity market and are not any specific reason to have caused any sudden spike in import as alleged by the petitioner to have caused them any injury. Also, the petitioner while claiming threat of injury did not show how such factors are causing some threat to them as admittedly the situation of the domestic industry is already on a path of tremendous improvements. Thus, there is neither serious injury nor any threat of injury.
- r. Global cyclical effects may have impacted the Indian industry also but the situation has changed now and there is no need for safeguard duties on the imports of PUC.
- s. There is no causal relationship between imports and alleged injury as
  - i. Profit was declining when the undercutting was negative in the initial three years which shows any decline in profit ought to have been due to some other reasons.
  - ii. Injury claimed is not connected to imports and reasons such as raw material procurement issues, high interest cost etc are apparent.
  - iii. The reasons of any alleged injury is solely other reasons and are not driven by any sudden surge in imports as the DI could not show any such increase in imports.
  - iv. The DI is holding on to more than 85% of market share and no injury in terms of volume or price parameters is visible.
  - v. Thus, there is no causal link between alleged surge in imports and serious injury allegedly caused to the DI.
  - vi. Vedanta has significant legal issue and litigations concerning environmental issues qua their mines and any impact of the same should not be attributed to imports.
  - vii. It is an admitted fact as above that the industry has been through a volatile period and the same is over and the industry is gaining benevolent prices. Volatility in the segment cannot be made a base to claim remedy under safeguard scheme. Thus, the entire claim of injury on account of sudden and sharp increase in imports is unfounded.
- t. The petitioner has not established any case for imposition of Safeguard duties hence the request for duties for 2 years also needs to be denied.
- u. Imposition of Safeguard duties will have a huge impact on user industry that too when the prices of the subject goods have significantly gone up and BCD has been already increased by 2.5%. The claims of the petitioner are not based on facts.
- v. The NCV version of the adjustment plan does not permit any meaningful reading of the plan and DI should provide meaningful information for providing comments.
- w. The application is not maintainable and the current proceedings may be terminated.
- x. The present investigation cannot be carried out with the present scope of PUC which includes wide range of products which cannot be put together in the scope of one investigation and such bucketing will render distorted results which would be against the legitimate interests of users in India.

#### **IV. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)**

1. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting nations. The written submissions and the rejoinder submissions made by them have also been considered appropriately. The submissions made by various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below:
2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of safeguard duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation.

4. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

**A. Domestic Industry (DI):**

5. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry as follows:

*"(b) "Domestic Industry" mean the producers -*

*(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*

*(ii) Whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;"*

6. Some of the interested parties have contended that the SEZ plant of M/s Vedanta is only for export and hence cannot be included in the domestic capacity. However, the DI holds that SEZ unit of M/s Vedanta should be treated as domestic industry for the reasons given below:.

- a. The term used in the safeguard law is "*producers -in India*" and the SEZ Units established in SEZs are very much producers in India.
- b. The relevant criteria for standing and scope of 'domestic industry' are production and not utilization of such production.
- c. Under the SEZ Act, import implies bringing goods or receiving services, in a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by any other mode and export implies taking goods, or providing services, out of India, from a Special Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode. Therefore, sale by an SEZ unit into DTA is not an export and is in fact a domestic sale.
- d. The sale made by a unit in SEZ are treated as domestic sale in the books of accounts; customs authorities also treat the sales to Indian buyers by SEZ units as domestic sales; civil, criminal or business laws are applicable to SEZs; SEZ is treated as an Indian manufacturer for various regulations.
- e. As per Anti Dumping authorities' decisions, an EOU or a unit in SEZ is treated as a domestic industry.
- f. In DG Safeguards case of saturated fatty alcohols, a 100% EOU is treated as domestic industry.
- g. Exports by Indian SEZs are treated as goods 'originating in India' by other countries.
- h. Various benefits given to SEZ unit should not impact the treatment of such unit as a domestic industry.

7. In this regard, I observe as under:

- (i) The Special Economic Zones Act, 2005 (SEZ Act) enacted on 23rd June, 2005 states that it is :-
 

"An Act to provide for the establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion of exports and for matters connected therewith or incidental thereto."
- (ii) Section 2 (i) of SEZ Act defines Domestic Tariff Area (DTA) as:-
 

"Domestic Tariff Area" means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones;"
- (iii) Section 2 (m) (ii) of SEZ Act, 2005 defines export to, inter alia, mean "supplying goods, or providing services, from Domestic Tariff Area to a Unit or Developer".
- (iv) Section 30 of the SEZ Act provides that:-
 

"Subject to the conditions specified in the rules made by the Central Government in this behalf:-

  - (a) any goods removed from a Special Economic Zone to the Domestic Tariff Area shall be chargeable to duties of customs including anti-dumping, countervailing and safeguard duties under the Customs Tariff Act, 1975, where applicable, as leviable on such goods when imported; and

- (b) the rate of duty and tariff valuation, if any, applicable to goods removed from a Special Economic Zone shall be at the rate and tariff valuation in force as on the date of such removal, and where such date is not ascertainable, on the date of payment of duty.”
- (v) Section 53 of the SEZ Act further provides that:-  
A Special Economic Zone shall, on and from the appointed day, be deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes of undertaking the authorized operations.  
(2) A Special Economic Zone shall, with effect from such date as Central Government may notify, be deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations, as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962:  
Provided that for the purposes of this section, the Central Government may notify different dates for different Special Economic Zones.
- (vi) Rule 47 of the Special Economic Zones Rules, 2006 states as under:  
“Sales in Domestic Tariff Area — (1) A Unit may sell goods and services including rejects or wastes or scraps or remnants or broken diamonds or by-products arising during the manufacturing process or in connection therewith, in the Domestic Tariff Area on payment of customs duties under section 30, subject to the following conditions, namely:  
(a) Domestic Tariff Area sale under sub-rule (1), of goods manufactured by a Unit shall be on submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India, under the provisions of the Foreign Trade Policy”
8. From the aforementioned provisions of the SEZ Act & Rules made thereunder it is observed that:
- The fundamental objective of establishing of SEZ units is promotion of exports.
  - The areas of the SEZs are excluded from the definition of Domestic Tariff Area (DTA) and removals therefrom are subject to duties of customs including anti-dumping, countervailing and safeguard duties under the Customs Tariff Act, 1975.
  - Supply of goods from DTA to the SEZ constitutes export.
  - Under Section 53 of the SEZ Act, an SEZ is deemed to be a territory outside the customs territory of India and is also deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations, as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962.
  - Domestic Tariff Area sale of goods manufactured by a SEZ unit can be made only on submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India.
9. As discussed below, the contentions of the DI for treating the SEZ unit as part of domestic industry are not acceptable.
- DI's contention that the term used in the safeguard law is "producers -in India" and the SEZs Units established in SEZs are very much producers in India is not acceptable as an SEZ unit is deemed to be a territory outside the customs territory of India as described under section 53 of SEZ Act, 2005 and all produce therein is treated as if produced outside the territory of India.
  - The DI has argued that relevant criteria for standing and scope of 'domestic industry' are production and not utilization of such production. In my view, as an SEZ is deemed to be a territory outside the customs territory of India, it cannot be treated as domestic producer or domestic industry. At first, eligibility of a unit as domestic producer/industry is to be established and then only its production can be taken into account for the purpose of establishing standing as domestic industry.
  - It has been contended that under the SEZ Act, import implies bringing goods or receiving services, in a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by any other mode and export implies taking goods, or providing services, out of India, from a Special Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode. Therefore, sale by an SEZ unit into DTA is not an export and is in fact a domestic sale. I observe that as per Section 2 (m) (ii) of the SEZ Act, supplying goods or providing services from the Domestic Tariff Area to a Unit or Developer also comes under the definition of export. Also, any goods removed from a Special Economic Zone to the Domestic Tariff Area are chargeable to duties of customs including safeguard duty.

- d. The contention of DI pertaining to the treatment of sale made by a unit in SEZ as domestic sale in the books of accounts or by customs authorities; application of civil, criminal or business laws to SEZs or SEZ being treated as an Indian manufacturer for various regulations raised by the applicant are not relevant. The eligibility of a unit in SEZ as domestic industry has to be decided within the framework of existing legal provisions of Safeguard law read with SEZ Act and rules.
  - e. Anti Dumping authorities' decisions on treatment of an EOU or a unit in SEZ as a domestic industry are taken within the framework of anti-dumping laws and the same are not applicable to safeguard investigations.
  - f. The applicants have pointed out that in DG Safeguards case of saturated fatty alcohols, the domestic industry is a 100% EOU. Since SEZs and EOUs are governed by different legal provisions, the same is not applicable in the current investigations.
  - g. It has been contended that exports by Indian SEZs are treated as goods 'originating in India' by other countries. In my view, the treatment given to the exporters in SEZ by other countries as per their domestic laws is not relevant here.
  - h. The DI has argued that various benefits given to SEZ unit should not impact the treatment of such unit as a domestic industry. In this regard the eligibility of SEZ as domestic industry is being decided on the basis of various relevant provisions of safeguard rules and SEZ Act & rules made thereunder and not on the basis of any benefits given to them.
10. I also find that in one of the past safeguard findings issued vide F.N0.D-22011/14/2011 dated 27.09.2012 concerning imports of electrical insulators into India the issue as to whether an SEZ unit can be included in the scope of SEZ was decided by the Director General (Safeguards) as under:
- "A unit operating in SEZ cannot claim market disruption due to imports. These SEZ units are deemed to be outside Indian Customs Territories and not competing with other domestic units. Accordingly, it is decided that the data in respect of the SEZ unit of WSI, situated in Vishakhapatnam, is not to be considered for the purposes of present investigation."
11. In view of the foregoing discussions, I hold that the SEZ unit of M/s Vedanta is to be excluded from the scope of Domestic Industry. Accordingly installed capacity and other data in respect of SEZ unit of M/s Vedanta have not been considered for the purpose of present investigation.
12. The application is filed by (i) M/s. Vedanta Limited –Aluminium & Power, (ii) M/s Bharat Aluminium Company Ltd. and (iii) M/s Hindalco Industries Limited and together they account for more than 50% of the Indian production and hence are major producers. It is evident from the table given below:
- Table-1
- | YEAR    | Production of DI<br>(MT) | All India Production<br>(MT) | Share of DI<br>(%) |
|---------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2011-12 | 8,77,948                 | 19,18,126                    | 46                 |
| 2012-13 | 9,31,324                 | 20,72,915                    | 45                 |
| 2013-14 | 10,52,132                | 20,89,929                    | 50                 |
| 2014-15 | 13,61,447                | 25,57,548                    | 53                 |
| 2015-16 | 15,60,141                | 28,15,481                    | 55                 |
13. Accordingly, it is held that the applicant domestic producers constitute and represent the Domestic Industry (DI) (excluding the SEZ Unit of M/s Vedanta) within the definition of DI under Sec 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975.
- B. The Product Under Consideration (PUC):**
14. Several interested parties have raised issues on the product under consideration. These issues are addressed below :-

- i. Some of the interested parties argued that the PUC is too wide and is bucketing of heterogeneous products under one PUC.: In this regard I am of the view that merely because different products included in the scope of PUC differ in terms of shape, size or composition, the same does not necessarily imply that the resultant products are substantially different so as to merit a separate treatment.
  - ii. It has been contended by some of the interested parties that PUC as defined in the preliminary finding is not only vague but also does not define the product which is being imported and against which safeguard duty is to be imposed. : There is no basis of the argument. The scope of PUC in preliminary findings is very clear and is reproduced below.  
“The product under consideration Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys) (hereinafter referred to as PUC) is classified under Customs Tariff Heading No.7601 of Chapter 76 of the Customs Tariff Act 1975”.
  - iii. It has been argued that the tariff classification identifies Aluminium not Alloyed and Aluminium Alloys differently and for the present investigation it cannot be treated as one product.: This argument can not be held as correct. There are several precedents showing a number of products under different Customs classification being taken together as PUC.
  - iv. Some of the interested parties argued that the domestic industry does not produce Aluminium Alloys and Aluminium alloys falling under sub-heading 760120 should not be included in the scope of PUC and it should be restricted to sub-heading pertaining to aluminium not alloyed which is 760110.: The applicants submitted that they produce the like or directly competitive article to the PUC. In this regard I have examined the information provided at the time of spot verification of the domestic data and find that the applicants are producing and selling products falling under sub-heading 760120 as well.
15. In view of above, the product under consideration (PUC) taken up for investigation is “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” (hereinafter referred to as PUC) classified under Customs Tariff Heading No.7601 of Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975. It covers the entire product range under Customs Tariff Heading No.7601.
16. It is also held that domestically produced “PUC” falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced “PUC” is a like article to the imported “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” falling under Customs Tariff Heading No 7601, within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

#### C. Source of information:

17. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 7601 of Chapter 76 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data taken from Export Import data bank, Ministry of Commerce (<http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp>) from 2011-12 to 2015-16 (up to January, 2016) and the domestic data from 2011-12 to 2015-16 submitted by the DI in their application. The said domestic data was verified on the basis of Excise Returns and other documents provided by the DI in the office of D.G (Safeguard).
18. It was pointed out by some interested parties that there was a mismatch in the domestic data and that the installed capacity of SEZ unit of M/s Vedanta has been included by the DI in the total installed capacity shown in the application filed by the DI. I observe that the DI in their application had not mentioned that one of their units was an SEZ unit. Accordingly, an on-site verification at manufacturing units of DI was conducted by Directorate General of Safeguards.
19. On examination of the domestic data from 2011-12 to 2016-17 (till June, 2016), it was observed that in some of the manufacturing units, the entries of production and sales/captive consumption of hot metal is reflected in Excise Returns (ER-1) under CTH 7601 alongwith the entries of the products ingots, billets, wire rods etc.. However, these products i.e ingots, billets, wire rods etc. are being produced from the hot metal already entered in the Excise Return. As both hot metal and the PUC (produced from the hot metal) fall under same CTH 7601, there was overlapping in the earlier verified data pertaining to clearances/inventory resulting in some mismatch of the domestic data reflected in the 1st verification report.

20. The verified domestic data in the 2nd verification report does not contain the data of the SEZ unit of M/s Vedanta Ltd.. Also, the issue related to overlapped data mentioned above has been resolved and these final findings are based on the 2nd verification report. The on site verification report (non confidential version) has also been placed in the public file.
21. Further the import data taken from Export Import data bank, Ministry of Commerce (<http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp>) from 2011-12 to 2015-16 is being used for POI analysis. The import data taken from the website of Ministry of Commerce and the verified domestic data for the period 2016-17 (April to June, 16) is being used for the post POI analysis. The cost data have been provided by the domestic industry duly certified by Cost Auditors of the companies and same has been examined by the Advisor (Cost) to DG (Safeguard).

**D. Period of Investigation (POI):**

22. It has been observed that neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define ‘period of investigation’ or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea (Para 7.196,7.199 and 7.201). The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Country to decide the “length of the period of investigation” and its “breakdown”.

*“We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports.”(paras. 7.196, 7.199 and 7.201)*

23. In view of above, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2011-12 to 2015-16 for the purpose of the present investigations.

**E. Confidentiality of information submitted:**

24. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
25. I find that the Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non- confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 read with Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997 and No.D22011/75/2009 dated 21.12.2009. Further, the

Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

#### F. Increased Imports:

26. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

*“(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :”*

27. The safeguard rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have “increased in such quantities” for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.
28. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines ‘increased quantity’ as follows:

*“(c) “increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production.”*

29. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in *Argentina—Footwear (EC)*, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract is as follows:

*“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious injury.’”*

30. The Panel on *US — Wheat Gluten*, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows:

*“8.31 [Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1[of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”*

31. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned law and WTO jurisprudence.

#### Increased Import in absolute terms:

32. The analysis of the trend in imports of PUC in the light of the above mentioned provisions has been done. PUC is imported into India from a number of countries including UAE, Malaysia, Russia, South Africa, Oman, Qatar, Bahrain and Thailand. Some of the interested parties contended that there is no actual sudden and sharp increase in imports required by the WTO Agreement.
33. In this regard, the analysis of the import data for the Period of Investigation from 2011-12 to 2015-16 reveals as under:

Table-2

Financial Year	Total Import (MT)	Trend
2011-12	2,42,533	100
2012-13	3,08,279	127
2013-14	3,48,889	144
2014-15	3,43,428	142
2015-16	4,21,964	174

34. It is apparent from the data in the table above that there is a surge in import in absolute terms i.e. import increased from 2,42,533 MT during the period 2011-12 to 4,21,964 MT during 2015-16. Further, I observe that during the most recent period of 2014-15 to 2015-16, there is a sudden increase of 23% in imports which is significant enough, sharp enough and recent enough.

#### **Import in relation to Production:**

35. The imports of the product under consideration in India over the years are as follows:

Table-3

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	Import with respect to total production (%)
2011-12	2,42,533	19,18,126	13
2012-13	3,08,279	20,72,915	15
2013-14	3,48,889	20,89,929	17
2014-15	3,43,428	25,57,548	13
2015-16	4,21,964	28,15,481	15

36. It is seen that the imports of PUC during the period of investigation have increased in relation to all Indian production. The import with respect to total production increased from 13% in 2011-12 to 15% in 2015-16.

#### **G. Determination of Serious Injury and Threat of Serious Injury:**

37. Sub-section 6(c) of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:

“Serious injury” means an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry;

38. Sub-section 6(d) of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:

“threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury.

39. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides as follows:

*“In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.”*

40. With regard to the overall impairment in the position of the industry, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that an evaluation of each listed factor will not necessarily

have to show that each such factor is "declining" to justify a finding of serious injury. Relevant extract is as follows:

*"139. In our view, it is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is "a significant overall impairment" in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of "serious injury".*

41. Accordingly, in analysing serious injury or threat of serious injury, all factors which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry which are as under:

- a. **Production:** The production of the DI over the years is as follows:

Table-4

Financial Year	Production of DI (MT)	Trend
2011-12	8,77,948	100
2012-13	9,31,324	106
2013-14	10,52,132	120
2014-15	13,61,447	155
2015-16	15,60,141	178

It is seen that the production of domestic industry increased from 8,77,948 MT in 2011-12 to 15,60,141 MT in 2015-16.

- b. **Changes in the level of Sales:** Table below shows the changes in the level of sales over the period of investigation.

Table-5

Financial Year	Import (MT)	Sales of DI (MT)	Captive consumption(DI) (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Total Demand (MT)	Market Share (%)			
						Import	DI (excluding captive consumption)	DI (including captive consumption)	Others
2011-12	2,42,533	6,27,554	1,02,981	9,45,192	19,18,260	13	33	38	49
2012-13	3,08,279	7,10,800	88,898	9,97,410	21,05,387	15	34	38	47
2013-14	3,48,889	6,71,101	76,202	9,40,006	20,36,198	17	33	37	46
2014-15	3,43,428	6,75,798	69,964	11,34,836	22,24,026	15	30	34	51
2015-16	4,21,964	8,90,587	30,472	10,63,907	24,06,930	18	37	38	44

It is seen that the sales of the Domestic Industry increased from 6,27,554 MT in 2011-12 to 8,90,587 MT in 2015-16.

- c. **Market Share:** It is also seen from the table above that the imports had a market share of 15% in 2014-15 which increased to 18% during 2015-16 and the market share of Domestic industry also increased from 30% to 37% (excluding captive consumption) and from 34% to 38% (including captive consumption) during the same period. However during the same period market share of other producers decreased from 51% to 44%.
- d. **Capacity Utilisation:** The DI is manufacturing different aluminium products in addition to the PUC. The common input for all aluminium products manufactured by the DI is aluminium hot metal. The aluminium hot metal can be used for manufacturing of an aluminium product whether PUC or non-PUC as decided by the DI. In other words, there is no dedicated hot metal capacity for producing the PUC. In case, if the entire hot metal production is used for the manufacture of non-PUC items, the DI is left with no quantity of hot metal for the manufacture of PUC. In these circumstances, the dedicated capacities (if any) of the PUC will be irrelevant. Therefore, only the capacity of hot metal production is relevant and the same is taken for the purpose of calculating capacity utilization. Table below shows the capacity utilization of the installed capacity by DI.

Table-6

Financial Year	Installed Capacity of Hot Metal (MT)	Production of Hot Metal (MT)	Capacity Utilisation (%)
2011-12	12,51,400	12,55,713	100
2012-13	12,53,700	13,17,023	105
2013-14	13,54,480	14,10,367	104
2014-15	16,38,728	16,86,726	103
2015-16	20,39,569	19,84,765	97

It is observed that the capacity utilization of the Domestic Industry has remained around 100% throughout the entire POI.

- e. **Employment & Productivity:** The table below shows employment & productivity over the years.

Table-7

Financial Year	Production (MT)	Employment (Nos) (Indexed)	Productivity per employee (MT) (Indexed)
2011-12	8,77,948	100	100
2012-13	9,31,325	95	112
2013-14	10,52,132	112	107
2014-15	13,61,447	112	139
2015-16	15,60,141	106	168

The employment as well as productivity per employee is higher in 2015-16 as compared to the base year 2011-12. There is slight decrease of 5% in employment in the year 2015-16 as compared with 2014-15. However, the productivity has increased by 21% during the same period.

- f. **Profit & Loss (Indexed):** The profitability of the Domestic Industry has declined during 2015-16 and domestic industry recorded losses. This is observed from the table below:-

Table-8

Financial Year	Domestic profit/loss (Rs/Kg) (Indexed)
2011-12	100
2012-13	11
2013-14	-4
2014-15	154
2015-16	-23

**g. Other Important Factors:-**

(i) **Inventories:** Position of inventories is as follows:

Table-9

Financial Year	Inventory Indexed (MT)
2011-12	100
2012-13	91
2013-14	149
2014-15	635
2015-16	197

Inventories have increased from 100 points in base year 2011-12 to 197 during the year 2015-16. During the recent period, the inventories have decreased from 635 points in 2014-15 to 197 points during the year 2015-16. I also observe from the actual data that the inventories as a percentage of total annual production are very insignificant. Hence, changes in the levels of inventories are not relevant for the purpose of determination of injury in the present case.

(ii) **Price undercutting, suppression/depression:**

a. The price undercutting has been calculated by taking into consideration the average landed value of import from the period 2011-12 to 2015-16. The applicable customs duty under Customs Tariff Act, 1975 based upon various Trade Agreements between India and other countries has also been considered while calculating the average landed value of imports. The variation (indexed) of landed prices of imports, sales realization, profit/loss and price undercutting with respect to cost of sales of 2011-12 are as under:-

Table-10

(Indexed with respect to cost of sales of 2011-12)

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Cost of sales (Indexed)	100.0	108.8	110.4	116.8	104.5
Net sales realisation(Indexed)	105.6	109.4	110.2	125.5	103.2
Landed value (indexed)	109.2	111.9	116.3	125.4	112.4
Profit/(loss) (Indexed)	5.6	0.6	-0.2	8.6	-1.3
Price Under cutting (Indexed)	-3.6	-2.5	-6.2	0.1	-9.2

b. It is observed that the landed value of the imports of PUC is higher than the sales realization and cost of sales of the Domestic Industry during POI. The imports were thus not seen to be suppressing the Domestic Industry prices in the market and price undercutting is negative.  
 c. DI in their rejoinder submission argued that the price undercutting is clearly positive in the present case and since there is significant difference in alloy and non-alloy products, the DG may compare the two separately. However, I find that contrary to this, DI has contended in their earlier submissions that the injury analysis is not required to be undertaken separately for each type of the product under consideration and that on the contrary, separate injury analyses is illegal and have even quoted case law in support of their contention. I have examined their contentions and hold that once a single PUC has been defined covering both alloys and non-alloys, there is no scope for making any separate injury analysis.

42. Although there is a surge in import in absolute terms as well as in relation to total domestic production, the factors like production, domestic sales, productivity of DI have improved and capacity utilization has remained around 100% throughout the entire POI. Further, it is observed that the landed price of imports is higher than the selling prices of the domestic industry during POI. Therefore, a conclusion can not be

drawn that the imports were suppressing the Domestic Industry prices in the market. As can be seen, the price undercutting is negative. Therefore, it can not be established that the Domestic Industry is suffering on account of import prices. The market share of import increased from 15% in 2014-15 to 18% during 2015-16 whereas the market share of Domestic industry increased from 30% to 37% (excluding captive consumption) and from 34% to 38% (including captive consumption) during the same period. Further, I observe that the rate of increase of market share of imports is less than the rate of increase in market share of domestic industry. On the other hand, the industry profitability has turned negative during the most recent period, leading to injury of the DI.

43. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the above factors, shows improvement in the position of DI in certain areas despite loss of profitability. It is thus concluded that, there exists an injury to the DI but it can not be stated to be a serious injury or a threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation. In view of the above facts, there appears no need for evaluation of other parameters like causal link, unforeseen circumstances, adjustment plan and public interest.
44. An attempt was also made to analyse the trend in the period after the POI i.e. upto 1st quarter of 2016-17. The import data taken from the website of Ministry of Commerce and the verified domestic data for the period 2016-17 (April to June, 16) has been considered for post POI analysis. The data analysis is as under:

**Table-11**

	2015-16	2016-17 ( upto June,16)	2016-17 (Annualised)	Increase/decrease (%) in 2016-17 as compared to 2015-16
Total Imports (MT)	4,21,964	98,209	3,92,836	-6.9
Production (MT)	15,60,141	4,04,910	16,19,640	3.8
Domestic Sales (MT)	8,90,587	2,39,624	9,58,496	7.6

45. On scrutiny of the above data, it is observed that during the post POI i.e 2016-17 (up to June,16) (Annualised), there is a decrease in the imports by about 6.9% between the period 2015-16 and period up to June, 16 (Annualised). Further during the same period there is an increase of about 3.8% in production and increase of about 7.6% in domestic sales of DI. This shows that the position of DI has improved during post POI period.
46. Further, average monthly LME prices of aluminium have been examined for the post POI period from the website <http://www.lme.com/metals/non-ferrous/aluminium/> and it is observed that the LME prices are on increasing trend since January,2016 as shown in the table below:

Table-12

MONTH	USD/Ton	Trend
Jan-16	1479.09	100
Feb-16	1535.23	104
Mar-16	1530.22	103
Apr-16	1563.96	106
May-16	1,555.96	105
Jun-16	1591.83	108
Jul-16	1629.47	110
Aug-16	1,641.13	111
Sep-16	1589.68	107
Oct-16	1663.57	112
Nov-16	1735	117

47. From the above I find that the average monthly LME price of aluminium has moved upwards from USD 1564 level during April, 2016 to USD 1735 in Nov, 2016, giving scope of better realizations to the domestic producers. Further, depreciation of Rupee during the most recent period has enhanced the competitiveness of the DI.

#### **H. Conclusion:**

48. The imports of the product under consideration have increased in absolute terms as well as in relation to production during the Period of Investigation.
49. Market share, production, domestic sales and productivity of DI have improved and capacity utilization is almost at 100% during the period of investigation.
50. The landed price of imports is higher than the selling prices and cost of sales of the domestic industry during POI and price undercutting is negative. Production, domestic sales, capacity utilization, productivity have improved during the period of investigation. Hence, based on the above data, it can not be concluded that the imports are responsible for decline in profitability of domestic industry
51. Analysis of post POI data shows that import is decreasing whereas production and sales of DI has increased. As LME prices have moved upwards from USD 1563 during April, 2016 to USD 1735 in Nov, 2016, domestic producers will get higher realizations. The depreciation of Rupee is also working in their favour.
52. There exists an injury to the DI but there exists no serious injury or threat of serious injury to the domestic industry in the POI and hence no protection under the safeguard law is required. Moreover, the Govt. of India has already provided relief to the DI, by increasing Custom duty on PUC from 5% to 7.5% with effect from 1st March, 2016 vide Finance Bill 2016, which will further improve their position.

#### **I. Recommendations:**

53. In view of the discussions detailed above and the conclusions reached, safeguard duty on the PUC is not recommended.

[F. No. 22011/10/2016/Pt- VIII/1684]

VINAY CHHABRA, Director General